प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय विश्वविद्यालयों की डिग्री कचान्नों के पाट्यक्रमानुसार मुद्रा न्त्रिविकोषण, विदेशी विनिमय एवं राष्ट्रीय न्त्राय के सिद्धान्तों तथा सम्बन्धित भारतीय समस्यान्त्रों का सरल भाषा में विशद विवेचन करते हुए न्त्राधुनिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

त्राशा है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी पुस्तक का अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुमाव आमंत्रित किये जाते हैं।

विशम्भर सहाय ष्ट्रायोध्या प्रसाद मिश्र

१ जुलाई १६६०

﴿ मुद्रा का ऋाविष्कार, विकास, परिभाषा एवं कार्ये

√२. सुद्रा का वर्गीकरण, दलाई एवं ऋच्छी सुद्रा

ं√रं. मुद्रा-र्मान

√४. स्त्रीर्श्मान

√५. पत्र-मुद्रा चलन

🍕 सुद्रा का मूल्य-निर्धारण एवं परिवर्तन

ॐ. निर्देशांक

□ ६. भारतीय चलन का इतिहास

१०. भौरतवर्ष में दार्शनिक प्रणाली

र. विदेशी विनिमय एवं विनिमय जियत्रण

🍕 २. ऋंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष

र्रे अंतर्रोष्ट्रीय व्यापार एवं भारत का विदेशी व्यापार

🈾 ४. संरच्या एवं भारत में संरच्या नीति

१५. भारत के व्यापारिक समस्ती ते

१६. राष्ट्रीय त्र्याय, वचत, विनियोग श्रीर पूर्ण वृत्ति

द्वितीय खण्ड

१. ऋषिकोषरा

🗸 २. केन्द्रीय बैंक

√३. भारतीय मुद्रा बा**जा**र

४. रिजर्व तैंक स्त्राफ इरिडया

√4. स्टेट वैंक श्राफ इरिडया

√६. संयुक्त पूँ जी वाली ऋथवा व्यापारिक वें

७. श्रीदोगिक ग्रर्थ-व्यवस्था

्र विदेशी विनिमय वैंक

६. ऋन्तर्राष्ट्रीय वैंक

१.º. सहकारी वैंक

११० केली वैंकर तथा साहकार

१२. वैकिंग के सिद्धान्त

.११. साल एवं साख-पत्र

^{है}१ंड्र. वैकिंग विधान

प्रथम खंड

मुद्रा विदेशी विनिमय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय आय

अध्याय १

मुद्रा का श्राविष्कार, विकास, परिभाषा एवं कार्य

विनिमय का विकास-विभिन्न देशों के त्रार्थिक इतिहास से यह प्रकट होता है कि प्रत्येक देश को अपने आर्थिक विकास के प्रारम्भिक युग में ही विनिमय की सुविधा के लिए मुद्रा का सहारा लेना पड़ा। श्राति प्राचीन काल में जबिक प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तुओं का स्वयं उत्पादन कर लेता था, विनिमय की कोई त्रावश्यकता नहीं थी। त्रातः विनिमय के माध्यम का कोई प्रश्न नहीं होता: पर धीरे-घीरे लोगों की आवश्यकतायें बढ़ती गई; उनकी पूर्ति करना बिना दूसरों की सहायता के असम्भव हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उत्पादित वस्तुओं के अतिरिक्त श्रन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुत्रों के उपभोग की श्रावश्यकता होने लगी। श्रतः विनिमय प्रथा का प्रारम्भ हुन्ना। पहले वस्तुन्नों का पारस्परिक न्नादान-प्रदान हो जाता था। एक व्यक्ति अपनी उत्पादित वस्तुत्रों से दूसरे की उत्पादित वस्तुत्रों को बदल लेता था। परन्तु ज्यों-ज्यों सभ्यता के विकास के कारण मनु<u>ष्य की त्रावर्</u>य-कताएँ बढ़ती गईं वस्तुओं के पारस्परिक अदल-बदल में कठिनाइयाँ बढ़ती गईं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसी विनिमय-माध्यम की आवश्यकता हुई। यही विनिमय का माध्यम मुद्रा कहलाता है। इसके प्रचलन से वस्तुत्रों का पारस्परिक अदल-बदल न होकर मुद्रा के द्वारा अदल-बदल प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार विनिमय दो प्रणालियों के अनुसार हो सकता है।

(१) प्रत्यत्त वस्तु विनिमय प्रणाली (Direct Exchange or Barter)— इसके अनुसार गेहूँ उत्पादन करने वाला व्यक्ति अपने उपभोग से बचे हुए गेहूँ को चना उत्पादन करने वाले व्यक्ति के उपभोग से बचे हुए चने से बदल लेता है।.

(२) अप्रत्यच क्रय-विक्रय प्रणाली (Indirect Exchange or Purchase and Sale)—इसके अनुसार पहला व्यक्ति अपने अतिरिक्त गेहूँ को बेचकर सुद्रा प्राप्त करता है और उस सुद्रा से चना खरीदता है। इसी प्रकार दूसरा व्यक्तिं अपने अतिरिक्त चने को बेचकर सुद्रा प्राप्त करता है और उस सुद्रा से गेहूँ खरीदता है।

श्रद्ल-बदल की श्रमुविधाएँ —यहाँ यह जान लेना श्रावश्यकीय प्रतीत, होता है कि व्यक्तियों को प्रत्यच्च विनिमय में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिनसे बचने के लिए मुद्रा का श्राविष्कार किया गया। प्रत्यच्च विनिमय की सबसे

पहली किठनाई दिपत्ती आवश्यकताओं की पूर्ति के संयोग के अभाव से उत्पन्न हुई, अर्थात् ऐसा संयोग किठनता से प्राप्त होने लगा जिसमें गेहूँ देने वाले व्यक्ति को चना देने वाला ऐसा व्यक्ति मिल जाय जिसे गेहूँ की आवश्यकता हो । उपरोक्त हो व्यक्तियों में प्रत्यन्न वस्तु विनिम्य तभी हो सकता जब गेहूँ वाले को चने की आवश्यकता हो तथा चने वाले को गेहूँ की आवश्यकता हो । यदि गेहूँ वाले को चने की आवश्यकता हो तथा चने वाले को चीनी की आवश्यकता हो तो ऐसी अवस्था में प्रत्यन्न वस्तु विनिम्य से काम नहीं चल सकता । मुद्रा के प्रचलन में यह किताई शीव्र हल हो जाती हैं। गेहूँ वाला व्यक्ति गेहूँ वेचकर चना खरीद लेगा। चना वाला व्यक्ति चना वेचकर चीनी खरीद लेगा।

मुद्रा के प्रयोग के कारण सर्वमान्य मूल्य-मापक का अभाव। पहली कठिनाई यदि सामने न भी आवे तो प्रत्यत्त वस्तु विनिमय करने वालों के सामने एक अन्य कठिनाई आ सकती है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु की कितनी मात्रा दूसरे व्यक्ति की वस्तु की कितनी मात्रा में बदले। जिस व्यक्ति के पास र मन अतिरिक्त नेहूँ है वह ४ मन चने चाहता है और दूसरा व्यक्ति १ मन गेहूँ चाहता है, यद्यपि उसके पास ६ मन चने हैं। इस अवस्था में क्या २ मन गेहूँ के बदले में ४ मन् चने प्राप्त किये जाय अथवा ६ मन चने के बदले में १ मन गेहूँ प्राप्त किया जाय या दोनों के अदल-बदल में दूसरा कोई अनुपात निर्धारित किया जाय। इस प्रकार विनिमय दर निर्धारित करने की कठिनाई भी प्रत्यत्त वस्तु विनिमय प्रणाली की एक मुख्य कठिनाई है। यह कठिनाई भी मुद्रा से दूर हो जीती है। मुद्रा के प्रचलन से प्रत्येक वस्तु की कीमत मुद्रा में निर्धारित हो जाती है। गेहूँ १ स्पये में २ सेर मिलता है तथा चना २॥ सेर। स्पष्ट है कि २ सेर गेहूँ का मूल्य २ से सेर चना हो गया। मुद्रा के माध्यम से विनिमय दर निर्धारण सरलता से हो गया।

मुद्रा के माध्यम सं विनमय दर निर्धारण सरलता सं हो गया।
अविभाजकता — बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनका मूल्य विभाजन करने से कम हो जाता है और कुछ वस्तुओं का तो मूल्य विभाजन से नहीं के बराबर हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की वस्तु है तो उसे विनिमय में प्रत्यद्ध रूप से कठिनता हो सकती है। एक व्यक्ति के पास घड़ी है और उसके बदले में वह गेहूँ, चना, चीनी तथा चावल चाहता है और यह चारों वस्तुएँ पृथक-पृथक चार मनुष्यों से प्राप्त हो सकती हैं। घड़ी के चार टुकड़े नहीं किये जा सकते क्योंकि देस करने से बड़ी का नृत्य प्रायः नहीं के जराबर हो जायगा और सम्भव है कि वह इकड़े उन चार व्यक्तियों में से किसी के काम न आवें, अतः वह चारों वस्तुओं की प्राप्त नहीं कर सकता। अधिक से अधिक वह अपनी घड़ी किसी एक व्यक्ति को दे तथा किसी एक ही वस्तु को प्राप्त करें। मुद्रा के प्रचलन से यह कठिनाई भी समाप्त

हो बाती है। घड़ी रुपयों में वेची बाती है और इन रुपयों से आवश्यकतानसार गेहँ.

चना, चीनी, चावल इत्यादि लिया जा सकता है। इस प्रकार आर्थिक विकास के प्रारम्भिक युग में प्रत्यच्च विनिमय की उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया।

मुद्रा का प्रयोग—बहुत दिन तक मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम के रूप में ही कार्य करती रही। इसे धन के रूप में संचय आदि करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठा था। परन्तु धीरे-धीरे मुद्रा का महत्व बढ़ता चला गया तथा इसे विनिमय (१) के माध्यम तथा सुर्व<u>मान्य मूल्य-मापक</u> के अतिरिक्त और भी कार्यों को करना पड़ा।

उपरोक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि जैसे-जैसे विनिमय की आवश्यंकता और किटनाई बढ़ती गई, मुद्रा की खोज आरंभ हो गई। अन्वेद कालीन भारत में गाय का मुद्रा के स्थान पर प्रयोग होता था। कौड़ियाँ, मँगे, मोती, सूखे फल आदि अनेक वस्तुओं का मुद्रा के स्थान पर प्रयोग किया गया। जहाँ तक सिक्कों के चलन का प्रश्न है विद्रानों की राय से लीडिया (Lydia) में सर्व प्रथम घात के सिक्कों का चलन हुआ। मिश्र में दीनार का सिक्का प्रचलन में रहा। कालान्तर में यह मानव समाज तथा आर्थिक-विकास का आवश्यक अग बन गया। जैसे-जैसे सम्यता का विकास होता गया और व्याप्तार एवं वाणिज्य का विकास हुआ मुद्रा की अधिक आवश्यकता पड़ी। इस बढ़ी हुई आवश्यकता ने घात के स्थान पर क्रिज़ी-मुद्रा को जन्म दिया जो कि बाद में वैंकों के विकास एवं विश्वसनीय सरकारों की स्थापना के साथ-साथ सार्वभौमिकता एवं सर्वप्रयता पकड़ती गई।

• मुद्रा की परिभाषा American, a medsuac, a standard &

मुद्रा की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने दृष्टिकोण से विभिन्न प्रमार से की है । काउदर (Crowther) के अनुसार जो वस्त विनिम्य के साधन के रूप में साधारणतया सर्वधाही हो तथा उसी समय मूल्य-मापन तथा मूल्य-संचय का कार्य करती हो वही मुद्रा है । मार्थाल (Marshall) के अनुसार ऐसी सब वस्तुएँ जो विना किसी. सन्देह तथा विना विशेष जाँच के सेवाओं और वस्तुओं के कय एवं सब प्रकार के व्ययों के भुगतान में स्वीकृत कर ली जाय वही मुद्रा है । सार्वध्यन (Robertson) के अनुसार कोई भी वस्तु जो माल के भुगतान में अथवा अन्य प्रकार के व्यापारिक अगुशाधन में सर्वत्र स्वीकृत हो वही मुद्रा है । सेलिगमैन (Seligman) के शब्दों में मुद्रा वह वस्तु है जिसमें सर्वग्राहिता हो । हाटले विदर्स (H. Withers) ने मुद्रा की परिभाषा विचित्र ढंग से को है— "मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है ।" वास्तव में विदर्स की परिभाषा से मुद्रा के विषय में कोई विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं होता कि मुद्रा क्या है । हाँ इस परिभाषा से एक बात अवश्य स्पष्ट होती है कि कोई

भी वस्तु नुद्रा हो सकती है यदि समाज उसे मुद्रा के रूप में मान ले। कुछ श्रौर परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

प्रो॰ ऐली (Ely) के अनुसार "मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु है जिसका विनिमय
के माध्यम के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वक इस्तांतरण होता है और जो ऋणों के अंतिम
भुगतान के रूप में साम्रान्यतया स्वीकार की जाती है।"

काउदर (Crowther) का कहना है कि मुद्रा वह चीन है जिसे साधारणतः

विनिमय का माध्यम मान लिया गया हो श्रौर साथ ही जो मूल्य की माप श्रौर उसके कोष का काम करती हो।

हॉम की परिभाषा में मुद्रा शब्द का उपयोग विनिमय-माध्यम तथा मूल्य-मान दोनों ही के लिए किया गया है।

ग्रन्य विचारानुसार ''सुद्रा में वे वस्तुएँ सम्मिलित होती हैं जो किसी एक समाज में सामान्य रूप में स्वीकार की जाती हैं श्रौर उनका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तान्तरंश होता है...... किन्तु कोई वस्तु ऐसी नहीं होती है जो सुनी स्थानों पर स्वीकार की जाती हो श्रौर इस ग्रर्थ में मुद्रुग सदैव स्थानीय होती है। र

मुद्रा के लिये किसी विशेष प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं। वह तो किसी भी वस्तु की बनाई ज्ञा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि उपरोक्त विभिन्न परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक देखा जाय तो सबसे यही ध्वनित होता है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसका चलन सब प्रकार के भुगतानों में मान्य है। मुद्रा विनमय के साधन, नुत्य-मानन तथा मूल्य संचय का कार्य करने वाली सर्वप्राह्म वस्तु है। जो वस्तु सम्पूर्ण ऋगा शोधन के लिये एक दूसरे के प्रति विना किसी संदेह के अबाध रीति से इस्तान्तिरत होती रहे तथा जो देने वाले व्यक्ति की साख के सोच-विचार के बिना निसंदेह स्वीकृत होती है ऐसी किसी भी वस्तु को हम मुद्रा कह सकते हैं। इस प्रकार किसी प्रकार के प्रतिबन्धरहित सर्वप्राहिता ही मुद्रा का विशेष लच्चण-है।

चूँ कि प्रत्येक वस्तु मुद्रा हो सकती है यदि समाज उसे मुद्रा के रूप में मान ले इसिक्ये विभिन्न देशों ने समय-समय पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को मुद्रा के रूप में माना है। मौद्रिक इतिहास के पढ़ने से पता चलता है कि आदि प्राचीन काल में

किसी प्रकार का अनाज, पशु, पत्तियाँ, कौड़ियाँ आदि वस्तुएँ भी मुद्रा के रूप में 1 "Money has been used to designate the medium of exchange as well as the standard of value."—Halm (Monetary

^{2 &}quot;Money consists of those things which, within a society, are of general acceptability passing from hand to hand as a medium of exchange"....... No commodity is, however, acceptable everywhere and in this sense money is always local,"

उपयोग में आती थीं। कालान्तर में आवश्यकतानुसार इन मुद्रा पदार्थों में परिवर्तन होता गया और ज्यों-ज्यों मुद्रा का महत्व अधिक होता गया और मुद्रा के कार्यों में वृद्धि होती गई त्यों-त्यों मुद्रा पदार्थ के चयन में भी परिवर्तन होता गया, यहाँ तक कि अधिकांश रूप ते सम्पूर्ण देशों में सोना या चाँदी ही मुद्रा के लिये विशेष उपयुक्त धातुएँ समभी जाने लगी। और जब तक कागजी मुद्रा का चलन न हुआ सोने तथा चाँदी की मुद्राएँ ही चलती रहीं।

यह समभाने के लिये कि सोना तथा चाँदी ही मुद्रा के लिये उपयुक्त घातुएँ क्यों मानी गईं मुद्रा के कार्यों का जानना आवश्यक है क्योंकि मुद्रा के कुछ आधुनिक कार्य ऐसे हैं जिनको मुद्रा सफलतापूर्वक तभी कर सकती है जब वह सोने या चाँदी की बनी हों।

साधारण तौर पर त्राधुनिक काल में मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं-

साधारणतया मुद्रा के कार्य तीन भागों में विभाजित किये जाते हें — ग्रीथमिक कार्य, <u>गौण कार्य</u> श्रोर <u>श्राकस्मिक कार्य</u>।

मुद्रा के प्राथमिक कार्य वे प्रारम्भिक तथा मुख्य कार्य हैं जिनके लिये मुद्रा का ऋाविष्कार हुआ और जो प्रत्येक प्रकार की मुद्रा प्रत्येक देश व प्रत्येक काल में सफलतापूर्वक कर संकती है। ये कार्य निम्नांकित हैं—

- (१) विनमय माध्यम मुद्रा सर्वश्राह्य होती है। इसे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्रकार के भुगतान में स्वीकार कर लेता है। इसिलये विनिमय कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। व्यक्ति अपनी वस्तुओं अथवा सेवाओं को वेचकर उनके बदले में मुद्रा प्राप्त करता है और उस मुद्रा से दूसरे की वस्तु या सेवा मोल ले लेता है। इस प्रकार यह विद्वमय के माध्यम का कार्य करती है।
- (२) मृल्यमापक—प्रत्येक वस्तु के मूल्यांकन करने में भी सुद्रा सहायता करती है, जिस प्रकार दूरी नापने के लिये फीट या गज़ इत्यादि का प्रयोग होता है, वज़न नापने के लिये मन, सेर, छुटाँक का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार वस्तु ऋगें का मूल्य सुद्रा में मापा जाता है। इसकी सहायता से वस्तु ऋगें के पारस्परिक मूल्यों की तुलना भी सरलता से हो जाती है।

मुद्रा के गौंगा कार्य वे कार्य हैं जो मुद्रा को सुमाज के आर्थिक विकास होने के पश्चात् करने पड़ते हैं। इन कार्यों की आरम्भ में समाज को कोई आवश्यकता ही नहीं होती परन्त बाद में यह कार्य भी आवश्यक हो जाते हैं। यह कार्य भी दो हैं—

(१) प्रथम मृल्य संप्रहं—समाज का आर्थिक विकास होने पर समाज के व्यक्तियों को पूँजी की आवश्यकता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है तथा असाधारण अवस्थाओं में असाधारण रूप से धन व्यय करने की सम्भावनाएँ भी बढ़ती जाती हैं। यह तभी हो सकता है जब धन एकत्रित किया जाय। वस्तुओं में धन का एकत्रीकरण

करना कठिन है। वस्तुम्रों को रखने के लिये स्थान मुधिक चाहिये मौसम तथा की देनकोड़ों ने बचाने के लिये देखमाल अधिक चाहिये, फिर भी दूध, दही आदि द्भुत्र वस्तुएँ देशी हैं जो बहुत समय तक एकत्रित नहीं की जा सकती हैं तथा उन सम्मण अमिणत वस्तुओं का एकत्रित करना और भी कठिन है जिनकी आवश्यकता एक व्यक्ति को भविष्य में हो सकती हैं। यह कार्य मुद्रा को ही करना पड़ता है। मनुष्य मुद्रा इक्ट्रा कर लेता है श्रीर इसी एकत्रित मुद्रा से मनवांछित सामान श्रथवा वस्तुएँ प्राप्त कर लेता है । मुद्रा का संग्रह ही धन का संग्रह है । इस प्रकार मुद्रा का मूल्य संचन कार्य भी आजकल एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है।

(२) मुद्रा का दूसरा गौगा कार्य <u>स्थगित देयमान हैं</u>। भविष्य में ऋगाशोघन का कार्य भी मुद्रा द्वारा ही भली प्रकार से हो सकता है; क्योंकि मुद्रा की कीमत अन्य वस्तुर्त्रों की कीमतों की ऋषेज्ञा ऋधिक स्थिर रहती है। इसलिये वर्तमान समय में लिया हुआ ऋण भविष्य में मुद्रा के द्वारा ही सरलता से चुकाया जा सकता है।

त्राघुनिक काल में पूँजीवादी उत्पादन के कारण मुद्रा को कुछ श्रौर भी कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें त्राकिस्मिक कार्य कहते हैं। इन कार्यों का महत्व, आ्राधुनिक अर्थव्यवस्था में हीं है। अप्रति प्राचीन काल में इस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता हीं नहीं होती थी तथा निकट भूतकाल में इस प्रकार के कार्य कम महत्व के थे। पर अन ऐसे कार्यों का महत्व अधिक वढ़ गया है। ये आकस्मिक कार्य निम्नाङ्कित हैं-

श्रीमुद्रा साख का आधार है — आजकल विशेषकर व्यापारियों में हुए ही, चे ह, बिल आहि साखपत्रों का प्रचलन बहुत अधिक हो गया है। व्यापारी इर में विनिन्द के कार्य साखानों की सहादता से ही अधिक होते हैं। पर ये साख-पत्र मुद्रा के त्राधार पर ही चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साख-पत्र को इसी ग्राशा पर स्वीकार करता है कि उसे उसके बदले में सुद्रा मिल ूजायगी। एक क्रानदार अपने प्राहक से नकद रुपया न लेकर उसका चेक इसी आशा पर ले लेता हैं कि उस चेक के बदले में उसे रुपया मिल जायगा। यदि इस प्रकार की कोई आशा न हो तो वह चेक कभी न ले । बूँक भी साख-पत्रों के द्वारा अपना कार्य करते हैं परन्तु उन माल पत्रों के मूल्य में सुदा ही त्राधार है। साख-पत्र तो केवल सुद्रा के क्राइप्त-प्रकृत की असुविधा से बचने के लिये प्रयोग में लाये बाते हैं। मुद्रा प्राप्ति की

(२) सुद्रा वितरस्य का कार्य सन्तोषजनक रूप से करती है। आजकल - उत्पद्भिन बड़ी मात्रा पर होता है। बहुत से व्यक्ति मिलकर एक वस्तु का उत्पादन करते हैं। उस उत्पादन में भूमि, अम, पूँजी, न्यवस्था आदि सबका भाग होता है।

समाज में साख-पत्र सुद्रा का कार्य करती है।

आएए के बिना साखपत्र समाज में चल ही नहीं सकते। इस प्रकार आजकल के

इन सक्का भाग मुद्रा में हो सरलता से दिया जा सकता है। क्योंिक कोई कारखाने वाला विभिन्न रुचि तथा जीवन-स्तर वाले हजारों अभिकों के उपभोग योग्य पदार्थों का संग्रह नहीं कर सकता। यह कार्य मुद्रा के द्वारा ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त सीमान्त उत्पादन का मूल्यांकन मुद्रा के कारण सरलता से हो जाता है और इसी सीमान्त उत्पादन के आधार पर उत्पादन के साधनों को पारिश्रमिक दिया जाता है। इस प्रकार मुद्रा की सहायता से वितरण की समस्या सरलता से इल हो जाती है।

3 सद्रा उपभोक्ता को सम-सीमान्त उपयोगिता प्राप्त करने में सहायक होती है। प्रत्येक उपभोक्ता वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता नद्रा की सहायता से ही आफ कता है तथा इसी की सहायता से सम-सीमान्त उपयोगिता के अनुसार उपभोग के लिये विभिन्न वस्तुओं की मात्रा को निर्घारित करता है। ऐसा वह सफलतापूर्वक सद्रा की सहायता से ही कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता की तुलना उस पर व्यय होने वाली सद्रा से की जाती है तथा इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं की सम-सीमान्त उपयोगिता के आधार पर मात्रा निर्घारित की जाती है। अत सद्रा उपयोक्ताओं को सम-सीमान्त उपयोगिता को सफलतापूर्वक लागू करोंके उन्हें उनकी आय से अधिकतम सन्तोष प्राप्त करने में सहायक होती है।

अ मुद्रा सब प्रकार की सम्पत्ति तथा पूँजी को एक सामान्य रूप देती हैं। आजकल के उत्पादन में विभिन्न प्रकार की पूँजी प्रचुर मात्रा में चाहिये। तरहत्तरह की मशीनें, इमारतें, कचा माल इत्यादि, अनेक वस्तुएँ एक कारखाने वाले को चाहिये। इन सब का संग्रह करना कारखाने वालों के लिये असम्भव ही हैं। मुद्रा इस कार्य को सरलतापूर्वक कर देती है क्योंकि मुद्रा से प्रत्येक प्रकार की पूँजी आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार सद्रा विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति तथा पूँजी का एक सामान्य रूप में प्रतिनिधित्व करती है।

मुद्रा का महत्वें (Importance of Money)

प्रत्येक वस्तु का महत्व उसकी उपयोगिता से स्पष्ट होता है। समाज के लिये
मुद्रा की उपयोगिता, मुद्रा के कार्यों तथा मुद्रा के प्राप्त लामों में प्रकृट होती है। इन
कार्यों तथा लामों को देखते हुए समाज के लिये मुद्रा के महत्व के बारे में कोई सन्देह
नहीं रह जाता। साधारण तौर पर तो समय की प्रगति के साथ अधिकांश वस्तुओं की
उपयोगिता कम होती जाती है परन्तु सद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसकी उपयोगिता बरीवर
बहरही है। अतः यह समाज के लिये उत्तरोत्तर अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है।
एक समय था जब कि मुद्रा को कोई जानता ही नहीं था। घीरे-घीरे इसका प्रचल्ने
प्रारम्भ हुआ पर अब मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण वस्तु हो गई है कि मुद्रारहित सम्य समाज
की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में प्रत्येक कार्य के लिये मुद्रा की

श्रावश्यकता होती हैं तथा मुद्रा की सहायता से हा विविध काय सरलता, से हो सकते हैं। वैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है बड़े मात्रा के उत्पादन बिना मुद्रा के श्रसंभव है श्रीर बिना बड़ी मात्रा के उत्पादन के न तो समाज का जीवन-स्तर ऊँचा हो सकता है न इतनो श्रिधिक श्राधिक समृद्धि हो सकती है। यह सब मुद्रा के कारण होता है। एक प्रचलित प्रामीण कहावत "सबसे बड़ा रुपया" मुद्रा के महत्व का संकेत करती है। यदि वर्तमान समाज को मुद्रामय कहा जाय तो इसमें श्रातिशयोक्ति नहीं होगी।

मुद्रा का इतना नहत्व होते हुए भी यह बात स्पष्ट रूप से समक्त लेनी चाहिये कि मुद्रा क्ष्यं कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है क्योंकि वास्तव में मुद्रा उसकी क्रय-शक्ति के लिए एकत्रित की बाती है न कि स्वयं उसके लिये। एक १००) के नोट का महत्व हमीलिये हैं कि हम उससे किसी भी समय किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। यदि ऐसा न हो तो १००) के नोट की कोई कीमत न रहे और वह बिलकुल महत्वहीन हो बाय। इससे स्पष्ट है कि मुद्रा का महत्व समाज में इसीलिये हैं कि वह प्रत्यच् विनिमय को कठिनाइयों को दूर करती तथा अन्य मौद्रिक कार्य करती है।

विनिमय की किटनाइयों को दूर करती तथा. अन्य मौद्रिक कार्य करती हैं।

मुद्रा के उपयुक्त कार्य ही मुद्रा से होने वाले लाभों को स्पष्ट करते हैं। मुद्रा का सबसे प्रथम तथा मुख्य लाभ यही है कि इससे प्रत्यक्त वस्तु. विनिमय की सम्पूर्ण किटनाइयाँ दूर हो जाती हैं। मुद्रा का प्रचलन होने के कारण किसी भी व्यक्ति की अपनी इव्छित वस्तु प्राप्त करने के लिये ऐसे व्यक्ति को तलाश करने में अपने समय तथा शक्ति को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं कि जिसके पास उसकी इव्छित वस्तु हो और जो बदले में उसकी वस्तु लेना चाहे। वह अपनी वस्तु को बेचकर दूसरी वस्तु स्तरीद सकता है। इसी प्रकार अब वस्तुओं के अदल-बदल के लिए विनिमय दर निर्घारण करने में किसी प्रकार के बाद-विवाद की आवश्यकता नहीं और न एक वस्तु की विभिन्न वस्तुओं से विनिमय दर की लम्बी तालिका रखने की आवश्यकता है। सब वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में निर्घारित होता है और इसकी सहायता से उनके पारस्पिक नूल्य का अनुपात भी निकाला जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्यन्त वस्तु-विनिमय की तीसरी किठनाई को भी मुद्रा समात कर देती है। अब किसी वस्तु को व्यर्थ में विभावित करने की आवश्यकता नहीं। उसको बेचकर अन्य वांछित वस्तुयें खरीदी जा सकती हैं।

इन कठिनाइयों को दूर करने के ऋतिरिक्त मुद्रा ऋपने कर्चन्यों द्वारा समाज के ऋार्यिक विकास में पर्याप्त रूप से सहायक हुई है। विनिमय का माध्यम तथा सर्व-सिन्य मृत्यमातक होने के नाते विनिमय के कार्य बड़ी ऋासानी से हो जाते हैं। इसी कार्या से ऋाजकल बाजार तथा न्यापार का चेत्र बहुत ऋषिक बढ़ गया है। यद्यपि इस चेत्र के बढ़ने में यातायात का माग मुख्य रूप से रहा है फिर भी मुद्रा का योग भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार सुद्रा की सहायता से बड़ी मात्रा का उत्पादन सफल हुआ है। मुद्रा की सहायता से वस्तुओं को श्रासानी से प्राप्त कर तोने के कारण विभिन्न प्रकार के व्यक्ति दूर-दूर से आकर एक स्थान पर कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार त्रार्थिक चेत्र में मुद्रा ने वड़ी मात्रा के उत्पादन को प्रोत्साइन दिया, विनिमय की कठिनाइयों को दूर करके विनिमय की मात्रा में वृद्धि की तथा इसके चेत्र को अधिक व्यापक बना कर समाज को अधिक वस्तुएँ उपभोग के लिये दी जिससे व्यक्तियों का जीवन-स्तर उच हुन्ना न्नौर वे ऋपनी न्नाय से ऋधिकतम सन्तोष प्राप्त करने में सफल हुए | वितरण की समस्या हल करने में भी मुद्रा ने काफी योग दिया | - ऋाधुनिक \ कल्याणकारी राज्य के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कार्यों को सफल बनाने में नुद्रा पर्यात ! सहायता करती है। यदि मुद्रा न हो तो सरकार द्वारा इतने सारे कार्य विभिन्न वस्तुन्त्रों के एकत्रीकरण तथा पारिश्रमिक वितरण की कठिनाई के कारण कभी पूरे न हो सकें। सामाजिक दृष्टि से भी मुद्रा का लाभ सराहनीय रहा है। बहुत से व्यापारियों के श्रार्थिक बन्धन को छुड़ाकर उन्हें श्रार्थिक स्वतन्त्रता तथा सामाजिक समानता प्राप्त करने में मुद्रा यथेष्ट रूप से सहायक हुई है। उदाहरण के लिये भारतीय ग्रामों में त्राज से २५ वर्ष पहले सामाजिक परम्परात्रों का वोलवाला था। एक गाँव के मिस्री को वर्ष पर्यन्त कृषकों का कार्य करने के पश्चात् उसे फ़्सल पर एक निश्चित मात्रा में अनाज मिल जाया करता था। वह कोई दूसरा कार्य कर नहीं सकता था। उसे अपने जीवन-यापन के लिये कुपकों पर ही निर्भर रहना पड़ता था तथा समाज में उसका कोई विशेष श्रादर नहीं था। यद्यपि गावों में कुछ सीमा तक यही प्रथा श्रव भी प्रचलित है परन्तु वहीं मिस्त्री यदि एक शहर में श्राकर बस जाय तो उसे कार्य के बदले में रुपये मिलने लगेंगे तथा वह जितना काम करेगा उसके अनुपात में उसकी आय होगी। उसे किसी विशेष वर्ग का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा तथा शहर में उसका सामाजिक स्तर भी निम्न नहीं रहेगा क्योंकि उसे मुद्रा के कारण उन रुढ़ियों से छुटकारा मिल गया जो ग्रामीण चेत्र में मुद्रा के स्त्रभाव में उसे दवाये रखती थी। इस प्रकार मुद्रा ने मानव को सामाजिक लाभ भी पहुँचाया है।

ुमुद्रा के दोष

कोई भी वस्तु केवल लाभमय या केवल दोषमय नहीं होती। प्रत्येक वस्तु में लाभ व दोष दोनों हैं। मुद्रा के लिये भी यही बात सत्य है। उपरोक्त लामों के होते हुए भी मुद्रा में कुछ दोष हैं। इसका मुख्य दोष इसके मूल्य का उतार-चढ़ाव-है। इसके मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं जिससे समाज के कुछ वर्गों को हानि होती रहती है। बाजार में कभी तेज़ी कभी मन्दी का कारण अधिकांश रूप में मुद्रा की नमात्रा होती है। कीमतों के स्थिरीकरण न होने से कुछ वर्गों को हानि हो जाती है।

मुद्रा के कारण कुछ लोग त्रावश्यकता से ऋधिक धन संग्रह करने में सफल होते हैं श्रौर वे अन्य व्यक्तियों का शोपण करने लगते हैं। इस प्रकार सुद्रा असमान धन वितरण तथा शोषण का कारण बन जाती है, फिर भी मुद्रा अवांछनीन नहीं कही जा सकती। वास्तव में मुद्रा के यह दोष उसमें स्वाभाविक नहीं हैं। ये दोष तो मुद्रा पूर्ति करने वाली संस्था की अनुभवहीनता तथा अनुपयुक्त संचालन तथा नियंत्रण नीति के कारण मुद्रा में त्रा जाते हैं। इन दोषों के लिये समाज की त्रार्थिक व्यवस्था ही मुख्य उत्तरदायो है न कि मुद्रा स्वयं ।

प्रश्न

9. मुद्रा को त्रालोचनात्मक परिभाषा दोजिये तथा उसकी प्रकृति समसाइये।

(श्रागरा बी० कॉम०, भाग १, १६५६)

- 2. "Money is what money does". Explain fully the meaning of this statement. What will happen if money suddenly disappears from the country?

 (Agra, B. Com. 1, 1956)
- 3. Discuss the importance of money in a civilized society and explain the different forms in which it circulates in a country. (Agra, B. Com. 1, 1957)

अध्याय २

मुद्रा का वगी करण, ढलाई एवं श्रद्धी मुद्रा

मुद्रा का वर्गीकरण

मुद्रा का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से हो सकता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से मुद्रा दो प्रकार की होती है। प्रथम, धातु-मुद्रा, द्वितीय, पत्र मुद्रा। धातु-मुद्रा धातु की बनी होती है। विशेषकर इस प्रकार की मुद्रा के अन्तर्गत सोना और चाँदी के सिक्के का चलन होता है। पत्र-मुद्रा काग़जी मुद्रा होती है। किसी विशेष व्यक्ति, संस्था अथवा कोष द्वारा यह मुद्रा निकालों जाती है। सरकार स्वयं काग़जी मुद्रा छाप सकती है। काग़जी मुद्रा की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम बना दिये जाते हैं। मूल्य के आधार पर धातु मुद्रा प्रायः दो प्रकार की होती है। प्रधान मुद्रा तथा गौण मुद्रा। प्रधान मुद्रा उस धातु से निर्मित की जाती है जो किसी भी देश में वहाँ के विधानानुसार विनिमय माध्यम तथा मूल्यमापक के रूप में निश्चित की जाती है। यह सोना अथवा चाँदी दोनों की हो सकती है। ये सिक्के निश्चित आकार, परिमाण, वजन, मूल्य तथा शुद्धता वाले बनाये जाते हैं। इन सब बातों का निर्देश प्रत्येक देश के टकन विधान द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के मुद्रा के प्रधान लज्ज्ञण तीन होते हैं—

- (१) स्वतंत्र, प्रथक मुक्ति टकंन—प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार धातु के बदले में टकशाला से मुद्रा प्राप्त कर सकता है। समान वजन तथा समान मूल्य की घातु देकर सिक्कों के परिवर्तन की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को होती है। इसमें सरकार की ओर से किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता। यह बात अवश्य है कि सरकार घातु को मुद्रा में परिवर्तन के कार्य के लिये कुछ शुल्क ले और यदि वह चाहे तो न भी ले। इस दृष्टि से सिक्का परिवर्तन करने का टकन शुल्क तीन प्रकार का हो सकता है—
- (अ) निश्शुल्क टंकन इस प्रणाली के अन्तर्गत जनता से किसीं भं प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। टकसाल के अधिकारी बिना कुछ लिये हुए ही घातु के बदले में सिका दे देते हैं। सिकों की पूर्ति पर जो कुछ व्यय होता है वै सरकार अन्य करों के द्वारा जनता से वस्त्ल कर लेती है।
 - (व) टंकन शुक्क-इसके अन्तर्गत टकसाली अधिकारी जनता से उतन

शुल्क लेते हैं जितना सिकों के बनाने में व्यय होता है। इस प्रकार इस प्रथा के अन्तर्गत टकसाली शुल्क तथा टकसाली व्यय में समानता होती है।

(स) अतिरिक्त टंकन शुल्क—इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार शुल्क के रूप में वास्तविक व्यय से अधिक धन-राशि प्राप्त करती है अर्थात् इसके अन्तर्गत बनता से टक्साली शुल्क टक्साली व्यय से अधिक लिया जाता है। यह शुल्क दो प्रकार से वंसूल किया जाता है। एक तो उतनी कीमत की धातु सिक्के में से निकाल-कर कम कीमत वाली धातु की मिलावट करके। दूसरे धातु को सिक्के में परिवर्तन करते समय में ही सम्बधित व्यक्ति से सिक्कों के रूप में निर्धारित शुल्क लेकर।

जब सिक्के ढालने का एकाधिकार केवल सरकार तक ही सीमित रहता है जनता का कोई भी व्यक्ति टकसाल में घातु देकर सिक्के प्राप्त नहीं कर सकता। जब सिक्के बनाने तथा निकालने का पूर्ण अधिकार केवल सरकार को ही होता है तब इस प्रशाली को प्रतिबन्धित टंकन प्रशाली कहते हैं।

- (२) आंतरिक तथा बाह्य मूल्य में समानता—प्रधान सिक्के के ऊपर बो मूल्य श्रंकित होता है उसे बाह्य मूल्य कहते हैं श्रौर सिक्के की धातु को बेचकर बो मूल्य प्राप्त हो सके उसे श्रान्तरिक मूल्य कहते हैं। प्रधान सिक्के के इन दोनों मूल्य में समानता होनी चाहिये। उदाहरण के लिये भारतीय रुपये के ऊपर १०० नये पैसे श्रंकित होते हैं श्रर्थात् इसका बाह्य मूल्य १०० नये पैसे हैं। यदि इसकी चाँदी को बेचकर १०० नये पैसे प्राप्त हो जाय तो रुपये के बाह्य तथा श्रान्तरिक मूल्य में समानता हो गई। सिद्धान्त रूप से प्रत्येक देश के प्रधान सिक्के में यह गुण होना चाहिये। उसके बाह्य तथा श्रान्तरिक मूल्य में समानता हो नी चाहिथे। रुपया भारत का प्रधान सिक्का हैं। परतु इसका बाह्य मूल्य श्रान्तरिक मूल्य से श्रिधिक है श्रौर इस हिन्द से भारतीय रुपया प्रधान सिक्के की श्रेणी में नहीं श्राता।
- (३) असीमित विधि प्राह्मता—मुद्रा का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के लेन-देन का मुगतान करना होता है। यह तभी सम्भव है जब मुद्रा प्रत्येक प्रकार के लेन-देन में असीमित संख्या में स्वीकार की जा सके। इसीलिये कानून द्वारा प्रधान मुद्रा को यह विशेषता प्रदान कर दी जाती है जिसके अनुसार देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह मुद्रा असीमित संख्या में कानूनन स्वीकार करना पड़ता है। उदाहरण के लिये भारतीय रुपया असीमित विधि प्राह्म है। अतः यदि कोई ऋगी अपने धनी को २०००) रुपये का ऋण २०००) रुपये के सिक्कों में चुकावे तो धनी को २०००) के सिक्के लेने पड़ेंगे। वह यह नहीं कह सकता कि इनका तो बोक्त आधिक हो जायगा मुक्ते तो सौ-सौ रुपये के रूट नोट दे दीजिये। इसी प्रकार यह कितनी ही बड़ी रक्तम क्यों न हो यदि इसका भुग-तान रुपयों में किया जाय तो लेने वाला किसी भी दशा में इन्कार नहीं कर सकता।

गौण मुद्रा—गौण मुद्रा को संकितिक तथा प्रतीक मुद्रा भी कहते हैं। यह मुद्रा छोटे-छोटे भुगतानों के काम में लाई जाती है। इस प्रकार यह मुद्रा प्रधान-मुद्रा के सहायक का काम करती है तथा यह कम कीमती धात की बनाई जाती है। इस प्रकार की मुद्रा को केवल सरकार ही दाल सकती है। इसका बाह्य मूल्य स्नान्तरिक मूल्य से अधिक होता है। यह सिक्के लेन-देन में एक निश्चित संख्या तक ही काम में लाये जाते हैं। उदाहरण के लिये भारत में १, २, ५, १० नये पैसों के सिक्के इसी प्रकार के सिक्कों हैं। ये १० रुपये तक ही लिये जा सकते हैं। १० रुपये से अधिक लेन-देन को इन सिक्कों में भुगतान लेने से धनी इन्कार कर सकता है। उदाहरण के लिये यदि किसी को १५० रुपये देने हैं और वह १५० रुपये १० नये पैसे के सिक्कों में देना चाहे तो धनी यह कह सकता है कि मुक्ते इन नये पैसों के सिक्कों के बदले में १५ रुपये ही दीजिये और कानूनन स्नृणी को यही करना पड़ेगा। १०० रुपये तक का मुगतान इन सिक्कों में हो सकता है क्योंकि सरकार द्वारा यह सिक्के १०० रुपये तक ही विधि-प्राह्य घोषित किये गये हैं। इस प्रकार गौण मुद्रा के निम्न तीन लच्चण होते हैं—

- (१) प्रतिबन्धित टंकन—इसके अन्तर्गत जनता को धातु के बदले में मुद्रा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता।
- (२) बाह्य मूल्य की आन्तरिक मूल्य से अधिकता—मुद्रा पर श्रंकित मूल्य उसकी धातु के बाजारी मूल्य से अधिक होता है।
- (३) सीमित विधि प्राह्मता—विभिन्न प्रकार के भुगतानों में यह एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार की जा सकती है।

पत्र-मुद्रा — त्राधुनिक युग में पत्र-मुद्रा का बोलबाला है। त्राठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में सब देशों में धातु मुद्रा का साम्राज्य था। प्रत्येक देश की प्रधान मुद्रा सोने. त्रथवा चाँदी ही की हुत्रा करती थी। त्रौद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् त्रौद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति के कारण त्राधिकाधिक विनिमय क्रियात्रों के लिये मुद्रा की माँग बढ़ती गई। इसके लिये सोने-चाँदी की पूर्ति पर्यात मात्रा में नहीं थी। इसके साथ ही साथ मौद्रिक समितियों तथा बैंकों के कार्यों का विकास होता गया। धातु मुद्रा के कतियय दोषों को दूर करने के लिये पत्र-मुद्रा का चलन प्रारम्भ हुत्रा। यह चलन प्रथम युद्ध के पश्चात् ही तीत्र गति से बढ़ने लगा क्रौर इस समय तो प्रायः पत्र-मुद्रा ही सब देशों में चलती है।

धात गुड़ा के चलन में सबसे बड़ा दोष तो यह था कि इसके लिये बहुत बुड़ी मात्रा में सोने अथवा चाँदी की आवश्यकता पड़ती थी। इसके टलाने में भी कुब बहुत होता था। इसके घिसावट के कारण बहुमूल्य धातुओं में पर्याप्त हार्नि ही जाती थी। अधिक मात्रा में इधर-से-उधर ले जाने में भी इसमें कुछ,न-कुछ, असु-

विधा होती ही है। सुरकार संकटकालीन अवस्था में पूर्ति वांछित मात्रा में नहीं बढ़ा सकती। इन दोगों के कारण धात मुद्रा की लोकप्रियता कम हो गई, और अब पत्र-सुद्रा ही अधिक लोकप्रिय है।

पत्र-मुद्रा तीन प्रकार की हो सकती है-

- (१) प्रतिनिधि पत्र-सुद्रां—इस प्रकार की पत्र-सुद्रा बहुमूल्य धातु का प्रतिनिधित्व करती है। जितने मूल्य की पत्र-सुद्रा छापी जाती है उतने ही मूल्य का सोना व चाँदी किसी ग्रिधिकोष के निधि में अथवा देश के खजाने में रख ली जाती है। वास्तव में इस प्रकार की पत्र-सुद्रा चलाने का उद्देश्य यह होता है कि सुद्रा दालने का व्यय कम हो जाय और देश बहुमूल्य धातु की धिसावट की हानि से बच जाय।
- (२) परिवर्त नीय पत्र-मुद्रा—यह पत्र-मुद्रा किसी भी समय में धातु के प्रधान तिकों में बदली जा सकती है। पत्र-मुद्रा निर्गमनक संस्था यह आश्वासन देती है कि उस पत्र-मुद्रा के बदले में किसी भी समय माँगने पर प्रधान धातु की मुद्रा दे दी जायगी। इसी विश्वास पर जनता इसे स्वीकार करती है। इस पत्र-मुद्रा के चलाने में एक यही लाभ होता है कि इसके वास्तविक मूल्य के बराबर सोने-चाँदी के रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिये सोना-चाँदी कम मूल्य में रक्खा जाता है और शेष मूल्य किसी प्रकार के स्वीकृत विनियोगों में जमा रहता है। अतः इस प्रकार की पत्र-मुद्रा के चलाने के लिये उतने मूल्य की सोने-चाँदी की आवश्यकता नहीं पहती जितनी पत्र-मुद्रा के चलाने के लिये पहती है।
- (३) अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा—जैसा नाम से स्पष्ट है इस प्रकार की पत्र-मुद्रा के बदले में किसी प्रकार के सिक्के अथवा धातु देने के लिये सरकार किसी प्रकार से वाध्य नहीं होती। इस पत्र-मुद्रा का चलन का आधार सरकार की साख में विश्वास होता है। जनता सरकार की साख में विश्वास करती है और इसी आधार पर उसे स्वीकार करती है। सरकार इस प्रकार की मुद्रा तभी निकालती है जब सरकार को इतनी अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़े कि उसके लिये निधि में जमा करने को उचित मात्रा में सोना-चाँदी प्राप्त न हो सके।

मुद्रण अथवा ढलाई (Coinage)

सिक्कों के उपयोग के साथ-ही-साथ सिक्कों की ढलाई की समस्या भी उत्पन्न
- हुई | लोडिया तथा मिश्र में पहिले-पहल सिक्कों की ढलाई का काम चालू किया
नया | सिक्कों की ढलाई की कला ही मुद्रा का टंकरण अथवा मुद्रश कहलाती है |
- सिक्कों में आधुनिक सुधार कई चरशों (Steps) में किए गए प्रयतों का परिशाम
है | मुद्रश (Coinage) निम्नांकित उद्देश्यों से किया जाता है :—

सिक्कों में से घातु को काट कर अथवा गला कर निकालने की अवृत्ति को रोकना; सब सिक्के समान तौल, समान आकार और समान शुद्धता के हों, इनके चलन में कम-से-कम घोलेबाजी एवं जालसाजी हो; कम-से-कम बिसाई हो और इन पर इनके निकालने वाली सरकार के कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारक हों। इन तमाम उद्देश्यों की पूर्ति तभी हो सकती है अब कि मुद्रा-दलाई जनता के द्वारा न हो। अतः प्रायः सभी देशों में मुद्रा की दलाई का काम वहाँ की सरकारों को सौपा जाता है।

दो प्रकार की प्रमुख मुद्रण प्रणालियाँ पाई जाती हैं-

- (१) स्वतंत्र मुद्रण (Free Coinage)—इसे असीमित मुद्रण भी कहते हैं। इस प्रणाली में जनता को यह अधिकार रहता है कि वह घातुओं को सरकारी टकसाल पर ले जाकर सिक्कों में ढलवा ले। सरकार ढलाई के प्रतिफल में शुल्क लेती भी है और नहीं भी। जब शुल्क लेकर ढलाई की जाती है तो इसे सशुल्क ढलाई (Brassage) कहते हैं। इस शुल्क में ढलाई का वास्तविक मृ्ल्य ही सम्मिलित होता है, लाम नहीं। जब सरकार ढलाई विना किसी शुल्क के करती है तो इसे निःशुल्क मुद्रा ढलाई (Gratuitous Coinage) कहते हैं। कभी-कभी सरकार सिक्कों की ढलाई के लिए मुद्रण व्यय से अधिकं दाम जनता से वस्त करती है। इस अधिकता को मुद्रण लाभ कहते हैं और इस प्रकार के मुद्रण को सलाम मुद्रण (Seigniorage) कहते हैं। प्राचीन काल में स्वतंत्र मुद्रा ढलाई कई देशों में—जापान, भारत, इंगलेंड, यू. एस. ए., फ्रांस आदि में प्रचलित थी। भारत में १८६३ ई० तक स्वतंत्र मुद्रण प्रणाली प्रचलित थी। हरशेल समिति के सिकारिश के अनुसार चाँदी का स्वतंत्र मुद्रण रोक दिया गया।
- (२) सीमित मुद्रण (Limited Coinage)—इस प्रणाली के श्रंतर्गत सिक्के सरकारी आजा पर ही तैयार किये जाते हैं। सरकार को मुद्रा पूर्ति का एका-धिकार रहता है। सरकार स्वयं धातु खरीद कर मुद्रा की ढलाई कराती है। जनता को स्वतंत्र मुद्रा ढलाई की मुविधा नहीं होती।

मुद्रा-वस्तु की विशेषताएँ (Qualities of a good money material)

ऊपर लिखा जा चुका है कि किसी भी वस्तु की मुद्रा बनाई जा सकती है। जिस वस्तु को समाज के लोग मुद्रा मान लें वही मुद्रा का कार्य कर सकती है। समय-समय पर मुद्रा-वस्तु में परिवर्तन भी होता रहा। जब समाज को किसी विशेष मुद्रा-वस्तु से असुविधा प्रतीत हुई तो दूसरी मुद्रा-वस्तु चुन ली गई, क्योंकि किसी भी वस्तु में मुद्रा बनने के लिए कुछ ऐसे गुणों की आवश्यकता है कि जिससे वह मुद्रा के कर्त्तव्यों का सफल पालन कर सके। उदाहरण के लिए मुद्रा का एक कार्य मूल्य

संचय है, इसिलये यह त्रावश्यक है कि जिस वस्तु की मुद्रा बनाई जाय वह टिकाऊ हो, ऋषिक दिनों तक रह सके। यदि वह शीघ्र नष्ट होने वाली हो तो उसके द्वारा मूल्य ऋथवा घन का संचय नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऋन्य कार्यों के करने के लिये मुद्रा-वस्तु में कुछ और भी गुण होने चाहिये। ऋतः मुद्रा के विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिये मुद्रा-वस्तु में निम्नांकित गुणों का होना ऋावश्यक है—

- (१) सर्वप्राह्मता—मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिये जिसे समाज के सक व्यक्ति स्वीकार कर लें। इसके लिये मुद्रा-वस्तु में उपयोगिता का गुण होना त्रावश्यक है। वैसे कानून के द्वारा प्रत्येक मुद्रा सर्व-प्राह्म बना दी जाती है, फिर भी यदि वह वस्तु स्वयं उपयोगी है, मुद्रा के अतिरिक्त वह और भी किसी प्रकार के काम में लाई जा सकती है तो इम प्रकार से बनी हुई मुद्रा में सवप्राह्मता का गुण स्वाभाविक हो जाता है और इस प्रकार की मुद्रा संकटकालीन त्रवस्था में भी सरलता से अपना कार्य करंती रहती है। इसके अतिरिक्त उपयोगी वस्तु की मुद्रा का प्रयोग दूसरे देश में भी किया जा सकता है। सोने का सिक्का अपने देश में तो चलेगा ही पर वह विदेशों में भी यदि सिक्के के रूप में नहीं तो घातु के रूप में त्रापना मूल्य रक्लेगा। कागज़ी-मुद्रा में यह जात नहीं है। अतः मुद्रा को अधिकाधिक च्लेत्र में सर्वप्राह्म बनाने के लिये मुद्रा वस्तु में यह गुण होना त्रावश्यक है। अर्थात् मुद्रा-वस्तु में मौद्रिक मूल्य के साथ ही साथ उसका वास्तविक अथवा आन्तरिक मूल्य भी होना चाहिये।
- (२) दिकाऊपन, दीर्घायुतिका, दीर्घकालीनता— मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिये जो शीम नष्ट होने वाली न हो। जो श्रिधक दिन तक दिक सके। यदि वह बहुत दिनों तक रक्ली जाय तो कीड़े, मकोड़ों तथा मौसम श्रादि के द्वारा नष्ट न की जा सके। उदाहरख के लिये यदि मुद्रा के लिये किसी लकड़ी को चुना जाय तो वह बहुत दिनों तक संग्रह नहीं की जा सकती जबिक सोने-चाँदी के सिक्के बहुत दिनों तक संग्रह किये जा सकते हैं। मुद्रा को घन-संग्रह का कार्य करने के लिये मुद्रा-वस्तु में यह गुख होना श्रावश्यक है।
- (4) वहनशीलवा मुद्रा-वस्तु हल्की होनी चाहिये, उसके एक टुकड़े का मूल्य तो ऋषिक पर वजन बहुत कम होना चाहिये जिससे मद्रा को एक स्थान से दूमरे स्थान में ले जाने में व्यक्तियों को किसी प्रकार की श्रमुविधा न हो तथा उसके स्थानान्तर में व्यय भी श्रधिक न हो। यह गुण सोने-चाँदी के सिक्कों में लोहे श्रादि के िक्कों से श्रधिक मात्रा में पाया जाता है। एक तोले सोने या चाँदी का मूल्य एक तोले लोहे के मूल्य से कहीं श्रधिक है। इसीलिए सोने-चाँदी के सिक्को ही बनी बाते हैं लोहे के नहीं।
- (४) समरूपता—जिस वस्तु की मुद्रा बनाई जाय वह वस्तु ऐसी होनी चाहिये जिसके किसी एक टकडे अथवा एक पिंड के गुए अथवा मूल्य में भिन्नता

न हो । यदि उससे श्रौर भी छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये जायँ तो समान-श्राकार वाले सब टुकड़ों के मूल्य बराबर ही रहें। यदि ऐसा न हो तो इस प्रकार की वस्तु से बने हुए सिक्कों के मूल्यों में विभिन्नता श्रा जायगी। उदाहरण के लिये यदि दो फीट शीशम की लकड़ी ली जाय तो हो सकता है कि इस लकड़ी का कोई भाग कचा हो तथा कोई भाग पका हो। पक्के भाग का मूल्य श्रिष्ठिक होता है कच्चे का कम। यदि इस लकड़ी के सिक्के बनाये जायँ तो कच्चे तथा पक्के भाग के िक्कों की सर्वन्राख्यता में श्रन्तर पड़ जायगा। कच्चे भाग के सिक्के शीश खराब हो सकते हैं, इसी-लिये इन्हें लोग किठनाई से लेंगे। इसके विपरीत सोने की दो फीट छुंड़ में इस प्रकार की किठनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस छुड़ में से तो कहीं भी टुकड़े काटे जायँ समान टुकड़ों का समान मूल्य रहेगा। यह गुण्ए सोने तथा चाँदी के टुकड़ों में पाया जाता है, इसीलिये उन्हों दो घातुश्रों को सिक्कों के लिये लोगों ने श्रिष्ठक उपयुक्त समभा है।

- √(१) सुगेयता मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिये जिसके पहचानने में कि वह असली है या नक़ली किसी प्रकार की किठनाइ न पड़नी चाहिये क्योंकि यदि यह पहचान ठीक प्रकार से न हो सके तो समाज में नक़ली सिक्कों का प्रचलन बहुत बढ़ सकता है। असली वं नक़ली सोना चाँदी भी आसानी से पहचाना जा सकता है और इसीलिये ये धातुएँ सिक्कों के लिये अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं।
- ्रह्) सुविभाजिता मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिये कि जिसके टुकड़े करने से मूल्य का हास बिलकुल न हो। जितना मूल्य किसी एक मात्रा के टुकड़े का हो यदि उसके और भी छोटे-छोट टुकड़े कर लिये जाय तो उन सकका मूल्य मिला कर पहले वाले टुकड़े के बराबर होना चाहिये। अथवा बहुत से टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ा टुकड़ा बना लिया जाय तो भी उसका मूल्य उतना ही रहना चाहिये। यदि मुद्रा-वस्तु में यह गुगा न हो तो ऐसी वस्तु की मुद्रा बनाने में हानि उठानी पड़ेगी। १० तोले सोने की एक छड़ का जितना मूल्य है ठीक उतना मूल्य उसको १०० टुकड़ों में भी बेचकर प्राप्त किया जा सकता है और यदि इन टुकड़ों को पिघला कर फिर एक कर दिया जाय तो भी उतना मूल्य मिल जायगा अर्थात् मोने के टुकड़े को और भी छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेने से उसके मूल्य में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ता। यह बात लकड़ी के टुकड़े में नहीं है। इसी गुगा के कारण सोना-चाँदी एक अच्छी मुद्रा-वस्तु मानी गई है।
- ्ष न्त्रलमान्विता वस्तु ऐसी होनी चाहिये जिस पर किसी प्रकार का ठप्पा या चिह्न भली प्रकार ऋंकत हो सके तथा उसके मूल्य में परिवर्तन न हो। उदाहम्स्क के लिए यदि कोई घातु मुद्रा वस्तु चुनी जाय तो उसमें इस प्रकार से पित्रलने की एकि होनी चाहिये कि उसमें विशेष श्राकृति के दुकड़े बनाये जा सकें, उस पर विशेष

प्रकार की मोहर छापी जा सके, किनारे ढाले जा सकें। एक दुकड़े को पिघलाकर छोटे-छोटे दुकड़े किये जा सकें तथा छोटे दुकड़ों को पिघलाकर बड़ा दुकड़ा किया जा सके। यदि मुद्रा-वस्तु के लिये कोई कागज़ चुना गया हो तो वह कागज तथा छापने की स्याही इत्यादि इस प्रकार की हो कि उस पर आसानी से छापा जा सके तथा जो छपे वह विगड़ न सके और न उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सके। सिक्तों के ऊगर की आंकित सामिग्री वैसी ही बनी रहनी चाहिये।

- (二) मृत्य-स्थिरता मुद्रा वस्तु का मृत्य स्थिर रहना चाहिये। उस वस्तु के मृत्य में समय-समय पर अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिये। वस्तु के बाजार मृत्य में बार-बार परिवर्तन होने से मुद्रा के चलन में किठनाई हो सकती है। सिक्के का मृत्य धातु के रूप में अधिक हो सकता है। ऐसी दशा में लोग सिक्कों को पिचला-कर धातु के रूप में वेचने लगेंगे तथा सरकार सिक्कों की पूर्ति करने में असफल हो बायगी। इसके साथ ही साथ ऋग्णें के भुगतानों में भी किठनाई होगी। लेन-देन का कार्य तभी सफलतापूर्वक हो सकता है जब मुद्रा-वस्तु का मृत्य प्रायः स्थिर रहे।
- (६) मीमितता मुद्रा-वम्तु की पूर्ति सीमित होनी चाहिये। वह वस्तु लोगों को श्रासानी से न मिल बानी चाहिये। जिस वस्तु की पूर्ति सीमित नहीं होती श्रिधिक मात्रा में हर समय हर स्थान पर मिल बाती है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता श्रियवा बहुत कम मूत्र्य होता है। इस प्रकार की वस्तु की मुद्रा सफल नहीं हो सकती। जिस वस्तु की मुद्रा बनाई बाय उस वस्तु की पूर्ति बहुत ही कम श्रियांत् सीमित होनी चाहिये। सोने-चाँदी में यह बात पाई बाती है। इन घातुश्रों की पूर्ति बहुत ही कम होती है, इसीलिये इनको मुद्रा के लिये श्रादर्श घातु माना बाता है।

उपरोक्त गुण मुद्रा के त्राधुनिक कार्यों के लिये त्रांत त्रांवश्यक हैं। मुद्रा विनिमय माध्यम का कार्य सफलतापूर्वक तभी कर सकती है जब मुद्रा वस्तु में सर्व- प्राह्मता, वहनशीलता तथा सुगमनीयता के गुण हों। मूल्य मापक होने के लिये मुद्रा-वस्तु का समरूप तथा सुगेय होना त्रांवश्यक हैं। मूल्य संचय का कार्य करने के लिये मुद्रा-वस्तु के मूल्य में स्थिरता होनी चाहिये तथा वह त्राधिक दिनों तक टिक्नेवाली होनी चाहिये। इसी प्रकार मुद्रा के द्वारा स्थिगत देयमान का कार्य भली भाँ ति तभी हो सकता है बबिक मुद्रा-वस्तु के मूल्य में स्थिरता हो। इस प्रकार मुद्रा के कर्चव्यों तथा मुद्रा-वस्तु के गुणों में घनिष्ठ संबन्ध हो। उपरोक्त गुणों के न होने में मुद्रा त्राप्य सारे कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकती। सोने-चाँदी में प्राय: ये सब गुण, गये बाते हैं। त्रौर इसीलिये इन दोनों घातुत्रों को मुद्रा के लिये त्रादर्श माना गृंश है।

श्राधुनिक काल में घातु मुद्रा का चलन बहुत कम हो गया है। अब अधिक-तर कागबी मुद्रा का ही प्रयोग हो रहा है। अतः मुद्रा-वस्तु सोने-चाँदी के स्थान में कागज ही है। कागज में वे सब गुण नहीं पाये जाते जो गुण एक मुद्रा-वस्तु में होने चाहिये ब्रौर सम्भव है कि मुद्रा सम्बन्धी ब्रार्थिक संकट वर्तमान समय में कागज़ी मुद्रा ब्रपनाने से ही उत्पन्न हो गया है।

मौद्रिक नीतियाँ

प्रत्येक मौद्रिक नीति का अन्तिम उद्देश्य मुद्रा के आन्तिरिक व बाह्य मूल्यों में स्थिरता लाना होता है, क्योंकि तभी पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता आती है। मूल्यों की स्थिरता देश के औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नित के लिये आवश्यक है। इस-लिये देश की सरकार अथवा केन्द्रोय बैंक को समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार ऐसी सुद्रा नीति अपनानी पड़ती है जिससे मूल्यों की स्थिरता बनी रहे।

प्रायः मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन मुद्रा प्रसार ऋथवा मुद्रा संकुचन से ऋधिक होते हैं। इसिलये यदि मुद्रा प्रसार ऋथवा मुद्रा संकुचन नियंत्रित किया वा सके ऋथवा इन ऋवस्थाओं को दूर किया जा सके तो मूल्यों में स्थिरता ऋगने की सम्भानवना हो जाती है। मुद्रा प्रसार को रोकने के लिये दो प्रकार के उपायों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के उपायों के द्वारा मुद्रा प्रचलन की मात्रा में कमी की जाती है तथा द्वितीय श्रेणी के प्रयत्नों में उत्पत्ति में वृद्धि की जाती है। मुद्रा चलन की मात्रा को कम करने के लिये प्रायः निम्नांकित उपायों का प्रयोग किया जाता है—

- (१) नवीन पत्र-मुद्रा का निर्गमन बंद कर दिया जाय।
- (२) प्रचलित मुद्रा को समाप्त कर दिया जाय श्रौर उसके स्थान पर कम मात्रा में नवीन मुद्रा चालू की जाय।
- (३) वेतनों, मजदूरियों तथा बैंकों में जमा की हुई धन-राशि स्त्रिनिवार्य रूप से कम कर दी जाय। वेतन तथा मज़दूरी कम करने से जनता के पास कम सुद्रा पहुँचती है। बैंकों में जमा की हुई रकम कम करने से बैंकों द्वारा उधार दी जाने वाली रकम कम हो जाती है।

प्रश्न

- 9. नियंत्रित चलन (Managed Currency) से त्रापका क्या तात्पर्य है ? इसके लाभ तथा हानियों की विवेचना करो। (त्रागरा, बी० ए० १६५६)
- 2. "Metallic money has lost its importance in modern economic life." Explain and amplify this statement.

 (Agra B. Com. Pt. I, 1957)

श्रध्याय ३

मुद्रा-मान (Monetary Standards)

मुद्रा-मान एक अधिक विस्तृत शब्द है। मुद्रा संबंधी सभी प्रकार के नियम, सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ, आदि इस चेत्र में आती हैं। इस में प्रामाणिक सिक्के, सांकेतिक सिक्के, कागजी-नोट, साख-मुद्रा का विकास, बहुमूल्य धातुओं का क्रय-विक्रय एवं आयात-निर्यात तथा मूल्य-मान सम्मिलित हैं। मूल्य मान का तात्पर्य उस मुद्रा इकाई से हैं जिसमें किसी देश की सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य नापा जाता है। एक आदर्श मुद्रा मान कीमतों को स्थिरता प्रदान कर आर्थिक अनिश्चितता को दूर करता है तथा देश में ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित करता है जिनमें देश का व्यापार, व्यवसाय एवं वाणिज्य पनप कर उन्नति कर सके। इस प्रकार मुद्रा-मान का अधिक महत्व बढ़ गया है।

मुद्रा-मान दो प्रकार के होते हैं:—(ऋ) घातु मान (Metallic Standard) जिसमें घातु की मुद्रा चलन में रहती है, ऋौर (ब) पत्र मान (Paper Standard) जिसमें कागजी मुद्रा का ही मूल्य के मान के रूप में उपयोग किया जाता है।

- (ग्र) घातु-मान के इस प्रकार से भेद किये जा सकते हैं-
- (१) एक घातुमान (Monometallism) केवल एक ही प्रकार की घातु के सिक्ते चलन में रहते हैं। चलन में स्वर्ण श्रयवा रजत घातु ही (कोई एक) रहती है। मारत में १८६३ ई० तक रजत-मान रहा था। इंगलैंड में १६३१ तक तथा फांस में सन् १६३६ तक स्वर्णमान रहा। जब मुद्रा स्वर्ण की या उसका मूल्य स्वर्ण के श्राधार पर श्राँका जाता है तो उसे स्वर्णनान कहते हैं श्रीर जब मुद्रा चाँदी की होती है तो उसे रजत मान (Silver standard) कहते हैं।
- (२) द्विशातुमान (Bimetallism) जब दो धातुश्रों प्रमुखतः स्वर्ण एवं रजत के सिक्के एक साथ ही प्रामाणिक सिक्कों के रूप में चलन में रहते हैं तो होनों प्रकार के सिक्के श्रमीमित विधि-प्राह्म होते हैं तथा दोनों धातुश्रों को विनिमय दर कानून द्वारा निश्चित की जाती है, परन्तु जब दोनों धातुश्रों के सिक्के चलन में हों श्रीर उनमें से एक सिक्के की दलाई स्वतन्त्र होती ही श्रीर दूसरी धातु के सिक्कों की दलाई सीमित हो तो इस प्रकार के द्विधातु मान को पंगु धातुनान (Limping bimetallism) कहा जाता है। इस मान को पंगु

या लँगड़ा इसिलिए कहा जाता है कि जिस धातु के सिक्के की स्वतंत्र दलाई नहीं होती वह किटनाई के साथ चालू रहता है— मुद्रा-मान की एक टाँग वेकार रहती है। फांस में इस प्रकार का मान प्रचलित था जहाँ चाँदी के सिक्कों की स्वतन्त्र दलाई नहीं थी। जब दोनों धातुत्रों के सिक्के असीमित विधिग्राह्म एवं स्वतन्त्र दलाई वाले हों परन्तु परस्पर विनिमय कानून द्वारा निश्चित (जैसा कि द्विधातुमान में होता है) न होकर बाजारू कीमतों के आधार पर निश्चित होने के लिए छोड़ दिये जाते हैं तो इस प्रणाली को सामानुपाती द्विधातु मान (Parallel bimetallic standard) कहते हैं। यह टकसाली अनुपात स्थिर न होकर कीमतों के परिवर्त्तन के साथ बदलता रहता है।

(३) प्रादिष्ट मान (Fiat standard)—प्रादिष्ट मान में मुद्रा की इकाई की कीमत स्वर्ण अथवा अन्य किसी प्रकार की घातु की एक निश्चित मात्रा के बराबर नहीं रखी जाती। इस प्रकार की मुद्रा की इकाई का मूल्य दूसरी किसी भी वस्तु की कीमत से स्वतन्त्र रूप में निर्वारित होती है। सरकार जानते हुए भी ऐसी मुद्रा की निकासी कर सकती है जिसका घातु-मूल्य नहीं के बराबर हो। सन् १८६२ से १८७६ ई० के बीच तक इस प्रकार का मान संयुक्त राज्य अमेरिका में चालू रहा। इस प्रकार के मान से एक लाम यह है कि मुद्रा और साख को इतना बढ़ाया जा सकता है कि देश के मनुष्यों को यथेष्ट रोजगार मिल सके। दूसरे, यथेष्ट प्रवंघ द्वारा इस मान को धातु-मान की अपेद्या अधिक लोचवान (elastic) बनाया जा सकता है। परन्तु इसके प्रचलन में दो मुख्य कठिनाइयाँ हैं:—(१) यदि सभी देश इस मान को अपना लें तो अतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत उलभन पैदा हो जायगी तथा, (२) यह भय सदैव बना रहता है कि प्रादिष्ट भद्रा की अधिक निकासी न हो जाय।

एक धातुमान के लाभ (Advantages of monometallism)

- (१) ऐक ही धातु की मुद्रा चलन में रहने के कारण यह मान लोगों की समक्त में आसानी से आ जाता है तथा ग्रेशम का नियम, कि दो धातुओं के चलन में अञ्जी धातु के सिक्के चलन से लुप्त हो जाते हैं, भी लाग नहीं हो पाता।
- (२) बहुमूल्य धातु—सोना या चाँदी के सिक्के चलन में रहने के कारण इस मान में जनता का विश्वास भी अधिक बना रहता है।
- (३) स्वर्ण या रजत पर मह मान ऋाश्चित होने के कारण ऋन्तर्राष्ट्रीय व्या-पार तथा लेन-देन में सविधाजनक रहता है।
- (४) स्वर्ण या रजत की कीमतों में उतार-चढ़ाव बहुत कम होते हैं। न्य्रतः इस मान के भी अन्तर्गत मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है।

एक घातुमान के दोष (Disadvantages)

- (१) संसार भर में सोने अथवा चाँदी की मात्रा के अपर्याप्तता के कारण सब देश इस मान को एक साथ नहीं अपना सकते।
- (२) इस मान के ऋंतर्गत श्रावश्यक लोच का श्रमाव रहता है। यदि मुद्रा की श्रावश्यकता हो परंतु पर्याप्त स्वर्ण या रजत कोष में न हो तो मुद्रा की निकासी नहीं हो सकती, जैसे युद्ध काल में। इसी कारण से प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत ऋषिकांश देशों ने इस मान को त्याग दिया।

द्विषातुमान (Bimetallism) भी संसार में पर्याप्त समय तक प्रचलित रहा। इंगलैंड, अमरीका, फांस, इटली आदि देशों ने इस मान को अपनाया। १६०६ ई० में इस मान का अंत हुआ। द्विधातुमान की सफलता के लिए निम्नांकित चार बार्तों की आवश्यकता रहती है—

- '(ऋ) प्रत्येक द्विचातुमान देश को ऋपनी मुद्रा की इकाई की कीमत सोने की निश्चित मात्रा के बराबर घोषित करनी पड़ती है और साथ-साथ मुद्रा इकाई को एक निश्चित मात्रा के बराबर रखना पड़ता है।
- (व) सरकार सोना ऋौर चाँदी की स्वतंत्र ढलाई तथा स्वतंत्र बाजार की व्यवस्था करती है ताकि देश के भोतर ऋौर बाहर सोने ऋौर चाँदी के सिक्कों की कीमत उनके वास्तविक मूल्य (intrinsic value) के बरावर रहे।
- (छ) सोना और चाँदी के सिक्के दोनों ही अपरिमित विधि प्राह्म घोषितः करने पड़ते हैं।
- (द) एक प्रकार के सिक्कों के बदले में दूसरे प्रकार के सिक्कों को बदलने की गारंटी देनी होती है।

द्विघातुमान के लाभ (Advantages)

- (१) दिघातुमान प्रणाली के त्रांतर्गत सुरिच्चत कोष विस्तृत रहते हैं त्रौर बनता का विश्वास बना रहता है। मुद्रा की परिवर्तनशीलता बनी रहती है; क्यों कि यदि एक घातु कम प्राप्त होती है तो दूसरी घातु उसकी पूर्ति कर देती है। यह बात एक घातुमान में नहीं होती।
- (२) इस प्रणाली में कीमतें ऋषिक स्थिर रहती हैं। सोना और चाँदी दोनों, ही चलन में रहने के कारण यदि एक घात का मूल्य कम हो जाता है तो दूसरी का बढ़ सकता है अथवा एक की पूर्ति ऋषिक हो तो दूसरी की कम हो सकती है और इस अकार से मुद्रा के च्रति पूरक कार्यों (Compensatory actions) द्वारा मूल्यों का प्रियरिकरण हो जाता है। यदि एक ही घात का कोष है तो सुरच्तित कोष की कीमत में भारी परिवर्तन होने का मय रहता है।

(३) द्विघातु मान वाले देश का विदेशी व्यापार उन सभी देशों के साथ सुविधापूर्वक चल सकता है जिनकी मुद्रा सोने या चाँदी की है। एक धातुमान वाले देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इतना विस्तृत नहीं हो सकता और न विदेशी विनिमय में अधिक स्थिरता ही आ सकती है।

द्विधातुमान प्रणाली के दोष (Defects) '

- (१) इस प्रणाली के ऋंतर्गत ग्रेशम का नियम लागू होता है, जिसके ऋनु-सार ऋच्छी सुद्रा चलन से बाहर हो जाती है। इससे विनिमय ऋनुपात नष्ट हो जाता है ऋौर एक धातुमान स्थापित हो जाता है।
- (२) द्विधातुमान प्रणाली तभी सफल होती है जब संसार के अपन्य देश इस प्रणाली को मानते हों। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से दोनों धातुओं के बाजारू तथा टकसाली अनुपात में समानता रखी जा सकती है। इस प्रकार अपन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान स्थापित हो जाने से प्रेशम का सिद्धान्त लागू नहीं होगा। परंतु संसार के देश अपने व्यक्तिगत हितों की ओर ही अधिक देखते हैं, अतः अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना कम रहती है।
- (३) द्विधातुमान प्रणाली के अन्तर्गत सोने आरे चाँदी की सट्टेबाजी को भी खूब प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्येक व्यापारी को वस्तुओं के दांम सोने और चाँदी में अलग-अलग लिखने पड़ते हैं। बाजार में दोनों सिक्कों के अनुपात बदलते रहते हैं अौर साथ ही वस्तुओं का मृल्य भी बदलता रहता है। इससे आन्तरिक व्यापार में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होतों है।
- (४) दो घातुश्रों के सिक्के चत्तन में रहने के कारण सदैव मुद्रा प्रसार की सम्भावना बनी रहती है जिसके स्रार्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है जिसका सामा-जिक व स्रार्थिक प्रभाव बड़ा गम्भीर पड़ता है । इसके स्रतिरिक्त दोनों घातुश्रों के सिक्कों में विसावट की हानि भी रहती है।
- (५) दो घातुओं के चलन में चितिपूर्ति कार्य (Compensatory action of the double standard) तभी तक पूरा होता है जब कि दोनों प्रकार के पर्याप्त कोष हों। एक घातु की कीमत गिरने के कारण जो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है वह दुसरी घातु के मूल्य में वृद्धि होकर वस्तुओं के मूल्य कम कर सकती है। इस प्रकार यह चितिपूर्ति का कार्य होता है। व्यावहारिक जीवन में दोनों घातुओं के कोष कभी भी पर्याप्त नहीं हो पाते जिसके, कारण अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान स्थापित नहीं हो सकता।

शेशम का नियम (Gresham's Law)

बुरी मुद्रा की अच्छी मुद्रा के चलन से बाहर कर देने की प्रवृत्ति को ही

ग्रेशम का नियम कहते हैं। सर टामस ग्रेशम इंगलैंड की महारानी एलिजावेथ प्रथम के त्रार्थिक सलाहकार थे । प्रेशम ने मुद्रा सम्बन्धी श्रध्ययन करके यह नियम प्रतिपादित किया कि यदि किसी देश में एक ही समय श्रव्छी ऋौर बुगं मुद्रा का चलन हो तो बुरी मुद्रा की प्रवृत्ति सदैव अञ्च्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकालने की रहती है (Bad money drives good money out of circulation)। ऋच्छी मुद्रा से ऋभिप्राय उन सिक्कों से था जो वज़न में पूरे होते हैं, वैवानिक रूप से ऋसीमित मात्रा में ग्राह्म हों तथा दूसरी मुद्रा में परि-वर्तनशील हों । बुरी मुद्रा से उनका ऋर्य घिसे-पिटे ऋथवा सीमित, ऋपरिवर्त्तनशील सिकों से था । महारानी ने मुद्रा सुघार के लिए बाजार में पूर्णकाय (full-bodied) सिक्के प्रसारित हुए परन्तु अनुभव विपरीत दिशा में रहा कि अञ्छे सिक्के चलन में त्राते ही बाबार से ब्रहश्य हो बाते रहे ब्रौर निकृष्ट सिक्के ही चलन में रह गए। ग्रेशम ने श्रध्ययन के पश्चात उपरोक्त नियम निकाला जिसको बाद में मार्शल ने इस प्रकार स्पष्ट किया "घटिया मुद्रा, यदि संख्या में परिमित नहीं है, तो वह बिढिया मुद्रा को चलन से निकाल बाहर करेगी।" (An inferior currency, if not limited in quantity, will drive the superior currency out of circulation- Maishall)। मार्शल की परिभाषा में 'यदि मात्रा में परिमित नहीं हैं जुड़ा है। इस वाक्य का ब्राश्य यही है कि यदि किसी देश में मुद्रा सीमित मात्रा में हुई तो त्रागे चलकर यह मुद्रा समाप्त हो जायेगी त्रीर उसका स्थान नई मुद्रा ले लेगी । परन्त अपरिमित हो तो खराब मुद्रा ही चलन में रहती है अच्छी मद्रा को जनता जमा (hoard) कर लेती है। टेलर का कहना है कि जो मुद्राएँ विनिमय या घातु मूल्य में घटिया होती हैं वे उन मुद्रास्त्रों की स्त्रपेन्ना जो विनिमय या घातु मूल्य में अधिक श्रेष्ठ होती हैं, चलन में रहने की अधिक ग्राहकता या दृदता (tenacity) दिखलाती हैं।

नियम के लागू होने के कारण (Why does the law operate)— इस प्रश्न को सममना, िक अच्छी मुद्राएँ चलन से किस प्रकार अलग हो जाती हैं, अधिक कठिन नहीं है, क्योंकि प्रथमतः लोगों में मुद्रा जमा करने अथवा एकत्रित रखने की (hoarding), स्वभावतः इच्छा होती है और इन उद्देश्यों के लिये पूर्णकाय सिक्के, नये सिक्के व नोटों ही का प्रयोग रहता है और दैनिक चलन के लिये बुरी मुद्रा अर्थात् विसी, कम वजन या कम मूल्य की मुद्रा से ही काम चलाते हैं। दूसरे, सिक्कों को गलाने के लिये और आमूषण आदि बनवाने के लिये भी पूर्णकाय, नये सिक्के ही लाभदायक रहते हैं। पुराने, कम वजन वाले सिक्कों में हानि होने की स्वभावना रहती हैं। अतः इस प्रकार के सिक्के बाजार में चलन में रखे जाते हैं और अच्छे सिक्के चलन से बाहर हो जाते हैं। तीसरा कारण है विदेशी भुगतान तथा निर्यात का । विदेशों के भुगतान के लिये घातु के सिक्के ही विदेशियों द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं ऋौर इन सिक्कों को तौल के हिसाब से लिया जाता है। यही कारण है कि विदेशी भुगतान ऋथवा निर्यात के लिये सबसे ऋच्छे सिक्के लिये जाते हैं ऋौर खराब सिश्के चलन में रह जाते हैं।

नियम का चेत्र (Scope of the Law)

ग्रेशम का नियम मनुष्य की प्रकृति को ही प्रदर्शित करता है और प्रत्येक मुद्रा-मान में लागू होता है, जैसे —

- (१) एक धातुमान (Monometallism) प्रणाली में जब एक ही घातु के प्रामाणिक अथवा सांकेतिक सिक्के चलन में रहते हैं तो उनमें से कुछ घिसे, कम वजन वाले या पुराने सिक्के हो सकते हैं और कुछ नये, वजन में पूर्ण हो सकते हैं। पिछली प्रकार के सिक्के चलन से बाहर हो जाते हैं और प्रथम प्रकार के सिक्के चलन से बाहर हो जाते हैं और प्रथम प्रकार के सिक्के चलन में बने रहते हैं। और यदि सांकेतिक एवं प्रामाणिक सिक्के चलन में हैं तो सांकेतिक सिक्के ही चलन में रहेंगे और प्रामाणिक सिक्के जमा किये जाने लगेंगे। जार्ज पंचम और विक्टोरिया के सिक्के भारत में एक ही समय चलन में थे। विक्टोरिया के सिक्के चलन से बाहर हो गये क्योंकि उनमें चाँदी का अधिक अर्थ था।
- (२) द्विधातुमान (Bimetallism) पद्धित में —यदि दो बहुमूल्य धातुत्रों के सिक्के एक कान्ती निश्चित दर पर चलते हों तो जिस घातु का टकसाल पर अधिक मूल्य लगाया जाता है वह उस घातु के सिक्कों को चलन से हटा देगा जिसका मूल्य टकसाल पर बाजार से कम लगाया जाता है। उदाहरणार्थ किसी देश में सोने त्रौर चाँदी के सिक्कों का टकसाली मूल्य १:१५ है अर्थात् १ सीने का सिक्का १५ चाँदी के सिक्कों के बराबर है। अब यदि बाजार में चाँदी का माव गिर जाता है अ्रौर बाजार भाव १:१६ हो जाता है परन्तु टकसाल पर वही मूल्य प्रचित्त है अर्थात् चाँदी का मूल्य अधिक लगाया जा रहा है अ्रौर सोने का मूल्य कम। अतः सोने से सिक्के दबा कर रख लिये जायँगे अ्रौर चाँदी के सिक्के ही चलन में रहेंगे। दूसरे शब्दों में अतिमूल्यत सिक्के (Overvalued Currency) अत्रवमूल्यत सुद्रा (undervalued currency) को चलन से बाहर कर देगा।
- (३) पत्र-मुद्रा चलन (Paper Currency) में यदि एक ही प्रकार की पत्र-मुद्रा चलन में है तो सड़े-गले; फटे-पुराने नोट चलन में रहेंगे श्रौर श्रच्छे नए नोट लोग जमा कर लेंगें। यदि परिवर्त्तनशील तथा श्रपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा एक साथ चालू हैं तो परिवर्त्तनशील पत्र-मुद्रा श्रच्छी समभी जाने के कारण चलने से बाहर हो जायगी श्रौर श्रपरिवर्त्तनशील मुद्रा चलन में रहेगी।

नियम के श्रपवाद (Exceptions or Limitations of the Law)

ग्रेशम का विचार था कि यह नियम सभी दशात्रों में लागू होता है परंतुः निम्नांकित परिस्थितियों में यह नियम लागू नहीं होता—

- (१) किसी देश की अच्छी और बुरी समस्त प्रकार की मुद्रा की मात्रा, वास्तविक मुद्रा की माँग से अधिक नं हो तो यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि सभी प्रकार के सिक्के चलन में आवश्यक होंगे। हाँ यदि मुद्रा की कुल मात्रा उसकी संपूर्ण माँग से अधिक हो तो अतिरिक्त मात्रा के बराबर अच्छे सिक्के चलन से बाहर हो जायँगे।
- (२) यदि समस्त समाज बुरे सिक्कों का पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर दे तो बुरी मुद्रा श्रव्ही मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर सकेगी।
- (३) यदि मुद्रा इतनी खराब हो चुकी है कि लोग उसे अस्वीकार करने लगे हैं तो वह नोट या सिक्का स्वयं प्रचलन से निकल जायगा।
- (४) यदि बुरी मुद्रा की मात्रा सीमित है तो यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि सीमित होने के कारण आगे चल कर उनका चलन समाप्त हो जायेगा।
- (५) यदि सभी राष्ट्र द्विघातु मान प्रणाली को अपना लें तो उसमें च्रित-पूरक प्रभाव के कारण ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि यह प्रणाली निश्चित समानुपातिक आधार पर प्रचलित होती है।
- (६) यदि देश में बैकिंग व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो चुकी है श्रौर लोग चेकों का प्रयोग करते हैं तो फिर सुद्रा के चलन का प्रश्न ही नहीं उठता श्रौर न फिर प्रेशम का नियम ही लागू होता है।

षातुमान और द्विषातुमान के श्रंतर्गत यह नियम विशेष रूप से प्रतिपादित होता है। षातुमान का श्रंत होने के साथ एवं कागजी मान के विकसित होने के साथ इस नियम में शिथिलता श्रा गई है। परंतु फिर भी यह नियम सत्य है। सन् १६४०-४२ में भारत में चाँदी का रुपया इसी नियम के श्रंतर्गत बंद हुश्रा था।

प्रश्न

१—"अब अच्छे द्रव्य और बुरे द्रव्य मुद्रा में प्रचलित हैं और दोनों में से किसी में भी करण का मुग्रतान किया जा सकता है तो अच्छे द्रव्य को या तो गला देते हैं या देश के बाहर भेज देते हैं।" इस नियम की विवेचना की जिए।

(आगरा बो. ए. १६५०)

the Indian currency system satisfy the test of a good currency system. Does tem?

(Agra B. Com. 1957)

3. Discuss the advantages and dangers of paper money.

How can its overissue be checked?

(Agra B. Com. I, 1957)

अध्याय ४.

स्वर्णमान

एक घातुमान का सुप्रसिद्ध एवं सर्वे प्रिय मान स्वर्णमान रहा है.। इसके श्रांतर्गत स्वर्ण को मूल्यमान के रूप में उपयोग किया जाता है। श्रथींत् देश की सुद्रा अत्यच् या अप्रत्यच्च रूप से स्वर्ण में परिवर्त्तनशील होती है। रॉवर्टसन (Robertson) ने इस मान की परिभाषा इस प्रकार से की है, "त्वर्णमान वह स्थिति है जिसमें एक देश अपनी मौद्रिक इकाई-मूल्य एवं स्वर्ण की निश्चित मात्रा का मूल्य परस्वर वैरावर रखता है।" (Gold standard is a state of affairs in which a country keeps the value of its monetary unit and value of a defined weight of gold at an equality with one another,—Robertson.) कालबोन (Coulborn) की परिभाषा भी इसी से मिलती-जुलती है—''स्वर्णमान एक ऐसी व्यवस्था है जिसके स्रांतर्गत एक चलन की मुद्रा की मुख्य इकाई एक निश्चित स्वर्ण की मात्रा में बदली जा सकती है।" (The gold standard is an arrangement whereby the chief piece of money of a country is exchangable with a fixed quantity of gold of a specific quality.) स्वर्णमान वाले देश में विधान द्वारा कोषागार, या केन्दीय बैंक पर यह उत्तरदायित्व डाल दिया जाता है कि वह निश्चित दरों पर देश की मुद्रा को स्वर्ण में बदलता रहे। उदाहरणार्थ बेंक श्चॉफ इंगलैंड पर यह उत्तरदायित्व था कि ४.२४०६ पौंड प्रति श्चौंस की दर पर प्रत्येक विकेता से स्वर्ण क्रय करे एवं ४.२४७७ पौंड प्रति श्रौंस की दर पर प्रत्येक क्रेता को सोने का विक्रय करे।

स्वर्णमान के लिए आवश्यक द्शाएँ (Conditions for gold standard—स्वर्णमान को बनाए रखने के लिए निम्नांकित दशाएँ आवश्यक हैं —

देश को अपनी प्रचिलत मुद्रा तथा मान की इकाई को सोने के मूल्य में निश्चित करना होता है। यह भी दो प्रकार से संभव हो सकता है। प्रथमतः मुद्रा-इकाई में सोने की मात्रा निश्चित कर दी जाती है, जैसा इंगलैंड में किया गया था। तथा दूसरे सोने की टकसाली (Mint value) मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है जैसे मारत में एक तोले सोने का मूल्य २१ | ० थो षित किया गया था जो अब ६२ ६० ५० नए पैसे निर्धारित किया गया है।

- (२) बैंक या किसी अन्य मुद्रा अधिकारी को इसी निश्चित कीमत पर स्वर्ण विकेताओं से क्रय करना चाहिए तथा केताओं को बेचना चाहिए।
- (३) चालू मुद्राएँ (Token coins) मुख्य मुद्रास्त्रों (standard coins) में परिवर्त्तनशील होनी चाहिए।
- (४) स्वर्ण के आयात-निर्यातं पर किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए।

सरकार स्वर्णमान के प्रचलन के लिए त्रावश्यक नियम बनाती है त्रौर यह भी निश्चित करती है कि स्वर्णमान को किस रूप में स्वीकृत किया जाय।

स्वर्णमान के रूप (Forms of gold standard)

स्वर्णभान के निम्नांकित चार रूप देखने को मिलते हैं।

- . (अ) स्वर्ण मुद्रा मान (Gold currency standard)—इस मान को स्वर्ण टंक मान (gold coin standard) या स्वर्णमान मुख्य (gold standard proper) भी कहते हैं। इस प्रकार के मान की ये विशेषताएँ हैं—
 - (१) सोने के सिक्के चलन में रहते हैं।
 - (२) सोने की स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई होती है।
 - (३) भुगतान के लिए स्वर्ण अपरिमित विधि ग्राह्य होता है।
 - (४ स्वर्ण का आयात-निर्यात अप्रतिबन्ध रूप से होता है।
- (५) चलन की मुद्रा की मात्रा स्वर्ग कोष पर निर्भर होती है। कोष के घटने बढ़ने के साथ ही मुद्रा मात्रा में भी कमी या वृद्धि होती है।
 - (६) सभी प्रकार की मुद्रा स्वर्ण में परिवर्त्तनशील रहती है।

प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व चीन श्रौर भारत श्रादि देशों को छोड़ कर सभी देशों में इस मान का प्रचलन था। इंगलैंड में सॉबरेन (Sovereign) के रूप में स्वर्ण की मुद्रा प्रचलित थी। इस सॉबरेन में ११३ हुई श्रेन शुद्ध सोना होता था तथा शेष टाँका जिसकी कीमत २ पौड १७ शि० १० है पैंस होती थी तथा इसी कीमत पर बैंक श्रॉफ इंगलैंड सोना बेचता था श्रौर श्रावश्यकता पर २ पौं० १७ शि० ६ पें० के मूल्य पर कय करता था। श्रमेरिका ने यह मान १६३३ ई० में छोड़ा था। इस मान में मुद्रा की मात्रा स्वर्ण कोष पर निर्भर करती है, श्रतः मुद्रा में प्रसार एवं श्रत्थिक संकुचन का भय श्रिषक नहीं रहता। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति प्रकृति पर छोड़ दी जाती है। श्रंतर्राष्ट्रीय वाजार में भी विनिमय दरों में परिवर्त्तन श्रायात तथा निर्यात बन्न की सीमाश्रों तक ही संकुचित रहता था। स्वर्ण का स्वतंत्र श्रायात-निर्यात होने के कारण देश के स्वर्ण कोषों में परिवर्त्तन होते रहते थे जिससे कीमत भी उतरती-चढ़ती रहती थी जिसका प्रभाव देश के स्वर्ण के श्रायात-निर्यात पर पहता था।

स्वर्ण-मुद्रा मान के लाभ (Advantages of G. C. S.)

इस मान के प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं—

- (१) इसमें स्वर्ण के सिक्के चलन में रहने के कारण जनता. का विश्वास बना रहता है। यदि ख्रांकित मूल्य (face value) समाप्त भी हो जाय तो उस सिक्के के ख्रांतरिक मूल्य (intrinsic value) बनी रहती है जिससे स्वर्ण किसी दूसरे उपयोगी कामों में लिया जा सकता है। इस प्रणाली में पत्र-मुद्रा एवं अन्य छोटे सिक्के स्वर्ण में परिवर्त्तनशील रहते हैं जिससे विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। इसके ख्रांतिरिक्त स्वर्ण कोष के बरावर ही मुद्रा निकाली जाने की प्रथा होने के कारण भी विश्वास बढ़ जाता है।
- (२) यह प्रणाली स्वयं संचालित होती है, कारण कि स्वर्ण के स्त्रायात-निर्यात पर सरकार का कोई हस्तच्चेप नहीं होता। स्वर्ण के स्रनुसार ही मुदा की मात्रा रहती है। जब सोना स्रधिक स्रायात हो जाता है तो मुद्रा की मात्रा बढ़ती है जिससे मूल्य स्तर बढ़ जाते हैं स्त्रीर स्त्रायातों को प्रोत्साहन मिलता है। परिणामतः प्रतिकृल भुगतान संतुलन (unfavourable balance of trade) होता है स्त्रीर स्वर्ण (जो स्रधिक था) निर्यात कर दिया जाता है। इस प्रकार मूल्य-स्तर स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। सरकार को स्वयं-संचालकता लाने के लिए भी स्त्रधिक प्रयत्न नहीं करने पड़ते।
- .(३) मल्यों में श्रिधिक उतार-चढ़ाव नहीं होते। मृल्यों में परिवर्त्तन का प्रमुख कारण मुद्रा की कय शक्ति में परिवर्त्तन रहता है। परंतु सोने की मात्रा में बहुत ही कम परिवर्त्तन होते हैं श्रीर स्वयं धातु के मृल्य में स्थिरता बनी रहती है। इससे देश के मूल्यों में भी श्रिधिक उतार-चढ़ाव नहीं हो पाते।
- (४) इस प्रणाली में विदेशी विनिमय दर भी स्थिर रहती है। जब सभी देशों में स्वर्णमान का चलन होता है और उनकी मुद्राश्चों की कीमत सोने की कीमत पर श्राधारित होती है तो उन देशों की पारस्परिक विनिमय दरों में भी स्थिरता श्रा जाती है। इससे विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है।

स्त्रणं मुद्रा-मान के दोष (Disadvantages)

वास्तव में देखा जाए तो स्वर्णमान के लाभ काल्पनिक हैं। व्यावहारिक जीवन में अनेक दोष दृष्टिगोचर हुए हैं, जैसे—

(१) यह मान देश की मुद्रा-प्रणाली को प्रकृति पर निर्भर एवं बेलोच र (inelastic) बना देता है। मुद्रा की मात्रा स्वर्ण-कोष पर निर्भर रहती है, ग्रतः इसे वही राष्ट्र ग्रपना सकते हैं जो धनवान हैं। सब राष्ट्र या कम स्वर्ण रखने वाले देश इस प्रणाली को ग्रपनाने में ग्रसमर्थ रहते हैं। साथ ही यह मान केवल शांति के समय हो प्रतिपादित हो सकता है संकट-काल या युद्ध-काल में नहीं। इसीलिये हुए ग्राच्छे दिनों का साथी (fair weather friend) कहा गया है।

- (२) यह प्रणाली बहुत खर्चीली है। स्वर्ण का एक बड़ा भाग ताले में बंद पड़ा रहता है। इससे उस स्वर्ण का देश के अन्य आर्थिक हितों में प्रयोग नहीं हो पाता और न उस पर ब्याज के रूप में कुछ आय ही प्राप्त हो पाती है। फिर स्वर्ण के निक्के प्रचलन में रहने के कारण उनमें घिसावट आती है। यह राष्ट्रीय हानि है जिसे शायद ही कोई राष्ट्र वर्दाश्त कर सके।
- (३) स्वर्णमान तभी सकल हो सकता है जब कि उसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त हो और सभी देश स्वर्णमान के नियमों का पालन करें। परंतु प्रथम महायुद्ध के समय और बाद में कोई देश अपने निर्यात स्त्रायात निर्वाध रूप से नहीं कर सका और प्रतिबंधित मुद्रा-प्रणाली अपनानी पड़ी।
- (४) विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व लाने के लिए स्वर्ण-कोष इतना आवश्यक नहीं है जितना कि आपसी मौद्रिक सहयोग (International Monetary Fund) विना स्वर्ण मान की स्थापना के ही आवश्यक कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों के अनुसार स्वर्णचलन मान विनिमय दरों की स्थिरता को भग करता है। और साथ ही कीमतों की स्थिरता सभी परिस्थितियों में उचित भी नहीं होती। उसमें आवश्यक लोच रहनी ही चाहिए। इस प्रकार स्वयं विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता भी दोषों से मुक्त नहीं है।
- (५) वास्तव में देखा जाय तो सोने के प्रत्येक परिवर्त्तन के साथ-साथ मूल्य-स्तर में भी परिवर्त्तन होते हैं। यह स्वर्ण के मूल्य में परिवर्त्तन कई कारणों से हो सकता है। जैसे नई खानों की खोज या पुरानी खानों की समाप्ति। पुनः सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि स्वर्ण-कोषों का संसार में असमान वितरण है। संसार का है स्वर्ण अमेरिका पर ही है। यह असमान वितरण कीमतों में स्थिरता पहले तो लाने नहीं देखा और फिर इस प्रकार यह न्यायसंगत भी नहीं रहेगा।

इन्हीं दोषों को देखते हुए अन्य प्रणालियाँ प्रयोग में लाई गई।

(ब) स्वर्णपाट मान श्रथवा स्वर्ण धातुमान (gold bullion standard)—यह मान स्वर्ण चलन मान का दूसरा रूप है। इसकी विशेषतायें निम्न हैं।

इस स्वर्ण मान के अन्तर्गत सोने के सिक्के का अचलन नहीं होता है। चलन में कम कीमती घातु के सिक्के अथम कागजी नोट चलते रहते हैं। इसमें सोने की दल्भई की स्वतन्त्रता आस नहीं होती। पत्र मुद्रा के पीछे शतप्रतिशत स्वर्ण निधि भी नहीं होती। सोने की कीमत सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती है तथा सरकार को हो नियत कीमत पर असीमित मात्रा में सोना खरीदने तथा बेचने की व्यवस्था करनी पहती है। सुविधा के लिए एक न्यूनतम मात्रा निश्चित कर दी जाती हैं जिससे कम मात्रा में एक बार सोना नहीं बेचा जा सकता। सरकार द्वारा इस बात का प्रबन्ध किया जाता है। विदेशी मुगतानों के लिये प्राप्त करने में किसी को कठिनाई न हो इस प्रकार स्वर्णपाटमान में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है। देश में सांकेतिक सिक्के अथवा पत्रमुद्रा चालू रहती है। और ये दोनों सरकार द्वारा निश्चित दरों पर सोने में बदली जा सकती हैं।

स्वर्णपाटमान के लाभ

इस मान में स्वर्णचलनमान के सम्पूर्ण गुरा होने के अतिरिक्त उसके दोघों से मुक्ति होती है। इसमें सिक्तों के मुद्र ए का व्यय बच जाता है, क्योंकि इसके त्रान्तर्गत सिक्कों का चलन ही नहीं होता। इसके साथ-ही-साथ विसावट द्वारा सोने का विनाश बच जाता है तथा सोने के सिक्कों का प्रयोग न होने से सोने के उप-योग में जो बचत होती है वह राष्ट्रीय सुरिच्चत कोषों के स्थापित करने में काम में त्रा जाती है। सोना छोटे-छोटे व्यक्तिगत कोपों में जमा न होकर एक स्थान पर सरकारी कोषागार अथवा देश की केन्द्रीय वैंक में एक ही स्थान पर जमा होता है। इस मान में मुद्रा की पूर्ति में पर्याप्त लोच भी रहती है; क्योंकि यदि सुरच्ति कोप तथा चलन के बीच का अनुपातं कम कर दिया जाय तो थोड़े ही सोने के आधार पर अधिक मुद्रा चलाई जा सकती है। इस मान में विनिमय दरों की स्थिरता भी स्वर्ण प्रचलन मान की अपेद्धा अधिक होती है और यदि स्वर्णमान नियमों का पालन किया जाय तो इसमें भी स्वयं संचालकता का गुण ब्रा जाता है। जिस समय समाज में मद्रा की माँग कम हो जाती है तो लोग सोना खरीदने लगते हैं। स्वर्ण कोषों में कमी आ जाती है तथा चलन की मात्रा घट जाने के कारण चलन की पूर्ति तथा माँग में सामञ्जस्य स्थापित हो जाता है ऋौर जब मुद्रा की माँग ऋधिक हो जाती है तो लोग सोना बेचने लगते हैं जिससे स्वर्णकोषों में सोना ऋधिक जमा होने लगता है। यह मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने में सहायक हाता है और इस स्थित में भी माँग तथा पूर्ति में सामञ्जस्य स्थापित हो जाता है। इसी दृष्टि से यह मान स्वयं संचालित समभा जाता है।

उपरोक्त गुणों के होते हुए भी स्वर्णपाटमान में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं:--

(१) यह मान भी स्वर्णचलन मान की भाँति साधारण परिस्थितियों में ही ठीक प्रकार से कार्य करता है। संकटकालीन अवस्था में इस मान के अनुसार आवश्यक मुद्रा पूर्ति नहीं हो पाती, चूँकि इस मान के अन्तर्गत सोने का सिक्का नहीं चलता। सोना जनता के समन्ने चलन में न आने के कारण जनता का विश्वास इस मान में इतना इद नहीं होता जितना स्वर्णमान में होता है। इसके अतिर्क्त स्वर्ण चलन मान की । अपेन्ना इस पद्धित में सरकारी इस्तन्नेप की आवश्यकता भी अधिक पड़ती है। सरकारी इस्तन्नेप के कारण तुटियों की सम्भावना अधिक बढ़

बाती है। इस मान में किसी सीमा तक अपेचाकृत व्यय भी अधिक होता है। एक तो सोना मुरिच्चत कोषों में व्यर्थ पड़ा रहता है, उसके उचित संरच्चण के लिये व्यय करना पड़ता है तथा सांकेतिक व काग़जी मुद्रा का उचित प्रबन्ध और नियन्त्रण रखने के लिये निरीच्चण आदि के प्रबन्ध में काफी व्यय पड़ जाता है।

स्वर्ण मुद्रा मान तथा स्वर्ण धातुमान की तुलना

स्वर्ण घातु मान

- १. स्वर्ण का प्रयोग मूल्य-मान के रूप में ही होता है, विनिमय-माध्यम के रूप में नहीं।
- र, न तो सोने के सिक्कों का चलन ही रहता है श्रीर न स्वतंत्र मुद्रा ढलाई ही।
- सैंद्धांतिक दृष्टि से स्वर्ण का कय-विकय किया जा सकता है परन्तु व्यव-हार में स्वर्ण केवल विदेशी भुगतानों के लिये ही प्राप्त रहता है।
- ४. विनिमय दर्रों की स्थिरता पर अप्रिक जोर दिया जाता है।
- ५. स्वर्ण के त्रायात-निर्यात पर सरकारी इस्तचेप नहीं रहता त्र्रौर मूल्यों का निर्घारण स्वयं रहता है।

स्वर्ण मुद्रा मान

- सोने का प्रयोग विनिम्य का माध्यम तथा मूल्यमान दोनों के ही रूप में किया जाता है।
- २. सोने के सिक्के चलन में रहते हैं ऋौर स्वर्ण की दलाई स्वतंत्र होती है।
- ३. सोना घरेलू आवश्यकता तथा विदेशी आवश्यकता दोनों ही के लिए उपलब्ध रहता है।
- ४. देश के अ्रान्तरिक मूल्यों की स्थिरता का विशेष ध्यान रखा जाता है।
- ५. सरकार का स्वर्ण मूल्य पर पूर्ण अधिकार रहता है और स्वर्ण की विनिमय दर बार-बार निर्धारित करनी पड़ती है।
- (स) स्वर्ण विनिमय मान (Gold exchange standard)—उपरोक्त दोषों को दूर करने के लिये एक अन्य प्रकार का स्वर्णमान व्यवहार में लाया गया जिसको लोग स्वर्ण विनिमयमान (Gold exchange standard) कहते हैं। इस पद्धति की निम्न विशेषतायें हैं:- देश में सोने का सिक्का नहीं चलता और न प्रतिनिधि पत्रमुदा। सांकेतिक सिक्का कम कीमती धातुओं के सिक्के तथा पत्रमुद्रा का ही चलन होता है। देश की प्रामाणिक मुद्रा को एक निश्चित दर पर स्वर्णचलनमान अथवा स्वर्णपाटमान वाले देश की मुद्रा से जोड़ दिया जाता है और व्यवहार में कवल विदेशी भुगतानों के लिये विदेशी विनिमय रूप में सिक्का दिया जाता है और इसी प्रकार विदेशी भुगतान भी किसी स्वीकृत विदेशी मुद्रा में ही स्वीकृत किये बाते हैं। संदेप में इस मान के अन्तर्यंत सोने का उपयोग न तो विनिमय माध्यम के रूप में होता है और न मूल्यमान के रूप में। परोव्हरूप से कीमत स्तर सोने की कीमतों द्वारा ही निश्चित किया बाता है।

स्वर्ण विनिमय मान के निम्नांकित गुण हैं-

इस मान के द्वारा किसी शक्तिशाली स्वर्णमुद्रा के साथ देश की मुद्रा को जोड़कर कम सोने वाला एक निर्धन देश भी स्वर्णमान के सब लाभों को प्राप्त कर सकता है। विदेशी विनिमय दर को नियंत्रित करके विदेशी विनिमय दर स्थिर रक्खी जा सकती है। यदि देशी मुद्रा को जोड़ने वाली विदेशी मुद्रा का उचित चयन किया जाय तो विदेशी भुगतानों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रहती। चूँ कि इस मान के अन्तर्गत सोना न बाहर भेजा जाता है और न बाहर से मँगाया जाता है इसिलये इसमें सोने के आयात तथा निर्यात सम्बन्धी खर्च बच जाते हैं। इसी प्रकार सिक्कों की विसावट से होने वाला व्यय भी बच जाता है। सोना सुरच्चित कोशों में वेकार नहीं रहता। उसका उपयोग मुद्रा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में किया जा सकता है। इस मान में सरकार को कुछ आय भी हो जाती है। विदेशों में रक्खे जाने वाले निर्मेगों को विनियोग करने से कुछ व्याज प्राप्त होता है। विदेशों विनिमय खरीदने तथा वेचने की दरों में अन्तर रखकर भी कुछ लाम कमाया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वर्णमान संचालन सम्बन्धी सारा उत्तरदायित्व विशेषकर विदेशी सरकार के ऊपर होता है जिसकी मुद्रा से देशी मुद्रा का सम्बन्ध जोड़ दिया जाता है। देश की सरकार को तो केवल विदेशी विनिमय दर की स्थिरता पर ही ध्यान देना पड़ता है।

स्वर्ण विनिमय मान के दोष

इस मान के सफल संचालन के लिये विदेशों से मौद्रिक सम्बन्ध ऋधिक धनिष्ठ करना पड़ता है जिससे कठिन परिस्थितियों में इस मान के टूट जाने का भय रहता है। देश को मौद्रिक नीति में सम्बधित विदेशी मौद्रिक नीति के सहारे चलना पड़ता है ऋौर यदि जिस देश से मौद्रिक सम्बन्ध जोड़ा गया है वह स्वर्णमान का परित्याग कर दे तो सम्बन्धित देशों की सुद्रात्रों की परिवर्तनशीलता अपने आप समाप्त हो जाती है। जिस देश की सुद्रा से विभिन्न देशों की सुद्राएँ सम्बन्धित की जाती हैं उस देश की मुद्रा प्रणाली कुछ सीमा तक असुरिवत हो जाती है। उस देश के पास सोने का कोष तो सीमित होता है परन्त सोने की माँग अधिक हो जाने की सम्भावना रहती है। ऐसी अवस्था में उस देश की मुद्रा-प्रणाली ही अस्तव्यस्त हो सकती है। इस मान के अन्तर्गत तरल आदेशों Liquid Assets) का एक देश से दूसरे देश को इस्तान्तरण में कठिनता होती है। इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन को बनाये रखना भी कठिन हो जाता है। यह प्रणाली इतनी कठिन है कि जन साधारण की समभा में सरलता से नहीं आती । जनता इस पर विश्वास कठि-नाई से करती है। जनता को सदैव यह शंका बनी रहती है कि कहीं इस प्रकार की मुद्रा चलन से बाहर न हो जाय तो उसके पास कोई क्रय-शक्ति ही न रहे। इस प्रणाली के अन्तर्गत कभी-कभी अधिक कोषों के रखने की आवश्यकता होती है। यह

स्वयं संचालक नहीं होती। इस प्रकार के मान में मुद्रा की पूर्ति भी श्रिधिक लोचदार नहीं होती।

हिल्टन यंग कमीशन ने स्वर्ण विनिमय मान के ब्यावहारिक परिचालन की बाँच करते समय कुछ दोषों का वर्णन किया था कि यह प्रणाली जनसाधारण की समक्त से परे हैं। ब्रत्यधिक सिद्धांतों पर निर्भर रहने के कारण जनता का विश्वास नहीं जमने पाता। भारत में ब्रानेक कोषों का निर्माण।हो गया था जैसे स्वर्णमान कोष, पत्र-मुद्रा कोष। इसका परिचालन विदेशी चलन पर निर्भर हो जाता है ब्रोर इसमें ब्रावश्यक लोच की भी कमी है।

स्वर्णे समता प्रणाली (Gold parity standard)

यह स्वर्ण समता मान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंतर्गत स्थापित हुआ माना बाता है। यह स्वर्णमानों का एक नवीनतम परिष्कृत रूप है। इस मान के आंतर्गत मुद्रा अधिकारी राष्ट्र की मुद्रा की विदेशी विनियम दर एक निश्चित स्वर्ण राशि के बराबर स्थायी रखने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है।

स्वर्णमान का संचित्र इतिहास

१६ वीं शतीब्दी में चाँदी की कीमतों में इतने अधिक परिवर्तन हुए कि रजतमान अपनाना असम्भव हो गया। अतः स्वर्णमान ही का प्रचलन रहा। १६१४ ई०
से पूर्व समस्त स्वर्णमान वाले देशों में स्वर्ण मुद्रा मान प्रचलित था। इसमें स्वर्ण
मुद्रा-मान की सभी विशेषताएँ पाई जाती थीं। इसी समय कुछ देशों में स्वर्णविनिमयमान भी चलन में था विशेषकर उन देशों में जहाँ स्वर्ण-कोष कम थे। उदाहरगार्थ भारत, हालैंड, डेन्मार्क, हंगरी आदि देश थे। स्वर्ण-विनिमय मान भारत में
सन् १६०७-८ में स्थापित किया गया और १६१७ तक प्रचलित रहा। आंतरिक
उपयोग के लिए चाँदी का रुपया प्रामाणिक सिक्का था जो विदेशी व्यापार के लिए
स्टिलंग में १ शि० ४ पें० प्रति रुपया के हिसाब से परिवर्त्तनशील था। युद्ध काल
तक स्वर्ण मुद्रा मान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर सफलतापूर्वक चलता रहा।
परन्तु प्रथम युद्ध के प्रारम्भ होते ही देशों ने सोने का संचय प्रारम्भ कर दिया और
आयात-निर्यात पर प्रतिवन्घ लगा दिये गये। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के
लिए सभी देशों ने स्वतन्त्र रूप से पत्र-मुद्रा को चालू कर दिया और अंत में स्वर्णमान व्यवस्था जीर्ण-शीर्ण हो गई।

युद्ध समाप्ति पर ब्र्सेल्स में सन् १६२० में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन आयो-तित किया गया जिसमें स्वर्णमान पुनः स्थापित करने पर जोर दिया गया । आर्थिक पुनर्निर्मास के लिए भी मुद्रा-मूल्यों में स्थिरता होना आवश्यक थी । अमेरिका ने स्वर्स के आयात-निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटा कर इस और प्रथम कदम बढ़ाया। १६२७ में भारत में भी यह अपनाया गया । इस पुनर्स्थापना का उद्देश्य युद्ध-पूर्व जैसी आर्थिक व्यवस्था कायम करना था । इस पुनर्स्थापना में प्रत्येक देश की अलग-अलग समस्याएँ थीं । युद्ध-रत देशों—इंगलैंड, फांस, बर्मनी में—मुद्रा प्रसार हो गया, श्रतः इन देशों ने स्वर्ण-धातु मान अपनाया । परन्तु परस्पर देशों में पुरानी मौद्रिक सह्योगिता समाप्त हो जाने से स्वर्णमान की सफलता में भीषण कठिनाइयाँ आती गई । व्यापार पर प्रतिबन्ध लगने लगे और धीरे-धीरे इंगलैंड, अमेरिका और फांस आदि देशों ने इस मान को १६३६ ई० तक छोड़कर संसार से समाप्त कर दिया ।

स्वर्णमान में स्वयं-संचालकता के लिए कुछ गुण स्त्रावश्यक हैं जैसे:—
(१) स्रांतर्राव्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबन्ध न हो स्रन्यथा व्यापार शेष (balance of trade) में उचित दिशा में परिवर्तन नहीं होता । इधर स्वर्ण का वितरण भी प्रत्येक देश की स्रावश्यकतानुसार हो जाता है स्त्रीर मुद्रा का प्रसार भी कोष के स्ननुरूप ही हो पाता है। (२) स्वर्ण के स्त्रायात-निर्यात के कारण देश के मूल्य पर जो प्रभाव पड़ता है उसको स्वयं ठीक होने देना चाहिए। (३) सरकार देश में शांति स्त्रीर सुरचा बनाये रखे ताकि मुद्रा को गाड़ने की (hoarding) प्रवृत्ति कम हो सके। स्वर्ण-मान समाप्त हो जाने के निम्न कारण थे —

- (१) स्वर्ण के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाकर तथा व्यापार शेष में सरकार द्वारा परिवर्त्तन करके स्वर्णमान के नियमों का पालन नहीं किया गया । इससे स्वर्ण अमरीका, फांस आदि कुछ देशों में ही एकत्रित हो गया ।
- (२) युद्ध काल की जर्जरित एवं भावी युद्ध से सुरिक्ता के लिए आर्थिक व्यवस्था करना आवश्यक हो गया । इससे आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये गए । संरक्त्या एवं प्रशुल्क नीति अपनाई जाने से भी स्वर्णमान को धक्का लगा ।
- (३) स्वर्णपाटमान ऋौर स्वर्ण विनिमय मान के ऋपनाने से स्वर्णमान का संचालन ऋगसानी से न हो पाया ऋौर स्वयं-संचालकता के गुण जाते रहे।
- (४) बैकों के विकास ने साख मुद्रा को विकिसत किया जिसके फलस्वरूप सरकार को मुद्रा नीति में इस्तच्चेप करना पड़ा और प्राचीन मान में शिथिलता आ गई।
- (५) युद्धोत्तर काल की राजनैतिक चालों ने भी स्वर्णमान को तोड़ने में सहायता दी। अमेरिका ने युद्ध-रत परास्त देशों से हर्जाना वसूल करना प्रारम्भ कर दिया जिससे डॉलर की माँग बढ़ गई और देश स्वर्णमान को छोड़ने के लिए बाध्य हो गये ताकि विनिमय दर स्थिर रख सकें। इस प्रकार आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस मान का परित्याग कर दिया गया।
- (६) स्वर्णमान अपनाने से मूल्यों में एकरूपता आ गई। यदि कोई देश अपने यहाँ मुद्रा प्रसार या संकुचन करने लगा तो उसका कुप्रभाव सभी देशों पर

पड़ता था। इससे भी देशों ने स्वर्णमान अपनाना परिस्थितियों का दास बनना समका और वे मुक्ति प्राप्त करने लगे।

(७) सबसे गहरा कुप्रभाव महान् अवसाद (Great Depression) का पढ़ा। अमरीका के वाल-स्ट्रीट संकट (१६२६ई०) ने संसार भर में मन्दी, निराशा एवं अति-उत्पादन की भावना फैला दी जिसके परिणामस्वरूप दूसरे स्वर्णमान वाले देशों ने सुरक्षा के लिए, इस मान को छोड़ना प्रारम्भ कर दिया।

परन्तु फिर भी स्वर्णमान का महत्व भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि स्वर्ण ने अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के माध्यम तथा मूल्यमान का काम किया है और इस प्रकार क्यापार के विस्तार की दशाएँ उपस्थित की हैं। दूसरे स्वर्ण ने विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता लाने में भी सफलता प्राप्त की है क्योंकि इस घातु के स्वयं का मूल्य अधिक षटता-बढ़ता नहीं। अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी अधिक अन्तर नहीं रह बाता।

श्रवः प्रश्न उठ सकता है कि क्या स्वर्णमान पुनः स्थापित किया जा सकता है श्रव स्वर्णमान की सफलता के लिए जो दशाएँ लिखी जा चुकीं उनका पालन करना किन जान पड़ता है । काउदर (Crowther) का कथन है कि "स्वार्थी क्यापारिक प्रणाली के सहारे चल कर किसी भी प्रकार की श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली चाहे वह राष्ट्र के हित में ही क्यों न हो, सफल नहीं हो सकती ।" कीन्स भी इसी विचार से मिलते-जुलते शब्द लिखते हैं कि स्वर्णमान स्थापित होना, श्रव श्रयम्भव-सा है, कारण कि मूल्यों की श्रास्थरता के कारण स्वर्ण में मुद्रा-चेत्र ने श्रपनी प्रियता सो दी हैं। श्रवः पत्र-मुद्रा मान ही नियन्त्रित रूप में सम्भव है । जब तक स्वर्णमान को सारे देश स्वीकार नहीं कर लेते, स्वर्णमान कोषों का ठीक वितरण नहीं होता, मुद्रा स्थित की नीति एवं संरच्ण नीति का परित्याग नहीं किया जाता, श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रयों को मात्रा कम नहीं होती, श्रीर देशों में राजनैतिक स्थिरता कायम नहीं होती, तब तक स्वर्णमान की स्थापना का विचार एक स्वप्न मात्र ही रहेगा।

श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भुगतानों की सुविधा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से १६४४ ई० अन्तर्राष्ट्रीय सुदा कोष (International Monetary Fund) तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास वैंक (International Bank for Reconstruction and Development) की स्थापना की गई है, जिसके अनुसार स्वर्ण को अब भी आधारिक महत्व (basic importance) दिया गया है—(१) सदस्य देश को अपने अंश का निश्चित प्रतिशत स्वर्ण में जमा करना होता है। (२) सदस्य देश को अपनी मुद्रा की कीमत सोने में बतानी पड़ती है जिसके आधार पर विनिमय दर निर्धारित होती है। (३) कोष (IMF) किसी मुद्रा को सोना देकर खरीद सकता है।

रजत-मान (Silver standard)

इस मान में स्वर्ण के स्थान पर चाँदी का प्रयोग होता है। अन्य सभी नियम स्वर्णमान के ही रहते हैं। चीन काफी समय तक रजत मान अपनाये रहा। भारत में यह मान १८३५ से १८६३ ई० तक चलन में रहा। परन्तु वाद में चाँदी की मात्रा बढने से, माँग कम होने से, चाँदी की कीमतें गिरने लगी। हरशेल समिति की सिफारिशों पर सन् १८६३ ई० में रजत मान समाप्त कर दिया गया।

प्रश्न

- 1. Describe fully the gold standard (Agra, B. A, 1957)
- २. स्वर्ण मान तभी अच्छी प्रकार सफल हो सकता है जब कि वह वास्तव में स्वर्ण मान हो जिससे प्रत्येक देश The rules of gold standard के अनुसार कार्य करता रहे ताकि मुद्रा मान से किसी को अविश्वास न हो सके। इस कथन की व्याख्या की जिए।

(आगरा, बी. ए. १६५६)

२. स्वर्ण विनिमय मान का मंचित वर्णन की जिये । इसके अवगुर्णो पर प्रकाश डालिए । (वी. ए. १६५४, आगरा वि•)

अध्याय ५

पत्र-मुद्रा-चलन

(Paper Currency Standard)

कागज का त्राविष्कार एवं कागजी मुद्रा का प्रारंभ सर्वप्रथम चीन में हुन्ना । ६ वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीनो सम्राट ईसेनटुंग (Isientung) के समय पत्र-मुद्रा का चलन हुन्ना। घीरे-घीरे यह मुद्रा एशियाई देशों में स्थान पाती गई न्नौर १७ वीं शताब्दी के न्नंत में परिवर्त्तनशील पत्र-मुद्रा एवं १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सरकारी न्नानानुसार न्नपरिवर्त्तनशील पत्र-मुद्रा संसार में चलने लगी। इन नोटों का न्नानार-प्रकार, रंग न्नादि विभिन्न देशों में विभिन्नता लिए हुये थे। प्रथम महायुद्ध में पत्र-मुद्रा को प्रोत्साहन मिला, इधर स्वर्णमान के टूटने पर भी न्नप्रधिकांश देशों ने पत्र मुद्रा चलन को ही न्नपनाया। द्वितीय युद्ध काल में तो पत्र-मद्रा चलन को न्नाश्चर्यजनक प्रोत्साहन मिला।

पत्र-मुद्रा के लाभ (Merits of paper money)

पत्र-मुद्रा की लोकप्रियता सर्वव्यापी है। यह लोकप्रियता इस चलन में निहित लामों के कारण है जिनको इस प्रकार गिनाया जा सकता है—

- (१) मूल्यनान घातु की बचत कागजी मुद्रा के चलन से केवल बहुमूल्य घातु की आवश्यकता ही कम नहीं हुई अपितु इस बचो हुई (सोने-चाँदी) घातु को देश के अन्य मौतिक एवं कलात्मक कार्यों में अधिक उपयोगी बनाने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। घातु मुद्रा के चलन से ट्रट-फूट में जो राष्ट्रीय चृति होती थी वह दूर हुई है।
- (२) स्थानांतर की सुविधा—मूल्य के अनुपात में कागजी नोटों का भार बहुत ही कम होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को अधिक सुविधानुसार एवं सुरचापूर्य ते जाये जा सकते हैं।
- (३) मितव्ययता—पत्र-मुद्रा के उत्पादन में व्यय घातु मुद्रा की ऋषेत्वा बहुत ही कम पहता है। इस प्रणाली में घातु को निकालना, साफ करना, गलाना तथा दालना ऋषिद कार्यों पर बिल्कुल ही व्यय नहीं होता। कागजी-मुद्रा में तो केवल छपाई का योदा सा व्यय रहता है। इस प्रकार इसमें पूँजी ऋषेर अम दोनों की बचत होती है जिन्हें ऋन्य उपयोगी कार्यों पर लगाया जा सकता है।
- (४) लोच (Elasticity)—पत्र मुद्रा प्रणाली में त्रावश्यक लोग पैदा करने का महत्वपूर्ण गुण होता है! सोने-चाँदी के सिक्कों को माँग के अनुसार-

घटाने-बढ़ाने में पर्याप्त व्यय एवं हानि का सामना करना पड़ता है परंतु पत्र-सुद्रा में चलन आसानी से न्यूनाधिक किया जा सकता है।

- (५) संकटकालीन मित्र जब स्वर्णमान अञ्छे मौसम का मित्र है तो पत्र मुद्रा संकटकालीन मित्र अवश्य मानी बानी चाहिए; क्यों कि संकट काल (युद्ध अथवा मंदी) में सरकार कागजी नोट द्वाप कर अपनी आय प्राप्त कर लेती है।
- (३) अन्य लाभ—इन लाभों के अतिरिक्त अन्य लाभ भी हैं जैसे पत्र मुद्रा के गिनने एवं सम्हाल कर रखने की सुविधा रहती है। पत्र मुद्रा की समानता एवं एकरूपता एक विशेष गुण है जिससे कि निश्चित मूल्य की मुद्रा आसानी से पहिचानी जा सकती है।

पत्र-मुद्रा की हानियाँ—(Evils of paper money)

जहाँ पत्र मुद्रा से अपनेक लाभ हैं वहाँ इससे अर्थ व्यवस्था जनता में दोष उत्पन्न होने का भय भी सदैव बना रहता है। इन हानियों एवं दोषों को निम्न प्रकार से देख सकते हैं।

- (१) जनता के विश्वास की कभी—पत्र मुद्रा में केवल वाह्य मूल्य (Face Value) ही होती है आंतरिक मूल्य (Intrinsic Value) नहीं। उसका चलन बंद होते ही कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता। अतः जनता की इस पत्र-मुद्रा में कम विश्वास रहता है।
- (२) मुद्रा प्रसार का भय—सरकार श्रपनी इच्छानुसार किसी भी मात्रा में नोट छपवा सकती है। कोष इत्यादि रखने के सख्त नियम नहीं होते श्रौर श्रपिर-वर्तनशील मुद्रा में तो यह मात्रा बिल्कुल ही श्रप्रतिवंधित होती है। इस प्रकार इस चलन में मुद्रा प्रसार का भय सदैव बना रहता है जिसके भयानक परिखाम जनता को भोगने पड़ते हैं। जर्मनी में युद्ध काल में भीषण मुद्रा प्रसार हो गया था श्रौर वहाँ की श्रर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी।
- (३) नष्ट होने का भय-पत्र-मुद्रा का गलने, फटने, सड़ने एवं तेल लगने से खराब होने का भय सदा बना रहता है। फिर इसको सुरक्षा के लिए गाड़ भी नहीं सकते।
- (४) चलन का सीमित चेत्र—धातु मुद्रा एक निश्चित मृल्य पर विदेशी मुगतानों में काम त्राती है परंतु कागजी मुद्रा का चेत्र सीमित होता है उसका त्रांति रिक मूल्य कुछ भी नहीं होने के कारण दूसरे देशों में इसका मूल्य कुछ भी नहीं रहता।
- (४) मृ्ल्यों में श्रानिश्चितता—पत्र-मुद्रा वाले देश में मृ्ल्य स्तरों में उच्चा-वचन श्रिधक परिमाण में होते हैं जिससे देश की श्रर्थव्यवस्था सुदृद्ता नहीं पकड़ पाती श्रौर विदेशी विनिमय दरों में उथल-पुथल रहती है।

६. परिकल्पना (Speculation) को प्रोत्साहन—पूँजीयादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में पत्र-मुद्रा एवं साख-मुद्रा की निकासी की अनियमितताएँ एवं अनि-श्चितताएँ व्यापारिक चक्रों (Trade Cycles) के मुख्य कारण हैं। एक अर्थशास्त्री के विचार में कोई भयंकर से भयंकर बीमारी किसी व्यक्ति को जितना अधिक से अधिक कष्ट दे सकती है, उससे भी अधिक कष्ट पत्र-मुद्रा के कारण समाज को होता है।

परंतु उपरिलिखित दोषों में ऋधिकांश दोष स्वयं पत्र-मुद्रा के न होकर पत्र-मुद्रा के व्यवस्थापकों एवं सरकार के कारण हैं। किसी वस्तु की ऋच्छाई-बुराई उसके उपयोग करने वालों पर निर्भर करती है। पत्र मुद्रा को समुचित व्यवस्थित कर एवं नियंत्रण में रख कर ऋविकसित एवं ऋर्द्ध विकसित देशों की ऋार्थिक व्यवस्था को उन्नतशील बनाने तथा समाज को ऋधिक कल्याणकारी बनाने में उपयोगी बनाया जा सकता है।

पत्र-मुद्रा मान (Paper standard or currency exchange standard)

पत्र-मुद्रा-मान में किसी घातु-मुद्रा को आधार नहीं बनाया जाता। देश में अपरिवर्त्तनीय पत्र-मुद्रा का चलन रहता है और यही देश की प्रामाणिक मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होती है। यह मुद्रा अपरिभित विधिग्राह्य होती है। चलन की पूर्ति को उसकी मांग के बराबर बनाये रख कर कीमतों की स्थिरता मुरित्ति रखी जाती है। परंद्र विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण कोष की आवश्यकता रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोष की स्थापना से यह आवश्यकता भी दूर हो गई है।

प्राद्घ्य मान (Fiat standard) को कभी-कभी नियंत्रित पत्र चलन मान (Managed paper currency standard) भी कहते हैं। इसमें मुद्रा का द्यांतरिक मूल्य कुछ भी नहीं होता, यह अपरिवर्त्तनीय रहती है। क्रय-शक्ति भी किसी धातु पर आधारित नहीं होती। लोगों का विश्वास है कि संकट काल में तो पत्र मुद्रा से ही नहीं अपितु सरकार पर से और धातु मुद्रा पर से भी विश्वास हटने लगता है। अतः प्रादिष्ट मान को एक स्थायी रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि देश के मानवीय एवं मौतिक साधनों का पूर्ण विकास हो सके।

एक आदर्श पत्रमुद्रा चलन प्रणाली में निम्नलिखित लच्चणों का होना आवश्यक है—

- (१) विश्वास (Confidence)—पत्रमुद्रा में जनता का विश्वास होना स्त्रानवार्य है। इस विश्वास के लिये पत्र मुद्रा को परिवर्त्तनशील बनाये रखने के लिये इसके आधार में उचित मात्रा में धातुक निधि रैक्खी जानी चाहिये।
- (२) परिवर्त्तनशीलता (Convertibility)—इसके श्रनुसार पत्र-मुद्रा हर समय व्यक्ति के इच्छानुसार भातु श्रयना घातु मुद्रा में परिवर्तित हो जानी चाहिये। यह तमी सम्मव है जब यह उचित घातु निधि पर श्राधारित हो।

- (३) चलनाधिक से रिच्चित (Security against over-issue)—ग्रार्थात् पत्रमुद्रा का चलन ऐसा न हो कि जिसमें पत्र मुद्रा निर्गमनक संस्था पर पूर्ति की मात्रा के बढ़ाने में किसी प्रकार की रोक न लगा सके। यदि पत्रमुद्रा सरकार ऋथवा बैंक द्वारा इच्छापूर्वक कितनी भी मात्रा में बढ़ाई जा सके तो फिर चलनाधिक का भय सदैन बना रहता है। इस प्रकार की पत्रमुद्रा में जनता में विश्वास नहीं होता। उसका कोई मूल्य भी नहीं रहता। इसके लिये भी उचित मात्रा में घात्तुक निधि का रखना ऋनिवार्य है।
- (४) लोच (Elasticity)—पत्रमुद्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसका निर्गमन घातु मुद्रा के समान ब्रालोचदार न रहे। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है घातु मुद्रा की पूर्ति घातु की मात्रा पर निर्भर होती है ब्रौर मुद्रा की माँग इतनी ब्राधिक हो सकती है कि उसकी पूर्ति के लिये पर्याप्त मात्रा में घातु प्राप्त न हो सके। इसी दोष को मिटाने के लिये पत्रमुद्रा का चलन प्रारम्भ हुत्रा था। इसीलिये पत्रमुद्रा का लोचदार होना एक मुख्य लच्चण माना गया है। यह तभी सम्भव है कि पत्रमुद्रा चलन के ब्राधार रूप घात्विक मुद्रा की निधि इतनी रहे कि जिसके ब्राधार पर पत्रमुद्रा चलन में पर्याप्त लोच रक्खी जा सके। इस गुण को बनाये रखने के लिये इस बात का भी ध्यान रखना ब्रावश्यक है कि चलनाधिक के दोष की सम्भानवना न हो जाय।
- (४) मितव्ययता (Economy) पत्रमुद्रा चलन मितव्ययी होना चाहिये । एक प्रकार से पत्रमुद्रा स्वयं मितव्ययी है इससे घातु की बचत तथा उसके विसावट की बचत होती है और इसका संचालन व्यय भी घातु मुद्रा संचालन व्यय से कम रहता हैं। काग़ज़ी नोट छापने में इतना व्यय नहीं होता जितना घातु के सिकके ढालने में। इसके अतिरिक्त पत्रमुद्रा की अधिक मितव्ययी बनाने के लिये दो अन्य बातों का ध्यान भी रखना आवश्यक हैं। इसके लिये इस प्रकार का कागज निर्मित किया जाय जो अपेचाकृत अधिक समय तक टिकाऊ रहे। जिससे थोड़े ही चलन में वह खराब न हो जाय नहीं तो खराब पत्रमुद्रा के बार-बार बदलने में व्यय बढ़ जायगा। दूसरी बात पत्रमुद्रा के मुद्रग्-विधि को भी मितव्ययी बनाना आवश्यक है। इसके छापने का खर्च कम से कम होना चाहिये। इसके लिये पत्रमुद्रा के आकार-प्रकार तथा डिज़ाइन आदि पर ध्यान देना आवश्यक है।

पत्र-मुद्रा संचालक-संस्था

ऋर्थशास्त्रियों का इस बात पर बहुत समय से मतभेद चला आ रहा है कि पत्र-मुद्रा का संचालन किसके ऋषिकार में रहे। इसका संचालन केवल सरकार द्वारा हो ऋथवा देश के विभिन्न बैंकों द्वारा ऋथवा केवल केन्द्रीय बैंक द्वारा। जहाँ तक विभिन्न बैंकों का सम्बन्ध है प्रायः सब ऋर्थशास्त्री एक मत हैं कि पत्र-मुद्रा संचालन का श्रिधिकार विभिन्न वैंकों को नहीं दिया जाना चाहिये। एक तो इन बैकों का चेत्र सीमित होता है दूसरे ये बैंक आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जिसके कारण पत्र-मुद्रा की पूर्ति त्रावश्यकता से अधिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये बैंक पत्रमुद्रा संचालन सम्बन्धी नीति इस प्रकार अपना सकते हैं कि विभिन्न नीतियाँ विरोधात्मक हो जायँ। इन बैंकों के द्वारा सम्पूर्ण देश में पत्र मुद्रा सम्बन्धी एक-सी नीति का पालन नहीं हो सकता। भिन्न-भिन्न वैंकों द्वारा संचालित पत्रमद्रा विभिन्न प्रकार की होने के कारण श्रासानी से नहीं पहचानी जा सकती। इस प्रकार की पत्रमुद्रा के लिये विभिन्न बेंकों के द्वारा सुरिवत निधि की मात्रा भी अधिक होगी तथा विभिन्न बैंकों द्वारा पत्रमद्रा संचालन में नियंत्रण अथवा निरीच्चण की भी सुगमता नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग केन्द्रीयकरण का युग है, अतः पत्रमुद्रा के संचालन में केन्द्रीय संस्था ही अधिक उपयुक्त होगी। उपरोक्त कारणों से देश के विभिन्न बैंकों द्वारा पत्रमुद्रा के संचालन के पत्त में विरले ही विशेषज्ञ हैं। प्रायः सभी विद्वान यही स्वीकार करते हैं कि यदि पत्र मुद्रा संचालन का अधिकार बैंकों को दिया जाय तो देश की एक ही बैंक को दिया जाना चाहिये। विशेषकर उस बैंक को जो केन्द्रीय वैंकों के कर्त्तव्यों का पालन करे। पत्र मुद्रा संचालन का कार्य एकाधिकारी की कोटि में होना ही श्रेयस्कर है।

यह स्वीकार करने पर कि पत्रमुद्रा के संचालन में किसी भी संस्था का एका-धिकार होना स्रावश्यक है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि यह एकाधिकार सरकार को अयवा केन्द्रीय बैंक को मिले । इस प्रश्न पर अर्थशास्त्रियों में काफी विवाद हुआ है श्रीर दोनों पत्त के अर्थशास्त्री अपने मतों के समर्थन में प्रवल तर्क का सहारा लेते है। सरकार द्वारा पत्र मुद्रा संचालन का समर्थन करने वाले विद्वान इस बात पर बहुत बल देते हैं कि जनता का विश्वास सरकारी पत्रमुद्रा में ही ऋधिक हो सकता है क्योंकि इस प्रकार के पत्रमुद्रा की परिवर्तनशीलता स्थापित रखने के लिये देश की सम्पूर्ण सम्पत्ति निधि के रूप में रहती है। त्रातः सरकारी पत्र मुद्रा त्राधिक सुरच्चित है। इसके साथ ही साथ सरकार पत्रमुद्रा का चलन सीमित ही रक्खेगी नहीं तो पत्रमुद्रा के परिवर्तनशीलता में कठिनाई आ सकती है। सरकारी पत्रमुद्रा संचालन राष्ट्रीय-करण तथा समाजवाद के सिद्धान्तों के अनुरूप है। वर्तमान समय में लोगों का अकाव उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की त्रोर है। इसी प्रकार जनता समाजवादी त्र्यार्थिक व्यवस्था को अधिक चाहती है। सरकार द्वारा पत्रमुद्रा संचालन से इस उद्योग का राष्ट्रीय-करण स्वयं ही हो जाता है तथा इसके साथ ही साथ पत्रमुद्रा संचालन से लाभ सरकारी कोष में जायगा जो जनता ही में व्यय किया जायगा। यह समाजवादी श्रार्थिक व्यवस्था का एक मुख्य लच्चण है, इसलिये सरकारी पत्रमुद्रा संचालन श्राध-निक विचारधारा के अनरूप है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी पत्र मुद्रा का संचालन सरकार द्वारा ही होना चाहिये क्योंकि प्राचीन समय में मुद्रा पूर्ति का कार्य सरकार के ही हाथ में रहा है। यही व्यवस्था पत्रमुद्रा के लिये भी उपयुक्त होगी। त्राजकल त्रार्थिक योजनात्रों का युग है। त्रार्थिक योजनात्रों का संचालन सरकार द्वारा ही होता है। इन योजनात्रों की सफलता के लिये उचित परिमाण में मुद्रा चाहिये त्रौर उसी के त्रमुख्य देश की मौद्रिक नीति होनी चाहिये। देश की मौद्रिक नीति तथा योजना सम्बन्धी नोति में पूर्ण रूपेण सामझस्य तभी हो सकता है जब योजना संचालन तथा पत्र मुद्रा संचालन दोनों कार्य सरकार द्वारा ही किये जायँ।

इसके विपरीत दूसरे पच्च के अर्थशास्त्रियों का यह कथन है कि सरकारी काम 'पायः शिथिलतापूर्वक होते हैं। सरकार की निजी ऋाधिक ऋावश्यकताएँ होती हैं। उन त्रावश्यकतात्रों की पूर्ति के लिये जनहित का विशेष विचार न करके सरकार अधिक पत्रमुद्रा का प्रसार कर सकती है। सरकार का देश के व्यापारी वर्ग से किसी प्रकार का प्रत्यव सम्बन्ध नहीं होता इस कारण समाज को ऋार्थिक क्रियाऋों के लिये कितनी पत्रमुद्रा की स्रावश्यकता है सरकार ठीक-ठीक रूप, से नहीं जान सकती, इसका ठीक ऋनुमान तो बैंक ही लगा सकता है, जिसका ब्यापारी वर्ग के साथ प्रत्यन्त सम्बन्ध होता है। बैंक श्रौद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र से धनिष्ठ सम्बन्ध रखने के कारण मुद्रा की माँग की दशास्त्रों का स्रच्छी प्रकार से ज्ञान रखता है स्त्रौर इसी हिसात्र ते यह पत्रमुद्रा का संक्रचन अथवा प्रसार कर सकता है। इस प्रकार बैंक द्वारा निर्मित पत्रमुद्रा त्रिधिक लोच वाली होती है। जहाँ तक सुरिच्ता तथा परिवर्तनशीलता का -सम्बन्ध है सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिनके कारण पत्रमुद्रा निर्गमन करने वाले बैंक को समुचित रूप में निधि रखने के लिये बाध्य होना पड़े। ऋौर यही बैंक -सरकार को भी त्रावश्यकता पड़ने पर यथोचित मात्रा में इस प्रकार पत्रमुद्रा दे सकती है कि उससे मुद्रा प्रसार की बुराइयाँ न आने पावें। वास्तव में दोनों पत्तों के न्तर्कों को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा निर्गमन ऋधिक हितकर प्रतीत होता है। यदि पत्र मुद्रा संचालन का ऋधिकार केन्द्रीय बैंक को दिया जाय तो देश के मुद्रा तथा साख बाजार पर अधिक सफलतापूर्वक नियंत्रण रक्खा जा सकता है। इससे बैंक द्वारा निर्मीमत पत्र मुद्रा के सम्पूर्ण लाभ समाज को प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि केन्द्रीय वैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया नाय तो सरकारी पत्र मद्रा के लाभ भी समाज को प्राप्त हो सकेंगे।

वास्तव में इस प्रश्न पर विवाद ऋब केवल सिद्धान्त की दृष्टि से महत्वपूर्ण रह गया है व्यवहार में पत्रमुद्रा संचालन का पूर्ण ऋषिकार प्रायः राष्ट्रीयकृत केन्द्रीय बेंक को ही दिया जाता है। यह प्रथा श्रम विभाजन सिद्धान्त के ऋाधार पर भी उचित है। सरकारी मशीनरी तथा ऋषिकारी राजनैतिक व प्रशासकीय चेत्र में ही ऋनुभवी तथा ऋषिक कार्यच्चमता वाले हो सकते हैं ऋार्थिक चेत्र में नहीं। विशेषकर मौद्रिक चेत्र के लिये तो बेंक ही उपयुक्त संस्था है। ऋतः पत्रमुद्रा संचालन का एकाधिकार केन्द्रीय बेंक को ही दिया जाना चाहिये।

पत्र-मुद्रा सिद्धांत (Principles of note issue)

पत्र-मद्रा चलन के सम्बन्ध में दूसरा विवादास्पद विषय इसके सिद्धान्त के बारे में है कि इसका चलन किस सिद्धान्त पर श्राधारित हो। इस सम्बन्ध में दो महान्त ग्राभी तक प्रतिपादित किये गये हैं। प्रथम - करंसी सिद्धान्त । द्वितीय-बैंकिंग सिद्धान्त । प्रथम सिद्धान्त के अनुसार पत्र-सुद्रा को पूर्णरूप से सुरक्षित करने के लिये यह ब्रावश्यक है कि निर्गमित पत्र-मुद्रा के मूल्य के बराबर धात में निधि रक्सी जाय। पत्रमदा चलन में वृद्धि अथवा कमी के साथ ही साथ घात्विक निधि में भी कभी अथवा वृद्धि आवश्यकतानुसार होती रहनी चाहिये। इस सिद्धान्त के समयकों का यह कथन है कि पत्रमुद्रा का वास्तविक उद्देश्य सोने-चाँदी की बचत करने का है। सोने-चाँदी की विसावट श्रादि की हानि से बचने का है तथा साथ ही साथ मदा संचालन व्यय में कमी होने का है। यह तभी सम्भव है जब पत्रमद्रा चलन में रहे और उसके मुल्य के बराबर बहुम ल्य धातुयें निधि में रक्खी रहें। इसके साथ ही साथ इसी सिद्धान्त के अपनाने से सरकार द्वारा अति सदा प्रसार का भय नहीं रहता। चलनाधिक्य से सुरचा तथा परिवर्तनशीलता इसी सिद्धान्त के श्राधार पर चालित मुद्रा में हो सकती है। परन्तु इस सिद्धान्त पर त्राधारित पत्रमुद्रा चलन में लोच का अभाव रहेगा। समाज की आर्थिक प्रगति के अनसार विनिमय कार्यों की बृद्धि के साथ ही साथ मुद्रा की मात्रा भी बढ़ती रहनी चाहिये। यदि पत्रमुद्रा का आधार बहमूल्य धात्यें रक्खी जाय तो पत्र मुद्रा चलन की वृद्धि बहमूल्य धात स्रों की पर्ति के त्राधार पर हो सकेगी न कि श्रावश्यकता के अनुसार।

उपरोक्त दोष को दूर करने के लिये अन्य अर्थशास्त्रियों का मत है कि पत्रमुद्रा चलन अधिकोषण िस्द्रान्त पर आधारित होनी चाहिये। इसके अनुसार निर्गमित पत्र मुद्रा के मूल्य के बराबर बहुमूल्य धातुओं को निधि में रखना आवश्यक नहीं है बहुमूल्य धातुओं का निधि में रखना पत्रमुद्रा की परिवर्तनशीलता को कायम रखने के लिये आवश्यक होता है पर किसी देश में चिलत सम्पूर्ण पत्रमुद्रा एक ही साथ बहुमूल्य धातु अथवा धात्विक मुद्रा में परिवर्तित नहीं की जा सकती। उसका कुछ भाग ही परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार की परिवर्तनशीलता चिलत पत्र मुद्रा के मूल्य से कम मूल्य की बहुमूल्य धातुओं को निधि में रखने से कायम रह सकती है। इसके साथ ही साथ इसी सिद्धान्त पर आधारित पत्रमुद्रा चलन में पर्याप्त लोच रह सकती है। अतः इस मतानुसार पत्रमुद्रा का चलन बैकिंग सिद्धान्त के आधार पर ही होना चाहिये। इस सिद्धान्त के अनुसार पत्रमुद्रा चलन में चलना-धिक्य का मय ही रह सकता है। वह भय सरकारी कान्तन द्वारा बहुत सीमा तक कम किया जा सकता है। पत्रमुद्रा चलन के मूल्य तथा रिच्त बहुमूल्य धातुओं के मूल्य में एक अनुपात निर्घारित किया जा सकता है जिससे पत्रमुद्रा निर्गमनक संस्था अत्य-धिक पत्रमुद्रा का प्रसार नहीं कर सकती।

इस प्रकार दोनों सिद्धान्तों में गुण व दोष हैं फिर भी श्राधुनिक समय में पत्रमुद्रा चलन को श्रिधिकोपण सिद्धान्त वालों का समर्थन ही श्रिधिकांश में प्राप्त है।
प्रायः सम्पूर्ण देशों में जहाँ-जहाँ पत्रमुद्रा का चलन है श्रिधिकोषण सिद्धान्त के श्राधार
पर ही पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। यह श्रवश्य है कि इसे सुरिच्चित परिवर्तनीय तथा श्रावश्यक लोचदार बनाये रखने के लिये घात्विक निधि के सम्बन्ध में
विभिन्न प्रणालियाँ श्रपनाई पई हैं। इनमें से कुछ प्रणालियाँ श्रपने उद्देश्य में श्रसफल रहती हैं तथा कुछ प्रणालियाँ सफल। यहाँ एक प्रश्न यह उठ सकता है कि
विभिन्न प्रणालियों में कौन-सी प्रणाली श्रथवा पद्धित किस देश विशेष को श्रपनानी
चाहिये। यह तय करने के लिये यह श्रावश्यक है कि हम पहले एक श्रादर्श प्रणाली
के लच्चण निश्चित कर लें तथा जिस प्रणाली में श्रिधिकतम लच्चणों का समावेश हो
सके वही प्रणाली श्रपनायी जानी चाहिए।

पत्रमुद्रा चलन की विभिन्न विधियाँ (प्रणाली व पद्धित) (Systems of note issue)—पत्र मुद्रा चलन की निम्नांकित प्रणालियाँ प्रचलित हैं—

- (१) निश्चित अधिकतम पत्रमुद्रा चलन पद्धित (Fixed maximum note issue)—इस पद्धित के अनुरूप सरकार कानून द्वारा पत्र मुद्रा चलन की एक सीमा निश्चित कर देती है जिससे अधिक पत्र मुद्रा नहीं चलाई जा सकती जब तक कि तत्स-म्बन्धी कानून में परिवर्तन न कर दिया जाय । इस प्रणाली के अन्तर्गत धात्विक निधि का कोई ध्यान नहीं रक्खा जाता । सरकार बैंक की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अधिकतम सीमा निर्धारित करती है । सरकार बैंक की साख को ध्यान में रखते हुये कि वह किस सीमा तक पत्र मुद्रा को परिवर्तनशील बनाये रख सकती है, उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित कर देती है । इस प्रकार की पत्रमुद्रा चलन पद्धित कुछ दिनों तक इंगलैंड में रही थी । इस पद्धित में लोच का अभाव रहता है क्योंकि निर्धारित सीमा से अधिक पत्र मुद्रा नहीं चलाई जा सकती और सीमा कानून द्वारा बार-बार नहीं बदली जा सकती ।
- (२) साधारण निध-पद्धति (Simple deposite method)—इसमें पत्र मुद्रा चलन के मूल्य के बराबर सोने या चाँदी में धात्विक निधि रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार की पत्रमुद्रा प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा कहलाती है। इस पद्धिति में लोच तथा भितव्ययता वा अभाव रहता है। इस प्रकार की पद्धति में पत्रमुद्रा आव-श्यकतानुसार नहीं बढ़ाई जा सकती। इसमें व्यय भी उतना ही बना रहता है। इस पद्धति में स्वरिद्धता तथा परिवर्तनशीलता का पर्याप्त लाभ रहता है।
- (३) न्यूनतम-निधि पद्भित (Minimum reserve method)—इस पद्भित के अन्तर्गत कान्न द्वारा निधि में रक्खे जाने वाले सोने-चाँदी की न्यूनतम सीमा निर्धाग्ति कर दी जाती है। इससे कम निधि नहीं की जा सकती चाहे पत्रमुद्रा

चलन में कितनी ही दृद्धि क्यों न कर दी जाय। इस पद्धित में लोच, मितव्ययता तथा परिवर्तनशीलता त्रादि' के सब गुरण पाये जाते हैं परन्तु यह पद्धित त्राधुनिक युग में प्रायः चलन में नहीं है। क्योंकि त्राजकल की बढ़ती हुई सुद्रा की माँग के कारण निधि की उचित न्यूनतम सीमा निधिरित करना कठिन है।

- (४) निश्चित विश्वसनीय निर्गमन प्रणाली (Fixed fiduciary note issue)—इस पद्धित के अनुसार किसी प्रकार की धात्विक निधिन रखते हुये एक निश्चित मात्रा में पत्रमुद्रा का चलन हो सकता है। परन्तु उससे अधिक 'चलन होने पर सोना या चाँदी में धात्विक निधि रखना अनिवार्य हो जाता है।
- (४) श्रांशिक निधि पद्धति (Proportional reserve method) इस पद्धिति के अनुसार पत्रमुद्रा चलन तथा धालिक निधि का अनुपात निश्चित कर दिया जाता है कि कितनी धालिक निधि अधिकोष में होनी चाहिये। यह निधि सरकार की अनुमति से कम या अधिक की जा सकती है। शेष पत्रमुद्रा चलन का भाग उतने ही मूल्यों के विनियोगों द्वारा सुरिच्चित किया जाता है। इस पद्धित में लोच तथा मितव्ययता के गुण होते हैं। चलनाधिक्य का भय नहीं होता। परिवर्त्तनशीलता कायम रहती है। इस पद्धित में एक मुख्य दोष यह है कि इसमें निश्चित मूल्य का सोना चाँदी व्यर्थ ही निधि में रक्खा जाता है जिसकी पत्रमुद्रा परिवर्तन के लिये भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती।
- (६) आंशिक अनुपात निधि पद्धति (Percentage method) इस पद्धति के अनुसार निधि का कुछ अंश देश में सोना-चाँदी के रूप में रक्खा जाता है। तथा कुछ विदेशीय अधिकोषों की हुिएडयों तथा विदेशी मुद्राओं में रक्खा जा सकता है। आजकल यह प्रणाली ही सबसे अच्छी मानी जाती है। अधिकांश देश अपनी पत्रमुद्रा चलन इसी प्रणाली पर आधारित किये हुए हैं।

भारत में पत्रमुद्रा चलन

मारत में पत्रमुद्रा चलन यूरोपियों के संसर्ग से ही प्रारम्म हुन्ना है। वैसे इस देश में धातुमुद्रा के स्थान पर कुछ काल के लिये चर्ममुद्रा का भी प्रयोग हुन्ना था परन्तु बाहुल्यता धातुमुद्रा की ही है। इस देश में सर्व प्रथम १८०६ ई० में स्थापित वेंक न्नाफ बगाल ने पत्रमुद्रा का निर्गमन किया था। इसके परचात् वैंक न्नाफ बम्बई तथा बैंक न्नाफ मद्रास को भी नोट निर्गमन का न्नाधिकार दे दिया गया था। ये नोट प्रायः कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के शहरों तक ही सीमित थे। सरकार ने प्रत्येक बैंक के लिये नोट निर्गमन की न्नाधिकतम सीमा निर्धारित कर दी थी न्नीर प्रत्येक बैंक को निर्गमित नोटो के एक-तिहाई न्नाथवा चौथाई मूल्य के बराबर धातु निधि रखनी पहती थी। ये नोट सरकारी नेटों के समान विधिन्नाह्म नहीं थे।

सन् १८६१ ई० में सरकार ने पत्रचलन ऐक्ट पास कर दिया जिसके अनुसार १०, २०, ५०, १००, ५००, १००० तथा १०००० रुपये के नोट चालू किये । प्रारम्भ में सम्पूर्ण देश को कलकत्ता, बम्बई तथा महास के तीन चेत्रों में विभाजित कर दिया गया था तथा प्रत्येक चेत्र के नोट उसी चेत्र में विधियाह्य होते थे। सन् १६१० ई० तक चेत्र सात हो गये थे। साधारण तौर पर नोट अपने निर्गमित चेत्र में ही चला करते थे। फिर भी सरकारी भुगतानों को चुकाने के लिये किसी भी चेत्र के नोटों में भुगतान किया जा सकता था। चेत्र सीमित होने से व्यापार में काफी बाधा पड़ती थी। अतः १६०३ ई० में चेत्रों को विस्तृत करने या तोड़ने का प्रयत्न प्रारम्भ किया गया। सन् १६०३ ई० में ५ रुपये का नोट सभी चेत्रों के लिये अपरिमित विधियाह्य बना दिया गया। इसी प्रकार १०, ५० तथा १०० रुपये के नोटे धीरे-धीरे अपरिमित विधियाह्य सभी चेत्रों के लिये कर दिये गये।

प्रारम्भ में भारतीय नोटों का निर्णमन निश्चित विश्वासिश्रत निर्णम प्रणाली के आधार पर किया गया था। इसके अनुसार ४ करोड़ रुपये की कीमत तक के नोट सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर निकाले जा सकते थे परन्तु इससे ऊपर के प्रत्येक नोट के पीछे रुपये के सिक्कों, धातुओं अथवा भारत सरकार की रुपया प्रति भूतियों के रूप में १०० प्रतिशत निधि आवश्यक होती थी। विश्वासिश्रत निर्णमन की सीमा धीरे-धीरे बढ़ाकर १६१६ ई० तक २० करोड़ रुपये कर दी गई थी। इस प्रकार यहाँ की पत्रमुद्रा प्रणाली प्रारम्भ में सुरिच्चत थी तथा अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में निर्णमन की सम्भावना बहुत कम थी। फिर भी यह प्रणाली स्वयं संचालित नहीं थी। पर्याप्त मात्रा में घातु निधि रखनी पड़ती और उसका अधिकांश भाग देश के बाहर ही रक्खा जाता था। केन्द्रीय बैंक की अनुपरियित में कोष निधि कोषागारों में रक्खी रहती थी और इस प्रकार देश की चलन प्रणाली पूर्णतया बेलोच थी।

प्रथम युद्ध के पश्चात् वैिबंग्टन स्थानीय सिमिति के द्वारा भाग्तीय चलन प्रणाली में कुछ सुधार के सुभाव दिये गये। सिमिति के सुभावों तथा सरकारी श्रनुभव के श्राधार पर सन् १९२३ ई० में एक ऐक्ट पास किया गया जिसके श्राधार पर पत्रमुद्रा निधि नियमों में निम्नांकित परिवर्तन हो गये—

- (१) कुछ निधि का कम-से-कम ५०% धातु निधि के रूप में रन्वना आवश्यक हो गया।
- (२) शेष निधि को २० करोड़ रुपयों की प्रतिभ्तियों के रूप में भारत में तथा उससे बची हुई सम्पूर्ण निधि को एकवर्षीय प्रतिभृतियों में लन्दन में रखना स्त्रावश्यक हो गया।
- (३) मुनाये हुए विनिमय बिलों के आधार पर ५ करोड़ रुपयों के नोट निका-लने का अधिकार सरकार को दे दिया गया।

- (४) भारत सचिव लन्दन में ५० लाख पौड की कीमत से ऋधिक सोना नहीं रख सकता था। ऋभी तक भारतवर्ष की पत्र-मुद्रा परिवर्तनशील थी। परन्तुः हिलटन यंग कमीशन ने यह सिफारिश की कि नोटों को रुपयों में बदलने का उत्तर-दायित्व समाप्त हो जाना चाहिये परन्तु सरकार ने इस सुमाव को स्वीकार नहीं किया। कमीशन की ऋन्य सिफारिशें निम्नांकित थीं—
 - (१) नोट का निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त एक केन्दीय बैंक की स्थापना
 - (२) पत्र चलन निधि तथा स्वर्णमान निधि का ऐकीकरण
- (३) अनुपातिक निधि निर्गमन प्रणाली की स्थापना । सरकार ने कुछ सुमावों को तो मान लिया । केन्दीय बैंक की स्थापना का प्रश्न स्थिगित कर दिया । कालान्तर में १६३४ ई० के रिजर्व बैंक आप इिख्या ऐक्ट के अनुसार १ अप्रैल सन् १६३५ ई० से रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया ।

श्रव नोट निर्मामन का एकाधिकार रिजर्ब बैंक को प्राप्त है। इस बैंक द्वारा निर्मामित पत्र-मुद्रा श्रपरिमित विधिश्राह्म है। इन नोटों को भारतीय सरकार की गारन्टी प्राप्त हैं। बैंक को सम्पूर्ण निर्मामित नोटों के मूल्य का ४०% धन सोने के सिक्तों, सोने, श्रथवा विदेशी प्रतिभृतियों या विदेशी मुद्राश्रों में निधि के रूप में रखना पड़ता है। १६४८ ई० तक विदेशी मुद्राश्रों में केवल स्टरिलंग ही एकि ति किया जा सकता था। परन्तु श्रव श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किसी भी सदस्य देश की मुद्रा को निधि के रूप में रक्खा जा सकता है। सम्पूर्ण निधि में कम से कम ४० करोड़ रुपये की कीमत का सोना रखना श्रावश्यक है। शेष ६० प्रतिशत पत्र चलन के लिये रुपये के सिक्के, सरकारी प्रतिभृतियाँ, स्वीकृत विनिमय बिल तथा प्रतिशापत्र का श्राघर होना श्रावश्यक है। सरकारी प्रतिभृतियाँ, स्वीकृत विनिमय बिल तथा प्रतिशापत्र का श्राघार होना श्रावश्यक है। सरकारी प्रतिभृतियों की मात्रा ५० करोड़ रुपयों से श्रिषक नहीं हो सकती। विशेष परिस्थितयों में राष्ट्रपति की पूर्वस्वीकृति से इस मात्रा में १० करोड़ रुपये की वृद्धि की जा सकती है। इसके श्रितिरक्त विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति की प्रवस्तीकृति से इस मात्रा में रिजर्व वैंक के निर्ममन सम्बन्धी नियमों में कुछ शिथिलता हो सकती है। स्वित्ते में रिजर्व वैंक के निर्ममन सम्बन्धी नियमों में कुछ शिथिलता हो सकती है। स्वित्ते विना राष्ट्रपति की श्राज्ञा के नहीं।

इस समय भारत में १, २, ५, १०, १००, तथा १००० रुपये के नोट प्रच-लित् हैं। तथा अप्रैल १६५६ ई० से ५००० तथा १०००० रुपयों के नोट भी चलन में आ गये हैं। भारतीय पत्र मुद्रा प्रणाली अपने वर्तमान रूप में देश के उपमुक्त ही प्रतीत होती है। यह पर्याप्त लोचदार है। विभिन्न चलन निधियों के एकी-करण से अब यह प्रणाली अपन्ययी नहीं रही। स्वीकृत विनिमय बिलों तथा प्रतिशा-पत्रों की आड़ में पत्र-मुद्रा निर्ममन की व्यवस्था से प्रणाली और भी अधिक लोचदार स्थितियों के लिये समुचित व्यवस्था हो गई है। फिर भी इस प्रणाली में निम्नांकित दोष हैं—

- (१) इस प्रणाली के अनुसार सरकारी इस्तच्चेप की सम्भावना बहुत बढ़ जाती है।
- (२) यह प्रणाली त्रान्तरिक मूल्यों में स्थिरता स्थापित करने में सफल नहीं रही।
- (२) कुछ लोगों के मतानुसार इस प्रणाली में यथोनित लोच नहीं है। निधि व्यवस्थायें प्रत्यच्च कड़ी होने के कारण इसमें देशी ऋर्य-व्यवस्था की ऋावश्यकता-नुसार मुद्रा मात्रा को कम ऋथवा ऋधिक करने का गुण नहीं है।
- (४) यह प्रगाली स्टर्गलंग पर अब भी निशेष रूप में आधारित है। नोटों की परिवर्तनशीलता प्रायः स्टर्गलंग पर ही निर्भर है। स्टर्गलंग की कीमतों के घटा-बढ़ी का रुपये की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ता ही है। अब भारतीय कागजी नोट वास्तविकता में अपरवर्तनीय पत्रमुद्रा मात्र ही रह गये हैं। रिजर्व कैंक अथवा सरकार नोटों को चाँदी के सिक्कों में बदलने के लिये बाध्य नहीं है।

प्रश्न

१ भारत में १६५६ में नोट जारी करने की विधि अनुपातिक कोप प्रथा (Proportional Reserve System) से बदल कर किश्चित कोप प्रयाली (Minimum Reserve System) क्या का गइ? भारत के चंलार्थ पर इसका क्या प्रभाव एड़ा?

(ग्रागरा दी. ए. १६५६)

- २. पत्र-मुद्रा किन-किन सिद्धांतो पर श्राधारित द्दोना चाहिए? इस सम्बन्ध में रेजर्व वैद्ध के विधानों की सम्बन्धित धारणात्रों का उल्लेख कीजिए। (आगरा वी. ए. १९५६)
- 3. Explain the various systems of note issue. Which of these systems has been adopted in India? (Agra B. Com. I, 1957)
- 4. Discuss clearly the main features of the Fiduciary Issue system and the minimum reserve method of note issue as adopted by India. Cive your arguments in support of them.

 (Agra B. Com. I, 1957).

अध्याय ६

मुद्रा का मूल्य-निर्घारण एवं परिवर्त्तन

(Value of Money-its Determination and Changes)

मुद्रा मूल्य निर्धारण--मुद्रा के विषय में प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् मुद्रा के मूल्य के बारे में भी अध्ययन करना आवश्यक है। मुद्रा के मूल्य का तात्वर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से होता है। साधारण वस्तुओं का मूल्य मुद्रा से ही मापा जाता है। परन्तु मुद्रा का मूल्य उसके द्वारा प्राप्त वस्तुओं से नापा जाता है। बाजार में वस्तुओं का मूल्य माँग तथा पूर्ति पर निर्भर होता है और यही शक्तियाँ प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारण करती हैं। क्या मुद्रा का मूल्य भी अन्य वस्तुओं की भाँति पूर्ति तथा माँग के द्वारा हो निर्धारित होता है!

मुद्रा का परिमास सिद्धांत (The Quantity Theory)

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। यह सिद्धान्त सामान्य पूर्ति तथा माँग के सिद्धान्त पर ही आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार अन्य परिस्थितियाँ समान रहने पर यदि मुद्रा के परिमाण में वृद्धि कर दी जाय तो इसका मूल्य कम हो जाता है और यदि मुद्रा की पूर्ति में कमी कर दी जाय तो उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अर्थात् मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की कय शक्ति में विरोधात्मक सम्बन्ध है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से मुद्रा की कय शक्ति कम हो जाती है और पूर्ति के घटने से वह शक्ति बढ़ जाती है। उगर्रा के जिये नान लीजिये किसी समाज में मुद्रा की ५०० इकाइयों की पूर्ति है अर्थेर टस नमाज में किसी एक वस्तु की र००० इकाइयों का कय-विकय होना है तो ऐसी अवस्था में एक मुद्रा की कय शक्ति अ बद्धा आ के बरावर होगी। यदि मुद्रा का परिन ए दे०० से बढ़ाकर १००० कर दिया जाय तो प्रत्येक मुद्रा के बदले में केवल दो (२) वस्तुयें ही प्राप्त हो सकेंगी और यदि उसकी पूर्ति घटकर २५० कर दी जाय तो प्रत्येक मुद्रा व वस्तुओं को खरीद सकेगी। उपरोक्त उदाहरण से निम्नांकित निष्कर्ष निक्त जा सकते हैं—

⁽१) मुद्रा का मूल्य अथवा उसकी कय-शक्ति मुद्रा की मात्रा के द्वारा निर्धा-रित होतों है।

- (२) मुद्रा की मात्रा के परिवर्तन से मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है।
- (३ मुद्रा मात्रा की वृद्धि से मुद्रा का मूल्य घट जाता है। तथा मात्रा की कमी से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है।
- (४) मात्रा तथा-मूल्य का परिवर्तन प्रतिकृत अनुपातिक आधार पर होता है अर्थात् यदि मात्रा दुगनो कर दी जाय तो मूल्य आधा रह जाता है और यदि मात्रा आधी कर दी जाय तो मूल्य दुगना हो जाता है। यहो मुद्रा परिमाण विद्वान्त है।

संचेप में यह_सिद्धांत बताता है कि मुद्रा का मूल्य तथा उसके परिवर्तन मुद्रा के परिमाण द्वारा नियंत्रित होते हैं।

सिद्धान्त का समीकरण (Equation of the Quantity Theory of Money)—प्राचीन ऋर्थशास्त्री मुद्रा का ऋर्थ केवल चलन से ही लगाते थे। साख-मुद्रा का महत्व उस समय नहीं था। ऋतः निम्नांकित समीकरण प्राचीन काल में प्रचलित था—

$$\frac{M}{T} = P$$
 त्रथवा $\frac{H}{a} = a$

इस समीकरण में म (M) का श्रर्थ समय विशेष पर प्रचलित मुद्रा से है, व (T) का श्रर्थ वस्तुओं 'एवं' सेवाश्रों की मात्रा से तथा क (P) का सामान्य मूल्य-स्तर से । व (T) को स्थिर माना गया है। क (P) में परिवर्तन म (M) में परिवर्तन होने के कारण ही होते हैं तथा वे एक ही दिशा में होते हैं । यदि म (M) श्रिधक हो जाता है तो क (कीमत) भी बढ़ जायेंगी तथा म कम होने पर कीमतें (π) नीचे हो जायेंगी ।

इस संमीकरण में साख सुद्रा तथा रुपये की माँग को कोई महत्व नहीं दिया गया। रुपए को माँग ब्यापार, वस्तुश्रों एवं सेवा (व (Γ)) द्वारा निर्मित होती हैं।

कुछ समय परचात् इस विद्धान्त में अर्थशास्त्रियों को त्रुटियाँ प्रनीत होने लगीं । मुद्रा भी एक बस्तु हैं। अतः अन्य वस्तुओं की भाँति इसके मूल्य निर्धारण में भी पूर्ति के अतिरिक्त माँग का भी प्रभाव होना चाहिये और व्यवहार में ऐसा होता भी है। मुद्रा की माँग से तात्पर्य उन वस्तुओं तथा सेवाओं से हैं जिनके कय-विकय के लिये मुद्रा की आवश्यकता पड़ती हैं। इस प्रकार मुद्रा की माँग कय विकय होने वाली वस्तुओं के परिमाण के परिवर्त्तन से भी मुद्रा के प्रसिमाण पर निर्भर होती हैं। वस्तुओं के इस परिमाण के परिवर्त्तन से भी मुद्रा के मूल्य में परिवर्त्तन होता है। उपरोक्त उदाहरण में १०० मुद्रायें मुद्रा की पूर्ति है तथा कय-विकय के २००० वस्तुयें मुद्रा की माँग है। इस पूर्ति तथा माँग के अनुसार प्रत्येक मुद्रा के बदले में ४ वस्तुयें प्राप्त हो सकती हैं। यदि मुद्रा की माँग

में परिवर्त्तन कर दिया जाय तो मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्त्तन हो जायगा । उदाहरण के लिये यदि कय-विक्रय करने वाली वस्तुयें २००० से घटकर १००० रह जायँ और मुद्रा की पूर्ति वही बनी रहे तो प्रत्येक मुद्रा के बदले में ४ वस्तुश्रों के स्थान में केवल २ वस्तुयें ही प्राप्त होगीं और यदि वस्तुश्रों की मात्रा बढ़ाकर ४००० कर दी जाय तो प्रत्येक मुद्रा के बदले में द वस्तुयें प्राप्त होंगी। इस उदाहरण से निम्नांकित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

- (१) मुद्रा का मूल्य मुद्रा की माँग अर्थात् कय-विक्रय हेतु वस्तु मात्रा पर निर्भर होती है। यदि क्रय-विक्रय हेतु वस्तु के परिमाग्रा में परिवर्तन कर दिया जाय तो मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्त्तन हो जाता है।
- (२) वस्तु मात्रा में वृद्धि करने से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है तथा वस्तु मात्रा कम करने से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है।
- (३ मुद्रा के मूल्य तथा क्रय-विक्रय हेतु वस्तु मात्रा परिवर्त्तन में श्रमुकाल श्रमुपातिक सम्बन्ध है श्रर्थात् यदि वस्तु मात्रा दुगनी कर दी जाय तो मुद्रा का मूल्य भी दो गुना हो जाता है श्रोर वस्तु मात्रा श्राधी कर दी जाय तो मुद्रा का मूल्य भी श्राधा रह जाता है।

इस समीकरण को प्रो॰ फिशर ने जन्म दिया। इसमें प्रयुक्त (M) म का अर्थ कुल चलन की मात्रा, व (V) = चलन का वेग, स (M') साख की मात्रा, चा (V') साख के चलन का वेग, क (P) कीमत और व (T) = ज्यापार व वस्तुओं की मात्रा। फिशर का विचार है कि अल्पकाल में ज्यापार (T) स्थिर रहता है, न आबादी बढ़ती है और न उत्पादन बदलता है। उत्पत्ति की रीतियाँ तथा उपयोग की आदते निश्चित रहती हैं और माँग (T) स्थिर रहती है। अतः "अन्य बातें समान रहें तो सामान्य मूल्य-स्तर के सभी परिवर्त्तनों का मुद्रा के परिमाण के परिवर्त्तन से प्रत्यन्न तथा अनुपातिक संबंध होता है।"

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुन्ना कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की माँग के ऊपर निर्भर होता है। त्रतः मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की माँग का स्पष्ट तात्पर्य समक्त लेना त्रावश्यक है। त्रभी तक मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य उन सिक्कों की संख्या से लिया गया है जो किसी समय में एक समाज में चलते हैं परन्तु चलने वाले सिक्कों की संख्या ही मुद्रा की पूर्ति में सिम्मिलित नहीं होती। मुद्रा की पूर्ति में सिक्कों की चलन गित (Velocity of Circulation) का भी ध्यान रखना पड़ता है; क्योंकि सिक्के की चलन गित के बढ़ने तथा घटने से मुद्रा के मूल्य में परिवर्त्तन हो खाता है। उदाहरण के लिये यदि एक मार्ग ने लाँच बार विनिमय का कार्य किया

जाय तो वह पाँच रुपयों के बरावर हो जाता है। वह श्रकेला रुपया विनिमय च्लेत्र में इतना कार्य करता है जितना पाँच रुपये करते।

इसलिये नुद्रा की मात्रा का अनुमान लगाते समय मुद्रा की चलनगित का ध्यान रखना आवश्यक है। यही नहीं वर्तमान समय में विशेषकर श्रौद्योगिक देशों में अधिकांश कर विक्रय के कार्य साख-पत्रों के द्वारा होते हैं। ये साख-पत्र मुद्रा का ही कार्य करते हैं। यदि साख-पत्रों की मात्रा में परिवर्त्तन हो जाय तो मुद्रा के नृल्य में भी परिवर्त्तन हो जाता है। वास्तव में साख-पत्र मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हें। इस प्रकार मुद्रा के परिमाण में मुद्रा की मात्रा के साथ ही साथ साख-पत्रों की मात्रा का भी सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है। मुद्रा के समान साख-पत्र की चलनगित के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रा की तरह एक साख-पत्र भी एक से आधिक विनिमय का कार्य कर सकता है। वेतन में प्राप्त चेक एक व्यक्ति द्वारा अनाज वाले दूकानदार को दिया जा सकता है। वेतन में प्राप्त चेक के द्वारा वस्तु वाले से वस्तु खरीद सकता है तथा वस्तु वाला उसी चेक के आधार पर वर्तन खरीद सकता है। इस प्रकार एक ही चेक द्वारा तीन विनिमय के कार्य हो जाते हैं जिनके लिये उतनी ही घन राशि के तीन चेकों की आवश्यकता होती। अतः चेकों की संख्या में उनकी चलनगित का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्त में निम्नांकित चार तत्व सम्मिलित होते हैं—

- (१) चलनमय मुद्रा की मात्रा
- (२) मुद्रा चलनगति
- (३) चलनमय साख पत्रों की मात्रा
- (४) साख-पत्र चलनगति

नियम की सीमाएँ (Limitations of the Theory)—ऋर्थशास्त्र के ऋन्य विषयों की भाँ ति यह नियम भी कुछ सीमाएँ रखता है और लागू होने के लिए निम्नांकित दशाएँ पूरी होनी चाहिए—

- (१) व्यापार की मात्रा स्थिर रहना—व्यापार की मात्रा (T) मुद्रा की माँग को निर्धारित करती है। यदि व्यापार बढ़ जाता है तो रुपए की माँग बढ़ जाएगी। इससे मुद्रा का मृल्य बढ़ेगा अथवा मृल्य स्तर गिरेंगे। अतः व्यापार की मात्रा स्थिर मानी जाती है।
- (२) साख-पत्रों की मात्रा—साख-पत्रों, चेक, बिल, हुगडी ब्रादि से चलन की मात्रा बढ़ती है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि साख-पत्रों की मात्रा सौमित होती है।
- (३) चलन की गति में भी स्थिरता मानी जाती है। परिमाण सिद्धांत की यह मान्यता है कि देश में जनसंख्या, उत्पत्ति तथा उपभोग स्थिर रहता है ताकि केंग (v) में परिवर्तन न हो।

(४) मुद्रा संचय—िसदांत में यह माना जाता है कि चलन में प्रत्येक प्रकार की मुद्रा चलन में रहती हैं। उसका संचय (Hoarding) नहीं किया जाता अन्यथा परिवर्तन स्पष्ट होंगे।

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की आलोचना

यद्यपि इस शताब्दी में मुद्रा परिमाण सिद्धान्त में विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किये जा चुके हैं फिर भी इस सिद्धान्त की काफी आलो-चना की जाती हैं के कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि इस सिद्धान्त में कोई विशेषता नहीं है। यह तो माँग एवं पूर्ति के नियम का ही एक रूप है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। मुद्रा मूल्य निर्घारण नहीं सममा जा सकता वरन् इसकी सहायता से मुद्रा मात्रा परिवर्तन के विभिन्न परिमाणों का ज्ञान होता है और उनके आधार पर मुद्रा परिमाण में ही परिवर्तन के द्वारा कीमतों के नियंत्रित करने के उपाय निकाले जा सकते हैं भे अन्य विद्वानों के मतानुसार यह सिद्धान्त माँग एवं पूर्ति नियम पर आधा-रित स्वयं-सिद्ध-सत्य है। अतः इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। वास्तव में इस सिद्धान्त के द्वारा कीमतों का समायोजन करने में विशेष सहायता मिलती है। मुद्रा एवं आधिकोप के कार्यों की ठीक विवेचना के लिये इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण आव-र्यकीय है।

तीसरा त्राचिप इस सिद्धान्त के विरुद्ध यह लगाया जाता है कि इस सिद्धान्त के श्रन्तर्गत न "श्रन्य परिस्थितियाँ समान रहें" वाली शब्दावली सिद्धान्त को काल्प-निक बना देती है, क्योंकि संसार में परिस्थितियों का स्थिर रहना कठिन है, प्रायः परिस्थितियाँ स्थिर नहीं रहतीं। जब वे परिस्थितियाँ जिनकी स्थिरता पर सिद्धान्त आधारित है यदि स्थिर रह सकों तो फिर ज्यावहारिक दृष्टि से सिद्धान्त का कोई महत्व नहीं रह जाता। श्रन्य विद्धानों के मतानुसार इस सिद्धान्त में माँग की श्रपेद्धा पूर्ति पर ही श्रिषिक बल दिया गया है। परन्तु माँग का प्रभाव भी मुद्रा की क्रय-शक्ति पर पहता है। पूर्ति के साथ ही साथ माँग भी मुद्रा के मूल्य पर श्रपना प्रभाव डालती है।

कुछ विद्वानों के अनुसार सुद्रा चलन के परिमाण का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया वा सकता। ऐसा न होने से सिद्धान्त का व्यावहारिक महत्व नष्ट हो जाता है। देश में जितनी सुद्रा है वह सब एक साथ विनिमय के कार्य में नहीं लाई जाती। कुल पूर्ति का कितना माग विनिमय के कार्य में आता है और कितना संचय के कंप में निर्यंक रहता है, इन बातों का ठीक पता लगना कठिन है। इसके अतिरिक्त किसी विशिष्ट देश की कीमतों की तेजी अथवा मंदी के कारणों का विवेचन इस सिद्धान्त के द्वारा नहीं हो सकता। आधुनिक काल में एक देश की कानतों पर भी निर्मर होती है। यह बात उन वस्तुऔर

के लिये अधिक सत्य है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय न्यापार होता है। यह सिद्धान्त मूल्य-स्तर में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को भी नहीं बतलाता कि कीमतों के स्तर में किस प्रकार परिवर्तन होता है। कभी-कभी यह देखा गया है कि मुद्रा चलन मात्रा में परिवर्तन न होने पर भी न्यापार में मन्दी आ जाती है, वस्तुओं की कीमतें गिरने लगती हैं। इस प्रकार न्यापार चक्र के फलस्वरूप हुये कीमतों का परिवर्तन इस सिद्धान्त के द्वारा नहीं समकाया जा सकता। इसी प्रकार समाज द्वारा उत्पादित सम्पूर्ण वस्तुओं का विनिमय भी मुद्रा के माध्यम से नही होता। उत्पादित वस्तुओं का कुछ भाग उत्पादक लोग स्वयं उपभोग कर लेते हैं। कुछ का विनिमय प्रत्यद्व विनिमय प्रणाली के आधार पर होता है जिसमें मुद्रा कोई कार्य नहीं करती। इस प्रकार वस्तुओं की उस मात्रा का ठीक-ठीक पता लगाना जिसका विनिमय माध्यम मुद्रा हो अत्यन्त कठिन हैं। उपरोक्त कठिनाइयों के समन्न मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की न्यावहारिक उपयोगिता प्रायः नहीं के बराबर ही रह जाती है।

प्रोफेसर कीन्स के मतानुसार वर्तमान विनिमय के कार्य श्रिधिकतर साख-पत्रों द्वारा होते हैं जिनका धातु निधि से बहुत कम सम्बन्ध रहता है। मुद्रा द्वारा होने वाले श्रिधिकांश व्यवहार श्रौद्योगिक तथा श्राधिक होते हैं। व्यापारिक विनिमय बहुत कम होता है। परन्तु सिद्धान्त के समीकरण में व्यापार शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि त्रिटपूर्ण है।

उपरोक्त त्रालोचनात्रों के होते हुए भी यह रिद्धान्त नितान्त त्रमुपयोगी नहीं कहा जा सकता । मौद्रिक जगत में यह सिद्धान्त काफी मान्यता रखता है । सुद्रा सम्बन्धी विवेचन इस सिद्धान्त के बिना अपूर्ण ही समभा जाता है। व्यवहार में भी यह सिद्धान्त कभी-कभी उपयोगी सिद्ध होता है। प्रोफेसर फ़िशर ने यह सिद्ध किया है कि डालर स्थाइन मान योजना (Compensative Dollar Scheme) में इस सिद्धान्त की काफी सहायता रही है। इसी प्रकार प्रोफेसर कीन्स भी यह स्वीकार करते हैं कि संख्यात्मक जाँच के लिये मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के समीकरण की सहायता से ऋधिक उन्नति की जा सकती है। इसके ऋतिरिक्त यह सिद्धान्त कुछ सीमा तक मूल्य-परिवर्तन प्रकृति को समकाने का प्रयत्न तो करता ही है व्यवहार में प्रायः यही देखा गया है कि मुद्रा की मात्रा में दृद्धि करने से उसकी क्रय-शक्ति कम हो जाती है। वास्तव में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन इसी प्रकार के अनमवीं के ब्राधार पर किया गया है तथा मुद्रा स्फीति काल में मुद्रा की क्रय शक्ति का कम होना सिद्धान्त की सत्यता को प्रमाणित करता है। हो सकता है कि यह सिद्धान्त प्रत्येक समय के मूल्य-स्तर परिवर्तन को समभाने में श्रसमर्थ रहे । सम्भव है कि यह मूल्य परिवर्तन सिद्धान्त में प्रतिपादित कारखों से अधिक प्रवल कारखों के आधार पर हो गये हों जिससे सिद्धान्त की महना कम प्रतीत होती है परन्तु इससे यह ऋर्थ

नहीं लगाया जा सकता कि यह सिद्धान्त विलकुल कार्ल्पानक तथा ऋपूर्ण है। मौद्रिक चेत्र में यह सिद्धान्त ऋपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रसंग में राबर्टसन ने सत्य ही कहा है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा का मूल्य समम्भने के लिए एक ऋन्पम सत्य है। यह एक ऐसा सत्य है कि जिसका समभना वास्तविक जीवन में मुद्रा की मात्रा और वस्तुश्रों के मूल्य में संपर्क स्थापित करने के लिए ऋगवश्यक है।

मुद्रा-चलन के वेग को निर्धारित करने वाले तत्व (Factors determining the Velocity of Circulation of Money)

हम मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त में यह देख चुके हैं कि यह परिमाण मुद्रा चलन के वेग पर निर्भर रहता है और मुद्रा-मूल्य पर प्रभाव डालता है। मुद्रा-चलन के वेग का अभिप्राय इस चलन की गित से हैं जिससे वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों विनिमय के लिए आती-जाती है। उदाहरण के लिए एक १०० हमए का नोट एक सताह में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास विनिमय के माध्यम के रूप में १० वार आती-जाती है तो उस नोट का साप्ताहिक चलन वेग १० होगा अर्थात् एक सौ का नोट १००० हमए के विनिमय का काम करेगा। इस प्रचलन वेग पर निम्मांकित बातों का प्रभाव पड़ता है —

- (१) मुद्रा की मात्रा—देश के आर्थिक जीवन को मुचार रूप से चलाने के लिए मुद्रा के निश्चित परिमाण की आवश्यकता बनी रहती है। यदि मुद्रा इस परिमाण से कम है तो विनिमय संबंधी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा के चलन का वेग अधिक हो जायेगा और यदि मुद्रा की निकासी अकिक है तो प्रचलन वेग कम रहेगा।
- (२) जनता में बचत की क्षमता— मुद्रा चलन की गति पर इस बात का मी प्रमाव पड़ता है कि लोग अपनी आय का कितना भाग बचाते हैं और कितना भाग उपयोग के लिए रखते हैं। उपभोग के लिए जितना भाग कम होगा उतनी ही चलन की गति बढ़ेगी और बचत का भाग कम होने से गति में शिथिलता होगी।
- (३) देश में नगद लेन-देन—नगद क्रय-विक्रय में मुद्रा की आवश्यकता सदैव पड़ती रहती है और चलन का वेग बना रहता है। जहाँ उधार लेन-देन होगा वहाँ मुद्रा की आवश्यकता कम तथा निश्चित समय के बाद होती है। अतः चलन का वेग कम रहता है।
- (४) जनता की द्रवता पसंदी (Liquidity preference)—यदि लोग अपने पास दैनिक खर्चों को चलाने के लिए या ऋगा त्रादि का शोधन करने के लिए अितना रूपया नगदी में ऋपने पास रखेंगे उतनी ही प्रचलन गित कम होगी। अर्थात् ऋधिक नगद कोष द्रव्य की चलन गित को मन्द करते हैं।

- (४) मजदूरी प्रणाली का रूप एवं ऋण प्राप्ति की सुविधाएँ—यदि मजदूरी समय-समय पर दी जाती है तो प्रचलन ऋधिक होगा एवं लंबे समय के बाद देने की प्रथा है तो दैनिक ऋावश्यकताऋों की पूर्ति करने के लिए लोग मुद्रा-कोप बना लेंगे ऋौर गति कम हो जायगी। इसी प्रकार ऋण को सुविधाएँ प्रचलन वेग को कम करती हैं।
- (६) सामान्य आर्थिक, व्यापारिक एवं यातायात की उन्नांत—जहाँ आर्थिक व्यापारिक उन्नित होती हैं एवं यातायात संचार के साधन उन्नत होते हैं वहाँ लेन-देन एवं सुद्रा के उपयोग का चेत्र बढ़ जाता है और मुद्रा-चलन में गितशीलता आती है। जहाँ आर्थिक विकास नहीं होता, व्यापारिक उन्नित नहीं होती वहाँ समाज का लेन-देन वस्तु विनिमय (Barter) होने लगता है और सुद्रा की आवश्यकता कम रह जातो है। कृषि-प्रधान देशों में भी सुद्रा की प्रचलन गित कम रहती है।
- (७) साख की गतिशीलता—साख का आधार अंतिमतः रुप्या ही होता है। अतः साख के वेग में अधिकता मुद्रा-प्रचलन वेग की अधिकता का ही रूप है। जितनी जल्दो साख का भुगतान एवं हस्तांतरण होगा साख का वेग भी बढ़ेगा।
- (८) कीमतों का भावी श्रनुमान—यदि भविष्य में कीमतें चढ़ जाने का श्रनुमान है तो सौदों की गतिविधि बढ़ जाएगी श्रौर चलन का वेग बढ़ जाएगा। भविष्य में मन्दी की श्राशा में क्रय-क्रय होगा श्रौर मुद्रा चलन का वेग घटेगा। मृल्य-निर्धारण के श्रन्य सिद्धान्त
- (१) बचत श्रीर विनियोग का सिद्धांत (Saving and Investment Theory)—इस सिद्धांत के मूल प्रतिपादक कीन्स का मत है कि मुद्रा का मूल्य जनता की श्राय तथा उसकी बचाने की शक्ति तथा बचत श्रीर विनियोग के संबंध पर निर्मुर करता है। इस प्रकार से इस सिद्धांत में सभी प्रकार की श्रार्थिक घटनाएँ निहित हैं। इसकी श्राधारिक बातें इस प्रकार हैं—
- (अ) किसी निश्चितसमय में मुद्रा का मूल्य द्राज्यिक आय (मुद्रा की मात्रा, चलन का वेग तथा अन्य आयों) तथा वस्तुओं की मात्रा (पूँजी की मात्रा, बचत तथा लाभ) पर निर्भर रहता है। (ब) बचत का आश्य है कि द्रव्य नए उपभोग की वस्तुओं पर ब्यय नहीं किया जाता और विनियोग का अर्थ पूँजी को नई वस्तुओं पर ब्यय करना होता है। (स) इन दोनों में कभी समानता नहीं रहती। कभी विनियोग अधिक होते हैं और कभी बचत। (द) यदि बचत विनियोग से अधिक होती है तो मूल्य स्तर गिरते हैं और जब विनियोग बचत से अधिक होते हैं तो मूल्य ऊपर चढ जाते हैं।

इस सिद्धांत में कुछ दोष हैं। विनियोग और बचत समान मानना केवल अपना सिद्धांत निर्दोष दिखाना है। व्यावहारिक रूप से दोनों समान नहीं हो सकते। खुट्च के अनुसार इस सिढांत में साख नीति एवं सामयिक परिवर्त्तनों का ख्याल नहीं रखा गया है।

मुद्रा मृत्य परिवर्तन (Changes in Value of Money)—मुद्रा परिमाश सिद्धान्त के त्राघार पर प्रायः यह निश्चित है कि मुद्रा के परिमाश में वृद्धि तथा कमी से मुद्रा के मृल्य में परिवर्तन होता है। त्र्र्थशास्त्रीय भाषा में मुद्रा मात्रा वृद्धि को मुद्रा स्त्रीति तथा मुद्रा मात्रा में कनी को मुद्रा संकुचन कहते हैं।

मुद्रा स्फीति (Inflation) — जहाँ तक मुद्रा स्फीति अथवा मुद्रा प्रसार का सम्बन्ध है इसकी परिभाषा ऋर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से की हैं। क्राउदर के अनुसार मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरे अर्थात् वस्तुओं का मृल्य बढ़े। केमरर के अनुसार जब मुद्रा की मात्रा अधिक हो और वस्तुओं की मात्रा उत्पादन घटने के कारण कन हो जाय तब मुद्रा स्कीति कहलातीं है। वास्तव में मुद्रा स्मीति की ग्रवस्था तभी उत्पन्न होती है जब कि ग्रावश्यकता से ग्रधिक मात्रा में मुद्रा चलन में आ जाय अथवा उत्पादन इतना घट जाय कि अपेजाकृत मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाय। इस सम्बन्ध में आवश्यकता से अधिक मात्रा में मुद्रा के होने का वास्तविक अर्थ समझना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में आवश्यकता से अधिक मुद्रा की मात्रा हानिकारक नहीं होती जब कि मुद्रा-स्फीति को लोग प्रायः हानिकारक ही समऋते हैं। कुछ लोगों के विचार से जब मुद्रा की पूर्ति उसकी त्राय से त्राधिक हो जिससे कि उसकी क्रय शक्ति घट जाय त्रीर कीमतें बहु बायँ तो यही ऋवस्या मुद्रा-स्फीति की ऋवस्था मानी जानी चाहिये। पीगू ने मुद्रा स्फीति की परिभाषा निम्न प्रकार से की हैं - "मुद्रा-स्फीति की अवस्था तब होती है बाद कि मौद्रिक आप उत्पादन किया की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ रही हो।" इस प्रकार त्र्ययशास्त्रियों ने मुद्रा स्कीति की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की है। जहाँ तक साधारण जनता का सम्बन्ध है वह मुद्रा स्काति को मुद्रा की क्रय-शक्ति से समस्तती है। एक साधारण व्यक्ति को मुद्रा स्नोति तभी खटकती है जब कि उसकी स्राय बढती हुई कीमतों के समान न बढ़े। अर्थात् जिस प्रकार वस्तुओं का कीमत स्तर बद्वा चला बाय उसी अनुगत से यदि लोगों को आय में भी वृद्धि हो तो मुद्रा रहोति किटी को अरुचिकर प्रतीत नहीं हाती । लेकिन अधिकांश जनता के साथ यह बाद परित नहीं होती है और इसीलिये मुद्रा स्फीति बुरी समभी जाती है।

प्रतिभिक्त दशा में विशोषकर जब कि व्यापार अवसाद से उत्कर्ष की आरेर उच्ची कारा है मुद्रा स्कीति हितकर होती है। परन्तु यदि मुद्रा स्कीति बराबर होती चर्ता बाय और उत्पादन उसके अनुसार न बढ़े तो सांधारण जनता को आर्थिक कम्टों का सामना करना पहता है। यह निश्चित करना कि किस सीमा तक मुद्रा स्फीति हितकर है एक कठिन कार्य है। साधारण तौर पर भी मुद्रा स्फीति का हितकर व श्रहितकर होना जनता के विभिन्न वर्गों पर निर्भर होता है। क्योंकि मुद्रा स्फीति का प्रभाव विभिन्न वर्गों पर विभिन्न रूप से पड़ता है कुछ मुख्य वर्गों पर मुद्रा स्फीति का प्रभाव नीचे दिया जा रहा है—

- (१) उत्पादक वर्ग मुद्रा स्तीति से उत्पादक वर्ग को प्रायः लाभ होता है क्यों कि उनके भंडारों में एकत्रित निर्मित माल का मौद्रिक मूल्य वढ़ जाता है। जितना माल उनके भंडार में है उसकी कीमत पहले से अधिक हो जाती है। यद्यां धोरे-धारे यह माल समात हो जाता है क्यों के मुद्रा स्त्रीति के कारण कच्चे माल तथा मज़दूरी आदि का मूल्य भी बढ़ जाता है। वस्तुओं का लागत व्यय अधिक हो जाता है परन्तु व्यवहार में लागत व्यय इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से निर्मित माल की कीमतें बढ़ती हैं। इसके अतिरिक्त यदि मुद्रा स्त्रीति के कारण लोगों की आय में वृद्धि होती है तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, जिससे निर्मित वस्तुओं की माँग बढ़ सकती है। बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिये उत्पादन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और यदि उद्योग में कमागत उत्पादन व्यय हास नियम लागू हो रहा हो तो वस्तु का लागत व्यय और कम हो जाता है तथा उत्पादकों का लाम बढ़ जाती है। इस प्रकार मुद्रा स्त्रीति काल में उत्पादकों को लाभ ही रहता है।
- (२) विनियोगी वर्गे— जो व्यक्ति उद्योग तथा व्यवसाय में स्पया लगाते हैं उनको मुद्रा स्फीति काल में कुछ ऋंश तक तो लाम होता है क्योंकि उद्योगों में ऋधिक लाम होने के कारण इन लोगों की ऋाय भी बढ़ जाती है। परन्तु कुछ विनियोगी ऐसे भी होते हैं जो निश्चित व्याज दर पर ऋपना स्पया लगा देते हैं। ऐसे विनियोगी वर्ग को उपमोक्ताओं के नाते हानि होती है। क्योंकि उनकी ऋाय तो वही बनी रहती हैं परन्तु कीमतें ऊँचा हो जाने के कारण उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। ऋतः उन्हें या तो ऋपना जीवन स्तर नीचा करना पड़ता है ऋथवा ऋपने जीवन स्तर को जनाये रखने के लिये पहले से ऋधिक द्रव्य व्यय करना पड़ता है छोर इससे उनकी जचत कम हो जाती है जिसका भविष्य में उनके विनियोग व्यापार पर भी बुरा ऋसर पड़ता है।
- (३) उपभोक्ता वर्ग पर भी, मुद्रा स्फीति काल में मुद्रा स्फीति का यही प्रभाव पड़ता है जो निश्चित त्राय वाले विनियोगियों पर । उपभोक्तात्रों को मुद्रा की क्रय शिक्त कम हो जाने के कारण पहले से ऋधिक व्यय करना पड़ता है ऋौर यदि ऋधिक व्यय करने की गुंजायश नहीं है तो ऋपने जीवन स्तर को निम्न बनाना पड़ता है ऋर्यात् उन्हें ऋपनी उपभोग सामग्री में कमी करनी पड़ती है । कुछ सीमा के पश्चात्

यह कमी उनकी कार्यसमता पर बुरा प्रभाव डालती है। कार्यसमता कम हो जाती है अप र यह देश को अपर्थिक उनति के जिये घातक सिद्ध होती है।

- (४ श्रिमिक वर्ग—इस वर्ग में वे सब व्यक्ति सम्मिलित किये जाते हैं जो अपनी सेवाश्रों श्रयवा श्रपने श्रम को बेंचकर श्राय प्राप्त करते हैं। इस वर्ग में कार खाने श्रौर कृषि में काम करने वाले मजदूर, नौकरी करने वाले व्यक्ति तथा श्रम्य श्रिमक श्रामिल रहते हैं। मुद्रा स्फीति के कारण जहाँ तक रोजगार की वृद्धि होती है वहाँ तक श्रमिकों को लाभ होता है। रोजगार श्रिधिक हो जाने के कारण श्राय में वृद्धि होती है परन्तु प्रत्येक श्रमिक की श्राय विशेषकर वास्तविक श्राय कम हो जाती है। मज़रूरी इतनी श्रिधक नहीं बढ़ती जितनी श्रिधक कीमतें बढ़ जाती हैं। इस कारण से बढ़ी हुई मज़रूरी से भी पहले की श्रपेचा कम वस्तुयें तथा सेवायें खरीदी जाती हैं। इस वर्ग में जिन व्यक्तियों को मासिक वेतन मिलता उन्हें श्रिधक हान उठानी पड़ती है क्योंकि मासिक वेतन दैनिक मज़दूरी से श्रीधक स्थिर होता है। मुद्रा स्फीत काल में मासिक वेतन दैनिक मज़दूरी से श्रीधक स्थिर होता है। मुद्रा स्फीत काल में मासिक वेतन दैनिक मज़दूरी से श्रीधक स्थिर कम होती है जब कि दैनिक मज़दूरी शीघ बढ़ती है श्रीर उसके बढ़ने की दर भी श्रीधक होती है।
- (४) साहू कार वर्ग जो व्यक्ति दूसरे को उघार रुपया देने का कार्य करते हैं उन्हें मुद्रा स्फीति काल में हानि उठानी पड़ती हैं। सबसे पहले व्याज दर प्रायः वही रहता है जिससे ऐसे व्यक्तियों को मौद्रिक आय उतनी ही बनी रहने पर वास्तिविक आय कम हो जाती हैं। दूसरे पहले दिये हुये ऋग्ण की रक़म जो इस काल में उन्हें वापस मिलती है उसकी कय शक्ति पहले से बहुत कम होती हैं। अतः वस्तुओं और सेवाओं से उन्हें हानि उठानी पड़ती हैं। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि किसी साहूकार ने १०० रुपये ऐसे समय उधार दिये जब १० रुपये मन गेहूँ विकता था। यदि उस समय वह गेहूँ खरीदता तो १००) से १० मन गेहूँ खरीद सकता था। अपने को १० मन गेहूँ से वंचित रखकर मान लो उसने १०० दिये जो मुद्रा स्फीति काल में उसे वापस दिये गये। इस समय गेहूँ की कीमत मुद्रा स्फीति के कारण २० मन हो जाय तो वह १००) में केवल ५ मन गेहूँ ही प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार उसके पास अब १० मन गेहूँ क्रय करने वाली मुद्रा का प्राप्त हुई। इस प्रकार मुद्रा स्कीति काल में केवल ५ मन गेहूँ क्रय करने वाली मुद्रा प्राप्त हुई। इस प्रकार मुद्रा स्कीति काल में साहूकार वर्ग को हानि उठानी पड़ती हैं।
- (६) इसके निपरीत ऋगी नर्ग को मुद्रा स्कीति काल में लाभ होता है क्योंकि उसके निये ऋग का बोम इलका पहता है। उपरोक्त उदाहरण में मान लीजिये १००) एक किसान ने ऋग लिये थे। उन १००) से उसने उस समय १० मन नेहूँ

खरीदा लेकिन मुद्रा स्फीति काल में १००) का ऋग्ण ब्रदा करने के लिये उसे केवल ५ मन गेहूँ बेचने की ब्रावश्यकता है। इस प्रकार उसे ५ मन गेहूँ का लाम मिल जाता है।

इस प्रकार मुद्रा स्कीति काल में कुछ वर्गों को लाभ तथा कुछ वर्गों को हानि होती हैं फिर भी व्यावहारिक जीवन में उचित मुद्रा-स्कीति से व्यक्तियों को विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि इस काल में रोज़गार ऋषिक होने के कारण सबके हाथों में पर्याप्त मुद्रा होती हैं। इसलिये कुछ वर्गों के लोगों को छोड़कर मुद्रा स्कीति काल में व्यक्ति ऋषिक समृद्धिशाली हो जाता है। मारतवर्ष में इस समय की मुद्रा स्कीति इसका प्रत्यच्च प्रमाण हैं। इतनी तेजी ऋषिक होते हुये भी ऋषिकांश लोग इतने परेशान नहीं हैं जितने १६३५ से पहले सस्ती कीमतें होने पर भी परेशान थे। कारण यही है कि वस्तुयें सस्ती थीं। तब लोगों के पास उनके खरीदने के लिये रुपया नहीं था। ऋजिकल वस्तुयें तेज हैं लेकिन उनके खरीदने के लिये काम रुपया हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मुद्रा संकुचन काल से मुद्रा स्कीति काल ऋषिक ऋच्छा होता है। यद्यिप ऋार्थिक स्थिरता की हिण्ट से दोनों स्थितियाँ ऋवांछुनीय हैं।

मुद्रा संकुचन (Deflation)

मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्कीति मुद्रा प्रसार का विपरीत लच्च्ए है। पीगू (Pigou) के अनुसार मुद्रा-संकुचन कीमतों के गिरने की वह स्थिति हैं, जो उस समय उत्पन्न होती हैं, जब कि वस्तु आं और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आयु की अपेदा अधिक तेजी से बढ़ता है। इस अकार निम्न प्रकार से मूल्य स्तर में हास मुद्रा-पतन कहलाएगा—

(ऋ) उत्पादन यथापूर्व रहता है और मौद्रिक आय घटती हैं। (व) मौद्रिक आय एवं उत्पादन दोनों घटते हैं परन्तु मौद्रिक आय ग्रिधक तेज़ी से घटती है। (स) यि उत्पादन बढ़े और मौद्रिक आय यथापूर्व रहे अथवा दोनों अवस्थाओं में वृद्धि हो परन्तु उत्पादन अधिक तेज़ी से बढ़े। (द) यदि मौद्रिक आय घटे तथा उत्पादन बढ़े।

परन्तु मुद्रा-संकुचन साधारण रूप से निम्न माँति प्रारंभ होता है जो फिर बढ़ता ही जाता है - जब मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है तो मुद्रा संकुचन की नीति सरकार द्वारा अपनायी जाती है। जनता से अधिक टैक्स लिया जाता है, जबर्दस्ती ऋण्ण (Forced Loans लिए जाते हैं. प्रचलित अपरिवर्त्तनीय नोटों को रह किया जा सकता है, उत्पादन में बृद्धि की जाती है, जनता को बैकों से कठिनाई से अथवा

ऋधिक •याज दर पर ऋण मिल पाते हैं, तथा कभी-कभी सरकार साख निर्माण पर भी प्रतिवन्ध लगा देते हैं ।

मुद्रा संकुचन के परिणाम

मुद्रा स्कीति की भाँति मुद्रा-सकुचंन अथवा मुद्रा विस्कीति का प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रथक-प्रथक रूप से पड़ता है। प्रायः इसका प्रभाव विभिन्न वर्गों पर मुद्रा स्कीति के प्रभाव से विपरीत पड़ता है। (१) उदाहरण के लिये विनियोगी वर्ग में उस भाग को लाभ होगा जिलकी आय निश्चित होती है। क्योंकि अब ऐसे व्यक्ति उतनी ही घनराशि में पहले से अधिक वस्तुयें खरीद सकेगा। परन्तु जिन विनियोगियों की ग्राय कम हो जाती है उनको मुद्रा सकुचंन से विशेष लाभ नहीं होता । ऐसे लोगों को साधार**ण**तया हानि ही उठानी पड़ती है । (२ <u>) उत्पादक</u> वर्ग को हानि सहनी पड़ती है। एक तो माँग कम होने से बिक्री कम हो जाती है इस-लिये आय कम हो जाती है। और दूसरे बहुत उद्योग तथा व्यवसाय बंद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके भंडार में एकत्रित माल की मौदिक कीमत कम हो जाती है। उन्हें पहले की अपेदा कम मुद्रा मिलती है। इस अवस्था में कपकों को अधिक हानि उठानी पड़ती है क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि मुद्रा संकुचन काल में अन्य वस्तुओं की अपेदा कृषि उपज की कीमतें अधिक नीचे गिर जाती हैं। इस काल में व्यापारी वर्ग को भी भारी हानि उठानी पड़ती है। माल की बिक्री कम होने से आ्राय घट जाती है तथा मुद्रा अथवा रुपये का फेर उचित रूप से न बँधने के कारण पूँबी की कमी का अनुभव होने लगता है तथा साथ ही साथ रक्खे हुए माल की कीमत गिरने लगती है।

- (३) श्रिमिक वर्ग —श्रिमिक वर्ग को इस परिस्थित में प्रायः हानि उठानी पड़ती हैं क्यों कि चीजों के भाव गिरने से बहुत से उद्योग-धन्धे बंद हो जाते हैं तथा बहुत से मिलों में छुँदनी हो जाती है, बेकारी बराबर फैलती जाती है। श्रिमिकों में काफी निराशा फैल जाती है। यद्यपि की मतें सस्ती होने के कारण उन्हें एक निश्चित संख्या की मुद्रा में पहले की अपेदा अधिक वस्तुयें पात होने लगती हैं पर यह लाभ महत्व-हीन हो जाता है। क्यों के वरोजगारी फैल जाने से बहुत से श्रिमिकों के पास आय का कोई साधन नहीं रहता और उन्हें कभी-कभी भूखों रहना पड़ता है।
- (४) उपभोक्ता वर्ग—उपभोक्ताओं की दृष्टि से यहकाल ग्रन्छा काल होता है। सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रचुरता चर्रो श्रोर दिखलाई-पड़ती है श्रीर श्रव द्रव्य की एक निश्चित संख्या से वे पहले से श्रिधिक वस्तुयें खरीद सकते हैं तथा उनकी बहुत सी श्रावश्यकतायें पूरी हो बाती हैं।
- (४) बहाँ तक ऋगा तथा साहूकारों का सम्बन्ध है विस्फीति काल में ऋगी वर्ग को हानि होती है; क्योंकि उनके ऊपर ऋगा का बोक पहले से अधिक हो जाता

है। कृषक वर्ग पर इस काल में ऋण और भी अधिक हो जाता है। साहूकारों को इस काल में लाभ होता है। बात यह है कि मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाने के कारण ज्याज तथा मूलधन के रूप में मिलने वाली रक्तम की वास्तविक कीमत बढ़ जाती है; परन्तु दूसरे रूप में इस वर्ग को हानि उठानी पड़ती है। ज्यापार तथा उत्पादन के सकुचन के कारण ऋणों की माँग काफी बढ़ जाती है तथा ज्याज की दरें नीचे गिर जाती हैं।

मुद्रा की इन दोनों बातों को लार्ड कीन्स ने बड़े अच्छे ढंग से कहा है, "मुद्रा स्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनावश्यक तथा अनुपयुक्त है।" बास्तव में दोनों परिस्थितियाँ देश के लिये हानिकारक हैं तथा यथा-सम्भव देश की मुद्रा में स्फीति तथा विस्फीति की प्रवृतियाँ न आनी देनी चाहिये।

सदा संस्फीति (Reflation)

कोल के शब्दों में कभी-कभी अवसादी प्रभाव को दूर करने के लिये जान-ब्भकर मुद्रा प्रसार किया जाता है। कभी-कभी अत्यधिक मुद्रा संकुचन हो जाने के कारण मुद्रा की कीमतें बहुत ही नीचे गिर जाती हैं, जिससे उत्पादकों को अधिक हानि उठानी पड़ती है। वे लागत व्यय भी वसूल नहीं कर पाते। उद्योगों का चलना कठिन हो जाता है और देश का आर्थिक जीवन अत्यन्त संकट काल में हो जाता है। ऐसे समय में आर्थिक जीवन की रचा के लिये सरकार को ऐसी नीति अपनानी पड़ती है कि जिससे धीरे-धीरे कोमतों को फिर ऊँचा किया जा सके अर्थात् मुद्रा संस्कीति के द्वारा मुद्रा संकुचन काल में जो मुद्रा चलन से बाहर निकल जाती है उसे फिर चलन में लाया जाता है।

साधारण तौर पर मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा संस्फीति दोनों की एक-सी प्रवृतियाँ हैं। दोनों परिस्थितियों में मुद्रा की मात्रा का विस्तार किया जाता; है और दोनों में कीमतों की वृद्धि होती है। फिर भी इन दोनों में कुछ अन्तर भी है। मुद्रा संस्फीति में कीमतों धीरे-धीरे बढ़ती हैं। मुद्रा स्फीति में वे तेजी से बढ़ती हैं। मुद्रा स्फीति के परिणाम बुरे हो सकते हैं लेकिन मुद्रा संस्फीति के परिणाम बुरे नहीं होते। मुद्रा संस्फीति गिरी हुई कीमतों को ऊँचा उठाने के लिये होती है जब कि मुद्रा स्फीति सामान्य कीमत स्तर से भी कीमतों को अधिक ऊँचा उठाने का प्रयत्न करती है। मुद्रा स्फीति प्राकृतिक भी होती है परन्तु मुद्रा संस्फीति सदैव कृतिम होती है।

मुद्रा अपस्फीति (Disinflation-)

मुद्रा स्कीति को दूर करने की नीति को मुद्रा अपस्कीति कहते हैं। जब किसी देश में मुद्रा स्कीति इतनी अधिक हो जाती है कि वस्तुओं के दाम आवश्यकता से

अधिक बढ़ते ही चले जायँ तो सरकार को बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये मुद्रा अपस्फीति की नीति अपनानी पड़ती है। मुद्रा अपस्फीति तथा मुद्रा संकुचन दोनों की प्रकृति एक-सी है। दोनों से मूल्य स्तर गिरता है। मुद्रा संकुचन में कीमतें सामान्य स्तर से काफी नीचे गिर जाती हैं। यह मंदी की दशायें उत्पन्न करता है, जब कि मुद्रा अपस्फीति आर्थिक जीवन में स्थिरता लाने का प्रयत्न करती हैं।

मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा संकुचन में आजकल मुद्रा स्फीति के ही उदाहरण् अधिक मिलते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री आर्थिक योजनाओं की सफलता के लिए मुद्रा स्फीति पर ही अधिक बल देते हैं। मुद्रा संकुचन की आवश्यकता तो कभी-कभी ही पहती है। इसके विपरीत मुद्रा स्फीति एक सामान्य नीति हो गई है। इसके फलस्वरूप अब मौद्रिक विद्वानों के समन्न यह एक विकट समस्या उपस्थित है कि मुद्रा स्फीति की घातक प्रवृति को किस प्रकार रोका जाय। अधिकांश विद्वानों का मत है कि मुद्रा स्फीति के प्रश्न को अधिक उत्पादन के द्वारा ही सुलभाया जा सकता है के

मुद्रा-प्रसार को रोकने की रीकियाँ — ये रीतियाँ दो उपायों के रूप में हो सकती हैं — वे उपाय जिनसे मुद्रा विस्तार रोका जाए और दूसरे वे जिनसे उत्पादन में वृद्धि हो। मुद्रा मात्रा को कम करने के ये उपाय हो सकते हैं — (१) किसी विशेष प्रकार की मुद्रा को रह कर दिया जाए या अपरिवर्त्तनशील मुद्रा गैरकानूनी घोषित हो जाए।

(३) <u>वेतन, मजदूरी, बैंक जमाओं, ब्याज में श्रानिवार्य कटौती कर दी जाए ।</u> (३) <u>घाटे के बजटों की व्यवस्था रोक कर संतुलित ब</u>जट तैयार किए जाएँ

ताकि नोट प्रकाशन या नई मुद्रा निकासी दूर हो, चलन परिमाण कम हो जाती है।

(४) नसे-नये करों द्वारा एरकार जनता से मुद्रा चलन के कुछ भाग को वापस कर एकती है जिससे शेष में जनता के पास कम मुद्रा रह जाती है। यही दशा सरकार द्वारा जनता से ऋग लेने से होती है। बचत को प्रोत्साहित करके सरकार जितना ऋषिक ऋग ले लेगी, उतनी ही मुद्रा चलन में कम हो जाती है।

प्रकार द्वारा <u>सोना, प्रतिभ</u> तयाँ तथा अन्य स्वीकृत वस्तुयं बेंचना प्रारम्म कर दिया जाता है जिससे जनता के पास ये वस्तुयें जमा हो जाती है और इनके बदले में मुद्रा सरकार के पास पहुँच जाती है। इस प्रकार समाज में पहले की अपेदा कम मुद्रा रह जाती है।

(देर्ज कम्पनियों के लाभांश बाँटने पर प्रतिबन्ध लगा देने से भी मुद्रा चलन की मात्रा कम हो जाती है।

(के बैंक दर में वृद्धि कर देने से केन्द्रीय बैंक द्वारा खुले बाज़ार व्यवसाय

करने से तथा अन्य वैधानिक नियंत्रणों द्वारा बैंकों की साख निर्माण शक्ति को कम करके भी सुद्रा चलन की मात्रा में कमी की जा सकती है।

द्वितीय श्रेणी के उपायों के श्रन्तगंत उत्पादन वृद्धि के लिये निम्मांकित प्रयत्न किये जा सकते हैं —

- (१) देश के मुख्य-मुख्य उद्योगों को विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये कृषि-उत्पादन वृद्धि हेतु <u>किंचाई ब्रादि की स</u>िव-धाओं में वृद्धि तथा नये-नये दंगों से खेती करने को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। उद्योगों की उन्नति के लिये ब्रार्थिक सहायता, करों में छूट, कच्चे मालों, कारीमरों तथा मुशीनों की व्यवस्था ब्रादि उपाय किये जा सकते हैं।
- (२) ऐसे नवीन उद्योग सरकार द्वारा चलाये जा सकते हैं जिनको व्यक्तिगत पंजीपित चलाने में असमर्थ हों । नवीन उद्योगों के प्रारम्भ करने में एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इन उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि प्रारम्भ से ही हो जानी चाहिये नहीं तो लोगों को कार्य अधिक मिलने के फलस्वरूप जनता में मुद्रा चलन की मात्रा के बढ़ जाने की सम्भावना रहती है ।
- (३) श्रायातों को प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे देश के श्रन्दर वस्तुश्रों की मात्रा में वृद्धि हो श्रौर साथ-ही-साथ निर्यातों की कमी होनी चाहिये जिससे देश की वस्तुयें बाहर न जा सकें।

इन उपायों के ऋतिरिक्त मुद्रा प्रसार के मुख्य परिगाम—बढ़ती हुई कीमत स्तर—को रोकने के लिये कीमतों पर नियंत्रण करना भी ऋावश्यक हो जाता है। सरकार को ऋनिवार्य ऋावश्यक वस्तु ऋों को बेंचने के लिये सस्ती दूकानें खोलनी पड़ती हैं। वितरण पर नियंत्रण रखने के लिये राश्मिंग ब्यवस्था भी लागू करनी पड़ती हैं तथा नियंत्रित प्रणालों के विरुद्ध कार्य करने वालों को कड़े से-कड़े दंड देना पड़ता है। तभी बढ़ते हुये मूल्यों की प्रवृत्ति रोकी जा सकती है।

यदि देश में मुद्रा चलन की मात्रा कम रह जाय अथवा वस्तुओं का उत्पादन अधिक बढ़ जाय तो मुद्रा संकुचन की दियति आ जाती है और ऐसी दशा में वस्तुओं के मूल्य गिरने लगते हैं। वस्तुओं के मूल्यों में अधिक गिरावट की दशा भी देश के आधिक विकास में बाधा डालती है। अतः इस दशा को दूर करना भी आवश्यक हो जाता है और इसके लिये उपरोक्त विश्वांत उपायों के विपरीत प्रयत्न करने पड़ते हैं। मुद्रा संकुचन की अवस्था को रोकने के लिये निम्नांकित उपाय दियें जा सकते हैं—

भी केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक दर को कम करके तथा प्रतिभूतियों को जनता से खरीदकर बैकों की साख निर्माण शक्ति को बढ़ा सकता है जिससे जनता के पास अधिक मुद्रा पहुँच जाती है। (र) केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारें राष्ट्रीय विकास की योजनायें बनाकर कार्यदायित्व चेत्र को बढ़ा सकती है जिससे रोजगार बढ़ जाता है ऋौर जनता के हाय में ऋष्क रुपया पहुँच जाता है।

(३) त्रायातों को कम किया जाता है जिससे देश में वस्तुत्रों की मात्रा ऋधिक न होने पावे। निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता है जिससे देशी वस्तुत्रों की माँग विदेशों में ऋधिक हो जाय श्रौर देशी उद्योग-धन्धों की उन्नति हो।

(४) करों तथा भूमि के लगान त्रादि में कमी कर दी जाती है जिससे जनता के पास अधिक मुद्रा बनी रहे।

(५) जो उद्योग कीमतों के गिर जाने के कारण चालू रहने में असमर्थ हो जाते हैं उनका काम चालू रखने के लिये सरकार विशेष प्रकार से आर्थिक सहायता देती है जिससे लोगों को रोजग़ार मिलता रहे और जनता के पास अधिक मुद्रा पहुँचती रहे।

(६ कभी कभी कीमतों को ऊँचा बनाये रखने के लिये पहले से उत्पन्न ची जों को नष्ट भी कर देना पड़ता है। अप्रमेरिका में इस प्रकार के उपाय कई बार काम में लाये गये।

इस प्रकार विभिन्न उगर्यों से कीनतों में दिश्यता लाने का प्रयत्न किया जाता है परन्तु कीमतों की स्थिरता लाने में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता 🤻। सबसे पहली कठिनाई है कि यह निष्कर्ष निकालना कि थोक ग्रथवा खेरीज कीमतों में किन कीमतों में स्थिरता लाई जाय कठिन हो जाता है। सब प्रकार की कीमतों में स्थिरता लाना प्रायः कठिन होता है। श्रौर यदि विभिन्न वस्तुश्रों की तुलनात्मक कीमतों को लाने का प्रयत्न किया जाय तो यह श्रीर भी कठिन हो जाता है। इसके श्रविरिक्त कीमर्तों की स्थिरता भी कभी-कभी श्राधिक विकास के लिये श्रधिक उचित सिद्ध नहीं होती। ऐसी दशा में उत्पादकों में एक प्रकार की निराशा छा जाती है। श्रीर कर्मा-कभी कीमतों के परिवर्तन से बहुत पहले श्रार्थिक जीवन में श्रस्थिरता ऋा बाती है। इसलिये बहुत से ऋर्यशास्त्री क्रीमत स्थिर रखने के उद्देश्य को ही उचित नहीं सममते। यही नहीं कभी-कभी कीमतों की वृद्धि अथवा कभी देश के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उदाहरण के लिये यदि कीमतों में कमी विभिन्न प्रकार के ऋाविष्कारों के कारण उत्पादन व्यय में कमी हो जाने से हो रही है तो इस प्रकार की कमी को रोकना देश के हित में नहीं होगा। उपरोक्त कठिनाइयों के होते हुये भी ऋधिकांश ऋषंशास्त्रियों का यही मंत है कि प्रत्येक देश को ऐसी ही मुद्रा नीति अपनानी चाहिये बो कीमतों में परिवर्तन कम-से-कम करने में सहायक हो सके। कुल अर्थशास्त्रियों का यह भी मत है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य तटस्थ मुद्रा की स्थापना होना चाहिये। वस्तुत्रों की मात्रा में कमी ख्रौर वृद्धि के कारण सामान्य कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों को रोकना उचित नहीं है। लार्ड कीन्स के मतानुसार मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय श्राय का श्रिष्ठकतम करना ही होना चाहिये। जिस प्रकार वृत्तिहीनता दूर हो सके श्रौर पृर्णवृत्ति की स्थिति न हो तब तक सस्ती मुद्रा नीति द्वारा कीमत स्तर को ऊँचा उठाना चाहिये। इस प्रकार मुद्रा नीति के उद्देश्यों के बारे में श्रथशास्त्रियों में काफी मतभेद है। व्यावहारिक दृष्टि से तो यही कहा जा सकता है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य श्रार्थिक स्थिरता प्राप्त करना ही होना चाहिये क्योंकि श्रास्थिरता की दशा सदैव चिन्तनीय होती है। श्रार्थिक स्थिरता से तात्वर्थ प्रगतिशील श्राधिक स्थिरता से है न कि जहाँ की तहाँ श्रार्थिक स्थिरता। प्रत्येक राष्ट्र को ऐसी मौद्रिक नीति श्रपनानी चाहिये जिससे देश के श्रार्थिक विकास में उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे।

प्रश्न

- 9. द्रव्य के मूर्त्यों में परिवर्त्तन का उत्पादन और विवरसा पर गम्भोर प्रभाव पडता है और यह परिवर्त्तन अधिक सामाजिक महत्व रखते हैं, व्याख्या कीजिए। (श्रागरा १६५७)
- 2. Explain carefully the concepts of the supply of money and the demand for money. (Agra B. A. 1957)
 - 3. Discuss critically the quantity theory of money.
 (Agra B. A. 1957)
- 4. What do you understand by the quantity theory of money? What are its limitations? (Agra B. Com. Pt. I, 1956)

श्रध्याय ७

निर्देशांक

(Index Numbers)

मृल्यों में होने वाले परिवर्त्तनों को मापने के लिए सूची श्रंकों श्रथवा निर्दे-शांकों (Index Numbers) की सहायता ली जाती है।

मृत्य निर्देशांकों का अर्थ और महत्व (Meaning & Importance)

मुद्रा परिमाण िद्धान्त मूल्य स्तर परिवर्तन समभाने में चाहे पूर्ण सफल न हो पर व्यवहार में मूल्य-स्तर परिवर्तन समय-समय पर होता रहता है। श्रौर इस मूल्य परिवर्तन के माप की श्रावश्यकता रहती है कि विभिन्न समयों में श्रयवा विभिन्न देशों में मूल्य-स्तर में किस श्रमुपात में परिवर्तन हुश्रा। श्रथवा मुद्रा के मूल्य या उसके क्य शक्ति में किस श्रमुपात में परिवर्तन हुश्रा। श्रथवा मुद्रा के मूल्य या उसके क्य शक्ति में किस श्रमुपात से घटा-बढ़ी हुई। श्रथशास्त्रियों ने इस प्रकार के परिवर्तन को मापने के लिये मूल्य निर्देशांक का सहारा लिया है। मूल्य निर्देशांक की सहायता से इम किसी पूर्व काल के मूल्य स्तरों की तुलना उत्तर काल के मूल्य स्तर से करते हैं। मूल्य-निर्देशांक वे संख्या हैं जो एक निर्धारित समय का श्राधार मानकर चुनी हुई वस्तुश्रों की कीमतों की तुलना उन्हीं वस्तुश्रों की किसी दूसरे समय पर कीमतों से तुलना करने में उपयोग में लाये जाते हैं।

इस प्रकार मूल्य निर्देशांक एक ही दृष्टि में विभिन्न समयों पर मुद्रा की क्रय शक्ति अथवा मूल्य स्तर के परिवर्तन प्रकट करते हैं।

व्यवहार में यह देखा गया है कि वस्तुत्रों के मूल्य का परिवर्तन एक ही दिशा में नहीं होता त्रौर न एक अनुपात में होता है। उदाहरण के लिये यदि जनवरी रह्य क्या जनवरी रह्य में कुछ वस्तुत्रों के मूल्य की तुलना की जाय तो इनमें से कुछ वस्तुत्रों का मूल्य बढ़ा तथा कुछ, वस्तुत्रों का कम हुआ मिलेगा। मान लीजिये गेहूँ, चना, चीनी व घी ये चार ही पदार्थ लिये जायँ तो हो सकता है कि गेहूँ की कीमत २०% बढ़ गई हो। चने की कीमत में १५% की वृद्धि हुई हो, चीनी की कीमत में ५% वृद्धि हुई हो, चीनी की कीमत में ५% वृद्धि हुई हो, तथा घी की कीमत १०% कम हो गई हो तो ऐसी अवस्था में इन परिवर्तनों से सामान्य मूल्य स्तर के परिवर्तन का कोई आभास नहीं मिलता। इन परिवर्तनों को इसी रूप में देखने से हम यह नहीं कह सकते कि मुद्रा की क्रय शिक्ष में जनवरी १६५७ की अपेदा जनवरी १६५० में क्या परिवर्तन हो

गया है क्योंकि मुद्रा की कय शक्ति तीन वस्तुत्रों में विभिन्न श्रनुपात से बढ़ी तथा एक वस्तु में कम हुई। ऐसी दशा में तो यही कहा जा सकता है कि सामान्य तौर पर मुद्रा की कय शक्ति बढ़ी श्रीर न यही कहा जा सकता है कि इसकी क्रय शक्ति कम हुई। यह किठनाई मूल्य निर्देशांक से दूर हो जाती है। उपरोक्त उदाहरण में यदि जनवरी १६५७ में गेहूँ की एक निश्चित मात्रा १०० रुपये में मिलती थी वहीं जनवरी १६५० में ११० रुपये में। १०० रुपये का चना ११५ रुपये में, १०० रुपये की चीनी (१०५) रुपये में, १०० रुपये का ची हिं रुपये में मिलता है। इस प्रकार जनवरी १६५७ में ये चारों चीज १०० रुपये में मिलती थीं उतनी ही जनवरी १६५० में ४२० रुपयों में मिली श्रयांत् (१०० रुपये में मिलती थीं उतनी ही जनवरी १६५० में ४२० रुपयों में मिली श्रयांत् (१०० रुपये की चीज़ के दाम १०५ रुपये हो गये। इस श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि सामान्य तौर पर देश के मूल्य स्तर में ५ % की वृद्धि हो गई श्रयान मुद्रा की क्रय शक्ति में इतनी कमी हो गई। उपरोक्त प्रणाली से मुद्रा की क्रय शक्ति के परिवर्तन मापे जाते हैं तथा इसी पद्धित को मूल्य-निर्देशांक कहते हैं।

मृत्य-निर्देशांक निर्माण करने की निम्नांकित दो विधियाँ हैं:

- (१) सामान्य निर्देशांक (General Index Number)
- (२) भारशील निर्देशांक (Weighted Index Number)

सामान्य निर्देशांक निर्माण करने में सबसे पहले इस बात की आवश्यकता होती है कि हम उस उद्देश्य को भली प्रकार समक्त लें जिसके लिये निर्देशांक बनाने हैं। क्योंकि उसी के अनुसार वस्तुओं का चयन करना ठी़क होगा। यदि हमें कीमतों का ही निर्देशांक बनाना है तो बहुत सी वस्तुत्रों का चयन करना पड़ेगा। श्रौर यदि निर्देशांक निर्माण का उद्देश्य सीमित है तो कुछ सीमित विशेष वस्तुत्रों का चयन करना पड़ेगा । उदाहरण के लिये मान लीजिये मिल मज़दूरों के वेतन में वृद्धि करने की समस्या को इल करने के लिये मूल्य निर्देशांक की त्र्यावश्यकता है तो इस दशा में उन्हीं वस्तुन्त्रों का चयन करना उपयुक्त होगा जिन वस्तुन्त्रों का उपमोग मज़दूरों के द्वारा किया जाता है। यदि इस समस्या को हल करने के लिये धनी वर्ज द्वारा उपयोग की जाते वाली वस्त्यें चयन की जायँ तो यह ठीक न होगा । इसलिये मूल्य निर्देशांक बनाने के लिये सबसे प्रथम उसके उद्देश्य का ज्ञान त्र्यावश्यक भी है। उद्देश्य स्पष्ट होने पर उसके अनुसार उन वस्तुओं का चयन करना चाहिये जिनकी कीमतों के आधार पर निर्देशांक निकालना है। मूल्य निर्देशांक निर्माण के लिये तीसरी बात आधार वर्ष का चुनना है। किस वर्ष को आधार माना जाय जिससे अन्य समय की कीमतों की तुलना की जाय। आधार वर्ष ऐसा होना चाहिये कि जिसमें कीमतों का चढाव-उतार ऋघिक न हुआ हो। कोई ऐसी घटना न घटी हो जिससे तत्कालीन आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा हो । आधार वर्ष असाधारण नहीं होना चाहिये। साधारण तौर पर प्रत्येक देश की सरकार समय-समय पर आधार वर्ष निश्चित करती है। भारत में पहले १६३६ आधार वर्ष माना जाता था। अब १६४६ आधार वर्ष माना जाता है। इसके पश्चात् कीमतों का चुनाव आवश्यक है। इनका चुनाव निर्देशांक बनाने के उद्देश्य पर निर्भर है। यदि मुद्रा के मूल्यों में परिवर्त्तन को दिखाना है तो थोक कीमतें अधिक उपयोगी होती हैं। जीवन-निर्वाह व्यय के सूचनांक बनाने के लिए फुटकर कीमतें चुनी जानी चाहिए। ये कीमतें दैनिक साप्ताहिक एवं मासिक हो सकती हैं। यह निर्देशांक बनाने वाले की सुविधा एवं उद्देश्य पर निर्भर है। पाँचवा निर्णय औसत के निर्धारण के संबंध में होता है। सामान्यतया गणित के औसत का उपयोग होता है परंतु कभी-कभी ज्यामितिक औसत (Geometrical Average) को भी अपनाया जा सकता है।

इसके चयन के पश्चात् सूचनांक बनाना सरल हो जाता है। आधार वर्ष के मूल्यों को १०० मान लिया जाता है। अभीष्ट वर्ष की कीमतें निर्देशांक निकालने के लिए रख दी जाती हैं। आधार वर्ष की कीमतों (१००) के संबंधित मूल्य (Price relatives) निकाल लिए जाते हैं और फिर औसत ज्ञात कर लिया जाता है जिससे उच्चावचन का प्रतिशत ज्ञात हो जाता है।

उदाहरख के लिए निम्न तालिका उपयोगी होगी :--

वस्तुएँ	१६३६ के मूल्य	मूल्य संबंध	१६५⊏ के मूल्य	नए मूल्य संबंध
गेहूँ	प्रतिमन ८ रुपए	१००	२४ रुपए	३००
चावल	" ε "	200	२७ ''	३००
दाल	" १० "	200	80 "	800
कपड़ा	प्रति गज ६ स्राना	200	१ <u>१</u> >>	800
दूघ	प्रति सेर ३ "	१००	१० त्र्याना	३३३
		५००		१७३३
	ऋौसत	200	श्रौसत	. ३४६

इस प्रकार १६३६ ई० की अपेदा १६५८ में वृद्धि ३४६ प्रतिशत हुई।

(२) भारशील सूचनांक (Weighted Index Numbers)—प्रत्येक वस्तु. का महत्व विभिन्न वर्ग अथवा व्यक्ति के लिए विभिन्न रहता है। अतः सूचानांक बनाते समय प्रत्येक वस्तु को उचित महत्व देना चाहिए और इस प्रकार बनाए गए निर्दे- शांक भारशील सूचनांक कहलाते हैं। इस प्रकार इनके बनाने में सामान्य सूचनांकों से कोई विशेष अंतर नहीं है केवल भार या महत्व प्रत्येक वस्तु को दिया जाता है।

निर्देशांक सप्रभाव सूचनांक निकालना

वस्तुएँ	१६३६ स्राघार वर्ष		१९५⊏ का वर्ष			
	मूल्य	भार	भारशील ऋौसत	मूल्य	भार	नवीन भारशील स्रौस
गेहूँ	८)प्रतिमन	પ્	१०० × ५ = ५००	२४)प्रति मन	પ્	३०० × ५ = १५००
चावल	۴) "	8	१०० ×४ = ४००	२७) "	8	३०० X ४ = १२०c
कपड़ा	६आ.प्र.ग.	₹	१०० × ३ = ३००	१-५०,, गज	3	४०० × ३ = १२०¢
दाल	ا در (۱۹۶	२	₹00×₹=₹00	४० ,, मन	२	४०० % २= ८००
दूघ	३ स्त्राना	8	१०० × १ = १००		8	! ३३३ × १ = ३३ ३
प्रतिसेर					•	
		१५	श्रीसत १००		શ્પ્	त्र्रौसत ५०३३ १५ = ३३५.५३

श्रीसतन १६३६ के मूल्य की अपेदा १६५८ में इन वस्तुओं के मूल्यों में २३५'५३% वृद्धि हुई है अर्थात् रुपए की कीमत में २३५'५३% हास हुआ है।

निर्देशांकों के निर्माण में कठिनाइयाँ

निर्देशांकों के निर्माण में व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों प्रकार की किटनाइयाँ हैं प्रथम तो प्रतिनिधि वस्तुओं को चुनना बहुत किठन है, क्योंकि वस्तुओं का प्रयोग तथा उनकी किस्म में परिवर्त्तन होता रहता है। यदि आधारिक वर्ष की वस्तुओं का ही उपयोग होता है तब तो फल ठीक प्राप्त हो सकते हैं अन्यथा वास्तिवक परिणाम नहीं निकल पाते। प्रत्येक वस्तु को भार (Weight) दिया जाता है परंतु यह व्यक्ति और समय के अनुसार बदलता रहता है। अतः प्रयुक्त औसत और भार (Weight) भी अनुमान पर ही आधारित होता है। व्यावहारिक किठनाइयों में मूल्य का एकत्रीकरण आधारिक वर्ष का चुनाव आदि तुटियों से रिक्त नहीं है। अतः निर्देशांक इतने सत्य नहीं हो पाते जितने कि सोचे जाते हैं । रावर्टसन के शब्दों में मुद्रा के मूल्य परिचर्त्तनों को ठीक ठीक नाम लेना न तो सैद्धांतिक हिन्द से ही संभव है और न व्यावहारिक हिन्द से ही। इतना अवश्य है कि यदि सुद्रा के मूल्य में परिवर्त्तन होते हैं और सतर्कता रखी जाती है तो प्रत्यन्त उपभोग के लिए उसकी माप उचित रीति से की जा सकती है। मार्शल ने भी इसी विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि ''क्रय शक्ति की माप केवल असंभव ही नहीं अपित अविचारणीय भी है।'' ये

पिनर्देशांक केवल स्त्रार्थिक परिवर्त्तनों की केन्द्रीय प्रवृत्ति के ही द्योतक होते हैं । उन पर स्त्रिक विश्वास नहीं करना चाहिए ।

प्रश्न

- 1. Explain the nature, construction and uses of Index Numbers of prices.

 (Agra B. Com. I, 1957)
 - २, निर्देशांकों की कठिनाइयाँ बताइए।
- 3. What are the Index Numbers? How are they prepared? Discuss fully. (Agra B. Com. I, 1956)

अध्याय ८

भारतीय चलन का इतिहास

(History of Indian Currency)

श्राधुनिक काल से नवीन देशों की श्रपेक्स भारतवर्ष एक श्रत्यन्त प्राचीन देश है, जो भृतकाल में श्रपनी श्राधिक व श्रपनी श्रौद्योगिक व व्यापारिक उन्नित के लिये प्रसिद्ध रहा है। कोई भी देश बिना मुद्रा के व्यापारिक उन्नित नहीं कर सकता। श्रतः भारतवर्ष में सिक्कों का चलन श्रित प्राचीन काल में भी पाया जाता है। वैदिक, पौराणिक, बौद्ध तथा मुसलिम कालीन साहित्य में कहीं-न-कहीं मुद्रा के उपयोग का वर्णन श्राता है। श्रध्ययन की दृष्टि से भारतीय मुद्रा का विवरण सन् १८३५ ई० से किया जा सकता है। इस समय इस देश में विभिन्न प्रकार के सिक्कों का चलन था। देश जितने राज्यों में विभाजित था उतने प्रकार के ही सिक्कों का चलन था। सिक्कों में भारी विविधता थी। उनके रूप, मूल्य, वजन तथा शुद्धता में श्रिधिक श्रन्तर होता था जिससे व्यापार में भारी श्रमुविधा होती थी।

सन् १८३५ ई॰ में जब कि ईस्ट इंडिया कम्पनी में अपने अधिकृत च्रेतों में एक ही सिक्के के चलन का प्रयत्न किया यहाँ पर सोने व चाँदी दोनों प्रकार के सिक्के विधियाह्य थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने १६५ ग्रेन शुद्ध चाँदी के तौल में १८० ग्रेन अथवा एक तोला वाले चाँदी के रुपये को प्रामाणिक सिक्का घोषित कर दिया। सिक्के का स्वतंत्र मुद्रण रक्खा गया। इस प्रकार १८३५ ई० में भारतवर्ष में रजतमान के रूप में एक धातुमान स्थापित किया गया। इस समय से सोने के रुपये की कीमत चाँदी के स्वर्ण मूल्य के अनुसार निर्धारित होने लगी। सन् १८६४ ई० में भारतीय रुपये का स्वर्ण मूल्य एक रुपया बराबर र शिलिंग के रक्खा गया परन्तु चाँदी की पूर्ति में अधिकता के कारण तथा कुछ देशों में रजतमान की समाप्ति के कारण चाँदी की माँग कम होने से इसकी कीमत में गिरावट प्रारम्भ हुई, यहाँ तक कि १८६२ ई० में एक रुपये की कीमत केवल १ शिलिंग ३ पेंस रह गई। चाँदी की स्वर्ण में कीमतों के गिर जाने के कारण देश में चाँदी के आयात में वृद्धि हुई और स्वतन्त्र मुद्रण प्रणालों के कारण देश में मुद्रा प्रसार अधिक हो गया। कीमतें बढ़ने लगीं। विदेशी व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। विदेशी पूँजी का आयात कम हो गया जिससे देश के औद्योगिक विकास में बड़ी किनाई होने लगी। इधर सरकार को प्रति वर्ष के अगैद्योगिक विकास में बड़ी किनाई होने लगी। इधर सरकार को प्रति वर्ष

ऋंग्रेजी सिक्कों में पर्याप्त धन-राशि (Home Charges) के रूप में भेजनी पड़तीं थी। स्वर्ण में रुपये की क़ीमत गिर जाने से ऋधिक रुपयों की ऋावश्यकता होने लगी जिसके कारण सरकार को करों में वृद्धि करनी पड़ी ऋौर भारत सरकार को ऋपने बजट के सन्तुलन में कठिनाई ऋगुभव होने लगी।

उपरोक्त कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक मुभाव देने के हेतु १८६२ ई॰ में लार्ड हर्शेल की अध्यक्ता में एक समिति नियुक्त की गई जिसे निम्न प्रस्तावों पर मुभाव देने का आदेश दिया गया—

- (१) क्या भारत में चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण समाप्त करके स्वर्णमान ग्रहण कर लिया जाय ?
 - (२) क्या भारत में सोने के सिक्के चालू किये जायँ ?
- (३) क्या रुपये की Sterling (स्टलिंग विनिमय) दर घटाकर १ शिलिंग ६ पेंस कर दी जाय। समिति ने इस समस्यापर भली भाँति विचार करके निम्नांकित दो सुकाव दिये—
- (१) चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण बन्द कर देना चाहिये और सरकार चाँदी के रपयों के ढालने का काम स्वयं अपने हाथ में ले ले।
- (२) सरकारी खजानों में सभी प्रकार के लोकदायित्वों के भुगतान में सोना १ शि॰ ४ पेन्स प्रति रुपये की दर से स्वीकृत किया जाना चाहिये।

भारतीय सरकार ने सिमिति की सिकारिशों को स्वीकार करते हुये सन् १८६३ ई॰ में भारतीय मुद्रण ऐक्ट पास किया इसके अनुसार चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण समाक्ष कर दिया गया तथा उसकी विनिमय दर १ शिलिंग ४ पेन्स प्रति रुपये कर दी गई । रुपये की यह कीमत कुछ समय को छोड़कर १९१६ ई० तक प्रायः स्थिर बनी रही।

सन् १८६८ ई॰ में भारत में पूर्ण स्वर्णमान स्थापित करने के ख्रौचित्य को निश्चित करने के लिये सर हेनरी फाउलर की ख्रध्यच्ला में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने निम्नांकित सुकाव दिये—

- (१) भारत में चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण नहीं होना चाहिये।
- (२) सोने का स्वतन्त्र मुद्रण होना चाहिये। श्रौर ब्रिटिश सावरन को अपरिमित विधिश्राह्म मुद्रा घोषित कर देनी चाहिये।
- (३) रुपया सांकेतिक सिक्का होते हुये. भी ऋपरिमित विधियाह्य बना रहे। श्रीर उसकी विनिमय दर १ शिलिंग ४ पेन्स बनी रहनी चाहिये।
- (४) भारतीय सरकार को विदेशी भुगतानों के लिये पर्याप्त स्वर्ण कोष रखना चाहिये। श्रौर रुपयों के मुद्रण पर जो लाभ प्राप्त हो उसे सोने में एक विशेष सुर दित कोष के रूप में रखना चाहिये जो श्रन्य प्रकार के कोषों से सर्वथा पृथक रहे।

भारतीय सरकार ने प्रायः सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, केवल सोने के सिक्कों का स्वतन्त्र सुद्रण वाला प्रस्ताव ग्रस्वीकृत किया गया। इस प्रकार सन् १८६६ ई० से इस देश में निम्न विशेषतात्रों वाला मौद्रिक मान स्थापित किय गया—

- (१) देश के अन्तर्गत स्वर्ण सिक्कों के प्रचलन का न होना ।
- (२) देश की आन्तरिक आवश्यकताओं के लिये रुपयों का स्वर्ण में परिवर्तन न करना।
- (३) भारतीय सरकार द्वारा रुपये के बदले में एक निश्चित विनिमय दर पर विदेशों को सोना भेजने की व्यवस्था करना।
- (४) इस प्रसार की व्यवस्था को सफल बनाने के लिये स्वित्ति कोषों के एक श्रावश्यक भाग का इंगलैंड में रक्खा जाना।

उपरोक्त में।द्रिक मान देश के लिये हितकर सिद्ध नहीं हुआ। भारत में इसकी कड़ी आलोचना की गई तथा इस विषय पर भारतीय सरकार व भारत सचिव के बीच गहरा मतभेद भी था। अतः १६१३ ई० में इस समस्या को सुलक्षाने के लिये मिस्टर चैम्बरलेन की अध्यक्ता में एक अन्य कमीशन की नियुक्ति की गई जिसने निम्नांकित प्रमुख सुक्षाव दिये—

- (१) स्वर्ण विनिमय मान के रूप में भारतीय मौद्रिक मान चालू रक्खा जाय।
- (२) भारत में सोने के सिक्कों का मुद्रण त्र्यावश्यक नहीं है।
- (३) खर्ण-निधि में वृद्धि होनी चाहिये श्रौर उसे लन्दन में ही रक्खा जाना चाहिये।
- (४) पत्र-मुद्रा प्रणाली को अधिक लोचदार बनाने के लिये स्वर्ण मुद्रा के स्थान पर सोने के उपयोग को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- (५) स्वर्णमान की रजत शाखा को बन्द कर देना चाहिये क्रौर भारतीय सरकार को विनिमय दर को गिरने से बचाने के लिये १ शिलिंग २५६ पेन्स प्रति रुपयों की दर पर भारत में लन्दन पर बिल बेचने चाहिये। भारतीय सरकार इन सिफारिशों को लागू भी नहीं कर सकी कि प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो गया।

प्रथम महायुद्ध काल में भारतीय चलन

युद्ध के प्रारम्भ होते ही सम्पूर्ण देशों के साथ ही साथ न्यापार तथा न्यवसायों में अनिश्चितता आना प्रारम्भ हो गया । विनिमय दर कम होने लगे । लोग सेविंग्ज़ बैंक से अधिक तादाद में अपना रुपया निकालने लगे और पत्र-मुद्रा को रुपये के सिक्कों अथवा सोने में बदलने लगे । यहाँ तक कि थोड़े समय में दस करोड़ रुपये के मूल्य की पत्र-मुद्रा कोषागार को लौटा दी गयी तथा भारत सरकार को उसके लिये १८ लाख पाँड की कीमत का सोना देना पड़ा | विवश होकर भारतीय सरकार ने व्यक्तियों को सोना देना बंद कर दिया और इस प्रकार कुछ काल के लिये स्वर्ण-मान स्थिगत हो गया | नोटों को रुपयों में बदलने पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये । नोटों के प्रचलन में भारी वृद्धि हुई | सन् १६१६ ई० में युद्ध तो समाप्त हो गया परन्तु युद्धकालीन मौद्रिक कठिनाइयाँ वैसी ही बनी रहीं | चाँदी का मूल्य बराबर बढ़ता गया और नोटों को चाँदी में बदलना कठिन हो गया | अतः मौद्रिक सम्बन्धी जाँच के लिये वैविंगटन की अध्यव्हता में १६१६ ई० में मुद्रा प्रणाली में सुधार के सुमाब देने के लिये एक नई समिति नियुक्त की गई | इस समिति के मुख्य सुमाब निम्नांकित थे—

- १) रुपये की विनिमय दर एक रुपया बराबर दो शिलिंग के स्थापित की जाय।
- . (१) सावरन के बदले में रुपये देने का सरकारी उत्तरदायित्व समाप्त कर दिया जाय।
- ३) स्वर्णकोषों का ऋषिक से ऋषिक ऋषि भाग भारत में रक्खा जाय तथा शेष इंगलैंड में।
- (४) भारतीय पत्र मुद्रा प्रणाली में लोच उत्पन्न करने के लिये देश में अनुपातिक निधि प्रणाली प्रहण की चाय तथा पत्र चलन विश्वासाश्रित भाग कुलः चलन के ६०% से अधिक नहीं रहना चाहिये।
- (५) भारत में स्वर्ण के आयात तथा निर्यात का सरकारी नियंत्रणः समाप्त हो जाना चाहिये और रुपये की विनिमय दर स्टर्शलंग के स्थान पर स्वर्ण में नियत की जानी चाहिये।

सन् १६२० ई० में एक भारतीय मुद्रण संशोधन ऐक्ट पास किया गया जिसके अनुसार बेंबिंग्टन समिति की अधिकांश सिफारिशें मान ली गईं। भारत सरकार ने विनिमय दर को एक रुपया बराबर दो शिलिंग पर बनाये रखने का प्रयत्न किया परन्तु इससे सरकार को बड़ी हानि हुई तथा प्रयत्न सफल न हो सका क्योंकि बाज़ार में चाँदी की कीमत २ शिलिंग सोने से अधिक थी। भारत का व्यापाराशेष प्रतिकृल हो गया क्योंकि उच्च विनिमय दर के कारण निर्यात व्यापार में काफी कमी हो गई। सरकार के सभी प्रयत्न असफल होने के कारण सरकार ने विनिमय दर के नियंत्रण की नीति त्याग दी। इसके फलस्वरूप सन् १६२० ई० तक विनिमय दर गिर कर १ शिलिंग ५ पेंस रह गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार ने बैंबिंग्टन स्मिय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करके भूल की।

हिल्टन यंग कमीशन—सन् १६२५ ई० के अन्त तक इगलैंड में स्वर्णमान फिर स्थापित हो गया । इसके कारण रुपये की विनिमय दर स्टर्रालंग तथा सोने दोनों में १ शि॰ ६ पेन्स के बराबर हो गई। इसिलये भारतीय सरकार ने रुपये की विनिमय दर फिर से निश्चित करने के लिये इसी समय हिलटंन यंग की ऋष्यज्ञता में एक नवीन समिति नियुक्त की। इस समिति के निम्नलिखित मुख्य सुभाव थे—

- (१) भारतीय सरकार द्वारा संचालित स्वर्ण विनिमय मान को समाप्त करके स्वर्ण पाट मान स्थापित करना चाहिये क्योंकि तभी जनता का विश्वास भारतीय चलन में पूर्ण रूप से हो सकता है।
- (२) रुपये की विनिमय दर स्टर्शलंग व स्वर्ण में १ शि० ३ पेन्स तक स्थिर की जानी चाहिये।
- (३) चलन तथा साख पर नियंत्रण रखने के लिये भारतवर्ष में भी एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिये। इस बैंक को पहले २५ वर्ष के लिये नोट निर्ममन का एकाधिकार दे दिया जाना चाहिये। ये नोट ऋपरिमित विधिष्राह्म तथा भारतीय सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त होने चाहिये। इन कागजी नोटों के बदले में जनता को रुपये के सिक्के प्राप्त करने का वैधानिक ऋधिकार न हो फिर भी व्यवहार में उन्हें पत्र-सुद्रा के बदले में चाँदी के रुपये प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये।
- (४) स्वर्णमान निधि तथा पत्र चलन निधि को त्र्रालग-त्रालग रखने की प्रया को समाप्त करके इन दोनों कोषों को मिला देना चाहिये।
- (५) भारत सरकार द्वारा निर्गमित एक रुपये वाले नोट प्रस्तावित केन्द्रीय बैंक द्वारा फिर से निकाले जाने चाहिये।

उपरोक्त सिफारिशों सिमिति के अविकांश सदस्यों की सिफारिशों थीं। कुछ सदस्यों ने विशेषकर श्री पुरषोत्तमदास टाकुरदास ने इन सिफारिशों का विरोध किया था। परन्तु भारतीय धारा सभा ने बहुमतीय सुभाव को स्वीकार करके सन् १६२७ ई० में एक करंसी बिल पास कर दिया। उपरोक्त सुभावों में विनिमय दर पर ही बहुत विवाद चला और सैद्धान्तिक दृष्टि से इस विवाद का कुछ ज्ञान होना आवश्यक प्रतीत होता है। १ शि० ६ पें० की दर के पन्न में निम्नांकित मुख्य तर्क दिये गये थे—

- (१) १ शि॰ ६ पें॰ की दर विगत दो वर्षों से स्थिर थी जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यही दर भारत तथा अन्य देशों की आर्थिक दशाओं के द्वारा निर्धारित होकर प्राकृतिक दर हो गईं थी।
- (२) इस दर पर म्रान्तरिक कीमत स्तर, उत्पादन व्यय तथा म्रन्य म्रथं व्यवस्था का समायोजन हो चुका.था। इस दर में परिवर्तन करने से उपरोक्त सन्तुलन विगङ् सकता था।

(३) इससे नीची दर स्थापित करने से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के बजट पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ेगा। विशेषकर होम चार्जेज़ के रूप में भारतीय सरकार को पहते से अधिक रुपया इंगलैंड भेजना पड़ता। श्रीर यह तभी सम्भव था जब श्रिधिक कर लगाये जायँ। इस प्रकार इससे नीची विनिमय दर से जनता के कर भार में वृद्धि का भय था।

(४) कम विनिमय दर पर विदेशी वस्तुयें भारत में महँगी पड़ेगी जिससे

जनता को भोग में कठिनाई होगी।

उपरोक्त तर्क के विरुद्ध १ शि० ४ पेन्स के पन्न में निम्निलिखित तर्क दिये गये थे—

- (१) रुपये की विनिमय दर १ शि० ४ पेंन्स गत बीस वर्षों से चली स्त्रा रही श्री । स्रतः १ शि० ६ पें० के स्थान पर १शि० ४ पेन्स वाली विनिमय दर ही स्रिधिक प्राकृतिक थी।
- (२) इस समय भारतवर्ष में कीमत स्तर १९१४ के समान थी जब कि विनिमय दर १ शि० ४ पें० थी। इसिलये इस समय भी विनिमय दर १ शि० ४ पें० होनी चाहिये। १ शि० ६ पें० की दर कृत्रिम ही कही जा सकती थी क्योंकि इस पर कीमत स्तर, उत्पादन व्यय तथा ऋार्थिक जीवन में सन्तुलन नहीं हो पाया था।
- (३) ऊँची विनिमय दर से विवेचनात्मक उद्योग संरच्या के लाभ समाप्त हो जायँगे। विदेशी वस्तुत्रों की कीमतें इस देश में कम हो जाने के कारण यहाँ के उद्योग विकस्ति न हो सकेंगे।
- (४) ऊँची दर से भारतीय निर्यात में कमी पड़ेगी क्योंिक भारतीय वस्तुओं को कीमते विदेशों में अधिक हो जायँगी जिससे व्यापाराशेष भारत के प्रतिकृत हो सकता है।
- (५) १ शि॰ ६ पें॰ के दर में यह भय था कि यह दर केवल सोने का निर्यात करके ही स्थित किया जा सकता या और इससे देश के स्वर्ण कोषों में भारी कमी हो जाने की आशंका थी। इसके साथ ही साथ ऊँची विनिमय दर से श्रदृश्य मुद्रा प्रसार की सम्भावना होती है जो देश के लिये श्रहितकर होती है।

भारतीय सरकार ने विरोधियों के तर्क पर विशेष ध्यान न देकर बहुमतीय सुभान को स्वीकार करके १६२७ के बिल के द्वारा रुपये की विनिमय दर १ शि॰ . ६ पें० निर्धारित कर दी यद्यपि इस दर को बनाये रखने के लिये भारत सरकार को इंगलैंड में स्टर्शलग ऋग्ण भी लेना पड़ा था।

रिजर्व वेंक

हिलटन यंग कमीशन ने देश में केन्द्रीय बैंक के कार्य करने के लिये रिज़र्व

चैंक के स्थापना की सिफारिश की थी। भारतीय सरकार ने सन् १६२७ ई० में इस विचार को स्थिगित कर दिया परन्तु १६३४ ई० में केन्द्रीय सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक स्थाफ इशिडया ऐक्ट पास किया गया। इस ऐक्ट के स्रानुसार १ स्राप्रैल सन् १६३५ ई० को रिज़र्व बैंक की स्थापना हो गई।

प्रारम्भ में यह बैंक एक अंशघारी बैंक था, जिसकी आंशिक पूँजी ५ करोड़ रुपयों की थी और जो १०० रुपये के अशों में विभाजित की गई थी। सुविधा के लिये देश पाँच भागों में बाँटा गया था: वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा रंगून। अह्या के प्रथक हो जाने के पश्चात् चार ही चेत्र रह गये। इनमें से वम्बई चेत्र में ही अंशों का केन्द्रीयकरण अधिक रहा। बैंक का कार्यभार एक सेन्ट्रल बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के द्वारा चलाया जाता था। इस बोर्ड के सदस्य एक गवर्नर, दो डिप्टी गर्वनर्स के द्वारा चलाया जाता था। इस बोर्ड के सदस्य एक गवर्नर, दो डिप्टी गर्वनर्स के द्वारा चलाया जाता था। इस बोर्ड के सदस्य एक गवर्नर, दो डिप्टी गर्वनर्स के द्वारा चलाया जाता था। इस बोर्ड के सदस्य एक गवर्नर, दो डिप्टी गर्वनर्स के तथा दस डायरेक्टर्स व एक सरकारी आफिसर होता था। प्रत्येक चेत्र एक स्थानीय बोर्ड होता था, जिसके सदस्य तीन मनोनीत व्यक्ति होते थे। राष्ट्रीयकृरण से पहले केन्द्रीय बोर्ड में सोलह सदस्य होते थे और चेत्रीय बोर्ड के आठ सदस्य अधिक होते थे।

जहाँ तक रिज़र्व बैंक के कर्त्तव्यों का प्रश्न है अन्य केन्द्रीय बैंकों की माँति पत्र-मुद्रा की निकासी का एकाधिकार रिज़र्व बैंक को प्रदान कर दिया गया और भारतीय मौद्रिक इतिहास में प्रथम बार भारतीय चलन पद्धित, साख नियंत्रण, एवं मुद्रा संचा-लन एक ही मौद्रिक संस्था (रिज़र्व बैंक) को सौंप दिया गया। पत्रमुद्रा चलन कोष, स्वर्णकोष तथा अधिकोषण कोष इन तीनों का केन्द्रीयकरण कर दिया गया तथा रुपये की विनिमय दर के प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व भी रिज़र्व बैंक को सौंप दिया गया। रिज़र्व बैंक ने अपने सम्पूर्ण कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन किया। १६४६ ई० में रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अधिकारियों को मुआवज़ा दे दिया गया। राष्ट्रीयकरण से इसकी कार्य प्रणाली में कोई विशेष परिवर्त्तन नहीं हुआ।

रिजर्व बैंक की स्थापना होते ही अमेरिका ने अधिक मात्रा में चाँदी खरीदना आरम्म कर दिया था। इससे चाँदी के मूल्य में वृद्धि हुई और भारत सरकार ने संकटकालीन अवस्था के लिये एक-एक रुपये के नोट छापने का विचार कर लिया परन्तु १६३६ ई० में ही चाँदी के माव गिर गये और सन् १६३६ ई० तक चाँदी का सरलता से निर्यात होता रहा। १६३६ ई० से द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाने के कारण भारतीय चलन में विशेष परिवर्त्तन हुये। पर इससे पहले सन् १६२१ ई० में इंगलेंड द्वारा स्वर्णमान का परित्यागे करने पर भारतीय मुद्रा प्रणाली पर भी काफी प्रभाव पड़ा। इसका उल्लेख करना भी आवश्यकीय है। स्वर्णमान के स्थगित करने के फलस्वरूप स्टरिलंग का मूल्य स्वर्ण में कम होने लगा। चूँकि भारतीय स्पया स्टरिलंग से सम्बन्धित कर लिया गया था इसलिये भारतीय रुपये का स्वर्णमूल्य

भी शीव्रता से कम होने लगा । इस मूल्य पतन को रोकने के लिये भारत सरकार ने विनिमय नियंत्रण लागू किया । परन्तु बनवरी सन् १६३२ के अन्त तक ही विनिमय नियंत्रण को समाप्त कर देना पड़ा । इस काल की सबसे बड़ी विशेषता ऋधिक मात्रा में सोने का निर्वात रही है। प्रथम वर्ष में ही लगभग ५० करोड़ रुपये का सोना देश के बाहर चला गया। सोने का भाव रुपये में उत्तरोत्तर बढता ही गया। परि-गामस्वरूप सोने के निर्यात में भी वृद्धि होती रही। सन्१६३८ के मध्य तक लगभग ३५० करोड़ का सोना देश से बाहर चला गया था। इस स्वर्ण निर्यात के सम्बन्ध में इस समय बहुत मतमेद रहा । राष्ट्रीय विचारधारा के लोग इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण नियति को देश के लिये ऋहितकर समभते थे। उनके विचार से भविष्य में केन्द्रीय बैंक की स्थापना के साथ-ही-साथ भारतीय सुद्रा चलन को सुद्दढ बनाने के लिये स्वर्ण की स्नावश्यकता पड़ेगी । यदि स्वर्ण इतनी मात्रा में बाहर चला जायगा तो अविष्य में स्वर्ण की कमी बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त जब संसार के अन्य देश स्वर्ण एकवित करने में लगे हुये हैं उस समय भारत को सोने का निर्यात करना उचित प्रतीत नहीं होता । ऋतः इस विचारधारा के लोगों ने भारतीय सरकार को स्वर्ण निर्यात पर रोक लगाने की माँग की, परन्तु भारतीय सरकार ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया वरन् स्वर्ण निर्यात को श्रावश्यक तथा उचित समभा। सरकारी मत के समर्थकों का कहना था कि भारतवर्ष में सैकड़ों वर्षों से सोना बाहर से इकट्टा हो रहा है। यदि कुछ, समय के लिये इसका निर्यात हो जाय तो कोई हानि नहीं। साय-ही-साथ इस समय सोने के बेचने से भारतीय जनता को बहुत लाभ हो रहा है। क्योंकि सारा सोना सस्ते दामों पर खरीदा गया था बढ़ती हुई कीमतों का लाम उठाने से जनता को वंचित करना ठीक नहीं है। अन्त में इस अवसाद काल में व्यापाराशेप में संतुलन स्थापित रखने के लिये स्वर्ण निर्यात स्रावश्यक है। इस तर्क के ब्राधार पर सरकार ने स्वर्ण निर्यात में किसी प्रकार की बाधा डालना उचित नहीं समभा । यह ऋवश्य है कि यदि रुपये की विदेशी क्रीमत स्वतन्त्र रूप से निर्धा-रित होने दी बाती तो भारतीय सोना इतनी ऋधिक मात्रा में विदेशों में न जाता। परन्तु ऐसा न हो सका । १६३६ ई० में द्वितीय महायुद्ध के कारण परिस्थितियाँ ही बदल गईं ऋौर स्वर्ण का निर्यात भी कम होने लगा।

प्रश्न

प्रथम महायुद्ध कालीन भारतीय चलन की दशा का वर्णन कीजिये ।

श्रध्याय ६

भारतीय चलन का इतिहास (क्रमशः)

द्वितीय महायुद्ध तथा भारतीय चलन

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ में भारतीय चलन की निम्नलिखित विशेषतायें थीं—

- (१) भारतीय प्रामाणिक मुद्रा रुपया था।
- (२) रुपये के सिक्के, नोट तथा अठनी के सिक्के असीमित विधिमाह्य थे।
- (३) उपरोक्त सिक्कों के ऋतिरिक्त देश में चाँदी तथा गिलट की चविन्नयाँ दोस्रिनियाँ तथा इकिन्नियाँ ऋौर ताँ वे के पैसों का प्रचलन था।
- (४) देश का चलन स्टरिलंग विनिमय मान पर आधारित था तथा रुपये स्टरिलंग की विनिमय दर एक रुपया बराबर एक शि॰ ६ पेंस के थी।
- (५) सितम्बर सन् १९३६ ई॰ में १८० ६ करोड़ रुपयों की पत्रमुद्रा प्रचलित थी।

युद्ध प्रारम्भ होते ही देश में उत्पादन तथा व्यापार का विस्तार हुन्ना। कृषकों की ऋार्थिक दशा में पर्याप्त सुधार होने लगा। ऋौद्योगिक तथा व्यापारिक प्रगति तथा मूल्य स्तर के ऊँचे होने के कारण मुद्रा की माँग में काफी वृद्धि हुई ऋौर इसके साथ-ही-साथ रुपये के सिक्के प्रचलन से शनैः शनैः निकलने लगे। ऋतः एक-एक रुपये के नोट चालू किये गये। कुछ समय के पश्चात् विशेषकर फ्रांस की पराजय के पश्चात् जनता में भारतीय पत्रमुद्रा के प्रति विश्वास कम होने लगा। इसके फलस्वरूप लोगों ने पत्रमुद्रा को रुपयों में परिवर्त्तन करना प्रारम्भ कर दिया, यहाँ तक कि करीब ५ करोड़ रुपये के नोट प्रति सप्ताह परिवर्तित किये जाने लगे। ऋौर यह ऋधिकांश रुपया प्रचलन में न रह कर संचित कोप में जाने लगा। इस दोष को दूर करने के लिये १५ जून सन् १६४० को भारत सरकार ने एक ऋध्यादेश द्वारा रुपयों का व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक ऋगवश्यकता से ऋधिक मात्रा में जभा करना दंडनीय बना दिया।

फिर भी चाँदी के िकों. की माँग इतनी श्रिधिक बनी रही कि भारतीय टक्सालों इस माँग को पूरा करने में श्रिस्फल रहीं। इसके फलस्वरूप बाज़ार में चाँदी के सिक्कों की कीमत नोटों से श्रिधिक हो गई तथा रुपये के सिक्कों व छोटे-छोटे सिक्कों की भारी कमी पड़ने लगी। १६४२ व ४३ में तो छोटे-छोटे सिक्कों की इतनी अधिक कमी हो गई कि विभिन्न शहरों में पोस्टकार्ड तथा टिकट छोटे-छोटे सिक्कों का कार्य करने लगे। जनता को बहुत असुविधा होने लगी। इस असुविधा को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने भारत सुरत्ता विधान के अन्तर्गत छोटे-छोटे सिक्कों का संचय करना दंडनीय घोषित कर दिया। साथ ही साथ इन सिक्कों की पूर्ति बढ़ाने के लिये बम्बई तथा कलकत्ते की टकसालों में पैसों का टालना प्रारम्म किया गया। छोटे सिक्कों की टलाई के लिये लाहौर में एक नई टकसाल की स्थापना की गई। गिलट का अधन्ना चालू किया गया। इकन्नी तथा दोअन्नी में गिलट की मात्रा बढ़ा दी गई। पैसे का सिक्का छेद वाला तथा छोटा कर दिया गया। छोटे छेद वाले पैसों की योजना प्रायः असकल रही क्योंकि जनता इन पैसों का अन्य रूप से प्रयोग करने लगी और सरकार को इन पैसों का टालना बन्द कर देना पड़ा। तेजी के साथ छोटी कीमत के सिक्को निकालने के कारण घीरे-धीरे छोटे सिक्कों की कमी दूर हो गई।

चाँदी के रुपयों की समस्या हल करने के लिये रिज़र्व बेंक ने एक रुपये का नोट निकाला, उसे अपरिमित विधि प्राह्म घोषित किया तथा उन्हें चाँदी के रुपयों में बदलने का कोई उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया। इसके अतिरिक्त चाँदी की बचत करने के लिये देश में प्रचलित सभी चाँदी के सिक्कों की प्रामाणिक शुद्धता कम कर दी गई। चवन्नी अठन्नी तथा रुपये की शुद्धता के से घटाकर के कर दी गई। चवन्नी अठन्नी तथा रुपये की शुद्धता के से घटाकर के कर दी गई। चवन्नी अठन्नी तथा रुपये की शुद्धता के स्वयों व अठिन्नयों का विमुद्रीकरण कर दिया गया। क्वम्बर सन् १६४१ में एडवर्ड के रुपये तथा अठिन्नयों का विमुद्रीकरण कर दिया गया। नवम्बर सन् १६४१ में एडवर्ड के रुपये तथा अठिन्नयों का विमुद्रीकरण कर दिया गया। नवम्बर सन् १६४१ में एडवर्ड के रुपये तथा अठिन्नयाँ मी बंद कर दी गई। १ नवम्बर १६४३ से जार्ज पंचम तथा जार्ज बच्ठम की कै शुद्धता वाली अठिन्याँ व रुपये भी बंद कर दिये गये और इनके स्थान में चाँदी की कम मात्रा वाले नवीन सिक्के चलाये गये।

इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप भारत की मुद्रा प्रणाली में स्त्रविश्वास तथा स्त्रपर्यात पूर्ति के घक्कों का सरकार ने सफलतापूर्वक निराकरण कर दिया। परन्तु चलन तथा साखमुद्रा का अत्यधिक विस्तार और उसके कारण उत्पन्न होने वाली कीमत वृद्धि रोकने में सरकार असफल रही। वास्तव में इस दिशा में कोई प्रयत्न भी नहीं किया गया। प्रत्युत इस काल में सरकार की सामान्य नीति अधिक से स्त्रधिक पत्र मुद्रा निकालकर मुद्रा व्यय को पूरा करना था। अतः पत्रमुद्रा तथा साख मुद्रा बरावर बढ़ती ही चली गई। इसके फलस्वरूप मूल्य स्तर भी बरावर ऊँचा होता गया। १६४३ ई० से देश में मुद्रा स्फीति को स्थिति उत्पन्न हो गई। यद्यपि द्वा स्फीति को दूर करने के लिये सरकार ने जनता से अपृण्य लेना तथा नये नये कर

लगाना प्रारम्भ कर दिया । फिर भी इन दोनों कामों में सरकार असफल रही । न तो मूल्य स्तर बढ़ने से कक सका और न जीवन निर्वाह व्यय ही कम हुआ।

यद्यपि मूल्य स्तर की वृद्धि होने के बहुत से कारण थे परन्तु प्रमुख कारण चलन तथा साख मुद्रा का ऋत्यधिक विस्तार ही था। युद्ध काल में चलन की कुल वृद्धि ११६८: ६४ करोड़ रुपया थी जिसका ८२.५% प्रतिशत पत्रमुद्रा की वृद्धि ११.८ रुपये के सिक्कों की वृद्धि तथा ५.६ प्रतिशत केलगभग छोटे सिक्कों की मात्रा की वृद्धि के कारण हुआ था। १६३६ ई० में नोटों की चलन १८० करोड़ रुपयों के बराबर था। यह चलन १६४५ ई० में बढ़कर १०३४ करोड़ रुपयों के बराबर हो गया। इसी प्रकार १६३६ ई० में मूल्यांक को यदि हम १०० मान लें तो १६४५ ई० में यही मूल्यांक बढ़कर २५० हो गया।

जहाँ तक विनिमय दर का सम्बन्ध है नियंत्रण होने के कारण विनिमय दर में कोई विशेष परिवर्त्तन नहीं हुआ यद्यपि भारत का व्यापाराशेष निरंतर अनुकूल ही बना रहा और यह अनुकूलता बढ़ती ही गई। सन् १६३८ व ३६ ई॰ में व्यापाराशेष की अनुकूलता १८ करोड़ रुपये के लगभग थी, जो १६४३ व ४४ ई॰ में ६१ करोड़ के लगभग हो गई। इस अनुकूल व्यापाराशेष के बदले में भारत को न तो सोना प्राप्त हुआ और न वस्तुयें ही। इसके बदले में बृटिश सरकार ने स्टर्शलंग प्रति-भूतियाँ दी जिनका उपयोग रिजर्व बैंक के द्वारा निधि के रूप में किया गया जिसके आधार पर देश में पत्र मुद्रा का विस्तार किया गया।

युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण सरकार को विनिमय नियंत्रण करना पड़ा, श्रातः भारत रच्चा श्रध्यादेश के श्रन्तर्गत भारतीय सरकार ने सिक्कों, धातुश्रों, प्रति-भृतियों तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवसायों के नियंत्रण का सारा भार रिज़र्व बैंक को सौंप दिया। प्रारम्भ से ही कड़ा विनिमय नियंत्रण लागू कर दिया गया। विदेशी विनिमय व्यवसाय के लिये केवल कुछ भारतीय सम्मिलित पूँजी बैंकों तथा विदेशी बैंकों को लाइसेन्स दिये गये।

युद्धकालीन विनिमय नियंत्रण की मुख्य विशोषतायें निम्नांकित थीं-

- (१) साधारण तौर पर साम्राज्य देशों की मुद्रास्त्रों के क्रय-विकय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था।
- (२) साम्राज्य के बाहर के देशों की मुद्रा के क्रय-विक्रय पर कठोर नियंत्रण लगाया गया।
- . (३) यात्रा व्यय तथा व्यक्तिगत भुगतानों के लिये यथासम्भव सुविधा प्रदान की जाती थी।
- (४) विदेशी विनिमय व्यवसाय समय-समय पर लंदन द्वारा घोषित विनिमय दरों के आधार पर किया जाता था।

- (५) रुपये की विनिमय दर १८ पेंस पर ही स्थिर रक्खी गई।
- (६) रिज़र्व बैंक की आज्ञा के बिना विदेशों से प्रतिभूतियाँ खरीदना आधवा उनका निर्यात करना रोक दिया गया था।
- (७) विनिमय नियंत्रण के दृष्टिकोण से कामनवेल्थ देशों को एक स्टर्गलिङ्ग के त्रेत्र में मान लिया गया था झौर इस त्तेत्र के भीतर कोषों के इस्तांतरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। परन्तु इस त्तेत्र के बाहर कोषों के इस्तांतरण पर कड़ा नियंत्रण रक्ला गया।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का मुख्य उद्देश्य पूँजी के निर्यात श्रीर विदेशी दरों में होने वाले स्नेह को रोकना था। इसके लिये श्रायात नियंत्रण तथा निर्यात नियंत्रण की कठोर नीतियाँ श्रपनाई गई क्योंकि विनिमय नियंत्रण के श्रयनार्गत विना लाइसेन्स के स्टर्शलंग चेत्र के बाहर के देशों से कोई भी माल नहीं मँगाया जा सकता था। श्रीर न कोई बैंक बिना रिज़र्व बैंक की श्राज्ञा प्राप्त किये विदेशी विनिमय बैंच सकती थी। यह नीति विदेशी व्यापार के भारी श्रयंतुलन को रोकने के लिये तथा श्रायातों को उचित प्राथमिकता देने के लिये श्रावश्यक थी। इसी प्रकार निर्यातों पर भी नियंत्रण किया गया जिससे निर्यातों को कीमत विदेशों में न रहकर भारत में श्राज्ञाय। उनकी कीमतों का भुगतान बैंक द्वारा निश्चित रीति से हो। साधारण तौर पर श्रमेरिका को निर्यात हुई की वस्तुश्रों का मूल्य बृटिश सरकार को हस्तारित कर दिया जाता था तो उसे साम्राज्य डालर कोष में जमा करती थी श्रीर बाद में उसका उपयोग युद्ध सामग्री खरीदने के लिये किया जाता था।

युद्धोत्तर काल में भारतीय चलन

साम्राज्य डालर कोष

युद्ध के पहले स्टर्रालंग चेत्र के अधिकांश सदस्य देश अपने-अपने विदेशी विनिमय कोषों को लन्दन में स्टर्रालंग के रूप में रक्खा करते थे। स्टर्रालंग का अन्तर्राष्ट्रीय मान था। अतः वह किसी भी देश की मुद्रा में परिवर्तित हो जाता था। युद्ध प्रारम्भ होते ही स्टर्रालंग की परिस्थिति में परिवर्तन हो गया। अब स्टर्रालंग के बदले में प्रत्येक देश की मुद्रा का मिलना किंठन हो गया। कुछ सदस्य देश अपनी विदेशी मुद्रा को अपनी संरचता में रखने लगे और उसके क्रय व विक्रय में प्रतिवर्ग्य लगाने लगे। इस विषय में समान नीति निर्धारण हेत्र तथा सफल युद्ध संचालन के लिये स्टर्रालंग चेत्र की सम्पूर्ण विदेशी विनिमय आय को एक सामूहिक कोष में रखने के लिये सम्बन्धित देशों में एक समभौता हुआ। इसके अनुसार बैंक आफ इंगलंड तथा बृटिश कोषागार के संरच्ण में इस प्रकार का कोष रखने की व्यवस्था

की गई। इस कोष की सबसे प्रमुख मुद्रा अमेरिकन डालर थी, जिसके कारण इस कोष का नाम साम्राज्य डालर कोष रक्खा गया। इस कोष में से प्रत्येक सदस्य देश केवल उसी समय विदेशी विनिमय प्राप्त कर सकता या जब उसकी आवश्यकता अर्मनवार्य हो। भारतवर्ष में १६३६ ई० से १६४६ ई० तक ४०५ करोड़ रुपये की कीमत का डालर इस कोष में जमा किया या जब कि उसका समकालीन व्यय केवल २५० करोड़ रुपये के बराबर या। फिर विदेशी विनिमय व्यय को कम करने के लिये भारत सरकार सतत् प्रयत्न करती रही। कठोर आयात नियंत्रस नीति द्वारा वस्तुओं के आयात में काफी कमी की गई। १६४२, ४३ ई० में उचार पट्टा प्रकाली का प्रारम्भ हुआ जिससे डालर में अगतान करने की आवश्यकता काफी कम हो गई। इस प्रणाली के अन्तर्गत भारत में मशीनरी, स्पात तथा अन्य सामानों का काफी आयात हुआ और जैसे-जैसे युद्ध कालीन स्थित सरल होती गई आयात नीति उदार बनती गई। फिर भी अमरीका से भारी मात्रा में खाद्यान्न तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं. के आयात करने के कारण विदेशी विनिमय की कठिनाई बनी ही रही। स्वर्फ का भी पर्याप्त नियंत्रण रक्खा गया। सोने का नियंत्र बहुत ही सीमित कर दिया गया।

इमारे पौंड पाउने

दितीय युद्ध में भारतीय मुद्रा चलन के अन्तर्गत पींड पाउने की समस्या एक विशेष रूप से उपस्थित हुई । युद्ध से पूर्व भारत के ऊपर इंगलैंड का बहुत-सा ऋण्या और यह ऋण्या निर्यात आधिक्य के द्वारा शनी:-शनी: अदा किया जा रहा था। युद्ध काल में निर्यात आधिक्य में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि भारत ने अपना पुराना ऋण्या तो चुका ही दिया और इसके अतिरिक्त भारत का इंगलैंड पर बहुत अधिक ऋण्या हो गया।

इंगलेंड उस समय इस ऋणका भुगतान करने में असमयं था। अतः भारत से प्राप्त वस्तुओं के मूल्य को इंगलेंड अपने यहाँ स्टरिलंग प्रतिमृतियों के रूप में भारत के नाम से जमा कर लेता था और चूँकि भारतीय पत्रमुद्रा का निर्ममन स्टरिलंग प्रतिमृतियों के आधार पर हो सकता था तो भारत के नाम से जमा की गई स्टरिलंग प्रतिमृतियों के आधार पर भारत में नोट छाप लिये जाते थे और इन्हीं नोटों से भारतीय निर्यातों का भुगतान कर दिया जाता था। ये प्रतिमृतियों उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई जिनसे जैसा कि पहले लिखा जा चुका है देश का पुराना ऋण चुक गया और बाद में देश के नाम से यह धन राशि स्टरिलंग के रूप में जमा होती गई। इस प्रकार इंगलेंड के द्वारा भारत से माल खरीदने के कारण तथा डालर कोष में जमा किये हुये विदेशी विनिमय को भी स्टरिलंग प्रतिभृतियों में परिवर्तित कर देने

के कारण पौंड पाउने में वृद्धि होती गई, यहाँ तक कि सन् १६४७ ई० में इस पौंड पाउने का मूल्य १७०० करोड़ रुपये के लगमग था।

युद्ध के पश्चात् इन पौंड पाउनों के भुगतान करने की समस्या उपस्थित हुई। इस विषय पर चर्चा तो युद्ध काल से ही होने लगी थी ख्रीर पौड पाउने भुगतान के सम्बन्ध में इंगलैंड में दो विभिन्न मतों के व्यक्ति थे। कुछ लोग तो पौंड पाउनों के पूर्ण रूप से भुगतान करने के पक्त में थे। उनका कहना था कि भारतवासियों: ने ऋघिक परिश्रम करके तथा अपने स्वयं के उपमोग को कम करके कष्ट सहते हुये युद्धकाल में इंगलैंडवािसयों की सहायता की थी, परन्तु यह सहायता किसी दान अथवा आभार आदि के रूप में नहीं थी। इसका आधार केवल आर्थिक था। भारतीयों ने हमें वस्तुयें दी थीं । ऋन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के श्राधार पर ऋतः ऋार्थिक व नैतिक दोनों दृष्टियों से पौंड पाउनों का पूर्ण भुगतान होना चाहिये। इसके विपरीत विपिन्नियों का मत यह था कि पहले तो पौंड पाउनों का भुगतान ही नहीं होना चाहिये श्रौर यदि भुगतान करने के पत्त में निर्णय किया जाय तो पौंड पाउनों की रकम में काफी कमी करके भुगतान करना चाहिये। उनके इस प्रस्ताव का आधार यह था कि इंगलैंड युद्ध में केवल अपने स्वार्थ के लिये ही नहीं कृदा था वरन् उसने तो संसार के विभिन्न देशों की रचा करने के लिये यह कदम उठाया था। इंगलैंड ने युद्ध में पड़कर भारत को भी शत्रुख्नों के हमले से रच्चा की। इसलिये इंगलैंड द्वारा युद्ध में किये हुये व्यय के ऋधिकांश भाग को भारत के द्वारा भुगतान होना चाहिये। स्रतः भारत के नाम से जमा पौड पाउने के धन राशि को भारत की स्रोर स्रार्थिक योग समका जाना चाहिये। इस प्रकार भुगतान करने अथवा न करने के ऊपर बहुत दिनों तक वादविवाद चलता रहा परन्तु अन्त में इंगलैंड की सरकार ने प्रायः सम्पूर्ण धनराशि को घीरे-घीरे सुविधानुसार भुगतान करने का निश्चय किया।

१५ अगस्त १६४७ को भारत का भारतीय संघ एवं पाकिस्तान में विभाजन हुआ। इसी समय देश के चलन का भारत और पाकिस्तान में १३ और ३ के अनुपात में विभाजन किया गया। विदेशी ऋणों को चुकाने का दायित्व भारत ने लिया और पाकिस्तान ने अपना भाग भारत को किश्तों में चुकाने का वायदा किया। परन्तु इस राशि का कोई भी अंश पाकिस्तान ने नहीं चुकाया।

रुपए का अवमूल्यन (Devaluation of Indian Money)

अपने विषरीत व्यापाराधिक्य को जुकाने के इंगलैंड के सारे प्रयत्न विफल रहें तो अंत में अचानक ही १८ सितम्बर १६४६ को उसने अपने पौंड का अव-मूल्यन कर दिया जिसके अनुसार डालर मूल्य ४-०३ प्रति पौंड के स्थान पर २.८० डालर प्रति पौंड रह गया। मारतीय रुपए का स्वतंत्र रूप से अप्रतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई महत्व न था। वह स्टरिलंग मुद्रा से पूर्ण रूपेण संबंधित था। पौंड की कीमत घट जाने के कारण भारत के पौंड पावनाओं में कमी होने का भय था। यद्यिप देश में मुद्रा प्रसार था और पड़ोसी देश पाकिस्तान ने मुद्रा अवमूल्यन न करना ही निश्चय किया परंतु उपरिलिखित परिस्थित में भारत को रुपये का अवमूल्यन करना ही पड़ा। रुपए की कीमत १ शि० ६ पें० से घट कर १ शि० ४ पेंस रह गई। कहा जाता है कि इसके परिणामस्वरूप १६५० तक १७२ करोड़ रुपए की घाटे में कमी हो गई। और १६५०-५१ में घाटा केवल ४ करोड़ हो रह गया। परंतु कोरिया युद्ध के बाद व्यापारिक मंदी आरम्भ हुई और मारत का व्यापारिक घाटा २३२ ६२ करोड़ १६५२-५३ ई० में और १६५६-५७ ई० में ३४० करोड़ रुपया हो गया। दूसरा परिणाम यह हुआ कि देश में कीमतें ऊँची उठनी आरम्भ हुई। तीसरे पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन न होने के कारण पाक रुपये की कीमत १४४ भारतीय रुपया हो गई। भारत ने इस दर को अस्वीकार कर दिया और नतीजा यह रहा कि भारत-पाक व्यापार स्थिगत हो गया। परंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रयत्नों के कारण यह खिंचाव कम हो गया। डालर चेत्रों से अपना व्यापार बढ़ा है।

रुपये का पुनमूल्यन (Revaluation)

जैसे कि पीछे लिखा जा चुका है रुपये का श्रवमूल्यन १६४६ में करके उसकी कीमत विदेशी बाजार में गिरा दी। श्रव प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि रुपये का पुनर्मूल्यन करके उसकी विदेशी कीमत में वृद्धि की जाए। इसके लिए. निम्नांकित बातों का सहारा लिया जाता है—

पुनर्मूल्यन से खाद्यान्न, कच्चा माल व मशीनों आदि आयातित वस्तुओं की कीमत घट जायगी और निर्यातों का पहले की अपेचा अधिक मूल्य मिलेगा। १६४६ में अवमूल्यन द्वारा देश में मूल्य स्तर जो ऊपर चढ़ गये थे वे भी नीचे हो जायँगे और साथ ही भारत-पाक के व्यापारिक व आर्थिक संबंधों में भी सुधार होगा। इस प्रकार रुपए का पुनर्मूल्यन मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति रोकेगा। उद्योगों के लिये आवश्यक सामग्री सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराएगा और आंतरिक अर्थं व्यवस्था को सुदृढ़ बनायेगा।

परन्तु पुनर्मूल्यन के कारण देश की आयातित वस्तुओं (जिनकी देश के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्यता है) का आयात रक सकता है। अथवा विदेशी लोग भारत के साथ मूल्य विभेद (Price differentiation) नीति को अपना सकते हैं और इस प्रकार आयात मूल्य में अधिक पड़ सकते हैं। फिर भारत का अनुसरण अन्य पड़ोसी देश पाक, लंका, बरमा भी कर सकते हैं और पूर्व वांछित

लामों से बंचित होना पड़ सकता है। पुनर्मूल्यन से निर्यातों के दाम बढ़ेंगे। इससे देश को आर्थिक हानि होने की अधिक संमावना रहती है क्योंकि जूट, चाय, कपास एवं सूती वस्त्र आदि अधि मूल्यत माल विदेशों में प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप में नहीं ठहर सकेगा। किसी मुद्रा का बार-बार मूल्य परिवर्त्तन करते रहने से राष्ट्रीय सम्मान को आधात पहुँचता है। भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री देशमुख के अनुसार पुनर्मूल्यन देश के घाटे को एक बड़े परिमाण में बढ़ा देगा। इधर पाकिस्तान ने रूपए का पुनर्मूल्यन करके भारतीय रुपये के पुनर्मूल्यन के प्रश्न ही को हटा दिया है। भारत में मुद्रा स्कीति (Inflation in India)

भारत में मुद्रा स्फीति किस अंश तक है इस विषय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विभिन्न विचार हैं परन्तु इस बात से सभी लोग सहमत हैं कि देश में मुद्रा-प्रसार की स्थिति विद्यमान है और इसके प्रति उदासीन रहा गया तो यह भयंकर रूप धारण कर लेगी। मुद्रा-प्रसार के लच्चण द्वितीय युद्ध काल के समय तथा स्वाधीनता के पश्चात् ही दृष्टिगोचर होने लगे थे परन्तु भारतीय राजनीतिशों का ध्यान इस स्थिति की ओर काफी समय बाद आकृष्ट हुआ।

मद्रा प्रसार के कारणों में प्रमुख कारण ये हैं—

(१) देश में चलन तथा साख मुद्रा का विस्तार श्रत्यधिक मात्रा में बहुता जा रहा है। युद्ध काल में यह प्रसार भयंकरतापूर्वक हुन्ना। इसका कारण या कि युद्ध संबंधी खर्चों को चलाने के लिए सरकार ने श्रिधिक नीटों को छापा तथा साथ ही नागरिक उपयोग को कम करने की हिष्ट से भी कीमतें बढ़ाना उचित ठहराया गया। मारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को दिये गये श्रुणों के बदले में भी नोट छाप दिये थे श्रीर साथ ही डालर मुद्रा को भी साम्राज्य डालर कोष (Empire Dollar Pool) में जमा कर दिया जाता था श्रीर उनके बहले में नोट छापे जाते थे। पुनः युद्ध काल के पश्चात् महँगाई भर्तों में वृद्धि हुई जो श्रिधिक नोट छप कर ही यूरी की गई। इसी कारण चलन की मुद्रा सन् १६३६ की श्रपेत्ता सन् १६४८ में १३ मुनी बढ़ गई तथा साल चारगुनी। (२) वस्तुश्रों की कमी भी कीमतों की वृद्धि में सहायक हुई। इस कमी का कारण श्रायातों में कमी, देश की श्रांतरिक खाद्य उत्पादन का घटना, श्रकाल इत्यादि थे। (३) सट्टे की प्रवृत्ति ने भी लोगों में जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ा दी तथा यातायात की श्रमुविधा ने स्थानीय दुर्लभताश्रों को बढ़ा दिया। (४) युद्ध के पश्चात् सरकारों ने हीनार्थ श्रर्थ प्रबंध किया जिसके परिशासकर मी मुद्रा स्कीति को प्रोत्साहन मिला।

रकार द्वारा रोकने के उपाय

सरकार ने प्रारंम में ही मूल्य नियंत्रण तथा राशनिंग द्वारा मुद्रा प्रसार का

सामना किया। सट्टा बन्द कर दिया गया, करों में दृद्धि की गई श्रौर नये कर लगाये गये। ऊँची ब्याज पर जनता से ऋ्णा लिए गये; कंपनियों के लामांशों पर ६% की सीमा लगा दी गई श्रौर शासन व्यय को कम कर (Economy Drive) दिया गया। उत्पादन बढ़ाने के लिये भी सरकार ने कुछ कदम उठाये जैसे श्रिधिक श्रन्त उपजाश्रो श्रांदोलन को बीज, ऋ्णा, खाद, िसचाई की सुविधाएँ प्रदान कर प्रोत्साहित किया। श्रिधिक भूमि को कुषि योग्य बनाया तथा उत्पादन उद्योगों को कर से मुक्त किया गया। खाद्यानों श्रादि का श्रायात बढ़ाया गया श्रौर नये सरकारी सहायता द्वारा नये कर उद्योगों की स्थापना की गई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना सन् १६५१ में लागू होने पर मुद्रा प्रसार की प्रवृत्तिपर कुछ श्रंकुश लगा श्रौर कीमतें नीचे गिरने लगीं। यह गिराव १३% था। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १८०० करोड़ रुपये की घाटे की श्रर्थ व्यवस्था की गई श्रौर सन् १६५६ से ही कीमतें उठनी प्रारम्भ हो गई। श्रौर श्राजकल मुद्रा प्रसार श्रपना भयंकर रूप धारण किए हुए हैं। श्रातः तृतीय पंचवर्षीय योजना में कीमतों को नीचा करना, मुद्रा प्रसार रोकना तथा कृषि उत्पादन को बढ़ा देना प्रमुख स्थान पाएँगे।

आर्थिक नियोजन (Economic Planning)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में २४०० करोड़ रुपये की व्यवस्था थी श्रौर लगभग ४०० करोड़ रुपये की हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing) की संभावना थी। परन्तु द्वितीय योजना काल में विशुद्ध रूप से १२०० करोड़ रुपये की घाटे की व्यवस्था रखी गई है। परन्तु श्रनुमानतः इस घाटा की व्यवस्था १६०० करोड़ रुपये के लगभग होगी। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के मूल्य-स्तरों में श्राशातीत वृद्धि हुई है जिससे मध्यम वर्ग श्रौर मजदूर वर्ग के रहन-सहन तथा उपभोग पर कुप्रभाव पड़ा है।

प्रश्न

- श्रपने देश में दितीय विश्व युद्ध के समय श्रीर उसके पश्चात् मुद्रा स्फांति के कारखों का विवेचन कीजिए। राज्य द्वारा किए गए उसके नियंत्रण के उपायों का संज्ञित वर्णन करिए।
 - (त्रागरा, वी. काम. १६५६)
 - 2. Trace the history of Indian currency since 1926.
 (Agra, B. Com. I, 1956)
- 3. Discuss the evils of currency inflation on the different classes of people in a country, with special reference to the postwar period.

 (Agra B. Com. I, 1956)

श्रध्याय १०

भारतवर्ष में दाशमिक प्रणालो

(Metric System in India)

भारत में दाशमिक सिक्के

मौद्रिक जगत में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक देश सविधानसार श्रपनी-श्रपनी मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन करता रहता है। ये परिवर्तन विभिन्न समयों पर प्रथक-प्रथक रूप से होते हैं जिसके कारण विभिन्न देशों की सद्रा प्रणालियों में अधिक विविधता आ गई है जो अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग में बाधा पहुँचाती है। ग्रतः इस ग्रन्तर्राष्ट्रीय युग में मौद्रिक चेत्र में भी समानता लाना त्रावश्यक हो गया है। मुद्रा प्रणाली में दशमलवीयकरण की प्रवृत्ति इस विश्व में एक उचित प्रयत्न है। भारतवर्ष में भी दशमलवीयकरण के ऊपर बहुत समय से विचार हो रहा था। सबसे पहले सन १८६७ ई० में इस विषय पर विचार किया गया था तथा सन् १८७० ई॰ एक दाशमिक ऐक्ट भी पास किया गया था परन्तु ये ऐक्ट लागू नहीं किया जा सका। इसके पश्चात सन् १६३६ ई॰ में भारत सरकार ने एक ऐक्ट पास करके पिछले ऐक्ट की व्यवस्थात्रों को समाप्त कर दिया। सन् १६४० ई० में भारतीय दाशमिक सभा स्यापित को गई। इस संस्था ने बराबर दाशमिक प्रणाली के अपनाने पर ज़ोर दिया है। दाशमिक प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्रामाणिक मापदंड का विभा-जन तथा उपविभाजन के के कम से होना चाहिये जिससे ऊपर से नीचे का माप-दंड १० का माग देकर तथा नीचे से ऊपर का मापदंड १० का गुणा करके प्राप्त किया जा सके। मुद्रा मूल्यों का मापदंड है और यह सब मापदंडों से अधिक महत्व-पूर्ण है। इसिलये मुद्रा प्रणाली में दशमलवीयकरण त्र्यावश्यक है। इसी दृष्टि से भारतीय दाशमिक सभा अन्य मापदण्डों के साथ-ही-साथ मुद्रा प्रणाली के दशम-लबीयकरण पर विशेष बल देती चली आ रही है।

मारतीय सरकार ने फरवरी सन् १९४६ ई॰ में दाशमिक मुद्रा प्रणाली लागू करने के लिये घारासमा में एक बिल पास किया। इस बिल में रुपये की प्रामाणिक सिका मानकर उसे १०० सेंट में विभाजित करने का सुभाव दिया गया था। परन्तु ये बिल कार्यरूप में परिण्त न हो सका। सन् १९४९ ई॰ में भारतीय सरकार ने एक नया बिल प्रस्तुत किया जिसके अनुसार रूपये को लंका की मुद्रा प्रणाली के आधार पर १०० सेंट में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके अन्तर्गत रूपये का सिक्का अठन्नी व चवन्नी की शकल, वजन तथा आकार वैसे के वैसे बने रहेंगे परन्तु इसके नीचे के सिक्कों में परिवर्तन किया जायगा। परन्तु यह नया बिल भी कार्य रूप में परिण्त नहीं हो सका। नई मुद्रा प्रणाली संचालन करने में भारत सरकार को कुछ कठिनाइयाँ प्रतीत हुईं। सबसे पहले तो परम्परागत प्रणाली को छोड़ने का भावावेश के कारण जनता विरोध करती है तथा कुछ समय तक नई तथा पुरानी मुद्रा में साथ-ही-साथ चलने के कारण उनके परिवर्तन में साधारण जनता को कठिनाई होती है। और अन्त में और भी मापदंड प्रचलित प्रथा के आधार पर होने के कारण नई मौद्रिक प्रणाली से मेल नहीं खाते। बहुतों की दर नई मुद्रा प्रणाली के कारण परिवर्तित होनी चाहिये। उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भी अन्त में १६५६ ई० में भारतीय सरकार ने भारतीय मुद्रा सिवयम पास किया जिसकी प्रमुख धारायें निम्नांकित हैं—

- (१) देश की मुख्य मुद्रा इकाई रुपया ही रहेगी। श्रौर सबसे छोटी मुद्रा इकाई पैसा ही रहेगा परन्तु वर्तमान पैसा चलन श्रविध तक यह नया पैसा कहा जायगा।
 - (२) वर्तमान रूपया १०० नये पैसों में विभाजित होगा।
- (३) वर्तमान अठनी तथा चवनी की कीमत क्रमशः ५० और २५ नये पैसों के बराबर होगी। अन्य सांकेतिक सिक्कों के स्थान पर १०, ५, २ और एक नये पैसे के सिक्के चलाये जायेंगे। तथा प्राचीन सांकेतिक सिक्कों का शनै:-शनैः विमुद्री-करण हो जायगा। तीन वर्ष के पश्चात् नई मुद्रा पूर्ण रूप से चालू हो जायगी यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- (४) रुपये तथा पैसे के अविरिक्त ५० नये पैसे तथा २५ नये पैसे के दो .सिक्के और चलाये जायेंगे परन्तु इनका निर्गमन पहले नहीं होगा।
- (५) ऐक्ट की व्यवस्थाओं को सरकार सुविधानुसार लागू कर सकेगी। ये व्यवस्थायें १ अप्रेल १९५७ ई० से लागू हो गई है।

उपरोक्त ऐक्ट के अनुसार १ अप्रेल १६५७ ई० से नये सिक्कों का चलन आरम्भ हो गया। कम से कम तीन वर्ष तक नये व पुराने दोनों प्रकार के सिक्के चलते रहेंगे। रुपये का रूप वर्तमान रूप के समान ही रहेगा। केवल उसकी पीठ पर १०० नये पैसे अंकित रहेंगे। इस प्रकार रुपये के आधारभूत मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसे केवल ६४ पैसों में विभाजित न करके १०० नये पैसों में विभाजित कर दिया गया है। साधारण रूप से पुराना एक आना ६ नये पैसों के बराबर होता है और प्रत्येक तीन आने के बाद १ नया पैसा और जुड़ जाता है। उदाहरण के

लिये तीन त्राने १८ नये पैसे के स्थान पर १६ नये पैसे का होगा। १ पैसा २ नये पैसे के बराबर निर्धारित किया गया है। जब तक नये व पुराने दोनों प्रकार के सिक्कों का चलन रहेगा इनके परिवर्तन में लोगों को कुछ न कुछ कठिनाई त्र्यवश्य होगी परन्तु पुराने सिक्कों का चलन समाप्त हो जाने पर यह कठिनाई भी दूर हो जायगीं तथा बाद में मौदिक प्रणाली सरल तथा सुगम रह जायगी।

अन्य आर्थिक प्रस्तावों की भाँति नई मौद्रिक प्रणाली के ऊपर भी देश में बहुत वादिववाद रहा। प्राचीन मौद्रिक प्रणाली के पद्म वालों का मुख्य तर्क यह रहा कि देश की जनता इस प्रणाली से पूर्ण रूप से परिचित हो गई है तथा इस प्रणाली का देश के अन्य मापदएडों से पारस्परिक सामंजस्य बैठ गया है जिससे वस्तुत्रों की कीमत निकालने में जनता को कोई परेशानी नहीं होती है, यहाँ तक कि व्यापारी वर्ग में बहुत से ऐसे नियम प्रचलित है कि जिनके आधार पर अधिक से अधिक तथा कम से कम वस्त का ठीक-ठीक मूल्य बड़ी आसानी से निकल आता है। अतः परम्परागत मद्रा प्रणाली का परिवर्तन करना उचित प्रतीत नहीं होता । इसके अतिरिक्त सरकार को लोक कल्याए के लिये और भी बहुत से कार्य करने हैं जिनके लिये सरकार के पास उचित समय, साधन तथा कर्मचारी नहीं है । ऐसी अवस्था में एक नवीन समस्या का जन्म देना व्यावहारिक कुशलता का परिचय नहीं होता। इस विचारधारा के लोगों के अनुसार मुद्रा प्रणाली में इस समय परिवर्तन करना केवल पश्चिमी देशों के अनु-सरण करने की इच्छा पर ही आधारित प्रतीत होता है। देश में इस परिवर्तन की कोई ब्रावश्यकता नहीं। बहुत से लोग तो दशमलवीय प्रणाली को विदेशी प्रणाली समम्बर निरादर की दृष्टि से देखते हैं जब कि वास्तविकता यह नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार दशमलव प्रणाली का अपविष्कार तो भारतीयों ने ही किया था। यद्यपि इस प्रणाली को वे व्यवहार में परिणत न कर सके। इसके अतिरिक्त नवीन मुद्रा प्रणाली के विपिन्नियों के कुछ तर्क तो निराधार हैं। जनता को कठिनाई प्रत्येक समय में प्रतीत होगी चाहे नवीन पद्धति स्त्राज प्रारम्म कर दी जाय या १०० वर्ष बाद प्रारम्भ की जाय। तथा इस सुघार में कुछ श्रिधिक साधनों की भी त्र्यावश्यकता नहीं है। साथ ही साथ यह बात ऋौर ध्यान देने योग्य है कि इस समय आमीए ऋार्थिक चेत्र के ऋषिकांश भाग में मुद्रा का प्रचलन होता ही नहीं। बहुत सी ग्रामीण जनता वस्तु विनिमय के त्राधार पर ही त्रपना कार्य चलाती है। परन्तु पंचवर्षीय योजनात्रों के फलस्वरूप मुद्रा चलन उत्तरोत्तर बढ्ता जायगा, यहाँ तक कि जो जनता इस समय मुद्रा का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर रही वह भी अपने सब कार्य मुद्रा के सहारे ही करने लगेगी तो उस अवस्था में मुद्रा परिवर्तन का कार्य वर्तमान समय से अधिक कटिन हो जायगा । वर्तमान समय में मुद्रा परिवर्तन से कम लोग प्रभावित होंगे जब कि मिविष्य में इससे अधिक प्रभावित होंगे। एक बात अौर भी है। अब जोड़-नाकी, पुर्या-भाग श्रादि का काफी काम मशीन भी करने लगी हैं। परन्तु भारतवर्ष में इस

प्रकार की मशीनें अभी बहुत कम प्रयोग में लाई जाती हैं। जो मशीनें काम करती भी हैं वे प्राचीन मुद्रा प्रणाली के प्रचार पर ही हिसाब लगाती हैं। पर आर्थिक उन्नित के साथ ही साथ इस प्रकार की मशीनों की संख्या भी बढ़ेगी। यदि देश की सुद्रा प्रणाली में परिवर्तन कुछ वर्षों बाद किया जाय तो उस समय वे सब मशीनें बेकार हो जायँगी जब कि इस समय थोड़ी ही मशीनें बेकार होंगी। अतः व्यय व बरबादी की दृष्टि से भी मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन के लिए यही समय उपयुक्त प्रतीत होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी नवीन प्रणाली आवश्यक प्रतीत होती है। संसार के लगभग ५० ऋौद्योगिक देशों ने दशमलवीय मुद्रा प्रणाली को स्वीकार कर लिया है श्रौर सब जगह यह प्रगाली सफलतापूर्वक चल रही है। इसलिये भारत में भी इसके चलन में किसी प्रकार असुविधा की आशंका नहीं है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली का अन्तर्राष्ट्रीय आघार होने के कारण देश के सभी भागों में विना विरोध के इसे स्वीकार करने की सम्भावना है जब किसी दूसरी प्रणाली का किसी भाग में बहिष्कार हो सकता है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है संसार के प्रायः सम्य देशों ने गिएत के चिह्न दशमलवीय आधार पर ही बनाये हैं। नाप और तौल की कोई भी ऐसी इकाई असुविधाजनक नहीं हो सकती जिसमें इस दशमलवीय आधार को ग्रह्ण न किया जा सके । भारतवर्ष में भी जब ग्रान्य मापदराडों में दशमलवीय प्रथा का चलन हो जायगा तो मौद्रिक दशमलवीय प्रणाली का वर्तमान दोष भी समाप्त हो जायगा । इस प्रकार दाशिमिक प्रणाली को ग्रहण करके भारत भी उन देशों में सम्मिलित हो जायगा जिन्होंने मापदंड के इस त्राधार को मान लिया है। ऐसा करने से भारत अपनी अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं को एक चेत्र में और कार्यरूप में परिगात कर सकेगा, जो इस बात का एक प्रभावशाली प्रमाग होगा कि भारत अपनी आर्थिक उन्नति में बाधा डालने वाली प्रत्येक परम्परा को तोड़ने के लिये तैयार है। इसके स्रतिरिक्त भारत सरकार के विचिविभाग ने दशमलवीय प्रगाली के स्थायी लाभों की गणना निम्न प्रकार से बतलाई है-

- (१) इस प्रणाली से सरल तथा शीव्र लेखा विधि का निर्माण हो सकेगा ।
- (२) यह प्रणाली व्यय तथा मूल्य निर्धारण की एक सही श्रौर सप्रभाविक रीति सिद्ध होगी।
- (३) इस प्रणाली के द्वारा घरेलू कामों ख्रौर उपभोग की वस्तुख्रों की कीमतें सरलता से नापी जा सकेंगी।
- · (४) त्र्यनावश्यक तथा विविध प्रकार की मुद्रा इकाइयों के स्थान पर नवीन तथा बोधगम्य मुद्रा की इकाइयों का चलन हो जायगा।
- (५) कीमतों के छोटे-छोटे परिवर्तनों की ग्राधिक सही नाप हो सकेगी जिससे सुद्रा का न्यय ग्राधिक ग्राधिक ढंग से किया जा सकेगा।

- (६) शिचा संस्थात्रों में हिसाब-किताब सीख़ने तथा उसके लगाने में विद्यार्थियों के समय तथा परिश्रम में काफी बचत हो जायगी।
- (७) पूरानी मुद्रा प्रणाली के त्राधार पर हिसाब जोड़ने में एक ग्रेजुयेट को भी एक अशिच्वित व्यापारी के सामने नीचा देखना पड़ता है। एक अशिच्वित दूकान-दार जो हिसाब आधा मिनट में मौखिक लगा देता है उसे एक स्नातक कागज पेंन्सिल की सहायता से भी ५ मिनट में लगाने में असफल रहता है। दशमलवीय प्रणाली से हिसाब-किताब लगाने के चेत्र में शिच्वित वर्ग की यह दयनीय दशा दूर हो जायगी।

नवीन मौद्रिक प्रणाली के प्रारम्भ हो जाने से उपरोक्त वादिववाद का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं रहा है। श्रव तक के श्रनुभव से यह निष्कर्ष निकाला जा स्कता है कि नवीन मौद्रिक प्रणाली नापतौल की दशमलवीय प्रणाली के प्रारम्भ हो जाने पर पूर्ण रूप से सफल हो जायगी। इस समय देश में नापतौल की लगभग १४० प्रणालियाँ प्रचलित हैं जिससे व्यापार में काफी श्रमुविधा तथा अष्टाचार होता रहता है। श्रतः सरकार शीघ्र ही नाप तौल में भी दशमलवीय प्रणाली प्रारम्भकरने वाली है। श्रीर यह देश के लिये हितकर भी होगा। तौल की नई श्राधार भूत इकाई किलोग्राम रक्खी गई है जिसका वजन पद तोला श्रथवा २ पौंड तीन श्रौंस रहेगा। यह प्रणाली निम्न प्रकार से होगी—

१ सेन्टीग्राम १० मिलीग्राम १ डेसीग्राम १० सेन्टीग्राम १० डेसीग्राम १ ग्राम १ डेकाग्राम १० ग्राम १० डेकाग्राम १ हे₹टोग्राम १ किलोग्राम १० हेक्टोग्राम १०० किलोग्राम १ किटल १०० किटंल १ मेट्रिक टन

नापतौल में दाशिमक प्रणाली घीरे-घीरे पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा राज-स्थान के विभिन्न देत्रों में लागू की जायगी। दिल्ली दोत्र में जनता को इसका परिचय आंशिक रूप से कराने के लिए यह लागू भी कर दी गई है। पंजाब में अमृतसर, बालंघर, लुधियाना, अम्बाला, पिटयाला व गुड़गाँव जिले में तथा पंजाब कृषि जन्य पदार्थ बाज़ार ऋषिनियम १६३६ के अंतर्गत गाड़ियों में लागू की जायगी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, आगरा, बरेली, गोरखपुर, भाँसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ तथा वाराससी म्यूनिसिपल द्वेत्र में लागू की जायगी। राजस्थान में श्रजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर तथा कोटा व उदयपुर के जिलों में पहले लागू की जायगी। यह नई प्रणाली स्ती वस्त्र, लोहा व स्पात व इन्जीनियरिंग भारी रासायनिक पदार्थ, सिमेन्ट, नमक, कागज लौहतर धातुश्रों तथा रवर व कहवा उद्योगों में भी लागू होगी। इन उद्योगों में वर्तमान नापतौल प्रणाली केवल दो वर्ष तक कायम रह सकेगी। बाद में इसे अन्य उद्योगों व आर्थिक गतिविधियों में लागू किया जायगा।

प्रश्न

भारतीय मुद्रा प्रकाली में दशमलव प्रकाली का क्यो समावेश किया यथा ? इमारे समाज को इससे क्या लाभालाभ है। (आगरा वी, काम. पार्ट १ १६५६)

ऋध्याय ११

विदेशी विनिमय एवं विनिमय नियंत्रण

(Foreign Exchange and Exchange Control)

विदेशी विनिमय का <u>अर्थ बहुत ही व्यापक है</u>। इसके अंतर्गत वे रीतियाँ जिनके द्वारा विदेशी भुगतान होता है (जैसे विदेशी बिलें, बैंक ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा) सिम्मिलित हैं। विदेशी विनिमय का अर्थ उन संस्थाओं से भी लगाया जाता है जो कि - इन विनिमय पत्रों का कय-विकय करती हैं तथा इसका अर्थ उस दर से भी है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्त्तन किया जाता है।

विदेशी विनिमय की <u>ऋावश्यकता विदेशी व्यापार के कारण उत्पन्न होती</u> है। प्रत्येक देश के <u>व्यापारी ऋपने देश की मुद्रा ही स्वीकार करते हैं</u>। ऋतः ऋपने देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलना पड़ता है।

विनिमय दरों का निर्घारण (Determination of Exchange Rate)

विनिमय दर का ऋर्ष उस दर से हैं जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदली जा सके। जैसे ५ रुपये के बदले में १ डालर मिले तो ऋमेरिका ऋौर मारत के बीच ५:१ से विनिमय दर कही जायगी। यह विनिमय दर सदा क्षिर नहीं रहती और विनिमय दर देशों की मुद्रा पद्धतियों पर निर्भर रहती हैं। विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की मुद्रा पद्धतियाँ प्रचलित होने के कारण विनिमय दर मी विभिन्न प्रकार से निर्धारित होती हैं। इन पद्धतियों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं—

१. स्वर्णमान ऋथवा रजतमान वाले देशों में विनिमय दर — जब दो देशों में मुद्राएँ सोने या चाँदी की होती है तो विनिमय दर प्रामाणिक सोने या चाँदी के सिक्कों में होने वाले शुद्ध सोने या चाँदी की मात्रा पर निर्भर रहता है। यह मुद्रा स्वर्ण में या रजत में पित्वर्जनीय होतो है। जैसे भारत में एक तोले सोने की कीमत १२० ६० है और इंगलैंड में १५ पौंड है तो दोनों देशों के बीच विनिमय-दर १२० ६० = १५ पौंड अर्थात् ८ ६० = १ पौंड हुई। ये सोने या चाँदी की मात्रा एवं कीमत देशों के विधान द्वारा निश्चित की जाती है। इसे टकसाली समानता (Mint Par of Exchange) या स्वर्ण मूल्य समानता दर (Gold Par of Exchange) कहा बाता है।

स्वर्ण ममता दर (Gold Par of Exchange) - विनिमय दरों की प्रवृत्ति समानता की प्रवृत्ति दिखाती हैं। परन्तु यह भी व्यापार-शेष के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। जैसे भारत व ब्रिटेन के बीच विनिमय पर १ पौंड = प्र रु हैं। यदि किसी वर्ष भारत ने ब्रिटेन से काफी आयात किया परन्तु नियति कम किया तो भारत का व्यापार शेष भारत के विर्दात हुआ जिसे वह पौडों में चुकाएगा। पौड की माँग बढ़ेगी। और माँग के नियम के अनुसार पौड की कीमत बढ़ जाएगी। अतः अब प्र रु के बदले में १ पौंड न मिलेगा बल्कि कुछ अधिक रुपयों में मिलेगा जैसे १ पौंड = 5 4 रु।

इस भुगतान को भारत या तो विदेशी बैंक से पौंड मुद्रा खरीद कर कर सकता है या स्वर्ण का निर्यात ब्रिटेन को कर सकता है। इनमें जो रीति लाभदायक होगी वही श्रपनाई जाएगी। स्वर्ण का निर्यात करते समय मार्ग व्यय, बीमा व्यय, पैकिंग व्यय का भी ध्यान रखा जाएगा। माना कि ये सारे व्यय '०२ पौंड पड़ते हैं तो १ तोला सोना ब्रिटेन को भेज कर १५ पोंड के स्थान पर १४-६८ पौड कमाएगा। यदि विनि-मय बैंक से १४.६८ पौंड से ऋधिक मुद्रा मिलती है तो भारत सोना का निर्यात नहीं करेगा त्रीर बैंक द्वारा भुगतान करगा। यदि विनिमय बैंक १४.६८ गैंड से थोडा सा भी कम मूल्य देगा तो भारत तुरंत ही सोने का निर्यात प्रारंभ कर देगा। अतः इस सीमा या बिंदु को भारत का स्वर्ण निर्यात बिंदु (Gole Export Point) कहा जाता है श्रौर ब्रिटेन के यह स्वर्ण श्रायात बिंदु (Gold Import Point) कहा जाएगा। स्वर्ण स्रायात स्रौर निर्यात बिंदु स्रों को स्वर्ण बिंदु (Gold Point घातु बिंदु (Specie Point) कहते हैं । इसी प्रकार भारत का ब्रिटेन को निर्यात ऋधिक है श्रीर श्रायात कम । तो ब्रिटेन भी वि-मय बेंक द्वारा या स्वरण निर्यात भारत को भुगतान करेगा । परंत ऐसा करने में उसे मार्ग व्यय स्त्रादि का ध्यान रखना पड़ेगा । यदि मार्ग '०२ पौंड हैं तो ब्रिटेन के व्यापारी को १५.०२ पौंड के बटले में १ तोला सोना भेजना होगा जो १२० रुपए के बराबर होगा। जब तक विनिमय बैंक १५०२ पौंड के बदले में १२० रु० से भ्राधिक देती रहेगी स्वर्ण निर्यात का प्रश्न नहीं उठता परन्तु जैसे ही कम देना स्वीकार किया ब्रिटेन भारत को स्वर्ण का निर्यात करने लगेगा। इस प्रकार १५.०२ पौंड ब्रिटेन के लिए स्वर्ण निर्यात िंदु हुन्ना स्त्रौर भारत के निए स्वर्ण त्रायात बिंदु । ऋतः ये बिंदु मार्ग व्यय ऋादि जोड़ कर या घटा कर निकाले ज ते है। जब ये व्यय ज़ोड़े जाते हैं तो मूल्य को उच्चतर घात बिंद (Upper Gold Points) या 'स्वर्ण निर्यात विंदु' (Gold Export Point) कहते हैं श्रौर जब व्यय घटाए जाते हैं तो निम्नतर स्वर्ण विंदु (Lower Gold Point) या स्वर्ण आयात बिंदु (Gold Import Point) कहते हैं। विनिमय दर इन बिंदु औं के बीच ही निश्चित हो होगी।

२. पत्र चलन प्रणाली में विनिमय दर-पत्र चलन प्रणाली में एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा से कोई सर्वाच नहीं होता और न यह मुद्रा किसी एक धातु में परिवत्तनशील ही होती है। ऐसे देशों के बीच विनिमय दर उन देशों की क्रय-शक्ति समता सिद्धांत पर आधारित होती है। इस सिद्धांत के जन्मदाता गुस्टाव कैसिल का कहना है कि स्वण् के स्थान पर किसी दैनिक उपयोग की वस्तु में दोनों देशों की मद्रात्रों की कय-शक्ति का पता लगाया जा सकता है त्रीर इस कय-शक्ति के ब्राधार पर परस्पर विनिमय-दर का निर्घारण हो सकता है। उदाहरणार्थ भारत में प्रु का उतना गेहूँ खरीदा जाता है जितना कि अमेरिका में १ डालर का। तो भारत श्रौर श्रमेरिका की विनिमय दर क्रय शक्ति समता सिद्धान्त पर १ डालर = ५ रुपये हुई । क्रय-शक्ति उन देशों के सामान्य मूल्य स्तर से ज्ञात होती है । इस क्रय शक्ति में समान तथा तुलनात्मक दो तरह से परिवर्त्तन हो सकते हैं । समान परिवर्त्तन होते पर विनिमय दरों में कर्तई परिवर्त्तन न होंगे परन्तु तुलनात्मक परिवर्त्तन (एक देश की मुद्रा की कय शक्ति में दूसरे देश की मुद्रा की कय शक्ति की ऋपेचा ऋधिक परिवर्त्तन होना) होने पर विनिमय दर में भी उसी श्रनुपात में तथा उसी दिशा में परिवर्त्तन होते हैं। यदि रुपये की क्रय शक्ति पौंड की क्रय शक्ति की तलना में २५% घट जाती है तो रुपये की क्रय शक्ति भी पौंड में ठीक इसी अनुपात में घट जाएगी। कैसिल के श्रनुसार नई विनिमय दर का पता लगाने के लिये श्राधार वर्ष की दर में प्रत्येक चलन को उस देश की निर्देशांक से गुणा कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत ऋौर ब्रिटेन में सन् र्१६३६)में विनिमय दर १ पौंड =४ रु० है। १६५८ में ये निर्देशांक भारत में ३०० हो जाते हैं स्त्रौर ब्रिटेन में १५० तो नवीन विनिमय दर प्रो॰ कैंसिल के अनुसार इस प्रकार होगी:-

कय शक्ति समता सिद्धांत की त्रालोचनाएँ

विदेशी मुद्रा की दर भी आंतरिक मुद्रा की दर के आनुसार ही निश्चित होती है। बैसे आंतरिक मुद्रा मूल्य उसकी माँग और पूर्ति के आनुसार निश्चित होता है उसी प्रकार उसकी नाह्य दर या विनिमय बाजार में उसकी माँग और पूर्ति पर निर्भर है परंतु क्रय शक्ति समता सिद्धांत केवल <u>क्रय शक्ति संबंधी विवेचना करता</u> है उसकी माँग की विवेचना करता है उसकी माँग की विवेचना नहीं करता। दूसरे यह सिद्धांत केवल उन कुछ वस्तुओं के सामान्य स्वनांकों से निर्धारित होता है जो आंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में स्वतंत्रतापूर्वक प्रवेश करती

हैं और श्रन्य सेवाओं श्रथवा पूँ जी के विनिमय पर कुछ भी ध्यान नहीं देता । तीसरे यह सिद्धांत टक्साली समानता के श्राधार पर नहीं बना वरन निर्देशांको के श्राधार पर बना है जो सदेव बदलते रहते हैं । चौथे, इस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विनिमय दरों के परिवर्त्तन देश के श्रांतरिक मूल्य-स्तरों के परिवर्त्तन के परि- स्ताम होते हैं परंतु यह भी देखा जाता है कि विनिमय दर के परिवर्त्तन स्वयं श्रांतरिक मूल्य स्तर में परिवर्त्तन कर देते हैं । जैसे श्रवमूल्यन का प्रभाव देश में द्वा प्रसार तथा मूल्य-स्तर बद्ना होता है । पाँचवा, यदि दो देशों का व्यापार श्रवला-बदली पर हो, सहेवाजी का राजनैतिक प्रभाव हो. स्वतंत्र व्यापार न हो श्रर्थात् नियात् प्रतिबंध हों तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत द्वारा विनिमय दर निकालना श्रीर भी किटन हो जाता है ।

विदेशी विनिमय द्रों में परिवर्तन (Fluctuations)

विदेशी विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों को चार भागों में बाँट झकते

- १. विदेशी बिलों की माँग ऋौर पूर्ति
- २. मुद्रा संबंधी कारण
- ३. राजनैतिक कारण
- ४. श्रौद्योगिक कारण
- १ विदेशी बिलों की माँग और पूर्ति—यदि किसी देश में विदेशी बिलों की माँग पूर्ति की अपचा अधिक होती है तो विनिमय दर में वृद्धि हो जाती है। इस माँग के अधिक होने के कई कारण हैं:—(अ) जब व्यापारिक शेप देश के अनुकूल हो तो विदेशी लोग देश की मुद्रा की माँग करेंगे जिससे इसका मूल्य बढ़ेगा। ब जब विदेशी लोग हमारे देश में पूँजी विनियोग करना चाहते हैं तो हमारी मुद्रा की माँग बढ़ती है। परंतु यदि हम दूसरे देशों में विनियोग करना चाहते तो विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ेगी और विनिमय दर में वृद्धि होगी। (स) स्टाक एक्सचेंज पर जब सटोरिए विदेशी सिक्योरिटियों में रुपया लगाना चाहते हैं तो विदेशी मुद्रा की अपवश्यकता होती है जिससे विदेशी बिलों की माँग बढ़ती है और विनिमय दर बढ़ जाती है। (द) वैंक भी कभी-कभी जब विदेशी बिलों की माँग कम होती है और सस्ते होते हैं। तो खरीद लेते हैं तथा तेज होने पर बच देते हैं जिससे लाभ कमा लेते हैं और यह किया भी विनिमय-दर में परिवर्तन करने में सहायक होती है।
- २ मुद्रा संबंधी कारण—मुद्रा की कय शक्ति में होने वाले परिवर्तन भी विनिमय दर में उच्चावचन उत्पन्न करते हैं। क्रय शक्ति समता सिद्धांत यही बताता है। जब मुद्रा मूल्यों में वृद्धि होती है तो देश में पूँजी लगाने में कम लाभ होता है

श्रौर वे श्रपनी पूँ बी देश से हटाना चाहते हैं इससे विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ती है श्रौर विनिमय दर में परिवर्तन होता है।

३. राजनै^{नि}क दशाएँ —सरकार द्वारा लगाए गए त्र्यायात कर, निर्यात-कर, तट-कर इत्यादि तथा देश में ऋसुरचा, राजनैतिक उपद्रव बिलों की माँग ऋौर पूर्ति पर प्रभाव डालते हैं जिससे विनिमय दर में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

४. श्रीद्यीगि म कारण-जब देश में श्रीद्योगिक शांति होती है, श्रीद्योगिक विकास हो रहा होता है एवं विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन दिया जाता है तो विदेशी अपनी पूँ जी उस देश में लगाना पसंद करते हैं जिससे उस देश के विलों की माँग बढ़ती हैं और विनिमय दर अनुकूल होती हैं । इसके विपरीत यदि औद्योगिक अशांति हैं, उद्योगों में हानि हो रही है तो विदेशी ऋपनी लगी हुई पूँजी हटाना चाहेंगे जिससे विदेशी बिलों की माँग बढ़ेगी ख्रौर विनिमय-दर में परिवर्तन होगा।

अप्रगामी विनिमय (Forward Exchange)

श्रप्रगामी विनिमय बाबार व्यापारियों को भविष्य में विनिमय-दरों में होने वाले उतार-चढ़ावों से होने वाली संभावित हानि से बचने के लिए पूरी सुविधा दी जाती है। विनिमय दर के उतार-चढ़ान व्यापारियों को लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं। किसी भी विदेशी मुद्रा की जो मात्रा देश की मुद्रा के बदले में भविष्य की एक निश्चित तिथि को मिल सकती है, उसे अअगामी विनिमय दर कहते हैं। यह त्रप्रगामी विनिमय दर विभिन्न देशों की वैकिंग पद्धति, चैंक-दर, ब्याज दर मुद्रा-नीति, विनिमय-नियंत्रण स्त्रौर स्रांतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर निश्चित की चाती है। वस्तुतः इसके श्रंतर्गत सुरच्ना के सौदे (Hedging Contracts) होते हैं। विदेशी विक्रेता विक्री का सौदा करते समय उस देश से माल वर्तमान भावों में क्रय (purchase) कर लेते हैं ताकि विक्रय-माल की सुपुर्दगी तक भावों में होने वाले उच्चावचनों की हानियों से बचा बाए। इसी प्रकार क्रेता भावी दामों पर विक्रय का सौदे कर लंते हैं जिससे भविष्य में हानि न हो।

निदेशी विनिमय नियंत्रण (Foreign Exchange Control) विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य

विनिमय नियंत्रण का स्रर्थ स्रिधिकारियों द्वारा किए गए प्रत्यक्त स्रथवा परोक्त इस्तच्चेप से है ताकि विनिमय दर्गे अथवा व्यापार को प्रभावित किया जा सके । विनि-मय-नियत्रण विनिमय दर में होने वाले भयंकर उच्चावचनों को रोकने के लिए तथा उनमें स्थायित्व लाने के लिए, व्यापार शुषों के ख्रंतरों को समायोजित करने के लिए किया जाता है। कभी-कभी इसका उद्देश्य सरकार द्वारा आय प्राप्त करना भी होता है। आजकल विनिमय नियत्रण का प्रयोग कुछ विशेष देशों के आयात-निर्यातों को रोकने के लिए, व्यापारिक भेद-भावों के लिए, संरच्चण प्रदान करने के लिए तथा पूँ जी के निर्यातों को रोकने के लिए भी किया जाता है।

विनिमय नियंत्रण के उपाय

विनिमय नियंत्रण निम्नांकित उपायों द्वारा किया जा सकता है:

(१) आयात-निर्यात कर, कोटा, तट कर एवं लाइसेंसों द्वारा—आयात-निर्यातों द्वारा विनिमय दर बहुत प्रभावित होती है। अतः सरकार आयात निर्यात का नियंत्रण नए-नए कर तट-कर लगा कर आयातों को कम करने के लिए आयात कर लगा कर, आयात के लाइसेंस देकर तथा निर्यातों को बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनका कोटा निश्चित कर सकती है। व्यापारिक संतुलन बनाए रखने के लिए अवमुल्यन भी कर सकती है।

(२) चैयाज तथा बैंक दरों द्वारा—विदेशी विनिमय बाजार का संबंध पूँ जी ख्रौर विनियोग के लेनदेन से बहुत अधिक रहता है। ब्याज दर में अधिक वृद्धि कर दी जाए तो विदेशी लोग देश में पूँजी लगाते हैं और देश की मुद्रा की माँग बढ़ जाती है जिससे विनिमय दर बढ़ जाती है। ब्याज दर या बैंक दर घटाने पर लोगों को कम लाभ होते हैं जिससे अपनी पूँजी हटाते हैं और विदेशी मुद्रा की माँग करते हैं जिससे विनिमय दर गिरती है। इस प्रकार विनिमय दर का नियंत्रण केन्द्रीय बैंक द्वारा सुद्रहता के साथ हो सकता है।

(द) विनिमय बंधन (Pegging of Exchange)—कमी-कभी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा विनिमय-दर की सामान्य-विनिमय दर से ऊँची या नीची रखने के लिए एक निश्चित बिंदु या मात्रा निर्धारित कर देती है। इसे ही विनिमय बंधन कहते हैं। जैसे सन् १६२८ के बाद मारत ने रुपए की विनिमय दर १ = १ शि॰ ६ पेंस बाँध दी थी।

(४) विनिमय समानीकरण कोष (Exchange Equalization Fund)
— ब्रिटेन ने सर्वप्रथम इस प्रकार के कोष का निर्माण किया था जिसका उद्देश्य
सद्देशाजी के कारण विनिमय दर में होने वाले उत्थान-पतन को रोकना था। इस फंड
की राश्चि स्टर्रालंग दिलों और सोने में थी। इसमें स्टर्रालंग के बदले अन्य मुद्राओं को खरीदा जा सकता है और विनिमय दर में स्थायित्व लाया जाता है।

(अर्विनमय प्रतिबंध—इसका तात्पर्य मुद्रा ऋधिकारियों को कानूनन रोकना है जिनके द्वारा विनिमय बाजार में माँग ऋौर पूर्ति प्रमावित होती हैं। यह एक अत्यक्त कठोर और ऋत्यधिक प्रमावशाली नीति है।

भारत में विदेशी विनिमय नियंत्रण

रिजर्व बेंक भारत में द्वितीय महायुद्ध से, विदेशी विनिमय का नियंत्रण कर

रहा है। जिसके लिए विनिमय नियंत्रण विभाग (Exchange Control Department) की स्थापना की गई है। सन् १६४७ के विनिम्य नियंत्रण कानून (Foreign Exchange Control Act 1947) के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को विदेशी विनिमय का कय-विकय करने के लिए अधिकार दिया गया है। यह वैंक उन्हीं कार्यों के लिए विदेशी विनिमय देता है जो सरकार द्वारा आयात-निर्यात के आंतर्गत निश्चित किए जाते हैं। ये कैंक व संस्थाएँ समय-समय पर रिजर्व बैंक को विदेशी विनिमय का तेखा-जोखा भेजती हैं ताकि उनके उपयोग का ज्ञान हो सके। सन् १९५४ से वर्मा के यात्रियों को भी मुद्रा लाने का अधिकार दिया गया है बशर्त्ते कि वे अशोक चिन्ह वाले नोट लाते हैं। इसी प्रकार सन् १६५५ से पाकिस्तानियों को ऋधिकार दिया गया कि वे पाकिस्तानी नोट १०० रुपए के प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से ले जा सकते हैं। परन्तु भारतीय नोट प्रति व्यक्ति ५० रुपए से ऋधिक नहीं ले जा सकते। विदेशी मुद्रा कोष को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने १ जनवरी १९५७ से उन विदेशी यात्रियों को जो मनोरंजन एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए जाते हैं विदेशी विनिभय का अलाउंस देना बंद कर दिया है। इसके अतिरिक्त २७ जून १९५७ से भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा मनीत्र्यार्डर द्वारा भेजने की सुविधा भी समाप्त कर दी है।

प्रश्न

1. What are the motives of Exchange Control? Describe the methods of Exchange Control. (Agra B. A. 1957).

2. कव समता सिद्धांत (Purchasing Power Parity) पर टिप्पणी लिखिए

(श्रागरा १६५७ बी. ए. बी. काम)

3. What do you understand by favourable and unfavourable rate of exchange? What are the factors which cause the exchange rate to be favourable or unfavourable? (Agra B. Com. I. 1957).

4. Show how the foreign exchange value of a country's currency is determined.

(Agra B. A. 1959)

5. विनिमय दर को कौन-कौन सी बातें प्रभावित करती हैं ? (श्रागरा बी. ए. १९५६)

अध्याय १२

श्रंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोप

(International Monetary Fund)

प्रथम महायुद्ध के पर्चात् संसार के प्रायः सम्पूर्ण देशों को मौद्रिक तथा विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देशी तथा विदेशी व्यापार में भी कठिनाइयाँ सामने स्राने लगी। प्रत्येक देश इन कठिनाइयों को निवारण करने के लिये अपनी मौद्रिक नीति में परिवर्तन करने लगा। विनिमय अवमूल्यन तथा विनि-मय नियंत्रण की प्रणालियाँ प्रायः सभी देश अपनाने लगे । ऐसी अवस्था में प्रत्वेक देश अपने हित के लिये ही मौद्रिक नीति में परिवर्तन करना वांछनीय समभता था। श्रन्य देशों के हितों का कुछ भी ध्यान नहीं रक्खा जाता था। इस प्रकार इस काल में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के स्थान पर पारस्यरिक स्पर्धा का ही अधिक बोलावाला हो गया जिससे राष्ट्रों की ऋर्थिक दशा डाँवाडोल होने लगी। दूसरे महायुद्ध ने इन समस्यात्रों को त्रौर भी जाटिल बना दिया। प्रत्येक देश में युद्ध कालीन विध्वंस के कारण त्राधिक पुनर्वासन तथा पुनर्निर्माण की गम्भीर समस्यायें त्रावश्यक रूप से युद्ध समाप्त होने के पश्चात् स्राने को थी। इन समस्यायों का हल स्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना श्रसम्मव था। इसके श्रतिरिक्त संसार के कुछ बड़े-बड़े नेताश्रों का यह भी विचार हुन्ना कि न्नाधुनिक काल में युद्ध प्रायः न्नार्थिक कारणों से ही होते 🖥 । ऋतः युद्ध निवारण हेतु भी ऋन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ऋावश्यक है । इस ऋावश्यकता की पूर्ति के लिये इंगलैंड, अमेरिका तथा कनाड़ा ने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की योजनायें निर्मित की । इन पर विचार करने के लिये अमेरिका ने सन् १६४४ ई० में ब्रिटनउड्ज़ नामक स्थान पर एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-परिषद् बुलाई । इस परिषद् में ४४ मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विचार-विनिमय के पश्चात् इन प्रति-निधियों के द्वारा एक योजना स्वीकृत की गई। इस योजना के अनुसार एक अन्त-र्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक स्थापित करने का निश्चय किया गया।

जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सम्बन्ध है इसके स्थापित करने के लिथे निम्नांकित उद्देश्य घोषित किये गये—

- (१) इस संस्था द्वारा स्थाई रूप से विभिन्न देशों के मध्य मौद्रिक सहयोग का विकास करना।
 - (२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और सन्तुलित विकास को सुविधा-

जनक बनाना ग्रौर इस प्रकार सभी सदस्य देशों में ऋधिक-से-ग्रिधिक व्यक्तियों को कार्य दिलाने का प्रबन्ध करना।

- (३) विनिमय स्थिरता को स्थापित करना । सदस्य देशों के मध्य निर्धारित विनिमय व्यवस्थार्श्वों को बनाये रखना तथा प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय श्रवमूल्यन को रोकना ।
- (४) सदस्य देशों के लिये कोष के साधनों को उपलब्ध करके उनमें विश्वास उत्पन्न करना और प्रत्येक देश की उसके शोधनाशेष की त्रुटियों को दूर करने में सहायता देना।
- (५) सदस्य देशों के बीच चालू ब्यवसायों के सम्बन्ध में बहुदेशीय शोधन प्रणाली की स्थापना करना तथा विदेशीय विनिमय सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटाने में उनकी सहायता करना।
- (६ उपरोक्त व्यवस्थाओं के अनुसार सदस्य देशों के अन्तर्राष्ट्रीय शोधना-शेष के असन्त्रलन की अवधि और उसके अंश को कम करना।
- (७) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति के लिये विनिमय सम्बन्धी किंटनाइयों को दूर करना।

कोष की निधि — कोष की निधि का मूल्य ८८० करोड़ डालर निश्चित किया गया जिसके लिये प्रत्येक सदस्य देश के अभ्यंश निश्चित कर दिये गये। कितप्य बड़े देशों के अभ्यंश निम्न प्रकार से हैं —

देश	अभ्यंश करोड़ डालर में
मंयुक्त राज्य श्रमेरिका	२७५
ब्रिटेन	१३०
रूस	१२०
चीन	પૂપ્
फ्रांस	४५
भारत	80

त्रन्य सिमलित देशों के अभ्यंश भी इसी प्रकार निश्चित कर दिये गये थे । बाद में सिमलित होने वाले देशों के अभ्यंश की रकम को निश्चिय करने का अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दे दिया गया था । अभ्यंश के मूल्य में परिवर्तन सम्बन्धित देश की प्रार्थना पर किया जा सकता है । प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी भी देश के मुद्रा कोष को दें बहुमत के आधार पर बदल सकता है यदि सम्बन्धित देश की स्वीकृति प्राप्त हो जाय । प्रत्येक सदस्य देश को अपने अभ्यंश का दे अथवा सरकारी स्वर्ण तथा डालर जमा का के सोने में देना होता है । और श्रेप्तानी अपनी मुद्रा में बमा किया जाता है । स्वर्ण के अविरिक्त शेष अभ्यंश

अन्तर्गप्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकत्ता के रूप में सदस्य देश की केन्द्रीय बैंक के पास ही रक्खा जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कोप का विधान तथा प्रवन्ध

कोप के कार्य संचालन का भार एक गवर्नर मंडल कार्यकारिणी संचालक, प्रवन्ध डांयरेक्टर तथा उसके कर्मचारियों पर डाला गया है। कोष का दैनिक कार्य कार्यकारिणी संचालक समिति द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इस समिति के बारह (१२) सदस्य होते हैं ५ स्थाई तथा ७ स्थाई। प्रथम ५ उन पाँच बड़े-बड़े गण्ट्रों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं जिनके अभ्यंश सबसे अधिक हैं। २ की नियुक्ति लेटिन अमेरिका के देशों द्वारा की जाती है। और शेष का अन्य सदस्य देशों द्वारा। निर्वाचन अनुपातीय प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। कोई भी सदस्य देश साधारण सूचना देकर कोष की सदस्यता से प्रथक हो सकता है। कोष का प्रधान कार्यालय अमेरिका में है। परन्तु इसकी शाखायें सदस्य देशों में स्थापित की जा सकती हैं।

मुद्रा कोष में स्वर्ण का स्थान

श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से सदस्य देशों को त्रिना स्वर्णमान स्था-पित किये ही स्वर्णमान का लाभ प्राप्त होता रहता है। इस कोप में स्वर्ण तीन प्रकार से सम्बन्धित है:

- (१) प्रथम प्रत्येक सदस्य देश के अभ्यंश का एक निश्चित भाग स्वर्ण में कोष के पास जमा होता है।
- (२) प्रत्येक सदस्य देश अपने चलन का प्रारम्भिक स्वर्ण में निर्भारित करता है।
- (३) किसी सदस्य देश की सुद्रा की दुर्लभता की दशा में उसे स्वर्ण में खरीदने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा कोष के अन्तर्गत स्वर्ण को चलन में रखने अथवा स्वर्णभान स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण कीमतों के सामूहिक माप का काम करता है। और प्रत्येक सदस्य देश निश्चित कीमतों पर सोने को खरीदने तथा बेचने के लिये तैयार रहता है।

विनिमय द्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

प्रत्येक सदस्य देश को अपने चलन का मूल्य १ जुलाई सन् १६४४ के आधार पर स्वर्ण अथवा अमरीकन डालर में निर्धारित करनी पड़ती है। इस प्रकार अमरीकन डालर सदस्य देशों की मुद्राओं का मूल्यमापक बन जाता है। इसके कारण विभिन्न देशों के विनिम्मय दरों के निर्धारण करने में कोई कठिनाई नहीं रही। प्रत्येक सदस्य देश आवश्यकतानुसार निर्धारित विनिम्मय दर में १० प्रतिशत तक परिवर्तन कर सकता है। इससे अधिक परिवर्तन के लिये कोष की आज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। २० प्रतिशत ते अधिक परिवर्तन के लिये विदस्य देशों की संख्या का दो-

तिहाई बहुमत त्रावश्यक है। नियम भंग करने पर सम्बन्धित देश को कोष की सुवि-धात्रों से वंचित किया जा सकता है। त्राथवा उसे कोष की सदस्यता से प्रथक किया जा सकता है।

कोई भी सदस्य देश एक वर्ष के अन्दर कोष से अपने चलन के बदले में अपने अभ्यंश के २५ प्रतिशत से अधिक विदेशी विनिमय नहीं खरीद सकता और योग में वह अधिक से अधिक अपने अभ्यश २००% विदेशी विनिमय खरीद सकता है। सकटकालीन अवस्थाओं में ये सीमायें दीली की जा सकती हैं। ऋणी सदस्य को मुद्रा कोष के ऋण पर १% से लेकर २१% तक ब्याज देना पड़ता है। दिये गये ऋण के विषय में कोष इस बात का भी ध्यान रखता है कि सम्बन्धित देश ऋण को कोष के विषय उद्देशों में प्रयोग न कर सके।

कोष का महत्व तथा कार्य

ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ग्रन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक च्लेत्र में पारस्परिक सहयोग श्रथवा सहकारिता की भावना पर की गई है। युद्धोत्तर काल में कुछ सदाश्रों के दर्लभ होने की सम्भावना पहले ही हो गई थी। इसलिये मुद्रा कोष के द्वारा इस प्रकार की दुर्लभता को दूर करने का प्रयत्न किया गया । यदि किसी समय कोष अपने साधनों से किसी मुद्रा की माँग को पूरा न कर सके तो वह विशेष देश से उधार ले सकता है अथवा सोना देकर खरीद सकता है। यह करने के पश्चात भी यदि कोष मुद्रा की पूर्ति में असफल रहे तो वह दुर्लभता के कारणों की सूचना देते हुये राशनिंग व्यवस्या के त्राधार पर त्राधिक रूप में सबकी माँग पूरी कर सकता है। इस प्रकार कोष अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की एक सुन्यवस्थित तथा आवश्यक संस्था है। यह त्राल्पकालीन ऋण देकर सदस्य देशों के शोधनाशेष के घाटे को दूर कर देता है अथवा कम कर देता है। इस प्रकार इस संस्था के कारण सदस्य देशों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ऋल्पकाल कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। सुद्रा कोष केन्द्रीय बैक ऋथवा स्थिर कोघ के द्वारा ही सदस्य देशों के साथ व्यवसाय कर सकता है। ऋौर सदस्य देश भी कोष के साथ केन्द्रीय बैंक स्त्रादि संस्थास्त्रों के द्वारा ही व्यवसाय कर सकता है। कोष शोधनाशेष सन्तुलन हेतु किसी सदस्य देश की आ्रान्तरिक आर्थिक संगठन में हस्तत्त्वेप नहीं कर सकता और न उसे निजी संस्थात्रों अथवा ब्यक्तियों के साथ व्यवसाय करने का ऋधिकार है।

मुद्रा कोष का श्रालीचनात्मक सिंहावलीकन

यद्यपि मुद्रा कोष ने सदस्य देशों को श्रल्पकालीन ऋग् देकर पर्याप्त सहायता पहुँचाई है फिर भी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों दृष्टिकोणों से इसकी पर्याप्त आलोचना की गई है। सबसे बड़ी श्रालोचना कोष के श्रम्यंश निर्धारण के श्रवैश-

निक श्राधार पर है। श्रालोचकों का कहना है कि विभिन्न देशों का श्रम्यश किसी वैज्ञानिक श्राधार पर निश्चित नहीं किया गया है। वास्तव में श्रंग्रें जो तथा श्रमरीकनों के श्राधिक तथा राजनैतिक स्वार्थों को ध्यान में रखते हुये श्रम्यंश निर्धारित किये गये हैं। यही कारण है कि रूस को शीन्न ही त्यागपत्र देना पड़ा श्रौर श्रन्य समाजवादी राष्ट्र भी इसके सदस्य नहीं हो सके। इस प्रकार की त्रृटि को दूर करने के लिये श्रम्यंश सम्बन्धित देशों की विदेशी व्यापारों की मात्रा के श्राधार पर निर्धारित किये जाने चाहिये थे। श्रथवा व्यापार। रोप की स्थित या विदेशी विनिमय की श्रावश्यकता को श्राधार बनाया जाना चाहिये था। पर ऐसा नहीं किया गया श्रौर इसीलिये बहुत से राष्ट्र इससे श्रसन्तुष्ट रहे।

कुछ त्रालोचकों के त्रनुसार मुद्रा कोप की कार्यकारिणी की सदस्यता भी इसी प्रकार से रक्खी गई है कि त्रमरीकन हितों की रचा होती रहे। उनके त्रनुमार इसी-लिये लेटिन त्रमेरिका के देशों के लिये दो (२) स्थान सुरिच्चत किये गये हैं। इस प्रकार की सदस्यता से भविष्य में पिश्चमी देश त्रपने त्रार्थिक हितों की उन्नति के लिये सुद्रा कोष द्वारा इस प्रकार की नीति का पालन करवा सकते हैं जो त्राविकसित देशों के लिये हानिकारक हो जिसके फलस्वरूप ऐसे देशों को उसकी सदस्यता से प्रथक हो जाना पड़े। यदि ऐसा हुत्रा तो जिस उद्देश्य से त्रन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा कोष स्थापित किया गया है वह उद्देश्य हो पूरा न हो सकेगा। व्यावहारिक दृष्टि से भी कुछ लोगों ने मुद्रा कोष पर त्रारोप लगाये हैं। इनके त्रनुसार कोप ने त्रमुणों के प्रदान करने त्रीर त्रावश्यक सुविधात्रों के प्रदान करने में भेद-भाव किया है। तथा शक्तिशाली देशों से यह त्रपनी त्राज्ञा का पालन नहीं करवा पाता। उदाहरण के लिये फ्रांस ने गत वर्षों में कोष की त्राज्ञा के विरुद्ध त्रपनी सुद्रा का त्रवमूल्यन कर दिया है, फिर भी कोष ने फ्रांस को किसी प्रकार से दंडित नहीं किया।

उपरोक्त श्रालोचनाश्चों को ध्यान में रखते हुये भी कोष की उपयोगिता में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । कोई भी व्यक्ति श्रयवा मानव निर्मित संस्था सब सम्बन्धित लोगों को शत प्रतिशत संतुष्ट नहीं कर सकती । श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी इसी सूत्र के श्राधार पर सब राष्ट्रों को सन्तुष्ट नहीं कर सकती, फिर भी यह एक सामयिक श्रावश्यकता को पूर्ण करती है। इसकी कार्यप्रणाली में जो छेद द्वष्टिगोचर हो रहे हों वे समय-समय पर श्रनुभव के श्राधार पर दूर किये जा सकते है। श्रीर इस प्रकार यह संस्था प्रगतिशील तथा श्रिष्ठक-से-श्रीधक देशों को हितकारक बनाई जा सकती है। इसके श्रभी तक के इतिहास से स्पष्ट है कि कोष ने सदस्य देशों की पर्याप्त सहायता की है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से प्रगट होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा को ष तथा भारत

भारत श्रन्तरिष्ट्रीय मुद्रा कीष का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश हैं। पहले तो भारत के दो प्रस्ताव कि भारत को कोष की कार्यकारिणी में स्थाई स्थान दिया जाय तथा इसके पाँड पाउना श्रुणों को मुद्रा कोष के कार्यच्चेत्र में सम्मिलित किया जाय श्रुस्तीकृत कर दिये गये थे। इससे भारत कोष का सदस्य बनने में संकोच कर रहा या। पर रून के प्रथक हो जाने से भारत इसका स्थाई रूप से सदस्य बन गया तथा पाँड पाउना श्रुणों के सम्बन्ध में ब्रिटेन से संतोषजनक समभौता हो गया। श्रुतः श्रुक्टूबर सन् १९४६ ई० में भारत ने कोष की प्रारम्भिक सदस्यता प्राप्त कर ली। इस सदस्यता से भारत को काफी लाम हुआ है। सन् १९४८ व १९४६ में भारत ने अपने ज्यापाराशेष घाटे को पूरा करने के लिये करीब ६ करोड़ डालर का श्रुण कोष से लिया था। कोष की सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात् भारत ने श्रुधिक समय से चले श्राये रुपये स्टरिलंग का वैधानिक सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। श्रीर प्रश्रुण सन् १९४७ ई० से रुपये का मूल्य स्वर्ण में नियत कर दिया है। भारत समय-समय पर मुद्रा कोष से श्रुण लेता रहता है। जब-जब शोधनाशेष का घाटा बढ़ जाता है भारत कोष से श्रुण लेता है और कोष यथासम्भव भारत की श्रुण प्रार्थनाये स्वीकार कर लेता है। भारत ने कोष से श्रुव तक निम्न प्रकार से श्रुण प्राप्त किये हैं।

इस प्रकार भारत को कोष से काफी सहायता मिली हैं। वास्तव में भारत ने कोष की सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने में ख्याति प्राप्त की है। कोष ने १६-४६ ई० में भारत को ही अपने रुपये का अवमूल्यन करने की आजा दे दी थी। अवमूल्यन के पश्चात् भारतीय व्यापाराशेष में भी काफी सुधार हो गया है। कोष ने भारत की उद्योग संरच्या नीति में भी कोई हस्तचेप नहीं किया है। प्रत्यच्च संकटकालीन अवस्था में मुद्रा कोष ने भारतीय सरकार को व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाने की आजा प्रदान करती है। यही नहीं कोष की सहायता के आधार पर भारत को विश्व कैंक की सहायता भी प्राप्त हुई है। विश्व कैंक ने भी भारत को उसकी विकास योजनाओं के लिये काफी सहायता दी है। इस प्रकार कोष की सहायता से भारत को लाभ ही हुआ है।

^{1.} अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I. M. F.) क्या है। यह किस प्रकार कार्य करता है ? इस कोष से मारत से क्या लाम हुआ है ? (आगरा बी. ए. १६५६)

^{2.} India's admission to the International Monetary Fund marks the inauguration of a new currency standard for India. Explain carefully and examine the existing Indian currency system.

(Agra B. A. 1956)

ऋध्याय १३

श्रंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भारत का विदेशी व्यापार

(International Trade and India's Foreign Trade)

देश के विभिन्न प्रदेशों अथवा चेत्रों में होने वाले व्यापार को देशीय. आंत-रेक अथवा अंतरर्थानीय व्यापार (Internal, Inland or Interregional Trade) हहते हैं। त्रांतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार से त्राभिपाय दो पृथक-पृथक राष्ट्रों के बीच होने वाले व्यापार से है जैसे भारत का पाकिस्तान या श्रमिरिका से व्यापार । दोना हा मकार के व्यापार का उद्देश्य फालतू या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वस्तुत्रों स्रथवा सेवा के बदले ऐसी वस्तएँ या सेवा प्राप्त करना है जो कि उपलब्ध नहीं हैं अथवा आसानी से सुलभ नहीं होती। इस प्रकार दोनों के विनियोग से ऋधिकतम ऋगवश्यकता ऋों की संतुष्टि होती है। देश के ऋंदर लगभग सभी स्थानों पर ब्याज एवं मज़रूरी एक से होते हैं ऋतः उत्पत्ति के साधन ऋासानी से गतिशील होते हैं। इस कारण विभिन्न देशों में एक ही वस्तुत्रों त्रौर सेवात्रों के उत्पादन व्यय में त्र्यंतर रहता है। यह उत्पा-दन ब्यय में स्रांतर ही वस्तुस्रों के विशिष्टीकरण (Specialisation) का कारण होता है स्त्रीर एक ही वस्त भी कीमत विभिन्न देशों में विभिन्न होती है। इसके श्रतिरिक्त श्रम, उत्पादन वितरण । स्थानीय कर एवं श्रन्य नियम समान रहते हैं । परंतु विभिन्न देशों में समानता नहीं रहती, इस कारण भी उत्पादन ब्यय में विभिन्नता स्त्रा जाती है। देशी व्यापार में मुद्रा-प्रगाली, त्र्यायात-निर्यात, विनिमय त्र्यादि की कोई समस्या नहीं होती परंत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। श्रतः राष्ट्रीय श्रौर श्रंतर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रलग-श्रलग सिद्धांतों की श्रावश्यकता होती हैं। परंतु मौलिक रूप में समस्याएँ एक ही हैं। श्रौहिलिन (Ohlin) के शब्दों में श्रांतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है।"

श्रांतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण

त्रांतर्राष्टीय व्यापार की उत्पत्ति का कारण वस्तुत्रों का विशिष्टीकरण एवं उनके मूल्यों में क्रांतर है। यह ऊपर भी वर्णन किया जा चुका है। विभिन्न देशों में इस मूल्यांतर का कारण प्राकृतिक साधन, क्रार्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दशाएँ होती हैं।

उपरोक्त कथन को सिद्ध करने के लिये एक काल्पनिक उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिये उत्पति के निश्चित साधनों से भारत में २० गज सूती-बस्त्र

ही साधनों से १० गज सूती वस्त्र अथवा ३० गज जूट का सामान तैयार किया जा सकता है। उपरोक्त ग्रंको से स्पष्ट होता है कि भारत में दोनों वस्तुत्रों का उत्पादन पाकिस्तान की अपेता सरल पड़ता है क्योंकि जितनी लागत से पाकिस्तान में 🚱 🗷 गज़ सुती वस्त्र तैयार होता है उतनी लागृह्य से भारत में २० गज़ तैयार होता है न्त्रौर उसी लागत से यदि पाकिस्तान हैं गैज़ जूट का माल तैयार करता है तो भारत उसी लागत पर ४० गज़ जूट का सामान तैयार करता है। <u>अतः एक ही लागत</u> पर पाकिस्तान की अपेद्धा भारत में दोनों वस्तुयें अधिक मात्रा में उत्पादित होती हैं। इसलिये स्वभावतः भारत को ही इन दोनों वस्तुत्रों का उत्पादन करना चाहिये श्रीर पाकिस्तान को भेजना चाहिय श्रीर इसी में दोनों को लाभ होना चाहिये पर यदि गम्भीरता से ख्रंको पर विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि ऐसा होते हुये भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दोनों देशों को तभी लाभ होगा जब भारत सूती वस्त्र नैयार करे श्रौर उसे पाकिस्तान को भेजे तथा पिकस्तान जूट का माल तैयार करे श्रौर भारत को भेजे। 822 17 FUTT यदि भारत दोनों वस्तुत्रों को ऋपने यहाँ उत्पादन करे तो एक गज़ सूती वस्त्र के स्थान पर २ गज़ जूट का सामान मिल सकेगा क्योंकि उदाहरण में २० गज़ स्ती वस्त्र की लागत ४० ग जूट के सामान के बराबर है। इसलिये विनिमय दर १ गज़ स्ती कपड़े के बदले में २ गज़ जूट का सामान हुई। पाकिस्तान में यही विनिमय दर १ गज़ सूती कपड़े के बदले में ३ गज़ जूट का सामान हुई होगी क्योंकि वहाँ १० गज सूती वस्त्र की लागत ३० गज जूट के सामान की लागत के बराबर है। ऋतः पाकिस्तान में १ गज़ स्ती वस्त्र के बदले में २ गज़ जूट का सामान मिल सकेगा जब कि भारत में १ गज़ सूती वस्त्र के बदले में २ गज़ जूट का सामान मिलेगा।

अथवा ४० गज़ जूट का समान तैयार किया जा सकता है परंतु पाकिस्तान में उतने

ब्यापार द्वारा वस्तुओं का आदान-प्रदान करें ।

मान लीबिये कि इस आदान-प्रदान में विनिमय दर एक गज़ सूती कपड़े के बदलें में रहें गज़ जूट का सामान निश्चित होती हैं तो दोनों देशों को आधे २ गज़ जूट के सामान का लाम हो जाता है। यदि भारत दोनों वस्तुओं को आपने यहाँ उत्पादन करता तो उसे सूती वस्त्र के प्रत्येक गृज़ के बदलें में २ गज़ जूट का सामान मिलता जब कि पाकिस्तान से वह २ भे गज़ जूट का सामान पा सकता है। इसी प्रकार यदि पाकिस्तान दोनों वस्तुओं को आपने यहाँ उत्पन्न करें तो जूट के माल के प्रत्येक ३ गज़ के बदलें में १ गज़ सूती कपड़ा प्राप्त हो सकेगा और यदि वह सूती कपड़ा

भारत से मँगाये तो ३ गज़ जूट के माल के स्थान पर २५ गज़ जूट का सामान देने

प्रेंधी दशा में दोनों देश को लाम तभी होता जब भारत केवल सूती वस्त्र का उत्पादन करे ऋौर पाकिस्तान केवल जूट का सामान बनाये ऋौर फिर दोनों देश ऋापस में

से ही काम चल जायेगा है गज़ जूट के सामान की बचत हो जायगी। इस प्रकार दोनों देशों को लाभ होगा जब कि भारत सूती वस्त्र तैयार करे श्रौर पाकिस्तान जूट का सामान तैयार करे यद्यपि होनों वस्तुत्रों की लागत व्यय पाकिस्तान की ऋपेना भारत में कम पड़ती है। इस सिद्धांत को उलनात्मक लागत का नियम कहते हैं और इसी के त्राधार पर त्राधिकांश त्रान्तर्राष्ट्रीय न्यापार होता है। इस सिद्धांत के ऋनुसार प्रत्येक देश केवल उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसके उत्पादन में उसे अधिक-तक सुविधायें हों अथवा न्यूनतम असुविधायें हों जिससे अन्य देशों की अपेद्धा वस्तु के उत्पादन में लागत व्यय कम रहे। इसी सिद्धांत के ऋाधार पर भारतवर्ष में कपास के उत्पादन में अधिकतम नविधायें हैं और पाकिस्तान में जुर का माल उत्पादन करने में न्युनतम असुविधायें हैं जिससे तुलनात्मक दृष्टि से भारत में सुती बन्न का उत्पादन तथा पाकिस्तान में जट के सामान का उत्पादन कम लागत पर होता है। प्क निश्चित लागत व्यय पर जितना वस्त्र पाकिस्तान उत्पाद्व करता है उसका दुगुना भारतवर्ष में उत्पन्न होता है। परन्तु भारत उसी लागत व्यय पर जितना वस्त्र तैयार करता है जूट का सामान उससे दुगुना तैयार कर पाता है पर पाकिस्तान उसी लागत च्यय पर जितना सूती वस्त्र तैयार करता है उससे <u>३ गुना जूट का</u> सामान तैयार करता करने में और पाकिस्तान को जूट का सामान तैयार करने में दोनों देशों को लाभ होता है यदि वे इन वस्तुत्रों का त्रादान-प्रदान करने लगें।

उपरोक्त उदाहरण में यह दिखलाया गया है कि प्रत्येक देश को है। गज जूट के माल का लाभ होता है क्योंकि विनिमय दर १ गज सूती वस्त्र = २ र गज जूट वस्तु के है पर वास्तव में लाभ कम या अधिक हो सकता है। यदि पाकिस्तान को सूर्ता कपड़े की आवश्यकता अधिक है तो एक गज सूती कपड़े के बदले में २३ गज से अधिक पर ३ गज से कम जूट का माल देने को पाकिस्तान को बाध्य होना पड़ेगा। हो सकता है कि वह २ है गज जूट का सामान देने को तैयार हो जाय। ऐसी हालत में भारत को है गज का तथा पाकिस्तान को है गज का लाभ रहा। इसके विपरीति यदि भारत की जूट सामान के लिए माँग अधिक प्रवल है और पाकिस्तान की भारतीय कपड़े की माँग अधिक प्रवल नहीं है तो भारत को १ गज कपड़े के बदले में कम से कम जूट का सामान लेने को तैयार होना पड़ेगा जो कि २ गज से कम न होगा। हो सकता है कि भारत केवल २ है गज जूट के सामान के बदले में ही एक गज सूती कपड़ा देने को तैयार हो जाय, ऐसी दशा में भारत की अपेचा पाकिस्तान को अधिक लाभ रहेगा। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस देश की वस्तु की माँग विदेश में अधिक प्रवल होती है जितनी प्रवल विदेशी वस्तु की माँग उस देश में नहीं होती तो उस देश को विदेश की अपेचा अधिक लाभ होता है। यह निष्कर्ष सर्वया सस्य है। व्यापार में यातायात

के व्यय अधिक वस्तुएँ तथा अधिक देशों के होने से उपरोक्त निष्कर्ष असत्य नहीं होता है।

विदेशी व्यापार के लाभ (Advantages of Foreign Trade)

विदेशी व्यापार का ऋाधार यह है कि इसमें प्रत्येक देश को लाभ होता है।
यह निम्न प्रकार दर्शीया जा सकता है:—

﴿. विदेशी व्यापार द्वारा विभिन्न देशों के बीच अस विभाजन संभव होता है। विदेशी व्यापार के कारण प्रत्येक देश ऐसी वस्तुत्रों का उत्पादन करता है जिन्हें न्यूनतम लागत पर पैदा कर सके। इस प्रकार विशिष्टीकरण संभव होता है त्रौर उत्पादन त्रमुकुल परिस्थितियों में होता है जिससे मानव का कल्याण होता है।

र विदेशी व्यापार से उपमोग का स्तर बढ़ता है तथा उपमोग में विभिन्नता आती है। एक देश में, यदि किदेशी व्यापार हैं तो, ऐसी वस्तुएँ आयात की जाती हैं बो देश में उत्पन्न नहीं होतीं अथवा तेज कीमत पर उत्पादित की जा सकती हैं। विदेशी व्यापार में उस देश से माल आता हैं जहाँ पर कम लागत पर उत्पादन होता और उपभोक्ता उस बाजार से वस्तुएँ खरीद सकते हैं जहाँ से उन्हें सस्ती मिलती हैं।

रे. विदेशी व्यापार संकटकालीन स्थिति को दूर करता है। देश में अतिवृध्यि या अनावृष्टि से दुर्भिक्त पड़ता है या कोई वस्तु कम उत्पन्न होती है तो विदेशों से उसे मँगा सकते हैं और आर्थिक संकट दूर किया जा सकता है।

४. विदेशी व्यापार द्वारा संसार के देशों में वस्तुओं की कीमत में समानता रहने की प्रवृत्ति रहती है। इससे उपभोग का स्तर बढ़ता है।

- 4. विदेशी व्यापार से प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलता है जिससे देश के उत्पादकों और व्यापारियों को सुधारों एवं कार्यद्मता के प्रति सजग एवं सचेष्ट रखा जा सकता है। इस देश के प्रवंध में भी कार्यशीलता आती है और प्रतियोगिता के मय से उत्पादक या व्यापारी उपभोक्ता से अधिक मूल्य वसूल नहीं कर सकते।
- ६. विदेशी व्यापार की सहायता से देश में आवश्यक कञ्चा माल, मशीनें, विशेषशों को उपलब्ध किया जा सकता है तथा इनकी सहायता से देश के औद्योगी- करण को विकस्ति किया जा सकता है।
- ७. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने की दृष्टि से भी अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार लामकारी है।
- प्राचित के सभी साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। देश की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वस्तु विदेशों में भेज कर उसे नष्ट होने से बचाया जा सकता है श्रीर श्राधिक उन्नति की जा सकती है।

परन्तु उपरितिखित लाभ तभी दृष्टिगोचर होते हैं जब कि विभिन्न देशों

में पारस्परिक सहानुभूति हो श्रौर व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो श्रन्यया विदेशी व्यापार से कभी भी इतने लाभ प्राप्त नहीं हो पाते ऋौर निम्नांकित हानियों की गुंजायश रहती है। जैसे (१) विदेशी व्यापार द्वारा प्रचुर मात्रा में मिलने वाले साधन खप जाते हैं श्रौर फिर उनका मिलना उस देश में प्रायः श्रसंभव ही हो जाता . है। (२) विदेशी व्यापार द्वारा उन्नत प्रतियोगिता का विकास होता है श्रौर इस प्रतियोगिता में केवल विकसित देश ही भाग ले सकते तथा लाभ उपार्जित कर सकते हैं। अविकसित देशों में उद्योग-धंघे या तो स्थापित ही नहीं हो पाते अथवा पनप नहीं पाते और ऋर्थिक विकास में ऋरीर भी ऋषिक पिछड़ जाते हैं। (३) विशिष्टी-करण द्वारा देश का एक दिशायी विकास हो पाता है। बहुमुखी आर्थिक विकास नहीं हो पाता । इससे संकटकाल या युद्धकाल में देश को बुरे आर्थिक परिसाम भोगने पड़ सकते हैं और दूसरी ऋोर देश में कितने ही ऋार्थिक एवं प्राकृतिक साधन वेकार पड़े रहते हैं। (४) इस प्रकार विदेशी व्यापार देश की ऋर्य-व्यवस्था की दसरे देशों की अर्थ-व्यवस्था पर आश्रित कर देता है। यह पराश्रयी भावना एवं प्रवृत्ति देश के सम्मान एवं त्रार्थिक विकास में रोड़ा ऋटकाती है तथा ऋार्थिक संकट के समय भयंकर रूप धारण कर सकती है। (५) विदेशी व्यापार द्वारा ऐसी वस्तएँ त्राती रहती हैं जिनका सेवन समाज एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हो सकता है त्रीर त्रागे चल कर बुरी त्रादत डाल देता है। जैसे भारत में सिगरेट का प्रयोग और चीन में अफीम का उपयोग। (६) विदेशी व्यापार द्वारा दो देशों में प्रतिद्वदिता का जन्म होता है और फिर एक राष्ट्र हमेशा दुसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने की सोचता रहता है।

ये हानियाँ २० वीं शताब्दी में तो पर्याप्त प्रतिलक्षित होने लगी हैं ह्यौर पारस्परिक द्वेष-भाव एवं झंतर्राष्ट्रीय भगड़ों को जन्म दिया है ह्यौर राजनैतिक शोषण का झंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख साधन बना हुझा है । भारतवर्ष का विदेशी व्यापार

भारत विदेशी व्यापार के लिए ऋत्यन्त प्राचीन समय से प्रसिद्ध हैं। इसके व्यापारिक केन्द्र दिख्णी चीन, मलाया, ऋरव, फारस, पूर्वी ऋफीका, जावा, सुमात्रा तथा और भी ऋन्य देशों में थे। ईसा से २००० वर्ष पूर्व भारत लोहे ऋौर स्पात का निर्यात विदेशों को करता था। इसके ऋतिरिक्त बढ़िया रेशमी कपड़ा, मलमल, हाथी दाँत का सामान तथा दुशाले ऋादि विदेशों में भेजे जाते थे। ऋौर विदेशों से ताँवा, टीन, शीशा तथा चीनी ऋादि वस्तुएँ देश में ऋाया करती थीं। प्राचीन समय में भी भारत दूसरे देशों को जितने मूल्य का माल निर्यात करता था उससे कम मूल्य का माल ऋायात करता था। ऋौर इस प्रकार भारतीय व्यापार सर्वदा देश के ऋनुकुल रहता था।

सन् १२०० ई० के पश्चात् मुस्लिम आक्रमणों के कारण देश की राज बैतिक ब्यवस्था में शिथिलता आना आरंभ हो गया और इसका प्रभाव भारतीय व्यापार पर भी पड़ा। पुन्द्रहवें अताब्दी में योक्प में व्यापारिक जाअति प्रारंभ हुई। योक्प निवासी अपनी व्यापारिक उन्नित के लिए नए-नए देशों का पता लगाने लगे। कुछ लोग विशेषकर पुर्तगाल निवासी भारत में व्यापारिक केन्द्र बनाने में सफल हुए। उन्होंने घीरे-घीरे भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर गोआ, डामन, ड्यू आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया। उनके कार्यों से भारतीय व्यापार को हानि होने लगी। इसके पश्चात् योक्प की अन्य शक्तियाँ भी विशेषकर उच, फान्सीसी और अँगे ज भारतवर्ष में व्यापार करने की दृष्टि से प्रभुत्व जमाने लगे। इस होड़ में पारस्परिक फगड़े होने लगे और अंत में अंग्रे जों ने घीरे-घीरे भारत में अपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित कर लिए और अन्य योक्पीय शक्तियों की अपेदा अधिक शक्तिशाली बन गए।

श्रॅंग्रेजों ने उस समय के सुगल सम्नाटों तथा श्रन्य शासकों को प्रारंभ में यससंभव संतुष्ट रक्खा। श्रारंभ में ईस्ट इिएडया कम्पनी श्रपने हित में भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करती रही, परन्तु कुछ समय बाद कम्पनी के कमेचारियों में स्वार्थ श्रिषक फैल गया। इसके फलस्वरूप कम्पनी का व्यापार संबंधी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके कारण एक दूसरी कम्पनी भारत से व्यापार करने के लिए खोली गई। परन्तु सन् १७०२ ई० में ये दोनों कम्पनियाँ मिल कर एक हो गई। विदेशियों को उनके व्यापार के लिए सभी प्रकार की सुविधाएँ दी जा रहीं थीं क्योंकि विदेशियों ने शासकों को प्रसन्न कर लिया था। इस प्रकार भारतीय व्यापार श्रवनित को दिशा में चल पड़ा था।

विदेशियों में इस समय तक श्रॅंभे जों की व्यापारिक शक्ति बहुत बढ़ गई श्रौर उन्होंने इस परिस्थितियों से लाभ उठाकर भारतीय व्यापार को बहुत धक्का पहुँ-चाया। श्रव तक इंग्लैयड का सोना-चाँदी काफी परिमाण में भारत में श्राता था किन्तु धीरे-धीरे उसका श्रायात बंद कर दिया गया; क्योंकि भारत के तैयार माल का श्रायात इंग्लैयड में कम हो गया श्रौर इंग्लैयड श्रपने यहाँ का तैयार माल भारत को मेंबने लगा। इसी समय श्रॅंभे जों ने मुक्त व्यापार की नीति श्रपनाई। इसके फल-स्वरूप श्रॅंभे जों को इस व्यापार से श्रिधिक लाम होने लगा। श्रठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत से ईस्ट इंडिया कम्पनी ने केवल १० लाख पाउन्ड का व्यापार किया। परन्तु १८३४ ई० में यह बढ़कर ८० लाख पाउन्ड की सीमा तक हो गया।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीय व्यापार में बड़ा परिवर्तन हो गया। सन् १८६६ ई॰ में स्वेज नहर का निर्माण हो जाने से भारतीय विदेशी व्यापार में

एक नया युग प्रारम्भ हुआ। इससे पहिले भारत को आने वाले अँग्रेजी जहाजों को 'केप श्राफ़ गुड होप' होकर श्राना पड़ता या श्रौर इसमें ५००० मील अधिक सनुद्री यात्रा करनी पड़ती थी। स्वेज नहर के निर्माण से भारत और इंगलैगड की दूरी में काफी कमी ह्या गई । इघर १८५७ के पश्चात् भारत में ह्राँग्रेजी राज्य काफी हद हो गया। इस राज्य की स्थापना से मुगलकालीन ऋशान्ति व ऋराजकता समाप्त हो गई। देश में शान्ति स्थापित हो गई। यातायात के साधनों का विशेषकर रेलों का काफी विकास हुआ। इन कारणों से भारतीय विदेशी व्यापार को काफी प्रोत्साहन मिला। इसी समय बम्बई ऋौर स्वेज़ के बीच में समुद्री तार से संबंध स्थापित कर दिया गया, जिससे समुद्री यातायात में सरलता हो गई। इन कारणों से ऋव भारत-वर्ष से कम मृल्य वाली भारी वस्तुएँ विदेशों को जाने लगीं ख्रौर इल्की परन्तु वहु-मूल्य वस्तुएँ विदेशों से इस देश में आने लगीं। उदाहरण के लिए गेहूँ, चादक, तिल्हन, चमड़ा, जूट आदि विदेशों को निर्यात किया जाने लगा और विदेशों से सूती वस्त्र, मशीनें, रेलों का समान तथा अन्य निर्मित वस्तुऋों का आयात होने लगा। यद्यपि भारत से व्यापार करने की सब देशों को स्वतन्त्रता रही पर परिस्थितियाँ ऐसी सामने ऋाई कि जिनसे भारतीय विदेशी व्यापार में इंगलैयड वालों का प्रमुख स्थान रहा। इसके कई कारण थे। सबसे पहिले ब्रिटेन का जहाज़ी बेड़ा सबसे ऋधिक शक्तिशाली तथा चमतावान था। वैंकों पर भी ब्रिटेन का अधिकार अधिक था। भारतीय रेलों में ब्रिटिश पूँजी लगी हुई थी। उन पर ऋँग्रेजों का ही ऋधिकार था। अतः ये रेले प्रत्यच् अथवा अप्रत्यच् रूप से अँग्रेजी व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ दिया करती थीं जो दूसरों को उपलब्ध नहीं थी। ऋँग्रेजी राज्य होने के कारण देश की ऋार्थिक व व्यापारिक नीति भी ऋँग्रेजों के द्वारा निर्घारित की जाती थी । उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रांत तक भारतीय विदेशी व्यापार में इंगलैएड की प्रभुसत्ता बनी रही। इस समय तक देश के ऋायात का ५% तथा निर्यात का २५% अँग्रेजों के ही हाथ था। अमेरिका के ग्रह युद्ध ने भी भारत के साथ ऋँग्रेजी व्यापार को प्रोत्साहित करने में काफी सहायता दी, विशेषकर लंकाशायर को अमेरिका की करूची रुई मिलने में कठिनाई होने लगी और यह पूर्ति भारत की रुई से की गई । इससे भारत की निर्यात की मात्रा अधिक बढ़ गई । इस समय तक भारत का कुल निर्यात श्रायात की अपेचा अधिक रहा करता था श्रीर प्रति वर्ष व्यापारिक संदुलन देश के अनुकूल होने के कारण भारत का रूपया इंग्लैएड निवासियों पर वच रहता था।

इस प्रकार १६ वीं श्रताब्दी के उत्तराद्ध में भारतीय विदेशी व्यापार की निम्नलिखित विशेषताएँ थी —

१—स्वेज नहर के निर्माण से, देश में शान्ति स्थापना से, यातायात के साधनों की उन्नति से, भारतीय विदेशी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई। श्रायात तथा निर्यात दोनों उत्तरोत्तर बढ़ते गए। सन् १८५४-५५ई० में श्रायात व निर्यात कमशः २६८५ व २५८५ लाख र० के हुए। वे १६००ई० में बढ़ कर क्रमशः ८४६८ तथा १२४६२ लाख र० के हो गए।

२—इस काल में भारतीय निर्यात निर्मित तथा बहुमूल्य वस्तुओं के स्थान पर, कच्चे माल का अधिक होने लगा और आयात में निर्मित माल की प्रधानता होने लगी। इस दृष्टि से यह काल व्यापार तथा उद्योगों के लिए अवनित काल कहा जा सकता है क्योंकि विदेशी नीति के कारण भारतीय उद्योग नष्टभ्रष्ट होने लगे।

३— श्रायात श्रौर निर्यात में वस्तुश्रों के परिवर्तन होने पर भी व्यापार का संद्रुलन देश के अनुकूल ही रहता था। ऊपरी दृष्टि से यह बात संतोषजनक समभी जा सकती हैं पर वास्तव में यह स्थिति देश के प्रतिकूल पड़ने लगी, क्योंकि देश का कच्चा माल बहुत श्रिषक परिमाण में विदेशों को जाने लगा श्रौर वहाँ से निर्मित माल यहाँ श्राने लगा। संतुलन अनुकूल बनाए रखने के लिए देश को श्रिषक से श्रिषक कच्चे माल को विदेशों में भेजने के लिए बाध्य होना पड़ा। इससे देश में कच्चे माल की कमी रहने के साथ ही साथ रोजगार पर भी धक्का लगा। बेरोजगारी बढ़ने लगी और कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ने लगा।

४—इस समय के ज्यापार में ब्रिटेन का भाग उत्तरोत्तर बढ़ने लगा । इंगलैंगड मारत से आयात भी अधिक करने लगा और निर्यात भी क्योंकि दोनों ओर से इंगलैंगड को लाभ रहता था । मुक्त व्यापार नीति के कारण भारतीय कच्चा माल इंग्लैंगड में सस्ता पड़ता था और अँग्रेजी माल भारत में अन्य विदेशी माल से सस्ता रहता था । इस प्रकार अँग्रेज भारतीय बाजारों में अन्य विदेशियों से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा कर सकते थे ।

५—इस काल में चावल, गेहूँ, चाय, जूट, तिलहन, कपास, चमड़ा ऋादि कच्चे माल का निर्यात बढ़ता गया तथा सूती, ऊनी वस्त्र, मशीनें, ऋौर लोहे व काँच के सामान ऋादि निर्मित वस्तुऋों का ऋायात बढ़ता गया।

सन् १६१४ ई० में प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ते ही विदेशी व्यापार पर प्रतिकृत प्रभाव प्रारम्भ हो गया,। युद्ध काल में व्यापार कम ही रहा। इसके कई कारण थे। युद्ध के कारण देशों में यातायात के प्रबन्ध में काफी अव्य-वस्या हो गई थी, जिससे माल के आने-जाने में काफी असुविधा हो गई। शत्रु देशों से व्यापार विलकुल बंद हो गया तथा अन्य देशों से सामुद्रिक खतरों के कारण भी व्यापार कम हो गया। युद्ध में लगे हुए देशों की कयशक्ति कम हो जाने से भारतीय वस्तुश्रों की माँग विदेशों के कम हो गई। यातायात की श्रमुविधा तथा मार्ग में शत्रु भय के कारण बहुत से देशों ने विदेशों से माल लेना बन्द कर दिया। वे श्रपने देशों में ही वस्तु निर्माण करने लगे। इससे भी भारतीय व्यापार घट गया। व्यापारी जहाज़ युद्ध के कार्य में फँस गए जिससे वे व्यापारिक वस्तुश्रों को एक देश से दूसरे देश को ले जाने में श्रममर्थ हो गए। इसके साथ ही साथ जहाजों की कमी के कारण, जोखिम श्रधिक होने के कारण जहाजी भाड़े में काफी वृद्धि हो गई। इसका प्रभाव भी भारतीय व्यापार पर बुरा पड़ा। विदेशों में काग़जी सुद्रा का प्रसार बड़े जोरों से हुआ। इसके कारण भारतीय वस्तुएँ विदेशों में महँगी पड़ने लगीं जिससे उनकी माँग कम हो गई। इन सब कारणों के श्रतिरिक्त भारतीय सरकार ने श्रायात पर कर बढ़ा दिया तथा चाय श्रीर जूट पर निर्यात कर लगा दिया। इन करों का प्रभाव भी विदेशी व्यापार पर प्रतिकृत पड़ा।

इस प्रकार प्रथम महायुद्ध काल में भारतीय व्यापार में अबनित हुई। दोनों, आयात व निर्यात कम हुए। सन् १६१३ ई० में आयात १६८ करोड़ ६० तथा निर्यात ४३१ करोड़ ६० का था जो कि १६१६ ई० में कमशः १५० व ३५७ करोड़ ६० ही रह गए। इसके पश्चात् व्यापार में बृद्धि होना प्रारम्भ हुआ और सन् १६१८ ई० में देश का कुल आयात २१६ करोड़ ६० का और निर्यात ४६८ करोड़ ६० का था। इस समय में कच्चे माल के निर्यात में कुछ बृद्धि हुई परन्तु निर्यात माल के आयात में कुछ कमी हो गई। युद्ध के प्रारम्भिक वर्ष में कच्चे माल का निर्यात कुल निर्यात का ४०% के लगभग होता था जो १६१६ में ५१% के करीब हो गया, जब कि इसी काल में निर्मित माल का आयात ७६% से कम होकर ७०% पर पहुँच गया।

प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर, कुछ वर्षों तक तो युद्ध का प्रतिकृत प्रभाव व्यापार पर बना रहा । युद्ध में संतम्न देशों की आर्थिक स्थिति सुधरने में कुछ समय लगा । इससे भारतीय व्यापार में यथोचित उन्नति न हो सकी । यह नहीं, मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई संधि के कारण योरुपीय देशों की आर्थिक व्यवस्था शीघ ही ठीक न हो सकी । इंग्लैगड को स्वर्णमान पद्धति त्यागनी पड़ी । कर्मनी आदि देशों में मुद्रा स्फीति प्रचुर मात्रा में होने लगी । इन कारणों से कुछ समय तक भारतीय व्यापार को उचित प्रोत्साहन न मिला । साथ ही साथ देश में अम सम्बन्धी भगड़ों में दृद्धि हुई । इससे उत्पादन भी कम हुआ । सन् १६२१ ई० से स्वदेशी आन्दोलन ने जोर पकड़ा । विदेशी माल के बहिष्कार की नीति ने विदेशों से विशेषकर इंग्लैगड से आने वाले माल में काफी कमी कर दी । इन अतिकृत्ल परिस्थितियों से भारत को एक

लाभ त्रवश्य हुत्रा कि देश में बड़े-बड़े उच्छोगों का श्रीगरोश हो गया। युद्ध काल से ही भारतीय उद्योगपितयों तथा सरकार का ध्यान कुछ त्रंश में देश में बड़े-बड़े उद्योगों की उन्नति की स्रोर गया।

युद्ध के समाप्त होने पर्निर्यात न्यापार में तो उपरोक्त कारणों से कमी हुई परन्तु आयात न्यापार में वृद्धि होने लगी । युद्ध के कारण रुका हुआ आयात प्रारम्भ हो गया । रुपये की विदेशी दर बढ़ जाने से विदेशी माल भारत में सरता पड़ने लगा जिससे आयात की मात्रा बढ़ गई और इसी कास्ण सन् १६२१ ई० में भारत का निर्यात आयात से ५० करोड़ रु० के लगभग अधिक हुआ । परन्तु यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही और १६२६ ई० तक स्थिति में काफी सुधार हो गया।

इस काल की व्यापारिक विशेषताएँ निम्नांकित थीं-

देश में सुती कपड़े की मिलों के विस्तार के कारण तथा स्वदेशी स्रान्दोलन के कारण विदेशी सूती कपड़े के आयात में काफी कमी हो गई, परन्तु रसायनिक पदार्थों का आयात बढ़ गया। इसी प्रकार विदेशों से मिट्टी के तेल का आयात भी काफी बढ़ गया, क्योंकि इसका प्रयोग जनता के द्वारा अधिक होने लगा और साथ ही साथ मोटर यातायात के विकास ने इसकी माँग ऋौर बढ़ा दी। विदेशों से चावल मँगाया जाने लगा । यहाँ से निर्यात किए हुए माल में निर्मित माल की मात्रा ऋधिक तथा आयात में इसकी मात्रा कम होने लगी। इसी काल में भारतीय व्यापार में इंग्लैंग्ड की प्रचुरता का कम होना प्रारम्भ हो गया श्रीर उसके स्थान पर विश्व के श्रन्य देशों के साथ भारतीय आयात व निर्यात धीरे-धीरे श्रिधिक होने लगे। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् लगभग १० वर्ष तक अग्रार्थिक उत्कर्ष का दौरदौरा रहा । इसके बाद सन् १९३९ ई॰ से विश्वन्यापी ऋार्थिक ऋपकर्ष प्रारम्भ हुआ । उद्योग व न्यापार में शिथिलता स्राने लगी। प्रत्येक देश स्रपनी स्रार्थिक व्यवस्था की रचा के लिए विदेशी व्यापार पर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने लगा । इसके फलस्वरूप विदेशी बाजार की महत्ता सब देशों में घटने लगी। इस अपकर्ष काल में निर्मित वस्तु श्रों के मूल्य की ऋषेचा कृषि पदार्थों के मूल्य में ऋषिक गिरावट हुई। भारत के निर्यात में कृषि पदार्थों की ही प्रमुखता थी। इसलिए भारतीय निर्यात का मूल्य बहुत कम हो गया। सन् १६३१ ई० में इंग्लैएड ने स्वर्ण पद्धति का त्याग किया । इसके फलस्वरूप सोने की कीमत अधिक बढ़ गई ख्रौर बहुत सा सोना भारत से बाहर जाने लगा। सन् १६३३ ई.० में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी स्वर्णमान पद्धित को त्याग दिया। इसका प्रभाव भी भारत के व्यापार पर बुरा ही पड़ा। मार्थिक म्रव्यवस्था से बचाने के लिए तथा विदेशीय व्यापार की उन्नति के लिए. मुख्य-मुख्य देश एक दूसरे से व्यापारिक संघियाँ करने लगे ।, पराधीन होने के कारगाः ्र भारतवर्षे इन संबियों से भी कोई विशेष लाम प्राप्त न कर सका ।

सन् १६३३ ई० के परचात् भारत के व्यापार में कुछ प्रगित प्रारंभ हुई। निर्यात में बृद्धि होने लगी, आयात कम होने लगा क्यों कि इस समय तक अपकर्ष की प्रगित समाप्त हो चुकी थी। इसको रोकने की विभिन्न योजनाएँ अपनी सफलता दिखलाने लगीं। इसर दितीय युद्ध की आशंका भी धीरे-धीरे बढ़ने लगी और युद्ध भय के कारण शस्त्रों पर अधिक व्यय होने लगा। इससे विदेशी व्यापार में भी कुछ उन्नित होने लगी। फिर भी इस काल में भारत का विदेशी व्यापार कम ही रहा। सन् १६२६ ई० में भारत में २६० करोड़ ६० के लगभग आयात हुआ और ३१८ करोड़ ६० का माल बाहर में जा गया। परन्तु १६३४ ई० तक दोनों में काफी कमी हो गई। आयात घट कर १३४ करोड़ ६० के लगभग रह गया। निर्यात को वस्तुओं का मूल्य भी १५५ करोड़ ६० के लगभग हो गया। इस प्रकार जब कि व्यापारिक संतुलन १६२६ ई० में ५६ करोड़ ६० के लगभग भारत के पच्च में था वह १६३४ में केवल २० करोड़ ६० के रह गया।

इस विश्वव्यापी मंदी काल में भारतीय व्यापार में शिथिलता लाने का दायित्व बहुत सी परिस्थितियों पर है। सब से पहिले तो विश्व का ६०% सोना केवल अमेरिका और फान्स के खबानों में था।

विदेशों में विज्ञान तथा यन्त्रों की सहायता से कृषि होने लगी। कृत्रिम पदार्थों का उत्पादन होने लगा जिससे भारतीय माल की खपत विदेशों में कम हो गई । प्रत्येक देश में राष्ट्रीयता की भावनात्र्यों ने श्रौद्योगिक उन्नति करने में पर्याप्त प्रोत्सा- हन दिया श्रौर इस कारण श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में बहुत कमी श्रा गई।

इस काल में भारतीय विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताओं में आयात और निर्यात के मूल्यों में कभी होना तथा अधिकाधिक संरच्या करों का लगाया जाना रहा। विभिन्न देशों में व्यापारिक संधियाँ हुई। भारत से सोने का निर्यात काफी मात्रा में हुआ। इस काल में भारतीय व्यापार में जापान का भाग उत्तरोत्तर बहुता गया। परन्तु अमेरिका का व्यापार कम होता गया। चावल, तिलहन, गेहूँ, काफी, चमड़ा, कच्ची रुई, तैयार सूती माल तथा लाख आदि के निर्यात में धीरे-धीरे बृद्धि होती गई।

सन् १६३५ ई० से लेकर १६३६ ई० तक का काल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के. . लिए उन्नति का काल कहा जा सकता है।

सन् १६३५ से ३६ ई० के भारतीय विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषतात्रों। का संज्ञिप्त वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

प्रारंभ में निर्यात व्यापार कुछ बढ़ा परन्तु इसके पश्चात् कम हो गया । देशः के कच्चे माल का निर्यात तथा विदेशी निर्मित माल का ऋायात दोनों में कमी हुई । कन्ची रुई तथा तिलहन के व्यापार में कभीं हुई परन्तु चाय, जूट और सूती कपड़े के व्यापार में वृद्धि हुई । ब्रिटिश साम्राज्य के देशों से व्यापार की मात्रा घट गई परन्तु जापान और जर्मनी से हमारा व्यापार बढ़ने लगा। व्यापार संतुलन की भारत के पत्त् में अनुकूलता उत्तरोत्तर कम होती गई।

द्वितीय महायुद्ध-काल-प्रत्येक युद्ध युद्ध में संलग्न देश की राजनैतिक तथा ह्यार्थिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन कर देता है। वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक व ऋार्थिक संबंध इतने गहरे हो गए हैं कि कहीं भी युद्ध प्रारंभ क्यों न हो बाय उसका प्रभाव प्रत्यच्च व अप्रत्यच्च रूप से प्रायः सम्पूर्ण देशों पर पड़ता है। सन् १९३६ ई० में ज्यों ही द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुन्ना विभिन्न देशों की ऋपिंक व्यवस्था में एक भटका सा लगा। भारत भी इससे श्रञ्जता न बचा। प्रारंभ में कीमतों में वृद्धि हुई तथा युद्ध सामग्री बनाने के लिए भारतीय कब्चे माल की माँग विदेशों में बढ़ने लगी। इघर भारतीय व्यापारी लाभ पाने के उद्देश्य से विदेशी माल को एकत्र करने लगे जिससे त्रायात की मात्रा में भी वृद्धि होने लगी। प्रथम २ वर्षों तक ये प्रवृत्ति बनी रही, परन्तु बाद में ऋन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी होने लगी। राज्य द्वारा विदेशी व्यापार पर नियंत्रण लगा दिया गया । युद्ध-जनित परिस्थितियौं के कारण जहाजों की कमी और उसके फलस्वरूप किराये की वृद्धि से आयात और निर्यात काफी कम हो गए। ज़र्मनी के द्वारा जहाजों के डुबाए जाने के कारण भी त्र्यायात-निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा । जब इटली से युद्ध छिड़ गया तो भूमध्यसागर भी व्यापार के लिए अयोग्य हो गया। इधर फ्रान्स तथा इंग्लैएड की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। जर्मनी श्रौर रूस से भारत का व्यापारिक संबंध बिल्कल समाप्त हो गया। जापान के युद्ध में भाग लेने पर पूर्वी द्वीप समूहों से भी भारत का व्यापार कम हो गया। ब्रह्मा जापानियों के हाथ में चले जाने से व्यापार में ऋौर भी कमी हो गई । यही नहीं जो देश तटस्थ ये उनके साथ भी हमारा व्यापार कम हो गया । सन् १६४१ ई॰ के बाद आयात और निर्यात् में कुछ वृद्धि हुई। मित्र राष्ट्रों से भारत का न्यापार बढ़ने लगा । इस समय तक मित्र राष्ट्रों की स्थिति शत्रुत्रों की अपेदा कुछ अच्छी हो चली थी। इघर इगलैएड तथा अन्य मित्र राष्ट्र अपने कार-सानों में युद्ध सामग्री बनाने के लिए ऋधिक से ऋधिक भारतीय कच्चे माल को मँगाने लगे। मोज्य पदार्थ तथा तैयार माल की माँग भी बढ़ गई स्रौर साथ ही साथ मध्य पूर्व के देश भी भारतीय माल की माँग करने लगे । इन कारणों से १९४१ के पश्चात् इमारे श्रायात-निर्यात दोनों बढ़ने लगे । परन्तु बाद में श्रायात कम होने लगा आरे १६४४ ई॰ तक ये प्रवृत्ति बनी रही। निर्यात में कुछ वृद्धि अवश्य होर्त रही । सन् १६४४ व ४४ ई० में श्रायात व निर्यात दोनों में वृद्धि हुई । इस स्रांति वर्ष में जहाजों की सुविधा हो जाने के कारण देश में श्रायात की वृद्धि हो चुकी थी। इस काल के भारतीय व्यापार की मुख्य विशेषताएँ निम्नांकित थीं—

देश का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार योक्पीय देशों से युद्ध प्रारंभ होते ही समाप्त हो गया, परन्तु ब्रिटिश कामनवेल्य देशों से निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई यद्यपि इन देशों से आयात कम हुआ। इंगलैगड और भारत के व्यापार में व्यापारिक-संतुलन की अनुकूलता भारत के पच्च में अधिक रही। युद्ध के प्रथम २ वर्षों में भारत और जापान के व्यापार में वृद्धि हुई परन्तु इसके पश्चात् इन दोनों देशों के बीच का व्यापार समाप्त हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के बीच होने वाले व्यापार में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई। मिस्त, फारस व अरब आदि देशों के साथ भारतीय व्यापार बढ़ गया और इन देशों के व्यापार का संतुलन भारत के अनु-कूल रहा।

भारतीय अन्तरिष्ट्रीय व्यापार के संबंध में इस काल की विशेष उल्लेखनीय बात निर्यात व आयात नियंत्रण के बारे में हैं। युद्ध का सकलतापूर्वक संचालन करने के लिए आयात व निर्यात दोनों पर नियंत्रण लगाना आवश्यकीय हो गया जिससे कि शत्रु राष्ट्रों के पास माल न पहुँच जाय तथा अन्य देशों को भी भारतीय माल अधिक मात्रा में न पहुँच जाय। आयात नियंत्रण की आवश्यकता विदेशी विनिमय की दुर्लभता के कारण हुई क्योंकि यदि आयात नियंत्रण न किया जाता तो भारतीय ब्यापारी अनावश्यक वस्तुओं को मँगाकर विदेशी विनिमय उन पर खर्च कर देते, जिससे अनिवार्य वस्तुओं के मँगाने के लिए सरकार के पास विदेशी मुद्रा कम रह जाती। इसलिए विदेशी दुर्लभ मुद्रा का संचय करने के लिए भी आयात के लाइसेन्स देने की ब्यवस्था आरंभ की गई। उपरोक्त व्यापारिक नियंत्रण और बंधन परिस्थितियों के अनुसार अधिक कठोर होते गए और यह कठोरता प्रायः सारे युद्ध काल में बनी रही।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्—युद्ध के पश्चात् भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्या-पार की सबसे मुख्य विशेषता व्यापारिक संतुलन की प्रतिकूलता रही । विदेशों से हमारा आयात बहुत अधिक हो गया और निर्यात कम । अनेक कारणों से इस काल में देश में खाद्यान की बड़ी कमी हो गई, जिसकी पूर्ति विदेशों से खाद्यान मँगाकर करनी पड़ी । युद्ध काल में उपभोक्ता की वस्तुओं का आयात भी बहुत रुका रहा । इन वस्तुओं का आयात भी बढ़ा । जैसे-जैसे इन पदार्थों के आयात से नियंत्रण हटता जाता था उनके आयात की मात्रा बढ़ती जाती थी । विभाजन के कारण जूट आदि जो कच्चा माल देश में ही मिल जाता था वह भी अब बाहर से आयात करना पड़ा । औद्योगिक विकास के लिए मर्शीनों आदि का आयात भी बराबर बढ़ता रहा । इनके अतिरिक्त इंगलैएड की बची हुई सेना-सामग्री भारतीय सरकार ने खरीदी । अँगेजों को पेन्शनों श्रादि का बहुत सा रुपया चुकाया। पाकिस्तान के पौण्ड पावना का हिस्सा मी मारत ने चुकाया। इनसे विदेशी व्यापार का संतुलन हमारे प्रतिकृल श्रिषक होता चला गया। सन् १६४७ ई० में तो व्यापारिक संतुलन इतना श्रिषक हमारे विपन्न में हो गया कि मारतीय सरकार के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। सन् १६४६ ई० की मई के महीने तक तो देश की व्यापारिक स्थिति श्रीर भी चिंताजनक हो गयी। श्रतः श्रायात की नीति में श्रीर कठोरता लानी पड़ी। दुर्लम मुद्रा प्रवेश से श्रायात की स्वीकृति देना स्थिगत कर दिया गया। इसी साल की जुलाई में एक निर्यात वृद्धि समिति नियुक्त की गई जिसने देश के निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ सुकाव सामने रक्खे। उदाहरण के लिए कमेटी ने निर्यात पर लगाये हुए करों को इटाने की कोशिश की। सरकार ने कमेटी की सिकारिशों के श्रनुसार कुछ प्रयत्न किया किर भी संतुलन देश के विपन्न में हो रहा, यद्यपि निर्यात में कुछ थोड़ा सुधार हुश्रा। इपये का श्रवमूल्यन भी किया गया। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप १६५० ई० में ब्यापार संतुलन कुछ श्रंश तक देश के पन्न में रहा।

भारत के विभाजन के पश्चात् फरवरी सन् १६४८ ई॰ तक भारत श्रौर पा-किस्तान के व्यापार के ऊपर किसी प्रकार का कर नहीं था । मार्च सन् १९४९ ई० से त्र्यायात व निर्यात कर के संबंध में पाकिस्तान की स्थिति एक विदेश के समान हो गई | देश का आयात निर्यात-नियंत्रण कानून पाकिस्तान पर भी लागू किया गया। पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल में ४० चंगीवर खोले गए जिन पर एक देश से दूसरे देश को त्राने-जाने वाली व्यापारिक वस्तुत्रों पर त्रावश्यक कर लिया जाने लगा। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ व्यापार कमिश्नरों की नियुक्ति करने का निश्चय किया । २ अप्रैल सन् १६४८ ई० को पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक नीति की घोषणा की । और २६ मई सन् १९४९ को भारत श्रीर पाकिस्तान के मध्य एक श्रस्थाई व्यापारिक समभौता हुआ। इसमें यह निश्चय किया गया कि दोनों देश एक दूसरे को जीवनोपयोगी श्रावश्यकतात्रों की पूर्ति में त्रावश्यक सहयोग देंगे । इस समभौते के श्रन्तर्गत भारत ने पाकिस्तान को सूत, कपड़ा शक्कर, मशीनें, इस्पात, लोहा, कोयला, टायर, ट्यूब, लकड़ी, जूट का बना सामान, दवायें ब्रादि वस्तुएँ देता रहेगा श्रौर पाकिस्तान भारत को कच्चा जूट, कच्ची रुई तथा लाहौरी नमक देगा । बहुत सी वस्तुओं के लिए दोनों देशों द्वारा मात्राएँ निर्धारित कर दी गई। सितम्बर १६-· ४६ ई॰ में मारतीय मुद्रा का अवमूल्यन होने से भारत व पाकिस्तान के बीच का व्यापार प्रायः समाप्त ही हो गया। अतः श्रप्रैल सन् १९५० ई॰ में दोनों देशों के बीच में एक दूसरा समभौता हुआ। इस समभौता, में यह तय किया गया कि दोनों देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थित रूप से भारतीय सिक्के में होना चाहिए त्रौर इसके लिए पाकिस्तान के स्टेट बैंक को अलग से हिसाब रखना चाहिए । दोनों

देशों को ठीक प्रकार से यातायात का प्रवन्ध करना चाहिए। इस समभौते के अन्त-र्श्यत पाकिस्तान ने भारतवर्ष को ४० लाख मन जूट तथा १॥ लाख मन गेहूँ देने का निश्चय किया श्रीर भारत ने पाकिस्तान को २० इजार टर्न जूट का निर्मित माल भेजने का वादा किया। इसके ऋतिरिक्त भारत ने सूती-ऊनी कपड़े, सरसों का तेल, तम्त्राकु, लोहे का बना सामान तथा इमारती लकड़ी आदि पाकिस्तान को देने के लिए वचन दिया। इस समभौते में यह भी निश्चित किया गया कि फल, मेवे, दूध, मळ्ली, ऋरडे, साबुन, सुपाड़ी, खालें व चमड़ा ऋादि वस्तुऋों पर ऋायात-दियदि के लाइसेन्स का कोई प्रतिबन्ध न रहेगा । फरवरी सन् १६५१ में दोनों देशों के बीच प्क नया समभौता हुन्रा। इस समभौते में भारत व पाकिस्तान की मुद्रान्त्रों का ऋनु-पातिक मूल्य तय कर दिया गया । खरीद के लिए भारत के १००) की दर पाकिस्तानी ६८॥)। स्रौर फरोख्त के लिए ६६=॥। निश्चित की गई। इस सममौते के स्राधार पर प्क निश्चित अवधि के अन्दर पाकिस्तान ने भारत को चावल और गेहूँ देने की मात्रा निश्चित की । इसी प्रकार पाकिस्तानी रुई के लिये भी मात्रा निर्घारित की गई । कुछ श्रन्य वस्तुत्रों के बदले में भारत ने पाकिस्तान को कोयला देने का वचन दिया । साधारण वस्तुत्रों के लिये विशेषकर सीमावर्ती व्यापार के ब्रान्तर्गत ब्राई हुई वस्तुत्रों के लिए किसी प्रकार के लाइसेन्स की त्रावश्यकता नहीं रक्खी गई। इन दोनों देशों के बीच में तीसरा व्यापारिक समभौता जून सन् १६५२ में हुन्रा। इस सनभौते में, समभौते की अवधि आयात-निर्यात के लिए समय-समय पर लाइसेन्स दिए जाने के लिए निश्चय किया गया। श्रीर यह भी निश्चय किया गया कि इस संबंध पर दोनों सरकारों द्वारा त्रावश्यकतानुसार परस्पर परामर्श होता रहेगा । सम-भीते में २ अनुसूचियाँ बनाई गई। पहिली अनुसूची क में उन २६ वस्तुओं का समावेश किया गया जो भारत द्वारा पाकिस्तान भेजी जाने वाली थीं श्रौर सूची ख में उन ११ वस्तुत्रों का वर्णन है जो पाकिस्तान भारत को भेजेगा। वस्तुएँ प्रायः वे ही हैं जिनका उल्लेख पिछले समभौतों में किया जा चुका है। इन स्चियों में वस्तुस्रों के नाम के त्रातिरिक्त उनका परिमाण तथा मूल्य भी निश्चित कर लिया गया था। विशेष रूप से इस समभौते में यह निश्चय किया गया कि स्रावश्यकता पड़ने पर पाकिस्तान भारत को २५ लाख गाँठों तक जूट देगा तथा भारत से पाकिस्तान कोयले के निर्यात के लिए सरकार उपयुक्त सुविधाएँ देगी और पश्चिमी पाकिस्तान को रेल द्वारा कोयला भेजने में वृद्धि की जायगी तथा भारत व पाकिस्तान के पड़ोसी जिलों में होने वाले व्यापार को विशेष दुविधाएँ दी जावेंगी।

इसके पश्चात् जुलाई १६५३ में ३ साल के लिए दोनों देशों के बीच एक समभौता आरे हुआ। इसमें वस्तुओं की मात्रा, उनका मूल्य तथा आवश्यक व्यापारिक सुविधाओं के देने के बारे में निश्चय किया गया। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं, फिर भी भारत श्रौर पाकिस्तान के बीच व्यापार में इतनी उन्नित नहीं हुई जितनी होनी चाहिये थी। इसका मुख्य कारण राजनैतिक सद्भावना की कभी ही समक्का जाता है। कुछ लोगों का विचार है कि पाकिस्तान भारत से श्रच्छे व्यापारिक संबंध बनाये रखने का इच्छुक नहीं है। इन लोगों के मतानुसार, इसी कारण से पाकिस्तान ने भारत की श्रपेक्ष जापान व फ्रान्स को श्रिषक व्यापारिक सुविधाएँ दी हैं।

जनवरी सन् १६५७ ई० में भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया सम-भौता किया गया। इस समभौते में भारत से कोयला, सीमेन्ट तथा जूट का सामान लेने की उत्सुकता दिखाई गई है। और भारत ने पाकिस्तान को अधिक विशेष सुवि-धाएँ देने में असमर्थता प्रकट की है, क्योंकि द्वितीय पंचवधींय योजना में भारत को स्वयं बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समभौते को पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित बनाने के लिए ३ विशेष समितियाँ बनाई गई थीं। पहिली सिनित का कार्य नए समभौते की रूपरेखा बनाना था। दूसरी समिति को वस्तुओं की सूची बनाने का कार्य सौंपा गया। तथा तीसरी समिति सीमान्त व्यापार की रूपरेखा पर प्रथक विचार करने के लिए बनाई गई। यह समभौता भी आगामी तीन वर्ष तक के लिए किया गया है। और इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहेंगे।

सन् १६५५ में पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन होते ही भारत-पाकिस्तान के व्यापार में कुछ परिवर्त्तन हो गया। अब पाकिस्तानी वस्तुयें भारत में सस्ती पड़ने लगीं और भारतीय वस्तुयें पाकिस्तान में मँहगी। पाकिस्तान भारत से विशेषकर कोयला लेता है और भारत-पाकिस्तान से जुट तथा रहें। यदि किसी प्रकार की बाधान डालों जाती तो भारत को लाभ रहता। कोयला अनिवार्य होने के कारण पाकिस्तान में कोयले की माँग कम न होती। तथा भारतीय मिलों के लिये भारत को कच्चा जूट तथा रहें सस्ती मिलती पर पाकिस्तान तथा भारत के व्यापारिक सम्बन्ध दोनों के राजनैतिक वातावरण पर आधारित हैं। इसलिये। पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन का मारत-पाकिस्तानी व्यापार पर वास्तिवक प्रभाव का अनुमान करना किन है। हाँ पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन के कारण विदेशों में भारत को पाकिस्तान से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, क्योंकि अवमूल्यन के फलस्वरूप पाकिस्तानी वस्तुयें विदेशों में सस्ती हो गई, भारतीय वस्तुयें मँहगी। यह प्रतिस्पर्धा जूट के बने हुये माल में अधिक हो गई। इसीलिये अवमूल्यन के पश्चात् भारत को जूट पर निर्यात कर समाप्त करना पड़ा।

पंचवर्षीय योजना के निर्मातात्रों ने भारत के विदेशी व्यापार की छाब तक की प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में व्यापार नीति निश्चित करने के लिये निम्नांकित ५ नियमों का संकेत किया है—

- १--योजना के अन्तर्गत उत्पादन तथा उपयोगों के लच्यों की पूर्ति
- २--- निर्यात में श्रधिक से श्रधिक वृद्धि
- ३ पर्याप्त विदेशी मुद्रास्त्रों की प्राप्ति
- ४— त्रायात त्रौर निर्यात का सरकारी मूल्य तथा कर त्रादि नीतियों से सामंजस्य

५-निश्चित व्यापारिक नीति का निर्धारण

योजना के निर्माताओं को यह आशा थी कि योजना काल में जूट तथा कपास आदि कृषि पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि होगी। इसी प्रकार सूती वस्त्र, जूट का निर्मित सामान, तेल, कोयला, मसाले आदि का उत्पादन मी अधिक बढ़ जायगा। इससे देश का निर्यात बढ़ेगा और देश को काफी परिमाण में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी। यहीं नहीं विजली के सामान, अन्य मशीनरी तथा साइकिल व रसायन संबंधी उद्योगों के विकास के कारण हमारे देश से नवीन वस्तुओं का निर्यात भी होने लगेगा। इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की व्यापारिक संधियों के कारण हमारा निर्यात और भी अधिक हो जायगा।

योजना सिमिति ने यह अनुमान लगाया था कि सन् १६५५-५६ ई० तक निर्यात में १०% तथा आयात में १८% की वृद्धि होगी और ११३ करोड़ ६० के मूल्य की अधिक विदेशी मुद्रायें प्राप्त होंगी परन्तु साथ ही साथ अधिक आयात होने के कारण १०८ करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्राओं की कमी होगी। इस प्रकार कुल मिलाकर भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति में प्रथम योजना काल के अंत तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी यही अनुमान लगुद्धा गया है। इस योजना के अन्त तक भारतीय निर्यात में विशेष वृद्धि की आशा नहीं है। भारत-वर्ष मुख्यकर चाय, जूट का सामान तथा सूती वस्त्र का निर्यात करता है। परन्त इन वस्तुओं को विदेशी बाजारों में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिये विदेशी बाजारों का अधिक विस्तार सम्भव नहीं। फिर भी अधिक से अधिक विदेशी व्यापारों को प्राप्त करने के लिये अकथ प्रयत्न करना पड़ेगा और साथ ही साथ द्वितीय योजना के कार्यक्रमानुसार औद्योगिक विकास होने से हमें अपने आयात में भी यथासम्भव काफी कभी करनी पड़ेगी, फिर भी व्यापार का संतुलन देश के विपन्न में ही रहेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समिति के अनुमान से आगामी ५ वर्षों में अर्थात् १६५६-५७ से लेकर सन् १६६०-६१ ई० तक भारतीय विदेशी व्यापार का संतुलन १३७५ करोड़ रुपयों से देश के पन्न में हो जायगा। इसमें से यदि पौन्ड पावने आदि की रकम को निकाल दिया जाय तो भी ६०० करोड़ रुपयों के मूल्य के बराबर विदेशी सुद्राओं की कभी रहेगी। इस प्रकार द्वितीय योजना काल के

त्रंत तक देश के विदेशी व्यापार की स्थिति में कोई विशेष सुधार होने की आशा नहीं है।

पिछले दो वर्षों के व्यापारशेष को देखते हुए यह पता लगता है कि देश में विदेशी विनिमय की कमी है। सन् १६५७-५८ में प्रथम छुमाही के त्रायात की कीमत ६२२ करोड़ रुपए हो गई जब कि संपूर्ण वर्ष का त्रमुमान केवल ८८६ करोड़ रुपए था। दूसरी योजना काल घाटे में त्रीर ऋधिक वृद्धि हुई हैं। सन् १६५८ के ऋतिम छः माहों में स्थिति में कुछ अंतर पड़ा है। निर्यातों को प्रोत्साहन, आयातों पर प्रतिवन्ध तथा विदेशी सहायता वर्त्तमान विनिमय संकट को कुछ हद तक सरल करने में सहायक हुए हैं।

आयात एवं निर्यात नीति तथा नियंत्रण

युद्ध काल में प्रत्येक भौतिक साधन का उपयोग सब से पहले युद्ध के लिए हीं किया जाता है, जिससे युद्ध में सफलता प्राप्त हो । यह तभी हो सकता है जब इन साधनों पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण रहे । इसी दृष्टि से आयात व निर्यात पर भी सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। स्रायात नियंत्रण द्वारा स्ननावश्यक वस्तुत्रों का त्रायात रोक दिया जाता है, केवल त्राति त्रावश्यक तथा युद्ध सम्बन्धी -सामग्री का त्रायात ही होता रहता है, इससे एक तो देश को विदेशों का ऋधिक सहारा नहीं लेना पड़ता, दूसरे विदेशी मुद्रा की ऋावश्यकता कम रहती है, क्योंकि निर्यात में कमी होने के कारण देश के पास विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है बिसका उपयोग सरकार को बड़ी भितव्ययता के साथ करना पड़ता है। इसी प्रकार निर्यात नियंत्रण द्वारा देश की वस्तुएँ अपरिमित मात्रा में बाहर नहीं जाने पातीं। बो वस्त देश अथवा युद्ध के लिए आवश्यक है और उसकी पूर्ति सीमित है तो ऐसी ·वस्तु का निर्यात रोक दिया जाता है। कुछ वस्तुत्रों का निर्यात सीमित कर दिया जाता है, कुछ देशों को निर्यात पर रोक लगा दी जाती है, जिससे शत्रु देशों के पास अत्यन्न व अप्रत्यन्न रूप से ऐसी वस्तुएँ न पहुँच जायें, जिनका प्रयोग शत्रु लोग देश के विरुद्ध युद्ध में करने लगें । निर्यातकर्ता प्राप्त विदेशी मुद्रा को मनमाने ढंग से काम में नहीं ला सकते,प्रायः सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा पर सरकार का ऋधिकार होता है। सर-कार उसे जिस प्रकार चाहे काम में ला सकती है।

उपरोक्त उद्देश्यों को सामने रखते हुए युद्ध काल में भारतीय सरकार ने आयात व निर्यात पर नियंत्रण लगाए। जहाँ तक आयात नियंत्रण का सम्बन्ध है कुछ वस्तुओं के लिए खुले तौर पर लाइसेन्स दिये गये, कुछ वस्तुओं के लिए कोटा नियत किया गया। कुछ वस्तुओं के आयात लाइसेन्स देने में उदारता की नीति अपनाई गई। आयात नीति सदैव के लिए एक सी नहीं रही, उसमें समयानुमार

परिवर्तन होता रहा । आयात सम्बन्धी लाइसेन्स देने के लिए दिल्ली में एक मुख्य आयात नियंत्रक की नियुक्ति की गई और उसके नीचे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कोचीन, नई दिल्ली, पांडिचेरी, राजकोट में आयात निर्यात-नियंत्रकों की नियुक्ति की गई। लाइसेन्स प्रदान करने के लिए विश्व के देशों को दो भागों में बाँटा गया। अथम डालर अथवा दुर्लम मुद्रा वाले देश, द्वितीय सुलम मुद्रा वाले देश।

श्रायात कर्ताश्रों को चार भागों में बाँटा गया: (१) स्थायी श्रायात कर्ता, (२) चास्तिक उपभोक्ता, (३) नवागंतुक, (४) श्रान्य। लाइसेन्स की श्रवधि ६ माह से लेकर डेंद्र वर्ष तक की होती हैं। प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में सरकार श्रपनी श्रायात नीति को घोषित करती है श्रौर उसी के श्रानुसार लाइसेन्स दिये जाते हैं। ये लाइसेन्स प्राय: ४ प्रकार के होते हैं—१—िकसी विदेश में उपभोग के लिए श्रावश्यक वस्तुर्श्रों के लिए।

२ - डालर च्रेत्र को मिर्च व मसाला भेजने के लिए।

३ - उन ५२ वस्तुओं के लिए जो देश के लिए त्राति त्रावश्यक हैं।

४-पाकिस्तान भेजी जाने वाली वस्तुत्रों के लिए।

Q. 1. Explain fully how India's foreign trade is at presen controlled and regulated.

How should it be developed ?

(A. U. 1954)

प्र०१—भारतीय विदेशी व्यापार के सम्बन्ध वर्तमान नियंत्रण प्रणाली को भाति समकाइये। विदेशी व्यापार का विकास किस प्रकार हो सकता है ?

केन्द्रीय सरकार ने श्रायात व निर्यात के नियंत्रण के लिए, यथोचित सलाह पाने के लिए श्रायात सलाहकार समिति व निर्यात सलाहकार समिति नियुक्त की हैं। फिर भी सरकारी नीति की कभी-कभी श्रालोचना होती रहती है। श्रालोचना से प्रभावित होकर सरकार ने १६५० ई० में श्रायात नीति पर विचार करने के लिए श्रायात नियंत्रण जाँच समिति नियुक्त की। इस समिति ने श्रायात संबंधी नीति व संचालन में स्थिरता, शीव्रता तथा चमता के गुणों का होना श्रावश्यकीय बतलाया। समिति ने श्रायात की मात्रा, श्रायात की वस्तुश्रों में प्राथमिकता श्रादि के बारे में भी सुमाव दिए। इसके श्रातिरक्त लाइसेन्स के समय को बढ़ाना, लाइसेन्स प्रणाली का विकेन्द्रीकरण करना, नवीन श्रायात कर्ताश्रों को सुविधा देना, सुलभ मुद्रा चेत्र से माल मँगाने की श्रधिक स्वतंत्रता देना श्रादि श्रावश्यक सुधार करने के लिए भी सुमाव दिए। भारतीय सरकार ने समिति के बहुत से सुमाव मान लिए। ४०० करोड़ रु० की वार्षिक श्रायात की सीमा निर्धारित की गई। प्राथमिकता के श्राधार पर श्रायात की जाने वाली वस्तुश्रों को ४ श्रीण्यों में बाँटा गया है: १. श्रावश्यक

कच्चा माल, उद्योगधन्धों स्रादि के लिए स्रानिवार्य पूजी पदार्थ, मशीनों के भाग तथा जनता के स्वास्थ्य व जीवन के लिए स्रावश्यक वस्तुएँ।

- २. ग्रन्य कच्चा माल ग्रौर पूँजी पदार्थ ।
- ३. ऋति ऋावश्यक पदार्थ ।
- ४. कम आवश्यक पदार्थ ।

स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् भारतीय सरकार का देश के आर्थिक विकास की ओर काफी ध्यान गया। आर्थिक विकास औद्योगिक विकास पर निर्मर होता है। श्रोद्योगिक विकास के लिये प्रारंभ में श्रायात पर नियंत्रण होना चाहिए। श्रीर बाद को इसे पूर्ण सफल बनाने के लिए निर्यात में काफी वृद्धि होनी चाहिए। वास्तव में वर्तमान व्यापारिक युग में श्रोद्योगिक विकास के लिए विश्वव्यापी विस्तृत व्यापार का होना श्राति श्रावश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने देश के निर्यात व्यापार में वृद्धि करने के लिए श्रानेक प्रयत्न किए। कुछ महत्वपूर्ण प्रयत्नों का विवरण निम्नांकित है—

- र-विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए मराडल मेजे गए।
- २ निर्यात की मात्रा में वृद्धि के लिए निर्यात वृद्धि परिषदों की स्थापना की गई।
- ३—वस्तुत्रों की किस्म तथा गुण को उच्च स्तर पर रखने के लिए प्रयत्न किया गया।
 - ४- विभिन्न प्रदर्शनियों में भारतीय वस्तुत्र्यों का प्रदर्शन किया गया।
- ५—विभिन्न वस्तुत्र्यों की बिक्री में वृद्धि के लिए व्यापारिक केन्द्रों की स्था-पना की गई।
- ६ ब्यापारिक नियमों को सुब्यवस्थित तथा जहाजरानी के भाड़े को कम-से-कम करने का प्रयत्न किया गया।
 - ७ -- निर्यात माल की गारन्टी देने की योजना पर विचार किया गया।

जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि के लिए विभिन्न देशों से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रश्न है केन्द्रीय सरकार ने ब्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल मेजे। इन प्रतिनिधि मण्डलों का कार्य देश की वस्तुओं का विभिन्न देशों में विज्ञापन कराना तथा उन का निर्यात बढ़ाना रहा है। इस प्रकार के प्रतिनिधि मण्डल रूस, पौलेण्ड, पूर्वी एशिया आदि देशों को मेजे गए। इस प्रयत्न के फलस्वरूप चीन के साथ भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुन बढ़ गया। इन्बे प्रकार एक प्रतिनिधि मण्डल पश्चिमी एशिया के देशों को मेजा गया जिसकी सफलता भी अच्छी रही।

चाय के निर्यात की दृद्धि के लिए एक विशेष समिति की स्थापना की गई। देशहरु के लिए इस समिति ने अमेरिका में चाय दृद्धि परिष्दें स्थापित की। ये

परिषदें चाय व्यापारियों तथा अन्य चाय उत्पादक देशों एवं लंका और इराडोनेशिया के सहयोग से चाय का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयतन करती हैं। श्रमेरिका स्थित चाय परिपद रेडियों तथा टेलीविजन पर प्रचार का कार्य कर रही है। इसी प्रकार भारतीय दूत मित्र संघ विदेशों, विशेषकर स्रमेरिका ब्रिटेन. स्रास्ट्रे-लिया और न्यू बीलैंड में भारतीय जूट के माल की खपत बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। यह प्रचार स्नान्दोलन विज्ञापन प्रदर्शिनियों तथा वायरलैस व टेलीविज़न वार्तास्रों द्वारा किया जाता है। पोस्टर्स तथा सिनेमात्रों की भी मदद ली जाती है। दुरीर उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुत्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए भी केन्द्रीय सरकार ने समितियों की स्थापना की है। उदाहरण के लिए श्राखिल भारतीय हाथ इरघा बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड ने विदेश में निर्यात बढ़ाने ,की एक योजना बनाई। इस योजना के अन्तर्गत बगदाद, रंगून, सिंगापुर तथा कोलम्बो में हाथ करघा बिकी व्यवस्था ब्राफीसर्स नियुक्त किए गए हैं। तथा कराँची, चटगाँव, रंगून, सिंगापुर, कोलम्बो ग्रौर ग्रदन ग्रादि में विकी केन्द्र खोले गए हैं। इसी प्रकार ग्राखिल भार-तीय दस्तकारी बोर्ड ने भारतीय दस्तकारी की वस्तुएँ विदेशी बाजारों को ऋषिक मात्रा में निर्यात करने की ऋोर काफी प्रयत्न किए हैं। भारतीय दस्तकारी की वस्तुऋों में तथा उनकी बिक्री व्यवस्था में ज़ो दोष हैं; उनको दूर करने के बरावर प्रयत्न किए जा रहे हैं। लघु उद्योगों के द्वारा उत्पादित वस्तुत्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए शैल्मिक शालाएँ स्थापित की गई हैं। एक कारपोरेशन भी बना है जो बड़े पैमाने पर माल के आर्डर लेगा, जिनको वह लघु उद्योगों में बाँट देगा और इस समय यह कारपोरेशन चमड़े के माल विशेषकर जूतों स्रोर बूटों का आर्डर विदेशों से प्राप्त कर रहा है।

कुछ वस्तुश्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन परिपरों की स्था-पना की गए हैं। श्रव तक सूती कपड़ा, रेशमी वस्न, नकली रेशम तथा रेयन के वस्न, इंजीनियरिंग व प्लास्टिक का सामान, काजू तथा काली मिर्च के लिए निर्यात संवधन परिषदें बन चुकी हैं। तथा कुछ श्रीर वस्तुश्रों के लिए परिपरें शीव ही बनाई जायेगी। यह परिषदें विभिन्न विदेशी बाजारों के बारे में श्रावश्यक विवस्ण प्राप्त करती हैं जिनसे यह ज्ञात हो सके कि किन देशों में कौन सी वस्तुश्रों की खपत हो सकती हैं। विदेशों को व्यापारिक प्रतिनिधि मएडल भेजे जाते हैं। विदेशी बाजारों में विभिन्न प्रकार से प्रचार किया जाता हैं, विशेषकर भारतीय वस्तुश्रों की उपयोगिता का विज्ञापन विदेशी बाजारों में इन परिषदों के द्वारा बड़ी संफलतापूर्वक हो रहा हैं। ये परिपरें निर्यात होने वाले माल के लिए किस्म तथा पैकिंग संबंधी प्रतिमान निर्धारित करती हैं। उनके निरीच्या की व्यवस्था करती हैं श्रीर निर्यात के संबंध में विदेश श्रायातकों, भारतीय निर्यातकों तथा भारत से निर्यात की गई वस्तुस्रों के बारे में स्राई हुए शिका-यतों की पूछ व जाँच-पड़ताल करती हैं।

निर्यात की वस्तुत्रों का प्रतिमान निर्धारण व गुण नियत्रण का कार्य भारतीय प्रतिमानशाला द्वारा किया जाता है। सूती कपड़ों पर एक व्यापार के प्रमाण का ठप्पा लगा दिया जाता है। निरीच्चक लोग कुछ वस्त्रों का निरीच्चण करके यदि वस्त्र निरीच्चक को कसौटी में पूरा उतरता है तो उस पर मुहर लगा दी जाती है। यह मुहर इस बात का प्रमाण है कि कपड़ा श्रेष्ठ है। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। इस योजना से विदेशों में भारतीय वस्त्र की साख बढ़ने की समावना है। इस समय ये निरीच्चक बम्बई व त्राहमदाबाद में नियुक्त किए गए हैं। कुछ वस्तुत्रों का प्रतिमान एगमाक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। खासकर पटसन, तम्बाकू श्रीर कच्ची ऊन वही बाहर भेजे जाते हैं जिन्हें एगमाक प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया हो।

निर्यात की मात्रा में बढ़ाने के लिए उत्पादकों को उन वस्तुत्रों में प्रयोग होने वाले कच्चे माल को विदेशों से प्राप्त करने के लिए यथोचित सुविधाएँ दी जाती हैं जिससे उत्पादकों को कच्चा माल ब्रासानी से मिल सके। इस प्रकार के कच्चे माल पर लगे हुए ब्रायात शुल्क में छूट देना प्रारंभ कर दिया गया है जिससे भार-तीय उत्पादकों को कच्चा माल सस्ता पड़े जिससे वे ब्रापने निर्मित माल को विदेशी बाजारों में ब्रान्य देशों से प्रतिस्पर्की होने पर भी सरलता से बेंच सके।

इसी प्रकार प्रदर्शिनियों तथा मेलों में भाग लेकर देश में निर्मित वस्तुश्रों के निर्यात की मात्रा को बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रदर्शनियों व मेलों में भारत श्रिधकाधिक भाग ले रहा है। उदाहरण के लिए सन् १९५४ ई० में काहिरा की प्रदर्शिनी में श्रिधकाधिक भारतीय वस्तुश्रों का प्रदर्शन किया गया था। इसके श्रितिरक्त बहुत से देशों में भारतीय दूतावासों से सबंधित प्रदर्शन केन्द्र खोल दिए गए हैं जहाँ भारतीय वस्तुश्रों का प्रदर्शन तथा उनके बारे में व्यापारिक ज्ञातव्य बातों का प्रचार किया जाता है। इस समय ऐसे मुख्य केन्द्र निम्नांकित स्थानों पर है—

कोलम्बो, बैंकाक, न्यूयार्क, लंदन. ब्रूसेल्स, रोम, सिकन्दरिया, टोकियो, बकार्ता, काबुल, ढाका, बर्लिन, हैम्बर्ग, जिनेवा, पेरिस इत्यादि।

उपरोक्त व्यापारिक केन्द्रों में न्यूयार्क, हैम्बर्ग तथा जिनेवा के व्यापारिक केन्द्रों में अच्छा कार्य हो रहा है। न्यूयार्क के व्यापारिक केन्द्र में वस्तुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त उन वस्तुओं के निर्माताओं, मूल्यों, निर्यातकर्ताओं तथा अन्य बातों के विषय में भी जानकारी पूर्ण रूप से ली जाती है। यह केन्द्र समय-समय पर परीच्रण के तौर पर नया भारतीय माल प्रदर्शित किया करेगा जिससे उसकी माँग बढ़ सके।

इसी प्रकार के व्यापारिक केन्द्र हैम्बर्ग ऋौर जिनेवा में भी स्थापित किए गए हैं। इन व्यापारिक केन्द्रों को कारपोरेशन का रूप देने की योजना बनाई जा रही है।

भारतीय निर्यात में सबसे श्रिधिक बाधा बहाजी भाड़े की पच्चपातपूर्ण दरें रही हैं। कुछ जहाजी कम्पनियाँ भारतीय वस्तुश्रों से श्रिधिक भाड़ा लेती हैं जिससे भारतीय माल को श्रिसमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इस दोष को दूर करने के लिए एक विशेष राज्य कर्मचारी नियुक्त किया गया है जो स्विस्तार इस समस्या का श्रध्ययन करेगा श्रौर संबंधित देशों की सरकारों से लिखा-पड़ी करके दरों में बरती जाने वाली पच्चातपूर्ण नीति को दूर करने का प्रयत्न करेगा। इसी प्रकार निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिए भारतीय माल की साख की गारंटी देने तथा उनके मूल्यों में स्थिरता लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप निकट भविष्य में भारतीय निर्यात में काफी वृद्धि होने की श्राशा है।

प्रश्न

- 9. संसार की वर्तनान व्यापारिक दशा में स्वतन्त्र व्यापार के पत्त में तक पूर्ण सुनाव दीजिए। (आगरा बी. ए. १६७६)
- ' २. कुछ ऐसे व्यापारिक उपाय बताइए कि जिनसे भारतीय स्तो कपड़े तथा चीनो का निर्यात बढ़ाया जा सके। (श्रागरा बी. ए. १६५६)
- 3. If international trade is based on the principle of territorial division of labour it should be complementary. How do you explain the competitive character of international trade?

 (Agra B. A. 1959)

अध्याय १४

संरच्या एवं भारत में संरच्या नोति

(Protection and Protection Policy in India) मुक्त ज्यापार तथा संरत्नगा

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के, उसमें अवरोध लगाने की दृष्टि से २ प्रकार होते प्रथम स्वतंत्र अथवा मुक्त व्यापार, द्वितीय, संरच्चित व्यापार अथवा संरच्चण वतंत्र ज्यापार में देश के अन्दर आने वाली अथवा उस देश से बाहर जाने वाली ातु स्रों पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं लगाई जाती। उसके फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच में व्यापार की जो स्वामाविक गति या प्रवाह होता है उसमें किसी प्रकार की ग्रस्वाभाविक बाधाएँ बन्धन या रुकावटें नहीं डाली जातीं। इसमें ग्रन्तर्रा ष्ट्रीय विनिमय की स्वतंत्रता रहती हैं । इस नीति के स्नन्तर्गत विभिन्न देशों के चीच वस्तुर्श्नों के त्रायात निर्यात में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती त्रौर विनिमय अपनी स्वामाविक गति से चलता है। फलतः मुक्त व्यापार की नीति के अन्तर्गत प्रायः त्र्यायात निर्यात कर नहीं लगाये जाते । परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह क किसी दशा में भी न लगाये जाते हों। यदि स्रायात-निर्यात कर केवल राष्ट्रीय स्राय के लिए लगाये जायँ तो भी ब्यापार मुक्त ब्यापार ही कहलाता है। परन्तु <u>जब</u>यह कर विदेशी स्पर्कों से ऋपनी वस्तुःश्रों को बचाने के लिए लगाये जाते हैं तो मुक्त न्यापार समाप्त हो जाता है और उस समय देश की न्यापारिक नीति संस्त्रण कं नीति हो जाती है। एडम स्मिथ के शब्दों में, मुक्त व्यापार का तात्पर्य उस अवस्थ से हैं जब विदेशी तथा स्वदेशी वस्तुत्रों में कुछ ग्रन्तर नहीं किया जाता, न विदेशी वस्तुत्रों पर कोई कर भार लादा जाता है त्रौर न स्वदेशी वस्तुत्रों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है।

किसी देश को कौन सी व्यापारिक नीति श्रापनानी चाहिए, यह देश की परिस्थितियों पर निर्मर होता है। प्रत्येक नीति को सापेचिक वांछ्ननीयता का निर्म्य उस देश की परिस्थितियाँ ही कर सकती हैं। प्रत्येक श्रार्थिक क्रिया का उद्देश्य श्रिषकतम श्रार्थिक उत्पादन व संतोष प्राप्त करना ही होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही विभिन्न प्रकार की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं श्रौर उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। इन दोनों नीतियों के बारे में भी यही बात है। दोनों में गुण व

दोष भी हैं। मुक्त ब्यापार के पन्न में जितने भी तर्क दिए जाते हैं वे प्रायः सम्पूर्ण अम विभाजन के लाभों पर आधारित हैं Lजिस प्रकार साधारण उद्योगघं वो में अम विभाजन तथा विशिष्टाकरण से अधिकतम उत्पादन होता है और उत्पादित धन का उर्चित विभाजन करने पर सबंधित व्यक्तियों को ऋधिकतम लाभ होता है, उसी प्रकार मुक्त व्यापार से विभिन्न देशों को ऋधिक से-ऋधिक लाभ होता है। प्राकृतिक तथा ऋन्य सुविधार्ऋों के कारण प्रत्येक राष्ट्र किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में त्र्राधिकतम कार्यच् मता रखता है। विशिष्टीकरण द्वारा देश के अम त्र्रौर पृँबी उन्हीं उद्योगों में लगाये बाते हैं बिनमें उनका प्रतिफल ऋघिकतम मिलता है। त्र्यतः मुक्त त्र्यन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण बड़े-से-बड़े पैमाने पर हो सकता है। ग्रौर इसीलिए मुक्त व्यापार को लोग ग्रच्छा समभते हैं। मुक्त व्यापार तुलनात्मक लागतों के नियम की स्वामाविक प्रवृत्ति है। इस नीति के अन्तर्गत प्रत्येक देश अपनी आवश्यक वस्तुत्रों को सस्ते से सस्ते बाजार में खरीद सकता है ग्रौर त्र्रपनी निर्मित वस्तुत्रों को ग्रच्छे से-स्रच्छे बाज़ार में बेच सकता है। इस प्रकार यदि किसी देश के सरकारी कानूनों द्वारा वाधा न डाली जाय तो उस देश की पूँजी व श्रम उन उद्योगों में जाने की प्रवृत्ति दिखलाते हैं जिनमें उनका उपयोग सबसे ऋधिक लाभप्रद किया जा सकता है ऋौर इसी कारण प्रत्येक देश का उत्पादन ग्रपनी चरम सीमा पर पहुँच सकता है स्रौर उससे सारे संसार का कुल उत्पादन बढ़ जाता है। वास्तव में मुक्त व्यापार की नीति से प्रत्येक देश को वह सारे लाभ ऋधिकाधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं जो लाभ ऋन्तर्रीष्ट्रीय व्यापार से लाभ होने चाहिए । ऋर्थात् कमागत उत्पादन वृद्धि नियम का ऋधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ सस्ते-से-सस्ते मूल्यों पर प्राप्त की जाती हैं। उत्पादन के साधनों का विशिष्टीकरण भली भाँति हो जाता है। अपने देश में उत्रन्न न होने वाली वस्तुत्रों का भी उपयोग संभव होता है। स्रथवा देश में उत्पन्न होने वाली ऋधिक कीमत वाली वस्तुएँ विदेशों से कम कीमत में प्राप्त हो सकती हैं। देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग ग्राच्छी तरह किया जा सकता है। जीवन स्तर उच्च होता है स्रौर पारस्परिक सद्मावना में वृद्धि होती है।

संरक्षण के द्वारा, उक्त व्यापार की अपेक्षा वस्तुओं के आयात-निर्यात में कमी हो जाती और उसी सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाम भी कम हो जाते हैं। फिर भी विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत संरक्षण भी वांछनीय होता है। वास्तव में आधुनिक काल में तंरक्षण समस्त देशों की व्यापारिक नीति का एक नियमित अंग बन गया है। और इसके पक्ष में निम्नांकित तर्क उपस्थित किए जाते हैं:—

- १ शिशु उद्योग (Infant Industries) का पच्च—यह तर्क जर्मनी के अर्थशास्त्री फेडिएक लिस्ट (Frederich List) द्वारा दिया जाता है जिसका आधार है कि संसार के तमाम देशों में आर्थिक विकास एक सा नहीं होता। कहीं उद्योग शीन्न प्रारंभ हो जाते हैं और कहीं विलंब से। विलंब से विकसित उद्योग वाले देशों में उद्योग शिशु अवस्था में होते हैं और वे विकसित देशों के वयस्क उद्योगों की प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते। यदि इन शिशु उद्योगों को संरच्चण प्रदान कर उन्नित और विकास का अवसर दिया जाए तो कुछ समय के बाद ही ये भी प्रतियोगिता में ठहरने योग्य हो जाते हैं परंतु यदि स्वतंत्र व्यापारिक नीति है तो विभाजित देशों ने उद्योग अविकसित देशों का आर्थिक विकास नहीं होने देंगे।
- २. वेकार साधनों का पत्त (Idle Resources Argument) सरंत्त्रण शिशु उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है वरन् उसके द्वारा नए उद्योगों को खड़ा करके देश के पड़े सुषुप्त एवं अनुपयोगी साधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में पड़े हुए वेकार साधनों का उपयोग संरत्त्रण द्वारा किया जाता है श्रीर देश के उत्पादन में वृद्धि करके देश के आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने में मनुष्य-साधन का भी उपयोग होता है श्रीर रोजगार बढ़ता है।
- ३. उद्योग विविधता का कारण (Diversification of Industries)—
 देश को स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से तथा संकट काल में भी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि देश में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए बाएँ तथा नए-नए उद्योग को संरच्यण प्रदान किया जाए। इस प्रकार विशिष्टीकरण की हानियों से बचा जाएगा तथा विभिन्न साधनों का उपयोग किया जा सकेगा।
- ४. आधारिक (Basic) उद्योगों को संरत्त्रण—प्रत्येक देश के आधारिक उद्योग होते हैं जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, युद्ध-सामिश्री उद्योग, इंजीनिय-रिंग उद्योग, आदि । देश का विकास इन्हीं उद्योगों के विकास पर आधारित हैं। सरकार को इन आधारिक उद्योगों को अवश्य ही संरत्त्रण देना चाहिए।
- ५. साधनों के संरच्नण का तर्क—देश में खिनज पदार्थ प्रकृति ने सीमित मात्रा में दिए हैं। यदि उनका लगातार विदोहन (Exploitation) िकया जाता रहा हो उस देश में ऐसे साधनों की सर्वत्र कभी आ जाएगी। अतः इन घरेलू साधनों की रचा की दिष्ट से भी संरच्नण देना आवश्यक है।
- ६. प्रतिरोधी (Retaliation) अथवा स्शिपातन (Dumping) के विरोध में तर्क —यदि कोई देश इमारे देश से जाने वाले माल पर प्रतिबंध लगाता

है तो हमें भी उस देश से त्राने वाले माल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस प्रकार के प्रतिबंध को प्रतिरोधी संरत्न्ण कह सकते हैं। राशिपातन के विरोध में तो सदैव संरत्न्ण प्रदान करना चाहिए। राशिपातन का त्राभिप्राय उत्पादन व्यय (Cost) से भी कम कीमत पर माल बेचना है ताकि त्रायात करने वाले देश में उम वस्तु की सर्व-प्रियता बढ़े त्रौर वहाँ का उद्योग पनप न सके। ऐसे माल के विरुद्ध सरकार को त्रवस्य संरत्न्ण प्रदान करना चाहिए।

- ७. मुद्रा को स्वदेश में रखने तथा देशीय बाजार बनाए रखने का पच्-श्रमेरिका का यह तर्क या कि यदि हम विदेशी माल नहीं मँगाते तो देशी मुद्रा देश में ही रहेगी। परन्तु यहाँ प्रश्न यह होता है कि यदि हम किसी देश के निर्यात स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे देश के निर्यात कौन स्वीकार करेगा। दूसरे संरच्चग द्वारा यह बाजार को बनाए रखा जा सकता है श्रीर देश में रोजगार भी बहुंगे।
- प्रावलंबन (Self-sufficiency) तर्क संकट काल में या युद्ध काल में विदेशों से माल मँगाना असंभव हो जाता है, इस कारण युद्ध सामग्री को जुटाना और जनता की आवश्यकताओं को जुटाना एक वड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। अतः देश में आवश्यकता की सभी सामग्री जुटाने के लिए भी संरच्य की नीति आवश्यक है।

संरत्त्रण विरोधी (Against Protection) तर्क

संरच्या के विरुद्ध भी। विशेषकर यह बात कही जाती हैं कि इससे देश की अथवा किसी विशेष उद्योग की उन्नित कुछ दिनों के लिए रक जाती हैं। यदि एक बार किसी उद्योग को संरच्या मिल गया तो उस उद्योग से सम्बन्धित व्यक्ति संरच्या को एक प्रकार का जन्मसिद्ध अधिकार मानने लगते हैं। एक बार संरच्या देने के उपरान्त उसको वापस लेना असम्भव हो जाता है। संरच्या के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धों की चिन्ता समाप्त हो जाने से उद्योगपितयों में एक प्रकार की शिथिलता आ जाती है और वे उद्योग उन्नित करने का प्रयत्न नहीं करते। कभी-कभी संरच्या से एकि पिकार स्थापित होने की सम्भावना हो जाती है। इससे उपभोक्ताओं को हानि होती है क्योंकि संरच्या किए जाने वाले उद्योगों में उत्यादित वस्तुओं की कीमत अधिक हो जाती है। इससे धन वितरण असमान हो जाता है। संरच्चित उद्योगों के उद्योगित धीरे-धीरे अनन्त धन राशि के स्वामी बन जाते हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संवर्ष और कटुता पैदा होती है और इसके कारण संसार में पूर्ण अम विभाजन अच्छी प्रकार से स्थापित नहीं हो पाता। विभिन्न देशों के उत्पादन के साधन सबसे अधिक लाभदायक उद्योग-धन्धों में न लग कर दूसरे उद्योगों में लग जाते हैं जिससे धनोत्यादन कम होता है और जनता की। जीवन स्तर निम्न हो जाता

है। कमी कभी राजनैतिक चेत्र में इसके कारण भ्रष्टाचार फैल जाता है। उद्योग-पति संरच्या पाने के लिए अथवा संरच्या को बनाये रखने के लिए संसद सदस्यों को बड़ी-बड़ी धन राशि रिश्वत के रूप में देने लगते हैं।

संरच्या प्रदान करने की रीतियों (Methods) में निम्नांकित अधिक प्रचलित हैं—

- १. संरक्त् प्रशुल्क (Protective Tariffs) यह आयातों को रोकने या कम करने की दृष्टि से आयातों पर लगाए जाते हैं। यथा मूल्य कर (Ad-valorem tax) तथा प्रामाणिक कर प्रमुख मेद है।
- २. ऋायात कोटा (Import Quotas)—इसके अन्तर्गत विदेशों से अपने वाले माल की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। ये कोटा संपूर्ण आयात के रूप में या प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग हो सकता है।
- * ३. विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)—विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण लगा दिए जाते हैं ताकि स्रायातों पर प्रतिबन्ध लग जाए।
- ४. सरकार द्वारा छार्थिक सहायता इस प्रणाली द्वारा सरकार व्या-पारियों त्रौर उद्योगपितियों को विशेष छूट, अनुदान, कम ब्याज या निब्यीज पर ऋण, करों ऋदि में छूट देती है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। देशी माल विदेशी माल की प्रतियोगिता में ठहर सकता है।
- ५. विनिमय हास अथवा अवमृत्यन—विनिमय दर में हास तथा सुद्रा का अवमृत्यन करके आयातों की कीमत बढ़ाई जा सकती है जिससे आयातों को हतो-त्साहन मिलता है। दूसरे देशों में निर्यातों की कीमत में घटोतरी हो जाती है जिसके फलस्वरूप निर्यात बढ़ते हैं।
- ६. कभी-कभी कुछ माल का आयात अथवा निर्यात पूर्णतया रोक दिया जाता है। इस प्रकार के कदम को निषेध (Prohibition) कहते हैं। भारत में संरच्चरा नीति

भारत में संरच्या नीति शिशु उद्योग तर्क पर श्राधारित है श्रौर इसके श्राधार पर इस देश ने मुक्त ब्यापार के सिद्धान्त को बिना श्रस्वीकृत किए हुए श्रपनी श्राधिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए विवेचनात्मक संरच्या की नीति श्रपनाई हैं। पीगू के शब्दों में किसी कृषि-प्रधान देश में जिसमें प्राकृतिक साधन विद्यमान हो उत्पादन शक्ति के विकास करने की हिट से संरच्या का पच्च बहुत सशक्त होता है। ऐसे देश में यह उत्पादन के विदेशी विनिमय के रुकने से जो तात्कालिक हानि होती है वह यह उद्योगों को द्रुततर विकास के कारण पूरी हो जाती है। जहाँ तक

भारत का प्रश्न है। इस देश के पास प्रायः सम्पूर्ण प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में हैं। देश कच्चे माल, शक्ति स्रोतों तथा जन शक्ति से सम्पन्न है। इसमें श्रौद्योगिक विकास तथा विस्तार की श्रपार संभावनायें हैं, परन्तु देश को उन्नत तथा सुरिच्चित विदेशी उत्पादकों से स्पद्धी करनी है जो बिना संरच्या के सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती। इसलिए देश के श्रौद्योगिक विकास का यही एक उपाय है कि विवेच-नात्मक संरच्या की नीति श्रपनाई जाय।

भारतीय फिस्कल कमीशन सन् १६२१ ई० ने जिसकी स्थापना देश में संरच्या प्रदान करने की जोरदार माँग के फलस्वरूप हुई थी भारत के लिए विवेचनात्मक संरच्या के पन्न में अपना मत दिया। इस नीति के अनुसार सरकार को संरच्या के लिए ऐसे उद्योग अथवा उद्योगों को चुनना चाहिये जिनमें विकःस की पर्यात सम्भावनायें हैं। पर जो विदेशों स्पद्धी के कारया समुचित उन्नित नहीं कर पाते अर्थात् संरच्या सब उद्योगों को नहीं दिया जाना चाहिए वरन् केवल योग्य तथा होनहार उद्योगों को ही दिया जाना चाहिए। किसी उद्योगों को संरच्या देते सनय निम्नांकित वार्तों का ध्यान रखना आवश्यकाय हैं —

- 2. उद्योग को प्राकृतिक साधन इस प्रकार के श्रवश्य प्राप्त होने चाहिए जिससे भविष्य में उसका कार्य भली प्रकार से चल सके श्रयीत् उसके लिए प्रचुर मात्रा में कच्चा माल, सस्ती शक्ति, श्रम की पर्याप्त उपलब्धि तथा बहुत विस्तृत बाजार होना चाहिए।
- २. उद्योग ऐसा हो जो संरक्षण के बिना या तो बिल्कुल ही विक्रित न हो सके अथवा उसका विकास इस शीव्रता से न हो सके जिस शीव्रता से वांछ्नीय हैं।
- ३. उद्योग ऐसा होना चाहिये जो ग्रंत में विना संरक्षण के विश्व प्रतिस्पद्धीं का सामना कर सके।

भारतीय फिरकल कमीशन के द्वारा जो सिफारिश की गई उस नीति को कार्यान्तित करने के लिए ३ सदस्यों का एक टैरिफ बोर्ड नियुक्त किया गया जो संबंधित उद्योगों के आवेदनों की उपयुक्तता की परीचा करता है और संतुष्ट होने पर सरकार को संरच्या प्रदान करने के उपायों के विषय में अपनी सम्मति देता है। यद्यपि इस टैरिफ बोर्ड की कार्य प्रयाली से देश के उद्योगपांत्यों को संतोप नहीं हुआ। कुछ शातें तो इस बोर्ड ने इतनी कड़ी रक्खीं कि जिससे उद्योगों के द्रुत विकास में बाधा पड़ी। अनेक बार संग्च्या की शतों की बड़े संकुचित ढंग से व्याख्या की गई जिससे कितयय उपयुक्त उद्योग राजकीय सहायता से विचित रह गये। शतें इतनी कड़ी और अनुदार रहीं जिनके कारया देश के औद्योगिक विकास में विलम्ब हुआ। यही नहीं, कभी-कभी टैरिफ बोर्ड प्रायः प्रभावहीन सिद्ध हुआ है। इसके निर्यायों को अनुचित ढंग से ठुकरा दिया गया है। फिर भी इससे विवेचनात्मक संरच्या की नीति दोषी

नहीं ठहराई जा सकती। यह दोष तो उस संस्था व सरकार का है जो इस नीति को उचित ढंग से पालन करने में असमर्थ रही। यदि पिछले ३५ वर्षों के ऋौद्योगिक विकास के इतिहास को देखा जाय तो यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न किमयों श्रीर दुर्वलतार्श्नों के होते हुए भी विवेचनात्मक संरच्या नीति के कारण भारत के कुछ प्रधान उद्योगों की बड़ी तेजी से उन्नति हुई हैं। लोहा ख्रौर इस्पात उद्योग जिसे सर्व-प्रथम संरच्न्ण दिया गया; या देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया है । श्रीर वह श्चन्य राजकीय सहायता के बिना ही विश्व स्पर्क्षा का सामना कर रहा है। इसी प्रकार चीनी उद्योग, कागज उद्योग, दियासलाई तथा स्ती कपड़े का उद्योग इसी नीति के कारण इतनी शीव्रता के साथ विकसित हो गये हैं। सन् १६४५ ई० में नए टैरिफ बोर्ड की स्थापना के फलस्वरूप कुछ श्रौर उद्योगों को संरच्छ मिल गया है। ऐसी श्राशा की जाती है कि एक स्थाई टैरिफ बोर्ड की सहायता से इस नीति का उपयोग श्रौर श्रन्छी तरह किया जा सकता है। उद्योगों को संरक्षण न मिल सका। दूसरे इस नीति के अन्तर्गत केवल स्थापित धन्धों को ही संरच्चण प्राप्त हो सकता है। भविष्य में स्थापित हो सकने वाले उद्योगों के लिए इस नीति के अन्तर्गत कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया । बहुत से ऋनिवार्य उद्योग ऐसे होते हैं जिनकी स्थापना ऋौद्योगिक उन्नति के लिए त्रावश्यक होती है परन्तु जो पूर्व निर्धारित ।संरक्तण के बिना प्रारंभ ही नहीं किए जा सकते। ऐसे उद्योगों को पहिले ही संरचण की गारंटी मिलनी चाहिए। इस नीति को कार्यान्वित करते समय ऐसे बहुत से अवसर आए, जब संर-चुण पाने के लिए त्रावश्यक दशास्त्रों का तात्पर्य संकुचित रूप से लगाया गया, स्त्रौर जिनके कारण कुछ उद्योगों को संरक्षण के अयोग्य ठहरा दिया गया। उदाहरण के लिए, संरक्षण पाने के लिए कच्चा माल, शक्ति, अम व बाजार का होना आवश्यक है परन्तु ये बातें बहुत श्रंश तक तो तभी प्राप्त हो सकती हैं जब कि उद्योग स्थापित ही कर लिए जायँ उदाहरण के लिए सन् १६२८ ई॰ में शीशे के उद्योग को संरचण देने के लिए मना कर दिया गया, केवल इस आधार पर कि इसके लिए आवश्यक कच्चे माल का २५% कच्चा माल अर्थात् सोडा बाहर से आता है। उस समय यह ध्यान नहीं दिया गया कि यदि शीशे का निर्माण यहाँ होने लगे तो संभव है कि देश में सोडा उत्पादन भी होने लगे । जहाँ तक बाजार का संबंध है, देशी बाजार के श्रितिरिक्त निर्यात बाबार की स्रोर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया । कुछ वस्तुस्रों के विदेश में बाबार प्राप्त करने की संभावना पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। इस कारण इस नियम के अन्तर्गत आवश्यक बार्तो-का ध्यान उचित रूप से नहीं रक्खा गया । नीति का विश्लेषण अथवा इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई कि आवश्यक घन्घों को भी संरत्त्य प्राप्त नहीं हो सका। कभी-कभी संरत्त्या पर तथा उसके उद्देश्य पर अनुचित रूप से बल दिया गया। संरच्एा को देश की आर्थिक उन्नति का साधन

न समभ कर इसे केवल कुछ विशेष उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से केवल बचाने का साधन मात्र समभा गया और इसी कारण से देश की वांछनीय औद्योगिक उन्नति न हो सकी । संरक्षण की नीति का उचित रूप से पालन न होने का उत्तरदायित्व कुछ ऋंश तक टैरिफ बोर्ड के संगठन पर भी है। सरकार ने टैरिफ बोर्ड की स्थापना के संबंध में फिरकल कमीशन की राय न मान कर स्थाई बोर्ड की स्थापना न करके केवल ग्रस्थाई तथा किसी विशेष उद्योग के लिए भी बोर्ड स्थापित किये जिनके मेम्बर बदले जाते थे और जिनकी शक्तियाँ सीमित थीं। अनिश्चित बोर्ड के सदस्य श्रपने पद के लालच में सरकार को प्रसन्न रखने के प्रयत्न में रहा करते थे। श्रतः व उग्रोग के सबंघ में संरक्षण देने व न देने के लिए निष्पन्त दृष्टिकोंण से विचार क ने में कभी-कभी ग्रसमर्थ रहते थे। इससे इस बोर्ड की नीति लचीली रहती थी। इसके अतिरिक्त टैरिफ बोर्ड का अधिकार केवल सलाह देना या और केवल उन्हीं -श्रावेदनपत्रों पर विचार किया जा सकता था जो सरकार द्वारा प्रेषित किए जाते थे। जाँच-पड़ताल का चेत्र बहुत ही सीमित था। ख्रतः बोर्ड को निष्पच विचार करने के ेलिए कभी-कभी उचित सूचनायें ही नहीं मिलती थीं । सरकार उद्योगों के आवेदन-पत्रों को बोर्ड के पास भेजने में बहुत देर कर दिया करती थी श्रौर बाद में बोर्ड की छिपारिश के अनुसार कार्य करने में आवश्यकता से अधिक समय लगा देती थी और कभी कभी किसी सिफारिश को बिना कारण दिए पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अस्वी-कृत कर देती थी। किसी-किसी उद्योग के संबंध में संरच्या की स्रावश्यकता की जाँच करने में ३० महीने से भी अधिक लग जाया करते थे। इतने लम्बे समय में उद्योगों की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाया करते थे।

इन दोषों के अतिरिक्त फिस्कल कमीशन के द्वारा शाही अधिमान नीति की लिफारिश करने के फलस्वरूप संरच्चण नीति से होने वाले लाभ और भी कम हो गये। शाही अधिमान नीति के अन्तर्गत वस्तुओं के आयात कर में खूट देने के फल-स्वरूप संरच्चित उद्योगों की प्रगति में बाधा पहुँची।

प्र० १ — युद्धोत्तर काल में भारतीय संरच्या नीति की व्याख्या कीजिये ? दितीय महायुद्ध के कारण भारत में स्थापित उद्योगों के विकास होने के साथ ही साथ कुछ नए उद्योग भी स्थापित हो गये । ग्रतः १६४० ई० में युद्धकालीन विकसित उद्योगों को संरच्या देने की नीति ग्रापनाई गई। इस उद्देश्य से सन् १६४५ में २ वर्ष के लिए ग्रस्थाई टैरिफ बोर्ड की स्थापना की गई। सन् १६४७ ई० में इसकी दुवारा स्थापना हुई।

संरत्त्रण चाहने वाले उद्योग को टैरिफ बोर्ड को यह सिद्ध करना पड़ता था कि वह सुसंगठित तथा उचित रूप से संचालित उद्योग है और वह उचित समय के भीतर इतनी उन्नित कर सकता है कि कुछ समय के पश्चात् वह बिना संरत्न्ण के सफलतापूर्वक चलता रहेगा तथा उसको राजकीय सहायता देना देश के हित में ही होगा। श्रौर ऐसा करने से देश की जनता पर कोई विशेष भार नहीं पड़ेगा।

संरच्या के योग्य उद्योगों के बारे में बोर्ड सरकार से सिफारिश करती थी कि उसे कितना संरच्या देना चाहिए। संरच्या के ऋलावा ख्रौर भी कोई सरकारी सहायता दी जानी चाहिए या नहीं रे तथा संरच्या पूरे ३ वर्षों के लिए दिया जाय या इससे कम समय के लिए।

पिछले बोर्डों की अपेद्या इस बोर्ड में सिफारिश करने में अधिक उदारता की। इस बोर्ड को अधिकार भी अधिक दिए गये थे तथा बोर्ड ने संरत्त्ण के लिए उद्योगों की बाँच करते समय देश के हितों का भी ध्यान रक्खा था। उपभोक्ताओं के हितों का भी बलिदान नहीं किया गया और सरकार ने भी इसकी सिफारिशों पर तुरन्त ध्यान दिया। इस सब का फल यह हुआ कि जब पिछले बोर्डों ने सोलह वर्षीय अविव में ५१ बाँचें की, इस बोर्ड ने ५ वर्षों के समय में ६० आवेदनपत्रों पर विचार किया। इस बोर्ड ने उद्योगों की सहायता के लिए कुछ अन्य निम्नांकित सिफारिशों भी की—

- १. संरच्या इस प्रकार दिया जाय कि विदेशी वस्तुत्रों के भाव देशी वस्तुत्रों से २० प्रतिशत तक ऋषिक रहें क्योंकि जनता देशी वस्तुत्रों की तुलना में विदेशी वस्तुत्रों को ऋच्छा समभती है और इस भावना की संतुष्टि के लिए वह २० प्रति-शत ऋषिक दान दे सकती हैं।
- २. देश में बनी वस्तुत्रों की माँग बढ़ाने के लिए एक निश्चित मात्रा में देश की बनी वस्तु खरीदने पर ही श्रायात के लाइसेन्स दिये जाने चाहिए।
- ३. संरच्ति उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल तथा मशीनरी पर लगे हुए कर में छूट दी जानी चाहिए ।
- ४. विदेशो विशेषजों को रखने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।
- ५. उन्हीं विदेशी कम्पनियों को सहायता देने पर विचार किया जाना चाहिए जिनकी पूँजी रुपयों में परिवर्तन हो चुकी है और जो भविष्य में भारतीय हित के विरुद्ध कार्य न करने का वचन दे।
- ६. उत्पादकों के संगठन, संयुक्त विकी संगठन तथा देशी वस्तुत्रों के उचित वर्गीकरण का प्रवन्ध किया जाना चाहिए।

सन् १६४८ ई० में भारत सरकार द्वारा नवीन श्रौद्योगिक नीति की घोषणा करने के बाद, घोषणानुसार के यें करने के लिए सन् १६४६ में एक नवीन भारतीय फिस्कल क्मीशन की नियुक्ति की गईं। कमीशन ने सिफारिश की श्रव संरत्न्य के उद्देश्य में परिवर्तन होना चाहिए इसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक वैकल्पिक नीति न मान कर राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के साधनों में से एक मुख्य नीति माननी चाहिए। इसके लिए एक दीर्घकालीन योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। जब तक इस प्रकार की योजना न बने तब तक रचा तथा युद्ध सम्बन्धी उद्योगों को हर हालत में संरच्या देना चाहिए। आधार भृत उद्योगों के लिए संरच्या देने की शर्तें तथा मात्रा टैरिफ़ बोर्ड को निश्चित करनी चाहिए और फिर यह ध्यान रखना चाहिए कि संरच्यित उद्योग कहाँ तक अपने दायित्व को पूरा कर रहें हैं। तथा अन्य उद्योगों के बारे में भली भाँति सोच-समक्ष कर संरच्या देना चाहिए। उपरोक्त विचार करने के लिए बोर्ड को निम्नांकित बातों का ध्यान रख कर अपनी सिफ़ारिश करने में सहायता मिलेगी।

- १. उदाहरण के लिए, यदि किसी उद्योग के पास अम, बाजार यातायात के साधन उपयुक्त हैं तो देश में केवल कच्चा माल प्राप्त न होने के कारण संरक्षण की स्वीकृति रोकनी नहीं चाहिए।
- २. चंरिव्त उद्योगों के उत्पादित माल को कच्चे माल के समान प्रयुक्त करने वाले संरिव्यत उद्योगों को सरकारी अनुदान दिया जाना चाहिए। भविष्य में स्थापित होने वाले अन्य प्रकार से उपयुक्त उद्योगों को भी संरव्या देना चाहिए।
 - ३. कृषि पदार्थों को ५ वर्षों के लिए संरक्षण देना चाहिए।
- ४ यथासंभव संरिच्चत उद्योगों के माल पर उत्पादन कर नहीं लगाना चाहिए त्र्यौर ऐसे माल पर सेल्स टैक्स लगाने में भी सावधानी वस्ती जानी चाहिए।

फिरकल कमीशन ने यह भी सिफ़ारिश की थी कि एक स्थाई टैरिफ़ कमी-शन नियुक्त किया जाना चाहिए जिसके ५ से ७ तक सदस्य होने चाहिए। इस कमीशन को आँकड़े एक करने, विभिन्न सूचनायें प्राप्त करने तथा सम्बन्धित जाँच-पड़ताल करने के लिए उचित अधिकार दिए जाने चाहिए। और यह कमीशन योजना कमीशन का भाग न हो कर एक स्वतन्त्र संस्था होनी चाहिए। उपरोक्त कमीशन के ३ मुख्य कार्य होने चाहिए--

- १. त्रायात-निर्यात पर संरक्तित कर तथा त्राय कर से सम्बन्धित प्रश्नों पर जाँच करना।
- २. मूल्य सम्बन्धी तथा संरच्या से देश की आर्थिक दशा पर पड़े हुए प्रभावों से सम्बन्धित नमस्या पर विचार करना।
- ३. संरत्त्रण करों का विवेचन तथा खिंहावलोकन करना । इनके अतिरिक्त इस कमीशन को समय-समय पर संरत्त्वित उद्योगों की प्रगति पर प्रकाश डालने वाली आलोचनाओं तथा अपने विचारों को भी सरकार के सामने रखनी चाहिए। इन

श्रालोचनात्रों के श्रन्तर्गत इन समस्यात्रों पर विचार किया जाना चाहिए कि स्वीकृत संरक्ष की शतों के श्रनुसार कार्य हो रहा है या नहीं ? संरक्ति उद्योग की उन्नति में बाघा पहुँचाने वाला कोई दोष तो नहीं श्रा गया है। तथा इसकी उन्नति के लिए किसी विशेष प्रकार की सहायता श्रावश्यकता तो नहीं है।

इस प्रकार इन्डियन फिस्कल कमीशन (१६५०) की की गई अनेक सिफा-रिशों से यह प्रकट होता है कि नवीन टैरिफ़ कमीशन सन् १६२१ के कमीशन से अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। यह कमीशन संरच्चण को आर्थिक प्रगति का एक साधन मान कर कार्य करेगी। इस कमीशन के सामने संरच्चण पाने के लिए अनिवार्य दशायें विस्तृत रूप से स्पष्ट हैं। यह कमीशन स्वतन्त्र रूप से काम करने के कारण अधिक शक्तिशाली होगा। अब संरच्चित उद्योगों पर निश्चित उत्तरदायित्व रक्खा गया है जिससे उद्योग पित पहले की माँति उदासीनता तथा अक्रमेंग्यता से काम न कर सकेंगे। और अभी तक न स्थापित हुए उद्योगों को संरच्चण भी आसानी से मिल सकेगा।

Q. 2 Write a note on the different 'Forms of Protection'.
प्र २—संरच्य प्रदान करने के ढंगों पर एक टिप्पणी लिखिये।
सरच्या प्रदान करने के ढग

साधारण तौर पर विभिन्न उद्योगों को विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार निम्नांकित ढंगों में से किसी एक ढंग से संरच्चण प्रदान किया जाता है—

- १. श्रायात कर—स्वदेशी वस्तुत्रों से प्रतियोगिता करने वाली विदेशी वस्तुत्रों के श्रायात पर कर लगाया जाता है। इससे विदेशी वस्तुत्रों का मृल्य बढ़ जाता है श्रौर इस प्रकार स्वदेशी उत्पादक विदेशियों की स्पर्धा करने में समर्थ हो जाते हैं। कभी-कभी यह कर इतना श्रीधक लगाया जाता है कि कर लगे हुए विदेशी माल के लिए कर लगाने वाले देश में कोई जाजार ही नहीं उहता श्रौर ऐसी परिस्थितियों में बह उद्योग शीध उन्नति कर लेता है।
- २. वैत्तिक सहायता—वैत्तिक सहायता द्वारा सरकार लागत का कुछ भार श्रिपने ऊपर से लेती है यदि किसी वस्तु का देश में उत्पादन करने से उसका लागत व्यय विदेश के लागत व्यय से श्रिधिक होता है तो लागत व्यय का कुछ भाग सरकार देती रहती है जिससे देशी उत्पादकों को लागत व्यय का भार कम उठाना पड़ता है श्रीर वह विदेशी वस्तुओं का सामना कर सकते हैं।
- ३. कोटा—इस प्रणाली के अन्तर्गत आयातों की मात्रा पर प्रतिबन्ध लगाया बाता है। स्वदेशी बाजार में आने वाली विदेशी वस्तुओं का परिमाण निश्चित कर दिया बाता है और निश्चित सीमा के बाद उसका आयात बंद कर दिया जाता

है। इस प्रकाली में उद्योगपितयों को बाहर से श्राने वाली वस्तुश्रों की मात्रा कर ज्ञान रहता है। श्रतः वे देश की माँग को पूरा करने के लिए उत्पादन करने में स्वतन्त्र होते हैं श्रौर कुछ सीमा तक विदेशी प्रतिस्पर्का से बच बाते हैं।

- 8. व्यापारिक संधियां— व्यापारिक संधियों द्वारा भी अपने उद्योगों की रहा की बाती है। प्रत्येक देश इस प्रणाली के अन्दर उन देशों से वस्तुएँ आयात करने का निश्चय करता है बिन देशों में उस देश की वस्तुओं की माँग होती है। इन व्यापारिक समझौतों के अन्तर्गत सम्बन्धित देश दूसरे देशों की अपेदा एक दूसरे को अधिक सुविधायें देते हैं।
- 4. विनिमय नियन्त्रण्— अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अपने अनुकूल बनाये रखने के लिए विदेशों व्यापार तथा भुगतानों पर कड़ी निगाइ रखनी पड़ती है। विनिमय नियन्त्रण् द्वारा देश की सरकार विदेशी व्यापार का आयोजन और उसकी दिशा का निर्धारण् देश हित में करती रहती है। जहाँ तक विनिमय नियन्त्रण् का उपयोग देश के उत्पादन को वांछित दिशाओं में मुड़ने के लिए किया जाता है वहाँ तक वह संरच्न्णात्मक होता है।
- ६. अवमूल्यन—इस प्रणाली के अन्तर्गत देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं में इस उद्देश्य से कम किया जाता है कि आयात कम हो और निर्यात बढ़े। ऐसी दशा में विदेशी वस्तुएँ अवमूल्यन करने वाले देश में महँगी हो जाती हैं। इस परिवर्तित परिस्थित में यह उद्योग देश की माँग को पूरा करने के लिए शीव्रता से प्रयत्न करने लगते हैं। अतः अवमूल्यन का परिणाम भी संस्व्यात्मक ही होता है।

व्यापार में राज्य का हस्तत्त्वेप कोई नवीन बात नहीं है। संकट काल में प्रायः प्रत्येक देश को कुछ न कुछ हस्तत्त्वेप करना ही पड़ता है, विशेषकर युद्धकाल में यह हस्तत्त्वेप ऋति आवश्यक हो जाता है, । भारत सरकार ने भो युद्धकाल में भारतीय आयात तथा निर्यात पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाये। युद्धोत्तर काल में भी सरकार निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के वर्गीकरण, चिह्नित करने और उनके रंग, रूप व आकार आदि गुणों में उन्नति करने की आवश्यकता का अनुभव कर रही है। फलस्वरूप उसने राज्य व्यापार पर सिकारिशें करने के लिए देशमुख कमेटी की सन् १९४६ई० में स्थापना की। कमेटी ने अर्ध सरकारी कारपोरेशन स्थापित करने की सिकारिश की जिसकी प्रारम्भिक पूँजी दो करोड़ रुपये की हो जो बढ़कर १० करोड़ रुपये हो सकती है और वह खाद्य की मात्रा इस्पात, कपास, कृषि और सूती वस्तुओं सम्बन्ध देश के विदेशी व्यापार का नियंत्रण करे, कमेटी ने भारत के बैकिंग, जहाजी और बीमा व्यवसाय का प्रगतिशील राष्ट्रीयकरण तथा ग्राम सहकारिता समितियों

की स्थापना पर जोर दिया । परन्तु देश के श्रिधकांश विशेषकों का यह विचार है कि विदेशी व्यापार का पूर्ण राष्ट्रीयकरण का समय श्रमी तक नहीं श्राया है, इस समय सरकार को केवल उन्ही भागों पर नियंत्रण करना चाहिए कि जिन्हें वह सफलता पूर्वक चला सकती है। कमेटी ने सिफारिश की कि पूँजी का ५१ प्रतिशत भाग श्रशों के रूप में केन्द्रीय सरकार से, शेष हिस्सों को व्यक्तिगत व्यापारी तथा राष्य सरकार सिरी । केन्द्रीय सरकार को व्यापारियों को न्यूनतम लाभ का विश्वास देना चाहिए। कार्परिशन का कार्य चलाने के लिए संचालक कमेटी होनी चाहिये जिसके सदस्य श्रमुभवी व्यापारी हों, श्रोर जिसके कार्य करने के लिए एक संचालक नियुक्त किया जाना चाहिए।

कमेटी के मतानुसार राज्य द्वारा विदेशी ज्यापार का संचालन तभी हो सकता है जब कि आन्तरिक ज्यापार की ज्यवस्था भी संगठित रूप से की ज़ाय, विशेषकर आयात की हुई वस्तुओं का वितरण करने के लिए सहकारी उपभोक्ता समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक सहकारी उपभोक्ता स्टोर होना चाहिए जिसका सम्बन्ध ट्रेडिंग कारपोरेशन से होना चाहिए।

उपरोक्त समितियों ने इस सम्बन्ध में निम्नांकित मुख्य सिफारिशों की हैं-

- १- यह कारपोरेशन अनाज, खाद, भौलाद, और पूर्वी अफरीकन रुई, के आयात सम्बन्धी व्यवहारिक कार्य तथा व्यापारिक समभौतों के फलस्वरूप विभिन्न कार्य जो इस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाते हैं, करेगा।
- २. कारपोरेशन को छोटे रेसे वाले रुई का व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इसी प्रकार उसे घरेलू उद्योगधन्यों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी अपने हाथ में ले लेना चाहिये। जब ये वस्तुयें विदेशी बाजारों में अपना प्रभुत्व बमा लें तब उनका व्यापार व्यक्तिगत व्यापारियाँ के हाथों में सौप दिया जाना चाहिये। उस कारपोरेशन को बिना सरकार की आज्ञा के किसी वस्तु में व्यापार नहीं करना चाहिये।
 - ३ कारपोरेशन को भारतीय बाजार में किसी अन्य देश की श्रोर से एजेन्ट का काम करके सामान खरीदने और बेचने का अधिकार दिया जाना चाहिये।
 - ४. इस कारपोरेशन को चाहिये कि वह समय-समय पर व्यापार नियंत्रण सम्बन्धी सलाह सरकार को देता रहे।
 - 4. जूट के सम्बन्ध में कमेटी ने यह सिफारिश की कि भारतीय जूट मिल एसी-स्विस्त तमाम जूट को स्वयं खरीदा करे और इसके अनुभव के बाद मैगनीज, जमहा और जूट के सामान को भी इस व्यापार में शामिल करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

किया जा सकता ह। कि चाय, अध्यक्ष, तथा चीती में सरकार द्वारा व्यापार करने की राय कमेटी ने नहीं ती। इस देशमुख कमेटी की सिफारिशों के आघार पर १८ मई सन् १६ ५६ ई० को नई दिल्ली में "दी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटिड" के नाम से एक कारपोरेशन स्थापित किया गया है जिसकी प्राधिकृत पूँजी १ करोड़ रुपये रहेगी जो १००-१०० रुपये के हिस्सों में बटी होगी और इसकी प्राप्त पूँजी ५ लाख रुपया होगी। उपरोक्त कारपोरेशन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खोला गया है —

- निर्घारित वस्तुत्रों का विदेशों से भारत में त्रायात और भारत से विदेशों को निर्यात करने के लिये यथोचित प्रवन्ध करना।
 - २. निर्घारित वस्तुश्रों का क्रय-विक्रय करना ।

प्रश्न

1. Examine the usefulness of the following as the methods of protection to industries —(a) tariffs, (b) Quantitative restriction, (c) Subsidies and tariff quotas (Agra B. A. 1956)

अध्याय १५

भारत में व्यापारिक समभौते

सामान्य रूप से तथा सैद्धान्तिक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मुक्त नीति के आधार पर सब देशों के लिए हितकारी होना चाहिए, पर विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में असमानता होने के कारण मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सब देशों को समान रूप से लाम नहीं पहुँचता। किसी को अधिक ओर किसी को कम लाम, यहाँ तक कि कुछ देशों को हानि तक होती है। ऐसी दशा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्चण की नीति अपनाई जाती है या विभिन्न प्रकार के व्यापारिक समभौते किए जाते हैं। यह व्यापारिक समभौते प्रायः २ प्रकार के होते हैं—

- १. द्विपत्तीय—इस प्रकार के व्यापारिक समभौते २ देशों के बीच में थोड़े समय के लिए होते हैं।
- २. बहुपूर्त्वाय इन समभौतों के श्रन्तर्गत समभौते श्रनेक देशों के बीच श्रौर बड़े समय के लिए हुँहोते हैं।

द्विपचीय समभौते साधारणतया १ वर्ष श्रथवा उससे कम समय के लिए किए जाते हैं। ये समभौते श्रस्थाई होते हैं। उसके विपरीत बहुपचीय समभौते स्थाई होते हैं। दिपचीय समभौतों का चेत्र सीमित होता है। इसके विपरीत बहुपचीय समभौते व्यापक होते हैं।

मारत वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक त्तेत्र में बहुत दिनों से प्रत्यत्त् व अप्रत्यत्त् रूप में सममौते करता चला आ रहा है। और सब से पहिला व्यापारिक सममौता इम्पीरियल प्रेंफरेन्स या शाही अधिमान के नाम से पुकारा जा सकता है। इस नीति के अन्तर्गत साम्राज्य के विभिन्न देशों से होने वाले आयात पर प्रशुल्क सुविधाएँ दी जाती थी; जिसके अनुसार साम्राज्य के अन्तर्गत देशों के बीच व्यापार का अधिकतर विकास हो सके। इस नीति का उद्देश्य साम्राज्य के विभिन्न सदस्य देशों के बीच प्रशुल्क स्कावटों को यथासंभव कम करना तथा साम्राज्य का व्यापार बढ़ाना था। आर्थिक दृष्टि से, इस नीति के आधार पर चलने से सब साम्राज्य देशों को खाभान्वत होने की समावना थी। इस प्रकार की नीति सबसे प्रथम कनाडा ने सन् स्टूर्ड के में अपनाई, जब कि उसने ब्रिटिश माल को आयात करों में छूट दी। इसके बाद सन् १६०२ ई० में उपनि वेशों की परिषद में शाही अधिमान के नियमों का समर्थन किया गया। इसके बाद इस नीति का समर्थन साम्राज्य देशों के द्वारा

बढ़ता ही चला गया। भारत के सामने यह समस्या सबसे पहिले सन् १६०३ ई० में आई, लेकिन भारत ने इस नीति का विरोध किया, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति तथा विदेशी व्यापार की परिस्थितियों को देखते हुए इस नीति से देश को हानि होने की सम्भावना थी। इस नीति से देश के कच्चे माल का निर्यात और अधिक बढ़ता और निर्मित माल का निर्यात और अधिक होता। इन दोनों बातों का प्रभाव भारतीय औद्योगिक विकास पर प्रतिकृल पड़ता। इस बात को ध्यान में रखते हुए उस समय की भारतीय सरकार ने इस सिद्धान्त को मानने के लिए निम्नांकित शर्तें रखीं—

- १. प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में प्रशुल्क सुविधायें देने के लिए भारतीय संसद कौ राय लेना त्रावश्यक होना चाहिए।
- २. किसी भी प्रशुलक सुविधा से, किसी भी भारतीय उद्योग को दिए हुए संरक्षण में कभी नहीं होनी चाहिए।
- २. इन सुविधाओं से लाभ की अपेता और किसी प्रकार की हानि अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ४. इंग्लैएड के सम्बन्ध में यह नीति एव्छिक हो। परन्तु अन्य देशों के लिए यह पारस्परिक आधार पर होनी चाहिए।

फिर इन शतों का व्यवहार में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और यह नीति विशेषकर इंग्लेश्ड के हित में ही अपनाई गई। सब से पहिले ब्रिटिश सूनी वस्त्र पर आयात प्रशुल्क कम किया गया। चाय के निर्यात कर में छूट की गई। इस प्रकार चमड़े के निर्यात करों में भी छूट दी गई। सन् १६३२ ई॰ में भारत और ब्रिटेन के बीच ओटावा सममौता हुआ जिसमें भारत सरकार द्वारा शाही अधि-मान के सिद्धान्त को पूर्ण रूप से स्वीकृत कर लिया गया। इस समय इस नीति के पच्च व विपच्च में अनेक तर्क दिए गए, जिनका अब व्यवहारिक महत्व तो विशेष नहीं है फिर भी ज्ञान इद्धि की दिष्ट से उन तर्कों की जानकारी वांछनीय है। शाही अधिमान के पच्च में निम्नांकित तर्क दिए गए थे—

- १. इस नीति से आर्थिक अपकर्ष के समय में भारत को आर्थिक सहायता माप्त हुई। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत उस समय विश्व के लगभग तिहाई देश सिम्मिलित थे। इस नीति के द्वारा इन देशों के बीच अवाध व्यापार सम्बन्ध बनार रहा जिससे इन देशों के अन्दर आर्थिक विकास उद्योग व रोजगार का स्तर ऊँचा बना रहा।
- र. ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि सिक्के पाउरड के प्रचलन से इन सब देशों में एक प्रकार की एकता बनी रही जिसके कारण जब कि संसार के श्रीर देश सुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों से पीड़ित थे इन देशों का श्रार्थिक व मुद्रा संबंधी ढाँचा सुद्रह बना रहा।

३. इस नीति ने साम्राज्य के देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिकृत्त करिस्थितियों से बचाया । जिस समय असाम्राज्य देशों के मध्य होने वालें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर संकट आये उस समय साम्राज्य देशों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सुचारू रूप से चलता रहा । इसका लाभ भारत को भी मिला ।

४. भारत की बनता ऋषेचाकृत कम आय वाली है। ऐसी जनता के लिए उपभोक्ता की वस्तुएँ सस्ती चाहिए और उनकी उत्पादित वस्तुओं के लिए सुर्राच्नत बाज़ार चाहिए बिससे उनकी न्यून आय स्थिर बनी रहे और उसमें कभी न हो। शाही ऋषिमान की नीति से में दोनों बातें पूरी हो सकती थीं। भारतीय कच्चे माल के लिए साम्राज्य देश के बाजार सुरच्चित थे। इसके साथ-ही-साथ इन देशों का निर्मित माल भारत में सस्ते दामों पर मिल सकता था। इस कारण से यह नीति सारत के हित में ही समसी गई। और इन्हीं तकों के आधार पर भारतीय सरकार ने इस नीति को अपनाया।

उपरोक्त तकों के होते हुए भी भारतीय अर्थशास्त्री तथा नेता इस नीति के पद्ध में नहीं थे। उनके मतानुसार इस नीति से भारत को हानि होने की ही आशंका थी। इसलिए उन्होंने निम्नांकित तकों के आधार पर इस नीति का विरोध किया—

१—भारत विशेषकर ऐसे कच्चे माल का निर्यात करता था जिसमें इसे प्रायः एकाधिकार प्राप्त था। इसिलए साम्राज्य देशों के बाजार में भी इसे बाहरी प्रतिस्पद्धी का कोई भव नहीं था। इसके विपरीत इंग्लैएड निर्मित माल का निर्यात करता था। उसे प्रतिस्पद्धी का सदैव भय रहता था। अतः इस नीति से इंग्लैएड को लाभ होने की संभवना तो थी पर भारत को कोई लाभ नहीं हो सकता था।

२—मारत का व्यापार ऋसाम्राज्य देशों से घीरे-घीरे बढ़ रहा था। उन देशों से मेद भाव करने में व्यापारिक सम्बन्ध विगड़ने की आशा थी जिससे ऋसा-माज्य देशों का बहुत बड़ा बाजार भारत के हाथ से निकल सकता था। हमारा व्यापार उन देशों से कम हो जाता, और यही हुआ भी।

रे भारत विवेचनात्मक संरच्या के सिद्धान्त को मान चुका था। ऐसी परिस्थिति में साम्राज्य देशों को रियायत देने से संरच्या की नीति विफल हो सकती थी। वास्तव में ऐसी स्थिति में संरच्या का कोई श्रर्थ ही नहीं रहता।

४— कुछ, वस्तुएँ श्रमाम्राज्य देशों से ही सस्ती मिल सकती थीं। पर इस नीति के श्रनुसार वे वस्तुएँ हमें साम्राज्य के देशों से ही खरीदनी पड़ती थीं जिससे यह वस्तुएँ मारत में महुँगी पड़ती थीं।

५—इस नीति के पालन करने से आयात कर की आय में कमी हुई जिससे सरकारी आय को धक्का लगा। नैतिक दृष्टि से भी यह नीति ठीक नहीं कही जा सकती कि एक देश समान परिस्थितियों में कुछ देशों के साथ उदारता की नीति का पालन करें तथा अन्य देशों के साथ अनुदार नीति अपनाये। मारतीय सरकार ने इन तकों की विशेष परवाह नहीं की और इंग्लैंग्ड के साथ शाही अधिमान के सिद्धान्त के आधार पर ही व्यापार होता रहा। और संरच्या नीति के होते हुए भी यदि भारत की औद्योगिक प्रगति ठीक नहीं हुई तो इसका दोष इसी नीति पर थोपा जा सकता है। यद्यि कुछ लोग उस मत को स्वीकार नहीं करते।

यह नीति द्वितीय विश्वयुद्ध तक किसी न किसी रूप में चलती रही। उसके पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब देशों को साम्राज्य तथा असाम्राज्य देशों में विभाजित करना ठीक नहीं रहा। अब सब देशों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना बढ़ गई है। आर्थिक चेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना बढ़ गई है। आर्थिक चेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है। साथ ही साथ राजनैतिक आर्थिक चेत्र में इंग्लैएड का महत्व बहुत कम हो गया है और अमेरिका का महत्व बहुत बढ़ गया है। इन परिवर्तित परिस्थितियों में शाही अधिमान नीति को काफी घक्का लगा। वास्तव में अब तो लोगों को शाही शब्द से ही घृषा सी होती है। विशेषकर अमेरिका ने इस नीति का घोर विरोध किया। फिर भी यह नीति दूसरे रूप में अब भी लागू की जाती है। जिस प्रकार इम्पाइर कन्ट्रीज (Empire Countries) के स्थान पर कामनवैल्थ आफ नेशन्स अधिक रचिकर समका जाता है उसी प्रकार से इम्पीरियल प्रेफरेन्स के स्थान पर कामनवैल्थ प्रेफरेन्स की नीति वर्तमान समय में अपनाई बा रही है।

सन् १६३२ ई० में इंग्लैएड और भारत के बीच में श्रोटावा समभौता स्वीकार किया गया। इस समभौते के अनुसार कोई भी देश ६ माह की स्वना देने के बाद समभौते से प्रथक हो सकता था। यह समभौता १ जनवरी सन् १६३३ ई० से लागू किया गया। संयुक्त राज्य से कुछ मोटरों के आयात कर में साढ़े सात प्रतिशत तथा अन्य वस्तुओं के आयात कर में दस प्रतिशत की छूट दी गई। और इंग्लैएड में जिन वस्तुओं पर १० प्रतिशत आयात कर लगाया गया था वे भारतीय वस्तुएँ आयात कर से मुक्त कर दी गई। इस प्रकार की नीति कुछ वस्तुओं के आयात कर के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य में भी अप्रनाई गई।

शाही अधिमान की नीति के समान ओटावा समभौते के सम्बन्ध में भी दोनों और से तर्क दिए गए। कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया और कुछ लोग इसके विरोध में भी रहे। समभौते के पद्म में निम्नांकित तर्क दिए गए थे—

१— सन् १६२६ ई० की विश्वमंदी के कारण मास्तीय कृषि वस्तुत्रों की कीमतें बराबर गिरती चली जा रही थी। सन् १६३१ में इंग्लैएड के द्वारा स्वर्णमान के त्याग करने पर तथा रुपए को पेपर स्टिलिंग से संबंधित करने के कारण स्थिति क्रीर भी खराब हो गई थी। इसके साथ ही साथ श्राफीका तथा दिल्ला श्रामेरिका के कृषि पदार्थों से भारत की प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती जा रही थी। ऐसी श्रवस्था में भारतीय कस्तुत्रों के लिए विदेशी बाजार कायम रखने की दृष्टि से यह समभौता त्र्यावस्थकीय था। क्योंकि इस समय भारतीय माल को श्रिधिक लोने वाले देश भारतीय माल पर श्रिधिक श्रायात कर लगा रहे थे। इसलिए भारत ने यह समभौता करके श्रपने वस्तुत्रों के लिए बाजार सुरिज्ञत कर लिया।

र—बहुत सी कृत्रिम वस्तुश्रों के निर्माण होने से भारत के कच्चे माल का निर्यात मी विदेशों में कम हो चला था । इस कमी की पूर्ति भारतीय सरकार ने समसौते के द्वारा संयुक्त राज्य तथा साम्राज्य के उपनिवेशों का बड़ा बाजार प्राप्त करके की। यदि भारत यह समसौता न करता तो भारतीय वस्तुश्रों के लिए यह बाजार न रहता।

समभौते के विपन्न में निम्नां कित तर्क दिए गए थे-

१—भारत की ऋौद्योगिक दशा पिछड़ी हुई थी। इसलिए इस समभौते से भारत को किसी विशेष लाभ की त्रावश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत समभौते के कारण संयुक्त राज्य तथा अन्य उपनिवेशों को भारत का विशाल बाजार प्राप्त हो गया।

र—इस समभौते के कारण भारत के विदेशी बाजार का रुख अन्य देशों से बदल कर केवल साम्राज्य देशों तथा संयुक्त राज्य तक ही सीमित होने की संभावना यी, और ऐसा ही हुआ।

२—भारत का नियात २ प्रकार की वस्तुओं का हुआ करता था। प्रथम उन वस्तुओं का जिनमें भारत को एकाधिकार प्राप्त था। द्वितीय उन वस्तुओं का जिनमें भारत एवं अन्य साम्राज्य के उपनिवेशों में प्रतियोगिता रहती थी।

इस प्रकार की वस्तु श्रों के निर्यात में इस समभौते से भारत को कोई लाभ नहीं हुशा। क्योंकि एकाधिकारी वस्तु श्रों की माँग तो बिना रियायत के भी वैसी बनी रहती श्रीर श्रन्य वस्तु श्रों में भारत के साथ जो रियायत की गई, वही रियायत श्रित्योगिता करने वाले साम्राज्य के श्रन्य देशों को भी दी गई जिससे भारत की स्थित में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुशा।

उपरोक्त तकों का भारतीय सरकार की नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऋौर इसी समभौते के अनुसार देश का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता रहा।

सितम्बर सन् १६३३ ई० में भारत श्रौर इंगलैगड के बीच में एक श्रौर व्यापारिक समभौता हुआ। इसका नाम मोदी-लीज समभौता है। इस समभौते के श्रमुसार भारत को श्रांशे जी माल की प्रतिस्दर्धों के विरुद्ध श्रपने वस्त्र उद्योग के संरद्धण का श्रिषकार दिया गया। साथ ही साथ उसे जापानी प्रतियोगिता से भी बचाने की श्रावश्यकता समभी गई। इस समभौते के श्रमुसार यह भी तै किया गया कि श्रायात कर पर लगाये गये श्रितिरक्त कर हटा दिए जायेंगे, यदि भारत ब्रिटेन से होने वाले वस्त्र श्रायात पर श्रातिरिक्त कर नहीं लगायेगा। भारतीय रई की खपत को लंकाशायर में प्रोत्साहन देने का विश्वास भी इस समभौते में दिया गया। इस समभौते से भारतीय वस्त्र उद्योग को काफी लाभ हुआ।

सन् १६३५ ई॰ में भारत और ब्रिटेन के बीच एक नया व्यापारिक सम-भौता किया गया। इस समभौते के अनुसार, भारत के उद्योग को उतना संरक्षण प्राप्त करने का आश्वासन दिया गया जिससे भारतीय उत्पादित वस्तुओं का मूल्य आयात वस्तुओं के मूल्य के बराबर हो जाये। परन्दु ऐसा करने में ब्रिटिश माल पर यथा संभव कम कर लगाये जायें। भारतीय उद्योगों को संरक्षण देते समय सम्बन्धित ब्रिटिश उद्योगपतियों से विचार विमर्श किया जाय। तथा आवश्यकता पड़ने पर यदि ब्रिटिश सरकार प्रार्थना करे तो भारतीय सरकार ब्रिटिश वस्तुओं पर लगे हुए आयात कर में संशोधन करे। इन बातों के बदले में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रई की अपनी मिलों में अधिक खपत करने का विश्वास दिया। और यह भी तय किया कि जब तक भारत ब्रिटिश इस्पात को सुविधायें देगा तब तक ब्रिटिश सरकार भी भारतीय पिगुआयूरन को उसी प्रकार की सुविधायें देगी।

सन् १६३६ ई० में भारत व ब्रिटेन के बीच में एक दूसरा समसौता किया गया। इस समसौते के अनुसार भारत में ब्रिटेन से आए हुए माल पर ७३ प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत तक आयात कर में ब्रूट दी गई। और भारत को भी इंग्लैंग्ड के द्वारा बहुत सी वस्तुओं पर छूट दी गई। भारत में मोटरें, बसें, साइकिलें; रसायन, रंग, औषियाँ तथा सीमेन्ट आदि वस्तुओं पर छूट दी। और इंग्लैंग्ड ने सूती उत्पादन, पटसन के कुछ माल, चाय, काफी मैगनेशियम, क्लोराइड, चावल, लाख, अलसीं, चपड़ा, तिलहन तथा मसाला आदि पर १०% से लेकर १५% तक की छूट दी। इस समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि ब्रिटिश इस्पात को भारत के द्वारा तथा भारतीय पिगआयरन को इंग्लैंग्ड के द्वारा मुक्ति मिलती रहेगी, और इंग्लैंग्ड भारत से दई की ६ लाख गाँठें आयात करेगा जिसके बदले भारत इंग्लैंग्ड सारत से दई की ६ लाख गाँठें आयात करेगा जिसके बदले भारत इंग्लैंग्ड

से ५ हजार लाल गज कपड़ा ग्रायात करेगा। ब्रिटिश वस्तु ग्रायात पर श्रायात कर कम कर दिया जाय जबिक इंग्लैंग्ड में भारतीय रहें पर श्रायात कर दुगना कर दिया गया। इस प्रकार यह समभौता न्नार्थिक दृष्टि से भारत के लिए ग्रहितकर ही था। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को हानि पहुँची तथा लकाशायर के उद्योग को प्रोत्साहन मिला। वास्तव में इस समभौते से ग्रन्य साम्राज्य देशों के माल से संयुक्त राज्य में भारत के साथ उन्हीं वस्तुन्नों में प्रतियोगिता होती थी जिनके निर्यात में भारत को ग्राधमान प्राप्त था। इससे भारत को कोई लाभ नहीं हुन्ना। परन्तु भारत की दी हुई सुविधान्नों से इंग्लैंग्ड को ज्यादा लाम हुन्ना क्योंकि इंग्लैंग्ड को ग्रन्य देशों को प्रतियोगिता का भय न था। इस प्रकार यह समभौता ग्राधकतर इंग्लैंग्ड को ही लाभकर सिद्ध हुन्ना। सन् १६४६ व ५० ई० के तटकर क्रायोग के सामने जब समभौते संबंधी प्रश्न न्नाए तो तटकर न्नायोग ने स्थित का ग्रन्छी प्रकार से ग्राध्यन करके किसी भी देश को श्रिधमान देते समय निम्न बार्तों को ध्यान में रखने के सुमाव दिए—

तटकर आयोग के मतानुसार प्रशुक्क सुविधाएँ ऐसी वस्तुओं के संबंध में प्राप्त को बायँ जिन्हें विश्व बाज़ार में समान वस्तुओं से प्रतियोगिता हो अथवा वे निर्मित वस्तुएँ हों। अथवा जिन्हें विश्व बाज़ार में अन्य देशों की प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं से प्रतियोगिता का भय हो। इसी प्रकार प्रशुक्क सुविधाएँ देते समय यह ध्यान रक्खा जाना चाहिए कि पूंजीगत वस्तुओं, यंत्र सामग्री तथा आवश्यक कच्चे माल के आयात में ही सुविधा दी जाय।

भारत का सममीता—भारतवर्ष को अपने वस्त्र उद्योग के संबंध में जापान से कही प्रतिस्पद्धी का सामना करना पड़ा है। सन् १६२२ ई० तक तो आर्थिक उत्कर्ण तथा व्यापारिक तेजी के कारण भारत के वस्त्र उद्योग को किसी विशेष कठिनता का सामना नहीं करना पड़ा। परन्तु इसके बाद परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया। जापान के द्वारा वस्त्र उद्योग के पुर्नगठन करने तथा चीन में वस्त्र उद्योग के कारखाने खुलने से भारत के हाथ से चीन का महात्वपूर्ण बाज़ार निकल गया। वहाँ पर भारतीय सूत की खपत कम हो गई। यही नहीं जापानी प्रतियोगिता भारत के बाबारों में मी बद्रती ही चली गई। आर्थिक मंदी के कारण तीव्रता और भी बद्रती गई। इन सब कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए भारतीय सरकार ने सन् १६३३ ई० में विदेशी आयात पर आपात कर ५०% के स्थान पर ७५% कर दिया। इससे नाराज होकर जापान ने भारतीय रुई का बहिष्कार कर दिया जिससे भारतीय वर्ष उत्पादकों तथा व्यापारियों को बहुत हानि उठानी पड़ी। वास्तव में रुई उद्योग चौपठ हो सवा। इस उद्योग की रह्मा करने के लिए जापान के साथ सन् १६३४ ई० में एक व्यापारिक समसौता किया सथा। इसके अनुसार दोनों देशों को अपनी-अपनी

श्रायात व निर्यात कर नीति में परिवर्तन करने का श्रधिकार मिला। और दोनों देशों ने एक दूसरे को अधिक से अधिक रियायतें देने का वचन दिया । यह तय किया गया कि जापानी माल के वस्त्र त्रायात पर ५०% से ऋषिक कर नहीं लगाया जा सकता यद्यपि कुछ किस्म के कपड़े इस घारा से अलग रक्खे गए। भारत ने जापान से ३२५ मिलियन गज कपड़ा आयात करने और जापान को १ मिलियन गाँठें हर्डे निर्यात करना स्वीकार किया । यदि जापान भारत से अधिक रुई ले तो भारत जापान से अधिक कपड़ा आयात करेगा। जापान द्वारा मेजे जाने वाले पकड़े की किस्में भी निश्चित की गई। इस समझौते. से पारस्परिक कटुता तो दूर हो गई परन्तु भारत को विशेष लाभ नहीं हुन्ना क्योंकि इससे भारत में जापानी माल ऋधिक श्राने लगा जिससे भारतीय कुटीर घनघों को श्राधात पहुँचा l फिर भी भारतीय **क**ई का निर्यात जापान में बहुत बढ़ गया श्रीर इस प्रकार रुई उद्योग को काफी लाभ हुआ। सन् १६३७ ई० में जापान के साथ दूसरा सममौता किया गया। इसके श्रनुसार जापान द्वारा कटपीस, रेश्मी वस्त्र तथा तैयार कपड़े श्रादि का श्रायात निश्चय करने का सुकाव दिया गया और अन्य वस्तुओं पर आयात कर इस प्रकार से लगाने की सिफारिश की गई कि जिससे भारतीय कुटीर घन्घों को कोई हानि न पहुँचे । यह समभौता सन् १६४१ ई० तक रहा । इसके बाद समयान्सार जापानी कपड़े के आयात आदि की मात्रा कम या अधिक की जाती रही।

भारत-ब्रह्मा समझौता—सन् १९४१ ई० में ब्रह्मा से व्यापारिक समझौता करने की आवश्कता प्रतीत हुई। इस समझौते के अनुसार अन्य साम्राज्य देशों के समान ब्रह्मा को १०% से लेकर १५% की रियायत दी गई। दोनों के बीच होने वाले मुक्त व्यापार को समाप्त कर दिया गया। कुछ वस्तुओं का आयात दोनों देशों में विना आयात करों के प्रारंभ करने का सुमाव रक्खा गया। दोनों देशों में परस्पर चावल का आयात पूर्ण तथा मुक्त रक्खा गया और भारतीय वस्त्र के आयात पर ब्रह्मा में १०% से अधिक आयात कर न लगाने की नीति निर्धारित की गई। इसी प्रकार भारतीय शक्कर के आयात कर न लगाने की नीति निर्धारित की गई। इसी प्रकार भारतीय शक्कर के आयात को ब्रह्मा के द्वारा सुविधा देना तथा भारत को लकड़ी का निर्यात, निर्यात कर से सुक्त कर स्वीकार किया गया। यह समझौता भी भारत की अपेन्ना ब्रह्मा के लिए ही अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ। वैसे भी भारत ब्रह्मा को निर्यात कम करता है परन्त वहाँ आयात अधिक करता है। इस समझौते से ब्रह्मा के आयात और भी बढ़ गए।

स्वतंत्रता प्राति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति स्वतंत्र रूह से अपनानी प्रारंभ की और प्रत्येक व्यापारिक समभौते में देशहित को ही सर्वोपिर रक्खा गया। विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान को व्यापारिक संबंध रखना एक कठिन काम हो गया। दोनों देशों के मध्य ज़ुब्ध राजनैतिक वातावरण का प्रमाव आर्थिक चेत्र पर भी पड़ता रहा, फिर भी पड़ोसी देश होने के नाते तथा दोनों देशों के कच्चे माल के संबंध में अनोखी स्थिति होने के कारण भारत व पाकिस्तान के व्यापारिक समभौते दोनों देश की अप्रधिक प्रगति हेतु अनिवार्य हो गए। इसलिए दोनों देशों के बीच परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर बहुत से व्यापारिक समभौते गये किए।

इस काल में भारत में श्रन्य देशों से समय-समय पर बहुत से व्यापारिक समभौते किये हैं। उन में से मुख्य-मुख्य समभौतों का संन्तित विवरण नीचे दिया जा रहा है—

- (१) भारत-त्रास्ट्रिया व्यापार समभौता—सन् १९४९ ई० में किया गया दूसरा समभौता १९५२ में किया गया त्रीर तीसरा १९५५ ई० में । इन समभौतों के अनुसार भारत त्रीर त्राट्रिया के मध्य त्रायात व निर्यात होने वाली वस्तुत्रों का निश्चय किया गया।
- (२) भारत-चेकोस्लोवािकया व्यापार समभौता—१९४६ ई० में हुन्ना दूसरा समभौता १९५३ ई० में हुन्ना । इस समभौते में भी दोनों देशों के मध्य न्नायात व निर्यात की वस्तुन्नों को निश्चित किया गया।
- (३) भारत और मिस्न के साथ १६४६ व १६५३ में व्यापारिक समभौते हुए । इसमें भी दोनों देशों की आयात-निर्यात वस्तुओं की सूची बनाई गई।

इसी प्रकार के व्यापारिक समभौते फिनलैंगड, हगरी, जर्मनी, पोलैंगड, यूगो-स्लाविया के साथ सन् १६४६ ई० में किए गए। इनमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहे, जिनमें आवश्यकतानुसार आयात व निर्यात की वस्तुओं की सूची में परिवर्तन होता रहा। सन्१६५१ ई० में भारत ने नावें के साथ व्यापारिक समभौता किया। इस देश से भारतीय शैल्पिकों को सहायता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से समभौता किया गया। भारत तथा स्वीडन के बीच १६५२ ई० में व्यापारिक समभौता हुआ। सन् १६५३ में ईराक, इएडोनेशिया तथा रूस के साथ व्यापारिक समभौते किए गए। रूस के साथ ५ वर्ष के लिए समभौता किया गया। इस समभौते में प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत और रूस का व्यापारिक समभौते में प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत और रूस का व्यापारिक समभौता आर्थिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि इस समभौते से भारत के औद्योगोकरस तथा उद्योगों के यन्त्रीकरण में काफी सहायता मिलती है। इस के साथ ही साय इसका राजनैतिक महत्व भी अधिक है। दोनों देशों के मध्य बढ़ते हुए व्यापार की सुविधा के लिए भारत और रूस के बीच नियमित व्यवस्था का भी संगठन किया जा रहा है। सन् १६५६ ई० में भारत ने चिली तथा उत्तर वियतनाम के साथ व्यापारिक समभौते किए।

भारत तथा हवाना चार्टर

दितीय युद्ध काल में विभिन्न देशों के श्राधिक चेत्र में श्रापक्षी सहयोग पर काफ़ी महत्व दिया गया है; श्रौर इसी भावना के फलस्वरूप श्रन्तर्राष्ट्रीय बेंक, श्रन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा कोष श्रादि श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाश्रों का जन्म हुन्ना। विभिन्न देशों के बीच व्यापार को सुचार रूप से चलाने के लिए एक श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ स्थापित करने का विचार किया जाने लगा। इस विचार को कार्य रूप में परिश्तत करने के लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन की एक रूपरेखा तैयार की गई। इस रूपरेखा पर विचार करने के लिए १६४७-४० ई० में करीब ५७ राष्ट्रों का हवाना में सम्मेलन हुन्ना। हवाना सम्मेलन में १४ राष्ट्रों द्वारा विचारपूर्वक तैयार किए गए एक प्रस्ताव पर हस्ताच्चर किए गये। इन में से भारत भी एक या। सन् १६५१ में श्रमेरिका ने इस प्रस्ताव (हवाना चार्टर) को स्वीकार न करने का विचार प्रकट किया श्रौर १तव ब्रिटेन ने यह घोषित । किया कि ऐसी परिस्थिति में श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के स्थापित होने की कोई श्राशा नहीं। इस चार्टर में श्रौद्योगिक देशों के विदेशी व्यापार की मात्रा बढ़ने पर काफ़ी बल दिया गया था; परन्तु पिछडे हुए देशों के श्राधिक विकास पर इस चार्टर में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। श्रौर इसी श्राधार पर इस चार्टर की श्रालोचना की गई।

फिस्कल कमीशन ने भी हवाना घोषणा-पत्र की बाँच की ह्यौर उसे यह माल्म हुम्रा जब तक भुगतानों के वर्तमान संतुलनों की कठिनाई बनी रहेगी तब तक घोषणा-पत्र भारत की व्यापारिक नीति को रूप देनें की स्वतन्त्रता पर गम्भीर सीमायें लागू नहीं करेगा । दीर्घ काल में यह भी संभव था कि भारत को ऐसी नीतियाँ बनाने के ऋधिकार से ही वंचित हो जाना पड़ता। बहुत सोच-विचार करने के पश्चात कमीशन ने यह रिफारिश की कि भारत को घोषणा-पत्र का अनुमोदन करना चाहिये वशर्ते कि अमरीका और इगलैन्ड सरीखे मुख्य आर्थिक दश भी इसका समर्थन करें ख्रौर साथ हो साथ देश की ख्रार्थिक स्थिति के खनुकुल वह नीति बनी रहें। कमीशन को यह आशा थीं कि घोषणा-पत्र में पिछुड़े देशों की अर्थिक प्रगति की शर्त को उदारतापूर्वक कियान्वित किया जायगा। कमीशन ने यह भी विकारिश को कि भारत को आयात-निर्यात कर सम्बन्धी जो रियायतें दूसरे देशों से मिलती हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिये। रियायतों की स्वीकृत के मामले में भारत को पूँजीगत वस्तुस्रों पर, स्रन्य मंशीनों खौर साधनों पर तथा स्रनिवार्य कच्चे पदार्थो पर विशेष ध्यान देना चाहिये। साथ ही साथ घरेलू ख्रौर छोटे-छोटे उद्योगों की विशिष्ट त्रावश्यकतात्रों को बो विदेशी बाजार पर त्राश्रित हैं व्यापारिक समभौतों में प्राथमिकता देनी चाहिये। किसी भी व्यापारिक समस्तीते से पहले व्यापार, उद्योग तथा अन्य सम्बन्धित स्वार्थी के प्रतिनिधियों से रियायतों के विषय में सलाह ले केनी चाहिये।

इस प्रकार भारत ने जनरल एग्रीमेन्ट वाले देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाये हैं। इन देशों का विश्व के व्यापार में ५५ प्रतिशत भाग है। यह एक बड़ी सफलता है। त्रौर सब देशों में सहयोग की भावना का प्रदर्शन है। हमारे देश ने एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत १६५४ ई० तक दूसरे देशों को पहली बार रियायतें देने की स्वीकृति दी।

Q. 1 Write a short note on exports and imports in India.

प्र०१ मारत के आयात व निर्यात पर एक संचिप्त टिप्पणी तिबिये। निर्यात की वस्तुएँ

मारत से जो मुख्य-मुख्य वस्तुयें विदेशों को भेजी जाती हैं उनमें से पहला नम्बर जूट का श्राता है। कचा जूट पहले बहुत निर्यात होता था पर कच्चे जूट को पैदा करने वाले चेत्र पाकिस्तान के श्रन्तर्गत चले जाने के कारण श्रव भारत को कचा जूट स्वयं श्रायात करना पड़ता है। जूट की निर्मित वस्तुयें श्रव भी इंगलैन्ड, श्रमेरिका, श्रास्ट्रे लिया, ब्रह्मा, पूर्वी श्रक्षीका, तथा मिश्र श्रादि देशों को भेजा जाता है। सन् १९५१ ई० को भारत ने करीब १०५ लाख रुपयों का जूट का निर्मित माल विदेशों को भेजा।

देश के निर्यात में चाय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जूट के बाद चाय ही देश को अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा देता है। हमारी चाय का सबसे बड़ा ग्राहक इंगलैंगड है। इसके परचात् अमेरिका, कनाडा, तथा आस्ट्रे लिया का।नम्बर आता है।

जहाँ तक कच्चे कृपास तथा कच्चे कपास की निर्मित वस्तु हों का प्रश्न है विभाजन के पश्चात् भारत के लिये कपास के निर्यात को बनाये रखना कठिन हो स्था है। श्रव तो भारत को स्वयं श्रपने लिये विदेशों से कपास मँगाना पड़ता है। श्रव भारत केवल छोटे तार की कपास का निर्यात इंगलैएड, जापान, तथा इटली श्रादि को करता है। कपास निर्मित वस्तु हों के निर्यात में भारत ने गत वर्षों में काफी उन्नति की है। युद्ध काल में हमारे देश ने सूती निर्मित वस्तु हों का निर्यात करना प्रारम्भ किया। तब से यह निर्यात बरावर बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय सूती वस्त्र के सबसे बड़े शहक मध्य पूर्व के देश पूर्वी श्रमीका, श्रास्ट्रे लिया, श्रीर लंका है।

तिलहन और बनस्पति तेल भी भारत से काफी मात्रा में बाहर भेजे जाते हैं। तिलहनों में मूँगफली एवसे महत्वपूर्ण है। युद्ध काल से तिलहन का निर्यात तो कम गया है क्योंकि उनकी खपत देश में ही काफी बढ़ गई है पर बनस्पति तेलों के निर्यात में काफी बढ़ गई है पर बनस्पति तेलों के निर्यात में काफी बढ़ गई।

भारतीय तम्बाक् की माँग भी विदेशों में बहुत है। विशेषकर इंगलैगड भारतीय तम्बाक् के लिये सबसे अञ्चा बाजार है। इसी प्रकार कची और पक्की खालें इंगलैगड, अमेरिका, जर्मनी, और फ्रांस, आदि देशों को मेजी जाती है।

श्रायात की वस्तुयें

जहाँ तक आयात की वस्तुओं का प्रश्न है खाद्य पदार्थों में भारत अनाज, मद्य, तम्बाक् तथा कुछ मसाले विदेशों से मँगाता है। खाद्यानों का आयात युद्ध के पश्चात् १६४६ ई० तक बढ़ता गया, इसके बाद यह कम होता गया। कची कपास, खनिज तेल, ऊन, धातुहीन वस्तुयें तथा ऊन और लकड़ी भो काफी मात्रा में बाहर से मँगाये बाते हैं। इसी प्रकार मशीनें, गाड़ियाँ स्ती तार और कपड़ा रसायन और आविषयाँ लौह धातुयें, लोहा और स्नात की वस्तुयें रंग और रोगन आदि भी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से आता है। इंगलैंगड और अमेरिका से विशेषकर मशीनें, वस्त्र, तथा बिजली सम्बन्धी यंत्र आदि आते हैं। निर्मित वस्तुयें विशेषकर इन्हीं दो देशों से आती है। खाद्यान की कमी को दूर करने के लिये अमेरिका, अर्जन्टाइना, कनाडा, आस्ट्रेलिया, टर्की, रूस और ब्रह्मा का मुख्य भाग रहा है तथा पाकिस्तान, मिश्र व सुडान से कपास का आयात होता रहा।

पाकिस्तान में खाद्य तथा कच्चे पदार्थ की ऋषिकता • है जब कि भारत श्रौद्योगिक उत्पादन श्रौर खनिक साधनों की तुलनात्मक दृष्टि से लाभदायक स्थिति में है। पाकिस्तान में केवल बड़े-बड़े उद्योगों का ही अभाव नहीं किन्तु उसमें इनके लिये त्राघार वस्तुत्रों का भी त्राभाव है। खाद्य सामग्री में भारतवर्ष की त्रौसत कमी ३० ऋौर ५० लाख टन के बीच की हैं। पाकिस्तान ५ लाख टन खाद्य सामग्री दे सकता है। भारतवर्ष को अपने जूट व्यवसाय के लिये ४० लाख कच्चे जूट की गाँठें पाकिस्तान से चाहिये। पाकिस्तान के पास भारत को जूट देने के पश्चात् भी ३० लाख गाठें विदेशों को निर्यात करने के लिये शेष रह जाती हैं। भारतीय सुती वस्र मिलों को बाहर से १५ लाख गाठें लम्बे रेशे वाली कपास की आवश्यकता है। पाकिस्तान प लाख गाठें इस प्रकार के कपास की दे सकता है। पाकिस्तान ५ अरब गज या इससे ऋधिक सूती कपड़े के लिये भारतवर्ष पर निर्भर है। इसी प्रकार ३ श्ररव ७० करोड़ पौड चीनी की त्रावश्यकता के लिये भी वह भारतवर्ष पर निर्भर रहेगा । ३० लाख टन कोयले की ग्रावश्यकता को भी उसे भारत से पूर्ण करना पड़ेगा उसे इस्पात, चमड़े का सामान, जूट की बनी हुई वस्तुत्रों, कुछ धातुर्वे तथा खनिज पदार्थं व शीशा भी भारतवर्ष से प्राप्त करना होगा । पाकिस्तान के सम्पूर्ण व्यापार को देखते हुये ये निश्चित है कि पाकिस्तान का भारत के शाथ व्यापार संतुलन रूप में है। विभाजन के पश्चात् शीव ही दोनों देशों की सरकारों ने आर्थिक जीवन को

सुरिच्चत रखने के लिये इस आवश्यकता का अनुभव किया और इस स्थिति को कमसे कम १ मार्च १६४८ तक जारी रखने का समभौता किया । समभौते की मुख्य बातें निम्न प्रकार की थीं।

- (१) दो देशों के बीच चुंगी की कोई सीमा या रुकावट न होगी।
- (२) देश के ऋंदर बनने वाले पदार्थों का कर तथा महसूल चुंगी ज्यों का क्यों रहने दिया जायगा।
- (३)मुख्य वस्तुत्रों तथा घन के स्वतंत्रतापूर्वक मेजने के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जायगी।

पाकिस्तान समभौते की शतों को पूरा करने में असफल रहा और भारतवर्ष ने २३ दिसम्बर १६४७ को कर तथा महसूल के सम्बन्ध में उसे निदेश घोषित किया। निम्नलिखित कर पाकिस्तान द्वारा लगाये गये भारतवर्ष ने भी उसी प्रकार का कदम उंठाया और भारत-पाकिस्तान के व्यापार का निस्तार निदेशी रूप में हुआ। पाकिस्तान ने निम्न प्रकार का निर्यात कर लगाया—

- (१) कच्चे जूट की प्रति गाँउ पर ५० रुपया निर्यात कर
- (२) कच्चे कपास की ४०० पौंड की प्रति गाँठ पर ६० रुपया निर्यात कर
- (३) १०% मूल्यानुसार निर्यात का कच्ची खाल श्रीर चमड़े पर
 - ' (४) १०% मूल्यानुसार निर्यात कर।बिनौलों पर

यह स्पष्ट है कि यह कच्चा माल मुख्यतर भारतवर्ष, जो भारतीय फैक्टरियों में सामान तैयार करने या कुछ दशाश्रों में जूट की भाँति बाहर भेजने के काम श्राता था। इन करों में नाम मात्र की वृद्धि, भारतीय तथा विदेशी उपभोक्ताश्रों के मूल्य पर पाकिस्तान की वार्षिक श्राय भें वृद्धि करनी हैं। यदि इन करों का प्रभाव निर्यात से पूर्व इन वस्तुश्रों के मूल्य में कमी करने के लिये हैं तो इसका कुछ श्रंश पाकिस्तान के उत्पादकों एवं निर्यातकर्त्ताश्रों को सहना होगा। सार रूप में यह कह कर श्रायात करने वाले को देना पड़ेगा। माल से बनने वाले सामान की दरों में भारत में वृद्धि करनी पड़ेगी। मारतीय। संघ द्वारा लगाये गये नवीन निर्यात कर निम्न प्रकार हैं—

- (१) २५ प्रतिशत मुल्यानुसार कर करवे के उत्पादन के अतिरिक्त सूती कपड़े और सूती वागे पर
 - (२) ८० ६० प्रति टन तिलइन पर
 - (३) २०० ६० प्रति टन वानस्पतिक तेलों पर
 - (४) २० व० प्रति टन मैगनीब पर

हमारा लगभग श्राघा सूती कपड़ा श्रौर सूत पाकिस्तान को चला बाता है।
यह कर रहिंद्ध पाकिस्तान के उपभोक्ताश्रों पर पड़ेगी। बहाँ तक श्रन्य वस्तुश्रों से
सम्बन्ध है यह सम्भव है कि पाकिस्तान कुछ दानस्पतिक वस्तुयें लेगा। किन्तु मेंगनीब
श्रौर तिलहन को पर्याप्त मात्रा में नहीं लेगा। इससे यह बात होती है कि भारतवर्ष
द्वारा लगाया हुश्रा निर्यात कर राज्य की श्राय के लिये उन वस्तुश्रों पर है बो
विदेशों को निर्यात की बाती हैं। इनमें पाकिस्तान का भाग बहुत कम है जब कि
पाकिस्तान द्वारा लगाया गया निर्यात कर केवल भारत-पाकिस्तान के व्यापार पर
प्रभाव डालता है।

मारत पाकिस्तान के व्यापार का भविष्य प्रायः श्रानिश्चित ही है। इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों के मध्य समय-समय पर सममौते होते रहते हैं। श्रोर उन्हीं के श्रमुसार व्यापार चलता है। जब तक काश्मीर की गुल्यी नहीं सुलेमती तब तक भारत-पाक व्यापार भविष्य के बारे में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं जा सकता।

पाकिस्तान बनने के बाद भारत के बिदेशी व्यापार का खास केंचा अपने मौलिक रूप से बिलकुल ही बदल गया है। देश के विभाजन से मारत के कच्चे जूट, कच्ची रुई, खाल ग्रौर चमड़े जैसी वस्तुत्रों का निर्यात कम ही नहीं हो प्या है, श्रिपित श्रंव भारत को इन वस्तुश्रों को पर्याप्त मात्रा में मँगवाना पड़ता है। वर्तमान काल में विश्व के सब देशों से इसे ही सबसे अधिक कच्चा जूट विदेशों से मँगवाना पड़ता हैं। जहाँ तक खाद्यानों का सम्बन्ध हैं विभाजन से देश पर बुरा प्रभाव पड़ेर है। विभाजन के बाद देश खाद्यान के लिये दूसरे देशों पर पहले से अधिक निर्मर हो गया है। यद्यि हमारे देश का न्यापार साम्राज्यवादी देशों के साथ प्रमुख रूप से चालु है बिन्तु अमेरिका तथा दूसरे विदेशों से हमारा व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। हमारें देशी व्यापार के भुगतान के !सन्तुलन की दशा बिगड़ती जा रही है। यह बुरी दशा का लच्च है। विशेषकर दुर्लभ मुद्रा वाले देशों के साथ व्यापार करने पर भारत के पास डालर की बहुत कभी है। इस 'विषय में पाकिस्तान की दशा बहुत श्रव्ही है क्यांकि यह निर्यात करने वाला है। भारत जनसंख्या की श्रिधिकता के कारण निर्यात करने की अपेद्धा आयात कर रहा है। निर्यात में सबसे बड़ी बाधा नियति योग्य वस्तुर्ज्ञों के लिये , ऋधिक बढ़ी हुई घरेलू माँग छौर विदेश में भेजी जाने वाली वस्तुत्रों की ग्रासन्तोपजनक व्यवस्था ग्रौर महगा होना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जिससे हम अपना निर्यात नहीं बढ़ा सकते हैं यह है कि बेचने वाला खरीददार बन गया हैं। भारत की वस्तुओं के मूल्य में काफी तेजी होतीं जा रही है श्रीर विश्व की वस्तुओं का मूल्य गिरता जा रहा है। कच्चे माल के महँगे होने के कारण श्रीर यातायात के तेज तथा मजदूरी श्रीर महगाई श्रीर टैक्सों के श्रधिक होने

के कारण वस्तुयं तेज पड़ रही हैं । विभाजन के बाद भारत श्रौद्योगिक वस्तुश्रों का ही निर्यात कर सकता है । पहले की तरह कच्चे माल का नहीं । श्रव भारत वस्तुश्रों का निर्यात तभी कर सकता है जब यहाँ की बनी वस्तुयें सस्तो हों । वस्तुश्रों को उत्तमता के सम्बन्ध में यह बात है कि भारतीय व्यापारियों को श्रपने उत्तरदायित्व का ध्यान स्वकर श्रपने नैतिक त्तर को बढ़ाने का उद्योग करना चाहिये । यद्यपि श्रायात के मुगतान के सन्तुलन से दशा मुधारी जा सकती है किन्तु इसके लिये बहुत कम मुगतान के सन्तुलन से दशा मुधारी जा सकती है किन्तु इसके लिये बहुत कम मुजायश है । मारत खाद्यान, मशीनरीं, तथा दूसरी श्रावश्यक वस्तुश्रों के लिये विदेशों पर निर्भर है । देश के हित को ध्यान में रखकर विलासता की वस्तुश्रों में कमी कर श्रधिक से श्रधिक निर्यात करने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिये । निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये भारत ने सन् १६४६ में मुद्रा का मूल्यन कर दिया । भारत के व्यापारिक सन्तुलन के लिये निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये श्रौर भी श्रनेक श्रयत्न किये जा रहे हैं । प्रयत्न दो दिशाश्रों में हो रहे हैं—

- (१) सभी विदेशों के निर्यात करने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना।
- (२) दुर्लभ मुद्रा वाले देशों को निर्यात करने वाले प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना।

सभी विदेशों को वस्तु भेजने के लिये जो प्रयत्न किये गये हैं उनमें से कुछ, यह हैं—२०० से अधिक वस्तुओं पर से नियन्त्रण हटाया गया है। विदेश में वाण्डिय प्रतिनिधित्व को हद किया गया है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भारतीय वस्तुओं का प्रचार करना। निर्यात के लिये किये गये आन्दोलन की सर्व-प्रथम सहायता करना, देश-देशान्तरों में व्यापारिक शिष्ट मण्डल भेजना, तथा दूसरे देशों से व्यापारिक समभौता करना इत्यादि है। और प्रयत्नों के जो सुभाव दिये गये हैं उनमें से विदेश स्थित व्यापारी प्रतिनिधियों के कार्यालयों में भारतीय वस्तुओं की अर्थानी भवनों (Show 100m) का खोलना तथा ब्रिटिश एक्सपोर्ट ट्रेड औंर्मनाइ जेशन (ब्रिटिश निर्यात व्यापार संगठन) जैसा एक संगठन स्थापित करना और विदेशों को मेनी जाने वाली वस्तुओं की उत्तमता के स्तर को बढ़ाना इत्यादि हैं। दूसने वस्तुओं के सम्बन्ध में यह बात है कि सुलम मुद्रा वाले देशों के लिये जिन वस्तुओं पर नियन्त्रण लगा हुआ है वे दुर्लम मुद्रा वाले चेत्रों को बेरोक-टोक मेनी जा सकती हैं। और इस प्रकार के चेत्र के लिये जूट की वस्तु तेल, तिलहन, और वस्त्र इत्यादि का कोटा उदारतापूर्वक निश्चत किया गया है।

भविष्य में भारत-पाक व्यापार प्रगति की श्रोर ही बढ़ेगा। जिस प्रकार इन दोनों देशों में मैंत्री बढ़ती जायगी उसी प्रकार व्यापार भी बढ़ता जायगा।

ं गत रेप वर्षों में भारतीय विदेशी व्यापार की परिस्थितियों में काफी परिवर्तन

हो गया है। २५ वर्षों से पहिले भारत विदेशों से विशेषतः परके माल का आयात करता था जिसमें वस्त्र, लोहे का सामान, यन्त्र, घिंदगाँ, चमड़े का सामान, शीशे व विसातलाने का सामान, कपड़ा सीने की मशीनें. मोटरें, साइकिल, कपड़ा सीने की मशीनें, तेल. साबुन. दवाइयाँ, कागज, शक्कर, दियासलाई आदि वस्तुएँ सम्मिलित होती थी। परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया ख्रौर देश में नये-नये कारखाने खुलते गये, पक्के माल का आवात कम होता गया. कच्चे औद्योगिक माल का आयात बढता गया। उदाहरण के लिए सन् १६३०-३१ में कच्चे माल का आयात ऊल आयात का १० प्रतिशत या जो १२३६-४० ई० में २२ प्रतिशत हो गया, इन्हीं दिनों में पक्के माल के त्रायात का प्रतिशत ८० से केवल ५६ रह गया। युद्ध काल में उनके माल का आयात और भी कम हुआ। सन् १६४०-४१ ई० में पक्का माल ७० करोड़ रुपयों का आयात किया गया जब कि सन् १६४४-४५ ई० में यह आयात ६५ करोड़ रुपयों का रह गया । कच्चे माल के ऋायात में बुद्धि इस काल में भी बनी रही। इसके ऋायात का मूल्य ४२ करोड़ से बढ़ कर ११७ करोड़ हो गया था। खाद्य पदार्थ का आयात भी १६४४-४५ ई० में १६४०-४१ की अपेदा कम हुआ, पर बाद में बदने लगा। सन् १६४५ ई० में भारत ने २२ करोड़ इपयों का खाद्य पदार्थ आयात किया जो बढकर सन् १६५१ ई० में २६२ करोड़ रुपयों के हो गया । बाद में विभिन्न प्रयत्नों के कारण देश में लाबान का उत्पादन बढ़ा; ऋतः आयात कम होने लगा। सन् १९५५ ई० में कुल ५३ करोड़ रुपयों का त्रायात हुत्रा। इसी साल कच्चे माल का त्रायात १६३ करोड़ तथा पक्के माल का आयात ४२७ करोड़ रुपयों का हुआ।

इसी प्रकार निर्यात व्यापार में भी काफी परिवर्तन हुआ है। २५ वर्षों पहले भारत मुख्यत: खेती की पैदावार तथा औद्योगिक कच्चे माल को बाहर भेजता था। निर्मित माल का निर्यात बहुत कम होता था, पर खेती की पैदावार तथा औद्योगिक कच्चे माल के निर्यात में उत्तरोत्तर कमी होती गई और निर्मित माल का निर्यात वीरे-घीरे बढ़ता गया। सन् १६३०-३१ ई० में कच्चे माल का निर्यात कुल निर्यात का ४० प्रतिशत था जो १६३६-४० ई० में ४३ प्रतिशत हो गया। इसी काल में पक्के माल का निर्यात २८ प्रतिशत से बढ़कर ३८ प्रतिशत तक हो गया। युद्ध काल में यह निर्यात और भी बढ़ा। सन् १६४०-४१ ई० में पक्के माल का निर्यात ८८ करोड़ रुपयों का था, जो बढ़कर सन् १६४४-४५ ई० में ११६ करोड़ हो गया। कच्चे माल का निर्यात, इसके विपरीत ६८ करोड़ रुपयों से घटकर ५८ करोड़ रुपया रह गया। परन्तु कुल निर्यात क्यापार इसी काल में ६८ करोड़ से बढ़कर २२७ करोड़ का हो गया। निर्यात की।मात्रा में उत्तरोत्तर बढ़ती हो गई। सन् १६५५ ई० में कुल निर्यात ५७६ करोड़ रुपयों का कच्चा माल तथा २४७ करोड़ रुपयों के खाद्य पदार्थ, १६७ करोड़ रुपयों का कच्चा माल तथा २४७ करोड़ रुपयों का पक्का माल निर्यात किया गया

गत २५ वर्षों के प्रारम्भिक काल में भारत विदेशों से बहुत सी वस्तुएँ मँगाया करता था पर निर्यात थोड़ी ही वस्तु का करता था। निर्यात में विशेषकर जूट, कपास, अनाज. तिलहन, खालें, और चाय आदि वस्तुएँ होती थीं। इन वस्तुओं के महत्व में घीरे-घीरे परिवर्तन होता वरहा। कपास का निर्यात कम होता गया, १६२०-२१ में भारत ने ४१६३ लाख रुपये के कपड़े का निर्यात किया कब कि सन् १६३८-३६ ई० में यह निर्यात केवल २१८२ लाख रुपयों का रह गया। इस समय में बूट व तिलहन का निर्यात मी कम हुआ। पर चाय तथा चमड़े का निर्यात बढ़ा। द्वितीय युद्धकाल में, जूट के निर्मित माल, कची रुई, सूरी वस्त्र, चमहा, अन्नक व चाय का निर्यात बढ़ा, पर कपास, तिलहन, तेल, मैगनीज तथा तम्बाक् का निर्यात कम हुआ। युद्धकाल में आयात सभी वस्तुओं के कम रहे। ये आयात इंगलैन्ड, ब्रह्मा, लंका आस्ट्रेलिया, कनाडा, अम्मीका, अमेरिका, जापान, मिश्र आदि देशों से होते रहे। इसी काल में भारत ने इंगलेंड, ब्रह्मा, लंका, आस्ट्रेलिया आदि उपरोक्त देशों को निर्यात किया। युद्ध के पश्चात् उपरोक्त देशों से तो व्यापार की मात्रा बढ़ती ही गई, साथ ही साथ कुछ नवीन देशों से भी व्यापारिक सम्बन्ध बोढ़े गये, और शत्रु देशों से भी व्यापार बढ़ने लगा।

· इन वर्षों में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अन्य विशेषता यह रही कि इस क्यापार का सन्तुलन प्रायः भारत के पत्त में ही रहता था। भारत विदेशों से कम मृत्य का माल आयात करता था, पर अधिक मृत्य का माल निर्यात करता था। यद्यपि अनुकृत सन्तुलन की मात्रा में कमी-बेशी होती रही पर कुछ वर्षों को छोड़कर यह सन्तलन मारत के पत्त में ही श्रिधिकतर रहा । सन् १६२६ ३० ई० में लगभग ুঙ करोड़ रुपर्यों का श्राधिक निर्यात किया गया, जब कि '१९३६-४० ई० में यह श्चनुकूलता केवल ३८ करोड़ रुपयों की 'रह गई । युद्धकाल में यह श्चनुकूलता बहती गई, यहाँ तक सन् १६४३-४४ ई० में भारतीय विदेशी व्यापार का ऋन्तर ६२ करोड़ रुपर्यों से भारत के पत्त में हो गया । यद्यपि दूसरे वर्ष ही यह घट कर ४२ करोड़ क्पये के रह गया। इसके उपरान्त भारत के विदेशी व्यापार का ग्रान्तर भारत के विपद्ध में रहने लगा । सन् १६४८ ई॰ में विदेशी व्यापार का अन्तर ४२ करोड़ रुक्ये है · मारत के विषद्ध में हो गया । १९४९ ई० यह अन्तर १४५ करोड़ रुपये के लगभग हो गया । इस प्रतिकूल श्रन्तर को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा इंगलैंव के पद-चिन्हों पर चलते हुए भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया तथा डाल चेत्र से माल श्रायात करने पर कठोर नियंत्रण लगाये गये । इन तथा श्रन्य प्रयत्नों हे इसरवस्य व्यापारिक अन्तर की स्थिति में सुधार प्रारम्म हुआ। अतः १९५० ई० आकर का अन्तर ३८ करोड़ इपयों से भारत के पत्त में हो गया जो १९५१ ई॰

इस प्रकार दितीय महायुद्ध से प्रथम भारत के ७० प्रतिशत निर्वात में खाद्य सामग्री तथा कच्चे माल का समावेश रहता था, तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार का संतुलन सदैव देश के अनुकृल रहता था। पर सन् १६३१ से प्रारम्भ होने वाली व्यापारिक मन्दी के कारण यह संतुलन बीरे- बीरे कम अनुकृल होने लगा। हमारे निर्यात का मूल्य काफी कम हो गया तथा इस बाटे की पूर्ति के लिए काफी मात्रा में सोने का निर्यात हुआ। अब मारत को अपने बरेलू काम को अदा करने के लिए यही एक उपाय रह गया था। सन् १६३६ ई० तक मारत को ३६२ करोड़ स्पर्यों की लागत का सोना निर्यात करना पड़ा।

युद्ध काल में भारतीय निर्यात में काफी परिवर्तन हुआ। जूट तथा सूती वस्त्र का निर्यात्त काफी अधिक बढ़ गया क्योंकि मध्यपूर्व तथा अफीका का बाजार भारत के हाथ में आ गया। यूरोप तथा अमेरिका भारतीय चाय की माँग बहुत हुई। इस काल में देश के निर्यात का मृल्य बढ़ गया पर आयात काफी कम रहे, इसके फलस्वरूप व्यापार का सन्तुल देश के पद्ध में रहा। इन वर्षों में भारत ने अधिकांशतः अपना व्यापार साम्राज्य देशों में फैलाया। आस्ट्रेलिया, कनाडा, मिश्र, ईराक तथा मध्य पूर्व के स्टिलंग चेत्र देशों के साथ निकटतम व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गये। इन सब देशों से व्यापार का सन्तुलन भारत के अनुकूल ही रहा। इसी काल में भारत व अमेरिका के बीच व्यापार बहुत बढ़ा।

युद्धोत्तर काल में देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आरे भी परिवर्तन हुए । देश के विभाजन के !फलस्वरूप व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई क्योंकि विभाजन के पहले इन दोनों देश के मध्य का व्यापार आन्तरिक व्यापार होता या जो विभाजन के बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में परिणत हो गया । इधर युद्ध वन्द हो जाने के कारण जहाजी सुविधाएँ अधिक मिलने लगी तथा आर्थिक पुनर्निर्माण व औद्योगिक उन्नति के लिए वस्तुओं का आयात अधिक होने लगा । सन् १६४८ ई० में व्यापार का कुल योग ६२३ करोड़ रुपये के था जो बढ़ कर सन् १६५१ई० में १६०० करोड़ रुपयों के हो गया।

इन वर्षों में कच्चे माल की आयात में काफी वृद्धि हुई। पाकिस्तान बन जाने के कारण कच्चे कपास हैत्या कच्चे जूट का आयात अधिक करना पड़ा। इसी प्रकार खाद्यानों की कमी के कारण खाद्यान के आयात में भी काफी वृद्धि हुई। अर्जन्टायना, अमरीका, कैनाडा, इटली, टर्की, रूस, आस्ट्रे लिया, स्याम तथा ब्रह्मा से खाद्यानों का अधिक आयात करना पड़ा। सन् १६४८ ई० में ३० लाख टन खाद्यान बहर से आया जो बढ़ कर सन् १६५१ ई० में ५५ लाख टन हो गया। इस काल में भारत में औद्योगिक विकास का होना प्रारम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की निर्मित वस्तुओं का पर्याप्त परिमाण में निर्यात होने लगा है। क्यये के अवमूल्यन तथा अन्य सरकारी प्रयत्नों के कारण इस ^हनियति में बरावर वृद्धि ही हो रहीं हैं।

देश के त्रायात तथा निर्यात व्यापार में इंगलैन्ड का स्थान श्रव भी महत्व-पूर्ण है, पर धीरे-धीरे उसका स्थान श्रमेरिका ले रहा है तथा श्रास्ट्रे लिया, कनाडा, ब्रह्मा तथा मिश्र देश के व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखने लगे हैं। मध्यपूर्व देशों के साथ भी मारत ने व्यापारिक सन्धियाँ की हैं। सुदूर-पूर्व के देशों के साथ भी भारतीय व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ गये हैं।

इस सारे व्यापार का ६८ प्रतिशत समुद्र के द्वारा होता है। स्थल मार्ग से व्यापार की इतनी कमी का कारण यही है कि भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान. तिब्बत, मध्य-एशिया स्नादि बहत पिछड़े हए हैं स्नौर निर्धन हैं। स्नतः न तो वे भारत से अधिक खरीदते हैं और उनके पास भारत के लिए कुछ बेंचने को है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है. इन दिनों श्रायात तथा निर्यात दोनों की बृद्धि हुई हैं, परन्तु युद्धोत्तर काल में व्यापारिक संतुलन देश के विपत्त में ही रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश को खाद्यान बहुत बड़ी मात्रा में स्त्रायात करना पड़ता है, कच्चे म ल का स्रायात भी बढ गया है। निर्मित माल का स्रायात कम हो गया है। इसके विपरीत अब भारत पहले की अपेद्या कच्चा माल कम निर्यात करता है, त्रौर पक्के माल की निर्यात की मात्रा बढ़ गई है। निर्यात में चाय, जट का सामान व सूती कपड़ा मुख्य हैं, तथा श्रायात में कपास. मशीनरी, खाद्यान, रेल व मोटर गाड़ियाँ तथा रासायनिक पदार्थ मुख्य हैं। यद्धोत्तर काल में इंगलैन्ड तथा कामन-वैल्य देशों से इमारा ऋायात कम हो गया है, इनके स्थान पर कामनवैल्थ से बाहर के देशों का भाग बढ़ गया है। इसी प्रकार निर्यात में भी कामनवैल्थ देशों का भाग कम हो गया है पर अन्य देशों का महत्व ऋधिक हो गया है। विभिन्न योजनात्रों के लिए सामान तथा खाद्यात्र का आयात करने के कारण सरकार द्वारा ऋायात काफी मात्रा में किया जाने लगा है। पर प्रवृत्ति युद्ध काल में प्रारम्भ हुई। युद्धोत्तर काल में इस प्रवृत्ति में प्रगति ही हुई और ऐसा अनुमान किया जाता है कि मविष्य में राज्य द्वारा आयात का भाग बढ़ता ही जायगा। अब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापारिक समभौतों द्वारा अधिक होने लगा है तथा यह प्रवृत्ति भी भविष्य में बढेगी।

(३) द्वितीय महायुद्ध से पहिले भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की तीन मुख्य विशेषताएँ थीं। प्रथम, हमारा देश अधिकतर कचा माल विदेशों को भेजता था और विदेशों से बने हुए माल का आयात करता था। दूसरे, भारत से निर्यात किए हुए माल को भात्रा आयात होने वाले माल की मात्रा से कहीं अधिक रहा करती थी। इसके फलस्वन्य व्यापार का संतुलन देश के ऋनुक्ल रहा करता था। तीसरे, हमारा विदेशी व्यापार, ऋधिकतर इंग्लैंगड तथा राष्ट्र संघ के देशों के साथ होता था। ऋगैर सर्कारी नीति भी इसी प्रकार की ग्हा करती थी कि जिससे उन्हीं देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध से भारत को लाभ रहे।

द्वितीय महायुद्ध तथा उसके बाद के काल में विदेशी व्यापार की उपरोक्त तीनों विशेषतात्रों में परिवर्तन हो गया। अब हमारा देश कच्चे माल का निर्यात पहिले से बहत कम करता है और निर्मित माल का निर्मात पहिले अधिक करता है। विदेशों से कारखानों में काम आने वाले औद्योगिक कच्चे माल का आयात ही अब अधिक होता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार का संतुलन देश के पन्न में नहीं रहता वरन् विपच्च में ही रहता है: अर्थात् इस काल में भारत विदेशों से अधिक मूल्य का माल ऋग्यात करता है और बदले में कम माल निर्यात करता है। डालर तथा स्टर्लिंग दोनों ही चेत्रों के साथ व्यापार का संतुलन देश के विपन्न में रहता है। दितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस स्थिति की ग्रौर भी ग्रधिक विकट हो जाने की संभावना है। क्योंकि इन वर्षों में भारत विदेशों से बहुत ऋधिक मूल्य की मर्शीनें, लोहा, रसायनिक पदार्थ तथा श्रौद्योगिक कचा माल मँगायेगा, जिससे हमारे देश का श्रीयोगीकरण शीव्रता से हो सके । श्राजकल भारत का व्यापार केवल इंग्लैएड तथा राष्ट्रसंघीय देशों के साथ ही सीमित नहीं रहा वरन् उसका च्रेत्र बराबर बढ़ता ही जा रहा है। मध्यपूर्व तथा सुदूर पूर्व के देशों में हमारा निर्यात बराबर बढ़ रहा है श्रीर श्रमरीका से हमारे श्रायात की मात्रा बरावर श्रधिक हो रही है। योरुप के साम्यवादी व प्रवातंत्र देशों के साथ भी भारतीय सरकार ने त्रानेक व्यावहारिक सभकौते किए हैं। श्रीर वस्तु विनिमय के श्राधार पर हमारा व्यापार इन देशों के साथ निरंतर बढ रहा है।

इस प्रकार, गत १५ वर्षों में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ सामने त्राई जिनके कारण भारतीय विदेशी व्यागर की कुल मात्रा तथा उसके स्वरूप में भारी परिवर्तन हो गए। पिछले महायुद्ध के समय जहाजों की कमी शत्रु-भय तथा मित्र राष्ट्रों में स्वयं त्रपने यहाँ युद्ध तथा जनता की त्र्यावश्यकता के लिए बने हुए माल की भारी माँग के कारण विदेशी माल का त्र्यायात इस देश में बहुत कम हो गया। इसके विपरीत हमारे कच्चे माल जैसे रुई, पटसन, त्रानाज, चाय लोहा, चमड़ा, खिनज, रबड़, तिलहन हत्यादि की माँग विदेशों में बहुत ऋधिक बढ़ गई। इसके फलस्वरूप बहाजों की कमी तथा हर प्रकार के नियंत्रण होने पर भी हमारे देश से मित्र राष्ट्रों की बहुत ऋधिक मात्रा में माल का निर्यात हुत्रा; परन्तु इन देशों से हमारे देश में बने हुए माल का त्र्यात बहुत कम हुत्रा। इससे भारत को २ लाम पहुँचे। पहिले तो हमारा देश जो इग्लैएड का ऋणी था जिसे लगभग १३ ऋरच स्पए ऋण चुकाना था वह

स्रव साहूकार देश बन गया श्रीर व्यापार संतुलन की श्रनुकूलता होने के कारण इन्लैग्ड लगभग १६ स्रारव रु० से भारत का ऋगी बन गया। दूसरे, इन्लैग्ड तथा स्रन्य देशों से स्रायात में कभी हो जाने के कारण हमारे देश में स्रनेक नए उद्योगों की स्थापना हो गई श्रीर युद्ध काल में इन कारखानों ने खूब लाभ कमाया। इसके साथ ही साथ बर्मनी तथा जापान की हार से भारतवर्ष ने मध्य पूर्व तथा सुदूर पूर्व के देशों में स्थापनी बस्तु श्रों के लिए एक विस्तृत बाजार प्राप्त कर लिया। युद्ध से पूर्व बापान का स्ता माल इन देशों में प्रायः बिका करता था। युद्धोत्तर काल में इन सब देशों में भारत के बने हुए माल की माँग बढ़ने लगी।

उपरोक्त अनुकृल परिस्थितियों के साथ ही साथ इसी समय कुछ प्रतिकृल परिस्थितियाँ मी उपस्थित बनी रही जिनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत को पूरा-पूरा लाम न हो सका। उदाहरण के लिए सन् १६४७ ई० में विभाजन के फलस्वरूप तेल, अनाज, चावल, पटसन आदि बहुत सी निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ पाकिस्तानी चेत्र में चली गई और अब भारत को भी इन वस्तुओं का आयात करना पड़ा। साथ ही साथ युद्ध के पश्चात् विदेश की बनी हुई सस्ती वस्तुओं का आयात पुनः प्रारंभ हो गया जिससे भारतीय कारखाने कुछ सीमा तक बन्द हो गए। इस प्रकार निर्यात की मात्रा में कभी होने तथा आयात की मात्रा में वृद्धि होने से व्यापार संतुलन देश के विपन्न में हो गया। यदि हम सन् १६४६ ई० से लेकर १६५५ ई० तक के आँकड़ों को देखे तो यही पता चलता है कि इन सारे वर्षों में व्यापार का संतुलन हमारे विपन्न में रहा।

इन वर्षों के प्रतिकृत व्यापारान्तर का भुगतान भारतवर्ष पौएड पावने की रक्तम, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य विदेशी सहायता के द्वारा करता रहा। इसके फलस्करूप इमारे पौएड पावने की बाक्री अब केवल ७०० करोड़ ६० रह गई है। पिछुते ५ वर्षों में हमें लगभग ३०० करोड़ ६० की विदेशी सहायता भी प्राप्त हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक तथा मुद्रा कोष से भारत को अपूर्ण भी प्राप्त हुआ है। इस बनराशि से देश ने अधिक आयात का भुगतान किया। परन्तु यह स्थिति बहुत दिनों तक इसी प्रकार नहीं चल सकती। इसलिए केन्द्रीय सरकार यथाशक्ति आयात की मात्रा कम करने के लिए और निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रही।

श्रायात कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत से नियंत्रण लगाए गए। अनावश्यक तथा विलासिता की वस्तुओं का श्रायात यथासंभव बंद किए गए और श्रायात होने वाली श्रावश्यक वस्तुओं को देश में ही निर्माण करने का प्रयत्न किया बाने लगा। इस संबंध में श्रानेक पए कारखाने विदेशी एँजी के सहयोग से स्थापित किए गए। ऐसे उद्योगों में तेल शोधक बर्मा शैल, स्टेएडर्ड-वैकुश्रम व

काल्टैक्स के कारखाने, मोटर उद्योग, साइकिल फैक्टरियाँ, रसायनिक व दवाई के उद्योग प्रमुख हैं। दूसरी ऋोर निर्यात को हरेक प्रकार से प्रोत्साहन दिया गया। ऋनेक वस्तुऋों के निर्यात के लिए निर्यात दिक'स-परिपद् स्थापित कर दी गईं। विदेशों में भारतीय वस्तुऋों की माँग को बढ़ाने के लिए व्यापारिक एजेंट तथा दूत नियुक्त कर दिए गए हैं जो ऋपने दूतावासों में मारतीय वस्तुऋों का प्रदर्शन करते हैं तथा ऋौद्योगिक प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं।

ऐसा अनुमान किया जाता है कि कुछ देत्रों में भारत अपनी निर्यात की वस्तुओं को और भी आगे बढ़ा सकेगा। उदाहरण के लिए बिबली का सामान, बिबली के मोटर, मिलाई की मशीने; सेनिटरी का सामान, छोटी-छोटी मशीनें, रसायिनक सामान, सीमेट, लोहे, शीशे व चमड़े का सामान, दवाहयाँ, कपड़े हाथ करवे तथा अन्य प्रह उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात अधिक मात्रा में विदेशों को हो सकेगा।

पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी बाधा श्रों के होते हुए भी भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी उन्नति हुई है। सन् १६३० के आसपास देश के वैदेशिक व्यापार की कुछ मात्रा ३०० करोड़ ६० के लगभग हुआ करती थी। आजकल यह मात्रा बढ़कर १३ अरब ६० की हो गई है। यदि वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों का भी ध्यान रक्खा जाय तो भी यही निष्कर्ष निकलता है कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की कुल मात्रा में काफी वृद्धि हो गई है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी सुधार हुआ है। अनाज व रुई का आयात बहुत कम हो गया है। इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में देश प्रायः स्वावलम्बी बनता जाता है और इस प्रकार करोड़ों क्यये की लागत का आयात बन्द होता जा रहा है। सैन् १६५१ ई० में इस आयात का मूल्य २१७ करोड़ ६० के लगभगथा जो १६५५ ई० में केवल ६६ करोड़ ६० का रह गयः। इसी प्रकार जूट की पैदावार भी बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। निर्यात के चेत्र में भी हमारे देश के सम्मुख एक बहुत बड़ा चेत्र पड़ा हुआ है और आशा है कि विभिन्न निर्यात विकास परिषदों की सहायता से इस स्थित का पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न किया जायेगा। देश को आयात कम तथा निर्यात अधिक करने की बड़ी आवश्यकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए बहुत सा सामान विदेशों से मँगाना है। इसके लिए दुर्लभ विदेशी मुद्रा तभी प्राप्त की जा सकती है जब कि इम अपने निर्यात को बढ़ावें तथा प्रत्येक सभव उपाय से अनावश्यक वस्तुओं के आयात को रोकें।

शोधनाशेष (Balance of Payments)

शोधनाशेष का अर्थ एक ऐसे विवरण से हैं जिसमें आयात-निर्यात एवं उन आयात-निर्यातों का मूल्य लिखा रहता है। इस विवरण के दायीं खोर आयात का सिवस्तार न्यौरा दिया जाता है और बाई ओर निर्यातों का सम्पूर्ण उल्लेख रहता है। संत्तेष में शोधनाशेष में एक ओर उन ब्योरों (items) को दिखाया जाता है जिन पर निदेशियों से प्राप्ति होनी है और दूसरी ओर ने ब्योरे होते हैं जिन पर निदेशियों को भुगतान करना है। यह ं निर्धिक आधार पर बनाया जाता है और पूर्वनिश्चित निनिमय दर पर इनका मूल्य लगाया जाता है।

इन विवरणों में निर्यातों को श्रोर (१) वस्तुश्रों का निर्यात, (२) सेवाश्रों का निर्यात, (३) विदेशी ऋणों तथा विनियोगों से प्राप्त होने वाली श्राय, (४) विदेशी यात्रियों द्वारा देश में किया जाने वाला व्यय, (५) विदेशियों से प्राप्त होने वाले सुग्रावजे, युद्ध-व्यय, दान, दंड इत्यादि, (६) श्रन्य प्रकार के भुगतान । श्रायातों में (१ वस्तुश्रों का श्रायात, सेवाश्रों का श्रायात, (३) विदेशियों को ऋण, व्याज व लाम चुकाने के भुगतान, (४) देश के यात्रियों द्वारा विदेशों में किया जाने वाला व्ययं, (५) विदेशों को दिए जाने वाले मुश्रावजे, दान, दंड श्रादि (६) श्रन्य प्रकार के भुगतान।

इस शोधनाशेष में दृश्य श्रीर श्रदृश्य (visible and invisible) श्रायात श्रीर निर्यातों का विवरण रहता है श्रीर इस प्रकार से इसका संतुलन (balance) सदैव बना रहता है।

व्यापार-शेष (Balance of Trade) शोधनाशेष से कुछ भिन्न हैं क्यों कि व्यापार-शेष में केवल दृश्य (visible) श्रायात निर्यात ही जाते हैं। श्रतः इसके श्रायात श्रीर निर्यात पत्नों का शेष (balance) मिलना श्रावश्यक नहीं। श्रायात श्रीषक हो सकते हैं तो कभी निर्यात। यदि निर्यातों का मूल्य श्रायात मूल्य से श्रीधक है तो व्यापार-शेष श्रतुक्त श्रयवा धनात्म (Favourable of Positive Balance of Trade) कहा जाता है। इसके निपरोत यदि देश के श्रायातों का मूल्य निर्यात मूल्यों से श्रीधक है तो इस व्यापार शेष को प्रतिकृत या श्रूणात्मक व्यापार-शेष (Unfavourable Adverse of Negative Balance of Trade) कहा जाता है। श्रतः व्यापारशेष कभी तो श्रनुक्त हो सकता है श्रीर कभी प्रतिकृता। यदाकदा ही यह शेष संतुत्तित होता है।

निम्नांकित तालिका में भारत के व्यापार शेषों की स्थिति सन् १९५६-५७ से १९५७-५८ के प्रथम ६ मास तक दी गई हैं:—

भारत के व्यापार-श्रोष (करोड़ रुपए)

ऋपैल जून	जुलाई सितम्बर	श्चक्टूबर दिसम्बर	बनवरी मार्च	योग	श्रप्रैल जून	जुलाई चितम्बर योग	
(१) स्त्रायात २३०	580	839	३०६	20191	8 3 2 3	CC3 225	

(२) निर्यात १५४ १३५ १७२ १७६ ६३७ १४० १२७ २६७

व्यापार-शोप -७६ -११२ -१२२ -१३० -४४० -१८३ -१७२ -३५४

ये व्यापार-शेष किस प्रकार अनुकूल किए जाते हैं ये हम यथास्थान इसी पुस्तक के अध्याय १३ में वर्णन कर चुके हैं।

प्रश्न

- 9. व्यापार मंतुलन (Trade Balance) एवं शोधनारीय (Balance or Payments) में क्या अन्तर हैं ? रस अतर का क्या महत्व हैं ? (अगरा बीच एक १६५७)
- व्यापारिक शेष सिद्धांत पूर्णास्थांत को शिक्षा प्रकार प्रगट नहीं करता ? उस प्रथन की भारत तथा इंगलैंड की स्थिति की ध्यान में रखते हुए समक्ताइए ? (आगरा बाट एक १६७६)
- 3. What specific information does the study of nation's halance of payments yield?

 (Agra B. A. 1959)

अध्याय १६

राष्ट्रीय आय, बचत, विनियोग और पूर्ण वृत्ति

(National Income, Savings, Investments and Full Employment)

ाप्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय अथवा लाभांश का तात्पर्य उस सतत प्रवाह से होता है जो कि देश के समस्त निवासियों के वस्तुओं और सेवाओं के संचय से प्राप्त होती है। पीगू के अनुसार, "राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सिम्मिलित होती है, जिसकी मुद्रा में माप हो सकती है। National Dividend is that part of the objective income of the Community, lincluding of course income derived from abroad, which can be measured in money"—Pigou. इस प्रकार पीगू ने उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा है जिनकी कीमत सुद्रा में न मापी जाए। उदाहरखार्थ माता-पिता या पत्नी की निशुलक सेवाएँ अथवा मित्र की कृतज्ञता। कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार राष्ट्रीय आय में से ऐसी आय को निकाल दना चाहिए जो कि बिना सेवा के प्राप्त की गई है जैसे दान या पेशन से प्राप्त आय। कुछ अधिकारी सरकारी अधिकारियों की सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्पित्तित नहीं करते हैं। परन्तु मार्शल ने देश के सब प्रकार के उत्पादन से प्राप्त होने वाली आय को (चाहे वह भौतिक वस्तुओं के रुप में हो अथवा अभौतिक वस्तुओं के रे राष्ट्रीय आय में जोड़ा है।

मार्शल के दृष्टिकोण को अपनाती हुई दूसरी परिभाषा फिशर (Fisher) की है—"National Dividend of Income consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from their human environment". राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय में, उपमोक्ताओं को प्राप्त होने वाली सेवाएँ सम्मिलित हैं चाहे वे भौतिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई हो अथवा मानवीय प्रयत्नों से।"

डा॰ बी॰ के॰ त्रार॰ बी॰ राव का विचार है कि राष्ट्रीय त्राय वस्तुत्रों श्रीर सेवाग्रों की घारा के मुद्रा-मूल्य द्वारा स्चित होती है। उनके श्रनुसार सभी

कीमतें चालू कीमतों के आघार पर आँकी वाती हैं परंतु उन आयातों को नहीं बोड़ा वाता को कि बिकी के लिए किए गए हैं। हा॰ राव का विचार क्लार्क की परिभाषा से मेल खाता है जो कि इस प्रकार है "किसी समय विशेष में राष्ट्रीय आय उन सेवाओं और वस्तुओं के मुद्रा-मूल्य द्वारा स्चित की जाती है जो उस समय में उपभोग के लिए प्राप्य है, ये मूल्य उनकी वर्त्तमान विकय कीमत पर निकाला जाता है। पूँची की उस वृद्धि को मिलाया जाता है जो नए पूँची गत माल के मूल्य के रूप में जुका दिया गया है। इसी प्रकार पूँची की घटोतरी (depreciation) और विसावर (obsolescence) को घटा दिया जाता है।"

राष्ट्रीय ऋाय को निम्नांकित शितयों द्वारा मापा वा सकता है—(१) उत्पत्ति गग्ना प्रगाली (Census of production method)-इसके त्रांतर्गत इम किसी एक उद्योग श्रथवा फर्म की शुद्ध उपज निकालते हैं। ऐसा करने के लिए सकल (Gross) उपज में से विकी आदि निकाल दी बाती है। इसी प्रकार देश के समस्त उद्योगों एवं व्यवसायों की शुद्ध उपच (Net products) निकाल कर राष्ट्रीय श्राय जात कर सकते हैं। इस ग्रुद्ध उजप में से प्रयुक्त मशीनरी इत्यादि की घटोतरी एवं अपन्य साधनों संबंधी न्यय घटा दिये जाते हैं। (२) श्राय गराना प्रसाली (Census of Incomes methods)—इस प्रकाली में देश वासियों की चाहे वे श्राय कर देते हो य न देते हों, स्त्राय का योग निकाला जाता है। इन स्त्रायों का योग (जो देश के सभी परिवारों की पृथक-पृथक आय की गणना करके निकाला जा सकता है। राष्ट्रीय श्राय का प्रतीक है। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि कोई श्राय या श्राय का ऋंश दुवारा न गिना गया हो । (३) व्यावसायिक गराना प्रसाली (Occupational census method)—विभिन्न उत्पादक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों की अव की गगाना की जाती है परंत कोई स्त्राय की दो बार गगाना न की जानी चाहिए। इन सब का योग राष्ट्रीय श्राय को सूचित करता है। स्टाम्प के श्रनुसार इस श्राय की ज्ञात करते समय युद्ध के समय के भत्ते, बृद्धायस्था पेशन फंड (Old age pensions) सम्मिलित नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये श्राय व्यावसायिक श्राय नहीं है। (४) चौथो प्रणाली में उत्पादन गणना श्रौर श्राय गणना दोनों ही का छंयुक्त प्रयोग किया जाता है।

इन प्रणालियों में से किसका प्रयोग किया जाए यह वहाँ के प्रयोक्ताओं एव उनके उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि सावधानीपूर्वक काम लिया जाए तो समं प्रणालियाँ उचित एवं शुद्ध परिणाम पर पहुँचती हैं परंतु व्यवहारिक रूप र उत्पत्ति गणना प्रणाली और व्यावसायिक गणना प्रयाली ऋषिक प्रचलित है क्योंनि इनमें आय को दुवारा गिनने की कम मुंबायश है। राष्ट्रीय त्राय एवं त्रार्थिक कल्याण परस्पर संबंधित हैं। इस परस्पर संबंध को एवं राष्ट्रीय त्राय के त्रध्ययन का महत्व हम इस प्रकार समक्त सकते हैं:—

राष्ट्रीय श्राय संबंधी श्राँकड़े हमें देश के जीवन स्तर एवं देश के कल्याण का स्तर के संबंध में विषय सूचना देते हैं। देश की श्रार्थिक प्रगति किस गित से हो रही हैं, उसमें क्या परिवत्तन हो रहे हैं, श्रार्थिक परिस्थितियों में क्या नवीनताएँ श्रा रही हैं एवं उनका देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी बातें इस अध्ययन से जात होती हैं। दूसरे श्राय संबंधी श्राँकड़ों को देख कर हम यह पता लगा सकते हैं कि देश का श्रार्थिक विकास समुचित श्राधार पर हो रहा है श्रथवा नहीं या श्रार्थिक विकास की सामान्य प्रवृत्ति क्या है १ तीसरे, राष्ट्रीय श्राय के श्राँकड़े देश के श्रार्थिक, व्यापारिक श्रौद्योगिक, प्रशुल्क नीति में सहायक होते हैं बो हमारी श्रर्थ-व्यवस्था में दोषों को यदि कोई हैं, स्पष्ट करती है।

भारत की राष्ट्रीय आय

भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान समय-समय पर लगाए जाते रहे हैं। दादाभाई नौरोजी ने सन् १८६७-७० के अनुमान ज्ञात किए जिनके अनुसार राष्ट्रीय आय २० रुपया प्रति व्यक्ति रही थी। लार्ड कर्जन के अनुसार सन् १६०० में प्रति व्यक्ति आय ३० रुपया आँकी गई। सन् १६३१-३२ में डा० वी० के० आर वी० राव ने ६५ रुपया प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। यह अधिक सही अनुमान माना जाता है। उन्होंने ग्रामीण चेत्रों और नागरिक चेत्रों की आय का पृथक पृथक अनुमान लगाया था। सन् १६३७-६८ में सर जेम्स ग्रिंग के अनुसार प्रतिव्यक्ति आय ५६ रुपया थी।

स्वतत्रता प्रांति के पश्चात् राष्ट्रीय श्राय की गर्णना की गई श्रौर श्रिधिक वैज्ञानिक एवं सुसंगठित कदम उठाए गए। वाणिष्य मंत्रालय के श्रनुसार भारत संघ में
प्रांति व्यक्ति की श्राय २०४ रुपया गिनी गई। परन्तु इसके पंचवर्षीय योजना काल में
राष्ट्रीय श्राय की गर्णना का महत्व श्रौर भी श्रिधिक बढ गया। इस बढ़ते हुए महत्व
को देखते हुए सरकार ने १६४६ में राष्ट्रीय श्राय समिति (National Income
Committee) की स्थापना की जिसका काम राष्ट्रीय श्राय संबंधी श्राँकड़ो में मुचार
के सुकाव देना एवं श्रिधक वैज्ञानिक रीति से राष्ट्रीय श्राय का पता लगाना है। इस
समिति की रिपोर्ट के श्रनुसार विभिन्न वर्षों में प्रति व्यक्ति श्राय इस प्रकार थी।

१६५३-५४—२४७ रुपए १६५१-५२—२७४.५ रुपए १६४२-५३—२६७ १६४८-४६—२४७ इन आँकड़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय लगातार बढ़ रही है परन्तु १६५२-५३ में पिछते वर्ग से प्रति व्यक्ति आय घटी जिसका कारण जनसंख्या में बृद्धि है। सूचनांको को देखने से पता लगता है कि सन् १६४८-४६ के योक कीमतों के आघार पर सन् १९५३-५४ में कीमतों में ६ बृद्धि हुई है। इस कारणा वास्तव में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि कम रही है।

योजना त्रायोग के अनुसार सन् १५५०-५१ की तुलना में १६७४-७४ तक कुल राष्ट्रीय आय को तीन गुना तथा प्रति व्यक्ति आय दुगना कर देने का आयोजन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल समाप्त हो चुका है। इस काल में राष्ट्रीय आय में १८% वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में ११% बढ़ोतरी हुई है जब कि अनुमान ७% वृद्धि का था। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल (१६६१) के अंत तक प्रांत व्यक्ति आय ३३१ रुपए देना है और राष्ट्रीय आय में २५% की वृद्धि का लच्य है। इसी काल में जनसंख्या लगभग ४१ करोड़ हो बाने का अनुमान है। केन्द्रीय आँकड़ा संगठन (Central Statistical Organisation) के नवीनतम अंको के (२७ अप्रैल ५६) अनुसार प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार थी:—

सन् १६५५-५६ — २६१ रुपए प्रति व्यक्ति " १६५६-५७ — २४१-५ " " " १६५७-५८ — २८६ ""

संपूर्ण राष्ट्रीय स्त्राय १६५६-५७ में ११००० रुपए थी जो १६५७-५८ में १०८३० रुपए रह गई जिसका कारण खाद्य परलों की कमी एवं इस च्रेत्र में न्यून उत्पादन रहा। दितीय पंचवर्षीय योंजना के प्रथम वर्ष में ५% की राष्ट्रीय स्त्राय में बृद्धि हुई परन्तु सन् १६५७-५८ में (द्वितीय वर्ष) १.५% का हास हुस्रा। प्रति व्यक्ति स्त्राय में ३.६% वृद्धि हुई जब कि १६५७-५८ के वर्ष में यह कुल २.८% ही रही। यदि इस हास की स्रोर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो सन् १६७४-७५ तक प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय स्त्राय की ५४६ रुपये कर देने के लच्य को पूरा करना सन्देहस्पर रहेगा।

परन्तु ऋन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति ऋाय बहुत कम हैं जैसा कि निम्नांकित ऋाँकड़ों से प्रकट हैं :—

देश	वर्ष	प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय रुपर्यो में	
30	. १९५३	४४६०	
श्रास्ट्रे लिया	"	२०६	
बर्मा फ्रान्स	१९५४	३६८६	

चापान	75	६ २८
पाकिस्तान	५३-५४	२४५
भारत	"	रद४
ब्रिटेन	१६५४	४०५७
श्र मेरीका	55	হ ৫৩४

श्रीसत श्रमरीकन की श्राय भारतीय से करीब २१ गुनी है श्रीर श्रीसत श्रंभेज की १४ गुनी। इस श्रीसत को बढ़ाने के लिए श्रावश्यक है कि (१) उत्पादन की सभी चेत्रों में बृद्धि कीजिए, (२) श्राय के वितरण में श्रसमानताश्रों को दूर किया बाए तथा (३) जनसंख्या की बृद्धि पर प्रतितंध लगाए जाएँ—

श्रयंशास्त्री कीन्स के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय दूसरे व्यय का श्राय होता है। बन एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है तभी विक्रेता को श्राय होती है। इसी प्रकार सेवा के बारे में कह निक्ति हैं कि मालिक नौकर को वेतन देता है तो मालिक के लिए व्यय है और दूसरी श्रोर नौकर को प्राप्त वेतन श्राय। इस प्रकार सार समाज की मौद्रिक श्राय समाज के कुल व्यय के तुल्य होगी। संदोप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक उपज के कोष में वृद्धि कर देना ही श्राय को उत्पन्न कर देने का उपाय होता है। कारण है कि उत्पत्ति के उत्पत्ति में साधनों श्रम, पूँजी, भूमि श्रादि साधनों का उपयोग किया जाता है तो उत्पत्ति के इन साधनों का भुगतान करता रहता है। एक व्यक्ति की श्राय (जब वह उसे प्राप्त कर लेता है) दूसरे व्यक्ति की श्राय को उत्पत्न करती है। व्यय करते समय व्यक्ति सभी श्राय को व्यय नहीं कर देता श्राय कुछ श्रंश भावी उपभोग के लिए बचा लेता है यही श्रंश बचत (Saving) कहलाता है। तो श्राय—उपभोग = बचत।

बन श्राय में वृद्धि होती है तो उपभोग भी बढ़ बाता है क्योंिक उपभोग की प्रवृत्ति (propensity to consume) में कोई परिवर्त्तन नहीं होता श्रातः उपभोग की प्रवृत्ति श्राय पर प्रभाव नहीं डालती है बिल्क विनियोग में हुई वृद्धि श्राय में वृद्धि हो बाती हैं। बितनी विनियोग में बढ़ती होती हैं उतने से ही श्राय में भी तरक्की होती है।

इस प्रकार बचत में परिवर्तन करने के लिए श्राय में परिवर्त्तन करना पड़ता है। जैसा कि उत्पर लिखा जा चुका है उपभोग की दशा में परिवर्त्तन नहीं के बरावर होता है। श्रवः देश की जनता यदि ८०% व्यय करने की श्रादी है तो बचत २०% ही होगी। बचत को बढ़ाने के लिये कुल श्राय बढ़ानी पड़ेगी। बचत को ब्यक्ति श्रपने पास नगदी (Cash) में रख सकता है, बैंक में भी जमा कराया जा सकता है या श्रुप देकर श्रयवा विनियोगों (सरकारी, श्रव्दंसरकारी, शेयर डिबेंचरों) में लकाया जा सकता है। इस बचत से संपत्ति-भूमि, मकान श्रादि खरीदे जा सकते हैं। इसे व्यक्तिय बचत मी इहते हैं।

सामाजिक बचत व्यक्तिगत बचत में श्रन्तर है। सामाजिक बचत तभी होगी जब कि कोई व्यक्ति इसके विरोध में कार्य न करे। जब एक व्यक्ति बचत करता है तो दूसरा इसके विरोध में कार्य अवश्य करता है जैसे एक व्यक्ति संपत्ति क्रय करता है तो दूसरा उसे बेचता है। • विनियोग (Investment)

सामाजिक बचत का तात्पर्य पूँजी का नया निर्माण होता है। जैसे सरकार द्वारा नहरें बनाने या उद्योग स्थापना के लिए लिया गया ऋण या मकानों का निर्माण । इन पूँजी के नए निर्माण को ही विनियोग कहते हैं। विनियोग बचत का रूप हैं जिसमें व्यक्ति भविष्य में आय प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। यह व्यक्तिगत विनियोग होता है जो अधिकांश में सरकारी नीति पर निर्मर रहता है। जैसा कि पहले अंकित किया जा जुका है बचत को ब्याज पर उठा दिया जा सकता है या विनियोग किया जा सकता है। जहाँ लाभ बढ़े हुए होते हैं वहाँ विनियोगों को प्रोत्साहन मिलता है जब कि ब्याज की दरें बढ़ने पर विनियोगों को हतोत्साहन मिलता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जहाँ पर पूँजी की सीमांत जुशालता (Marginal efficiency of capital अथवा लाभ की दर) ब्याज की दर के बराबर हो जाती है वहीं पर विनियोग (के समापन) की सीमा आ जाती है। भारत में आय. बचत तथा विनियोग

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय आय में १५% की वृद्धि हुई है। इघर विनियोग की मात्रा ४५० करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ कर ७६० करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो गई। और विनियोग की दर प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्ष में जो ५% से कम थी वह ७% से भी अधिक बढ़ गई। सन् १६७४-७५ तक प्रति व्यक्ति आय के दुगने होने का लच्य निर्धारित किया गया है जिसके अनुमान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना (१६६०-६१) काल के अंत तक राष्ट्रीय आय के ११% तक बचत का अनुमान है और तृतीय योजना की समाप्ति तक २०% बचत का लच्य रखा गया है। परंतु जनता को अधिक कष्ट अनुभव होने के कारण यह अंक १७% लगाया गया है जिसके अनुसार सन् १६६५-६६ में १४% ओर १६७०-७१ में १६% का लच्य रखा गया है। परन्तु किर भी यह बचत की दर अन्य देशों की तुलना में आशाजनक नहीं है।

भारत में पूँजी निर्माण की दर घीमी रही है। किसी भी देश की सम्पन्नता वहाँ के पूँजी के निर्माण पर आधारित होती है और पूँजी निर्माण का अर्थ बचत को अधिक करना होता है। वैसे तो भारतीयों के बचत का स्वभाव प्रकृति दस है फिर भी यहाँ की आय कम होने के कारण बचत में वांछित वृद्धिनहीं हुई। फिर नए-

नए कर एवं कई गुनी कीमतों की वृद्धि इस बचत की श्रिष्ठिकता में श्रीर श्रिष्ठक बाधक रहे हैं। राजाश्रों, जमींदारों श्रादि वगों के उन्मूलन से बचत करने की च्राता में हास हुश्रा है। यहाँ पर छोटी-छोटी बचत करने वाले व्यक्तियों के लिए श्रिष्ठक सुविधाएँ भी कम है। यह भारत जैसे ग्रामीण देश में श्रानिवार्य सुविधा होनी चाहिए। इस बचत को बढ़ावा देने के लिए यह श्रावश्यक है कि मुद्रा प्रसार रोका जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए, उत्पादकों के लिए बैंक, डाकलानों श्रादि की सुविधाएँ जुटा कर वस्तुश्रों की पूर्ति में वृद्धि की जानी चाहिए। ग्रामीण चेत्रों में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए श्रनेक डाकलाने तथा व्यापारिक बैंक खोले जाने चाहिए।

पूर्ण वृत्ति (Full Employment) का अर्थ

चाहे पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था हो या साम्यवादी अर्थका समाजवादी, बेरोज-गारी की समस्या न्यूनाधिक बनी ही रहती हैं। फिर भी पूर्ण रोजगारी की व्यवस्था करना तथा बेरोजगारी को रोकना प्रत्येक शासन का आजकल महत्वपूर्ण कार्य है। और कल्याग्यकारी राज्य में तो और भी अवश्यंभावी। पूर्ण वृत्ति का तात्पर्य ऐसी आर्थिक व्यवस्था है कि जिसमें प्रत्येक देशवासी को ऐसा व्यवसाय मिल जाए जिसकी कि उसे खोज हैं।

प्रत्येक अर्थ व्यवस्था में निम्नांकित कारणों के होने से कुछ, अंश तक बेकारी बनी रहना आवश्यक हैं:—(१) समाज में कुछ, लोगों का स्वभाव ही यह होता है कि वे काम करना ही नहीं चाहते। अतः वे बेकार ही बने रहते हैं परन्तु बेरोज-गारी इसी अवस्था में कही जातो है जब चाहते योग्य काम नहीं मिलता। (२) कुछ, लोग एक व्यवसाय को छोड़ कर दूसरा पकड़ना चाहते हैं और इस परिवर्त्तन में कुछ, दिनों बेकार बेठना पड़ा रह सकता है क्योंकि तुरन्त ही कार्य मिलना आवश्यक नहीं। (३) कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग किसी कार्य को सीखने में समय किता देते हैं। यदि इस प्रशिक्तण काल में उन्हें मजदूरी नहीं मिलती तो बेकारी की अवस्था ही कही जाएगी। (४) कुछ आकरिमक बेकारी जैसे इहतालों का या ताला-बंदी का होना, समय के अंतर से काम को नियुक्ति होना अथवा बाढ़ या खुशकी के कारण किन्हीं उद्योगों का काम रुकना, होती है। (५) कुछ मौसमी (Seasonal) बेकारी भी होती है जैसे चीनी, शक्कर की मिलें, फल-सुरक्ता (Pood and fruit preservation) उद्योग इत्यादि, इत्यादि।

इन परिस्थितियों में इम कह सकते हैं कि जनसंख्या के लगभग ६५ से ६८ प्रतिशत भाग तक रोजगार मिलना चाहिए।

पूर्ण वृत्ति के सिद्धांत

सर्व प्रथम रोजगार की अवस्था किसी देश के विनियोग संम्बन्धी नीतियों पर आधारित रहती है। जब ब्याज की दर घटती है तो विनियोगों को प्रोत्साहन मिलता है और ब्याज-दर बढ़ने पर विनियोग घटते हैं। अतः रोजगार बढ़ाने के लिए ब्याज दरों को घटाना आवश्यक है। रोजगार में उस समय तक बढ़ने की गुंबायश नहीं होती जब तक कि मावी लाभ बढ़ने की संमावना न हो। अतः दूसरे विचार के अनुसार विनियोग मावी लाभ की आशा पर निर्मर रहते हैं। रोजगार की मात्रा सरकारी नीति एवं इस्तच्चेप पर भी निर्मर करती है। मंदी (Depression) के दिनों में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार को आय से अधिक ब्यय करना पड़ता है तथा अमिनृद्धि (Boom) काल में कम ब्यय करना पड़ता है एवं उद्योगपितयों के लाभ कमाने की संज्ञा को नियंत्रित करना पड़ता है ताकि इड़तालें या तालाबंदी न हो। इस प्रकार से

- (१) अवसाद एवं अभिवृद्धिकाल में सरकार को उचित कदम, उद्योगों की वृद्धि के लिए एवं मजदूरी बनाए रखने के लिए, उठाने चाहिए।
- (२) मंदी से कुप्रभावित उद्योगों में ही ऐसा संगठन किया जाना चाहिए कि मजदूरों को उन्हीं उद्योगों में लगाना चाहिए जिनमें कि वे बेकार हुए हैं।
- (३) सरकार को श्रपनी श्रार्थिक नीति द्वारा उद्योगों श्रौर निर्यातों को प्रोत्साहन देते रहना चाहिए ताकि रोजगार का स्तर बना रहे।

इस प्रकार पूर्ण वृत्ति के लिए स्त्राधिक नियोजन सफलतापूर्वक बनाना चाहिए। परन्तु स्त्राधिक नियोजन की सफलता के लिए सरकारी नियंत्रण एवं प्रदर्शन स्त्रावश्यक माना बाता है।

भारत में पृश्र रोजगारी

भारतवर्ष में पूर्ण रोजगारी बनाए रखने के लिए प्रथम तो प्रामीखों की बेरोजगारी का ध्यान रखना चाहिए, दूसरे प्रति वर्ष नए उत्पन्न व्यक्तियों को रोजगार दिलाना तथा तीसरे कृषि तथा कुटीर उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों को श्रिषक रोजगार की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर भारत में श्राधिक नियोजन इसी सिद्धांत पर श्राधारित हैं। सेवा योजनालयों (Employment Exchanges) की स्थापना की गई, प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग १ करोड़ व्यक्तियों को रोजगार देने का लद्ध रखा गया परन्तु १६५३ में ही इस दिशा में श्रिषक गतिशीलता लाने के लिए योजना में संशोधन करने पड़े। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का श्रीद्योगीकरण के साथ-साथ रोजगार में वृद्धि मुख्य उद्देश्य रखा गया।

योजना-ग्रायोग के विचार में इस योजना काल में १५३ लाख व्यक्तियों को (लोक चेत्र में) रोजगार मिलने की त्राशा है। इस प्रकार इस काल में बेरोजगारी को कुछ (न्यून) ग्रांश तक ही समाप्त किया जा सकेगा। संभवतः तृतीय योजना की समाप्ति पर स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जाएगा।

प्रश्न

1. Are savings and investments in an economy always qual? If not, how can this condition be brought about?
(श्रागरा बी. ए. १६६६)

द्वितीय खंड

श्रधिकोषण सिद्धांत,

विधान कार्यप्रणाली

राष्ट्रीय एवं श्चन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ

ऋध्याय १

अधिकोषण

(Banking)

परिचय (Introduction)

अधिकोषस ने संसार के आधिक विकास में बड़ा मद्दापूर्ण योग दिया है। वास्तव में बैंक हो वर्तमान व्यापार का जीवन रक्त है। व्यापारिक लेनदेनों में बैंक कितना महत्वपूर्ण है, यह तो इस बात से पता चल जायेगा कि एक रोज के भी अधिकोष (Bank) बंद हो जाने से समस्त व्यापार ठए हो जाता है। बैक्कों के विकास के कारस ही पाश्चात्य देशों का औद्योगिक विकास संभव हो सका है।

बैंकू की परिभाषा—बैंक वह संस्था है, जो ऐसे लोगों से जिनके पास देने के लिये रुपया है, रुपया उधार लेती श्रीर श्रधिक व्याज पर उन लोगों को रुपया उधार देती है जिन्हें उसकी श्रावश्यकता होती है, श्रीर ऐसे लोग बैंक या बैंकर्स कह-लाते हैं। क्योंकि ये दोनों कार्य साख पर निर्भर हैं श्रतः कहा जा सकता है कि बैंक वह संस्था है जो द्रव्य तथा साख में व्यापार करती है। देश के व्यापारिक चेंच सुयोग्य श्रीर सुचार रूप से व्यवस्थित श्रधिकोषण का श्रधिक महत्व है।

जिस प्रकार द्रव्य की परिभाषा में द्रव्य वह है जो द्रव्य के कार्य करता है उसी प्रकार बेंक वह संस्था है जो बेंकिंग का कार्य करती है। त्रात: ऋषिकोष (Bank) लेन-देन करने वाली वह संस्था है जो साख और द्रव्य का क्रय-विकय उसी प्रकार करती है जिस प्रकार व्यापारी माल का क्रय-विकय करते हैं। बेंक कम ब्याज पर जनता को धनसाश प्राप्त कराता है त्र्यया उधार देता है। त्रौर ऋषिक ब्याज पर व्यापारियों तथा जनता को कई प्रकार के ऋषों के रूप में उधार देता है। यही बेंक का मुख्य कार्य है और यही उसके लाभ का साधन हैं।

सन् १६४६ के बैंकिंग कम्पनीज ग्राधिनियम (Banking Companies Act of 1959) ने बैंकिंग की परिभाषा इस प्रकार दी है। "बैंकिंग जनता के द्रव्य को धनराशि के रूप में स्वीकार करने को कहते हैं। जो धनराशि बैंक द्वारा निकाली जा सके ग्रीर जिसे स्वीकार करने का उद्देश्य दूसरों को उधार देना ग्रथवा विनियोग करना होता है।" बैंकिंग की इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि बैंक का मुख्य कार्य, जनता से धनराशि प्राप्त करना तथा उसे दूसरों को उधार देना है। किन्तु इस परिभाषा के लिये यह ग्रावश्यक है कि धनराशि बैंक द्वारा निकाली जाये।

राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में बेंकिंग का स्थान

वैंक उन व्यक्तियों में जिनके पास पूँजी है, परन्तु कौशल नहीं है श्रथवा कौशल है परन्तु पूँजी नहीं है, समुन्तुय करता है श्रौर लेन-देन के द्वारा पूँजी के प्रकीकरण, बचत तथा उत्पक्ति की बृद्धि में सहायक होता है।

श्रपने श्राहत के कार्यों से वह व्यापारियों का पर्याप्त समय बचाता है तथा श्रू खं देकर उनकी चिन्ता कम करता है श्रौर उन्हें निश्चिन्त करके व्यापार में सफल बनाता है। उनकी बहुमूल्य वस्तुयें श्राग्त तथा चोरी से बचाकर सुरचा का प्रवन्य करता है। श्रायात-निर्यात में स्पया लगाता है तथा बिलों के भुगतान में सहायता देता के प्राहक की साख बढ़ाता है जो फ्रों किलन के श्रमुसार उनका सबसे बड़ा धन है। नैतिक शिचा, ईमानदारी, विश्वसनीयता तथा ठीक समय पर काम करने की श्रादत बनाता है।

श्रतः किसी भी उद्योग या श्राधिक योजना की सफलता में बैंक का बहुत उच्च स्थान है। बैंकों के द्वारा देश में पूँजी एक त्रित होती है। क्यों कि बैंक जनता में बचाने की भावना को उत्पन्न करता है। इस प्रकार जनता द्वारा बचाई हुई रकम बैंक उन लोगों को ब्याज पर देता है जिनको उसकी श्रिधिक श्रावश्यकता है जो इसका श्रच्छा उपयोग करके देश का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जिन देशों में बैंकों का विकास नहीं हुश्रा है वहाँ पर ब्यापार तथा उद्योग-धंधे पिछड़ी दशा में हैं। बैंकों द्वारा ही देश में नवयुवक श्रच्छे ढंग से श्रिधिक संगठन करना सीखते हैं श्रीर इस प्रकार बैंक देश को विकास की श्रोर ले जाता हैं।

बैंकों को व्यापार, वाणिज्य तथा व्यवसाय का मुख्य केन्द्र कहा जाता है, क्योंकि बैंकों से व्यापारियों को निम्नलिखित लाभ होते हैं:—

- (१) बैंक उन लोगों से घन प्राप्त करके, जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, व्यापारियों को ऋगा देता है, जो इसका सदुपयोग करते हैं। इससे देश के उद्योग-घन्चे चेतते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है और सारे समाज की मलाई होती है।
- (२) बैंक-साख-मुद्रा के प्रयोग को प्रोत्साहन देता है, बिससे बिना रुपये के ही रुपये का कार्य चलता है।
- (३) बैंक साख-मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करके देश की मुद्रा-प्रगाली को लोचपूर्ण बनाता हैं।
- (४) बैंक रुपये को बहुत कम व्यय पर एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने का साधन उपलब्ध करता है।
 - (५) बैंक लोगों में रुपया बचाने की श्रादत डालता हैं श्रीर उनकी बचत को श्रापने यहाँ सुरिच्चित रखता है तथा कुछ ब्याज भी देता है।

(६) वेंक ग्रपने ग्राहकों की ग्रौर भी कई प्रकार से सेवायें करता हैं। जैसे, पूँजी-संबन्धी परामर्श देना, ग्राहकों की ग्राधिक ग्रावस्था की बाँच पहताल करना तथा उनकी बहुमूल्य वस्तुग्रों को ग्रपने यहाँ सुरचित रखना।

बेंकों का विकास—ईसामसीह के २००० वर्ष पूर्व दैविलोनियाँ के निवा-सियों ने वैंक-सम्बन्धी पर्याप्त प्रगति की थी। वहाँ पर मिन्दरों में वैंकों का कार्य होता था। पुजारीगण वैंकर्स का काम करते थे। किन्तु धार्मिक आस्था कम हो जाने पर लोगों में सुरज्ञा की भावना तथा पुजारियों का विश्वास कम हो गया। सरकार का विकेन्द्रीकरण हो जाने के कारण यूनान नथा रोम में वैंकों को ठेस पहुँची। कुछ लोगों ने इस बात का प्रचार किया कि ब्याज लेना महापाप है। इसका भी वेंकों पर कुप्रभाव पड़ा। आज भी इस्लाम धर्म में ब्याज लेना पाप माना जाता है। किन्तु सम्यता के विकास के साथ-साथ धन की आवश्यकता बढ़ी। अतः १२ वीं शताब्दी के मध्य में वैंक व्यवसाय में फिर जाग्रति हुई।

भारतवर्ष में भी वेंकिंग व्यवसाय बहुत प्राचीन है। यद्यपि पहले यह व्यवसाय श्राधुनिक ढंग से नहीं चलता था। वैदिक काल में भी रुपये का लेन-देन होता था। इतिहास में ऐसा प्रमाण मिलता है कि पाँचवीं शताब्दी में भारतवर्ष में हुँ दियों का चलन था। महाजन लोग देशी-विदेशी व्यापार को ब्याज लेकर श्रार्थिक सहायता प्रदान करते थे। मुस्लिम काल में भी मुल्तानी विधा शर्राफ लोग ऐसा कार्य करते थे। ये ही लोग सरकारी कोषाध्यत्त होते थे श्रीर श्रावश्यकता पड़ने पर सरकार को श्राण भी दिया करते थे। इसीलिये तो कुछ को जगत सेठ कहा जाता था। भारतवर्ष में श्रांग्रेजों के श्रागमन के पश्चात् वैंक व्यवसाय में श्रोर भी वृद्धि हुई क्योंकि श्रंग्रेज स्वयं व्यापारी थे श्रीर वैंकों के बिना उनका काम नहीं चलता था। श्राज तो सारे संसार में वैंकों का इतना श्राधिक महत्व हो गया है कि सरकार को वैंक व्यवसाय के विकास के लिये विशेष नियम बनाने पड़ते हैं।

वैङ्कों के कार्य-वैंक निम्नलिखित कार्य करते हैं :--

- (१) बैंक उचित ब्याज पर जनता से मुद्दती खाते, बचत खाते, चालू रखते हैं तथा किसी अन्य प्रकार से जमा प्राप्त करते हैं।
- (२) जनता द्वारा की हुई जमा की राशि तथा बैंक के स्वामी की पूँजी ब्याज पर उचार देते हैं। प्राप्य ब्याज तथा देय-ब्याज का ऋंतर ही उनका लाभ होता है। यह ऋगा माल की जमानत पर ऋथवा व्यक्तिगत ब्याज पर लिया जाता है।
- (३) वे रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधार्थे प्रदान करते हैं।
 - (४) वे जनता की बहुमूल्य वस्तुश्रों को श्रपने यहाँ मुरिच्चत रखते हैं।

- (५) बैंक अपने प्राहकों को बहुमूल्य घातु तथा प्रतिभूतियाँ कय-विकय करने के संबन्ध में परामर्श देते हैं अपेर कुछ साधारण फीस लेकर इनका प्राहकों के लिये कय-विकय करते हैं।
- (६) वैंक सरकार के कोषाध्यत्व होते हैं श्रौर सरकारी ऋग् व्यवस्था करते हैं।
- (७) कुछ बैंक कागजी-मुद्रा छापकर तथा उस पर नियंत्रण करके मुद्रा-प्रसाली को लोचदार बनाते हैं।
- (८) बैंक ऋपने ऋगा देने की नीति द्वारा देश की ऋार्थिक-व्यवस्था मुद्द करते हैं। वास्तव में ये देश के ऋार्थिक ऋभिभावक हैं।
 - (६) बैंक श्रन्तर्देशीय व्यापार के भुगतान की व्यवस्था करते हैं।
- (१०) बैंक उद्योगपतियों के लिये श्रपनी जमानत पर ऋगा दिलवाते हैं तथा उनके श्रशों तथा ऋगा पत्रों का भी गोपन करते हैं।
- (११) श्रपने प्राहकों का कर निर्घारण कराते हैं तथा उनकी स्रोर से कर, किराया तथा प्रीमियम इत्यादि का भुगतान करते हैं।
- (१२) श्रमेरिका में संभवतः कोई ऐसा व्यापारिक लेन-देन नहीं है जिसमें बैंक सहायता प्रदान न करते हों।

अच्छी बेंक व्यवस्था के गुए —िकसी भी देश का आर्थिक विकास एवं सम्पन्नता सुदृढ़ बेंक व्यवस्था पर निर्भर होती हैं। एक सुदृढ़ बेंक व्यवस्था में निम्न जिलित गुए होने चाहिये:—

- (१) बैंक का संगठन एवं नियंत्रण योग्य व्यक्तियों के हाथ में हो को अपनी ईमानदारी एवं कुशलता के कारण जनता का विश्वास प्राप्त कर सकें।
- (२) बैंक के कर्मचारी एवं व्यवस्थापक हर उद्योग तथा व्यवसाय की आवश्यकताओं से भली भाँति परिचित हों जिससे वे अपना कार्य सफलता से कर सकें।
 - (३) क्योंकि उद्योग तथा व्यवसाय बैंकों पर निर्मर होते हैं श्रातः बैंकों का कारबार व्यक्तिगव श्राधार पर न चलकर राष्ट्रीय श्राधार पर चलाया जाये।
- (४) प्रारंभ में विदेशी पूँजी तथा विशेषज्ञ भले ही रख लिये जाये, किन्तु किसी प्रकार भी ऐसी नीति निर्धारित करने में उनकी बात न मानी जाये, जो राष्ट्र के हित के विरुद्ध हो।
- (५) बैंकों को चाहिये कि वे बनता को घन बचाने तथा उसका विनियोग करने का पाठ पढ़ायें श्रौर इसके प्रचार पर पूरा ध्यान दें।
- (६) बैंकों को सरकारी सहानुभूति प्राप्त होनी चाहिये, जिससे उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन मिलता रहें।

- (७) बिकंग व्यवस्था देश की आर्थिक परिस्थितियाँ के अनुकूत होनी चाहिये जिससे वह समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकता को पूरा कर सके।
- (=) वैंकिंग व्यवस्था लोचपूर्ण होनी चाहिये जिससे साख का निर्मास देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार घट-वद् सक।
- (६) बैंकिंग व्यवस्था में प्रतियोगिता के स्थान नहीं मिलना चाहिये । विभिन्न अंगों के मध्य पूर्ण सहयोग एवं परस्पर के सम्बन्ध स्थापित होने चाहिये विससे आपस में प्रतिस्पर्धा न कर सकें।
- (१०) समस्त राष्ट्र की सेवा करने के लिये बैंकों को सुविधार्ये इर स्थान पर उपलब्ध होनी चाहिये। अर्थात् भिन्न-भिन्न स्थानों पर बैंकों की शाखार्ये स्थापित हों।

बेंकों की शाखायं—बेंकों के सम्बन्ध में अर्थशाखियों के दो विचार हैं। कुछ का कहना है कि बेंक एक इकाई के रूप में एक ही स्थान पर कार्न करें, बन कि कुछ की धारणा है कि बेंक भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपनी शाखायें स्थापित करें। इकाई बेंक का अर्थ है कि बेंक का केवल एक ही कार्यालय हो, जब कि शाखा बेंक का अर्थ है कि बेंक का केवल एक ही कार्यालय हो, जब कि शाखा बेंक का अर्थ है कि बेंक के भिन्न-भिन्न स्थानों पर कार्यालय स्थापित हों और ये कार्यालय प्रधान कार्यालय की देखरेख में कार्य करें। अमेरिका में इकाई बेंक व्यवस्था है। वहाँ पर कोई बेंक दूसरे राज्य में अपनी शाखा स्थापित नहीं कर सकता। यह बात आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न बेंक आपस में सम्बन्ध रखते हैं और इस प्रकार एक दूसरे के लिये शाखा का कार्य करते हैं। संसार के अधिकतर देशों में विशेषकर इंगलैंड, कनाडा, दिल्ला अफिका, आस्ट्रेलिया व मारत में शाखा बेंक व्यवस्था चालू है। शाखा तथा इकाई बेंक व्यवस्था में कुछ गुण तथा दोष पाये जाते हैं। शाखा व्यवस्था के गुण, इकाई व्यवस्था के दोष हो जाते हैं। तथा दोष गुण हो जाते हैं। अतः इम यहाँ पर केवल शाखा बेंक व्यवस्था के गुण तथा दोषों का ही वर्णन करेंगे। शाखा बनाम इकाई बेंक व्यवस्था वृहत् उत्पादन बनाम लघु उत्पादन की समस्या है। इकाई बेंक व्यवस्था लघु उत्पादन है, जब कि शाखा व्यवस्था वृहत् उत्पादन है।

शाखा बैंक व्यवस्था के गुण

- (१) श्रम विभाजन—शाखा वैंक व्यवस्था में वे सभी गुण हैं जो श्रम विभाजन में होते हैं। भिन्न स्थानों पर शाखायें स्थापित करके योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है। क्योंकि बहुत से कर्मचारी रखने होते हैं श्रतः श्रम विभाजन द्वारा उनकी योग्यता का पूरा लाभ उठाया जा सकता है।
- (२) श्राधिक नकद कोष की आवश्यकता नहीं—वैंक अधिक से अधिक रुपया ब्याज पर लगा कर लाम कमाया करते है, किन्तु ऐसा करना शाखा वैंक व्यवस्था में अधिक संभव है। यदि किसी शाखा में किसी समय रूपया निकालने

वालों की ऋधिक माँग आ जाये तो दूसरी शाखा से रुपया मँगाकर यह माँग पूरी की जा सकती है। ऋतः यह ऋावश्यक नहीं कि हर शाखा में पर्याप्त नकद कोष रक्ता जाये।

- (३) कम व्यय पर एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजना—एक ही बैंक की भिन्न-भिन्न शाखायें एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से कम व्यय पर रुपया भेज सकती हैं। इससे प्राहकों को सुविधा भिलती है ख्रौर वे कम व्यय के लालच में ऐसे बैंक से श्रपना हिसाब खोलना पसन्द करते हैं।
- (४) जोखम में कमी—जब बैंक की मिन्न-भिन्न स्थानों पर शाखायें होती है तो बैंकों का घन मिन्न-भिन्न स्थानों पर विनियोग होता है। किसी एक स्थान पर संकट आ जाने से बैंक नष्ट नहीं होते। यदि बैंक का समस्त घन एक ही स्थान पर विनियोगित हो और उस स्थान पर कोई आर्थिक संकट आ जाय तो बैंक का समस्त घन जोखम में पड़ जाता है। शाखा व्यवस्था में केवल कुछ अंश नष्ट हो सकता है, समस्त घन नहीं। १६२६ के कृषि-मंदी युग में अमेरिका की बैंकों को जितनी हानि उठानी पड़ी उतनी इंगलैंड के बैंकों को नहीं। क्योंकि अमेरिका में इकाई बैंक व्यवस्था के कारण समस्त घन एक ही स्थान पर विनियोगित था।
- (४) ब्याज की दर में समानता— बैंक की शाखाएँ सुगमता से ऐसे स्थान पर घन विनियोग करके जहाँ ब्याज की दर ऋधिक हो; ब्याज की दर में समानता लाती हैं। उस शाखा का घन, जहाँ घन की माँग कम होने से, ब्याज की दर कम है। उस स्थान पर ले जाकर विनियोग किया जा सकता है जहाँ घन की माँग ऋधिक है। ऐसा करने से देश के मिनन मिनन स्थानों में ब्याज की दर समान हो जानी है। ऋौर बैंक का घन किसी भी शाखा में ब्यर्थ नहीं रहता। कहीं न कहीं जाकर विनियोग हो ही जाता है। इसमें बैंक के लाभ में बृद्धि होती है।
- (६) अच्छे विनियोग में धन लगाने का अवसर—यदि वैंक किसी अच्छे विनियोग में धन लगाना चाहे तो शाखाओं द्वारा यह अवसर प्राप्त हो जाता है। मान लीजिये जूट मिलों के अशों में धन लगाना लाभप्रद समभा गया है तो कलकत्ते के स्थित शाखाओं द्वारा धन सुगमता से विनियोग किया जा सकता है। स्थोंकि जूट मिलों के समीप रहने के कारण वहाँ की स्थित का आर्थिक ज्ञान है।
- (७) देश की आर्थिक स्थिति का अच्छा ज्ञान भिन्न-भिन्न स्थानों पर शालायें स्थापित होने से देश के भिन्न-भिन्न स्थानों की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो बाता है। बनता से संपर्क स्थापित करके ये शालायें श्रपने ज्ञान की वृद्धि करती हैं, बिससे बैंक व्यवस्थापकों को एफल नीति निर्धारित करने का अवसर मिलता है।
 - (८) शालायें नवयुवकों को वैंक व्यवस्था का प्रशिद्धण प्रदान करती हैं।

शाखाओं में बैंक संबंधी भिन्न-भिन्न बातों का ज्ञान प्राप्त करने में सुगमता रहती है।

शाखा बैंक व्यवस्था के दोष

- (१) श्रम विभाजन की सीमा—श्रादम स्मिथ के श्रनुसार एक सीमा से श्रिषक श्रम विभाजन लामप्रद न होकर हःनिदायक होता है। यही बात बैंक की शासाओं पर भी लागू होती है।
- (२) नियन्त्रण की किंठिनाई—श्रिधिक शाखायें होने से प्रधान कार्यालय को उन पर नियन्त्रण करने में कठिनाई होती है जिसका फल यह होता है कि शाखायें मनमाना कार्य करने लगतो है श्रीर वैंक को हानि होती है। बिना कठोर नियन्त्रण के शाखाओं में कुप्रयन्ध होता है श्रीर व्यवस्था दोषपूर्ण हो जाती है।
- (३) स्रधिक व्यय—श्रधिक शालायें स्थापित करने से कर्मचारियों के वेतन तथा भवन के किराये पर श्रधिक व्यय करना होता है जिससे लाभ कम हो जाता है। प्रधान कार्यालय को भी शालाश्रों पर नियन्त्रण करने के लिये श्रधिक व्यय करना होता है।
- (४) संकामक संकट—यदि किसी कारण एक शाला पर कोई संकट आ जाये तो यह संकट दूसरी शाला को भी सहन करना पड़ता है। किसी शाला की कुव्यवस्था से अन्य शालायें भी बदनाम हो जाती है।
 - (४) लालफीतावाद—क्यों कि शाखारें स्वतन्त्र नहीं होती त्रातः उन्हें त्रापने हर निर्ण्य पर त्रानुमति प्रधान कार्यालय से प्राप्त करनी पड़ती है। त्रीर त्रावश्यक विषयों पर शीघ्र निर्ण्य नहीं दिया जा सकता। परिणामस्वरूप हानि होती है।
 - (६) प्रतिस्पर्धा में वृद्धि—वैंक भिन्न-भिन्न स्थानों पर शाखायें खोलकर लाभ कमाने के हेतु दूसरे बैकों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। बनता से ऋषिक व्याब पर रुपया प्राप्त करने तथा कम व्याब पर रुपया विनियोग करने का प्रयत्न करते हैं। इससे सभी बेंकों को हानि उठानी पड़ती है।
- (७) संचालकों का जनता से घानेष्ट संपर्क नहीं इकाई वैंक व्यवस्था में वैंक के संचालक स्थानीय व्यापारियों के घानिष्ट संपर्क स्थापित करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं और कार्य में द्धमता लाते हैं। शाखा व्यवस्था में संचालकों के लिये यह संभव नहीं। शाखा बैंक व्यवस्था के गुण दोघों से अधिक हैं। राष्ट्र की भलाई शाखा व्यवस्था द्धारा ही की जा सकती है। अनेकों वैंकों का पंजीकरण कराने की अपेद्धा यही अव्छा है कि कुछ बैंक अनेक स्थानों पर अपनी शाखायें स्थापित करें। शाखा स्थापित करने के लिये कोई विश्रेष वैज्ञानिक कार्यवाही नहीं करनी पड़ती।

भारतवर्ष में बैंकों की शाखायें — भारतवर्ष एक विशाल देश हैं। बढ़ी हुई जनसंख्या के लिये वर्तमान बैंक शाखायें कम हैं और जनता की त्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिये उनका विकास करना त्रावश्यक है। भारवर्ष में प्रति ४,००,००० व्यक्तियों के लिये बैंक की केवल एक ही शाखा है। भारतवर्ष के २,५०० नगरों में केवल ४०० नगर ऐसे हैं जहाँ पर बैंक हैं। प्रामों में तो बैंकों की शाखायें किंचित मात्र भी नहीं हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त बैंकों की शाखात्रों में कुछ बृद्धि हुई है, यद्यपि यह त्राशातीत नहीं है। किन्तु भारतीय ग्राम त्राज भी इस सुविधा से दूर हैं।

मिश्रित बेंक व्यवस्था— कुछ श्रर्थशास्त्रियों का कथन है कि भिन्न-भिन्न उद्देश्य के लिये भिन्न प्रकार के बेंक स्थापित की जायें, क्योंकि ऐसा करने से उनका विशिष्टीकरण होगा श्रोर वे श्रपना कार्य सुचार रूप से चला सकेगें। कुछ श्रर्थशास्त्री मिश्रित श्र्यं व्यवस्था के पत्त में हैं। मिश्रित बेंक व्यवस्था का श्र्यं है कि बेंक भिन्न-भिन्न उद्देशों की पूर्ति करें। व्यापारिक बेंक केवल श्रल्प काल के लिये चल सम्पत्ति घरोहर रखकर श्रयवा व्यक्तिगत साख पर श्रुग्ण देते हैं। लम्बी श्रवंधि के लिये श्रुण देना श्रयवा उद्योगधंघों को पूँ जी जुटाना इनके कार्य चेत्र से बाहर हैं। श्रौद्योगिक बेंक उद्योगधंघों के लिये पूँ जी जुटाते हैं, व्यापारिक बेंक नहीं। मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था में व्यापारिक बेंक न केवल श्रल्पकालीन श्रुण प्रदान करते हैं श्रपितु लम्बे काल के लिये उद्योगपित्यों को श्रुग्ण प्रदान करते हैं तथा उनके श्रयण्यां, का श्रभिगोपन करते हैं। जर्मनी में मिश्रित बेंक व्यवस्था बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। डेनमार्क तथा स्विटवरलैंड में भी इसके श्रव्छे परिशाम निकेले हैं।

मिश्रित बैंक व्यवस्था के गुगा

- (१) बैंक उद्योगपितयों के संपर्क में आकर उनकी कार्य प्रगाली से पिरिचित हो जाते हैं और समय-समय पर उन्हें विशेष परामर्श प्रदान कर सकते हैं।
- (२) बैंक क्रौद्योगिक संस्थाक्रों के क्रंशों तथा ऋग्णपत्रों का क्रिभिगोपन करके विनियोग करने वालों के हृदय में उद्योगों के प्रति विश्वास उत्पन्न करते हैं। इससे देश की पूँ की सिक्रय हो जाती है।
- (३) यदि बैंक के पास मुद्दती खाते में श्रिधिक रकम जमा हो गई है तो इसका लाभदायक उपयोग लम्बी श्रविध के लिये ऋण देकर ही किया जा सकता है।
- दोष—(१) मंदी काल में मिश्रित बैंकों को हानि उठानी पड़ती हैं, क्यों-कि उर्ख समय श्रीहोगिक संस्थाओं के श्रश तथा श्राग्पनों के मूल्य गिर जाते हैं। फोल, जापन तथा श्रमेरिका में श्राधिक मंदी के बुग में मिश्रित बैंकों को बड़ी हानि उठानी पड़ी।

(२) मिश्रित बेंकिंग व्यवस्था में वैंकों को हानि हो जाने से रुपया जमा करने वालों को भी हानि होती है। इससे जनता का वैंकों में विश्वास कम हो जाता है और देश की श्रार्थिक व्यवस्था को ठेस पहुँचती है।

उपरोक्त दोषों के कारण स्वीडन व बेल्जियम इत्यादि देशों में मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिबंध है। भारतवर्ष का भारतीय बैंक ऋाधिनियम भी मिश्रित बैंकिंग की आशा प्रदान नहीं करता। क्योंकि मिश्रित बैंकिंगं व्यवस्था के कारण बैंक संकट उपस्थित होते हैं।

बैंक संकट-बेंक श्रार्थिक कारबार का समस्त दाँचा बनता के विश्वास पर निर्भर है, बैंकिंग भवन की नीव ही जनता के विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। जनता के विश्वास में किसी प्रकार की कमी आ जाने से वैंकों पर संकट आ जाता है। वेंकों का संकट एक भयंकर संकामक रोग है। यदि किशी समय एक बैंक पर संकट आ जाता है तो सारे बैंक संकटयुक्त हो जाते हैं। बैंकों के संचालक अपने अनुमवों से यह जानते हैं कि जनता द्वारा जमा की हुई रकम जमा करने वालों द्वारा एक समय वापस नहीं माँगो जायेगो। इसलिये बैंक जमा की हुई रकम का ६०-७० प्रतिशत व्याज पर लगाये रखते हैं जिससे माँगने वालों का तुरन्त भगतान किया जा सके। यदि किसी समय जनता का विश्वास किसी वैं क पर कम हो जाता है तो लोग तरन्त ही अपना रुपया वापस माँगने दौड़ पड़ते हैं। बैंक के पास पर्याप्त पूँजी तथा विनियोग होते हुए भी यह कठिन हो जाता है कि उस समस्त पूँ जी तथा विनियोग को नकद रुपयों में परिवर्तित किया जा सके । रुपया माँगने पर बैंक यदि भुगतान तुरन्त नहीं करता तो बैंक को अपना कारबार तुरन्त बन्द करना पड़ता है और बैंक पर संकट श्रा जाता है। वे लोग जिनका रुपया दूसरे बैं कों में जमा है वे भी घवस बाते हैं श्रीर डरने लगते हैं कि उनका वैंक भी फेल न हो बाये। इसिलये वे भी अपना रूपया वापस लेने के लिये अपने बैंक पर दौड़ लगाने लगते हैं। अतः एक बैंक पर संकट आ जाने से सब बैंकों पर संकट आ जाता है।

इन संकटों को दूर करने के लिये वैंकों को चाहिये कि जनता का विश्वास हट बनाने के लिये माँगने पर क्यों का भुगतान तुरन्त करें और इस कार्य में अन्य वैंक अथवा केन्द्रीय वैंकों को भी यथाशक्ति सहायता करनी चाहिये। संकटमस्त वैंक को अधिक भात्रा में ऋग्ण मिलना चाहिये जिससे वह संकट का सामना कर सके। वैंक के प्रबंधकों का भी यह कर्तव्य है कि वे जमा की हुई रकम का कुछ नकद भाग अलग रखें। संकट काल में बैंकों को चाहिये कि भुगतान करने के लिये वे २४ घंटे खुले रहें जिससे जनता को विश्वास हो जाये कि वैंक के पास क्यों की कमी नहीं है। भारत विभाजन के पश्चात् पंजाब नेशनल वैंक पर दो बार ऐसा संकट अप्राया और वह इसी नीति को अपनाकर सफल हुआ। क्योंकि जनता का विश्वास प्राप्त हो जाने पर रुपया निकालने वाले फिर जमा करने लगते हैं ऋौर इस प्रकार वैंकों का संकट दूर हो जाता है। १६४६ के बैंकिंग ऋधिनियम में इस बात का उल्लेख है कि संकटकाल में रिजर्व बैंक भरपूर सहायता करें। बैंक के लिये यह भी ऋिनवार्य कर दिया गया है कि वह जमा की हुई राशि का एक निश्चित भाग से ऋषिक व्याज पर न लगावे।

बैंक संकट के कारण जमा करने वालों को हानि उठानी पड़ती है श्रीर देश का श्राधिक ढाँचा श्रस्त-व्यस्त हो जाता है। इसीलिये कुछ, लोग बैंकों के राष्ट्रीय-करण की माँग कर रहे हैं।

बेंकों का राष्ट्रीयकरण — द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् सभी देशों में श्राधिक चेत्र में राज्य द्वारा इस्तच्चेप श्रिविकाधिक हो गया है। समाजवादी प्रथा भी नियन्त्रित श्र्य व्यवस्था के पन्न में है। बेंक व्यवस्था श्राधिक दाँचे का श्राधार है। श्रतः बेंक पर पूर्ण राजकीय नियंत्रण की माँग के साथ साथ उनके राष्ट्रीयकरण की माँग की बारही है। बेंक सरकार के श्रधीन होने चाहिये। तभी इनका संचालन राष्ट्रीय उन्नति के लिये किया जा सकता है। इसके श्रितिरक्त बेंकों का मुख्य कार्य साख का निर्माण करना है। साख नियंत्रण बहुत श्रावश्यक होता है, क्योंकि श्रन्यथा साख को व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है। साख नियंत्रण भी सरकार द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा सकता है श्रीर व्यापार चक्रों के संकटों से भी, जो कि बेड्डो की बुद्धिहीनता तथा स्वार्थपूर्ण नीति के कारण उत्पन्न होते है, बेड्डों के राष्ट्रीयकरण द्वारा छुटकारा पाया जा सकता है। समाजवादी देशों का श्रनुभव भी इसी बात की पुष्टि करता है, क्योंकि वहाँ तो व्यापार संकट उत्पन्न हो नहीं होते। बेड्ड जनता के धन व विश्वास में व्यवसाय करते हैं। श्रतः उनके लाभ भी व्यक्तियों को न होकर जनता को होने चाहिये जो उनके राष्ट्रीयकरण द्वारा ही संभव हो सकता है।

ऐसा कहा जाता है कि स्वार्थपूर्ण तथा संकुचित नीति के कारण ही बैङ्कों के प्रति जनता में विश्वास पैदा नहीं हुन्ना। जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिये बैङ्कों के राष्ट्रीयकरण की माँग की जाती है न्त्रीर इसके पच्च में निम्नलिखित तर्क उपस्थित किये जाते हैं।

पच्च में

(१) व्यक्तिगत बैक्कों का अब तक का इतिहास यह बतलाता है कि इनकी व्यवस्था निराशाजनक एवं अकुशल रही है जिसमें घन का दुरुपयोग हुआ है। अतः राष्ट्रीयकरख द्वारा ही इन दोषों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि राज्य की देखरेख में घन का दुरुपयोग नहीं हो पायेगा और कुशल कर्मचारियों द्वारा बैक्क की व्यवस्था में चमता आयेगी।

- (२) समाववादी समाज की स्थापना के लिये भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण अनिवार्ष है, तभी बैंकों का उपयोग राष्ट्रीय प्रगति में किया जा सकेगा।
- (३) मारतवर्ष में ही नहीं अन्य देश में भी आर्थिक संकट आने के कारण बैंक असफल हुए हैं जिससे स्वया जमा करने वालों को हानि उठानी पड़ी। आज भी अनेकों छोटी-मोटी बैंक हानि में चल रही हैं। अतः स्पया जमा करने वालों की सुरद्धा के हेतु बैंकों का राष्ट्रीय करण अति आवश्यक है। इससे जनता में विश्वास बढ़ेगा और देश की पूँची का पूरा उपयोग हो सकेगा।
- (४) बैंकों का सभी कारबार जमा करने वालों की घनराशि पर चलता है। अंशघारियों की पूँ जी तो बहुत कम होती है। फिर भी बैंक की व्यवस्था कु इ हने-गिने अंशघारियों के प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। जमा करने वालों का प्रबंध में कोई हाथ नहीं होता। अतः बैंकों का प्रबंध उन संचालकों के हित में ही होता है; जमा करने वालों के हित में नहीं। राष्ट्रीयकरण होने से यह प्रवृत्ति समाप्त हो जायेगी और बैंक का प्रबन्ध जन-साधारण के हितों के लिये किया जा सकेगा।
- (५) अभी तक बैंक केवल लाभ के उद्देश्य से चलाये जाने वाले उद्योगों को ही रुपया प्रदान करती रही हैं, जिससे देश की आर्थिक आवश्यकताओं की दृष्टि से रुपये का संतुलित वितरण नहीं होता। निश्चित योजनानुसार रुपये का वितरण केवल सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।
- (६) बैंकों का नियंत्रण कुछ लोगों के हाथ में होना सार्वजनिक नीति के विरुद्ध भी है। यही कारण है कि अविकसित चेत्रों की उन्नति में रुपया नहीं लगाया चा सका तथा अविकतर बैंक कुछ राज्यों के बड़े नगरों में ही स्थापित हैं। श्रदः पिछड़े हुए चेत्रों में विकास के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है।
- (७) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् जमा करने वालों को अपने धन की कोई चिन्ता नहीं रहेगी, क्योंकि उसका सारा उत्तरदायित्व सरकार पर होगा।
- (८) आर्थिक योजनाओं को सफल बनाने के लिए सरकार को पर्याप्त मात्रा में रुपये की आवश्यकता है और यह रुपया वैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चार्ते ही सरलता से प्राप्त हो सकता है।
- (६) बैंक संचालक प्रायः उद्योगपित हैं। फलतः इन बैंकों से उनके ही उद्योगों का पोष्णु होता है। श्रम्य लोगों की भलाई नहीं होती। राष्ट्रीयकरण से सब की समान भलाई होगी।
- (१०) देश में साख-नियंत्रण के लिये तथा व्यापार चक्रों (Trade Cycles) के दोषों को दूर करने के लिये भी राष्ट्रीयकरण श्रवि श्रावश्यक है।

कुछ स्रर्थ-शास्त्री बैंकों के राष्ट्रीय करण के विरुद्ध हैं स्रोर विपच्च में निम्न लिखित तर्क उपस्थित करते हैं —

- (१) यह कथन कि योजना के लिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बहु रूपया मिल जायेगा, बहुत अमपूर्ष है, क्योंकि बैंक के पास जमा का जो इ रूपया होता है वह थोड़ी अपविध का होता है श्रीर उसका दीर्घ कालीन योजनाओं लिए निश्चितता से प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- (२) यह कहना भी गलत है कि सरकार के अधिकार में आने से बैंकों वे प्रवन्त तथा अन्य प्रकार के दोष दूर होकर कार्यकुशलता बढ़ जायेगी क्योंकि एक ते जिन उद्योगों का भारत में राष्ट्रीयकरण हो चुका है, उनका कार्य और विकास के गति बहुत उत्साहवर्षक नहीं है। दूसरे यदि सार्वजनिक चेत्र में कोई दोष न होते तो सरकार निजी चेत्र को विद्यमान ही क्यों रहने देती ! अत: सत्य तो यह है कि योग व्यक्ति भी दोनों चेत्रों में होते हैं और अयोग्य प्रबंध भी दोनों ही चेत्रों में देखने को मिलता है।
- (३) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंक के कर्मचारियों में सरकारी श्रक्सरी की कू श्राने लगेगी जिससे श्रन्य विभागों की भाँति लाल फीता शाही बढ़ जायेगी श्रीर कार्य-चमता भी कम हो जायेगी । फलतः बैंकों के कार्य-च्यय भी बढ़ जायेंगे।
 - (४) बेंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग प्रणाली की लोच समाप्त हो जायेगी।
- (५) देश की केन्द्रीय बैंक बैङ्कों पर पूर्ण नियंत्रण करके उनमें पर्याप्त सुपार कर सकती है फिर उनके राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता ही क्या है ?
- (६) जब बैक्क घाटे में चल रही हो उस समय उनका राष्ट्रीयकरण करके घाटे का काम सरकार को सौंपा जाये यह अर्समव है। बैक्क व्यवसाय से होने वाली हानि नये कर लगा कर पूरी की जायेगी ऋौर यह व्यर्थ का मार निर्धन जनता पर पढ़ेगा।

विदेशों में बैङ्कों का राष्ट्रीयकरण हंगलैन्ड में केन्द्रीय बैङ्क अर्थात् बैङ्क आफ इंगलैन्ड का राष्ट्रीयकरण हो गया है। किन्तु व्यापारिक बैंक अभी भी व्यक्तिगत रूप से चल रहे हैं। यह बात अवश्य है कि बैङ्क आफ इंगलैन्ड उन पर पूर्ण नियंत्रण ख्ली है। फ्रांस में केन्द्रीय बैङ्क के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक बैङ्कों का भी शब्द्रीयकरण हों गया है। चेकोस्लोवेकिया में भी बैङ्कों का सामान्य रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। किन्तु यह कहना कठिन है कि राष्ट्रीयकरण के अच्छे परिणाम निकलेंगे अथवा बुरे ? यह तो सरकार की राष्ट्रीयकरण की सामान्य नीति पर निर्मर है। बड़े-बड़े सभी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ बैङ्कों का राष्ट्रीयकरण भी आवश्यक है।

भारतवर्ष में वैद्धों का राष्ट्रीयकरण—रिजर्व बैद्ध आफ इन्हिया तथा स्टेट बैद्ध का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। किन्तु अन्य वैद्ध अभी व्यक्तिगत रूप से चल रही हैं। जब तक व्यक्तिगत श्रीयोगिक खेंत्र को मान्यता है तब तक बैद्धों का राष्ट्रीयकरण अनुचित हैं। व्यक्तिगत उद्योग-धंचे अपनी पूँजी की आवश्यकतायें व्यक्तिगत वें को द्वारा ही पूरी करा सकते हैं। वैद्धों के कर्मचारी अपनी सुरद्धा के लिये राष्ट्रीयकरण की गाँग कर रहे हैं किन्तु व्यक्तिगत उद्योगों की मलाई को ध्यान में रखते हुए वैद्धों का राष्ट्रीयकरण अवांछनीय है। हमारे देश में प्रशिद्धित एवं कुशल कर्मचारियों का अभाव है। यहाँ के सरकारी वर्मचारी अपने उत्तरदायित्व को नहीं समभते और राष्ट्रीयकरण हो जाने पर जनता को कठिनाई होती है। जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण यह बात सिद्ध कर चुका है कि सरकारी कर्मचारी बीमा व्यवसाय को इतनी कुशलता से नहीं चला सकते जितनी पूँजीपित चलाते हैं। बीमा तथा बैद्ध का व्यवसाय बद्धत कुछ अश्च में समान हैं। अतः वैद्धों का राष्ट्रीयकरण आर्थिक द्विट से द्वितकर नहीं है।

वैङ्कों के विभिन्न रूप--किसी भी देश में प्रायः निम्न प्रकार की वैङ्क पाई जाती हैं--

- (१) केन्द्रीय बैङ्क पह वह बैङ्क होती है जो देश के अन्य समस्त बैङ्कों पर नियंत्रण रख कर द्रव्य सम्बन्धी व्यवस्थाओं को सुलभाती है। सरकारी बैङ्क के साथ-साथ केन्द्रीय बैङ्क देश की सुद्रा तथा साख-व्यवस्था पर नियंत्रण रखती है। केन्द्रीय बैङ्क राष्ट्र की आर्थिक अभिभावक होती है।
- (२) सहकारी बैङ्क —यह बैङ्क मुख्यतः कृषकों को ऋण प्रदान करती हैं। को सहकारी बैङ्क कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं उन्हें भूमि-बन्धक बैङ्क कहते हैं। यह बैङ्क अपनी पूँजी सदस्यों को अंश बेचकर, जमा स्वीकार करके तथा ऋण प्राप्त करके संग्रहीत करते हैं। इन बैङ्कों का संगठन असीमित दायित्व के सिद्धान्तानुसार चलाया जाता है और देय धन के मुगतान का पूरा दायित्व प्रत्येक सदस्य पर होता है।
 - (३) श्रीद्योगिक वैङ्क इन बैड्डों का मुख्य कार्य उद्योग-धन्घों को पूँ जी खुटाना है। देश की साधारण न्यापारिक बैंक उद्योग-धन्घों को दीर्घकालीन ऋग्ण प्रदान नहीं करती, श्रतः श्रीद्योगिक वित्त की न्यवस्था करने के लिए एक भिन्न प्रकार की बैड्ड की श्रावश्यकता है।
 - (४) विदेशी विनिमय वैङ्क-इन बैङ्कों को प्रधान कार्यालय विदेशों में होते हैं। उनका मुख्य कार्य विदेशी व्यापार को ऋार्थिक सहायता प्रदान करना तथा विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करना होता है। इस कार्य को संपन्न करने के लिये ये बैङ्क

विदेशी हुन्डियों का क्रय-विक्रय करती हैं। कार्य च्चेत्र व्यापक होने के कारण विदेशी विनिमय बैड्रों की शाखाएँ विभिन्न देशों में फैली रहती हैं।

(४) व्यापारिक बैङ्क —इस प्रकार की बैङ्कों का मुख्य कार्य व्यापार को श्रह्य कालीन ऋण प्रदान करना है। यह ऋण माल गिरवी रख कर प्रतिभूतियों की जमा-नत पर श्रथवा व्यक्तिगत साख पर दिया जाता है। ऋण प्रदान करने के श्रातिरिक्त ये बैङ्क श्रन्य प्रकार की सेवाएँ भी करती हैं।

उपरोक्त विभिन्न प्रकार की सभी बैक्कों का पूर्ण वर्णन अगले अध्यायों में किया बायेगा।

प्रश्न

1. Define "Bank", and explain its place in economic organiza-

बैक्क की परिभाषा दीजिये, तथा राष्ट्र की ऋार्थिक व्यवस्था में इसका स्थान कताइये।

2. Describe functions of a Bank. What should be the essentials of a good banking system?

बैक्क के कार्यों का वर्णन कीजिये। एक अञ्की बैक्क व्यवस्था में क्या गुख् होने चाहिये ?

3. What is meant by Branch Banking and what are its merits and demerits?

शाला बैङ्क किसे कहते हैं ? श्रीर उसके गुगा एवं दोष क्या हैं !

- 4. What is Mixed Banking? Discuss its merits and demerits. मिश्रित बैक्क किसे कहते हैं ? उसके गुया तथा दोष बताइये।
- 5. Do you favour Nationalization of Banks? Give reasons, in the light of Indian conditions.

क्या श्राप बैक्कों के राष्ट्रीयकरण के पन्न में हैं ! भारतीय परिस्थितियों को भ्यान में रख-कर तर्क सहित उत्तर दीजिये।

6. Give an idea about different types of Banks found in India.

मारत में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के बैड्डों का संद्वेप में वर्णन

ग्रघ्याय २ केन्द्रीय वेंक

(Central Bank)

श्रार्थिक महत्व वाले श्राज के संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर केन्द्रीय केंक स्थापित न हो। श्राज सभी ने यह श्रानुभव किया है कि किसी देश के श्रार्थिक विकास के लिये केन्द्रीय बैंक श्राति श्रावश्यक है यद्यपि केन्द्रीय बैंक का विधान तथा उसके श्राधिकार विभिन्न देशों में विभिन्न हैं। फिर भी उद्देश्य समान हैं। यह श्रंतर तो केवल स्थानीय श्रार्थिक ढाँचे के श्रानुसार है। इस पर तो दो मत नहीं है कि केन्द्रीय बैंक को नोट छापने का एकमात्र श्राधिकार होना चाहिए विससे वह देश के द्रव्य बाजार पर पूर्ण नियंत्रण कर सके। श्राज संसार में केन्द्रीय बैंकों का महत्व इतना बढ़ गया है कि बैंकों के वर्गीकरण में इनको प्रथक् स्थान दिया जाता है। प्रारम्भ में केन्द्रीय बैंक साधारण बैंकों वाले कार्य भी करते थे किन्द्र श्रव इनके कार्य सर्वया भिन्न हो गये हैं।

१६वीं शताब्दी के श्रंत में लगभग प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक स्थापित हो चुकी थीं। श्रमरीका में तो केन्द्रीय बैंक (Federal Reserve Bank) की स्थापना सन् १६१३ में ही हुई है। इंगलैगड की बैंक श्राफ इंगलैगड संसार की सर्व प्राचीन केन्द्रीय बैंक है। भारतवर्ष में रिजर्व बैंक के नाम से केन्द्रीय बैंक की स्थापना १६५३ में हुई। १६२० में बुशेल्स में एक श्रन्तर्राष्ट्रीय श्राधिक सम्मेलन हुआ जिसमें सभी देशों ने यह प्रस्ताव पास किया कि उन सभी देशों में जिनमें श्रमी तक केन्द्रीय बैंक स्थापित नहीं हुई है, इनकी स्थापना केवल बैंकिंग तथा मुद्रान्यवस्था के लिये श्रपित, श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग प्राप्त करने के लिये शीव की जाये। इस प्रस्ताव के फलस्वरूव श्राज संसार के सभी सम्य देशों में केन्द्रीय बैंक स्थापित हो गये हैं।

केन्द्रीय बैंक किसे कहते हैं — केन्द्रीय बैंक वह संस्था है जो देश में मुद्रा तथा साल का सम्बन्ध स्थापित करके देश के हित में उनका उचित नियंत्रण करती है, मूल्यों में स्थिरता रखती है तथा देश की बैंकिंग व्यवस्था का संगठन करती है। केन्द्रीय बैंक देश की सभी बैंकों की कर्णधार होती है। यह सम्पूर्ण बैंकिंग संस्थाओं के लिये मित्र तथा स्थप्रदर्शक का कार्य करती है। सार्ध्या में केन्द्रीय बैंक सम्पूर्ण देश के कल्याण

श्रीर बनता के हित में कार्य करती है। इसका प्रारम्भिक उद्देश्य लाभ कमाना नहीं श्रिपिद्व राष्ट्र की सेवा करना है।

प्रथम महायुद्ध के उपगंत केन्द्रीय बैंक के उद्देश्य में कुछ परिवर्तन हुए हैं। व्यापारिक चक्रों के परिणामस्वरूप मूल्यों में जो उतार-चढ़ाव होते हैं उन्हें रोकने तथा अपूरुय में स्थिरता बनाये रखने के लिये किसी संस्था की सहायता की आवश्यकता है। इंग**लैंगड** के प्रमुख अर्थशास्त्री लार्ड कींन्स ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक उच्चतम राष्ट्रीय बैंक ऋर्यात् केन्द्रीय बैंक की स्थापना पर बल दिया। कुछ लोग संकट-काल में आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा आर्थिक मय दूर करने के लिये केन्द्रीय बैंकों की स्थापना के इच्छुक हैं। कुछ अर्थशास्त्री केन्द्रीय बैंक को सरकारी वैंक के नाम से सम्बोधित करते हैं, क्योंकि राज्य का समस्त कोष इसी के पास जमा रहता है और यही सार्वजनिक ऋग की व्यवस्था करती है। आधुनिक काल में राज्य तथा केन्द्रीय बैंक में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुन्ना है कि राष्ट्र के समस्त म्रार्थिक हित इसी संस्था को सौंप दिये गये हैं। साख का निर्माण करके देश के अन्य बैंकों को केन्द्रीय बैंक ऋार्थिक सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय बैंक न केवल अन्य वैंकों की कुछ धनराशि अपने यहाँ जमा रखती है वरन् संकटकाल में उनकी हुँडिया क्रय करके तथा उनकी प्रतिभृतियों की जमानत पर उन्हें ऋगा प्रदान करती है। इस प्रकार न केवल उनकी ऋाधिक सहायता करती है प्रस्तुत संकटकाल में उनका पश्चप्रदर्शन भी करती है। समय-समय पर उन्हें परामर्श भी प्रदान करती रहती है। केन्द्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा नहीं करती। साख नियंत्रण करके यह देश की मुद्रा प्रणाली को लोचदार बनाती है। सारांश में केन्द्रीय बैंक निम्नुलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की बाती है-

- (१) राष्ट्रीय हित के लिए ऋग्यदाता का कार्य करना तथा विभिन्न राज्यों एवं वैंकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- (२) देश में श्रार्थिक स्थिरता स्थापित करना, बैंकिंग प्रणाली का संगठन करना तथा विक्तु संबन्धी उत्तरदायित्व को पूरा करना।
- (३) श्रपनी क्रियात्मक नीति द्वारा देश में श्रार्थिक संतुलन एवं स्थिरता उत्पन्न करना।
- (४) मुद्रा तथा साल सम्बन्धी नीति पर नियंत्रण करना तथा कागजी मुद्रा प्रकाशित करना।
- (५) देश का ऋार्यिक प्यप्रदर्शन करना तथा नवयुवकों को ऋार्थिक विषय में शिश्चित करना।

केन्द्रीय वैंक के कार्य — केन्द्रीय वैंक के कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न अर्थ-शास्त्रियों ने अपने-अपने भिन्न-भिन्न मत प्रकट किये हैं। वेरा स्मिथ के मतानुसार केन्द्रीय वैंक को नोट प्रकाशन का पूर्ण अथवा आंशिक एकाधिकार प्राप्त होता है। और नोट प्रकाशन के इसी एकाधिकार से आधुनिक केन्द्रीय वैंकों के गौगा कार्य उत्पन्न हुए हैं। प्रो० किश के शब्दों में केन्द्रीय वैंक का मुख्य कार्य मौलिक मान की स्थिरता को बनाये रखना है। अर्थशास्त्री हान्द्रे के मतानुसार केन्द्रीय वैंक का मुख्य कार्य अंतिम अप्रादाता का कार्य होता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसे नोट प्रकाशन का एकाधिकार दिया जाता है। केन्द्रीय वैंक के कार्यों में प्रारम्म से ही अब तक बरावर विस्तार होता रहा है। आधुनिक काल में केन्द्रीय वैंक किसी एक कार्य को नहीं वरन अनेक कार्य करती हैं। केन्द्रीय वैंक के दो कार्य निम्नलिखित हैं—

- (१) कागजी मुद्रा प्रकाशित करना—केन्द्रीय वैंकों का विचार स्त्राने से पहले केवल सरकार ही कागजी मुद्रा प्रकाशित करता थी। परचात् यह स्त्रविकार स्त्रांशिक रूप में व्यापारिक वैंकों को दिया जाने लगा। स्त्राज्ञ तो कागजी मुद्रा के प्रकाशन का एकाधिकार केवल केन्द्रीय वैंक को है। केन्द्रीय वैंक ही देश की स्त्रावर्शन कागजी मुद्रा प्रकाशित करता है क्योंकि देश की मुद्रा का स्त्रावर्शन तथा वाह्य मूल्य स्थिर रखने का दायित्व केन्द्रीय वैंक पर होता है। स्तरः इस कार्य में उसे पत्र-मुद्रा प्रकाशन के एकाधिकार से पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। पत्र-मुद्रा का प्रकाशन के एकाधिकार से पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। पत्र-मुद्रा का प्रकाशन राजनीति से मुक्त होकर स्त्रार्थिक स्त्राघार पर होना चाहिये। इसीलिये साधुनिक स्त्रर्थशास्त्री सरकार द्वारा नोट-प्रकाशन के विरुद्ध हैं तथा केन्द्रीय वैंकों को इसका एकाधिकार देने के पन्न में हैं। जनता के विश्वास को बनाये रखने के लिये यह स्त्रावश्यक है कि नोट प्रकाशन का कार्य किसी ऐसी संस्था को सौंपा जाये जिसे राजकीय सहायता उपलब्ध हो। स्रतः स्त्रन्य वैंकों को यह कार्यन सौंप कर केन्द्रीय वैंक को ही इसका स्रिधकार दिया जाता है।
- (२) सरकारी बैंकर केन्द्रीय बैंक सरकारी बैंक का भी कार्य करती है। राज्यों तथा स्थानीय सत्तात्रों का हिसाब खोलकर उसकी घनराशि अपने यहाँ बमा रखती है। कर वस्ता होने से पूर्व सरकारी व्यय का मुगतान करती है। युद्ध तथा अन्य संकट काल में सरकार को ऋग् प्रदान करती है अथवा उसके लिये ऋग् की व्यवस्था करती है। यह सरकार की ब्रोर से सभी ब्राधिक मामलों की देखमाल करती है तथा विदेशी विनिमय एवं प्रतिभृतियों का क्रय विक्रय करती है। वास्तव में केन्द्रीय बैंक सरकार के ब्राधिक-परामर्शदाता को कार्य करती है। केन्द्रीय बैंक के परामर्श से ही मुद्रा, साख, विदेशी विनिमय, लोक ऋग तथा योजना संबन्धी नीतियाँ निर्धारित होती हैं।

- (३) बैंकों के बैंक का कार्य करना—केन्द्रीय बैंक साधारणतया अन्य बैंकों के नकद कीष की रहा करती है। प्रत्येक बैंक अपनी जमा का कुछ निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय बैंक के पास जमा रखती है जिससे संकट काल में इसका उपयोग हो सके। इस नीति से बैंकों की साख-निर्माण शक्ति लोचपूर्ण हो जाती है। नकद कोषों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बैंकों का पारस्परिक लेनदेन मो केन्द्रीय बैंक द्वारा ही होता है। बैंक द्रव्य का प्रयोग न करके केन्द्रीय बैंक के नाम चेक काटकर दूसरे बैंकों का सुगतान कर देती हैं। सभी बैंकों का हिसाब केन्द्रीय बैंक में होने के कारण ये चेक वहाँ जमा हो जाते हैं। केन्द्रीय बैंक संकटकाल में अन्य बैंकों की हुंडियाँ क्रय करकें तथा उनकी प्रतिभृतियों को अपने यहाँ गिरवीं रखकर अपूण प्रदान करती है। समय-समय पर परामर्श देकर उनका पथ-प्रदर्शन करती है। केन्द्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा नहीं करती और यही कारण है कि कह्वीय बैंक देश के अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा नहीं करती और यही कारण है कि
- (४) अन्तिम ऋणदाता का कार्य करना जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है केन्द्रीय वैंक वैंकों को संकटकाल में आर्थिक सहायता प्रदान करके अन्तिम ऋखदाता का कार्य करती है। किन्तु यह आर्थिक सहायता तभी प्रदान की जाती है जब वैंकों को किसी अन्य प्रकार से सहायता प्राप्त न हो सके। व्यापारिक वैंक जिन हुं डियों तथा प्रतिभृतियों को गिरवीं रखकर जनता को अल्पकालीन ऋख देती हैं केन्द्रीय वैंक उन्हें पुनः अपने यहाँ गिरवीं रखकर इन वैंकों को ऋण प्रदान करती हैं। व्यापारिक वैंकों को यह विश्वास होता है कि उनको समय आने पर केन्द्रीय वैंक से आर्थिक सहायता हो जायेगी। अतः वे अपने पास एक थोड़ी मात्रा में नकदी रख कर शेष केन्द्रीय वैंक में जमा कर देती हैं। परन्तु केन्द्रीय वेंक हर समय आर्थिक सहायता नहीं देती, केवल आर्थिक संकट आने पर ही यह सहायता प्रदान की जाती है। इससे दो लाम हैं एक तो व्यापारिक वैंक सतर्कता से काम करती हैं, दूसरे केन्द्रीय वैंक की शक्ति आर्थिक संकटों के लिये संचित रहती है। दुवारा भुनाने की कियाओं का ही यह परिखाम होता है कि जनता का वैंकों के प्रति विश्वास बना रहता है। अन्तिम ऋखदाता का कार्य करके केन्द्रीय वैंक वैंकों को फेल होने से बचाती है।
 - (४) एष्ट्र के घात्विक एवं विदेशी कोष की रचा करना—केन्द्रीय बैंक को नोट प्रकाशन का एकमात्र श्राधकार होता है, श्रातः राष्ट्र का समस्त स्वर्ण इसी के पास बमा रहता है। उस सोने के श्राधार पर ही तो नोट प्रकाशित किये बाते हैं। केन्द्रीय बैंक को देश के स्वर्ण एवं विदेशी विनिमय कोष का संरच्या करने की सावश्यकता इसिंबर मी होती है कि उसको देश में मूल्यों को स्थिर रखना पहता है। विदेशी विनिमय का कोष इसिंबर रखना श्रावश्यक है जिससे श्रान्तर्राष्ट्रीय

व्यापार का संतुत्तन देश के विरुद्ध हो जाने पर विदेशी ऋग्यदाताश्चों का सुगतान किया जा सके।

(६) समाशोधन गृह का कार्य करना— वेन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों के लिये समाशोधन गृह (Clearing House) का कार्य भी करती है। समाशोधन गृह बैंकों का एक सामान्य संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य बैंकों द्वारा उत्पन्न पारस्पिक लेन-देन का हिसाब करना होता है। केन्द्रीय बैंक का प्रमुख देश के अन्य बैंकों पर होता है और यह विभिन्न बैंकों के पारस्परिक लेन-देन का हिसाब इस प्रकार करती है कि अगतान नगदी में न होकर केवल खातों में प्रविष्टियाँ करके किया बाये। केन्द्रीय बैंक में सभी बैंकों के खाते होते हैं, अतः ये बैंक समाशोधन गृह का कार्य मली प्रकार करती हैं।

मान लीजिये पंजाब नेशानल बैंक को जयपुर बैंक से किसी चेक का मुगतान प्राप्त करना है। दोनों ही बैंकों का हिसाब रिजर्व बैंक में खुला है तो रिवर्व बैंक चेक की रकम जयपुर बैंक के नाम डालकर पंजाब नेशनल बैंक की जमा कर लेगा। इसी प्रकार की प्रविष्टियों को समाशोधन कार्य कहते हैं। किसी भी देश में बन व्यापारिक बैंकों की स्थापना हो जाती है तो समाशोधन यह की आवश्यकता पहती है। बिना इसके बैंकिंग व्यवसाय की उन्नति एक स्थान पर जाकर इक जाती है। समाशोधन गृह की स्थापना बैंक के कर्मचारियों को एक-दूसरे के चेक तथा द्रापट इत्यादि का रुपया वसूल करने के लिये बार-बार नहीं जाना पड़ता श्रीर न इन पुरची का सगतान ही नकद रुपयों में करना पड़ता है जिससे मार्ग में रुपयों के क्रूट जाने का भय नहीं रहता और इसकी स्थापना से बैंक को अधिक नकद कीय नहीं रखना पदता । समाशोधन गृह की स्थापना से वैंक कम नकदी रखकर भी अपना काम चला सकती है। इससे बैंकों की कार्यचमता बढ़ती है। प्रत्येक स्थान का समाशोधन यह एक स्वतन्त्र संगठन होता है जिसके अपने नियम होते हैं। अधिकांश समाशोधन गृहों ने यह नियम बना दिया है कि जिस बैंक की चुकता पूँजी एक सीमा से कम होगी वह उसकी सदस्यता नहीं हो सकती। बैंकों को समाशोधन यह के मंत्री को एक प्रार्थनापत्र देना पड़ता है जिसका प्रस्ताव का समर्थन ऋन्य सदस्य इत सकते हैं।

(७) साख पर नियंत्रण करना — अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने केन्द्रीय वैंकों का मुख्य कार्य साख पर नियंत्रण करना बतलाया है। देश के मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तनों से समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव पहता है। कुछ, वर्गों को लाम तथा कुछ को हानि होती है जो सर्वथा अनुचित है। केन्द्रीय वैंक मुद्रा की मात्रा को आव-श्यकतानुसार घटा-बढ़ा कर देश के मूल्य स्तर को स्थिरता प्रदान करती है, मुद्रा की मात्रा पर ही साख-विस्तार निर्भर होता है। देश में मुद्रा की मात्रा व्यापारिक आवश्यकता

से श्रिषिक है तो इससे मूल्य स्तर ऊँचे होते हैं जिससे उत्पादकों को लाभ तथा -उप भोकाश्रों को हानि होती है। मुद्रा की मात्रा कम होने से मूल्य स्तर घटते हैं जिससे कृषकों तथा उत्पादकों को हानि होती है। देश में श्रार्थिक मंदी श्राने के कारण बेरोजगारी बढ़ती है तथा धर्वत्र निराशा का साम्राज्य हो जाता है। श्रातः केन्द्रीय बैंक यह प्रयत्न करती है कि मुद्रा एवं साख की मात्रा व्यापारिक श्रावश्वकृतानुमार ही हो। जब बैंक यह देखती है कि देश में साख का विस्तार श्रिष्ठक मात्रा में हो रहा है तो वह उसकी गति कम करने का प्रयत्न करती है श्रीर साख का विस्तार कम होने पर उसे बढ़ावा देती है। साख पर नियंत्रण करके ही केन्द्रीय बैंक मुद्रा स्किति एवं मुद्रा संकुचन के दोषों को दूर करती है। साख के नियंत्रण से ही श्रांतरिक मूल्यों में स्थिरता श्राती है। केन्द्रीय बैंक विदेशी विनिमय की दरों में भी स्थिरता लाती है। क्योंकि विदेशी विनिमय दरों के परिवर्तनों का प्रभाव विदेशी व्यापार के लिये भातक सिद्ध होता है श्रीर देश की श्रार्थिक उन्नति बहुत कुछ श्रंश में विदेशी व्यापार के संतुलन पर निर्मर है। साख नियंत्रण द्वारा ही देश के उत्पादन एवं रोजगार की स्थित स्थायी रह सकती है।

- (८) केन्द्रीय बैंक की मुद्रा-नीति—किसी निश्चित लद्य की प्राप्ति के हेते मुद्रा की मात्रा में घटत-बद्दत करने की व्यवस्था को मुद्रा-नीति कहते हैं। श्रद्यधिक विकास वाले देशों में मुद्रा-नीति का मुख्य सम्बन्ध बैंकों के साख प्रदान करने की मात्रा की घटत-बद्दत से होता है। मुद्रा-नीति के दो रूप हैं: (श्र) मात्रात्मक (Quantitative), (ब) गुणात्मक (Qualitative)। मुद्रा तथा साख की मात्रा पर नियंत्रण रखने की नीति को मात्रात्मक नीति कहते हैं। इस नीति में केवल इस बात पर विचार किया जाता है कि मुद्रा साख की मात्रा कितनी हो, उसके उद्देश्य से कोई सम्बन्ध नहीं। जब कि गुणात्मक नीति में इस बात पर विचार किया जाता है कि किन कार्यों तथा उद्देश्यों के लिए साख प्रदान की जाये श्रीर किनके लिये नहीं। मान लीजिये यह नीति निर्धारित की गई है कि श्रुण केवल उत्पादक कार्यों के लिये दिये जाये उपमोग के लिये नहीं तो इसे गुणात्मक नीति कहेंगे। केन्द्रीय वैंक श्रपनी मुद्रानीति निम्निक खित लद्द्यों की प्राप्ति के लिये निर्धारित करती हैं—
- (अ) आन्तरिक मूल्यों में स्थिरता प्राप्त करना— स्वर्णमान की समाप्ति के प्रश्वात विशेषकर द्वितीय महायुद्धोपरांत सभी देशों में इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि देश के आन्तरिक मूल्यों में स्थिरता रहे । मूल्य स्थिरता से ही किसी राष्ट्र की आर्थिक मलाई होती है । मूल्यों के परिवर्णन देश के आर्थिक दाँचे को अस्तव्यस्त कर देते हैं और इसका उत्पादकों तथा उत्भोकाओं, शृग्यदाताओं एवं शृश्यियों तथा

स्वामियों तथा कर्मचारियों के सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है। ऋतः ऋांतरिक मूल्यों में स्थिरता रखना ऋत्यावश्यक है।

- (ब) विदेशी विनिमय दरों को स्थिर रखना—ग्रंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वास बनाये रखने के लिये तथा उसे प्रोत्साहन देने के लिये विदेशी विनिमय की दरों का स्थिर होना ग्रत्यावश्यक है। इसी से संसार की ग्रार्थिक मलाई हो सकती है। कुछ लोगों का विचार है कि केन्द्रीय वैंक को ग्रांतरिक मूल्य-स्तर की स्थिरता पर ही ग्राधिक ध्यान देना चाहिये। किन्तु कुछ सीमा तक ग्रांतरिक मूल्यों की स्थिरता मी विदेशी विनिमय की स्थिरता पर निर्मर होती है।
- (स) व्यापारिक एवं औद्योगिक चहल-पहल की स्थिरता—व्यापारिक एवं श्रीचोगिक चहल-पहल की स्थिरता द्वारा ही श्रान्तरिक मूल्यों की स्थिरता रह सकती है। व्यापारिक स्थिरता का तात्पयं देश की जनसंख्या एवं प्राकृतिक साधनों के पूर्ण उपयोग से होती है जिससे श्रार्थिक मंदी नष्ट होकर श्रीचोगिक चहल-पहल हो। किन्तु श्रीचोगिक चहल-पहल का तात्पर्य श्रिषिक उत्पादन (Overproduction) से नहीं है। व्यापारिक चहल-पहल की स्थिरता का बोध इस बात से होता है कि मांस का उत्पादन उतना ही हो जितनी देश की श्रावश्यकता है। कम बा श्रिषक नहीं।
- (द) रोजगार एवं वास्तविक श्राय में वृद्धि—मुद्रा-नीति इस पकार की होनी चाहिये जिससे देश के प्रत्येक प्रायां। को पूर्य रोजगार मिल सके श्रीर उनकी उच्चतम श्राय हो। रोजगार की कमी देश में श्रार्थिक संकट उत्पन्न करती है जिसके दुःखद परिस्थाम निकलते हैं। रोजगार द्वारा ही जनता को सुख मिलता है। इसी से देश में शान्ति रहती है।

जैमा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति मुद्रा की यात्रा में घटत-बढ़त करके ऋथवा साख पर नियंत्रण करके होती है। केन्द्रीय बैंक साख एवं मुद्रा पर कई प्रकार से नियंत्रण करती हैं।

साख पर नियंत्रण करने की रीतियाँ

(१) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)—बब केन्द्रीय बैंक साख तथा मुद्रा का नियंत्रण करने के लिये खुले बाजार में प्रतिभ्तियों का क्रय-विक्रय स्वयं करती है तक बैंक इन क्रियाओं को खुले बाजार की क्रियाएँ कहती हैं।

यदि किसी भी समय जब केन्द्रीय बैंक सोचती है कि अन्य बैंकों के पास अधिक कोष है और वे साख का निर्माण अधिक कर रही हैं तब वह अपने पास की प्रतिभूतियों को बाजार में बेचना प्रारम्भ क्र देती हैं | इन प्रतिभूतियों के केता इनका सुगतान केन्द्रीय बैंक को नकद में अथवा चैक देकर करेंगे | जब इन चैको क्ष मुगतान होगा तब अन्य बैंको का नकद कोष कम हो जायेगा । परिणामतः वे उचार देना कम कर देंगे | उनकी ब्याज दर में वृद्धि होगी और उन्हें साख की मात्रा भी कम करनी पड़ेगी । यदि केन्द्रीय बैंक बाजार में प्रतिभृतियों को क्रय करने लगेगा तो इसका उत्था परिणाम होगा । अर्थात् व्यापारिक बैंको के नकद कोष में वृद्धि होगी । उनकी अपृणा देने तथा साख निर्माण की शर्कि में भी इदि होगी ।

द्रव्य-बाजार में द्रव्य के मौरुमी हेर फेर से तथा सरकारी कोषों से होने वाली गड़वड़ को कम करने के लिये भी खुले बाजार की क्रिया की जाती है। उदाहरण के लिये वर्ष के कुछ मासों में व्यापार की तेजी होती है श्रीर व्यापार को श्रिधिक द्रव्य की श्रावश्यकता होती है उस समय केन्द्रीय बैंक जिल तथा प्रतिभृतियों को खुले बाजार में क्रय करके बाजार में श्रिधिक द्रव्य दे देती है क्योंकि व्यापारिक बैंक भी केन्द्रीय बैंक के ऐसा करने पर श्रिधिक साख का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार यदि सरकार कर रूप में बहुत श्रिषक द्रव्य बाजार में से खरीद ले तो भी बाजार में द्रव्य की कमी हो जाये। उस समय भी केन्द्रीय बैंक बिल तथा प्रतिभृतियाँ क्रय करके द्रव्य की कमी को पूरी करती है।

स्वर्ण-त्रायात तथा निर्यात का जो देश की मुद्रा पर प्रभाव पड़ता है उसको रोकने के लिये भी खुले बाजार की किया की जाती है। उदाहर एक लिये यदि किसी देश में स्वर्णमान हो त्रीर व्यापार का अन्तर (Balance of Trade) देश के विरुद्ध ही आरे स्वर्ण का निर्यात होने लगे तो जनता कागजी नोट के केन्द्रीय बैंक को देकर उससे स्वर्ण के कर बाहर मेजेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि बाजार में भूद्रा की कमी हो जायेगी। उस समय केन्द्रीय बैंक खुले बाजार की किया द्वारा अर्थात बिल और प्रतिभृतियाँ खरीद कर बाजार में द्रव्य की कमी पूरा करती है। यदि स्वर्ण देश में आ रहा हो तो उसका परिणाम यह होगा कि लोग केन्द्रीय बैंक को स्वर्ण देश के सार हो तो उसका परिणाम यह होगा कि लोग केन्द्रीय बैंक को स्वर्ण देश कर उससे नोट लेंगे। देश में कागजी नोट अर्थात मुद्रा आवश्यकता से अधिक हो जायेगी उस समय केन्द्रीय बैंक बिल तया प्रतिभृतियों को कन्द्रा अनावश्यक द्रव्य या मुद्रा को चक्कन में सीच लेती है।

खुदे बाबार की क्रिया इसिलये भी की जाती है कि जिससे काराज की दर मी मिर बाये। और सरकार अपने अपूर्ण को न्याज पर बेच सके अथवा पुराने अपूर्ण को बो ऊर्ची दर पर लिया गया था कम न्याज के अपूर्ण में परिवर्तित कर सके। खुले बाबार की किया का एक उद्देश्य यह भी होता है कि न्याज की दर नीची रहे जिससे आपार पनये और उन्नत हो।

खुले बाजार की किया को सकल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि बाजार में इतनी मात्रा में प्रतिमृतियाँ कर कर ली जारें जिससे बाजार में करने की मरमार हो जाये और उपये की मात्रा बढ़ जाने से ब्याज की दर नीची हो जाये। जब कभी ब्याज की दर बहुत अधिक गिर जाये तो केन्द्रीय बैंक को अपने पास रखी हुई प्रति-भृतियाँ पर्याप्त मात्रा में बाजार में बेचनी चाहिये जिससे जनता में बढ़ा हुआ स्पया बैंक में ही वापस आ जाये और बाजार में स्पये की कमी हो जाने से ब्याज की दर कँची उठ जाये, यदि केन्द्रीय बैंक खुले बाजार की कियाओं में योही ही मात्रा में अतिभृतियाँ खरीदता या बेचता है तो इससे यह उद्देश्य पूरा न होगा जिसके लिये यह किया गया है और साख पर पूरा नियंत्रया न हो सकेगा।

खुले बाजार की क्रियार्थे कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सफल होती हैं।

सदैव नहीं।

खुले बाजार की क्रियाओं की मीमायें

खुले बाजार की क्रियायें केवल निम्नलिखित धीमाश्चों के श्रंतर्गत ही सफल हो सकती हैं। इसके बाहर नहीं —

(१) केन्द्रीय बैंक द्वारा क्रय-विक्रय होने वाली प्रतिभृतियों की माँग एवं पूर्ति वाबार में होनी चाहिये। मुद्रा बाजार के सुवंगठित होने की अवस्था में ही ये कियाये सफल हो सकती हैं। मान लीजिये बैंक प्रतिभृतियाँ क्रय करना चाहती है किन्द्र बाजार में उनकी पूर्ति नहीं है। अथवा बैंक प्रतिभृतियाँ विक्रय करना चाहता है किन्द्र बाजार में उनकी माँग नहीं है तो बैंक को सफलता नहीं मिल सकती।

(२) खुले बाजार की क्रियात्रों के साथ बैंकों की साख निर्माण की नीति में कोई अन्तर नहीं आना चाहिये। यदि केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ खरीद कर बैंकों को अपृण प्रदान करते हैं। किन्तु यह बैंक बाजार में विश्वास की कमी के कारण अपने प्राहकों को ऋण न देकर अपने पास ही नकद राशि बढ़ा लेते हैं इसका साख नियंत्रण

पर कोई प्रमाव नहीं पड़ेगा।

(३, यह भी स्रावश्यक है कि वैंकों के नकद कोषों के घटने बुद्धने का व्यापारियों के ऋषा की माँग पर प्रभाव पड़े। केन्द्रीय वैंक प्रतिभृतियाँ क्रय करके वैंकों के
ऋषा देने की शक्ति में भले ही बुद्धि कर दे किन्तु श्रानिश्चित श्रार्थिक दशाश्रों के कारण
व्यापारी कम व्याज पर भी ऋषा न लेना चाहें तो केन्द्रीय वैंक का खुले बाजार में
स्त्राना विफल रहेगा। इसके विपरीत केन्द्रीय वैंक भले ही प्रतिभृतियाँ विक्रय करने
वैंकों से रुपया खींच ले, किन्तु व्यापारिक चहल-पहल एवं लाम की आशा में व्यापार्र
स्त्रिक व्याज पर ऋषा पाप्त करके केन्द्रीय वैंक की नीति को विफल बना देंगे।

बैंक दर — बैंक दर वह कटोती है जिस पर केन्द्रीय बैंक प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटोती करती है अथवा अन्य प्रकार की शेष प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। इस बैंक दर के द्वारा केन्द्रीय बैंक बहुत सरलता से साख का नियंत्रण कर सकता है। इसके विपरीत बाजार में प्रचलित दर को बाजार दर कहते हैं। यह वह दर है जिस पर देश की बैंक तथा अन्य संस्थायें बिलों को सुनावी हैं और ऋण देती हैं। यह बाजार दर बैंक दर पर ऋगश्चित होती है और उसी के अनुसार घटनी नदती है।

जब संसार में स्वर्णमान प्रथा अचिलत थी उस समय बैंक दर का महत्व बहुत श्रिष्ठिक था। साख नियंत्रण करने का सबसे उत्तम एवं प्रभावशाली उपाय बैंक दर में परिवर्तन करना ही था। केन्द्रीय बैंकों के राजनीति से प्रथक रहने के कारण बैंक दर श्रिष्ठिक महत्वपूर्ण होती है। किन्तु १६३१ में जब स्वर्णमान प्रथा समाप्त कर दी गई तभी से बैंक दर का महत्व कुछ कम हो गया है। दितीय महायुद्ध काल में बैंक दर कम करके मुद्धा प्रसार हुश्रा जिससे उपभोक्ताश्रों तथा जन साधारण को हानि हुई। किन्तु युद्ध के साधन जुटाने के लिये बैंक दर का कम करना श्रावश्यक समक्ता गया था। युद्ध समाप्ति के बाद भी जब मुद्धा-प्रसार का कुचक चलता ही रहा श्रीर जनता की कठिनाई कम न हुई तो बहुत से देशों ने मुद्धा-प्रसार रोकने के लिये बैंक दर कांची की। एक जर्मन विशेषज्ञ के परामर्श पर मारतीय रिजर्व बैंक ने भी श्रपनी बैंक दर स्रित्रात से बढ़ाकर ३५ प्रतिशत कर दी। इससे मूल्यों में गिरावट हुई श्रीर वनता में श्रसंतोष की लहर फैली। स्रतः यह स्पष्ट है कि मुद्धा-प्रसार एवं संकुचन के दुध्यमावों को रोकने के लिये बैंक दर एक क्रियाशील उपाय है।

बैंक दर का सिद्धान्त यदि केन्द्रीय बैंक चाहती है कि अन्य बैंक साख का किर्माण कम करें तो वह बैंक दर या बट्टा दर को ऊँचा कर देगी। इसका परिणाम यह होगा कि अब केन्द्रीय बैंक से अन्य बैंकों को अप्रुण ऊँची दर पर मिलेगा। इसलिये दे भी अपनी ब्याज दर को और ऊँचा उठायेंगे। फलस्वरूप व्यापारी गहरा अप्रुण कम लेंगे। और इस प्रकार साख का निर्माण कम होगा। यदि बैंक चाहती है कि साख निर्माण में अधिक वृद्धि हो तो वह अपनी बैंक दर को कम कर देगी। फलस्वरूप देश की ब्याज दर घट जायेगी और लोग रुपया अधिक उत्पार लेंगे। और इस प्रकार केन्द्रीय कि को साख निर्माण करने का अधिक अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक अपनी दर को ऊँची उठाकर या नीचे गिराकर देश में साख के निर्माण को निर्माण कर सकती है।

वैंक दर की सकियता—वैंक दर तभी सकिय समभी जाती है जब केन्द्रीय वैंक अंतिम भूग्यदाता के रूप में अपनी शर्ते उधार लेने वालों पर थोप सके। जब

बैंक ऐसा करने में सफल होती है तो इस स्थिति को "बाजार का बैंक के हाथ में होना" कहते हैं। बैंक त्राफ इंगलैएड ने बैंक दर का उपयोग एक भीषण शक्ति के रूप में किया। स्त्राज भी बैंक स्राफ इंग्लैंग्ड के संचालक प्रति गुरुवार को बैंक दर निश्चित करते हैं | बैंक दर आंतरिक एवं शहा आर्थिक स्थिति में सुधार करने के जिये प्रयुक्त होती है। जब देश का व्यापारिक संतुलन देश के विरुद्ध हो जाता है श्रीर अंत-राष्ट्रीय भुगतान करने के लिये स्वर्ण देश से बाहर जाने लगता है वो स्वर्ण के इस नियात को रोकने वे लिये बेंक दर में वृद्धि की जाती है। इसके आन्तरिक मल्यों तथा ब्याज की दरों में बृद्धि होती है श्रीर दिना स्वर्ण निर्यात किये अन्तर्राष्ट्रीय भगतान का संतुलन ठीक हो जाता है। बैंक दर ऊँची होने से विदेशी श्रिषिक ब्याज कमाने के हेट प्राप्त होने वाला भुगतान उसी देश में ब्याज पर लगा देते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी पूँजी देश में श्राने लगती है। फ़लस्वरूप देश में स्वर्ण का श्रायात बढ जाता है और निर्यात रक जाता है। उस देश की मुद्रा की निदेशों में मौंग बढती है जिससे विनिमय देश के पन्ने में हो जाती है। वैंक दर ऊँची हो जाने से लोग ऋग कम लेते हैं क्योंकि उन्हें अधिक व्याज देनी होती है। इससे मुद्रा संकुचन होता है। श्रीर व्यापारिक चहल-पहल में कमी हो जाती है। मूल्यों में गिरावट आ जाती है जिससे देश के निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है श्रीर श्रायात कम हो जाती है। फुलस्वरूप व्यापारिक संदुलन देश के पद्ध में हो जाता है।

वैंक दर कम करने का प्रभाव उपरोक्त के सर्वथा विपरीत होता है। इससे
मुद्रा प्रसार होता है, क्यों कि कम ब्याज के लालच में ऋणा लेने वालों की संख्या में
बृद्धि होती है। जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि होने के कारण आंतरिक मूल्यों में
बदोतरी होती है, इससे निर्यात कक जाता है और विदेशी माल का आयात होने लगता
है। फलतः व्यापारिक संतुलन देश के विरुद्ध हो जाता है और स्वर्ण का निर्यात होना
प्रारम्म हो जाता है। यही कारण है कि वैंक दर में कमी केवल तभी की जाती है ज ब
देश में आर्थिक मंदी हो, उद्योग-धन्ये तथा व्यापार ठप हो गये हो तथा निराक्षा
तथा बेरोजगारी का साम्राज्य छा गया हो।

साराश में बेंक दर ऊँची करने से साख का निर्माण कम तथा नीची करने से साख का निर्माण अधिक होता है। दूसरें शब्दों में मुद्रा प्रसार रोकने के लिये बैंक दर में बदोतरी तथा संकुचन की प्रवृत्ति रोकने के लिये बैंक दर में बदोतरी की जाती है। बेंक की दर केवल इसीलिये साख के नियंत्रण में सफल हो जाती है कि यह एक परिपाटी चल पड़ी है कि द्रव्य बाजार में व्यापारिक बैंक अपनी व्याज की दर को केंद्रीय बैंक की दर के आधार पर ही निर्धारित करती हैं। और केन्द्रीय बैंक की दर ऊँची चदती है तो व्यापारिक बैंक भी अपनी व्याज की दर चढ़ा देती हैं और केन्द्रीय बैंक

की दर गिरती है तो वे अपनी ब्याज की दर नीचे गिरा देती हैं। व्यापारिक कैं यह भी जानती हैं कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगी तो केन्द्रीय बैंक के पास श्रीर अस्त्र हैं जिससे वह व्याज की दर को प्रभावशाली बना सकती है। अस्तु वे बैंक केन्द्रीय बैंक के नेतृत्व को स्वीकार कर लेती हैं श्रीर अपनी ब्याज की दर को केन्द्री बैंक के नेतृत्व को स्वीकार कर लेती हैं श्रीर अपनी ब्याज की दर को केन्द्री बैंक की दर के अनुसार निश्चित करती हैं श्रीर फिर चाहे द्रव्य बाजार की स्थित को देखते हुए ब्याज की दर में परिवर्तन की आवश्यकता हो अथवा न हो।

बैंक दर की सफलता की सीमायें — बैंक दर की सफलता निम्नलिखित प

- (१) यदि बैंक दर के परिवर्तन के साथ-साथ बाजारी दर में परिवर्तन नह हुआ तो बैंक दर असफल रहेगी । अतः यह तभी सफल हो सकती है जब देश क सुद्रा बाजार सुसंगठित हो जिससे बैंक दर का प्रभाव देश में प्रचलित सभी ब्याज कं 'हरों पर पड़ सके। यदि ऐसा नहीं है तो बैंक दर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ रहेगी।
- (२) बैंक दर में परिवर्तन से व्यापारियों की ऋषा लेने की लागत प्रभावित होती है जो उत्पादन लागत का एक छोटा-सा अंश है। अतः बैंक दर का उत्पादन-सागत पर प्रभाव सद्भ ही रहता है। जब तक बैंक दर के परिवर्तन का प्रभाव देश की अर्थ व्यवस्था के समस्त चेत्रों पर न पड़े बैंक दर सफल न होगी। अतः देश की अर्थ व्यवस्था लोचपूर्ण होनी चाहिये जिससे बैंक दर का प्रभाव देश की अर्थ व्यवस्था के समस्त मागों अर्थात् मजदूरी, उत्पादन व्यय व यौद्धिक आय इत्यादि सभी पर पड़ सके।

बैंक दर की सिकयता कम होने के कारण

- (१) वर्तमान काल में संसार के सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में ऐसे अस्वितंन हो गये हैं जिन्होंने बैंक दर की सक्रियता कम कर दी।
 - (२) संसार में सस्ती मुद्रा नीति को ऋषिक महत्व दिया गया है।
- (३) बैंक दर की नीति की अपेचा साख नियंत्रण अन्य रीतियों का उपयोग होने सगा है।
 - (४) आंतरिक व्यापार में हुंडियों का प्रयोग कम हो गया है।
- (५) अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य बाजार की प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी है जिससे विदेशी स्ट्रा-बाजार बैंक दर की नीति को सक्रिय नहीं होने देते।
- (६) द्रव्य बाजार में तरल पूँची (Liquid Funds) की अधिकता हो

305

- (७) श्राज्यकल विभिन्न देशों की श्रर्थं व्यवस्था इतनी लोचपूर्णं नहीं है जितनी पहले थी।
- (८) बैंक दर का प्रमाव दीर्घकाल में दिष्टिगोचर होता है, अतः उसका प्रमाव अल्प काल में नहीं पड़ता।

निम्नलिखित कारखों से संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका में बैंक दर इतनी सिक्रय नहीं है जितनी श्रम्य देशों में—

- (श्र) बैंक दर तथा बाजारी ब्याज दर में रीत्यानुसार कोई सम्बन्ध नहीं है।
- (ब) स्वर्ण कोष की श्रिषकता है।
- (स) अमेरिका में सहेबाजी के लिये भारी च्रेत्र है और लोगों की उसमें रुचि है।
- (द) अमेरिका की फैडरल रिजर्व बैंक-बैंक दर निश्चित करने में पूर्ण स्वतंत्र नहीं है।

भारतवर्ष में रिजर्व बैंक बैंक-दर निश्चित करने में स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली है, इसी कारण स्वतन्त्रता के पश्चात् बैंक दर में जो परिवर्तन हुए हैं उनका द्रव्य बाजार पर सुप्रमाव पड़ा है। बैंक दर को सक्रिय करने के लिये वह त्रावश्यक है कि सभी आर्थिक विषयों का पूरा ध्यान करके यह यथा समय निर्धारित की जाये।

बैक्क दर तथा खुले बाजार की क्रियाओं का संबन्ध—विना पारस्परिक सम्बन्ध के बैंक दर तथा खुले बाजार की क्रियाएँ सफल नहीं हो सकतीं। श्रतः श्राव-श्यकता पड़ने पर दोनों शस्त्रों का उपयोग होना चाहिये। यदि कुछ बैक्क जिनके पास पूँजी की श्रधिकता है, कम ब्याज पर श्रूण देने को प्रस्तुत हैं तो बैक्क दर की वृद्धि से साल में कमी नहीं श्रायेगी। ऐसी परिस्थित में केन्द्रीय बैक्क को चाहिये कि बैक्क की दर को सिक्रय बनाने के लिये खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ बेचना प्रारम्भ कर दे जिससे द्रव्य-बाजार का श्रधिक धन केन्द्रीय बैक्क में श्रा जाये। इसी प्रकार बैक्क दर में बिना वृद्धि किये केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ बेचती हैं तो बैंक कुम दर पर श्रपनी हुन्डियों को केन्द्रीय बैंक से भुनाकर साख की कमी नहीं होने देगी। श्रतः खुले बाजार की विधि तभी सफल हो सकती है जब बैंक दर में भी परिवर्षन करा दिया जाये।

साख सम-विभाजन (Rationing of Credit)—वैंक श्राफ इंगलैंड ने १८वीं शताब्दी के श्रंत में साख का सम-विभाजन करके साख-नियंत्रण की नीति श्रपनाई थी। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् कर्मनी के रीचस् वैंक ने भी साख सम-विभाजन की नीति श्रपनाई। केवियत रूस में तो यह नीति वेन्द्रीय वैंक द्वारा पूर्ण क्रमेख अणनाई जाती है। जब केन्द्रीय बैंक को साख-विस्तार श्रनुचित प्रतीत होता है तो वह प्रत्येक बैंक को माँगी हुई मात्रा में श्रूण नहीं देती। वह ऋण का सम-विभाजन कर देती है। श्रीर प्रत्येक बैंक का व्यापार देख कर एक निश्चित राश्चि तक ऋण देने की घोषणा कर देती है। देश की व्यापारिक श्रावश्यकताश्चों को देख कर ऋण की श्रिष्कतम सीमा निश्चित कर दी जाती है श्रीर उसमें से हर बैंक का भाग (Quota) निश्चित कर दिया जाता है। इस प्रकार कोई भी बैंक श्रपने भाग से श्रिष्क ऋण नहीं ले सकती। यह रीति प्रभावकारी श्रवश्य है किन्तु कठोर है। क्योंकि इसमें सब बैंकों के साथ न्याय होना कठिन है। केन्द्रीय बैंक के लिये सभी बैंकों की श्रावश्यकता का ठीक श्रनुमान लगाना श्रसंभव है। यह श्रनुमान एच्एात रहित नहीं हो सकता।

श्रमेरिका के फैडरल रिजर्व बैंक के शासन मंडल को १६३४ में प्रतिमृतियाँ विनिमय ऐस्ट के श्रंतर्गत यह श्रधिकार दिया गया है कि वह श्रधिक सहेबाजी के लिये दी जाने वाली साख का नियंत्रण करने के लिये कुछ श्रावश्यक नियंत्रण निश्चित कर सकता है। १६४६ की भारतीय बैंकिंग ऐस्ट की घारा २१ के श्रंतर्गत रिजर्व बैंक श्राफ इन्डिया को भी यह श्रधिकार है कि वह श्रन्य बैंकों को यह श्रादेश दे सकती है कि वे किन-किन उद्देशों के लिये श्रुण दें तथा कितना उघार प्रतिभृति-श्रंतर (margin) रखें, इस प्रकार जब केन्द्रीय बैंक श्रन्य बैंकों की श्रावश्यकतानुसार धन-राशि देने में कभी कर देती है तब श्रन्य बैंकों के पास भी उघार देने के लिये श्रधिक घनराशि नहीं रहती है श्रीर फलस्वरूप उनकी साख निर्माण की शक्ति में भी कभी हो जाती है।

सीधी कार्यवाही (Direct Action)—कभी-कभी बट्टा दर अथवा खुले बाबार की किया के स्थान पर केन्द्रीय बैंक सीधी कार्यवाही करती है। जब केन्द्रीय बैंक देखती है कि कोई बैंक अपनी पूँजी तथा मुरिच्चत कोष को देखते हुये केन्द्रीय बैंक से अधिक अध्या खेती है अथवा वह बैंक सट्टा या पाटका (Speculation) के लिये अधिक अध्या खेती है अथवा अनावश्यक घंघों को अध्या देती है तो केन्द्रीय बैंक उस बैंक या ऐसे बैंकों के बिलों को मुनाना अस्वीकार कर देती है और यदि उसके बिल मुनाती भी है तो उनसे ऊँदी दर लेकर उन्हें दंडित करती है।

सीधी कार्यवाही को विवेक पूर्ण साख निर्माण भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें केन्द्रीय बैंक इस बात पर पूर्ण रूपेण विचार कर लेती है कि ऋण माँगने वाली बैंक उसकी नीति के ऋनुसार कार्य कर रही है ऋथवा नहीं। उन बैंकों को ऋण नहीं दिया जाता जो केन्द्रीय बैंक की नीति के विरुद्ध कार्य करते हैं। इस कार्यवाही को साख का गुकात्मक नियंत्रण भी कह सकते हैं। ऋमेरिका की फैडरल रिजर्व बैंक को सीधी कार्य-वाही करने के व्यापक ऋषिकार दिये गये हैं। यह बैंक उन बैंकों को यह आदेश दे

सकती है कि वे एक निश्चित सीमा से ऋषिक नकद एवं व्यक्तिगत साल पर ऋखा प्रदान न करें, उसके द्वारा वैंकों को यह ऋषिर दिया जा सकता है कि यदि वे एक निश्चित रकम से ऋषिक ऋखा प्रदान करेंगे तो उन्हें दंड दिया जायेगा। भारतीय रिजर्व वैंक को इस प्रकार के व्यापक ऋषिकार नहीं है।

नैतिक द्वाव (Moral Persuasion)— व केन्द्रीय वैक्क यह देखती है कि साख का अधिक निस्तार न होने देना देश के आर्थिक हित में है और व्यापारिक वैक्क अधिक साख निर्माण कर रही है तो यह उन्हें अपनी वतलाई हुई नीति के व्यवहार में लाने को कहती है । इसी प्रकार यदि केन्द्रीय वैक्क सममती है कि साख का विस्तार होना चाहिये तो वह व्यापारिक वैक्कों को वैसा ही करने को कहती है । केन्द्रीय वैक्क का द्रव्य बाजार में इतना अधिक नैतिक प्रभाव होता है कि प्रत्येक व्यापारिक वैक्क उसकी बात को मानता है । इस प्रकार अपने नैतिक दवाव से ही केन्द्रीय वैक्क साख व नियंत्रण करने में सफल होती है । कहीं-कहीं केन्द्रीय वैक्क साख सम्बन्धी नीति को धोषित कर देती है और व्यापारिक वैक्क उसी के अनुसार अपनी नीति में परिवर्तन कर लेते हैं ।

क्लार्क का कहना है कि जब तक केन्द्रीय बैङ्क को वैधानिक श्रधिकार प्राप्त न हों तब तक उसके नैतिक दबाव का कोई श्रर्थ नहीं । श्रमेरिका में प्रत्येक बैङ्क श्रपनी स्वतंत्र नीति निर्धारित करती है, श्रतः उसके ऊपर फैडरल रिजर्व बैङ्क का नैतिक दबाव कम है किन्तु ग्रेट-ब्रिटेन में जहाँ केन्द्रीय बैङ्क बहुत दिनों से स्थापित है, बैङ्क श्राफ इंगलेंड श्रन्य बैकों पर श्रपना नैतिक दबाव डालने में सफल होता है। जर्मनी में भी केन्द्रीय बैङ्क कई बार नैतिक दबाव डालने में सफल हुई। यद्यपि नैतिक दबाव की कुछ सीमायें हैं। फिर भी वह केन्द्रीय बैङ्क जो बैङ्क दर तथा खुले बाजार की क्रियाश्रों द्वारा साख पर नियन्त्रण नहीं कर सकती श्रपने नैतिक प्रभाव से कुछ, सफलीभूत हो सकती है।

केन्द्रीय बेंक अपनी सदस्य बेंकों के लिये अपनी सामान्य नीति सम्बन्धी आदेश देकर उन्हें सचेत करती रहती है। अपने परामर्श, आदेश तथा चेतावृनी द्वारा अपनी सदस्य बेंकों की साख नीति प्रभावित कर सकती है। युद्धोपरांत मारतीय रिजर्व बेंक ने भी अपनी अनुस्चित बेंकों को कई आदेश दिया कि वे सटोरियों को ऋण प्रदान न करें और प्रतिभृतियों तथा बहुमूल्य धातुओं की जमानत पर जो ऋण दिया जाये उसके लिये पर्याप्त मार्जिन रखें अर्थात् उनके मूल्य का कम प्रतिशत ही ऋण रूप में दिया जाये। केन्द्रीय बेंक तथा सदस्य बेंकों का यह पारस्परिक सहयोग देश की बेंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा सही बेंक नीति निर्घारित करने में सहायक होता है। श्रान्य जपाय—केन्द्रीय बैंक समय-समय पर सुद्रा बाजार की स्थिति का श्रान्यन करती रहती है श्रीर इस स्थिति से सुद्रा बाजार को ज्ञान कराने के लिये उद्योग, व्यापार, श्रायात, निर्यात, रोजगार तथा सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी श्रांकड़ों को प्रकाशित करती रहती है। केन्द्रीय बैंक का यह विज्ञापन तथा प्रचार राष्ट्रीय हित के लिये नीति को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। कनाडा की केन्द्रीय बैंक ने साख पर नियंत्रण करने के लिये लोचपूर्ण विनिमय दरों को ग्रहण करके व्यापारिक बैंकों को डिपाजिट प्रमाणपत्र जारी किये हैं।

केन्द्रीय बैंक उपरोक्त उपायों द्वारा साख पर नियंत्रण कर सकती है। किन्तु उपरोक्त उपायों का ठीक प्रयोग बैंक के विघान एवं संगठन पर निर्मर है। इस सम्बन्ध में मिन-मिन अर्थशास्त्रियों के मिन्न-मिन्न मत हैं। कुछ अर्थशास्त्री केन्द्रीय बैंक की अन्य कम्पनियों की माँति व्यक्तिगत रूप से संगठित करने के पच्च में हैं। कुछ उसके राष्ट्रीयकरण के पच्च में तर्क देते हैं। आधुनिक काल में समाजवाद का बोलबाला हो बाने पर राष्ट्रीयकरण की पृत्व स्थान अधिक है। बैंक आफ इंगलैंड, बैंक आफ फांस तथा भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकरण हो ही गया है। अमेरिका, नीदरलैंड तथा कुछ अन्य देशों में यह बैंक व्यक्तिगत रूप से चलाई जा रही है। केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के पच्च तथा विपच्च में प्रायः निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं:—

राष्ट्रीयकरण के पत्त में

- (१) केन्द्रीय बैंक श्रापने कार्यों से पर्याप्त लाम प्राप्त करती है। जो केन्द्रीय बैंक हिस्सेदारी की होती हैं वे श्रापने लाम का सरकार द्वारा निर्धारित लामांश श्रापने हिस्सेदारों में बाँट देती हैं। लाम का यह माग बहुत थोड़ा होता है। श्राधिक माग सरकार द्वारा जनहित में उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार व्यवहार में केन्द्रीय बैंक एक सरकारी बैंक के रूप में कार्य करती है। इससे श्राच्छा तो यह होगा कि हिस्सेदारों को थोड़ा भी लामांश प्राप्त न हो श्रीर सारा का सारा लाम राष्ट्रीय हित में व्यय कर दिया जाये जिसके लिये सरकारी स्वामित्व का होना श्रावश्यक है।
- (२) कैंन्द्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जिसको सार्वजनिक हित के लिये कार्य करना पड़ता है श्रीर इसलिये उसे अपने कार्यों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। यदि केन्द्रीय बैंक को मुचार रूप से देश के हित में कार्य करना पड़ता है तो उस पर सरकार का ही पूर्ण स्वामित्व होना चाहिये।
- (३) क्योंकि केन्द्रीय बैंक को अपने अधिकांश कार्यों पर एकाधिकार प्राप्त होता है इसिलये यह आवश्यक है कि उस पर सरकारी नियंत्रण रहे जिससे वह अपने कार्यों को मली-माँति सम्पन्न कर सके।

(४) केन्द्रीय बैंक को अधिकतर ऐसे कार्य करने होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जिनका प्रत्यच्च सम्बन्ध सरकार से होता है। यदि इन कार्यों को सुचार रूप से सम्पन्न न किया जाये तो देश में एक भारी अधिक हानि होने की संभावना होती है, हसीलिये केन्द्रीय वैंकों का राष्ट्रीयकरण अत्यंत आवश्यक है।

विपत्त में — राष्ट्रीयकरण हो जाने पर केन्द्रीय वैंक के कर्मचारी सरकारी नौकर हो जाते हैं। उन्हें तो अपनी वार्षिक उन्नति से सम्बन्ध है; वैंक की उन्नति से नहीं। निकम्मे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है और कुशल कर्मचारी हतोत्साहित होते है।

- (२) बैंकों की व्यवस्था की बटिल समस्या है। श्रतः इनका संगठन कुछ विशेषज्ञ कर सकते हैं; सरकारी श्रिषकारी नहीं। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति राज-नीतिक श्राधार पर होती है; कार्य-कुशलता के श्राधार पर नहीं।
- (३) राष्ट्रीयकरण से वेंक संगठन में लाल फीताशाही का जन्म हो जाता है। छोटे-छोटे मामलों पर निर्ण्य देने में भी छनावर्यक समय लग जाता है। मारतीयं जीवन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण हो जाने पर कार्य इतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले था। कभी-कभी भुगतान करने में कमैचारी इतनी असावधानी करते हैं कि वह जोखिम में पड़ जाता है।
- (४) बैंकों का संगठन सरकार के हाथ में आ बाने पर राजनीतिक आधार पर होता है। व्यापारिक आधार पर नहीं। मनमानी मुद्रा नीति निर्घारित करके सरकार अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा कर लेती है। मने ही जनता पर उसका कुछ भी प्रभाव पढ़े। सरकारी संगठन में मद्रा स्थिति तथा मुद्रा-प्रसार का भय रहता है।

जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है बहुत से देशों में केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीय-कर्रण हो गया है। भारत में तो न केवल रिजर्व बैंक श्रिपित उसके एजेंट स्टेट बैंक श्राफ इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण हो गया है।

प्रश्न

r. What functions are performed by Central Banks? How far is the Reserve Bank of India performing those functions?

केन्द्रीय बैंक के क्या कार्य हैं ! भारत की रिजर्व बैंक इन कार्यों को कहाँ तक सम्पन्न करती हैं !

2. How does a Central Bank control Currency and Credit? Bxplain with special reference to Reserve Bank of India.

केन्द्रीय बैंक मुद्रा तथा साख पर किस प्रकार नियंत्रण करती है ? रिश्वर्व बैंक के उदाहरण से समकाइये। 3. Critically examine the place of a Central Bank in the currency and banking system of a country with particular reference to the position of the Reserve Bank of India.

मारतीय रिजर्व बैंक के उदाहरण देते हुए किसी देश की मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था में केन्द्रीय बैंक के स्थान की विवेचना की जिये।

4. Show how the Central Bank can control other banks and make its credit policy effective.

केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण करके उनकी साल नीति को सिक्रय बनाती है !

5. What is meant by "Open Market Operations."? How does it differ from Bank Rate?

खुले बाजार की कियाओं का क्या अर्थ है ? यह बैंक दर से किस प्रकार मिन्न होती है ?

भ्रध्याय ३

भारतीय मुद्रा बाजा

(Indian Money Market)

मुद्रा बाजार का अर्थ — मुद्रा बाजार वह स्थान है जहाँ मुद्रा के प्राहक (उचार लेने वाले) मुद्रा के विकेताओं (उचार देने वालों) के संपर्क में आकर मुद्रा के उपयोग सम्बन्धी कय-विकय और लेन-देन करते हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रा बाजार उस बाजार को कहते हैं जहाँ उधार लेने वाले उधार देने वाले लोगों से ज्याज पर योड़े समय के लिये उधार लेते रहते हैं। मुद्रा बाजार का प्रयोग दो शब्दों में किया जा सकता है। विस्तृत अर्थ में दूसरे अंतर्गत सभी प्रकार के आर्थिक लेने देनों तथा प्रमुख मुद्रा बाजार पूँजी बाजार, विदेशी विनिमय बाजार, सोना चाँदी बाजार आदि बहुत स्वतन्त्र रूप से संगठित बाजारों का भी समावेश कर लिया जाता है। परन्तु संकुचित अर्थ में इसके अंतर्गत केवल अल्पकालीन आर्थिक लेन-देन आते हैं। अर्थात् यह उस अल्पकालीन कीष का भंडार सम्भा जाता है जिससे व्यापार तथा उद्योग-मन्थों को अल्पकालीन अपूर्ण मिलता रहता है।

भारतीय मुद्रा बाजार के अंग — अन्य बाजारों की भाँति मुद्रा बाजार के भी दो अंग होते हैं। क्रेता अर्थात् रुपया उघार लेने वाले और विक्रेता अर्थात् रुपया उघार देने वाले । मुद्रा बाजार में रुपया लेने वाले होते हैं — केन्द्रीय तथा राज्य की सरकार, स्थानीय सरकार जैसे जिला अंतरिम परिषद, नगरपालिका तथा महानगरपालिका। जो समय-समय पर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अन्य मुद्रा बाजार से लेती रहती हैं। ज्यापारी उद्योगपित, आयात-निर्यात कर्त्ता इत्यादि जो अपनी कार्यशील पूँजी, प्रतिज्ञा-पत्रों, हुरिडयों तथा अन्य जमानतों पर लेते रहते हैं। कृषक तथा जमीदार जो सेती, भूमि तथा अपने अन्य कमानतों पर लेते रहते हैं। कृषक तथा जमीदार जो सेती, भूमि तथा अपने अन्य कमानतों के लिये मकान, जमीन इत्यादि रखकर अनुख लेते हैं। अन्य लोग सामाजिक तथा धार्मिक संस्थायें भी कभी-कभी अपने कार्यों के लिए मुद्रा बाजार से अनुख लेते हैं।

रुपया उघार लेने वालों में सेठ, साहूकार, देशी बैक्क, सहकारी समिति, भूमि बंधन बैक्क श्रीद्योगिक बैक्क, पोस्ट श्राफिस, बीमा-कम्पनियाँ, विनिमय बैक्क, सम्मिलित पूँची वाले बेंक्क, इम्पीरियल बेंक्क आफ इंडिया तथा रिजर्व बेंक आफ इंडिया इत्यादि होते हैं जो समय-समय पर अपनी कार्य पद्धति के अनुसार अपने प्राहकों को रुपया उधार देते हैं।

भारतीय मुद्रा बाजार के इन ऋंगों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है—

(१) ऋगदाता-

- (क) योरोपीय तथा केन्द्रीय भाग—इस भाग के स्रंग रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, विनिमय बैंक, जीवन बीमा निगम तथा डाक विभाग है।
- (ख) भारतीय तथा स्वदेशी भाग—इस भाग में महाजन, साहूकार, स्व-देशी वैंकर, ऋण-कार्यालय, चिट कोष (जो दिख्णी भारत में पाये जाते हैं), व्यापारिक बैंक, सेविंग बैंक ब्रादि सम्मिलित किये जाते हैं।

ऋए लेने वाले —भारतीय बाबार में उधार लेने वाले निम्नलिखित हैं: —

- (क) केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकारें, श्रन्य स्थानीय सरकारी संस्थायें तथा विदेशी सरकारें।
 - (ख) व्यापारी तथा उद्योगी वर्ग ।
 - (ग) कुषक वर्ग
 - (घ) साधारण जनता।

मुद्रा बाजार का समस्त लेन-देन नकद घन, बिलों, प्रतिज्ञा-पत्रों ऋंशों तथा ऋरुमकालीन प्रतिभृतियों व ऋन्य शाखाओं द्वारा होता है।

भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएँ — कुछ लोगों का कथन है कि मुद्रा बाजार एक बड़ी सुरंगठित व्यवस्था है। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। उन देशों में भी जहाँ बैंकिंग व्यवसाय श्रति उन्नति पर है श्रीर जिसका मुद्रा बाजार पर बड़ा प्रभाव है वहाँ भी मुद्रा बाजार एक अस्त-व्यस्त संगठन है। अनेक भागों तथा उपविभागों में विमाजित है और प्रत्येक उपभाग का अलग चेत्र है। भारतीय मुद्रा बाजार तो श्रीर भी अधिक अस्तव्यस्त है। यहाँ पर संगठित संस्थाओं एवं स्वदेशी बैंकरों के मध्य एक गहरी खाई है। और ये दोनों वर्ग पूर्ण स्वतन्त्रता एवं प्रतिस्पर्धा के साथ कार्य करते हैं।

दूसरी विशेषता यह है। कि भारतीय मुद्रा बाजार में इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया का जो अब स्टेट बैंक में परिवर्तित कर दी गई है, बड़ा प्रभाव रहा है। यह बैंक एक शक्तिशाली व्यापारिक बैंक है और रिजर्व बैंक की प्रतिनिधि होने के नाते विशेष अधिकार प्राप्त है। अन्य व्यापारिक भारतीय बैंकों के प्रति इसका व्यवहार असहानुभृतिपूर्ण रहा है। तीसरे भारतवर्ष विदेशी वैंकों का भी ऋड्डा रहा है जिसके स्वामी एवं गसंठक पूर्णतया विदेशी रहे हैं। इन वैंकों ने भारतीय झांतरिक व्यापार को कभी कोई सहायता नहीं दी। रिंजर्व वैंक की स्थापना के पश्चात् इनके कार्यों पर कुछ नियंत्रस्य किया गया किन्तु इतना नहीं जितने की आवश्यकता थी। ऋतः बहुत से विषयों में ये भारतीय वैंकों से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें हानि पहुँचाते रहे।

श्रंत में १६३५ तक भारतीय बैंकों के संरक्षण एवं मार्गदर्शन के लिये कोई केन्द्रीय बैंक न थी। रिजर्व बैंक ने भी प्रारम्भ में इतना संरक्षण एवं नियंत्रण नहीं किया जितना श्रन्य देशों में केन्द्रीय बैंक करती है।

उपरोक्त विशेषतात्रों ने भारतीय मुद्रा बाबार में निम्नलिखित दोष उत्पन्न कर दिये—

भारतीय मुद्रा बाजार के दोष

- (१) विभिन्न श्रंगों में घनिष्ट सम्बन्ध की कमी—मुद्रा बाबार के विभिन्न भागों में न तो परस्पर कोई गहरा सम्बन्ध व सम्पर्क है श्रीर न इनके विभिन्न श्रंगों में कोई घनिष्ठ सहयोग ही है। भारतीय मिश्रित पूँची वाली बैंक, स्टेट बैंक, विदेशी विनिमय को तथा सहकारी बैंकों को श्रपना प्रतिद्वंदी मानते हैं तथा सहकारी बैंकों का देशी बैंकरों तथा साहूकारों से भी तिनक सम्बन्ध नहीं रहता। देशी बैंकरों श्रीर साहूकारों में भी कोई श्रिषक घनिष्ठ संबंध नहीं रहता श्रीर इन दोनों का सम्बन्ध भी इम्पीरियल बैंक तथा मिश्रित पूँची वाली बैंकों से बहुत कम स्थापित हो पाता है। श्रव रिचर्व बैंक स्थापित होने से यह दोष दूर हो गया है।
- (२) ब्याज की दरों में श्रांतर—मुद्रा बाजार के विभिन्न श्रंगों में धनिष्ठ सम्बन्ध न होने तथा उनका प्रभावशाली नियंत्रण न होने के कारण वैंक दर, बाजार ब्याज दर, स्टेट बैंक की हुंडी तथा बट्टा दर में बहुत श्रिषक श्रंतर रहता है। मिन्न-भिन्न स्थानों पर ब्याज की दर भी भिन्न होती है। ऐसी परिस्थित में रिजर्व बैंक की दर भी प्रभावशाली नहीं हो सकती। भारतवर्ष के विभिन्न बैंक श्रापस में प्रतिस्पर्धा करके श्रिषक जमा राशि प्राप्त करने के लिए भिन्न प्रकार के प्रलोभन देती हैं। एक सुसंग-टित मुद्रा बाजार में ब्याज की दर बैंक दर पर निर्मर होनी चाहिये। रिजर्व बैंक का कर्तव्य है कि वह ब्याज दर की सीमा निर्धारित करके इस विभिन्नता को दूर करे।
- (३) स्थिरता का श्रभाव कृषि-प्रधान देश होने के नाते ब्याज की दरें श्रृत परिवर्तन के साथ घटती-बढ़ती रहती हैं। शीत श्रृत में जब व्यापारिक चहल-पहल श्रिषक होती है तो ब्याज की दर ऊँची हो जाती है। वर्ष श्रृत में यातायात बन्द

हो जाने से न्यापार में कमी आ जाती है और फलस्वरूप न्याज की दर भी कम हो जाती है।

- (४) लोचपूर्ण नहीं—रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले इम्पीरियल बैंक ही साख पर थोड़ा-बहुत नियंत्रण करती थी। ख्रतः इसमें सम्य स्थापित नहीं हो पाता था यद्यपि रिजर्व बैंक ने इस दोष को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया है फिर भी भारतीय मुद्रा बाजार में पूर्ण लोच नहीं छा पाई। व्यापारिक ख्रावश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा उसी अनुपात से नहीं घटती-बढ़ती। भारतीय बैंकों के साधन बहुत सीमित हैं। उनके कोष भी परिमित हैं। ख्रतः देश के बढ़ते हुए व्यापार की आवश्यकताएँ पूरी करने में भारतीय मुद्रा बाजार असमर्थ रहता है।
- (४) धन का अभाव—भारत के अधिकांश निवासी निर्धन हैं। उनकी आय बहुत कम है। अतः उनमें बचाने की शक्ति नहीं। जो लोग बचाते भी हैं वे धन को बमीन में गाड़ कर रखते हैं अथवा आभूषण बनवा लेते हैं। अपने असमान वित-रख एवं शिचा के अभाव के कारण भारतीय धन का उचित उपयोग नहीं हो रहा है। उद्योग-धन्धों तथा व्यापार की आवश्यकता पूँजी की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त धन नहीं है। कुछ बैंकों के फेल हो जाने से जनता में बैंकों के प्रति विश्वास कम हो गया। बहुत से स्थानों पर बैंकों की सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। यदि प्राप्त भी हैं तो भी अविश्वास के कारण अधिकांश लोग बैंकों में अपनी बचत जमा करने से डरते हैं। प्रामीणों की बचत तो किसी भी अवस्था में बैंकों में न आने से देश के काम नहीं आती। अतः धन की कमी से भारतीय सुद्रा बाजार शक्तिहीन है।
- (६) साहूकारों का प्रभाव आधुनिक बैंकों की स्थापना हो जाने पर मी साहूकार तथा देशी बैंकर बड़े प्रभावशाली हैं। प्रामीण चेत्रों में उनका बोलबाला है ही। देश के आंतरिक व्यापार में भी उनका पूरा हाथ है। इस पर पूर्ण नियंत्रण करना कठिन है। अत: ये स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करते हैं और उनकी कार्य-विधि प्रत्येक स्थान पर अलग है। किन्तु यह आशा की जाती है कि देश भर में प्राम पंचायतें स्थापित हो जाने पर सहकारी बैंकों को प्रोतसाहन मिलेगा और साहूकारों का महत्व कम हो त्रायेगा।
- (७) समाशोधन गृहों की कमी—भारतीय मुद्रा बाजार का सबसे बड़ा दोष यह है कि यहाँ पर समाशोधन गृहों की कभी है। ये गृह केवल बड़े-बड़े नगरों में स्थित हैं। इससे बाजार के भिन्न-भिन्न अंगों के आपसी लेन-देन पूरा करने में असु-विधा रहती है।
- (म) हुन्ही प्रचलन की कमी—मारतीय मुद्रा बाजार में आब भी हुन्हियों की अभाव है। विदेशों में बैक्कों के घन का अधिकांश भाग हुन्हियों में विनियोजित होता



वाला केता इन हुन्डियों को अपने बैङ्क से बड़े पर भुना लेता है। यद्यपि इस प्रकार की हुन्डियों का प्रचलन बढ़ रहा है फिर भी भारतीय बैङ्कों का बहुत कम धन इन हुन्डियों को खरीदने में काम आता है।

भारतीय रिजर्व बैक्क जब तक हुन्डियों के संबन्ध में उदासीन रहेगी श्रीर उनकी नीति श्रत्यिक श्रसावधानी की रहेगी हम श्रन्छे हुन्डी बाजार की श्राशा नहीं कर सकते। श्रमेरिका के संयुक्त राज्य में एक श्रन्छी फैडरल रिजर्व बैक्क की स्थापना के हुन्डी बाजार का विकास किया। भारतवर्ष में रिजर्व बैक्क ने हुन्डी भुनाने की बहुत कम सुविधायें प्रदान की हैं। वह केवल "मान्य" हुंडियों का ही क्रय-विक्रय करती है। कभी-कभी मान्य शब्द के मिन-भिन्न श्रर्थ लगाकर हुन्डियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती। इन हुन्डियों के सम्बन्ध में रिजर्व बैक्क स्वयं श्रथवा स्टेट बैक्क के द्वारा हुंडी लिखने, स्वीकार करने तथा भुनाने वालों की श्रार्थिक स्थिति की छानबीन करती है। व्यापारी लोग इस प्रकार की छानबीन को पसंद नहीं करते क्योंकि इससे उनके व्या-पार की गोपनीयता के मंग होने का मय रहता है। यह तो ठीक है कि श्रन्तिम श्राण्य दाता के रूप में श्रुण देते समय बैक्क को सतर्क रहना चाहिये। किन्तु मुद्रा बाजार सुसंगाठित करके हुन्डी के प्रचलन का विकास करना भी उसका परम कर्त्तव्य है।

भारत में हुन्डी बाजार की उत्पत्ति—रिजर्व बैक्क ने हुन्डी बाजार की उत्पत्ति के प्रश्न पर कई बार विचार किया। किन्तु इस विचार को सर्वाधिक महत्व तो उस समय दिया जब नवम्बर १६५१ में बैक्क दर ३ प्रतिश्वत से बढ़कर ३ प्रतिश्वत की गई। जनवरी १६५२ में कुळ बड़ी-बड़ी बैंकों के परामर्श से रिजर्व बैंक ने एक हुंडी बाजार योजना तैयार की। प्रारम्भ में यह योजना अनुभव प्राप्त करने के लिये चालू की गई। किन्तु प्रथम वर्ष में इसका अधिक स्वागत होने से यह योजना स्थाई कर दी गई। किन्तु प्रथम वर्ष में इसका अधिक स्वागत होने से यह योजना स्थाई कर दी गई है। इस योजना के पूर्व अनुस्चित बैंक अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रिजर्व बैंक से प्रतिभृतियों की जमानत पर अनुस्य प्राप्त करती थीं। किन्तु यह प्रथा गुसारमक नियंत्रस्य के लिये उपयुक्त न थी। और इसके कारस्य मुद्रा बाजार लोचपूर्य नहीं था। हुन्डी बाजार की योजना इस कमी को पूरा करने में सफल हुई। हुन्डी बाजार न्ये योजना इस कमी को पूरा करने में सफल हुई।

- (१) रिजर्व वेंक अधिनियम की घारा १७ (४) (स) के अंतर्गत सभी अनुस्चित वेंक उन हुन्डियों की जमानत पर ऋषा प्राप्त करने की अधिकारी हैं जो ६० दिन के अंदर मारतवर्ष में ही देय हैं। इस योजना में ऐसी हुन्डियों की जमानत पर केवल ऋष दिया जा सकता है उन्हें सरीदा नहीं जा सकता।
- (२) किसी मी बैंक को इस प्रकार का ऋगा १० लाख से अधिक तथा किसी एक हुन्ही पर ५० हजार से अधिक का ऋगा नहीं दिया जा सकता।

N

- (३) इन हुंडियों के आधार पर याचना-ऋग तभी दिया जा सकता है जब रिजर्व केंक इन हुंडियों की सत्यता से संतुष्ट हो जाये। संतुष्ट होने के लिये रिजर्व केंक पूरी छान-बीन करती है।
- ' (४) धारा १७ (४) (स) के अंतर्गत यह विधान किया गया है कि ऐसी हुन्ही पर कम से कम दो या इससे अधिक अच्छे पद्धों के हस्ताच् र होने चाहिये जिनमें से एक अनुस्चित वैंक हों। अनुस्चित वैंक यह प्रमाशित करती है कि उस पद्ध की जिसने हुंडी स्वीकार की है, आर्थिक अवस्था अच्छी है।
- (4) क्योंकि योजना के श्रंतर्गत इन हुन्डियों की जमानत पर केवल शृथा जिया जा सकता है, भुनाया नहीं जा सकता। श्रतः शृथा लेने वाली वैंक शृथा का भुगतान करके इन हुन्डियों को चाहे जब हुड़ा सकता है। शृशा का भुगतान योड़ा- थोड़ा करके किया जा सकता है।
- (६) इस प्रकार की हुन्डियों को प्रोत्साहन देने के लिये रिकर्व बैंक ने ऋपनी केंक दर से चौथाई प्रतिशत व्याख कम लेना कि इन्त किया है। १ मार्च सन् १६५६ से पहले यह रियायत ऋाधा प्रतिशत थी। यदि बैंक दर ३-३ प्रतिशत है तो इन हुन्डियों की जमानत पर जो ऋखा दिया जायेगा उस पर केवल ३ प्रतिशत न्याख लगेगी।

इस योजना ने पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। सन् १६५२ में इस योजना के अंतर्गत केवल पर करोड़ रूपये के ऋण दिये गये ये जब कि १६५७ में ६६० करोड़ । यदि क्याज की रियायत आधा प्रतिशत घटा कर चीथाई प्रतिशत की जाती तो बैंक और अधिक ऋण प्राप्त कर लेती। १ मार्च १६५६ से पहले हुन्डियों पर लगे स्टाम्प का आधा व्यय रिजर्व बैंक सहन करती थी। इस रियायत की समाप्ति का इस योजना पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ा। रिजर्व बैंक को इस योजना को अधिक सफल बनाने के लिये कुछ और सुविधायें प्रदान करनी चाहिये क्योंकि अधिक हुन्डी प्रचलन से मुद्रा बाजार का विकास होता है।

भारतवर्ष में बेंकिंग व्यवसाय का विकास— स्पया उधार लेने-देने की प्रया भारत में प्राचीन काल से चली श्रा रही है। हुंडी तथा बिल का श्रयौग व्यापार में यहाँ तब से ही हो रहा है जब पाश्चारय देशों में लोगों को बेंकिंग शब्द का जान तक न था। महाजन तथा सेठ लोग देश का श्रान्तरिक तथा विदेशी व्यापार स्पया उधार ले-दे कर श्रंग्रेजों के भारत श्रागमन तक चलाते रहे। परन्तु जब श्रंग्रेजों ने भारतीय व्यापार में भाग लेना प्रारम्भ किया तब भारतीय सेठ-साहुकारों का पतन होने लगा जिसका मुख्य कारण यह था कि श्रॅग्रेज व्यापारी भारतीय महाजनों की पद्मति से परिचित न थे। श्रवः वे उनसे सहुयोग न कर सके। श्रॅग्रेजों ने श्रपने

व्यापार की सुविधा के लिये बंगाल, मद्रास तथा बम्बई में प्रेसीडेन्सी बैक्क स्थाफि किये। इन वैङ्कों के कार्य संचालन में ईस्ट इंडिया कम्पनी का ही सबसे बड़ा हार था। कुछ दिन पश्चात् इन बैङ्कों को नोट छापने का ऋघिकार भी दे दिया गया तथ इनको देश के अन्य मागों में अपनी शाखायें भी खोलने की अनुमति दे दी गई। परन्तु विदेशी ब्यापार में इन प्रेसीडेन्सी बैङ्कों का कोई हाथ न था। इन बैङ्कों क व्यवस्था बहुत अच्छी न थी क्योंकि इनके कार्य संचालन के लिये देश में को केन्द्रीय बैक्क न था। वाडलर कमीशन तथा चेम्बरलेन कमेटी ने देश में एक केन्द्रीय बैङ्क स्थापित करने पर बहुत बल दिया। ऋतः १६२१ में तीनों प्रेसीडेन्सी बैङ्कों के मिलाकर इम्पीरियल बैङ्क के नाम से एक अर्घ सरकारी बैङ्क चालू कर दी गई इम्पीरियल बैंक को पूरी तरह से केन्द्रीय बैंक कहना तो ठीक न होगा परन्तु उं केन्द्रीय बैंक के कुछ अधिकार प्राप्त थे। यह एक सम्मिलित पूँजी वाली बैंक थी जिस पर सरकार कानून द्वारा नियंत्रण करती थी। समय समय पर इस बैंक के कार्यों क बहुत आलोचना हुई क्योंकि जिस आशा से यह बैंक चालू की गई थी वह पूरी न हुई। दूसरे वैंकों की सहायता तथा पथ-प्रदर्शन करने के स्थान पर इम्पीरियल वैंक उसकी प्रतिद्वन्द्वी बन गई। इसने भारतीय व्यापारियों से अन्छा व्यवहार न किया बड़ी-बड़ी नौकरियों पर अँग्रेकों की ही नियुक्त की गई, और भारतीयों को बैंकिन ट्रेनिंग से वंचित रखा गया। इम्पीरियल वैंक स्थापित होने से पहले देश में कुछ सम्मिलित पूँची वाली व्यापारिक बैंक स्थापित हो गई थी श्रौर उनमें बहुत सी बैंक सफल न हो सकीं ऋौर उन्हें कार्य बन्द करना पड़ा। क्यों कि इन बैंकों की कार्य पद्धति आधुनिक ढंग की न थी और उनके कर्मचारियों को किसी प्रकार की वैंकिंग प्रशिचा प्राप्त न थी। बैंकों को फेल होने से बचाने तथा उनका पथ-प्रदर्शन करने को इम्पीरियल बैंक स्थापित की गई थी। परन्तु इम्पीरियल बैंक ने इन भारतीय बैंकों के साथ सदा ही सौतेली माँ-का-सा व्यवहार किया था। अतः भारतीय अर्थशास्त्रियौ ने यह स्रावाज उठाई कि इम्पीरियल बैंक को दिये हुए स्रिधिकार वापस लेकर उनके स्थान पर एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना करनी चाहिये। १६२५ में हिल्टन यंग कमीशन ने मी प्रिजर्व बैंक की स्थापना पर बल दिया। बहुत वाद-विवाद के पश्चात् १६३४ में रिजर्व वैंक आप इंडिया कानून तैयार किया गया और पहली अप्रैल १६३५ को रिजर्वे वैंक ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया। इस बैंक को हर प्रकार से विदेशी वैंकों-सी बनाने का प्रयत्न किया गया। यह एक सम्मिलित पूँची वाली बैंक थी। परन्तु १६४६ में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह बैंक अन्य बैंकों का पथ-प्रदर्शन करती हैं। संकटकाल में उनकी सहायता करती है। भारतीय साख तथा भुद्रा पर नियंत्रण करती है और किसी प्रकार भी श्रन्य बैंकों से प्रतिद्वन्द्विता नहीं

ती | रिजर्व वैंक के स्थापित हो जाने पर इम्पीरियल वैंक को दिये हुए अधिकार रस ले लिये गये । यह भी अन्य न्यापारिक वैंकों की तरह हो गई । परन्तु रिजर्व के आप्राफ इंडिया ने रिजर्व वैंक को अपनी एजेंट नियुक्त करके अन्य वैंकों पर आधात या । कुछ भी हो रिजर्व वैंक फिर भी उन सब कार्यों को करने में सफल रही जिसकी । से आशा की जाती थी और उसकी देख रेख में अनेक वैंक अपने कार्य का । उन करने में सफल हो गये । रिजर्व वैंक की स्थापना के पश्चात् बहुत कम वैंक न हुई हैं ।

भारतीय मुद्रा बाजार पर द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव — द्वितीय महायुद्ध जो सितम्बर १६३६ से अगस्त १६४५ तक चला, संसार के राजनीतिक तथा । विशेष दाँचे को बहुत कुछ बदल दिया। यद्यपि भारतवर्ष रणचेत्र से बहुत दूर था प्रभी इस युद्ध का प्रभाव कुछ कम न पड़ा। युद्ध का निम्नलिखित प्रभाव भारतीय द्वा बाजार पर पड़ा—

- (१) नई-नई बैंकों की स्थापना तथा नई शास्ताओं का खुलना—दितीय हायुद्ध का भारतीय मुद्रा बाजार पर प्रथम प्रभाव यह पढ़ा कि यहाँ नई नई वैंकों की गढ़-धी आ गई। अनेक नई बैंके स्थापित हुई और पुरानी बैंकों ने अपनी शासाओं बढ़ाया। इसका कारण यह था कि युद्धकाल में घंघों को खड़ा करने के लिये मशीन या यंत्र तो विदेशों से आ नहीं सकते ये जिससे कारलानें स्थापित किये जा सकते गैर न इमारत आदि बनाने की सुविधा थी। किन्तु बैंक स्थापित करने को इन खुआं की आवश्यकता न थी। उसके लिये केवल अल्पकालीन कोष की आवश्यकता गी और वह युद्धकाल में इस देश में भारी मात्रा में उपलब्ध थी। इसका परिणाम हि हुआ कि प्रत्येक बड़े पूँजीपित या व्यवसायी ने अपनी बैंक खड़ी कर दी। आज रेसा कोई प्रसिद्ध व्यवसायी नहीं है जिसने इस समय एक बैंक स्थापित न की हो। पदि भारत सरकार नवीन मिश्रित पूँजीवाली कम्पनियों के स्थापित होने पर रोक न संगाती तो संभवत: भारत में अनाप-शनाप बैंकों की वृद्धि न होती।
- (२) बैंकों की डिपाजिट में बढोतरी—यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भिक श्री में जनता का विश्वास बैंकों में कम हो जाने के कारण जमा की-रकम कुछ कम हुई किन्तु १६४१ के उपरान्त जमा की राशि अत्यन्त अधिक बढ़ी। समस्त उदस्य बैंकों की कुल जमा राशि अत्यन्त अधिक बढ़ी। समस्त सदस्य बैंकों की कुल जमा राशि अदयन्त अधिक बढ़ी। समस्त सदस्य बैंकों की कुल जमा राशि युद्ध आरम्म होने के समय २३८ करोड़ रुपये थी जो १६४६ में बढ़ कर १०६१ करोड़ रुपये हो गई। इस बैंक इस राशि की अत्यन्त अधिक बृद्धि के रुख्य कारण थे—भारत में युद्ध के व्यय के फलस्वरूप अत्यन्त अधिक मुद्रा प्रसार का होना, किं की नई नई शाखाओं का स्थापित होना, व्यापार आदि में बहुत लाम का होना,

तथा रुपये को लाभप्रद कार्यों में लगाने के साधनों की कमी का होना। बैंकों को जमाओं के सम्बन्ध में और भी विशेष बात हुई। युद्धकाल में स्थायी जमायें बहुत कम बढ़ी जब कि चालू जमाओं में अत्यन्त अधिक वृद्धि हुई। इसके भी कई कारण थे। प्रथम तो स्थायी जमाखातों की ब्याज दर चालू जमाखातों की अपेद्धा गिर गई। अतः स्वेसाधरण जनता चालू खाते में ही रुपया जमा करना अधिक पसन्द करने लगी। दितीय युद्धकाल में सोने, चाँदी, कम्पनियों के अंशों तथा मकानों के मूल्यों में अत्यन्त अधिक उतार-चढ़ाव होते रहते थे। अतः जनता अपनी बचत को चालू जमाखातों में रखना ही अधिक पसंद करती थी जिससे आवश्यकतानुसार यह रुपये सरलता से काम में लिये जा सकें। तृतीय युद्धकाल में मशीनें तथा अन्य सामान मिलने के कारण नये उद्योग-धंचे तथा कारखाने स्थापित नहीं किये जा सकते थे। उद्योगपित तथा व्यापारी अपने बढ़ते हुए लाम को चालू खाते में ही जमा करान अधिक अञ्चा समस्ते थे।

- (३) विनियोग की नीति में परिवर्तन—उद्योगों-घंघों श्रीर व्यापार के लिरे को शृश्य नी माँग यी वह कम हो गई। किन्तु सरकार ने एक के पश्चात् दूसरे शृश्य निकालने श्रारम्भ किये। १६३६ में जहाँ बैंक श्रपनी कुल डिपाजिटों का ५८ प्रतिशत शृश्य, नकद साल तथा बिलों के रूप में घंघों श्रीर व्यापार में लगाते ये वहाँ १६४१ में उन्होंने श्रपनी कुल डिपाजिटों का २० प्रतिशत इस रूप में लगाया। जैसे-जैसे महायुद्ध चलता गया उद्योग-घंघों को बैंकों से उधार लेने की श्रावश्यकता कम होते गई। उनके लाम को व्यवसायी चालू खाते में जमा रखते थे श्रीर उसी को कार्यशील पूँजी के रूप में लाते थे। इसका स्वामाविक परिणाम यह हुश्चा कि बैंकों ने श्रपने कोष को सरकारी प्रतिभृतियों में श्रिषकाधिक लगाना प्रारम्भ कर दिया। यही नहीं बैंकों ने नकद कोष मी श्रिषक रखना श्रारम्भ कर दिया। श्रनुस्चित बैंक १५ प्रतिशत इम्पीरियल बैंक १५ प्रतिशत नकद कोष रखने लगी। दूसरे शब्दों में युद्धकाल में बैंकों को तरल लेनी का श्रनुपात बढ़ गया। इसका परिणाम यह हुश्चा कि बैंकों को श्रपने का तरल लेनी का श्रनुपात बढ़ गया। इसका परिणाम यह हुश्चा कि बैंकों को श्रपने का तरल लेनी का श्रनुपात बढ़ गया। इसका परिणाम यह हुश्चा कि बैंकों को श्रपने का तरल लेनी का श्रनुपात बढ़ गया। इसका परिणाम यह हुश्चा कि बैंकों को श्रपने का कर दी।
- (४) बैंकों के संगठन में दुर्व्यवस्था—द्वितीय युद्धकाल में बैंकों की श्रात्यत शीष्ठ विकास तथा वृद्धि होने के कारण पुरोग्य तथा श्रनुभवी कर्मचारियों को श्रिष्ठि वेतन देकर श्रपने यहाँ रख लिया। नई-नई बैंकों ने पुरानी बैंकों के श्रनुभवी कर्म चारियों को श्रिष्ठिक वेतन देकर श्रपने यहाँ रख लिया। परन्तु छोटी-मोटी बैंकों के योग्य कर्मचारियों का मिलना कठिन ही नहीं वरन दुर्लभ हो रहा है। श्रात: श्रव

त्रावश्यकता है कि शीघ ही भारतीय वैंकों का एक संघ स्थापित किया जावे तथा वैंक कर्मचारियों की उच्च शिद्धा का प्रवन्ध किया जावे।

युद्धकाल में मेंद्रशे की तरह से बहुत-की बड़ी हुई बैंक युद्ध समाप्त होने पर फेल हो गई। अन्य कारणों के अतिरिक्त इसका एक कारण यह भी था कि ये बैंक आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगीं जिससे आपस में टकराकर चूर-चूर हो गई।

स्वतन्त्रता के उपरांत भारतीय द्रवय बाबार श्रगस्त १६४७ में भारत में स्वतन्त्र हुआ। भारत सरकार ने जनता की बचत को वैंकों तथा डाकखानों में जमा पर प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया। सन् १६४६ में एक वैंकिंग कम्पनीज ऋघिनियम पास करके वैंकों की स्थिति को सुदृदृ बनाया गया एवं जमा करने वालों की रच्चा करने का प्रयत्न किया गया। रिजर्व वैंक तथा स्टेट वैंक का उपित्रवण्ण करके उन्हें श्रधिक सेवा योग्य बनाया गया। श्रन्य वचत योजनायें कार्याच्यत करके भिन्न प्रकार की प्रतिभृतियां जारी की गई जिससे जनता की बचत पंचनवीय योजनाशों में काम श्रा सके। जीवन बीमा कम्पनियों का भी उपद्रीयकरण किया गया किन्तु इससे उद्योगपतियों को धन प्राप्त करने में कुछ कठिनाई होने लगी। क्योंकि सरकारी संस्था हो जाने पर जीवन बीमा निगम श्रपने धन का विनियोग सरकारी श्र्णों में श्रधिक करने लगा। जीवन बीमा कम्पनियों के शप्ट्रीयकरण का उद्देश्य ही पंचवर्षीय योजनाश्रों में धन लगाना था।

श्रलपवचत योजनायें — जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है सरकार ने कई प्रकार की श्रलपवचत योजनायें चालू की जिनमें १० वर्णीय ट्रेजरी सेविंग सार्टी फिकेट, नेशनल सेविंग सार्टी फिकेट तथा डाकखाने के सेविंग वैंक एकाउन्ट विशेष ठल्लेखनीय हैं। इन श्रलपवचत योजनाश्रों का पूर्ण वर्णन नीचे दिया जाता है —

डाकखाने का सेविंग वेंक खाता—सभी हेडपोस्ट श्राफिसों में, सब पोस्ट श्राफिसों में तथा बहुत से ब्रांच पोस्ट श्राफिसों में सेविंग वेंक का काम होता है। इनका मुख्य उद्देश्य किसानों, मजदूरों तथा मध्यम श्रेणी के लोगों में मितव्ययता की भावना जाग्रत करना है। किन्तु पोस्ट श्राफिस सेविंग वेंकों में श्रिषकांश मध्यम श्रेणी के ही व्यक्ति श्रपनी बचत जमा करते हैं। इनमें श्रिषकांश सरकारी बथ्द ग्रुष्ट सरकारी कर्मचारी, वकील, डाक्टर, श्रध्यापक तथा श्रन्य पेशे वाले लोग ही ग्रपना स्पया जमा करते हैं। पोस्ट श्राफिस सेविंग वेंक में श्रिषक-से-श्रिषक ५००० रुपये जमा किये जा सकते हैं। पहले यह नियम था कि एक वर्ष में कोई ७५० रुपये से श्रिषक जमा नहीं कर सकता था किन्तु श्रव यह बन्धन हट गया है। कोई भी व्यक्ति ५००० रुपये तक एक बार में जमा कर सकता है। कम से कम दो रुपये जमा किये जा सकते हैं। सेविंग वेंक में श्रव दो सौ रुपये से कम १६ प्रतिशत श्रीर २०० से उपर २ प्रतिशत ब्याज दी जाती है। कोई भी व्यक्ति रुपया जमा कर सकता है। रुपया एक स्पताह में केवल एक बार निकाला जा सकता है।

मारतवर्ष में पोस्ट आफिस सेविंक बैंक की स्थापना १८८२ में हुई । तब से उसमें जमा करने वालों की संख्या तथा जमा किया हुआ रूपया बराबर बढ़ता ही गया। पहले महायुद्ध के आरम्भ होने पर १६१४-१५ में लोगों में अवश्य घवराहट फैल गई और लोगों ने करोड़ों रूपया निकाल लिया। परन्तु शीघ ही लोगों में विश्वास फिर लौट आया और डिपाजिट बढ़ने लगी। १६३०-३१ में आर्थिक मंदी के कारण जितना रूपया जमा हुआ उससे अधिक रूपया निकाला गया। किन्तु फिर डिपाजिट में बृद्धि होने लगी। १२ मार्च १६३८ में ३७ ६ करोड़ रूपये जमा थे। और ७७५ करोड़ रूपये की डिपाजिट थी। जब दूसरा युद्ध आरम्भ हुआ और फांस का पतन हो गया तो जनता में फिर धवराहट फैल गई और लोगों ने अपना रूपया निकालना आरम्भ कर दिया किन्तु शीघ लोगों में विश्वास लौट आया और डिपाजिटों में बृद्धि होने लगी।

स्वतन्त्र भारत में डाक सेविंग खाते की सुविधायें ग्रामीण चेत्र में भी चालू कर दी गई हैं। प्रत्येक ग्राम में जिसकी जनसंख्या १५.६ से ऋषिक है एक डाकखाना खुल गया है। कुछ प्रमुख स्थानों पर चेक द्वारा रुपया निकालने की सुविधायें भी प्रदान कर दी गई हैं। मध्यवर्ग के लोग ऋपनी बचत डाकखानों में ही जमा करते हैं। वैंकों की ऋपेचा डाकखाने में ब्याज की दर भी कुछ, ऋषिक है ऋौर थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करने में तथा निकालने में ऋमुविधा नहीं होती। १६५५-५६ में डाकखाने के सेविंग बैंक खाते में १६१ करोड़ रुपये जमा थे। ३१ मार्च १६५८ को इसमें ६३ प्रतिशत ऋौर वृद्धि हुई। यह ऋगशा की जाती है कि ऋषिक स्थानों में चेक प्रथा चालू हो जाने से इस जमा में ऋौर वृद्धि होगी।

नेशनल सेविंग सार्टी फिकेट—ये सार्टी फिकेट द्वितीय महायुद्ध के समय निकाले गये। ये १२ वर्षों के लिए होते हैं। सार्टी फिकेट खरीदने वाला उन्हें कभी भी भुना सकता है। किन्तु पहले ३ वर्षों में कोई ब्याज नहीं मिलती। श्रीर उसके उपरांत क्रमशः ब्याज की दर बद्धी जाती है। १२ वर्ष पूरे हो जाने पर प्रारम्भ में लगाया हुश्रा स्थाब की दर बद्धी जाती है। उदाहरण के लिये कोई व्यक्ति १०० रुपये के कैश सार्टी-फिकेट लेता है तो १२ वर्ष के उपरांत उसको १५० रुपये मिलेंगे। एक व्यक्ति २५००० रुपये से श्रिषक के नेशनल सेविंग बैक्क सार्टी फिकेट नहीं खरीद सकता। नेशनल सेविंग सार्टी फिकेटों पर ब्याज की दर श्रब्छी है। इसके ब्याज पर श्राय कर भी नहीं लगता तथा जोखम बिल्कुल नहीं है। इस कारण मध्यम श्रेणी का व्यक्ति उनकी श्रोर श्रिषक श्राकर्षत होता है। यद खरीदने वाले को यह सुविधा दे दी जावे कि वह

अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सके जिसे उसकी मृत्यु के उपरांत रूपया दिया जावे तो वह और भी अधिक प्रचलित हो सकते हैं।

कुछ लोगों की सुविधा के लिये पंचवर्षीय तथा सप्तवर्षीय सार्टीफिकेट भी चालू किये गये हैं।

दस वर्षीय ट्रेजरी सेथिंग डिपाजिट सार्टीफिकेट — इन मार्टी केटी पर प्रति वर्ष रे में प्रतिशत क्याज दी जाती है। १००) से कम का सार्टीफिकेट नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति २५००० तक, संस्था ५०००० तक तथा धार्मिक संस्था १,०००,००० तक के सार्टीफिकेट खरीद सकती हैं। ये सार्टीफिकेट रिजर्व नैक्क, स्टेट वैक्क तथा किसी भी सरकारी खजाने से खरीदे जा सकते हैं। इन सार्टीफिकेटों को १० वर्ष से पहले भी मुनाया जा सकता है। किन्तु इनके लिंग लजाना कुछ कटौनी कर लेता है। ये सार्टीफिकेट इसी कारण इतने छथिक सफल नहीं हुए जितने डाक-खाने के सार्टीफिकेट सफल हुए हैं। फिर भी २१ मार्च १६५० को ६१-१३ करोड़ रूपये के ट्रेजरी सार्टीफिकेट निर्गामित थे।

दितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये सरकार को ऋषिक घन की ऋषिकता है। इसीलिये ऋल्पवचत योजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया किन्तु इससे बैक्कों में जमा घन राश्चि उतनी मात्रा में नहीं पहुँचती जितनी पहुँचनी चाहिए थी। जब तक सरकार ने व्यक्तिगत चेत्र को मान्यता प्रदान कर रखी है तब तक बैक्कों का ऋषीद्योगिक विकास में पूर्ण स्थान है। ऋतः बैंकों में जमा घनराश्चि से सरकारी संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिये।

प्रश्न

r. What are the constituents of the Indian Money Market? Point out the defects in its organization and suggest remedies.

भारतीय मुद्रा बाजार के ऋंग कौन-कौन से हैं ! इसके संगठन के दोष बतलाइये तथा सुघार के सुभाव दीजिये !

2. What has been the effect of the Second World War on the banking system of India?

द्वितीय महायुद्ध का भारतीय वैकिंग व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ?

3. Carefully explain the banking services rendered by the post office in India.

भारतीय डाक-विभाग की वैंकिंग सेवात्रों की विवेचना कीजिये।

4. Discuss the principal defects of Banking in India. Point out the effect of the lack of discounting facilities in Indian Money Market.

भारतीय बैंकिंग के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिये। भारतीय मुद्रा बाजार पर बेचान की मुविधात्रों की कमी का प्रभाव बतलाइये।

5. What are the defects in the Indian Money Market? How will you organise it on proper lines?

भारतीय मुद्रा बाजार की क्या कांमयाँ हैं ? इसका ठीक दंग से किस प्रकार संगठन किया जा सकता है ?

भ्रध्याय ४

रिजर्व बैंक आफ इन्डिया

(Reserve Bank of India)

रिजर्व वैद्ध की स्थापना—भारत में केन्द्रीय वैंक की आवश्यकता एन १८५६ से प्रतीत हो रही थी किन्तु भारत सरकार ने इसकी श्रोर कभी घ्यान नहीं दिया। सन् १९१३ में श्रीयुत् कीन्स ने जो चेन्वरलेन कमीशन के एक सदस्य थे भारत में एक केन्द्रीय वैंक स्थापित करने की योजना भारत सरकार के सम्मुख रखी थी। परन्तु सरकार ने इस पर घ्यान नहीं दिया। प्रथम महायुद्ध के उपरान्त तो केन्द्रीय वैंक की नितान्त आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इसीलिए सन् १९२१ में वैंक की स्थापना पर उसे ही कुछ केन्द्रीय कार्य सौंपे गये। १९१६ में जब हिल्टन यंग क्मीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तब इम्पीरियल वैंक की स्थिति, पूँजी, कार्यों, प्रवन्घ, शाखान्त्रों, प्रतियोगिता तथा भारतीयों की उसके प्रति आलोचनात्मक भावनान्त्रों को घ्यान में रख कर उसने इस बात का समर्थन किया कि भारत में इम्पीरियल वैंक से अलग एक स्वतंत्र केन्द्रीय वैंक स्थापित होनी चाहिये।

भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आव-श्यक जान पड़ी:--

- (१) भारतीय रुपये के अतिरिक्त आन्तरिक तथा बाह्य मूल्य में स्थायित्व प्रदान करने के लिये रिजर्व बैंक की नितान्त आवश्यकता थी। रिजर्व बैंक ही अपने नोट निकालने, प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय, बैंक दर निर्धारण, विदेशी विनिमय की एक निश्चित दर पर क्रय-विक्रय आदि के अधिकारों के कारण ऐसा करने में सफल हो सकती थी।
- (२) रिजर्व बैंक ही अपने नोट निकालने के एकाधिकार का उचित प्रयोग करके अन्य बैंकों के नकद कोष अपने पास रख करके, सरकारी बैंकों का कार्य करके, समाशोधन गृह का कार्य करके तथा अन्य-साधनों के द्वारा देश की साख नीति की अग्रावश्यकतानुसार उचित प्रबन्ध करने में सफल हो सकती थी।
 - (३) रिजर्व वैंक की स्थापना से ही देश की विभिन्न बैंकों के नकद कोषों के

कुछ भाग का केन्द्रीयकरण होना संभव हो सकता था। ऋौर यह कोष बैंकों के संकट काल में भी तभी ऋषिक काम ऋा सकती थी।

- (४) रिजर्व बैंक हो देश की बैंकिंग को मुन्दर बनाने तथा उसका उचित निय-त्रण तथा प्रबन्ध करने में सहायक हो सकती है।
- (५) रिजर्व वैंक ही अपना एक अलग कृषि विभाग स्थापित करके भारतीय कृषि की अर्थ व्यवस्था का उचित प्रवन्ध करने में समर्थ हो सकती थी।
- (६) रिजर्व वैंक की इसिलिये भी आवश्यकता थी कि वह सरकार का रूपया सुरिच्चत रखे। उसके ऋणों तथा विदेशी विनिमय के लेन-देनों का प्रबन्ध करे तथा उसे समय-समय पर आर्थिक विषयों पर मंत्रणा भी देती रहे।
- (७) देश के मुद्रा बाजारों के विभिन्न ऋगों में सहयोग स्थापित करने तथा उनसे सम्बन्धित ऋंकों को जनता की सुविधा के लिये ठीक समय पर प्रकाशित करने के लिये भी रिजर्व बैंक की नितान्त ऋगवश्यकता थी।

इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये १९३४ में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार १९३५ की अप्रैल में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 🖊

रिजर्व वैद्ध का विधान—वैंक के राष्ट्रीयकरण के पूर्व रिजर्व वैंक अंशधारियों की वैंक थी। इसकी पूँजी ५ करोड़ थी जो १००८ के अंशों में विभक्त थी। इस पूँजी में से २ करोड़ २० लाख रुपये के अंश केन्द्रीय सरकार को तथा शेष व्यक्तिगत अंशधारियों को निर्गमित किये गये थे।

बैंक का प्रबन्ध एक संचालन समिति द्वारा होता था जिसमें १६ संचालक इस प्रकार होते थे :—

- (त्र्य) एक गवर्नर तथा २ डिप्टी गवर्नर जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय संचालक संघ के परामर्श पर करती थी।
 - (ग) ४ संचालक जिन्हें केन्द्रीय सरकार मनोनीत करती थी।
 - (स) ८ संचालक जिन्हें स्रंशधारी चुनते थे।
 - (द) १ सरकारी ऋषिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार मनोनीत करती थी।

केन्द्रीय संचालन-सिनियों के लिये बैंक की भिन्न-भिन्न शाखाओं के कार्य की देखमाल करना संभव नहीं था। अ्रतः ४ स्थानीय संचालन सिमितियाँ नियुक्त की जाती थीं। प्रत्येक स्थानीय सिमिति में द संचालक होते थे जिनमें से ५ अंशिशाशियों द्वारा चुने जाते थे तथा ३ केन्द्रीय संचालन सिमिति अंशिशाशियों में से मनोनीत करती। थी।

बेंद्भ का वर्तमान विधान—एक विधेयक पास करके १ जनवरी १६५० से

रिजर्व वैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब वैंक का प्रवन्ध जिस केन्द्रीय संचालक समिति द्वारा होता है वह इस प्रकार है:—

- (ऋ) एक गवर्नर तथा ३ डिप्टी गवर्नर जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है।
 - (ब) ४ संचालक, जिन्हें केन्द्रीय सरकार चारों स्थानीय समितियों में से एक-एक मनोनीत करती है।
 - (स) ६ संचालक जिन्हें केन्द्रीय सरकार मनोनीत करती है।
 - (द) १ सरकारी ऋधिकार्रा, जिसे केन्द्रीय सरकार मनोनीत करती है। ऋौर को सरकार की इच्छानुसार कितने ही समय तक कार्य कर सकता है।

केन्द्रीय समिति के ऋतिरिक्त बैंक के प्रबन्ध के लिये : स्थानीय समितियाँ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली में नियुक्त की जाती हैं, जिसके ३ सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।

हर संचालक ४ वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता है। केन्द्रीय समिति की बैठक बुलाना गवर्नर के अधिकार में है किन्तु कोई भी ३ संचालक मिल कर गवर्नर से बैठक बुलाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वर्ष भर में ६ बैठकें बुलाना अनिवार्य है किन्तु ३ मास में एक बैठक अवश्य होनी चाहिये।

ऋंशाधारियों की रकम का मुगतान करके रिजर्व वैंक की समस्त पूँजी केन्द्रीय सरकार ने ऋपने हाथ में ले ली है।

रिजर्व चैंक के विभाग—रिजर्व वैंक २ विभागों में विभक्त है। एक निर्गमन विभाग (Issue Department) जो कागजी मुद्रा छापने का कार्य करता है तथा दूसरा बैंकिंग विभाग, जो श्रविकोषण सम्बन्धी सभी कार्य करता है। बैंकिंग विभाग के भी तीन उपविभाग हैं: (१) कृषि साख विभाग, जो ग्रामीण वित्त सम्बन्धी कार्य को सम्पन्न करता है तथा उनका श्रव्वेषण करता है। (२) विनियम नियत्रण विभाग, जो विदेशी विनिमय पर पूर्ण नियंत्रण रखता है तथा (३) श्रविकोष विभाग, जो देश की समस्त बैंकों पर नियंत्रण रखता है तथा समय-समय पर उन्हें श्रादेश देता है।

रिज़र्व बेंक के कार्य—देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक स्राफ इंडिया निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करती है—

(१) कागजी मुद्रा प्रकाशन (Issue of Currency Notes)—रिजर्व बैंक का कागजी नुद्रा निर्गमित करने का एंकाविकार प्रमुख है। इस कार्य को संपादन करने के लिए बैंक का एक स्वतन्त्र प्रकाशन विभाग है चिन् १६५६ से पहले कागजी मुद्रा की सुरखा के लिये सुरखित कोष, स्वर्ण सिक्कों, स्वर्णपाट, विदेशी प्रतिभृतियाँ तथा भारतीय प्रतिभूतियों में रखना आवश्यक था। कम से कम ४० करोड़ रुपये के मूल्य के स्वर्ण सिक्के अथवा स्वर्णपाट अनिवार्य रूप से कोष में होने चाहिये थे जिसमें से स्वर्ण कोष ४० करोड़ रुपये का अनिवार्य था। सन् १६५६ में उपरोक्त विधान में परिवर्तन कर दिया गया जिसके अनुसार कम-से-कम ४०० करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा ११५ करोड़ रुपये का सोना, जिसका मूल्यांकन ६२ रुपये ५० नये पैसे प्रति तोले के हिसाब होता है, होना चाहिये। यदि किसी समय यह स्वर्ण कोष कम पड़ जाता है तो इसके लिये रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार को एक निर्धारित दर से कर का सुगतान करेगी। विदेशी प्रतिभूतियाँ केवल (अ) बैंक आफ इंगलैंड के पास जमा धन, (ब) ६० दिन तक की हुन्डियाँ, जो इंगलैंगड में देय हैं तथा (स) ब्रिटिश सरकार की वे प्रतिभूतियाँ, जो केवल ५ वर्ष के लिये निर्गमित की गई है; सीमित हैं।

नोट प्रकाशन विभाग का शेष कोष सरकारी प्रतिभूतियाँ, स्वीकृत व्यापारिक हुंडियों अथवा प्रतिज्ञा पत्रों के रूप में होना चाहिये। इन प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्य की दर से निश्चित किया जाता है। रिजर्व बैंक को इस समय केवल रो, प्र, १००।, ५००। तथा १०००। के नोट छापने का अधिकार है।

र्द्वितीय महायुद्ध में कागजी मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई थी श्रीर मुद्रा स्फीति के कारण देश के कुछ वर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ा था। रिजर्व बैंक मुद्रा पर पूर्ण नियंत्रण करने में अधिकल रही किन्तु स्वतन्त्रता के उपरान्त रिजर्व बैंक ने इस दिशा में अच्छी सफलता प्राप्त की भिकन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हीनार्थ प्रबन्ध (Deficit Financs) के कारण नोटों की मात्रा पुनः बढ़ने लगी है ।✓

सरकार के लिये वेंक का कार्य करना — फेन्द्रीय सरकार की श्रोर से रिजर्व वेंक श्राफ इंडिया निः ग्रुल्क वेंकर का कार्य करती है। सार्वजनिक श्रुण की व्यवस्था तथा सरकार के लिये नवीन श्रुण भी निर्गमित करती है। सार्वजनिक श्रुण की व्यवस्था करने के लिये वेंक को सरकार से एक निश्चित दर से कमीशन मिलता है। सरकारी कोष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा विदेशों से भारत को तथा भारत से विदेशों को मिजने का कार्य भी रिजर्व वेंक ही करती है। सरकार के लिये श्रल्यकालीन श्रुण खजाने की हुंडियों द्वारा रिजर्व वेंक ही प्राप्त करती है। खजाने के हुंडियों के उपगुक्त न होने पर रिजर्व वेंक सरकार को श्रल्यकालीन श्रुण प्रदान करती है। सरकारी श्रावश्यकताश्रों की पूर्व के लिये १ लाख रुपये तक की स्टलिंग विनिमय का प्रवन्ध भी करती है। राज्य सरकारों के लिये भी रिजर्व वेंक यही कार्य करती है वो केन्द्रीय सरकार के लिये । मुद्रा बाजार के साथ सम्पर्क होने के कारण तथा देश की श्राधिक स्थित का पूर्ण ज्ञान होने के कारण भारत सरकार रिजर्व वेंक से

विचीय तथा वैंक सम्बन्धी मामलों पर परामर्श प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त सरकार रिजर्व वैंक का परामर्श नवीन ऋण जारी करने, पुराने ऋणों को परिवर्तित करने, ऋष साख, सहकारिता तथा वैंकों को प्रमावित करने वाले विषयों पर भी प्रपामर्श करती है।

वेंकों के बेंक का कार्य करना—परिवर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के बैंकों का नियंत्रण, पथ-प्रदर्शन तथा संगटन करना है। यह बनता के हितों की रचार्थ देश के समस्त अनुमूचित बैंकों के माँग दावित्व का ५ प्रतिशत तथा समय-दायित्वों का २ प्रतिशत अपने पास जमा कराती है, १९४० के बैंकिंग कर्मनीज ऐस्ट के अंतर्गत अन्य बैंकों के लिये भी नकद कीप बैंक के गास रखना अनिवार्य कर दिया गया है। रिजव बैंक इसके लिये धनराशि को बैंकों के आर्थिक संगटकाल में अंतिम ऋण्यदाता के रूप में सहावता करने के काम में लाती है। रिजव बैंक समय-समय पर देश के बैंकों से रिगेर्ट तथा उनके लेखों का पूर्ण वर्णन भी माँगती है। यह बैंकों के लेखों का निरीक्षण करती है। उनके समुख देती है। उनको साल निर्माण पर उचित आदेश देती है तथा उनकी अनुचित कियाओं को रोकने का प्रयत्न करती है। उनका धन एक स्थान से दूसरे स्थान को निःशुलक मेजती है तथा उनके आपरी लेन-देनों के लिये समाशोधनगृह का कार्य भी करती है।

रिजर्व वेंक का अनुस्चित वेंकों के साथ सम्बन्ध—रिवर्व वेंक श्राधिनियम की घारा ४२ के अनुसार अनुस्चित वेंक वह वेंक है जिसकी चुकता पूंजी तथा कोष ५ लाख रुपये या इससे अधिक है। ऐसे वेंकों का नाम एक सूची में लिख लिया जाता है। अतः इन्हें अनुस्चित वेंक कहते हैं। सूची में नाम प्रकिष्ट करने के पहले रिजर्व वेंक वेंकों के कार्यों की देखमाल करती है। सूची में प्रकिष्ट करने का अर्थ यह नहीं है कि रिजर्व वेंक ने वेंक की स्थिरता एवं आर्थिक सम्मन्नता का बीमा कर दिया है। यदि किसी वेंक का कार्य संतोषजनक नहीं है तो उसका नाम सूची से प्रथक किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है अनुसूचित वेंकों को अपनी माँग-दायित्व का ५ प्रतिशत तथा समय दायित्व का २ प्रतिशत रिजर्व वेंक के पास जमा करना पड़ता है। किन्तु गजट में प्रकाशित करके रिजर्व वेंक इस प्रतिशत को कमशः २० तथा द तक बढ़ा सकता है। यदि ये जमा इस निश्चित प्रतिशत से कम है तो रिजर्व वेंक संबन्धित वेंक से ब्याज प्राप्त कर सकती है और अधिक है तो ब्याज दे सकती है।

प्रत्येक ऋनुस्चित बेंक के लिये • ऋगनी स्थिति का साप्ताहिक विवरण रिजर्व वैंक के पास भेजना ऋनिवार्य है। न भेजने पर वैंक को दंडित किया जा सकता है। ऋगवश्यकता पड़ने पर ऋनुस्चित बेंक ऋपनी हुंडियों की कटौती करके ऋथवा ऋण्य के रूप में रिजर्व बैंक से सहायता प्राप्त कर सकती हैं। किन्तु यह ऋण किसी भी अवस्था में ६० दिन से ऋषिक के लिये नहीं दिया जा सकता।

श्रनुसूचित वेंक के साथ सन्बन्ध — कुछ शतें पूरी हो जाने पर रिजर्व वेंक श्रनुस्चित वेंकों के खाते भी श्रपने यहाँ खोल लेती है तथा समय समय पर उन्हें परामर्श भी देती है । सन् १६३८ तथा १६३६ में दो गश्ती पत्र भेजकर रिजर्व वेंक ने यह भी बतलाया कि वह किस प्रकार श्रनुस्चित वेंकों की सहायता कर सकती है।

विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना — रिजर्व बैंक को भारतीय रुपये के वाह्य मूल्य को स्थिर रखने का भी अधिकार दिया गया है। रिजर्व बैंक की विनिमय दर को स्थायित्व प्रदान करने के लिये विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय भी करती है। विदेशी विनिमय नियंत्रण कानून १६४७ के अनुसार रिजर्व बैंक यह क्रय-विक्रय केवल कुछ अधिकृत व्यक्तियों के साथ ही करती है। और वह भी केवल बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा देहली के कार्यालयों द्वारा यह क्रय-विक्रय उन दरों पर किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय सद्रा कोष की शतों को ध्यान में रखकर निश्चित कर देती है। और वह भी १००,००० स्थये से कम मूल्य का न होना चाहिये। अब रिजर्व बैंक ब्रह्मा, सीलोन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंगलैंड, दिल्ली अफ्रीका, फ्रांस, बेलजियम, नीदरलैंड, नार्वे, डेनमार्क, फिलिपाइन आदि देशों के विनिमय के क्रय-विक्रय का कार्य करती है।

साख-नियंत्रण—रिजर्व बैंक साख नियंत्रण के हेतु उन सभी शितियों का प्रयोग करती है जो किसी भी देश की केन्द्रीय बैंक को करने चाहिये। पहले मुद्रा बाजार के संगठित न होने के कारण रिजर्व बैंक की बैंक दर नीति सफल न हो सकी श्रीर उसको ३ प्रतिशत पर ही स्थिर बनाये रखना पड़ा। एक जर्मन श्रार्थशास्त्री के परामर्श से नवम्बर १६५१ में बैंक दर ३ से ३ भी प्रतिशत कर दी गई। इससे रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली पर श्रच्छा नियंत्रण कर लिया। किन्तु बैंक दर में बृद्धि करते ही सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी हो गई जिसका सार्वजनिक श्र्यण पर बुरा प्रभाव पड़ा। रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रिया द्वारा भी साख पर नियंत्रण करती है। इसे साख समिन्नमाजन तथा प्रत्यन्न कार्यवाही का भी श्रिधकार है।

कृषि साख व्यवस्था—रिजर्व बैंक ने सन् १६३५ में एक कृषिसाख विभाग की स्थानना की। इस विभाग के दो वैधानिक कार्य हैं: (अ) एक योग्य कर्मचारी वर्ग द्वारा कृषिसाख का पूर्ण अध्ययन कराना तथा सरकार, सहकारी बैंक तथा अन्य बैंकों को परामर्श प्रदान करना। (ब) कृषिसाख के सम्बन्ध में बैंक की कार्यवाही में एकता लाना तथा रिजर्व बैंक का सहकारी तथा अन्य बैंकों से कृषिसाख सम्बन्धी संपर्क बनाये रखना। यह विभाग प्रामीण ऋण तथा सहकारिता का विशेष अध्ययन करके समय-समय पर अपने निष्कर्षों को प्रकाशित करता रहता है। इसकों की सहाय-तार्थ रिजर्व बैंक सहकारी संस्थाओं को ऋण प्रदान करती हैं क्यों के इसकों को सीधा ऋण प्रदान करना इसमें अधिकार चेत्र से बाहर है। रिजर्व बेंक साधारण कार्यों के . लिये सहकारी समितियों को ऋण नहीं देती। कंवल आयत्तिकाल में ऐसा करती है। यह ऋण केवल उन्हीं सहकारी बैंकों को प्रदान किया जाता है जो रिजर्व बेंक के पास अपने माँग दायित्व का २६ प्रतिशत तथा सनद-दावित्व की १ प्रतिशत जमा रखते हैं। केवल निम्नलिखित प्रकार के ऋण प्रदान किये जाते हैं—

- (श्र) प्रांतीय सहकारी वैंकों तथा उनके द्वारा केन्द्रीय सहकारी वैंकों को सरकारी प्रतिभृतियों की जमानत पर ६० दिन के लिये ऋए।
- (ब) अन्य भूनिबन्धक वैंकों के ऋगापत्रों को जमानत पर इसी प्रकार के ऋगा, यदि ये ऋगापत्र शीव विक्रय योग्य हैं।
 - (स) खजाने की हुंडियों की कटौती करके।
- (द) मान्य सहकारी विक्री तथा गोदाम समितियों के प्रतिज्ञापत्रों की जमानत पर ६० दिन के लिये ऋण । यदि इन प्रतिज्ञापत्रों पर प्रान्तीय सहकारी वैंक का बचान हो गया है तथा ये कृषि विक्री के सम्बन्ध में लिखे गये हैं।
 - (ई) उपरोक्त प्रतिज्ञापत्रों की कटौती करके।
- (फ) भूमिवन्यक बैंकों के ऋग्णपत्र खरीदकर अथवा उनकी जमानत पर ऋग्ण देकर । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इन ऋग्णपत्रों की जमानत प्रांतीय सरकार ने कर रखी हो ।

िश्जर्व बैंक, ने कुछ विश्वपियाँ प्रकाशित करके सहकारी साख सम्मितियाँ, किन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा भूमिनन्धक बैंकों की उन्नति के लिये कुछ ठोस सुमान दिये। देशी बैंकरों तथा साहूकारों के साथ वार्तालाप करके उनकी उन्नति की भी योजना बनाई किन्तु देशी साहूकारों ने दुर्भाग्यवश इस योजना को स्वीकार नहीं किया।

अन्य कार्य—रिजर्व बैंक का यह भी दायित्व है कि वह भू या उससे अधिक मृ्ल्य वाले नोटों से थोड़े मृ्ल्य के नोटों में परिवर्तित करे । बिना ब्यांज दिये संस्थाओं तथा व्यक्तियों का रुपया जमा करे । सोने के सिक्कों तथा सोने का क्रय-विक्रय भी करे । रिजर्व बैंक सुद्रा, प्रतिभूयाँ, आमूषण तथा अन्य बहुमृ्ल्य वस्तुओं को सुरिच्चित रख सकती है । अपने प्राहकों का लागांश संग्रह कर सकती है तथा उनके ऋणपत्रों का सुगतान कर सकती है । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों का खाता खोलकर उसके प्रतिनिधि का काम कर सकती है तथा अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन कर सकती है । वैंकिंग

सम्बन्धी आँकड़े एकत्रित करके उन्हें प्रकाशित करती है। अपने निर्गमन एवं विभाग का सप्ताहिक विवरण पत्र में प्रकाशित करती है। मुद्रा तथा अर्थ सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट एवं भारतीय बेंकों के आँकड़े भी प्रकाशित करती है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसमें सरकार तथा जनता के समस्त्र देश की आर्थिक स्थित तथा समस्यायें. प्रस्तुत करती है।

रित सबके त्रातिरिक्त नवीन बैंकों को बैंकिंग कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है तथा उन्हें बन्द करने का स्रादेश देती है।

रिजर्व वैङ्क के प्रतिबंधित कार्य — रिजर्व बैंक निम्नलिखित कार्यों को नहीं कर सकती:—

- (१) व्यापार नहीं कर सकती तथा किसी व्यापारिक एवं स्रोद्योगिक संस्थास्रों के लाभ में प्रत्यत्त भाग नहीं ले सकती। यदि किसी ऋण की प्राप्ति में रिजर्व बैंक को ऐसी संस्थास्रों की सम्मत्ति में स्रिविकार प्राप्त हो गया है तो उसे शीव्रातिशीव बेच देना वाहिये।
- (२) रिजर्व बैंक न किसी कम्पनी के श्रंशों का क्रय कर सकती है श्रीर न उसकी जमानत पर ऋग दे सकती है।
- (३) किसी अचल सम्पत्ति के बन्धक पर न ऋण दे सकती है न उसे क्रय कर सकती है किन्तु अपने कार्यालय तथा कर्मचारियों के निमित्त अचल सम्पत्ति खरीद सकती है।
 - (४) असुरच्चित ऋण प्रदान नहीं कर सकती।
- (५) दर्शनी हुन्डी के ऋतिरिक्त ऋन्य प्रकार की हुन्डी न ऋाहरित कर सकती है न स्वीकार कर सकती है।
 - (६) चालू खाते की जमा पर ब्याज नहीं दे सकती।

रिजर्व वैद्ध की सफलतायें—रिजर्व बैंक की स्थापना के कारण ही, जिसने प्रथम अप्रैल १६५५ से अपना कार्य प्रारम्भ किया था, अपने अधिकतर कार्य सुचार रूप से चला रही है, इसी की स्थापना के कारण ही भारतीय बैंकिंग पद्धति कुछ सीमा तक सुदृद्ध, सुद्ध्यविद्धित तथा सुसंगठित हो सकी हैं। यह इसी का प्रभाव है कि भारतीय सुद्रा बाजार में ब्याज की दरें गिर सकी हैं। रिजर्व बैंक ने सदैव से ही अपनी बैंक दर ३ प्रतिशत रखी हैं जब से रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है तब से ही भारतीय सुद्रा बाजार में कभी भी रुपये की कभी नहीं हुई है। यद्यपि रिजर्व बैंक की स्थापना के पहले भी इम्पीरियल बैंक को सरकार १५ करोड़ रुपये तक का अप्रुण भारतीय कागजी सुद्रा रिजर्व से प्रति वर्ष अप्रुत विशेष में दिया करती थी किन्तु वह कभी भी भारतीय द्रव्य बाजार की स्थये की कभी को दूर करने में सफल न हो सकी थी। यह बड़े हुई की

बात है कि रिजर्व बेंक इस कमी को दूर करने में सफल हो सकी है। यही नहीं कि रिजर्व बेंक कुछ सीमा तक भारतीय मुद्रा तथा साख पढ़ित को भी नियंत्रित! कर सकी है। 'रिजर्व बेंक ने प्रारम्भ से ही सस्ती मुद्रा नीति (Cheap money policy) को - अपनाकर भारतीय व्यापार, उद्योग घन्यों तथा कृषि की बढ़ती हुई स्पये की मांग की पूर्त करने में आधातीत सफलता प्राप्त की है । इसने भारत सरकार तथा अन्य बेंकों को भी संकट काल में पूरी-पूरी आर्थिक सहायता प्रदान की है । समय-समय पर उसे उचित परामर्श भी देती रही है । इसने भारतीय मुद्राबाजार को मुक्यवस्थित करने तथा स्वदेशी बेंकरों को नियमबद्ध करने के लिये भी बार-बार प्रयत्न किये हैं । यह भारतीय स्पये के साख मूल्य तथा आतिरिक मूल्य को कुछ सीमा तक स्थायी रखने में भी सफल हुई है । नोट प्रकाशन द्वारा रिजर्व बेंक मुद्रा की मात्रा पर पूरा पूरा नियंत्रण रखती है । और व्यापार की आवश्यकतानुसार मुद्रा में लोच उत्पन्न करके मुटा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन की बीमारी को रोकती है ।

रिजर्व बेंक बहुत कम व्यय पर एक स्थान से दूसरे स्थान को काया मेजने की सुविधा प्रदान करती है। रिजर्व बेंक बेंकों के नियंत्रण के लिए एक बेंकिंग कम्पनी अधिनियम पास करने में सफल हुई है । इस अधिनियम के द्वारा देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुदृदृ बनाने के लिये बेंक को विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं। श्रोद्योगिक वित्त के लिये रिजर्व बेंक ने श्रोद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कराने में महत्वपूर्ण योग दिया है। देश के आर्थिक आँकड़े एकत्रित करके बेंक के सुवोग्य अधिकारी अनुसंधान करते हैं श्रीर अपने निष्कर्षों के आधार पर सरकार को आर्थिक विकास के लिये परामर्श देते हैं। रिजर्व बेंक ने देश के विभाजन तथा रुपये के अवमृत्यन जैसी महान घटनाओं के दुष्पारिणामों से देश को बचाया है। यह आशा की जाती है कि रिजर्व बेंक राष्ट्रीयकरण के कारण कृषि साल व्यवस्था एवं देश में बेंकिंग प्रथा को विकसित कराने में अब और अधिक सहायता प्रदान करेगी। द्वितीय योजना काल में १२०० करोड़ रुपये के घाटे की व्यवस्था तथा विदेशी विनिमय की कमी के कारण देश की अर्थ व्यवस्था पर जो भार पड़ रहा है उसमें रिजर्व बेंक को और भी महत्वपूर्ण करना है। सफलता के साथ-साथ रिजर्व बेंक को निम्नतिखित कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त न हुई।

रिजर्व वैङ्क की असफलतायें

(१) मुद्रा बाजार के विभिन्न विभागों में आज भी सहयोग का भारी अभाव है और आज भी एक दूसरे से प्रतिथोगिता कर रहे हैं। देश में अन्य छोटी-छोटी बैंक, सहकारी साख समितियाँ ओर देशी बैंक आज भी हैं, जिन पर यह नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकती है।

- (२) रिजर्व बैंक रुपये का आन्तरिक मृत्य स्थिर नहीं रख सकी है। दूसरे महा-युद्ध में जो मुद्रा प्रसार की नीति उसने अपनाई थी, उसके घातक-परिणामों से आभी तक देश को छुटकारा नहीं मिल सकता है। परन्तु वास्तव में सारा दोष रिजर्व बैंक ही का नहीं था। उस समय भारत में विदेशी सरकार थी, जिसने रिजर्व बैंक ऐक्ट की. सारी घाराओं का दुरुपयोग किया था।
- (३) रिजर्व वैंक देश में एक सुन्यवस्थित हुन्ही बाजार को विकसित करने में भी सफल नहीं हो सकी है। यह वैंकों को दुबारा भुनाने की सुविधाय बहुत थोड़ी ही मात्रा में प्रदान कर सकी है।
- (४) भारतीय मुद्रा बाजार की ब्याज की दरों की भिन्नता को भी यह दूर नहीं कर सकी है।
- (५) कृषि साल की उचित व्यवस्था करने में भी यह असमर्थ रही है। और जो संस्थायें देश में कृषि साल प्रदान करती हैं, उन पर भी पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाई है। रिजर्व बैंक की ये असफलतायें स्फलताओं के समस् अधिक नहीं हैं। रिजर्व बैंक देश के आर्थिक स्त्रेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है।

रिज़र्य वैङ्क तथा मुद्राबाजार—मुद्रा तथा साख का नियंत्रण करने के लिए रिज़र्व बैंक ब्राधुनिक शस्त्रों से पूर्णतया सुसिन्जित है। कागजी मुद्रा प्रकाशित करने का इसे एकाधिकार है। भारतवर्ष में लोगों को चेक द्वारा भुगतान की ब्रादत बहुत कम है। ब्रातः मुद्रा की समस्त पूर्ति रिज़र्व बैंक के नोट ही करते हैं। किन्तु ब्राव चेकों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में होने लगा है। ब्रातः रिज़र्व बैंक ब्रानुसूचित बैंकों की जमा घनराशि का कुछ प्रतिशत ब्रापने पास रख कर देश के बैंकों पर तथा उनके नकद कोषों पर नियंत्रण रखती है। सरकारी नकद कोष भी रिज़र्व बैंक के पास रहता है। इन सब बातों के कारण रिज़र्व बैंक के लिए देश की मुद्रा तथा साख पर नियंत्रण रखना सुगम है।

भारतीय मुद्रां नाजार में स्टेट बैंक का कुछ विचित्र स्थान है। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की शाखार्य नहीं हैं वहाँ रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में स्टेट बैंक ही केन्द्रीय बैंक का कार्य करती है। किन्तु साथ ही बैंकिंग के च्रेत्र में व्यापारिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करती है जो उचित नहीं। स्टेट बैंक की इस कार्य पद्धति के कारण देश की बैंक संतोध अनुभव नहीं करतीं और उनके हृदय में स्टेट बैंक के प्रति कुछ ईर्षा रहती है। अतः रिजर्व बैंक को चाहिये कि सभी बैंकों के साथ समान व्यवहार करे और स्टेट बैंक को विशेष स्थान न दे।

भारतीय मुद्रा बाजार को विदेशी विनिमय बैंक भी प्रभावित करती हैं। शक्तिशाली होने तथा संसार के सभी भागों में इनकी शासायें होने के कारण ये वैंक रिजर्व बैंक की नीति को कभी-कभी विफल बना देती हैं। अब देश स्वतन्त्र हो गया है। अतः रिजर्व बैंक इन विदेशी विनिमय बैंकों पर पूर्ण नियंत्रण कर सकती है और देश की भलाई के लिये अपनी स्वतन्त्र नीति निर्धारित कर सकती है।

प्रामीण वित्त के ६० प्रतिशत का देशी वैंकर तथा साहूकार ही प्रवस्थ करते हैं। किन्तु इन देशी वैंकरों पर रिजर्व वैंक का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। जब तक मुद्रा बाजार का इतना महत्वपूर्ण अंग रिजर्व वैंक के प्रभाव से बाहर रहेगा तब तक रिजर्व वैंक का नियंत्रण पूर्णतया सफल नहीं हो सकता। मुद्रा बाजार को पूर्णतया नियंत्रित करने के लिये रिजर्व वैंक का देशी साहूकारों से पूर्ण सम्बन्ध होना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में रिजर्व वैंक ने जो योजना बनाई है उतकी देशी साहूकार कान्तिकारी कहकर स्वागत नहीं करते। क्योंकि यह योजना उनके अस्तित्व को ही समाप्त करती है। रिजर्व वैंक को चाहिये कि इतने महत्वपूर्ण अंग को समाप्त न करके उसमें मुघार करने का प्रयत्न करे।

व्यापारिक हुंडियों की कमी के कारण रिजर्व वैंक की कटौती नीति सिक्रिय नहीं होती । जब तक वैंक की यह नीति सिक्रिय न होगी तब तक भारतीय मुद्रा बाजार अपने भाग्य पर जीवित रहेगा । अतः रिजर्व वैंक को एक समुचित एवं सिक्रिय वैंक दर नीति निर्धारित करनी चाहिये । हमारे देश में वैंक दर तथा बाजार दर में कोई समुचित सम्बन्ध नहीं है । स्टेट वैंक शक्तिशाली होने के कारण अपनी दर अलग निर्धारित करती है । जब तक वैंक दर मुद्रा बाजार को प्रभावित नहीं करती तब तक रिजर्व वैंक की सर्वोच्चशक्ति हीन रहेगी । अतः इस दिशा में मुधार करने के लिये एक ठोस कदम की आवश्यकता है । अनेक बाधार्य होते हुए भी आस्ट्रेलिया तथा दिख्य अफ्रीका की केन्द्रीय वैंक वहाँ के मुद्रा बाजार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किये हुई हैं और उनका बाजार के विभिन्न अंगों पर पूर्ण प्रभाव है ।

एक अञ्चे हुन्डी बाजार की स्थापना के लिये रिजर्व वैंक ने योजना बनाई है और व्यापारिक वैंकों के सहयोग से खड़ाने की हुंडियों का विकास करने के लिये प्रयत्नशील हैं। किन्तु यह योजना सफलता प्राप्त न कर सकी। खजाने की हुन्डियों का प्रचलन बढ़ जाने से रिजर्व वैंक सरकार से दम व्यय पर ऋण प्राप्त करके तथा इन हुंडियों की कटौती करके मुद्रा बाजार गर अधिक नियंत्रण कर सकती है।

रिचर्व बैंक ने एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ावा देकर सुद्रा बाजार में सुभार किया है। रिजर्व बैंक बैंकों की निरीच्या करके तथा उन्हें समय-समय पर परा-

मर्श देकर एक अञ्छी दिशा में उनका पथ-प्रदर्शन करती है और मुद्रा बाजार पर अपने प्रभाव की स्थापना करती है।

ं विदेशी मुद्रा के कय-विक्रय तथा उनके भार से देश की आर्थिक व्यवस्था की रज्ञा की है। विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करके रिजर्व बैंक उस पर पूर्ण नियंत्रण करती है और समय-समय अपनी नीति में परिवर्तन करके देश की आन्तरिक आर्थिक व्यवस्था पर उसका भार नहीं पड़ने देती। सरकार को परामर्श देकर एक हितकारी आयात-निर्यात नीति निर्धारित करती है।

रिजर्व वैंक ने इस बात के लिये कई कदम उठाये कि बैंक की साख देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित हो। सन् १६४६ के भारतीय रुपये के अवस्त्रम् के पश्चात् सहेबाजी का उदय हुआ। अतः रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को यह आदेश दिया कि वे ऋग केवल वास्त्रविक व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए प्रदान करें, सहेबाजी के लिये नहीं। बैंकों के लिये प्रतिदिन १,००,००० रुपये से अधिक वाले ऋगों की सूची रिजर्व बैंक के पास भेजना अनिवार्य कर दिया गया। इन सूचियों के निरीक्ष से यदि रिजर्व बैंक को यह ज्ञात हुआ कि कुछ ऋग अवांछनीय हैं तो उसे तुरन्त वापस लेने का आदेश दिया गया। बैंकों ने रिजर्व बैंक के आदेशों का पालन करके सहेबाजी से उत्पन्न बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में सफलता प्राप्त की।

राष्ट्रीयकरणोपरांत रिजर्व बैंक देश की साख एवं सुद्रा पर पूर्ण नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त कर रही है। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि सभी बैंकों का राष्ट्रीकरण देश के हित में है। इससे जनता को अपना धन बैंकों में जमा करने में सुरद्धा का आमास होगा। किन्तु राष्ट्रीयकरण तभी सुद्रा बाजार पर अञ्छा प्रमाव डाल सकता है जब राजनीति का इन आर्थिक संस्थाओं में समावेश न हो।

प्रश्न

1. What were the causes which led to the establishment of the Reserve Bank of India? Discuss its influence on Indian banking.

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किन कारणों से हुई ? भारतीय बैंकिंग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ?

2. Examine the constitution and functions of the Reserve Bank of India. Can you suggest any improvements in its organisation and working?

रिजर्व बैंक के विघान एवं कार्यों की विवेचना कीजिये। क्या श्राप इसकी व्यवस्था एवं कार्य पद्धति में सुधार के कुछ सुभाव दे सकते हैं ?

3. What is the business of the Reserve Bank of India? How

has the creation of the Reserve Bank improved Indian Banking and Currency?

भारतीय रिजर्व वेंक क्या कार्य करती है ! इसकी स्थापना से भारतीय वेंकिंग एवं सुद्रा में क्या सुधार हुन्ना है !

4. Indicate the chief defects in the working of the Reserve Bank of India and suggest into woments.

भारतीय रिजर्व वें के की कार्य पद्धति के मुख्य दोष बतलाइये तथा मुधार के मुभाव दीजिये।

5. Discuss the place of Reserve Bank of India ris-a-vis the Rural Credit.

प्रामीण साल में रिजर्व वैंक के स्थान की विवेचना कीजिये।

6. What is the relation of the Reserve Bank of India with the Joint Stock Banks of the country?

रिजर्व वैंक का देश के सम्मिलित पूँजी वाली वैंकों से क्या सम्बन्ध है ?

7. Express your views on "Nationalisation of Reserve Bank of India."

रिवर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण पर अपने विचार सफट कीजिये।

स्रध्याय ५

स्टेट बेंक आफ इण्डिया

(State Bank of India)

स्थापना—भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता तो सन् १८६६ से ही प्रतीत होने लगी थी। परन्तु भारत सरकार की उदासीनता के कार्स्ण् १६२० तक इस संबन्ध में कुछ भी न हो सका। आत में भारत सरकार ने परिस्थितियों से निवश होकर १६२७ में बम्बई, मद्रास तथा बंगाल की तीनों प्रेसीडेन्सियों में बैंकों का एकीकरण करके इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया एक्ट १६२१ के अंतर्गत इम्पीरियल बैंक की स्थापना की। सन् १६५५ में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इम्पीरियल बैंक का नाम बदल कर स्टेट बैंक आफ इंडिया कर दिया गया है। इस बैंक का भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी बैंक की स्थापना के साथ ही साथ भारत में आधुनिक बैंकिंग पद्धित का प्रादुर्भाव हुआ। इस बैंक की स्थापना भारत सरकार के समस्त लेन-देन करने, बैंकों के बैंक का कार्य करने तथा भारत में आधुनिक बैंकिंग की सुविधाओं की बृद्धि करने के लिये की गई थी, परन्तु सन् १६३४ में इम्पी-रियल बैंक एक्ट का शोधन कर दिया गया जिसके अनुसार इसके प्रथम दोनों कार्य इससे छीनकर रिजर्व बैंक को दे दिये गये। अब यह केवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्यापारिक बैंक के रूप में रह गई है।

रिजर्व वेंक की स्थापना के पूर्व इम्पीरियल वेंक आफ इंडिया की स्थिति—रिजर्व वेंक की स्थापना सन् १६३५ में हुई। उससे पहले इम्पीरियल वेंक सरकारी वेंक के रूप में कार्य करती थी। जितना भी सरकारी कोष होता था वह इम्पीरियल वेंक में ही रखा-जाता था। सरकारी खजाने का काम भी इम्पीरियल वेंक ही करती थी। इम्पीरियल वेंक इस कार्य के लिये कोई कमीशन न लेता था। सरकार को जितना क्या मिलना होता था वह इम्पीरियल वेंक लेता था और सरकार अपने व्यय के लिये उससे रूपया निकालती थी। परन्तु भारत सरकार के ऋण का प्रवन्ध भी इम्पीरियल वेंक ही करती थी।

सरकारी कारबार के अतिरिक्त १६३५ के पूर्व केन्द्रीय बैंक के भी कुछ कार्य करती थी। भारत के अधिकांश बैंक उसके साथ डिपाजिट रखते थे। इसके अतिरिक्त भारत के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में स्थापित ११ समाशोधन ग्रहों का भी प्रवन्त करती थी। इम्पीरियल वैंक जहाँ जहाँ उसकी शाखायें थीं वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपया मेजने की सुविधा प्रदान करती थी। वैंक तथा जनता दोनों ही इम्पीरियल कैंक द्वारा रूपया एक स्थान से दूसरे स्थान को मेज सकते थे। इम्पीरियल वैंक रूपया मेजने के लिये जो कमीशन लेती थी उसको मरकार नियंतित करती थी। इसके बदले में इम्पीरियल वैंक को सरकारी खजानों के द्वारा देश में एक स्थान में दूसरे स्थान को विना कुछ लिये ही रूपया मेजने की मुविना दो गई थी।

जब देश के मुद्रा बाजार में कमी पड़े तो उस कमी को पूरा करने के लिये कागजी मुद्रा बैंक को १२ करोड़ रुपये तक ऋख दे सकती थी। किन्तु बैंक को उसकी जमानत स्वरूप हुंडी या बिल खने पड़ते थे। सरकार बैंक से पहले ४ करोड़ रुपये के लिये ६ प्रतिशत और शेप म करोड़ के लिये ब्याज लेती थी। देश में बैंकिंग मुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से इम्पीरियन बैंक के लिये कानून में ५ वर्षों के मीतर १०० शाखायें स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया था। इम्पीरियल बैंक ने इस शर्त को पूरा कर दिया था। आधी शाखायें ऐसे स्थान पर स्थापित की गई थीं जहाँ पर कोई बैंक न थी। इसके बदले सरकार इम्पीरियल बैंक के पास अपना रुपया बिना ब्याज रखती थी।

एक व्यापारिक वैंक होने के नाते इम्पीरियल वैंक का वह सभी कार्य करती थी जो कि एक व्यापारिक वैंक करती है। इम्पीरियल वैंक भारतवर्ष में डिपाबिट ले सकती थी श्रीर ऋग ले सकती थी किन्तु देश के बाहर न तो डिपाजिट ही ले सकती थीन ऋण ही ले सकती थी। केवल लंदन शाखा को यह ऋषिकार था कि वह प्रेसीडेन्सी बैंकों के पुराने प्राहकों से डिपाजिट प्रहरण कर सकती थी और वैंक की सम्पत्ति या लेन-देन की जमानत पर बैंक के कारबार के लिये ऋगा ले सकती थी। इम्पीरियल बैंक अपना रुपया कहाँ लगावे इस पर कुछ प्रतिबन्ध लगे थे। इम्पीरियल बैंक केवल ट्रस्ट्री प्रतिभृतियों में रुपया लगा सकती थी। उदाहरण के लिये भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकार की प्रतिभृतियों में, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्रति-भूतियों में, ऋधिकृत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्रतिभृतियों तथा डिवेंचरों में ही इस्पीरियल बैंक श्रपना रुपया लगा सकती थी। इम्पीन्यिल बैंक उपर लिखी प्रतिभृतियों की जमानत पर ऋग दे सकती थी। इम्पीरियल बैंक हुंडियों ऋौर प्रामिसरी नोटों को स्वीकार कर सकती थी तथा माल ऋथवा उसके प्रलेखों को यदि जमा करा दिये गये हों तो उन्हें बमानत के रूप में खीकार करके ऋण दे सकती थी। किन्तु ६ महीने से अधिक के लिये ऋग नहीं दे ६कती थी और न उसे ऐसे किसी विनिमय साध्य पुर्जे (Negotiable Instrument) को ही स्वीकार कर सकती थी जिस पर दो व्यक्तियों तथा दो फर्मों के हस्ताच्चर न हों (जो आपस में सामेदार न हों) और जिनके पकने की अविध ६ मास से अधिक न हो। इसी प्रकार किसी व्यक्ति या फर्म को कितना ऋष अधिक से अधिक दिया जा सकता है यह भी निर्धारित कर दिया गया था। इम्पीरियल बैंक केवल उन हुंडियों तथा अन्य विनिमय साध्य पुर्जों को केवल लिख सकती यी और सुना सकती थी और स्वीकार कर सकती थी जिनका कि भारत में या लंका में भुगतान होने वाला हो। किन्तु कानून द्वारा इम्पीरियल बैंक को विदेशी विनिमय का कार्य करने की आजा नहीं थी। इम्पीरियल बैंक किसी ऐसे बिल इत्यादि को भुना भी नहीं सकती थी कि जिसकी अवधि ६ मास से अधिक हो और न किसी ऐसी विनिमय साध्य प्रतिभृति को क्रय कर सकती थी जिसकी अवधि ६ मास से अधिक हो। बैंक प्रतिभृतियों, आमृष्णों तथा स्वर्ण इत्यादि को सुराचृत रखने के लिये ले सकती थी। सोना खरीद और बेच सकती थी तथा प्राहकों के लिये लाम भूतियों का क्रय-विक्रय कर सकती थी और उन पर प्राहकों के लिये लाम और ब्याज प्राप्त कर सकती थी।

प्राप्त कर सकती थी।
इम्पीरियल बैंक की पूँजी तथा प्रबन्ध—इस बैंक की अधिकृत पूँजी
११.२५ करोड़ रुपये थी जो २,२५,००० अंशों में विभक्त थी। प्रत्येक अंश का मूल्य
५०० रुपये निर्धारित किया गया था। बैंक का सुरिच्चित कोष ६ २५ करोड़ रुपये का
था। १६३१ तक बैंक ने १६ प्रतिशत तथा उसके पश्चात् १२ प्रतिशत लामांश
घोषित किया।

सन् १६२० के अधिनियमानुसार इम्पीरियल बेंक का संगठन १६ संचालकों की, जिन्हें गवर्नर कहते थे, की समिति करती थी। इन १६ में १० गवर्नरों की नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल करते थे। इन १० में से २ प्रचन्घ गवर्नर, भारतीय आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, ४ गैर सरकारी गवर्नर, स्थानीय समितियों के ३ सेक्रेंटरी तथा १ भारत सरकार का अधिकारी होता था। शेष ६ गवर्नरों की तीनों स्थानीय समितियों के अश्राधारी निर्वाचित करते थे। यह निर्वाचित गवर्नर तीनों स्थानीय समितियों के प्रधान एवं उपप्रधान होते थे।

सने १८३४ के संशोधित श्रिघिनियम के श्रंतर्गत केन्द्रीय समिति में १६ संचालक होते थे जिनमें स्थानीय समितियों के प्रधान, उपप्रधान तथा सेक्रेटरी, स्थानीय समितियों के श्रंशधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ३ संचालक गवर्नर जनरल द्वारा, २ गैर सरकारी मनोनीत व्यक्ति, १ केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त श्रिधकारी तथा ५ वर्ष के लिए केन्द्रीय समिति द्वारा नियुक्त १ प्रबन्ध संचालक तथा १ उपप्रबन्ध संचालक समिलित होते थे। केन्द्रीय संचालक समिति का कोई निश्चित स्थान नहीं था। अतः उसकी बैठकें बम्बई या कलकत्ते में हुआ करती थी। उपप्रबन्ध संचालक को प्रवन्ध

संचालक की उपस्थिति में मत प्रदान करने का ऋधिकार न था। वैंक का सभी कार्य ऋंतर्नियमों के ऋंतर्गत होता था। केन्द्रीय समिति तो केवल साधारण नीति निर्धारित करती थी।

रिज़र्व वेंद्व की स्थापना के परचात् इम्पीरियल वेंद्व आफ इंडिया की स्थिति में परिवर्तन—इम्पीरियल वैंक रिजर्व वैंक की एक मात्र एजेंट नियुक्त कर दी गई। श्रीर इसलिये कुछ प्रतिबन्ध जो पहले इस पर लगे ये इम्बीरियल बैंक श्राफ इंडिया में संशोधन करके उठा लिये गये । अब इम्पीरियल बैंक सरकारी बैंक का कार्य वहाँ तक ही करने लगी जहाँ तक कि वह रिजर्व वैंक की एजेंट है। श्रीर उसका सरकार से कोई सीघा सम्बन्ध नहीं रहा। यहले की भाँति अब वह अन्य बैंकों का वैंकर भी नहीं। इम्पीरियल वैंक भारत के बाहर भी जमार्ये प्राप्त कर सकती, शाखाएँ खोल सकती तथा ऋण ले सकती हैं। वह अब विदेशी विनिमय का कार्य भी करने लगी तथा विदेशी हुं डियों का ऋय विकय तथा कटौती करने लगी। अब वह प्राय: वे सभी कार्य करने लगी जो एक ग्रन्य व्यापारिक वैंक कर सकती है। ग्रव वह विदेशी ह़ं डियों को लिख व बेचने लगी। परन्तु ये हुं डियाँ कृषि के सम्बन्ध की हैं तो ६ मास से अधिक तथा अन्य कार्य की हैं तो ६ मास से अधिक की न होनी चाहिये। इस्पी-रियल बैंक ऋव साख पत्र भी निकालने लगी ऋौर वह कमीशन पर कोई भी ऋर्य सम्बन्धी आदत का कार्य करने लगी। तथा जमानत पर अथवा बिना जमानत के ही किसी प्रकार की च्रित पूर्ति का उत्तरदायित्व लेने लगी । इम्पीरियल बैंक कोर्ट श्राफ वार्डस को छोड़ कर अचल सम्पत्ति अथवा उसके अधिकार पत्रों पर नहीं ले सकती। इम्पीरियल बैंक अधिक से अधिक कितना अपूर्ण सामेदार फर्म को दे सकती है यह भी कानून द्वारा सीमित कर दिया गया। इम्पीरियल बैंक बिना रिजर्व वैंक की अनुमृति के कोई नवीन शाखा नहीं खोल सकती। इम्मीरियल वैंक को श्रपनी कोई शाखा बन्द करने का भी श्रधिकार नहीं। इस प्रकार रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् इम्पीरियल वैंक के कार्यों तथा ऋषिकारों में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया गया।

रिजर्व वैङ्क की स्थापना के उपरान्त इम्पीरियल वैङ्क के कार्य—इम्पीरियल वैंक अपना समस्त कार्य १६३१ के इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के अंतर्गत करती है। सन् १६३५ में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के स्थापित होने के पहले इम्पीरियल बैंक के कार्यों पर विधान द्वारा बहुत से प्रतिबन्ध लग्ने थे। परन्तु १६३५ में इम्पीरियल बैंक के बहुत से कार्य रिजर्व बैंक ने अपने ऊपर ले लिये। अतः यह आवश्यक हो गया कि इम्पीरियल बैंक आफ इंग्डिया में संशोधन करके उस पर लगे प्रतिबन्धों को हटा लिया

जाये । इम्पीरियल वैंक के संशोधित विधान के अनुसार अब बैंक निम्नलिखित कार्य करने लगी---

- (१) इम्नीरियल बैंक निम्नलिखित जमानतों के श्राधार पर ऋण तथा साख दे सकती है—
- (ग्र) स्थानीय सरकार तथा ग्रन्य संस्थाओं के ऋणपत्रों तथा ग्रन्य प्रतिभृतियों पर, द्रस्टी प्रतिभृतियों तथा रिजर्व बैंक के ग्रंशों पर।
 - (ब) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित रेलवे प्रतिभूतियों पर ।
- (स) अन्य संस्थाओं जैसे जिला बोर्ड अथवा नगरपालिका अथवा सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के ऋणों पर ।
- (द) बैंक में जमा कराये हुए माल श्रयवा माल के श्रधिकार पत्रों के श्राधार पर।
- (ई) स्वीकृत हुं डियाँ, प्रतिज्ञा पत्रों अथवा दो से अधिक व्यक्तियों अथवा सामे द्वारा लिखे हुए संयुक्त और पृथक प्रमाण पत्रों के आधार पर।
- (द) सीमित दायित्व वाली कम्पिनयों के पूर्ण रूप से भुगतान किये गये अंशों पर।
- (२) यदि किसी ऋगा के सम्बन्ध में कोई प्रतिज्ञापत्र, ऋगापत्र, माल, माल के अविकार पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियाँ बैंक के हाथ बेची जाती हैं तो यह ऋगा सुगतान न होने पर उन्हें बेच कर अपने रुपये प्राप्त कर सकती है।
- (३) स्थानीय सरकार की स्वीकृति से कोर्ट आफ वार्ड स के सामाजिक, कृषि कार्यों तथा अन्य कार्यों के लिये रुपये उघार देना तथा उसे ब्याज सहित प्राप्त करना परन्तु ऐसे ऋण कृषि कार्यों के लिए तो ६ मास से अधिक तथा अन्य कार्यों के लिए ६ मास से अधिक तथा अन्य कार्यों के लिए ६ मास से अधिक के लिये नहीं होने चाहिये।
- (४) यह विनिमय हुंडियाँ तथा श्रन्य विनिमय साध्य पत्रों को श्राहरित कर सकती है, स्वीकृत कर सकती है तथा क्रय-विक्रय कर सकती है।
- (प्र) यह प्रथम भाग में (ऋ) से (स) तक उल्लेखित जमानतों में ऋपना रूपया लगा सकती है। ऋौर उन्हें वहीं पर दी हुई ऋन्य प्रकार की प्रतिभूतियों में परिवर्तित भी कर सकती है।
- (६) वह अपनी सम्पित पर रुपया उधार ले सकती है तथा अन्य प्रकार का कोई भी बैंकिंग कार्य कर सकती है। वह जैमा प्राप्त कर सकती है अौर किसी भी शर्व पर हिसाब रख सकती है। वह लोगों को उधार भी दे सकती हैं।
 - (७) वह सोने-चाँदी की क्रय-विक्रय भी कर सकती है तथा सोने-चाँदी के

वर्तन, श्राभृषण, जकाहिरात, श्रिषिकार तथा श्रम्य बहुमूल्य वस्तुश्रों को घरोइर के रूप में तथा सुरक्ति रख सकती है।

- (८) वह चल और अचल सम्मित्त तथा उसके अधिकार पत्रों को जो उसके अधिकार में हैं अथवा आदें उन्हें वेच सकती है तथा अन्य प्रकार क प्रयोग में ले सकती है।
- (६) वह विदेशी हुं हियों को लिख सकती है, परन्तु यदि ये हुं डियाँ कृषि के सम्बन्ध की हैं तो ६ मास से अधिक तथा अपन्य कार्यों के लिये हैं तो ६ मास से अधिक अविष की नहीं होनी चाहिये। यह वैंक साखपत्र भी निकाल सकती है।
- (१०) वह किसी भी सार्वजिनिक कम्पनी के साखरतों और श्रंशों को कमीशन पर न खरीद वेच तथा हरतांतरित कर श्रवने पास रख सकती है। वह उपर्युक्त रकम को देश में बाहर कहीं भी सार्वजिनिक श्रथवा श्रपनी हुण्डियाँ द्वारा पहुँचा सकती है। यह किसी भी स्टेट के साधक (Executor), धरोहरी (Trustee) श्रादि की की व्यवस्था कर सकती है।
- (११) वह कनीशन पर भी ऋर्य सम्बन्धी ऋादत कार्य कर सकती है। तथा जमानत पर ऋथवा बिना जमानत के ही किसी प्रकार की च्ितपूर्ति का ऋथवा प्रति-भृति का दायित्व ले सकती है।
- (१२) वह अन्य कोई कार्य जो ऐक्ट द्वारा स्वीकृत किया गया हो तो अन्य सभी कार्य जिनके करने की आवश्यकता प्रसंगवश आ जाये कर सकती है।

इम्पीरियल बैंक्क के वर्जित कार्य-१६३४ के उपरांत इर्मारियल बैंक के कार्यों पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये गये—

- (१) यह बैंक किन्हीं भी कृषि कार्यों के लिये ऋष ६ मास से ऋषिक तथा अन्य कार्यों के लिए ६ मास से ऋषिक अविष के लिये ऋण नहीं दे सकती। यह स्वयं ऋपने ऋंशों पर भी ऋण नहीं दे सकती। इसी प्रकार कोर्टस् ऋपक वार्ष्स को छोड़ कर ऋचल सम्पत्ति ऋथवा उसके ऋषिकार पत्रों पर भी ऋण नहीं दे सकती है।
- (२) यह बैंक किसी भी व्यक्ति के ऋथवा सामे के विनिमय साध्य पत्रों तथा ऋन्य ऋषिकार देने वाले साखपत्रों के जमानत पर न तो नकद साख ही दे सकती है न ऋणा। न इस प्रकार के पत्रों को खरीद या भुना ही सकती है जब तक इन पर कम से कम दो स्वतन्त्र व्यक्तियों के ऋथवा सामे के पृथक-पृथक हस्ताच्चर तथा दायित्व न हों। ऋगैर जो पारस्परिक सामेदार भी न हों। इम्गीरियल बैंक ऋषिक से ऋषिक कितना ऋण एक व्यक्ति ऋथवा सामे को दे सकेगी यह भी विधान द्वारा सीमित कर दिया गया है।

- (३) यह बैंक केवल उन्हीं प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय ऋथवा कटौती कर सकती है तथा उनकी जमानत पर रुपया उधार दे सकती है जिनको ट्रस्ट ने ऋपने विनियोग के लिये स्वीकार कर रखा है।
- (४) यह वैंक ऋब बिना रिजर्व वैंक की ऋनुमित के कोई भी नवीन शाख नहीं खोल सकती है।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का लगाना इसी लिये त्र्यावश्यक समका गया जिनसे इमी-रियल बैंक रिजर्व बैंक के रूप में जिस सरकारी धन को रखती है उसे सुरिच्त रख सके।

१६४४ तक इम्पीरियल बैङ्क का देश के मुद्राबाजार में स्थान-इम्पीरियल र्वेंक के रूप में इस वेंक ने सन् १९५५ तक कार्य किया। १ जुलाई १९५५ को यह वैंक स्टेट वैंक में परिवर्तित कर दी गई । परिग्गत होने तक इम्पीरियल बैंक ने देश में बैंकिंग सुविधात्रों का विस्तार किया। इस समय इसकी लगमग ४७२ शाखायें देश के कोने-कोने में कार्य कर रही हैं जिससे स्पष्ट है कि इसने राष्ट्र की व्यापारिक श्रीर व्यवसायिक चेत्र में कितनी सेवा की । इतनी ऋधिक शाखायें होने के कारण इसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर घन भेजने की सस्ती सेवायें प्रदान की । इम्पीरियल बैंक ने अपनी कटौती दर को स्थिर रख कर देश की अन्य संस्थाओं को भी कटौती दर स्थिर रखने को बाध्य किया। इम्मीरियल बैंक के पास पूँजी एक बड़ी मात्रा में है। श्रतः उसकी ब्याज दर सदैव कम रही है जिसका एक श्रुच्छा प्रभाव यह हुआ कि अन्य बैंकिंग संस्थात्रों को भी ब्याज की दरों को कम करने के लिये विवश होना पड़ा। यह बैंक सहकारी बैंकों को अधिक निकासी की सुविधायें प्रदान करके राष्ट्रीय हित में कार्य करती रही। इम्पीरियल बैंक खेती की फसलों की जमानत पर भी ऋण प्रदान करती रही जिसके कारण उनकी बिक्री श्रीर उनके यातायात में पर्याप्त सुगमता रही। इसने आर्थिक संकटों में बहुत से बैंकों को सहायता देकर समाप्त होने से बचाया। इसने देश के निकास गृहों का प्रबन्ध करके बैङ्किंग प्रणाली के विकास में सहायता पहुँचाई व्या इ्म्पीरियल वैंक ने देशी वैंकरों श्रीर श्रन्य व्यापारिक वैंकों को ऋण प्रापु करने में बहुत सुविधायें प्रदान कीं ।

इम्पीरियल बैंक भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक थी। इसकी साल मी पर्याप्त थी। अतः इसको स्थानीय सरकारों से बिना व्याज के जमा प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त भारत की कुल बैंकों की जमा का २३% भाग इसके पास था तथा कुल बैंकों हारा लिये ऋण और हुन्डियों का २०% और कुल विनियोग की २५% भाग इस बैंक का था। इसके पास ५,६२ करोड़ रुपये की अंश पूँजी थी और ५६५ व्याप्त हमें अंश प्राप्त हमें अंश हमें अंश प्राप्त हमें अंश हमें

करोड़ रुपये का सुरिच्चित कोप था। इस तथ्यों से इस वैक का भारतीय सुद्रावाचार में महत्व स्पष्ट हो जाता है।

इस्पीरियल येंद्व की आलोचनायें - यद्यवि इस्मीरियल वेंक ने देश को बैंद्विग सुघार प्रदान करने में बड़ी सहायता की है फिर भी समय-समय पर उसकी कार्य प्रणाली की बड़ी आलोचना हुई। इस वैंक के संचालन में अधिकतर विदेशियों का हाय था। बड़े-बड़े कर्मचारी भी सब बिदेशी ये। १६५५ तक अपनी स्थापना के ३४ वर्षों में इसने कभी भो भारतीयों को ऊँचे पर पर नियक्त नहां किया। भारतीय व्यापा-रियों की अपेदा यह विदेशां व्यासारियों को ही प्रोत्साइन देती थी। विदेशियों के हायों इसका संचालन होने से इसकी ऋगा नीति कभी भी निष्यस् नहीं रही। इसने भारतीयों को बहुत कन ऋण दिये जब कि विशेश में को बहुत ऋण दिये। श्रीर यह सदैव भारतीयों की जमा राशि से विदेशियों के स्वार्थी को पुग करती रही। कुछ ऋर्थ-शास्त्रियों ने यह भी श्रारीन लगाया कि दर्भीरियल वैंक ने जो श्रानी इतनी शाखायें खोल रखी हैं वे केवल जमा प्राप्त करने के उद्देश्य से ही खोड़ी है न कि राष्ट्रीय हित-के लिये । इम्पीरियल वैंक की कार्याविध का ठवसे वड़ा दौप यह रहा कि इसने हन्हियों के प्रयोग को बढ़ाने के लिये कोई विशेष प्रयन्त नहीं किया । श्रौर इसने केवल व्यक्ति-गत साख को ही महत्व दिया जिसके कारण भारतीय हुन्डी बाजार आज तक अविक-सित रहा। भारतीय व्यापारिक वैंकों की श्रोर से यह भी कहा गया कि इसको रिजर्व बैंक के एजेन्ट का कार्य छौंप कर ब्रानुचित प्रतियोगिता प्रदान करने की शक्ति प्रदान कर दी गई जिससे उनकी उन्नात में बाधा पड़ी।

उपरोक्त बहुत सी आले चनायें चैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने पर व्यर्थ हो गई हैं श्रीर अब इम्मीरियल चैंक स्टेट चैंक के रूप में सराहनीय कार्य करने लगी है।

स्टेट बैक्क का राष्ट्रीयकरण — एरकार ने इम्पीरियल बैंक का कार्य विधि की जाँच करने के लिए एक प्रामीण बैंकिंग जाँच समिति की नियुक्ति १६५० में की जिसने बैंक के राष्ट्रीयकरण को ही देश के हित में बतलाया। सरकार ने सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीयकरण को स्वीकार किया किन्तु कुछ कारणों से यह कार्य शीव सम्पन्न न हो सका। १६५१ में रिजर्व बैंक के श्रिखल भारतीय प्रामीण साख समिति ने भी भारतवर्ष में एक राष्ट्र बैंक स्थापित किये जाने पर बल दिया तथा यह अनुरोध किया कि राष्य बैंक एक ऐसी व्यापारिक संस्था होनी चाहिये जो बैंकिंग व्यवसाय के सिद्धान्तों का उलंघन किये बिना एक ऐसी नीति अपनाय जो सरकार की राष्ट्रनीति के अनुसार हो तथा जो अन्य बैंकों को रुपया भेजने की सुविधाये प्रदान करें। उसने यह भी सुक्ताव दिया कि राष्य बैंक्क सरकार के साक्षेत्र के सामे में स्थापित की जाएँ। यह सुदृढ़ व्यापारिक बैंक्क हो तथा उसकी देश भर में अनेकों शाखाये हों। अतः सरकार ने इम्पीरियल बैंक्क

को राज्य बैङ्क में परिएात करने की बोषिए। करके मई १६५५ में भारतीय संसद के सम्मुख एक विधेयक उरिध्यत किया जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। प्रथम जुलाई १६५५ से इम्पीरियल बैङ्क के स्थान पर स्टेट बैङ्क ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

स्टेट वैंक्क का संगठन — स्टेट बैंक को ६ स्थानीय च्चेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक च्चेत्र का प्रबन्ध एक स्थानीय समिति द्वारा होता है। किन्तु यह सिनियाँ केन्द्रीय समिति द्वारा नियुक्त होती हैं। स्टेट बैंक की केन्द्रीय समिति (Central Board) में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:—

- (ऋ) एक ऋध्यत् तथा एक उगाध्यत्त जिनकी नियुक्ति रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार करती है।
- (व) दो प्रवन्ध संचालक जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की अनुमित से केन्द्रीय समिति करती है।
- (स) ६ संचालक जिनका निर्वाचन रिजर्व बैंक के श्रातिरिक्त श्रान्य श्रांशघारी करते हैं।
- (द) प्र संचालक जिन्हें रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार मनोनीत करती है। इन प्र में से कम से कम दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिये जिन्हें सरकारी संस्थाओं एवं प्रामीण ऋर्थिक अवस्था का पूर्ण ज्ञान हो तथा शेष व्यापार, उद्योग, बैंकिंग तथा वित्त संबन्धी अनुभव रखते हों।
 - (ई) एक संचालक जिसे केन्द्रीय सरकार मनोनीत करती है।
 - (फ) एक संचालक जिसे रिजर्व बैंक मनोनीत करती है।

श्रध्यच्च, उपाध्यच्च तथा प्रबन्ध संचालक केन्द्रीय सरकार के नियमानुसार ५ वर्ष तक कार्यपद सँमालते हैं।

स्टेट बैंक को रिजर्व बैंक के परामर्श एवं केन्द्रीय सरकार की श्रनुमित से १६६० तक देश के विभिन्न भागों में ४०० शाखायें स्थापित करनी हैं। १६५६ में १०० से श्रिष्टिक शाखायें स्थापित कर दी गई थीं।

इम्पीत्यल बैंक के पुराने अंशों को समाप्त करके च्रित्पूर्ति प्रदान की गई है, किन्तु पुराने अंशघारियों को उनकी इच्छा पर यह अवसर प्रदान किया गया कि वे चाहें तो अपने अंशों को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर सकते हैं; उन प्रतिभृतियों पर ३५ प्रतिशत ब्याज मिलेगी और यह डेढ़ प्रतिशत कटोती पर परिवर्तित किये बाएँगे।

स्टेट बैंक की श्रिषिकृत पूँजी २० करोड़ रुपये हैं जो २० लाख श्रंशों में विभक्त हैं। इस समस्त पूँजी का ५५ प्रतिशत रिंजव बैंक के पास है तथा शेष ४५ प्रतिशत श्रन्य व्यक्तियों को दिया गया है जिसमें भूतपुर्व इम्गेरियल वेंक के श्रंशधारियों को प्राथमिकता दी गई है। रिजर्व वेंक के पास जो ५५ प्रतिशत श्रंग हैं उन पर जो लामांश मिलता है वह एक विकास कोप में जमा किया जाता है। इस कोप में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व वेंक भी विशेष भावों के लिये स्था जमा करते हैं। नवीन शालाएँ खोलने के कारण स्टेट वेंक को जो घाटा रहेगा वह इसी कोष से पूरा किया जायेगा। वे सब हा नियाँ तथा व्यय भी इस कोप से पूरे किये जा सकते हैं जिन की श्रमुसति केन्द्रीय सरकार रिजर्व वेंक के परामर्श से प्रदान कर दे।

स्टेट वेंड्स के कार्य—स्टेट वेंक श्राधिनियम के श्रांतर्गत स्टेट बैंक को निम्निलि-खित कार्य सौंपे गये हैं:—

- (१) निम्न लिखित जमानत पर नकद ठाख खोलना एवं ऋगा प्रदान करना ।
- (श्र) श्रवल सम्पत्ति को छोड़ कर स्कंध (mock) तथा वे प्रतिभूतियाँ जिनमें नियमानुसार दूस्ट धन विनियोग किया जा सकता है।
- (ब) स्थानीय सत्तात्रौँ द्वारा ऋथवा उनकी स्रोर से निर्गामत ऋखपत्र एवं । प्रतिभृतियाँ।
- (ए) केन्द्रीय समिति के आदेशानुसार भारतवर्ष या अन्य स्थानों में पंजीकृत सीमित दायित्व वाली कंपनियों के ऋण पत्र !
 - (द) माल तथा वे ऋषिकार प्रपत्र जो स्टेट वैंक के नाम कर दिये गये हैं।
- (ई) केन्द्रीय समिति की विशेष ऋनुमित से वे माल जो बैंक के पास गिरवीं रख दिये गये हैं।
- (फ) दो से अधिक व्यक्तियों एवं स्वतन्त्र साफेदारियों द्वारा लिखे प्रतिज्ञापत्र तथा बेचान की हुई स्वीकृत हुन्डिया ।
- (ज) उपरोक्त के ऋतिरिक्त, ऋतिरिक्त गिरवी के रूप में समिति दायित्व वाली कम्पनियों के अंशपत्र ऋथवा ऋचल सम्पत्ति ।
- (२) उन सभी वस्तुत्रों का बेचना जो स्टेट बैंक को जमानत एवं गिरवी के रूप में प्राप्त हुई हैं।
- (३) राज्य सरकार की अनुमित से कृषि कार्यों के लिये १५ मान तथा अन्य कार्यों के लिये ६ मास तक की कोर्ट आफ वार्ड स को उनकी सम्पत्ति की जमानत पर ऋष प्रदान करना।
- (४) हुन्डियों तथा ऋन्य विनिमय-साध्य विलेखों (Bills and other Negotiable instruments) ऋाहरित करना, स्वीकार करना, कटौती करना एवं क्रय-विक्रय करना।
 - (५) बैंक के धन को नं० १ में लिखी प्रतिभूतियों में विनियोगित करना।

- (६) साख पत्र लिखना, निर्गमित करना ऋथवा गश्तीरूप से मेजना।
- (७) सोने तथा चाँदी एवं उनके सिक्कों का क्रय-विक्रय करना।
- (८) जमा प्राप्त करना तथा खाते खोलना ।
- (६) बहुमूल्य वस्तुश्रों को सुरिच्चत रखना।
- (१०) उस समस्त चल एवं श्रचक सम्पत्ति का विक्रय करना जो ऋग् के भुगतान में बैङ्क को प्राप्त हो।
- (११) कमीशन लेकर एजेन्सी का कार्य करना तथा अपने माहकों के लिये जमानत देना।
- (१२) अपने ग्राहकों की आरे से उनकी सम्पत्ति की व्यवस्था करना तथा कमी-यन लेकर उनके लिये प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करना, उनके लाभांश एवं ब्याज को एकत्रित करना तथा हुन्ही एवं घन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना।
 - (१३) भारतवर्ष से बाहर देय हुन्डी आहरित करना ।
- (१४) कृषि वित्त के लिये १५ मास तथा अन्य कार्यों के लिये ६ मास तक की विदेशों में देय हुन्डियों का क्रय-विक्रय करना।
- (१५) ऋपनी ऋावश्यकता के लिये रुपया उधार लेना तथा उसके लिये ऋपनी सम्पत्ति गिरवीं रखना ।
 - (१६) इम्पीरियल बैङ्क के कर्मचारियों की पेंशन के लिये प्रबन्ध करना, तथा
- (१७) वे सभी कार्य करना, जो किसी भी बैङ्क के लिये आवश्यक हैं तथा विदेशी विनियम व्यापार में भाग लेना।

केन्द्रीय सरकार की विशेष श्रनुमित से स्टेट बैङ्क निम्नलिखित कार्य भी कर सकती है—

- (१) किसी भी बैङ्क को अथवा उसकी सम्पत्ति एवं दायित्वों का अथ करना।
- (२) किसी भी कम्पनी एवं सहकारी समिति को निस्तारण के हेतु किसी भी श्रविष तथा किसी वस्तु की जमानत पर ऋगुण प्रदान करना !
- (र्) रिजर्व बैंक की अनुमित से किसी भी बैंक के अंशों का क्रय-विकर करना।
 - (४) किरी भी सहायक वैंक की स्थापना करना एवं उसकी व्यवस्था करना।
- (५) यदि रिजर्व बैंक की प्रार्थना पर किसी बैंक का निस्तारण हो रहा है तो उसके लिये निस्तारक (Liquidator) का कार्य करना।

स्टेट वैंक के वर्जित कार्य—स्टेट वैंक अधिनियम के अन्तर्गत बैंक निम्न-लिखित कार्य नहीं कर सकती:— (१) बैंक ६ मास से ऋषिक के लिये ऋपने ऋंशों के ऋाधार पर ऋग प्रदान नहीं कर सकती।

(२) बैंक उन विनिमय हुन्डियों को नहीं सुना सकती श्रीर न उनकी सुरद्धा

.पर ऋगा प्रदान कर सकती है जिन पर एक ही व्यक्ति उत्तरदायी हो।

(३) किसी भी श्रवस्था में १५ मास से श्रधिक की कृषि हुन्हिया तथा ६ मास से श्रधिक की श्रन्य हुन्हियाँ नहीं भुना सकती।

(४) बैंक अपने भवन के अतिरिक्त कोई अन्य अचल सम्यत्ति कय नहीं कर

सकती।

स्टेट वेंक के कार्यों पर एक दृष्टि—बेंक का राष्ट्रीयकरण हुए अभी ४ वर्ष हुए हैं। अतः इसके कार्यों की आलोचना इतनी शीध नहीं की बा सकती। यह बात अवश्य है कि देश की सबसे बड़ी व्यापारिक बेंक होने के नाते यह अन्य बैंकों की सहायता करती है। जनता का इसमें पहले से अधिक विश्वास हो गया है, अतः इसकी जमा राशि में सतत बृद्धि हो रही है। इसका भविष्य बड़ा ही उज्बल है। यह आशा की जाती है कि देश की पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने में यह बैंक पूर्ण योग प्रदान करेगी, विशेषकर व्यक्तिगत औद्योगिक सेत्र में। इस बैंक से अब्छे कार्य की आशा इसलिये भी की जाती है कि प्रामीण सेत्रों में शाखाएँ खोल कर यह प्रामीणों की गड़ी हुई पूँची को प्राप्त करके देश के आर्थिक विकास में लगायेगी।

प्रश्न

Briefly explain the functions of State Bank of India.
 स्टेट बैंक के कार्यों की विवेचना कीजिये।

2. What was the position of the Imperial Bank of India before the creation of the Reserve Bank in India? In what ways has that position changed after the establishment of the Reserve Bank?

रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व इम्पीरियल बैंक ऋाफ इन्डिया की क्या स्थिति थी ! रिजर्व बैंक की स्थापना से इसमें क्या परिवर्तन हुऋ। है !

3. Examine the presesent position of the State Bank. What

restrictions have been placed on its activities?

इम्पीरियल बैंक की स्थापना क्यों श्रीर किस प्रकार हुई ? यह क्या कार्य कर सकती है श्रीर इसके किन कार्यों पर प्रतिबन्ध है ?

4. How, and why, was the Imperial Bank of India established? What business it can transact and which it is probibited to transact?

स्टेट बैंक की वर्तमान स्थिति की विवेचना की जिये । इसके किन कार्यों पर प्रतिबन्ध है !

5. What was the idea behind nationalisation of the State Bank of India? Has it justified nationalisation?

स्टेट बैंक के राष्ट्रीयकरण का क्या उद्देश्य था ? क्या इसके अच्छे परिणाम

ग्रध्याय ६

संयुक्त पूँजी वाली अथवा व्यापारिक बैंक

(Joint Stock or Commercial Banks)

देश की बैंकिंग व्यवस्था में संयुक्त पूँजीवाली बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये ही बैंक व्यापारिक वैंक के नाम से पुकारी जाती हैं। संयुक्त पूँजी वाली बैंक वह बैंक होती है जिसकी पूँजी श्रंशों में विभक्त होती है श्रीर जिन श्रंशों को बहुत से व्यक्ति कय कर लेते हैं। वे सभी बैंक जिनसे श्रिषकांश जनता परिचित है, संयुक्त पूँजीवाली बैंक ही हैं, उदाहरएत: पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक, जयपुर बैंक, कलकत्ता बैंक हती हैं, उदाहरएत: पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक, जयपुर बैंक, कलकत्ता बैंक हत्यादि॥ इन बैंकों के श्रंशधारियों का दायित्व सीमित होता है श्रीर इनका संगठन संचालन समितियाँ करती हैं। ये बैंक भारतीय कम्पनी श्रिष्ठिनयम के श्रन्तर्गत तो पंजीकृत होती ही हैं, इिएडयन बैंकिंग श्रिष्ठिनयम के श्रंतर्गत भी पंजीकृत होती ही हैं, इिएडयन बैंकिंग श्रिष्ठिनयम के श्रंतर्गत भी पंजीकृत होती हैं। रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये बिना कोई भी बैंक श्रपना सरोवार श्रारम्म नहीं कर सकती,। इन बैंकों पर रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण होता है। मारत वर्ष में ये बैंक्क निम्नलिखित कार्य करती हैं:

व्यापारिक वैद्धों के कार्य — इन बैंकों का मुख्य कार्य चालू, मुद्दती श्रीर जमाखाते श्राक्षित करना तथा थोड़े समय के लिये ऋण देना है। हुन्डियों को भुनाना
श्रथवा क्रय करना है (यद्यपि भारतीय बैंक यह कार्य करती है क्योंकि बिल बाजार का
उदय नहीं हुआ है।) सरकारी प्रतिभृतियों में श्रपना रुपया लगाना, नकद साल देना,
कृषि के उत्पादन को ग्राम से नियत बन्दरगाहों तक तथा बन्दरगाहों से विदेशों के
श्राये हुए माल को देश के भीतरी भागों तक पहुँचाने में श्राधिक सहायता देना है।
इसके श्रतिर्क्ति ये बैक्क श्रीर भी छोटे-मोटे कार्य करती हैं। उदगहरण के लिये रुपया
एक स्थान से दूसरे स्थान को मेजना इत्यादि। ये बैंक कृषि के धन्धे को सीधी श्राधिक
सहायता नहीं देतीं। वे केवल बड़े जमीदारों, चाय इत्यादि के बगीचों के स्वामियों
तथा ऐसे श्रन्य व्यक्तियों को ऋण्य देती हैं। पहले तो ये बैक्क मुद्दती जमा पर ४ से प्र
प्रतिशत श्रिक ब्याज देती थीं किन्तु श्रब्त श्रिक बेक्क चालू खाते पर भी ब्याज
नहीं देतीं श्रीर मुद्दती जमा पर भी २ प्रतिशत से श्रिषक ब्याज नहीं देतीं। बड़े-बड़े
श्रीचोगिक केन्द्रों में जहाँ प्रतिभृति श्रिषक मिलती है वहाँ बैक्क उनको जमानत पर

ऋष देती हैं। किन्तु जिन मंडियों तथा बाजारों में स्टाक बाजार की प्रतिभूति ऋषिक नहीं मिलती वहाँ कृषि के उत्पादन को ऋषिक रखकर यह बैंड्ड ऋष दे देती हैं।

भारतवर्ष में सार्वजिनक गोदाम नहीं है। इस कारण वैक्क अपने गोदाम ख़िती हैं जहाँ प्राहक का माल ख़कर उसकी जमानत पर उसे अप दे दिया जाता है। ऐसा भी होता है कि वैक्क प्राहक के गोदाम पर ही अधिकार कर लेती हैं और वहीं माल बन्द करके प्राहक को अप दे देती हैं। कारखानों को उसके तैयार माल के विरुद्ध अप दे देती हैं। कभी-कभी वैक्क इमारतों तथा अन्य स्थावर सम्पत्ति को गिरवीं ख़कर अप दे देती हैं। किन्तु इस प्रकार का अप अधिक नहीं दिया जाता। इसका कारण यह है कि इस प्रकार की सम्पत्ति शीध ही बेची नहीं जा सकती। वैक्क व्यक्तिगत जमानत पर भी अप दे देती हैं। ऐसी दशा में अपणी जो प्रामिस्थी नोट लिखता है उस पर दो अब्छे हस्ताचर लिये जाते हैं। सर्प तथा मैनेजिंग एजेंटों के हस्ताचर होने पर वैंक सरलता से अपण दे देती हैं। हुन्डी जो कि आज भी भारतीय बाजारों में प्रचलित है यद्यि पहले में उसका प्रचार कम है, वास्तव में दो हस्ताच्यों वाला पत्र है क्योंकि उससे देशी वैक्करों का बेचान होता है। किन्तु व्यापार की मात्रा को देखते हुए जितने दो हस्ताचर वाले पत्रों को यह वैंक्क स्वीकार करके व्याप्तियों को अपण अथवा साख देती हैं वे अपोक्ताकृत कम ही होते हैं।

ऋण देने का सब से अधिक प्रचलित ढंग यह है कि ऋगी वैद्ध को प्राप्तिस्री नोट लिख देता है और कम्पनियों के अंशा, माल अथवा बाँड अथवा अन्य कोई प्रतिभूति बैद्ध के पास जमानत के रूप में रख देता है, तथा बैद्ध उस ऋणी के नाम नकद साख खाता खोल देती है। यह ढंग दोनों पद्धों के लिए मृतिशादनक है। ऋणी जितना रूपया वास्तव में निकालता है उस पर ही उसे ब्याज देनी पड़ती है। फिर उसे यह भी सुविधा रहती है कि वह जब भी चाहे तब उस खाते में रूपया जमा कर दे अर्थात् कुछ, ऋण चुका दे। किन्तु ऋणी को जितनी नकद साख दी गई है उसकी आधी रकम पर अवश्य ब्याज देनी होगी। ऋण देने का यह ढंग भारतवर्ष में हुन्डी बाजार को विकसित नहीं होने देता, किन्तु यह अधिक पचलित है क्योंकि बैंक और व्यापारी दोनों ही इसे अधिक पसन्द करते हैं। वैद्ध को सुविधा यह है कि वह जब चाहे तो नकद साख की इस सुविधा को वापस ले सकती है अर्थात् ऋणी को अधिक ऋण अथवा साख देना अस्वीकार कर सकती है और ऋण लेने वाले को यह सुविधा होती है कि उसे निश्चित रकम पर ही ब्याज देनी पड़ती है।

यह बैङ्क ऋषिकतर देश के भीतरी व्यापार के लिये ऋल्पकालीन साख का प्रबन्ध करती हैं। विदेशी व्यापार, उद्योग-धन्घों तथा कृषि को ये बहुत कम साख देती है। पिछले कुछ वर्षों से भारत की कुछ, बड़ी बैंकों ने विदेशी विनिमय का कारबार करना प्रारम्भ कर दिया है, परन्तु अभी तक यह नहीं के बराबर है। उद्योग-घन्धों को यह बैङ्क थोड़ समय के लिये स्थायी पूँजी के रूप में सहायता देती हैं। अधिक समय के लिये स्थायी पूँजी के रूप में सहायता देती हैं। अधिक समय के लिये स्थायी पूँजी के रूप में यह बैंक उद्योग-घन्धों को सहायता नहीं देतीं। भारतीय बैंकों की कार्य पद्धति की एक विशेषता यह है कि वे हुन्डियों की अपेचा सरकारी प्रतिम्तियों में अपना समय अधिक लगाती हैं। इसका कारण यह है कि देश में व्यापारी हुन्डियों तथा बैंकों के स्वीकार योग्य पत्रों का अभाव है। अस्तु, बैङ्क अपना अधिकतर रूपया सरकारी प्रतिभृतियों में लगाती हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय बैङ्क और भी सहायक बैंकिंग का कार्य करती हैं। उदाहरण के लिये वे अपने प्राहकों को अर्थ सम्बन्धी परामर्श देती हैं, उन्हें न्यापार सम्बन्धी जानकारी कराती हैं। उनके लिये सरकारी प्रतिभूतियों तथा कम्पनियों के अंश क्रय-विक्रय करती हैं और उनके एवज में रुपया चुकाती हैं और प्राप्त करती हैं। उनके एजेंट अथवा प्रतिनिधि का कार्य करती हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त वे यात्रियों की सुविधा के लिये साख पत्र (Letter of Credit) देती हैं। रुपये को दूसरे स्थान पर भेजने के लिये बैङ्क ड्राफ्ट देती हैं तथा सरकार, कम्पनियों, नगरपालिकाओं तथा निगमों द्वारा निकाले हुए ऋग्ण वा अभिगोपन (underwriting) करती हैं। वे अपने ग्राहकों की सम्बन्ध में अन्य न्यापारियों को अपनी सम्मति देती हैं। वे अपने ग्राहकों की मृल्यवान वस्तुओं को सुरिक्ति रखती हैं।

भारतीय सिम्मिलित पूँजी वाली बैंकों के दोष तथा कठिनाइयाँ—भारत-वर्ष में संयुक्त पूँजी वाली बैंक पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाई हैं। क्योंकि ये बैंक कुछ कठिनाइयाँ अनुभव करती हैं जो निम्नलिखित हैं—

- (१) भारतीय पूँजी वाली बैंकों को अभी सरकार से प्रोत्साहन नहीं मिला है। नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों, वन्दरगाह ट्रस्ट, कोर्ट आफ वार्ड स इत्यादि ट्रस्टों का रूपया उनमें नहीं रखा जाता यद्यपि अब धीरे-धीरे स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। १९६५ के पूर्व देश में कोई बैंक न होने के कारण उन्हें कठिनाई के समय ठीक नेतृत्व तथा सहानता नहीं मिलती थी और न उनसे पारस्परिक सहयोग ही स्थापित हो पाता था।
- (२) विदेशी विनिमय वैंकों तथा स्टेट बैंक की प्रतिस्पर्धा तथा पारस्परिक सह-योग श्रीर सहानुभृति का श्रभाव भी उनकी उन्नति के मार्ग में एक रुकावट है। उनका यह भी विचार है कि मांवष्य में महकारी बैंक भी उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगी। बहाँ तक इन बैंकों का ऐक्सचेंज बैंकों तथा स्टेट बैंक की प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है यह बतलाया जा चुका है। जहाँ तक उनमें श्रापस में तथा मुद्रा बाजार के श्रन्य सदस्यों

में सहयोग तथा सद्भावना उत्पन्न करने का प्रश्न है उनके लिए ऋखिल भारतीय वैंकर्ष संघ की स्थापना की ऋावश्यकता है।

- (३) ऋभी तक बहुत से उद्योग-घन्चे तथा भारतीय व्यापार विदेशियों के हाथ • में हैं श्लीर वे स्वभावतः ऋपने देश के बैंकों को प्रोत्साहन देते हैं। इस कारण भार-तीय बैंकों की उन्नति तेन्नी से नहीं हुई। किन्तु ऋन भारत स्वतन्त्र हो गया है श्लीर ऋन यह कठिनाई कमशः दूर हो जायेगी।
- (४) यही नहीं कि विदेशी व्यवसायी तथा विदेशी व्यापारिक फर्में अपने देश के वैंकों से अपना कारबार चलाती है वरन् बो मारतीय व्यापारी इनके एजेंट का कार्य करते हैं अथवा जिनका विदेशी बीमा कम्पनियों तथा विदेशी जहाज कम्पनियों से कारबार होता है उनको भी ये विदेशी फर्में और कम्पनियाँ विदेशी विनिमय वैंकों से कारबार करने पर विवश कर देती हैं।
- (५) विछत्ते वैंक संकटों के कारण जो वैंक दूव गई उन में वैंकों की स्थानना में कठिनाई होती थी। लोग वैंकों में उनया जमा नहीं करते थे। किन्तु अब यह कठिनाई दूर हो गई है। विछने वर्षों में वैंकों की संस्थातथा डिपाजिट में जैसी स्वरित वृद्धि हुई है उमे देखते हुए यह कहना पड़ेगा कि वैंकों के विरुद्ध अब विश्वास जाता रहा है।
- (६) भारत की उन्नति न होने के कारण भारतीय वैंकों की उन्नति रुकी रही। स्थरत भारत की स्थर्थिक उन्नति के साथ-साथ भारत में वैंकिंग कारवार का विकास होना तथा जनता में वैंकिंग की स्थादत बढ़ाना स्थिनवार्य है जो स्थानी तक कम है।
- (७) इसके श्रितिरिक्त वैक्क को कुछ अन्य किटनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हिन्दू तथा मुसलमानों के पैनृक सम्पत्ति के उत्तरा- विकार सम्बन्धी कान्त ऐसे उन्नमें हुए हैं कि इस प्रकार की सम्पत्ति की जमानत पर बैंक अध्या देती है। थोड़े समय के लिये अध्या देने के लिये सबसे अच्छा ढंग यह है कि व्या- पारी अपनी सम्पत्ति के प्रलेख (Documents) बैंक के पास बिना बन्धक पत्र (Morregage Deeds) लिखे और उनका पंजीयन कराके रख दें और उन प्रजेखों का बैक्क के पास जमा करा देना ही बन्धक मान लिया जाये। किन्तु भारत सेंभ्यह मुविधा केवल बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास नगरों में ही दी गई है। अन्य स्थानों में यह सुविधा बैंकों को प्राप्त नहीं है।
- (=) व्यापारिक वैंक इस आशा से सरकारी प्रतिभृतियों में अपना रूपया लगाती हैं कि संकट काल में सरकारी प्रतिभृतियाँ शीव ही मुनायी जा सकती हैं। किन्तु कमी-कभी कठिनाई पड़ जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि बैक्क स्टेट बैक्क से सरकारी प्रतिभृतियों की जमानत पर ऋण प्राप्त न कर सके। अभी हाल में रिजर्व

बैङ्क ने भी इसी आशाय की घोषणा की है कि यदि किसी बैङ्क की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो यह आवश्यक नहीं है कि सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर उसे भ्राण दे दिया जायेगा।

- (६) भारत में श्रिधिक संख्या में बहुत सी ऐसी बैंक हैं जिनके पास श्रपनी निज की यथेष्ट पूँजी नहीं है। इस कारण उन्हें कठिनाई पड़ती है। वे जमा श्रिषिक श्राकिष्ठित करने के लिये ज्याज श्रिषिक देती हैं श्रीर इस कारण उन्हें श्रपना घन जीखिम के कारबार में लगाना पड़ता हैं। तभी वे श्रिधिक ज्याज कमा सकती हैं। जमा श्राकिष्ठित करने के लिये ये छोटी बैंक दूर-दूर श्रन्य प्रांतों में शाखायें स्थापित करती हैं। इस कारण उनकी देखभाल श्रीर व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पाती श्रीर उन्हें बड़ी बैंकों की प्रतिस्पर्धा को सहन करना पड़ता है। इस प्रकार की बैंक्क स्वभावतः निर्वल होती हैं श्रीर संकट के समय नहीं टहर सकतीं।
- (१०) इसके ऋतिरिक्त बहुत सी बैड्डों के संचालक योग्य ऋौर ऋनुभवी नहीं हैं ऋौर योग्य कर्मचारियों की कमी है। यही नहीं, नवीन बैड्डों को समाशोधन गृह का सदस्य बनने में बड़ी कांठनाई होती है। समाशोधन गृहों पर विदेशी बैड्डों का बहुत प्रभाव है। ऋौर वे नवीन बैड्डों को उसका सदस्य बनने देना नहीं चाहतीं। किन्तु ऋब यह कठिनाई क्रमशः दूर हो जायेगी।
- (११) मारत की सभी बैङ्क अंग्रेजी में अपना कारबार करती हैं। उनके चेक, रसीदें तथा हिसाब सभी अंग्रेजी में होते हैं। केवल कुछ बैङ्क ही ऐसी हैं जो हिन्दी में लिखे गये चेकों को तथा हिन्दी में किये हस्ताचरों को स्वीकृत करती हैं। भागत में व्यापारियों तथा जनता का एक बहुत बड़ा भाग अंग्रेजी नहीं जानता। भारतवर्ष की स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत अंग्रेजी का महत्व अब घटता जा रहा है, अतएव अब बैङ्कों को अपना कारबार हिन्दी अथवा प्रान्तीय भाषा में करना चाहिये।
- (१२) भारतीय बैङ्कों के सामने एक कठिनाई यह है कि यहाँ हुिएडयों तथा ऐसे पत्रों की बहुत कमी है जिन्हें बैङ्क स्वीकार कर सकें। इस कारण बैङ्कों को वितश होकर अपना अधिकांश कोष सरकारी प्रतिभृतियों में लगाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारते में निना किसी सम्पत्ति की जमानत पर अथवा दूसरे हस्ताच्चर लिये हुए ब्यक्तिगत साख पर अध्या देने की परिपाटी नहीं है जब कि अन्य देशों में यह बहुत प्रचलित है। और अधिकांश अध्या इसी प्रकार दिये जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि पिरचमी देशों में एक व्यक्ति एक बैङ्क का चलन है। अर्थात् एक व्यक्ति अपना सारा कारबार केवल एक बैङ्क से हिंग करता है। दूसरा कारण, प्रवन्ध अभिकर्ती हैं। बैङ्क जब किसी कंपनी को अध्या देते हैं तो वे जानते हैं कि कंपनी के वास्तिविक कर्त्ता-वर्ता मैनेजिंग एजेंट ही हैं। एक तीसरा कारण यह भी है कि अभी तक

इस देश में ऐसी व्यापारिक एजेंसियाँ नहीं हैं जो व्यक्तियों की माख के संबंध में बैक्कों को सारी जानकारी दे सकें।

- (१३) भारतीय वैद्धों ने ऋभी तक भारतवर्ष के परिस्थित के अनुसार ऋपने संगठन को नहीं बनाया। वे एक्सचेंज वैद्धों तथ स्टेट वैद्ध की नकल मात्र करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रबन्ध व्यय ऋषिक होता है, फिर भी उनके कर्मचारियों में न तो वह कुशलता है और न वह योग्यता। भारतीय बैद्धों ने न तो विदेशी एजेट वैद्धों की कुशलता ही प्राप्त की है न देशी वैद्धां की सादगी और मितव्ययता ही वे ऋपना सके। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय वैद्ध भारत के अनुकृत वैकिंग सगठन की नवीन पढ़ित निकाल जिसमें कम व्यय हो, क्योंकि भारत में ऐसे स्थान बहुत हैं जहाँ इतना काग्यार आरंभ में तो नहीं मिल सकता कि एक आयुनिक शाखा का व्यय निकल सके। फिर भी यहाँ वैकिंग की मुविधा की आवश्यकता है।
- (१४) बहुषा मारतीय वैङ्कों पर दोप लगाया जाता है कि वे अपनी वास्तविक लाम का बहुत बड़ा अंश अंशधारियों को इसलिये देती हैं कि जिनसे जनता में उनके प्रति विश्वास बना रहे, क्योंकि भारतीय जनता की यह धारणा है कि जो बैङ्क अधिक लाम बाँटती है वह उतनी ही अच्छी हैं। जहाँ तक बड़ी और पुरानी बैङ्कों का सबंध है यह आरोप निराधार है किन्तु छोटी बैकें यह करती हैं और इसका मुख्य कारण भारतीय जनता की उक्त अमपूर्ण धारणा है।

व्यापारिक वैङ्कों में रिजर्व वैङ्क ने निम्नालिखित दोप ऋतुभव किये हैं-

- (१) बैंकों के अधिकांश संचालक बैंक के व्यवसाय का पूर्ण ज्ञान नहीं रखते और न वे इतने अनुभवी होते हैं कि वैङ्क के अधिकारियों के कार्यों वर पूर्ण नियंत्रण रख सके। फलस्वरूप ये अधिकारीगण अनुगा प्रदान करने तथा बैंक का रुग्या विनियोगित करने में मनमानी करते हैं। बहुत से बैंकों की आन्तरिक अंकेच्चण व्यवस्था एवं रोक-थाम भी दोषपूर्ण है। अतः बहुत सी बैंक इवत अनुगा, विनियोग की घटोतरी इत्यादि का प्रवंध किये विना लाभांश घोषित कर देते हैं।
- (२) श्रविवेकपूर्ण विनियोग नीति श्रिवकांश वैंक उन कंपनियों के श्रंशों में स्पया विनियोगित करती हैं जिनमें संचालकों का हित है। ऐसे श्रंशों को शीव्रतम नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सरकारी प्रतिभृतियों में बहुत कम स्पया विनियोगित होता है।
- (३) ऋगा रेने की अनुचित नीति—बहुत-सी बैंक अपने साधनों से भी अधिक ऋग प्रदान कर देती हैं। अधिकांश ऋग ऐसे होते हैं जिनके लिये कुछ

सुरचा नहीं ली जाती। ऋण लेने वाले व्यक्ति ऋथवा फर्म की ऋार्थिक स्थिति की पूर्ण जाँच किये बिना ही ऋण दे दिया जाता है।

(४) शाखात्रों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं — कुछ बैंक स्त्रविवेकपूर्ण शाखारें स्थापित कर देती हैं। इन शाखात्रों पर प्रधान कार्यालय पूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाता। इन शाखात्रों से प्रधान कार्यालय में नियमानुसार सूचनायें एवं सूचियाँ प्राप्त नहीं होतीं त्रीर जो होती भी हैं तो उनकी गंभीरता से जाँच नहीं की जाती।

दोषों को दूर करने के सु-माव - भारतीय व्यापारिक बैंकों की कठिनाइयाँ तथा दोषों को दूर करने के लिये निम्नलिखित सुभाव दिये जाते हैं:—

- (१) प्रत्येक विदेशी विनिमय का कार्यचेत्र निश्चित हो बाना चाहिये; जिससे वह अन्य बैंक से प्रतियोगिता न कर पाये और देश की बैंकिंग प्रणाली की उन्नति में वाधक न हो।
- (२) सरकार को भी ऋपनी नीति में परिवर्तन करना आवश्यक है। उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे बैंकों के प्रति जनता का विश्वास दृढ़ हो जाये। इस विश्वास को अटल बनाने के लिये कुछ बैंकों को नगरपालिका, पोर्टट्रस्ट, जिला बोर्ड, तथा शिच्च्य आदि संस्थाओं के कोष जमा करने की आवश्यकता है।
- (३) भारत सरकार को सहकारी बैंकों की भाँति उन व्यापारिक बैंकों को, जो आभों में अर्थ व्यवस्था का प्रबंध करती हैं, करों में सुविधा देकर इनके लेन देन का संबंध स्थापित करके तथा अन्य सुविधायें देकर प्रोतसाहन देना चाहिये।
- (४) रिजर्व बैङ्क का भी भारी उत्तरदायित्व है। उसको भी श्रपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। सर्व प्रथम उसको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि देशी बैङ्क स्थानीय बैङ्कों में परिवर्तित कर दिये जाँय जिससे उनकी प्रतियोगिता से व्यापारिक वैंकों को श्राघात न पहुँचे। इतना ही नहीं, किन्तु उसको देश की छोटी-छोटी व्यापारिक वैंकों का एकीकरण कर देना चाहिये जिससे उनकी पारस्परिक प्रतियोगिता समाप्त हो जाये। इसके श्रातिरिक्त देश में समाशोधन ग्रहों के बढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिये।
- (५) ग्रीमीर्गों की ऋग् संबंधी आवश्यकतायें आज भी महाजनों द्वारा पूरी होती हैं। उनकी बचत का भी सदुपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि ग्रामों में बैंकिंग सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। रिजर्व बैंक की संरच्चकता में इन बैंकों को बड़ी-बड़ी व्यापारिक वैंकों के ऋतिरिक्त उन ग्रामों में जहाँ कच्चा माल एकत्रित होता है अपनी शाखायें खोलनी चाहिये। इस संबंध में रिजर्व बैंक्क को रुपया भेजने ऋौर मँगाने तथा कृषि हुिएडयों की पुनर्कटौती करने की सुविधायें प्रदान करनी चाहिये।
 - (६) भारतवर्ष में आँकड़ों का बहुत श्रभाव है, जिसके कारण आर्थिक श्रीर

वैंकिंग स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता श्रीर वैंकों को भी नवीन शासायें खोलने में श्रीर श्रपनी सास नीति निर्धारित करने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने श्रीर वैंकिंग विकास को पर्याप्त सहायता देने के लिये विश्वसनीय श्राँकड़ों का मिलना परमावश्यक है। यह केवल उसी समय संभव हो सकता है जब कि कुछ वैंक श्रापस में मिलकर श्रयवा श्रस्तिल भारतीय वैंक संब की श्रोर एक श्रांकड़ा विभाग, समाचार विभाग, श्रनुशीलन विभाग (Research Department) श्रीर एक प्रचार विभाग स्थापित कर दें।

- (७) वैंकों को अपनी कार्यविधि में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिये; जिससे अशिक्ति व्यक्तियों को भी वैंकों का प्रयोग करने में किटनाई न हो। भारतीय वैंकों को जनता की सुविधा का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये। वैंक का कार्य काल ऐसा होना चाहिये जो व्याप्तियों, उद्योगपतियों तथा अन्य साधारण आहकों के लिये सुविधा-जनक हो। वैंकों की आमशाखाओं का कार्य-समय क्रप्रकों की सुविधाओं को ध्यान में रख कर निश्चित करना चाहिये। भारतीय वैंकों के कृषि, व्यापार तथा अर्थ हुन्हियों के प्रयोग में अधिकाधिक सहायता देनी चाहिये। इन्हें व्यक्तिगत साख पर उधार देने की नीति को जहाँ तक हो सके प्रोत्साहित करना चाहिये। इन्हें अपनी जनता में चेक द्वारा ही अपने लेन-देन को करने की भावना भरना चाहिये। इन्हें अपनी ज्याज दरें भी अपने प्रतिद्विद्यों को कुचलने की इच्छा से चाहें जब घटाना-बढ़ाना नहीं चाहिये।
- (二) भारतीय बैंकों को नवीन, योग्य, अनुभवी, कार्यकुशल तथा विश्वस्त कर्मचारी नियुक्त करना चाहिये। जहाँ तक हो सके ऐसे व्यक्तियों को रखा जाना चाहिये जो भारतीय वैंकिंग प्रणाली के अभावों तथा विशेपताओं से पूर्ण रूप से परिचित हों। पुराने योग्य तथा अनुभवी कर्मचारियों को भी भारी प्रोत्साहन देना चाहिये। इस संबंध में स्वदेशी वैंकरों से अधिक सहायता मिल सकती है। क्योंकि वे भारत की प्राचीन वैंकिंग पद्धित से पूर्णतया परिचित हैं। भारत में अभी तक आधुनिक वैंकिंग की उच्च शिद्धा का भी उचित प्रवंध नहीं है। इस संबंध में उन्हें पूरा ध्यान देना चाहिये।
- (६) श्रिष्ठकांश भारतीय व्यापारिक वैंक विदेशी वैंकों की नकल करती हैं जिससे उनका व्यय बढ़ जाता है। श्रितः वैंकों को श्रपने कार्य में बहुत मितव्ययता से काम लेना चाहिये। इन्हें श्रंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी तथा श्रन्य प्रान्तीय भाषाश्रों में कार्य करना चाहिये। श्राधुनिक यंत्रों द्वारा हिसाब, जोड़, बाकी इत्यादि को श्रीर भी श्रिष्क सरल बनाना चाहिये। इन्हें स्वदेशी वैंकरों तथा विदेशी वैंकों से श्रपना संपर्क बढ़ाकर श्रीर उनसे सहयोग करके मितव्ययता श्रीर कार्यकुशलता सीखनी चाहिये।

- (१०) भारत में इंगलैंड की खियेड्स (Syeds) तथा अमेरिका की ब्रेड स्ट्रीट (Brad street) तथा दून (Dun's) जैसी संस्थायें स्थापित की जानी चाहिये। ये संस्थायें संभावी ब्राहक के चरित्र, आर्थिक स्थिति, व्यापक लेन-देन आदि के संबंध में वैंक को ठीक-ठीक सूचना देकर उन दोनों का संबंध स्थापित करने में समर्थ होती हैं। भारत में जहाँ तक संभव हो सके "एक व्यक्ति एक बैंक" के सिद्धान्त का पालन होना चाहिये।
- (११) बैंकों की श्रपनी प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिये एक श्रांखल भारतीय बैंकिंग संघ की स्थापना होनी चाहिये श्रीर इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि वह देश के भिन्न-भिन्न भागों में श्राण लेने वालों की साख के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। प्रत्येक वैङ्क को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि उनमें पारस्परिक सहयोग रहे श्रीर यह कार्य संघ द्वारा ही किया जा सकता है। यदि सघ को इस बात का श्रमुभव हो कि एक वैङ्क गलत श्रफ्वाहें उड़ाती है तो वह उस वैङ्क के विरुद्ध कार्यवाही करे श्रीर उसे उपयुक्त दंड दे। यही नहीं, किन्तु संघ के श्रमुरोध पर रिजर्व वैंक को चाहिये कि बंक श्रीर जनता दोनों ही के हित में कुछ विशेष उपयोगी कार्य करने के लिये प्रोत्साहन दे। श्रापसी प्रतियोगिता को समाप्त कर के छोटी-छोटी बैंकों का एकीकरण श्रावश्यक है। श्रतः रिजर्व बैंक को चाहिये कि वैंकों के एकीकरण के लिये श्रावश्यक कार्यवाही करे।

वेंकों का एकीकरण — जब दो अथवा दो से अधिक वैङ्क आपस में प्रतिस्पर्दी करती हैं तो इनका निजी अस्तित्व समाप्त करके सामूहिक रूप में एक स्वतंत्र वैङ्क स्थापित करना अथवा छोटी वैङ्क का बड़ी वैङ्क में विलयन करना एकीकरण कहलाता है। आजकल अनेकों व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थाओं का एकीकरण किया जा रहा है जिससे वहत् उद्योग के संगठन के लाभ प्राप्त किये जा सकें। यदि छोटी-छोटी वैङ्क भी अपना एकीकरण करके एक वहत् वैङ्क स्थापित कर लें तो इससे न केवल वैकों में वरन जन साधारण की भी भलाई होगी।

एकीकरण के लाभ—विलीनीकरण से पारस्परिक हानिकारक प्रतियोगिता का श्रन्त हैं। प्रवन्ध की कार्यक्रमता बढ़ जाती है। सुयोग्य तथा श्रमुमबी कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त हो जाती हैं। वृहत् उद्योगों के सभी लाभ प्राप्त करने में भी यह क्रिया सहायक होती है तथा इस किया से केन्द्रीय बैक्क की निरीक्षण तथा नियंत्रण द्यमता बढ़ जाती है जिससे मुद्रा बाजार में समानता श्रीर स्थिरता श्रा जाती है श्रीर बैंकिंग व्यवसाय की द्यमता बढ़ती है।

हानियाँ—विलीनीकरण से एकांधिकार के सभी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इससे ऋधिक शक्ति थोड़े से व्यक्तियों के पास केन्द्रित हो जाती है जिससे वे दुरुपगयो करके जनता का शोषण कर सकते हैं। इससे व्यवसाय का चेत्र बहुत छोटा हो जाता है त्रीर कर्मचारियों की छँटनी होती है जिससे वेकारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऋषिक शक्ति के केन्द्रित हो जाने से बहुधा बैंक्ट सट्टे का व्यापार ऋषम्म कर देती है जिससे अध्याचार बढ़ता है।

भारत में बेंकों का एकीकरण-दितीय महायुद्ध काल में उद्योग तथा व्यापार में बृद्धि हो बाने से अनेकों नवीन बैद्ध स्थापित हुई और उनकी शास्तायें बड़ी संख्या में खुल गई; प्रतिस्पद्धां के उद्देश्य से बहुत सी बैड्डों ने ऐसे स्थान पर भी शाखाएँ खोलीं बहाँ पर विशेष आवश्यकता न थी। नवीन वैद्वीं ने अधिक वेतन का अनोभन देकर पुरानी वैङ्कों के कर्मचारियों को अपने यहाँ नियुक्त किया जिससे पुरानी वैङ्कों की कार्यसमता कम हो गई श्रीर नवीन वैद्वीं का व्यय बढ़ गया। इतना होने पर भी वैद्वीं ने युद्ध काल में भारी लाभ प्राप्त किया । किन्तु युद्ध समाप्त हो बाने पर व्यवसाय तथा व्यापार में कभी ऋाई । नवीन वैद्धों को ऋपना व्यय पुरा करना कठिन हो गया तथा उन्हें घाटा रहने लगा जिससे बहुत सी शाखाएँ बन्द करनी पड़ी, कुछ बैड्डो का दूसरी वैङ्कों से एकीकरण हुआ। इससे पारस्परिक प्रतियोगिता समाप्त हो गई और कार्यच्मता में वृद्धि हुई। ऋतः वैंकिंग कम्पनी ऋधिनियम में विधान द्वारा एकीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। तीन वैंकों का एकीकरण करके यूनाइटेड वैक्क स्राफ इंडिया की स्थापना की गई । १६५१ में डालिनया के भारत बैक्क का पंजाब नेशनल बैक्क से एकी-करण हुन्ना। इससे दोनों वैङ्कों की प्रतिस्पर्का समाप्त हो गई श्रीर पंजाब नेशनल बैङ्क में भारत बैक्क के कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति से बैक्क की कार्यच्नता में वृद्धि हुई। भूत-पूर्व देशी रियासतों में जो रियासती बैंड्स थीं जैसे जवपुर बैंड्स, बीकानेर बैंड्स इत्यादि उनका स्टैट बैक्क स्राफ इंडिया से एकीकरण की योजना बनाई गई है और यह स्नाशा है कि यह योजना शीव ही कार्यान्त्रित की जायगी।

भारत की ४ बड़ी व्यापारिक बैंक — यों तो भारतवर्ष में अनुमूचित वैङ्कों के अतिरिक्त ६० अनुसूचित वैङ्के हैं, िकन्तु इनमें से हलाहाबाद वैंक लिमिटेड, वैङ्क आफ इंडिया लिमिटेड, वैङ्क आफ बड़ौदा लिमिटेड, सेन्ट्रल वैङ्क आफ इंडिया लिमिटेड तथा पंजाब नेशनल वैङ्क लिमिटेड ही सबसे शिक्तशाली वैङ्क हैं और इसीलिये ये "पाँच बड़ों" के नाम से पुकारे जाते हैं। अतः इन वैङ्कों का कुछ,-कुछ विवरण देना वांछनीय है:—

(१) इलाहाबाद बैंक लिमिटेड—यह भारत की सबसे प्राचीन व्यापारिक बैंक्क है। इसकी स्थापना १८६५ में १, ६०,००० रुपये की पूँजी से इलाहाबाद में हुई। सन् १६०० में इसकी पूँजी १० लाख तथा जमा राशि २ करोड़ हो गई। इस बैक्क ने ऋपना विकास बड़ी सावधानी से किया। १६३८ में इस बैक्क की ५६ शाखाएँ थीं जो अधिकतर उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में ही स्थित थीं। १६२२ में यह बैक्क पी० एएड आ० बैक्किक्क कार्पोरेशन से संलग्न हुई और १६२७ में चार्टड बैक्क आफ आस्ट्रेलिया ऐएड चाइना ने इलाहाबाद बैक्क को अपने अधीन कर लिया, क्योंकि चार्टड बैक्क आफ इंडिया, ऐएड चाइना बैक्किक्क कार्पोरेशन की सबसे बड़ी आंधारी थी। इस प्रकार इलाहाबाद बैक्क लिमिटेड पर योरोप वालों का ही पूर्ण आधिपत्य है। कुछ अर्थशास्त्री तो इसी कारण इलाहाबाद बैक्क को विदेशी बैक्क कहते हैं।

- (२) बैंक आफ इरिडया लिमिटेड-बैङ्क आफ इरिडया की स्थापना ५० लाख रुपये की पूँची से १६०६ में बम्बई में स्वदेशी ब्रांदोलन के समय में हुई। प्रारम्म से ही इस बैंड्र को भारत के बैंड्रिंग स्नेत्र में सबसे ऋषिक ख्याति प्राप्त करने का सौभाग्य रहा है। इस बैङ्क ने इंगलिश बैङ्किंग नीति को अपनाया और सदैव ही अनुदार एवं सावधानीपूर्ण नीति का ऋनुसरण किया। यद्यपि इसकी पूँजी, कोष एवं जमाराशि ५ करोड़ से ऊपर हो गई थी फिर भी १६३७ तक इस बैड्ड ने कोई शाखा नहीं खोली । १६३८ में भी इसकी कुल १६ शाखाएँ थीं। द्वितीय महायुद्ध काल में इस बैद्ध ने बड़ी प्रगति की श्रीर इसकी जमाराशि ७० करोड़ हो गई। भारतीय विदेशी व्यापार को श्रार्थिक सहायता प्रदान करने के हेतु सबसे पहली यही भारतीय बैंक थी जिसने लन्दन में अपनी शाखा स्थापित की। इस प्रकार बैंक अपनी अनुदार नीति त्याग कर अपने व्यवसाय का विकास करने लगी। प्रारम्भ में यह बैंक अचल सम्मत्ति एवं कम्पनी के श्रंशपत्रों की जमानत पर कोई ऋण नहीं देती थी। किन्तु १६११ में इसने इस नीति का त्याग किया श्रीर अब तो ये अंश पत्रों पर ऋण प्रदान करने लगी है। इस बैड्र की ३ विशेषताएँ हैं: (१) कम शाखाएँ, (२) श्रीद्योगिक केन्द्रों में ही व्यवसाय करना तथा (३) अधिक नकद कोष रखना। इसी कारण अपन्य बैंकों की अपेद्धा बैंक आफ इंडिया का व्यय ऋनुपात बहुत कम है।
- (३) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया लिमिटेड—सर सोराब जी पोचलान वाला के प्रयत्नों से १६११ में इस बैंक की स्थापना हुई । यह बैंक भारत की सबसे बड़ी एवं शिक्तशाली बैंक है । सर सोराब जी की देख-रेल में इस बैंक ने बड़े-बड़े संकटों का सामना किया । १६२३ में टाटा इन्डस्ट्रिल बैंक का इस बैंक से एकीकरण हुआ । फलस्वरूप इसकी पूँजी एवं कोष एकदम ८० लाख से बढ़कर २ करोड़ ६८ लाख तथा जमाराशि १४ करोड़ से १८ करोड़ हो गई । इस बैंक ने अपने व्यवसाय का लूक विकास किया और आज इसकी शाखाएँ भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में ३०० से अधिक हैं। इस बैंक की लन्दन में भी एक शाखा थी जो १६३४ में समाप्त हो गई । स बैंक का सम्पूर्ण प्रवन्ध सुयोग्य पारिसयों के हाथों में है और यह बैंक व्यापारियों की बड़ी सेना कर रही हैं।

- (४) बैंक श्राफ बड़ौदा लिमिटेड—यह बैंक बड़ौदा महाराज की संरक्षकता में १६०६ में स्थापित हुई। प्रथम महायुद्ध में इसकी बमाराशि १ करोड़ थी। सन् १६२० में यह ५ करोड़ से भी श्रिषिक हो गई। इस बैंक की ३५ शाखाएँ हैं जो श्रिषिकतर गुजरात तथा कठियावाड़ में स्थित है। भूतकाल में इस बैंक ने श्रपनी विकास नीति बहुत घीमी रक्खी। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत इसने श्रपनी शाखाओं की सख्या में वृद्धि की श्रीर श्रव इसकी गिनती पाँच बड़ों में होने लगी है।
- (४) पंजाब नेशनल वैंक लिमिटेड—सन् १८६६ में ४१,००० स्पये की पूँजी से यह बैंक पंजाब में स्थापित हुई । १९२० में स्वदेशी आन्दोलन के बल पकड़ जाने पर इसकी पूँजी १५ लाल तथा जमाराशि १ करोड़ से ऋधिक हो गई। १६१४ में इसकी जमाराशि १ करोड़ ४७ लाख से घटकर ७७ लाख रह गई किन्तु वैंक ने योग्यता के साथ इस संकट को पार किया और १६१६ में इसकी बमाराशि फिर १ करोड़ हो गई। १६४० में पंजाब नेशनल बैंक ने भगवानदास बैंक लिमिटेड को अपने में मिला लिया । भारत विभाजन का जितना बुरा प्रभाव पजाब नेशनल वैंक पर पड़ा उतना किसी ऋन्य बैंक पर नहीं । इसके व्यापार का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में था जो इसे बन्द करना पड़ा। पाकिस्तान से ऋाये शरणार्थियों की जमार्गाश का भुगतान इसने भारत में किया किन्तु लाला योघराच भल्ला जो भारत के सर्वोत्तम एवं अनुभवी वैंक व्यवस्थापक हैं उनकी देख-रेख में पंजाब नेशनल वैंक इस सकट की पार कर गई श्रीर कुछ दिन पश्चात् ही डालमिया की भारत बैंक लिमिटेड का पंजाब नेशनल बैंक से एकीकरण हुन्ना। भारत वैंक की समस्त देनदारियाँ पंजाब नेशनल वैंक ने ऋपने जपर लीं श्रीर भारत बैंक के कर्मचारियों को श्रपने यहाँ नियुक्त किया। भारत बैंक के एकीकरण से पंत्राव नेशनल बैंक की संचालन समिति में डालमिया के प्रतिनिधियों का प्रभुत्व हो गया । त्राज पंजाब नेशनल बैंक भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में बैंकिंग व्यवसाय कर रही है। अनेक सङ्कटों का सामना करने पर भी आज इसकी रिथित मुद्दर है।

प्रक्त

1. Mention the different kinds of banking service which Indian banks are able to offer their clients. Explain briefly how the service is helpful to the trader.

भारतीय बैंक ऋपने ग्राहकों की जिन विभिन्न प्रकारों से बैंकिंग सेवाएँ करती हैं उनका वर्णन कीजिये । यह सेवार्ये व्यापारियों के लिये कहाँ तक लाभदायक हैं ?

2. What are the usual functions of a bank? Explain the same as fully as you can.

बैंकों के साधारण कार्यों की पूर्णतया विवेचना कीजिये।

3. What are the difficulties and defects of Indian Joint Stock Banks? Give suggestions for their improvement.

भारतीय सम्मिलित पूँजी वाली बैंकों की किमयाँ तथा कठिनाइयाँ क्या हैं ? इनके सुधार के सुभाव दीजिये।

4. Discuss the work done by the Indian joint stock banks. Discuss their defects and suggest remedies to remove them.

भारतीय सम्मिलित पूँजी वाली बैंकों ने क्या कार्य किया है ? उनके दोष बतलाइये तथा उन्हें दूर करने के उपाय बतलाइये।

5. What are the causes of slow growth of joint stock banks in India? Explain clearly.

भारतीय बैंकों की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ? पूर्णतया विवेचना कीजिये।

6. Discuss the principal defects of Banking in India. Point out the effect of the lack of discounting facilities on Indian money market.

भारतीय वैंकिंग के मुख्य दोषों का वर्णन की जिये।

7, Carefully examine the causes that have retarded the development of the banking habit in this country. Suggest measures to improve the present position.

भारतवर्ष में किन कारणों ने लोगों में बैंकिंग की ऋादत पड़ने में बाघा डाली १ वर्तमान स्थिति में मुधार के मुफाव दीजिये।

8. Examine carefully the progress made in the field of Banking in India. What steps do you consider necessary to improve the position in this respect?

भारतीय बैंकिंग की प्रगति की विवेचना कीजिये। इस स्थिति में सुधार के लिये स्थाप क्या स्थावश्यक कार्यवाही करेंगे ?

ग्रध्याय उ

ऋौद्योगिक अर्थ-ज्यवस्था

(Financing of Industries in India)

उत्पादन में वृद्धि करने के लिये हमको भवन, मशीनें, श्रीजार तथा कब्ना माल, संचय, मजरूरी, इँघन, शक्ति तथा श्रन्य सहायक शक्तियाँ, जिनसे उद्योग को स्थापित किया जा सके तथा सेवाये जिनसे उद्योग में गति लाई जा सके, ब्राटि को अत्यधिक श्रावश्यकता पड़ती है श्रीर उन्श्री अर्थ-व्यवश्या करना ही श्रीचेंगिन अर्थ-व्यवस्था कहनाती है। साधारएतना निसी भी उद्योग में निम्न प्रकार की पूँजी की श्रावश्यकता होती है:—

- (१) स्थिर पूँ र्जा (Fixed Capital)—जो पूँ जी स्थायी सम्प्रांत पर विनियोग करने के लिये ली जाती है उसे स्थिर पूँ जी कहते हैं। इस प्रकार इस पूँ जी का प्रयोग प्रायः उस सम्पत्ति के लिये किया जाता है जिसमें उत्पादन में महापता मिलती है। इसका अनुमान लगाने के लिये यह ध्यान में रखना चाहिये कि जिस सम्पत्ति में इसका व्यय किया जाता है वह यद्यो बहुत बड़े समय तक व्यापार में रहती है, किन्तु उसका स्थान स्थायित्व भी परिवर्तनीय रहता है और उसमें समय के अनुमार परिवर्तन किया जा सकता है। श्रीद्योगिक विकास तथा नवान क्या विवर्गों के साथ-साथ स्थायी सम्प्रांत में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। किन्तु प्रत्येक अवस्था में इसकी अवधि विरोध ही मानी जाती है। इस प्रकार की पूँ जी के लिये दीर्घकालीन व्यवस्था की जानी चाहिये और उसमें उद्योग के स्थायित्व के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। यदि वह एकाकी अथवा सामेदारी हो तो पूँ जी प्रायः व्यापारियों की निजी पूँ जी होती है अथवा उसकी साहकारों से प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु सर्वजनिक क्यानियों में यह पूँ जी अश्वाराधियों से प्राप्त की जा सकती है। कभी-कभी वैक्किंग संस्थाएँ भी इस प्रकार की पूँ जी में सहायता देती हैं।
- (२) सिक्रिय पूँजी (Working Capital)—यह पूँजी उद्योग के साधारण कार्यों में लगाई जाती है। उद्योग में क्यंकर्जाओं का वेतन, मजदूरी, विज्ञापन, याता-यात व्यय, चल सम्पत्ति के क्रय, उत्यादन व्यय, तथा अन्य सामान्य खर्चों में लगाई जाती है, उस समय जब कि उत्पादित वस्तु के विक्रय में देर हो जाती है श्रीर विशेष

पूँची उसमें लगी होती है, उसके लिये भी अतिरिक्त कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है। इसलिये यह पूँजी मोटे रूप में समान व्यय अथवा आक्राक्तिक व्ययों के काम में लाई जाती है। कभी-कभी सिक्रय-पूँजी को "यथार्थ सिक्रय-पूँजी" कहते हैं। अर्थात् जो सम्पत्ति कम्पनी के उद्योग के दायित्वों से अधिक होती है उसके स्थिर पूँजी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में दायित्वों के मुगतान के पश्चात् जो पूँजी शेष रह जाती है उसको वास्तविक अथवा यथार्थ सिक्रय पूँजी कहते हैं। यह पूँजी उद्योग के आकार पर ही निर्भर करती है, उसका प्रवन्ध निजा अथवा उधार ली गई पूँजी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस पूँजी को सरलता से शिव्र ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः जिन व्यक्तियों से यह पूँजी को सरलता से शीव्र ही प्राप्त किया जा सकता है। कित्व व्यक्तियों से यह पूँजी ऋगुण के रूप में ली जाय उनका समय पर मुगतान किया जा सकता है, किन्तु यह विचार सदैव लाभदायक ही सिद्ध होता है कि व्यापार की सिक्रय पूँजी भी प्राय: स्थाई पूँजी के समान ही आवश्यक होती है। अतः उसके लिये भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। उस अवस्था में, जब कि पूँजी केवल आकरिमक अथवा सामयिक कार्यों के लिये ली जाये, किसी सीमा तक ऋग्यों पर आश्रित रहा जा सकता है। सिक्रय पूँजी की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सिक्रय पूँजी की किस प्रकार की आवश्यकता है।

भारतवर्ष में उद्योग-धन्धे अपनी पूँजी को निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं :--

(१) त्रांश निर्गमित करके-प्रत्येक कम्पनी को एक स्वीकृत रकम तक ग्रंश बेचने का ऋधिकार होता है। ये अंश कई प्रकार के होते हैं : साधारण ऋश तथा पूर्व अधिकार वाले अश । पर्व अधिकार वाले अंश भी कई प्रकार के होते हैं। यदि कम्पनी को किसी वर्ष में लाभ होता है तो एक निश्चित दर से सबसे पहले पर्व अधिकार वाले अशो पर ही लाम दिया जाता है चाहे स्थगित तथा साधारण अंशों के लिये कुछ भी शेष न रहे। पर्वाधिकार वाले अंशों को कभी कभी अविरिक्त लाभ में से भी कुछ अंश मिल जाता हैं। बहुत सी कम्पनियों में पूर्व अधिकार वाले अंशों को संचालक चुनने के लिये मता-घिकार प्राप्त नहीं होता । जिस कम्पनी में स्थगित अंश नहीं होते तो एक निश्चित दर से पूर्व अधिकार वाले अंशों पर लामांश देने के पश्चात् जितना भी लाभ का शेषांश बच जाता है वह साधारण ऋंशों में ही विभाजित कर दिया जाता है। किन्तु जिस कम्पनी में स्थिगित श्रंश भी होते हैं वहाँ श्रंशों पर भी एक निश्चित दर से ही लाभांश मिलता है श्रौर शेषांश स्थगित श्रंशों में विभाजित कर दिया जाता है। भिन्न-भिन्न प्रकृति के मनुष्य भिन्न प्रकार के ऋंशों को पसंद करते हैं। ऋतः उद्योगपति ऋषिक पूँची प्राप्ति के लिये उनकी इच्छानुसार उनको अंश बेचते हैं। स्रंश विकय करके जो रुपया प्राप्त होता है वह प्रायः मशीन क्रय करने के लिपे भवन इत्यादि बनाने के काम में लिया जाता है।

ऋण-पत्र वेच कर—प्रत्येक कम्पनी को ऋण प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। जब ऋण किसी विशेष व्यक्ति से न लेकर जनता से प्राप्त किया जाता है तो उसके लिये ऋण-पत्र श्रंशों की माँति ही निर्गमित किये जाते हैं। इन ऋण-पत्रों पर एक निश्चित दर से व्याज दी जाती है। ऋण-पत्र ऋषेर पूर्व निर्गमित ऋषिकार वाले श्रंशों में यह अन्तर है कि ऋण-पत्रधारी तो कम्पनी के ऋणदाता हैं परन्तु पूर्व ऋषिकार वाले श्रंशधारी कम्पनी के स्वामी हैं। इनसे निश्चित दर से लामांश तभी मिलेगा जब कि ऋण्-पत्र धारियों को निश्चित दर से व्याज का कम्पनी को लाम हो अथवा न हो, देनी ही पहेगी। ऋण-पत्र भी दो प्रकार के होते हैं जैसे सुरद्धित और अमुरद्धित। सुरद्धित ऋण-पत्र के बदले कम्पनी अपनी कुछ नम्पन्ति गिरदी रख देती है परन्तु अमुरद्धित ऋण-पत्रों में ऐसी कोई सम्पत्ति गिरदी नहीं रखी जाती। प्रत्येक प्रकार के ऋण-पत्र धारियों को कम्पनी की चल सम्पत्ति पर पूर्ण ऋषिकार प्राप्त होता है।

प्रवन्य श्रमिकत्तीत्रों से ऋण श्राप्त करके-भारतीय उद्योग-घन्धों की उन्नित करने के लिए यहाँ पर एक नवीन पद्धति का जन्म हन्ना जो अपने दङ्ग की एक विचित्र प्रणाली है। यह पद्धति पाश्चात्य देशों में बहुत कम प्रचलित है। परन्तु भारत की आर्थिक तथा औद्योगिक स्थितियों के अनुकल होने के कारण इस प्रणाली का भारत के उद्योग-घन्धों को आधुनिक दङ्ग से संस्थापित करने, उनका प्रवस्य करने तथा उनको प्रत्येक प्रकार की सहायना देने में पूरा-पूरा हाथ रहना है। प्रबन्व ऋभि-कत्ती ही साधारणतया नवीन श्रीद्योगिक संस्थाश्री के मूल संस्थापक होने हैं। वे ही उन्हें संस्थापित करने की जोखिम श्रीर उन्हें मुचार हम से चलाने का उत्तरहायित्व श्रपने ऊपर लेते हैं। वे ही इन कम्पानयों की श्रिधिकांश स्थिर तथा सकिय पूँजी को प्रदान करते हैं। बम्बई तथा ऋहमदाबाद की बड़ी बड़ी करड़ के मिलें उन के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही स्थापित हो सकी हैं। इन्होंने ही प्रयोगातमक कठिनाइयों तथा प्रारम्भिक असफलताओं का सामना करके अनेक सफल उद्योगों की नीव डाली है। व लोग कम्पनी के श्रंश स्वयं क्रय करके उसे आवश्यकतानुसार तथा संकट काल में ऋण देकर उसके ऋण-पत्रों को स्वयं ऋथवा ऋपने मित्रों को क्रय करवाकर तथा वैंकों एवं ऋन्य व्यक्तियों के लिये ऋण की जमानत करके कम्पनी को बहुत बड़ी ऋार्थिक सहायता पहुँ-चाते हैं। वे ही ऋपनी प्रतिष्ठा तथा विश्वसनीयता के कारण जनता से ऋधिकाधिक मात्रा में सार्वजनिक जनाएँ प्राप्त करने में सफल होते हैं। वर्तनान काल में वे अपनी कम्पनियों के ऋशों तथा ऋण-पत्रों के ऋभिगोपन का कार्य भी करने लगे हैं। इनके लम्बे व्यावहारिक जीवन ऋौर व्यापार संसार में नाम तथा प्रसिद्ध के सहारे जनता को नवीन कम्पनियों से संबन्ध स्थापित करने में मुविधा रहती है। नई-नई कम्पनियाँ भी इनके श्रनुभव तथा कुशलता को प्राप्त कर लेती हैं।

प्रवन्ध स्रभिकत्ती द्वारा श्रार्थिक सहायता के दोष—प्रवन्ध श्रिमिकर्ताश्चों ने श्रीद्योगिक श्रर्थ-व्यवस्था में पर्याप्त हाथ बटाया है। किन्तु यह सब श्रपित्वित सेवाएँ उन्होंने स्वार्थ त्याग तथा सेवा भावना से नहीं की परन्तु इसमें उनका निजी स्वार्थ रहा है श्रीर श्रपनी साख तथा ख्याति बनाये रखने के लिये ही उन्होंने यह सब कार्य किये हैं श्रीर करते रहते हैं। प्रवन्ध श्रिमिकर्त्ताश्चों की श्रार्थिक सहायता के श्रनेक दोष भी हैं जिनमें से मुख्य ये हैं:—

भारतीय बैंक प्रबन्ध श्रमिक त्तांश्रों की साख पर कम्पनी को ऋण देती हैं न कि कम्पनी की स्वयं की साख पर, श्रतः यदि किसी कारणवश्य प्रबन्ध श्रमिक त्तांश्रों की श्राधिक स्थिति दुर्बल हो जाये तो बैंक श्रपने ऋण को वापस ले लेती हैं। प्रमंडल श्राधिक स्थिति दुर्बल हो जाये तो बैंक श्रपने ऋण को वापस ले लेती हैं। प्रमंडल श्राधिक सुविधाश्रों के लिये बहुत कुछ सीमा तक श्रपने प्रबन्ध श्रमिक त्तांश्रों पर निर्भर रहती हैं। परिणाम स्वरूप उद्योग श्रौद्योगिक कारणों से प्रमावित न होकर श्राधिक कारणों के प्रमुत्व में श्रा जाते हैं तथा श्रर्थ उद्योग का सेवक न होकर उसका स्वामी वन बैठता है जिसका भारी भयावह प्रभाव उस उद्योग पर पड़ता है। प्रबन्ध श्रमिक त्तांश्रों पर निर्भर रहने के कारण प्रमंडल श्रपनी स्वतंत्र श्राधिक सहायता पद्धित विकसित नहीं कर पाती, प्रवन्ध श्रमिक त्तांश्रों द्वारा होने वाली श्राधिक पूर्ति बहुत महँगी तथा हानिकर होती है, क्योंकि वह श्रपने ऋणों पर बहुत श्रधिक ब्याज लेती हैं जीर श्रपने प्रभाव के कारण श्ररिव्त ऋणों को रिव्त ऋणों में परिवर्तित कर लेती हैं जिससे प्रमंडल उनके हाथ का खिलौना बन जाता है। प्रमंडल पर श्रपना श्राधिक प्रमुत्व बनाये रखने के लिये वे श्रपने व्यवस्थापित प्रमंडलों को समय-समय पर श्राधिक सहायता देते रहते हैं जिससे वे उनके ऋणा भार से सदैव द वे रहकर उनके चंगल में फँसे रहते हैं।

सार्वजनिक जमारों—भारतवर्ष में बैंकिंग मुविधात्रों की कमी होने के कारण सर्वधारण जनता बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के स्वामियों तथा प्रबन्धकक्तां श्रों के पास, जिनमें उनका पूरा-पूरा विश्वास है, अपनी बचत जमा करती रही है। प्रबन्धकक्तांश्रों के द्वारा ये जमाएँ स्थायी जमा के रूप में काम में लाई जाती हैं। ये जमायें स्थायी जमा के रूप में होती हैं और इनकी अवधि ६ मास से लेकर १ वर्ष तक, परन्तु अहम-दाबाद में ७ वर्ष तक होती हैं। ये जमाएँ बिना किसी प्रकार की प्रतिभृति दिये ही प्राप्त की जाती हैं और इन पर ब्याज २ प्रतिशत से ७ प्रतिशत तक दो जाती है। यह पद्धति श्रीद्योगिक कार्यों के लिये सुविधापूर्वक कम व्यय पर प्रचुर मात्रा में पूँजी प्राप्त करने की एक अच्छी तथा सरल प्रशाली है।

बेंक ऋगा—मारतीय बेंक उद्योगों की स्थिर तथा सक्रिय पूँजी की पूर्ति के लिये बहुत कम सहायता देती हैं। चालू पूँजी की पूर्ति में स्टेट बेंक संयुक्त स्कंध बेंकों का अवस्य कुछ हाथ है किन्तु इतना ऋषिक नहीं। व्यापारिक बेंक केवल उद्योग-धन्यों की

ऋार्थिक सहायता, हुन्डियों की कटौती करके श्रल्पकालीन सुरिद्धत ऋण देकर, नकद साल खाता खोलकर श्रिविकर्ष की सुविधाएँ देकर तथा व्यक्तिगत साल पर उधार देकर कर सकती हैं। ऋण बहुधा कच्चे माल, तैयार माल तथा श्रन्य प्रथम श्रेणी की प्रतिभृतियों की जमानत पर तथा दो श्रच्छे हस्ताद्ध्यों वाले प्रतिशापत्रों के श्राधार पर दिये जाते हैं। ऋण एक वर्ष से श्रिधिक श्रविध के लिये नहीं दिये जाते हैं। स्टेट बैंक तो केवल ह मास की श्रविध के लिये ही ऋण देती हैं। भ में ६ प्रतिशत तक व्याज देती है। यदि ऋण माल के श्राधार पर लिया जाता है तो ३० श्रथवा २५ प्रतिशत का श्रंतर बैंक श्रपने पद्ध में ब्लती हैं। भारतीय बैंक व्यक्तिगत साल पर तो बहुत ही कम ऋण लेती हैं। इस प्रकार भारत में श्रीद्योगिक कम्यनियों को प्रचुर मात्रा में बैंकिंग सुविधार्ये प्राप्त नहीं होती हैं।

वेंकों की श्राधिक सहायना में दोष—वेंकों के ऋगए प्रवान करने की पढ़ांत में कुछ दोष हैं—

- (१) बैंक जमानत में केवल ऐसी वस्तुओं को लेना चाहती हैं, जो कि आसानी से बेची जा सकें और स्थायी समाचि जैसे, मिम, भवन, मर्शान को नहीं चाहतीं।
- (२) वे जमानत पर मृत्य पर केवल ५० प्रतिशत मे ७० प्रतिशत तक ही ऋगुण देती हैं जिससे मंदी में उद्योगपतियों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- (३) कभी-कभी बैंक जमानत में एक विशेष प्रकार का ही माल लेना चाहती हैं जिससे उद्योगपतियों को अपने माल का पूरा मृत्य प्राप्त नहीं हो सकता है।
- (४) जमानती माल को बैंक ऋपने गोदाम में रखती हैं जिसमें माल के लाने-ले जाने पर बहुत व्यय होता है तथा उद्योगपति को उस माल को प्रयोग करने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- (५) बैंक की नं०४ की क्रिया से उद्योगपित का बाजार में मान कम हैं। जाता है।
- (६) रोकड़ लघार प्राय: देखने में तो बहुत मुन्दर प्रतीत होती है, किन्तु उद्योग-पित वैंक से ली हुई राशि केवल ५० प्रतिशत हो निकाल सकती हैं अथवा वैंक अपनी इच्छा पर कभी-कभी उसको बन्द कर सकती हैं। यदि ऐसे ऋग पर जनानत दी गई हो और जमानत का मुल्य कम हो गया हो तो वैंक आगे रुपया देना बन्द कर देती है।
- (७) दो हस्ताच्यों का अर्थ उद्योगों में प्रवन्त अभिकर्त्ता पदित को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि वैंक प्रायः प्रवन्त अभिकर्ताओं से सम्बन्धित रहते हैं। अतः प्रत्यद्व अथवा प्रोद्ध रूप से उद्योगों में प्रवन्त्र अभिकर्त्ता पदित को प्रोत्साहन देते हैं।

- (८) वैंकिंग जाँच कमेटी के समद्ध यह बात भी आई थी कि बैंक ऋगा देने में पद्मपात करती हैं तथा जिन लोगों से उनका स्वार्थ होता है उनको अनावश्यक ऋगा भी दे दिया जाता है।
- (६) बैंकों के ऋण देने की पद्धति में उनके प्रबन्धकों का बहुत बड़ा दोष रहता है, क्योंकि वे प्रायः जिन व्यक्तियों के प्रभाव में होते हैं उनको ही ऋधिकांश ऋण मिलता है।
- (१०) ऋगा का भुगतान भी भारत में बहुत शक्ति के साथ करवाया जाता है तथा ऐसी बहुत कम स्थिति होती है, जब ऋगी को कुछ छूट दे दी जाती है।
 - (११) बैंक में दीर्घकालीन ऋगा देने की बहुत कम व्यवस्था है।

विनियोग प्रन्यासों द्वारा (Investment Trust)—विनियोग प्रन्यास विशाल पूँजी वाली सार्वजनिक कम्पनियाँ होती हैं, जो उद्योग तथा पूँजी लगाने के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होती हैं तथा अपनी पूँजी अंश बेचकर एकत्रित करती हैं। ये संस्थाएँ उद्योग के अंश तथा प्रतिभृतियों का अभिगोपन करके उनसे मुद्रा बाजार में प्रधारित करती हैं। इन प्रन्यासों के कार्य तथा औद्योगिक बैंकों के कार्यों में केवल यही विशेषता होती है कि औद्योगिक बैंक विनियोक्ता के रूप में कार्य करती हैं। किन्तु ये प्रन्यास अंश तथा प्रतिभृतियों के निर्गमन में मध्यस्थ का कार्य करते हैं और केवल औद्योगिक प्रतिभृतियों से ही सम्बन्ध रखती हैं। ये संस्थार्य सामान्य विनियोक्ताओं से प्रत्यच्च अथवा परोच्च रूप में धन एकत्रित करती हैं तथा उद्योग की अर्थपूर्ति में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं। अमेरिका में पूँजी का निर्गमन करने वाली संस्थार्य विनियोग प्रन्यासों को अपनी आवश्यकता बतला देती हैं तथा प्रन्यास उसकी पूरी जाँच करके तथा उसके आवश्यक सोतों का अनुमान लगाकर उनके निश्चित अंशों का अभिगोपन कर लेती हैं और फिर अपने प्रमाव के कारण उसको जनता में निर्गमित कर देती हैं। इस प्रकार प्रतिभृतियों का विनियोग बड़ी सरखता से हो जाता है।

जब यह पून्यास किसी उद्योग के श्रंशों का श्रिभगोपन कर लेता है तो कम्पनी को श्रावश्यक परामर्श भी देता है तथा उसके विषय में विनियोक्ताश्रों द्वारा होने वाली पूछताछ का भी संतोषप्रद उत्तर देता रहता है तथा कम्पनी को श्रायकर तथा श्र्यं सम्बन्धी परामर्श भी देता रहता है। ये प्रन्यास कभी-कभी कम्पनी के संचालक मंडल में श्रपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, जो कि कम्पनी की श्रार्थिक व्यवस्था का समुचित नियंत्रण करता है, जिससे कम्पनी की श्रार्थिक स्थित सुदृढ़ हो जाती है तथा साधारण विनियोकाश्रों का कम्पनी के प्रति विश्वास बन जाता है।

विनियोग प्रन्यासों का टर्श्य कम्पनियों की लम्बी श्रार्थपृति का करना होता है। श्रतः इसके लिए वाणिज्य वैंकों के कार्य सर्वथा श्रनुप्युक्त होते हैं, क्योंकि उससे उनके उर्श्य की पूर्ति नहीं होती। साथ-इं-साथ इन प्रन्यासों को कम्पनी के प्रवर्तन में भी भाग नहीं लेना चाहिये, क्योंकि इससे या तो वे श्रस्यस्थ संस्था को जन्म दे सकते हैं श्रथवा श्रपना सम्बन्ध उससे प्रदर्शित करके श्रार्थिक हानि उटा सबले हैं। विनियोग प्रन्यासों को किसी प्रकार की प्रतिभृति लेने के पूर्व उसकी स्थापना की जाँच किसी विशेषज्ञ से वस्वा लेनी चाहिये। जिससे उनका निर्मान सुधियावर व हो सके श्रीर प्रन्यास विनियोक्ताओं को सही प्रतिभृति दिलाने में सफल हो सके।

भारत में इस प्रकार की संस्थायें दितीय महायुद्ध के पूर्व नाममात्र को भी नहीं थीं । किन्तु इस महायुद्ध तथा युद्धोत्तर काल में इस प्रकार की संस्थाओं की बाद सी श्रा गई है। टाटा इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन श्राफ इधिइया, इन्डिस्ट्रयल इस्टेस्टमेन्ट रुस्ट लिमिटेड, वर्डस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ब्राद्धि प्रमुख विनियोग प्रत्यास हैं। ये संस्थापें कृत्य साधनों वाले विनियोजकों को बहुत सहायता प्रदान करती हैं। एक साधारण विनि-योजक के पास न तो इतना समय ही होता है छीर न उक्के पास इतनी शक्ति, योग्यता तथा साधन ही होते हैं कि वह जिसकी प्रतिभूति में अपना स्वया लगाना चाहता है उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कर सके । परन्तु विनिमय प्रत्यास ऋपने मुयोग्य प्रबन्ध ऋभिकत्ती श्रों तथा विशेषशों की सहायता से यह कार्य बहुत ही सरलता से कर सकता है। इस प्रकार वह साधारण जनता से एक ऋच्छी प्रतिभृति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है । ये संस्थायें जनता में विनियोग करने की भावना जाएत ≉रती हैं। परन्तु हमारे देश के लिये यह एक नवीन संस्था है। अतः इसका विकास तथा प्रसार बहुत ही नियंत्रित रूप में हो जाना चाहिये जिससे यह देश की छीदोशिक उन्नति में पूर्ण रूप से सहायक हो सके। यदि इन विनियोग प्रन्यासों का प्रबन्ध अयोग्य तथा बेईमान व्यक्तियों के हाथ में होगा तो वे देश के लिये अधिक घातक सिद्ध हो सकते हैं। ऋतः हमारे यहाँ भी स्थायी प्रन्यासों को भी प्रोत्साहित करना चाहिये।

इस समय हमारे देश में विनियोग इन्यास बहुत कम है । इनकाँ विकास इतना नहीं हुआ है जितना अमेरिका तथा अन्य पाश्चात्य देशों में ।

श्रीद्योगिक चैंकों से ऋण प्राप्त करके—श्रीद्योगिक दीर्घवालीन वित्त का एक साधन श्रीद्योगिक वैंक भी है, श्रीद्योगिक वैंक का उद्देश्य श्रीद्योगिक संस्थाश्रों की पूर्ण दीर्घकालीन श्रार्थिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करना है जिनकी पूर्ति साधारण वैंकिंग संस्थाश्रों द्वारा नहीं की जा सकती। यह संस्था वैंकों से प्रतिस्पर्ध करने वाली

- (二) वैंकिंग जाँच कमेटी के समद्ध यह बात भी आई थी कि बैंक ऋग् देने में पद्मपात करती हैं तथा जिन लोगों से उनका स्वार्थ होता है उनको अनावश्यक ऋग भी दे दिया जाता है।
- (E) बैंकों के ऋण देने की पद्धति में उनके प्रबन्धकों का बहुत बड़ा दोष रहता है, क्योंकि वे प्रायः जिन व्यक्तियों के प्रभाव में होते हैं उनको ही ऋधिकांश ऋण मिलता है।
- (१०) ऋग का भुगतान भी भारत में बहुत शक्ति के साथ करवाया जाता है तथा ऐसी बहुत कम स्थिति होती है, जब ऋगी को कुछ छुट दे दी जाती है।
 - (११) वैंक में दीर्घकालीन ऋग्ए देने की बहुत कम व्यवस्था है।

विनियोग प्रन्यासों द्वारा (Investment Trust)—विनियोग प्रन्यास विशाल पूँजी वाली सार्वजनिक कम्पनियाँ होती हैं, जो उद्योग तथा पूँजी लगाने के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होती हैं तथा अपनी पूँजी अंश बेचकर एकत्रित करती हैं। ये संस्थाएँ उद्योग के अंश तथा प्रतिभृतियों का अभिगोपन करके उनसे मुद्रा बाजार में प्रधारित करती हैं। इन प्रन्यासों के कार्य तथा औद्योगिक बैंकों के कार्यों में केवल यही विशेषता होती है कि औद्योगिक बैंक विनियोक्ता के रूप में कार्य करती हैं। किन्तु ये प्रन्यास अंश तथा प्रतिभृतियों के निर्गमन में मध्यस्थ का कार्य करते हैं और केवल औद्योगिक प्रतिभृतियों से ही सम्बन्ध रखती हैं। ये संस्थायें सामान्य विनियोक्ताओं से प्रत्यच्च अथवा परोच्च रूप में धन एकत्रित करती हैं तथा उद्योग की अर्थपूर्ति में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं। अमेरिका में पूँजी का निर्गमन करने वाली संस्थायें विनियोग प्रन्यासों को अपनी आवश्यकता बतला देती हैं तथा प्रन्यास उसकी पूरी जाँच करके तथा उसके आवश्यक होतों का अनुमान लगाकर उनके निश्चित अंशों का अभिगोपन कर लेती हैं और फिर अपने प्रभाव के कारण उसको जनता में निर्गमित कर देती हैं। इस प्रकार प्रतिभृतियों का विनियोग बड़ी सरलता से हो जाता है।

जब यह पून्याम किसी उद्योग के श्रंशों का श्रिमिगोपन कर लेता है तो कम्पनी को श्रावश्यक परामर्श भी देता है तथा उसके विषय में विनियोक्ताश्रों द्वारा होने वाली पूछताछ का भी संतोषप्रद उत्तर देता रहता है तथा कम्पनी को श्रायकर तथा श्र्य सम्बन्धी परामर्श भी देता रहता है। ये प्रन्यास कभी-कभी कम्पनी के संचालक मंडल में श्रपने प्रतिनिधि को मेजते हैं, जो कि कम्पनी की श्रार्थिक व्यवस्था का समुचित नियंत्रण करता है, जिससे कम्पनी की श्रार्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है तथा साधारण विनियोक्ताश्रों का कम्पनी के प्रति विश्वास बन जाता है।

विनियोग प्रत्यासों का उद्देश्य कम्पनियों की लम्बी ऋर्यपृतिं का कमा होता है। ऋतः इसके लिए वाण्डिय वैंकों के कार्य सर्वथा ऋनुम्युक्त होते हैं. क्योंकि उससे उनके उद्देश्य की पूर्वि नहीं होती। सम्बन्धि-स्थ इन प्रत्यासों को कम्पनी के प्रवतन में भी भाग नहीं लेना चाहिये, क्योंकि इससे या तो वे ऋस्वस्थ संस्था को जन्म दे सकते हैं ऋथवा ऋपना सम्बन्ध उससे प्रदर्शित कमके ऋार्थिक हानि उटा सकते हैं। विनियोग प्रत्यासों को किसी प्रकार की प्रतिभूति लेने के पूर्व उसकी स्थापना की जाँच किसी विशेषक से करवा लेनी चाहिये। जिससे उनका निर्मनन सुविधाजनक हो सके ऋौर प्रत्यास विनियोक्ताओं को सही प्रतिभृति दिलाने में सफल हो सके।

भारत में इस प्रकार की संस्थायें द्वितीय महायुद्ध के पूर्व नाममात्र को भी नहीं थीं । किन्तु इस महायुद्ध तथा युद्धोत्तर काल में इस प्रकार की संस्थाओं की बाह सी स्रा गई है । टाटा इत्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन स्राफ इश्डिया, इन्डन्ट्रियल इन्वेन्टमेन्ट दृस्ट लिमिटेड, वर्डस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ब्रादि प्रनुख विनियोग प्रत्यास हैं। ये संस्थार्वे क्रह्म साधनों वाले विनियोजकों को बहुत सहायता प्रदान करती हैं। एक साधारण विनि-योजक के पास न तो इतना समय ही होता है और न उनके पास इतनी शक्ति. योग्यता तथा साधन ही होते हैं कि वह जिसकी प्रतिभृति में अपना दनया लगाना चाहता है उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कर सके । परन्तु विनिमय प्रन्यास अपने मुयौग्य प्रबन्ध अभिकत्तीं औं तथा विशेषजों की सहायता से यह कार्य बहुत ही सरलता से कर सकता है। इस प्रकार वह साधारण जनता से एक ऋच्छी प्रतिभृति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है । ये संस्थायें जनता में विनियोग करने की भावना जाएत करती हैं। परन्तु हमारे देश के लिये यह एक नवीन संस्था है। ग्रतः इसका विकास तथा प्रसार बहुत ही नियंत्रित रूप में हो जाना चाहिये जिससे यह देश की छीवांशिक उन्नति में पूर्ण रूप से सहायक हो सके। यदि इन विनियोग प्रन्यासी का प्रबन्ध श्रयोग्य तथा देईमान व्यक्तियों के हाथ में होगा तो वे देश के लिये अधिक घातक सिद्ध हो सकते हैं। ऋतः हमारे यहाँ भी स्थायी प्रन्यासों को भी प्रोत्साहित जरना चाहिये।

इस समय हमारे देश में विनियोग प्रन्यास बहुत कम है। इनकी विकास इतना नहीं हुआ है जितना अमेरिका तथा अन्य पाश्चात्य देशों में।

श्रीद्योगिक वेंकों से ऋण प्राप्त करके—श्रीद्योगिक दीर्घकालीन वित्त का एक साधन श्रीद्योगिक वेंक भी है, श्रीद्योगिक वेंक का उद्देश्य श्रीद्योगिक संस्थाश्रों की पूर्ण दीर्घकालीन श्रार्थिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करना है जिनकी पूर्ति साधारण वेंकिंग संस्थाश्रों द्वारा नहीं की जा सकती। यह संस्था वेंकों से प्रतिस्पर्धा करने वाली

नहीं किन्तु उनकी पूरक है। अथवा उनसे प्रतिद्वन्द्विता करने के लिये नहीं अपितु उनकी कपी को पूरा करने के लिये स्थापित होती है। श्रौद्योगिक बैंकों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

- (१) त्रौद्योगिक संस्थात्रों के द्वारा उघार लिये हुए उन दीर्घकालीन ऋषों की गारन्टी करना जो कि त्राधिक-से-त्राधिक २५ वर्ष की त्रावधि के लिये पूँची बाबार में प्राप्त करते हैं।
- (२) श्रौद्योगिक संस्थाश्रों द्वारा निर्गमित किये हुए श्रंशों, ऋग्ण-पत्रों श्रादि क श्रमिगोपन करना।
- (३) अभिगोपन किये हुए अंशों, ऋण पत्रों आदि को यदि जनता से तुरन्त क्रम न किया तो इनकी प्राप्ति अधिक-से-अधिक सात वर्ष की अविधि के भीतर खक्त बेचना।
- (४) श्रौद्योगिक संस्थाश्रों को इस प्रकार के ऋगा देना अथवा उनके ऋग-पश्रों को क्रय करना जिनका भुगतान २५ वर्ष के भीतर होने वाला है।
 - (५) इन उपयु क्त कार्यों के लिये निश्चित किया हुन्ना कमीशन प्राप्त करना।
- (६) अन्य उन समस्त कार्यों को करना जो कि उपर्युक्त कार्यों से सम्बन्धित है तथा श्रौद्योगिक बैंकों को अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को मली-माँति पूर्ण करने के लिये आवश्यक है।

उपरोक्त कार्य करने के लिये श्रीद्योगिक बैंक श्रपने श्रधिक-से-श्रधिक श्रंश जनता को बेचती है तथा जनता को श्रपने ऋण्-िवपत्र जारी करती है, जो श्रीद्योगिक संस्था श्रीद्योगिक बैंक से ऋण लेना चाहती है उसे रमारक-पत्र तथा श्रंतिनयम सहित एक प्रार्थना-पत्र बैङ्क के पास मेजना पड़ता है। बैंक उद्योग-धन्धे की श्रार्थिक श्राव-श्यकताश्रों को तथा उसकी चल-श्रचल सम्पत्ति को ध्यान में रखते हुए ऋण की धन-राशि स्वीकृत कर देती है। जिस उद्योग-धन्धे को ऋण दिया जाता है उसके प्रबन्ध में माग लेने के लिये श्रपनी श्रोर से किसी प्रतिनिधि को नियुक्त-कर देती है।

भारतवर्ष में समय-समय पर ऐसी बैंकों की स्थापना हुई परन्तु ये सफलता प्राप्त न कर सकीं ऋौर या तो समाप्त हो गई, ऋथवा व्यापारिक बैंकों में विलीन कर दी गई। भारतवर्ष में ऋौद्योगिक बैंकों की कुछ कारणों से उन्नति नहीं हुई।

भारतवर्ष में श्रोंद्योगिक बेंकों की एकति न होने के कारण—भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। श्रतएव ग्रामों में रहने वाले लोग श्रधिकतर श्रपनी बचत को छोने-चाँदी के श्राभूषण तथा भूमि ब्रय करने श्रीर कृषि का सुधार करने में तथा श्रपने प्राम वालों को श्रुण देने में लगाते हैं। मध्यम श्रेणी के वे लोग जो कि नगरों में

रहते हैं जिनमें छोटे व्यापारी तथा भिन्न-भिन्न देशों के लोग भी समिम् लित है वे अपनी बचत को भूमि, भवन तथा राजकीय अपूर्ण, नगरपालका अपूर्ण तथा कृषि सार्टी क्रिकेट अपूर्ण में लगभग श्रिषक पसन्द करते हैं । वे व्यवसायिक जो विम नहीं उठाना चाहते। बड़े-बड़े नगरों तथा ब्यापारिक केन्द्रों में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी बचत को उद्योग-घन्धों में न लगाकर सरकारी प्रतिभृतियों में लगाते हैं। जहाँ प्रामों तथा कस्बों का प्रश्न है वहाँ एक कारण तो यह है कि ये घन्धों की जोलिम ही नहीं उठाना चाहते। दूसरे वहाँ बैंक इत्यादि भी नहीं हैं जिनके द्वारा वे कम्पनियों के ऋंश-पत्रों के क्रय-विकय की भी कोई सुतिघा नहीं हैं, केवल बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में पॅजी-बाजार हैं। बैंक इत्यादि अम्पनियाँ अंशों पर ऋण नहीं देतीं। इस कारण भी लोग अपना रुपया श्रंशों में फैसाने में हिचकते थे। इसके अतिरिक्त उससे पूर्व भारत सरकार की नीति च्छोग-परहीं को अधिक प्रोत्साहन न देने की थी। इस कारण भी लोग अपनी बचत को उद्योग-धनवों में नहीं लगाते थे। भारतीयों का उद्योग घन्घों की क्रोर ग्राकर्पन न होने के केवल ये ही कारण नहीं थे-एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि कम्मनियों के प्रवन्ध श्रमिकर्त्ता जो कि कंपनी के सर्वेसर्वा हैं, वे कम्पनियाँ यदि सफल हो जाती हैं तो उनका ऋधि-कांश लाभ अपनी जेन में रख लेते हैं। अंशघारियों को बहुत कम लाभ मिलता है श्रीर कभी-कभी तो उन्हें बहुत घोखा दिया जाता है । भारत में कंपनियों का संगठन अन्य प्रकार का होता है कि अंशधारियों का उस पर तनिक भी प्रभाव नहीं होता ! प्रबन्ध स्रिमिकत्तां ही उनके वास्तविक स्वामी तथा कर्तावत्तां होते हैं। ऐसी दशा में कोई कम्पनी के अंशपत्रों में अपना रुपया क्यों लगाना चाहेगा ? ये ही कारण ये कि भारत में अधिकतर लोग अपनी बचत को उद्योग धन्धों में नहीं लगाते थे, किन्तु १६४० के उपरांत द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप लोगों का ध्यान उधर गया है श्रीर वे उद्योग-घंघों में ऋपनी पूँजी लगाने लगे हैं।

श्रम्य देशों में यदि कोई व्यवसायी श्रयवा व्यावसायिक बुद्ध स्वने वाला किसी धंचे की योजना करता है श्रीर कस्पनी स्थापित करता है श्रीर यदि उसकी योजना श्रम्ब्बी होती है श्रीर उसके सफल होने की संभावना होती है तो जनता उसके श्रंश क्रय कर लेती है। यही नहीं वहाँ वी वैंक नवीन कस्पनियों के श्रिशों का श्रमिगों कर देती हैं। किसी-किसी देश में बैंकों के श्रतिरिक्त पेशेवर श्रमिगोंपक हैं जो नवीन कस्पनियों के श्रंशों का श्रमिगोंपन करते हैं। श्रमिगोंपन (Underwriting) का श्रम्य यह है कि बैंक का श्रमिगोंपक (Underwriter) इस बान का उत्तरदायित्व लेता है कि यदि उसक्ममनी का श्रंश न बिंके तो वह शेष सारे श्रंश क्रय कर लेगा। इस कार्य के लियं वे थोड़ा-सा कमीशन लेते हैं। बैंक तो इसके लियं विशेषण रखती

हैं जो नवीन योजनात्रों की छानबीन करती हैं। श्रतः जब कोई प्रतिष्ठित बैंक या श्रमिगोपक नवीन कम्पनियों के श्रंशों के न बिकने पर उनको स्वयं क्रय करने का उत्तरदायित्व लेता है तो जनता में उसके प्रति विश्वास जम जाता है श्रीर उसके श्रंश बिक जाते हैं | फिर यदि कुछ शेष रह जाते हैं तो बैंक उसको क्रय कर लेती हैं। फिर आगे क्रमशः उन अंशों को जनता में बेच देते हैं किन्तु भारतवर्ष में न तो बैंक ही उस कार्य की करते हैं श्रीर न पेशेवर श्रमिगोपक ही । श्रस्त यहाँ जब तक किसी नवीन कम्पनी के पीछे कोई बड़ा पूँ जीपति या व्यवसायी न हो तब तक उसको पूँजी ही नहीं मिल सकती । उदाहरण के लिये यदि विरला बदर्स किसी नवीन कम्पनी को स्थापित करते हैं तो पहले वे तथा उनके अन्य मित्र ही उनके अंश क्रय करते हैं श्रीर शेष श्रंश वे जनता को बेच देते हैं। उनकी प्रसिद्ध मुद्रा बाजार में साख होने के कारण बहधा उस कंपनी के अंश विक जाते हैं। अन्यथा स्वयं उनको क्रय करके बेचने का प्रबन्ध करते हैं क्योंकि ये ही कम्पनी को स्थापित करते हैं तथा उसके यथेव्ट अंश अपने अधिकार में रखते हैं। अतएव वे अपने को उसका प्रबन्ध अभि-कर्त्ता नियुक्त कर लेते हैं और इस प्रकार वे उसके सर्वे सर्वा बन जाते हैं। आज देश में स्थिति यह है कि यदि टाटा एएड सन्स, बिरला ब्रदर्स, तथा डालमिया इत्यादि प्रसिद्ध पूँ जीपतियों की मैनेजिंग एजेंसी में कोई नवीन कम्पनी स्थापित होती है तब तो उसको पूँजी मिल जाती है। ऋन्यथा यदि कोई साधारण व्यक्ति जिसमें व्यवसायिक योग्यता है, श्रौर यदि वह कोई नवीन कम्पनी स्थापित करता है, तो उसको पूँ जी नहीं मिल पाती।

राजकीय आर्थिक सहायता प्राप्त करके—विदेशों में उद्योग-धंघे सरकार से भी आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। अमेरिका की बड़ी-बड़ी कम्पनियों को सरकार से सहायता प्राप्त होती है। इंगलैएड, आस्ट्रेलिया तथा जापान में भी उद्योगपितयों को पूँजी जुटाने के लिये सरकार ने नवीन-नवीन संस्थायें स्थापित की हैं। भारत की विदेशी सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया, किन्तु भारत की स्वतंत्र सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया, किन्तु भारत की स्वतंत्र सरकार ने इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करके एक केन्द्रीय संस्था जिसे औद्योगिक विच्च निगम कहते हैं तथा कुछ प्रान्तीय संस्थायें, जिन्हें राज्य विच्न नियम कहते हैं, स्थापित कीं।

श्रीद्योगिक वित्त निगम—इस निगम की स्थापना सन् १६४६ के श्रिष्टिनयम के श्रंतर्गत हुई। नियम के निर्म्नालखित कार्य हैं:—

(१) निगम ऋग्य-पत्रों की ज्याज ऋथंवा मूलधन संबंधी प्रतिभूति दे सकता है। इन ऋग्यों की ऋवधि १५ वर्ष से ऋधिक नहीं होगी।

- (२) सर्वजनिक सीमित कम्मिनयाँ तथा सहकारी समितियों को २५ वर्ष की अवधि तक के लिये ऋग् दे सकता है।
- (३) ५ वर्ष की अवधि के लिये १० करोड़ की सीमा तक जन निद्धेप रख 'सकती है।
- (४) श्रौद्योगिक संस्थाश्रों के श्रंश, श्रनुवंघ, ऋग्य-पत्र श्रादि का श्रामगोपन कर सकती है।
- (५) एक संस्था को ऋषिक है ऋषिक १ करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है। यदि ऋण केन्द्रीय सरकार द्वारा रिच्चत हो तो उसकी राश्चि बढ़ाई जा सकती है।
- (६) उद्योगों को (जिनको विदेशी पूँजी की श्रावश्यकता हो । श्रंतराष्ट्रीय वैंक से स्पया दिलवा सकती है।
- (७) कम्पनी के ऋण-पत्रों की गारंटी दे सकती है। खुले बाजार वाले ऋण-पत्रों की गारंटी २५ वर्ष से ऋषिक नहीं होगी।
- (८) जब तक संचित कोष प्रदत्त पूँजों के समान न हो जाये तब तक २ रै प्रतिशत से ऋषि लाभांश नहीं दिया जायेगा। ५ प्रतिशत ऋषिक-से-ऋषिक है।
 - (६) उद्देश्य की पूर्ति के लिये अधिक-से-अधिक कार्य।
- (१०) किसी पूँजी के १० प्रतिशत ऋथवा ५० लाख दाये से ऋषिक दत्त पूँजी में नहीं दे सकता।

संगठन वित्त नियम की ऋषिकृत पूँजी १० करोड़ रुपये है तथा निर्गमित पूँजी ५ करोड़ है। इसका विभाजन निम्नलिखित प्रकार से है—

श्रानुस्चित श्रिषिकोष १.२५ करोड़ रुग्या है । बीमा कमनियाँ, विनिमय प्रत्यास तथा श्रान्य १.२५ करोड़ रुप्या । सहकारी श्रिषिकोष ५० लाख रुग्या । यह पूँ जी केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक के द्वारा निश्चित श्रानुपात में दी जायेगी । श्रंशों का मूल्य ५ हजार रुपये रखा गया है । जून १६५२ में श्रंशों का निर्गमन इस प्रकार हुआ केन्द्रीय सरकार २०००, रिजर्व बैंक २०५४, श्रानुस्चित श्रिषकोष २४३५, बीमा कंपनियाँ श्रादि २५६८ तथा सहकारी श्रिषकोष ६४३, निगम के श्रंश केन्द्रीय सरकार के द्वारा गारंटी किये हुए हैं ।

निगम जन निचेपों द्वारा तथा उधार लेकर अपनी कार्यशील निधि को बना सकेगा। उसके लिए वह अपने अनुबंध सथा ब्याज वाले ऋणा-पत्रों का निर्ममन कर सकेगा, किन्तु यह निर्ममन निगम की पूँजी तथा कोषों के ५ गुने से अधिक नहीं हो सकता। इन पर दी जाने वाली ब्याज केन्द्रीय सरकार के निर्धारित ब्याज से अधिक

24

नहीं हो सकेगी । जन निच्चेप १० करोड़ से ऋधिक नहीं हो सकेंगे तथा उनका भुगतान ५ वर्षों के मोतर किया जाना चाहिये ।

निगम का प्रबंध संचालक मंडल, कार्यकारिगी समिति तथा प्रबंध संचालक द्वारा किया जायेगा। प्रबंध करने के लिये संचालक मंडल को सरकार की नीति का अनुसरग् करना पड़ेगा। वह अपनी सहायता के लिये परामर्शदात्री समिति नियुक्त कर सकेगा।

प्रबन्धक मंडल में १५ संचालक होंगे, जिनमें ४ केन्द्रीय सरकार द्वारा, ३ रिजर्व वैंक द्वारा, २ बीमा कम्पिनयों ऋदि द्वारा तथा २ सहकारी बैंकों द्वारा निर्वाचित होंगे। प्रबन्ध संचालक तथा उर प्रबन्ध संचालक भी कार्य करेंगे। कार्यकारिणी समिति में प्रबन्ध संचालक, समापित तथा संचालक मंडल में से चुने हुए दो ऋन्य संचालक होंगे। प्रबन्ध संचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा उप संचालक निगा द्वारा नियुक्त किया जायेगा। ये दोनों पूरे समय के लिये ऋषिकारी होंगे।

ऋग देने का ढङ्ग-ऋग प्रदान करने से पहले प्रमंडल विशेष सतर्कता व्यवहार में लाता है। यह अपने ऋणियों से फैक्टरी की स्थिति, उत्पादन की वस्त के स्वभाव, भूमि, भवन पर अधिकार, उनके प्रवन्ध, बाजार की आर्थिक अवस्थायें. मशीनों, उत्पादन व्यय, ऋगा लेने का उद्देश्य, ऋगा लौटाने का ढंग, ऋगदि के विषय में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् अपने एक कर्मचारी को फैक्टरी में जाँच करने के लिये भेजता है। यह कर्मचारी फैक्टरी सम्बन्धी सभी बातों को ज्ञात करने के पश्चात प्रमंडल को एक रिपोर्ट देता है। प्रमंडल के लिये हुए ऋग की गारंटी व्यक्तिगत श्रीर सम्मिलित रूप में देनी पड़ती है। प्रमंडल यह पता लगाने के लिये कि उसके ऋण का उचित प्रयोग हो रहा है अथवा नहीं, कुछ अन्य कार्यवाहियाँ भी करता है। ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में प्रमंडल ऋग्गी कम्पनी का प्रबन्ध श्रपने हाथों में ले सकता है श्रीर गिरवी रखे माल को बेच सकता है। यह ऋगा के उपयोग के संबन्ध में समय-समय पर रिपोर्ट भी माँग सकता है श्रीर जाँच भी कर सकता है। वह समय-समय पर सरकार केर्-विमिन्न मंत्रियों तथा वैज्ञानिक श्रीर श्रीद्योगिक व्यापारियों श्रादि से परामर्श लेता रहता है। १६५२ के एक संशोधन के अनुसार प्रमंडल से सहायता पाने वाले उद्योगों में जलयान भी सम्मिलित कर दिये गये हैं, परन्तु सामेदारी तथा लिमिटेड कम्पनियों को सहायता नहीं दी जा सकती। श्रिधिनियम के श्रनुसार प्रमंडल किसी भी कारखाने को उसकी चुकता पूँची की १० प्रतिशत ऋथवा ५० लाख रुपयों, बो भी कम हो, की सहायता दे सकता था, परन्तु १९५२ के संशोधनानुसार अब यह

सहायता १ करोड़ रुपये तक दी जा सकती है। सरकार द्वारा गारंटी देने पर इस सहायता में ऋौर भी बृद्धि हो सकती है।

निगम की आहोतन ं -अनंदर के विधान दवं कार्य के दक्क के संबन्ध में बड़ी स्त्रालोचनाएँ की गई है। कुछ स्त्रर्थशास्त्रियों का कथन है कि यह केवल बढ़े-बड़े उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। और इस प्रकार एक श्रीर तो छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को हानि नहुँचाने को संभावना हद हो जाती है, इसरी श्रीर पूँजी के केन्द्रीयकरण का भय उत्पन्न हो जाता है प्रमुद्धन निर्जा अग्रंशपारियों की संस्था है जिसका उपयोग केवत राज्य अथवा वर्गीय हिता को बहुने के लिये किया जा सकता है। तथा यह भी संभव है कि यह राष्ट्रिय हिती को ध्यान में न रखे। यद्यपि यह ब्रालोचना सर्वभा व्यर्थ है: क्योंकि रिजर्व वैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात प्रमंडल के ४० प्रतिशत ग्रंश सरकार के पास श्रा राये हैं तथा इस प्रकार राष्ट्रीय ऋहित होने की अब ऋाशा नहीं की जा सकती। प्रनंडल ने ऋार्थिक सहायता बहुत कम दी है। यही नहीं, किन्तु एक तो ऋख देने में पर्यान समय लिया तथा दूसरे इसने भारतीय बाजार को विकसित करने में कोई सहायता नहीं पहुँचाई है। यह भी कहा जाता है कि इसका कार्य करने का ढंग बहुत ही पुराना है श्रीर यह प्रार्थना-पत्रों को बहुत ही छोटी-छोटी बृटियो पर रह कर देता है। प्रनण्डल की न्याज दर भी बहुत ऊँची है। कुछ व्यक्तियों का यह भी आरोप है कि प्रमण्डल ने अर्घ-विकिसित तथा विछड़े हुए उद्योगों को कुछ भी सहायता नहीं दी, किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों तथा ऐसे उद्योगों को सहायता देता रहा है जिनकी स्थिति पहले से ऋच्छी थी।

निगम की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति - ज्त १६५६ तक निगम ने ६.६६ लाख रुपये वास्तविक लाम कमाया। यह लाम प्रवन्व-व्यय, ज्याज तथा बहीखाते में देने के पश्चात् बचा। सरकार ने २ प्रे प्रतिशत के हिसाब से ११.२५ लाख रुपये वितरित किये। जून १६५४ में ३०.६५ लाख रुपये लामांश बाँटा गया। निगम ने इस वर्ष ज्याज की दर ६ रे प्रतिशत तथा छूट की दर १ प्रतिशत ही रखी। इन वर्षों में वस्त्र सीमेंट, लोहा, रसायनिक आदि उद्योगों में व्यापक प्रगति हुई। इसके साथ कृषि में भी पर्याप्त उत्पादन हुआ है। सोदपुर ग्लास वर्षस कलकत्ता में संचीलक मण्डल ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि निगम उस काम को अपने हाथ में रखेगा तो प्रति वर्ष उसको हानि उठानी पड़ेगी तथा केन्द्रीय सरकार के उत्पादन मंत्रणालय की असम्पर्यता प्रकट करने पर कम्पनी ६२ लाख रुपये में बेच दी गई। निगम से ऋण लेने वाली अन्य ४ कम्पेनियों में असंतोषप्रद कार्य होने से निगम ने गिरवीनामे के अनुसार उनकी सम्पति पर अपना अधिकार कर लिया। इनमें से तीन कम्पनियों का

कार्य बन्द कर दिया गया और एक का कार्य अत्यंत नियमित रूप से चल रहा है : निझले ७ वर्षों में निगम ने चीनी उद्योग को ४.४३ करोड़, वस्त्रोद्योग को ४.११ करोड़, कागज को २.८१ करोड़ रुपये तथा रसायांनेक को २.८१ करोड़ रुपये ऋग के रूप में दिये हैं। जून १९५५ तक आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य भारत में ५ स्टेट-फाइनेंस निगम खोले गये हैं, जिससे कि राज्यों में कुल ११ निगम हो गये हैं। केन्द्रीय तथा राज्य निगम के कार्य तथा चेत्र निर्धारित कर दिये गये हैं। इस प्रकार उद्योग वित्त निगम देश की औद्योगिक अर्थ व्यवस्था में पर्याप्त प्रगति कर रहा है।

जिस समय यह निंगम स्थापित की गई थी उस समय श्रीद्योगिक वित्त के लिये सब से बड़ा प्रयास था। किन्तु इसकी स्थापना के पश्चात् श्रीद्योगिक वित्त के लिये कुछ श्रीर भी संस्थाएँ स्थापित हुई। लघु उद्योगों के लिये राज्य वित्त निगम, राष्ट्रीय श्रीद्योगिक विकास निगम, श्रीद्योगिक साख एवं विनियोग निगम तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम स्थापित हुई। श्रतः श्रव यह आवश्यक हो गया है कि श्रीद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगमों के कार्यत्तेत्र को पूर्ण तथा सक्ट कर दिया जाये।

राज्य-वित्त-निगम—श्रौद्योगिक वित्त निगम केवल बहुत उद्योगों को ही वित्त सम्बन्धी सुविदाएँ प्रदान करता है। व्यक्तिगत कम्मनियाँ साम्मीदारों तथा व्यक्तिगत क्षयु उद्योगों को यह निगम कोई सहायता नहीं देता। इस कमी को पूरा करने के हेतु १६५१ में भारतीय संसद ने राज्य वित्त निगम, श्रिधिनियम परित करके राज्यों को वह श्रिधिकार दिया कि वे श्रपने यहाँ श्रौद्योगिक वित्त निगम स्थापित करके लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करें। राज्य वित्त निगम लघु उद्योगों को २० वर्ष के लिये श्रूरण प्रदान कर सकता है।

भारत के १३ राज्यों में राज्य वित्त निगम स्थापित हो चुके हैं। राज्य वित्त निगम की पूँजी ५० लाख से कम तथा ५ करोड़ से ग्रधिक नहीं होती। निगम की २५ प्रतिशत पूँजी जनता से प्राप्त की जा सकती है। शेष पूँजी राज्य सरकार रिजर्व वैंक, अनुस्चित वैंक, सहकारी वैंक तथा बीमा कम्पनियों द्वारा जुटाई जायेगी। निगम पूँजी पर से ५ प्रतिशत से ग्रधिक लामांश घोषित नहीं कर सकता। कोई भी राज्य निगम ग्रपनी पूँजी की ५ गुनी रकम तक के लिये ऋण-पत्र जारी करके ऋण प्राप्त कर सकती है। ऋण-पत्रों की जमानत केन्द्रीय सरकार की श्रनुमित से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य वित्त निगम को जनता से जमाएँ प्राप्त करने का भी श्रधिकार है। किन्तु जमा की राशि निगम की चुकता पूँजी से श्रधिक नहीं हो सकती।

निगम का प्रबन्ध १० संचालकों की समिति के सुपुर्द होता है जिसमें से ३ संचालकों को राज्य सरकार एक संचालक को रिजर्व चैंक, एक संचालक को स्त्रीधोगिक वित्त निराम मनोनीत करती है । एक प्रवस्थ संचालक शस्य सम्कार द्वारा नियुक्त किया जाता है । शेष ४ संचालक अन्य अंशधारियों द्वारा निवर्शनत किये जाते हैं ।

राज्य वित्त निगम के कार्य—राज्य वित्त निगम को निम्नलिखित कार्य करने -के ऋधिकार हैं:—

- (ऋ) किसी उद्योग को २० वर्ष तक के लिये ऋग् प्रदान करना ऋथवा उनसे ऋग्य-पत्र क्रय करना।
- (ब) श्रीद्योगिक संस्थाओं द्वारा २० वर्ष की श्रवांच के लिये जो अनुसादिये जाते हैं उनकी जमानत करना।
- (स) श्रीद्योगिक संस्थान्नी के त्रारा तथा प्रत्य-ननी का श्रीमगीरन (under-write) करना। यदि निगम को ये पत्र स्वय क्रय करने पहें तो ये पत्र अवपे के भीतर स्वयं वेच देना चाहिये।

निगम किसी भी श्रीचोगिक संस्था को उनकी चुकता पूँजी के १० प्रतिशत से श्रिषक ऋष प्रदान नहीं कर उकता और वह १० प्रतिशत भी १० लाख से श्रिषक नहीं होनी चाहिये। निगम का सुख्य कार्य ऋष प्रदान करना है, श्रीचोगिक संस्थाश्री के श्रंशपत्र क्रय करना नहीं। राज्य वित्त निगमों ने लघु उद्योगों की मलाई के लिये इतना श्रच्छा कार्य नहीं किया जितने कि उनसे श्राशा थी क्योंकि इन निगमों के रास्ते में कुछ बाधाएँ हैं—

राज्य वित्त निगम की वाधाएँ—राज्य वित्त निगमों को निम्नलिखित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है—

- (१) निगम को श्रौद्योगिक संस्थाश्रों के लिये केवल पूँची जुटाने का श्रिषिकार है जब कि उद्योगों को कार्यशील पूँची की भी श्रावश्यकता होती है। श्रातः कार्यशील पूँची के लिये इन्हें इसका मुँह ताकना पड़ता है।
- (२) राज्य निगम एक न्यूनतम राशि से कम का ऋण प्रदान नहीं करती। ऋतः ऋति लघु उद्योग जिनकी ऋथिक ऋगवश्यकताएँ कम होती है, निगम के चेत्र से बाहर रह जाती हैं।
- (३) ऋण प्रदान करने के लिये निगम ऋण माँगने वाली संस्था के हिसाब-किताब की पूर्ण बाँच-पड़ताल करती है। लघु उद्योग ऋपने हिसाब वैज्ञानिक ढंग से नहीं रखतीं ऋौर न ऋंकेच्चण कराती है क्योंकि ऐसा करने में व्यय ऋषिक होता है।
- (४) लघु उद्योगों के पास इतनी सम्पत्ति नहीं होती कि वे उसे जमानत के रूप में रखकर ऋण प्राप्त कर सकें। निगम केवल सम्पत्ति के बन्धन पर ही ऋण प्रदान करती है।

(५) ऋण प्राप्त करने वाली संस्था को ब्याज के श्रातिरिक्त कुछ श्रीर भी व्यय करने होते हैं, जैसे बन्धन रजिस्ट्री व्यय, स्टाम्प इत्यादि । निगम ६ प्रतिशत से कम ब्याज दर ऋण नहीं देती श्रतः ऋण प्राप्त करने वालों को यह ऋण श्रिषक खर्चीला पड़ता है।

यदि उपरोक्त बाधात्रों को दूर करने का प्रयत्न किया जाये तो राज्य वित्त निगम लघु उद्योगों की अलाई के लिये त्राच्छा कार्य करने में सफल हो सकती है।

श्रीद्योगिक साख एवं विनियोग निगम—इस निगम का प्रारम्भ जनवरी १६५५ में निजी चेत्र में निजी प्रबन्ध के श्रंतर्गत किया गया। इसका 'उद्देश्य निजी उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। इसका संगठन श्रंतर्राष्ट्रीय निजी विनियोक्ताश्रों के श्रार्थिक योग के श्राश्वासन पर एक नवीन प्रयोग है।

निगम की अधिकृत पूँजी २५ करोड़ रुपया तथा निर्गमित पूँजी ५ करोड़ रुपया है, जिसमें ७५ करोड़ रुपया अमेरिकन विनियोक्ता तथा बैंकों के द्वारा, एक करोड़ रुपया ब्रिटेन के द्वारा बेंकों, कामनवेल्थ डेवलपमेंट से विक्त कम्पनी आदि के द्वारा ३५ करोड़ रुपया भारतवर्ष के द्वारा (जिसमें २ करोड़ विनिमय संस्थाओं तथा १५ करोड़ साधारण जनता का था) लगाया गया है। इस प्रकार इस पूँजी में भारत, ब्रिटेन तथा अमेरिका का क्रमशः ७० प्रतिशत, २० प्रतिशत तथा १० प्रतिशत है।

निगम को श्रंतर्राष्ट्रीय बैंक के द्वारा ४'७२ करोड़ रुपयों का ऋण प्राप्त हो सकता है तथा भारत सरकार ने उसको ७'५ करोड़ रुपयों का ऋण दिया है। यह रुपया ब्याज रहित है श्रोर इसका भुगतान १५ वधों के पश्चात् १५ बराबर प्रभागों (किस्तों) में किया जायेगा। यह रुपया संयुक्त राज्य श्रमेरिका के विदेशी शल्य प्रवन्ध (Foreign Operation Administration) के श्रघीन भारत श्रमेरिका तांत्रिक सहकारिता के श्रंतर्गत प्राप्त किया जा रहा है। हाल में केन्द्रीय वित्त १ त्री ने यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि यह श्रधिक योग निजी उद्योगों को सहायता देना है जिनको लाइसँस दिया जाने वाला है। इस सहायता से निगम साधारण ब्याज से एक प्रतिशत कम ब्याज पर ऋण देगी।

निगम की दूसरी विशेषता यह है कि उस पर कोई भी श्रीद्योगिक कम्पंनियों का दल हावी नहीं हो सकेगा। इसका प्रबन्ध ११ संचालकों के एक संचालक समिति के श्रधीन होगा जिसमें ७ भारतीय श्रंशघारियों द्वारा नियुक्त, दो ब्रिटेन द्वारा, एक श्रमेरिका द्वारा तथा एक भारत सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। यदि सरकार का श्रृण नहीं चुकाया जायेगा तो ऋण चुकाये जाने के समय तक सरकार एक श्रीर श्रन्य संचालक नियुक्त कर सकेगी। यदि निगम की श्रर्थ-व्यवस्था किसी प्रकार से

खराव हो गई हो तो सरकार उसमें समापन का आवेदन कर मणेगी। इसके आतिरिक्त निगम पर सरकार का हर प्रकार से (नयंत्रस्य रहेगा।

निगम उद्योगी को सीवा ऋण अथवा उनके अंशो का अभिगोनन करके आर्थिक सहायता देगा तथा तमय-सन्य रूप एक प्रवस्त सम्बन्ध परामर्श एवं सहायता भी देता रहेगा। इसका उद्देश्य उद्योगी को बहुमुखी सहायता देना है। अब निगम ने कागज, विद्युत, यंत्र, रसायनिक, ईंबन, सूर्ता वस्त्र, चीनी तथा खनिज पदार्थ आदि उद्योगों को सहायता देना प्रारम्भ कर दिया है। उद्योगों को किसी भी प्रकार की सहायता देने से पूर्व निगम उनकी पृत्र जान करता है, जिससे कभी-कभी ऋण देने में शिलम्ब हो जाता है।

सीमा कमिनियों के एक्ट्रियरण के पश्चात् १० मिनशत ख्रंश पूंजी स्रशार के अधीन चली गई है ! किर मी ख्रमी पर पूर्व कर से ।नजी संस्था ही है ख्रीर ख्रम भारत सरकार इसमें सबसे ख्रीक ख्रंशों की त्या मेंते हैं ! किन्तु सरकार ने निगम को पूर्ण ख्राश्वासन दिया है कि उसका उद्देश्य निगम पर किसी मकार का श्रीविकार करने का नहीं है ख्रीर यह उसके दैनिक कार्यों में कोई हस्तच्य नहीं करेगों ! इससे निजी चेत्रों का भय ख्रम निश्चित रूप से दूर हो गया है ! यर्तमान काल में इस निगम का महत्व बहुत ख्राधिक है ख्रीर ख्राशा की जाती है कि इसके द्वारा उद्योगों का विकास सुविधा से हो सकेगा ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम—इस निगम की स्थानना फरवरी १६५५ में इस विचार से हुई थी कि यह भारत के लघु उद्योगों की सहायना करेगा, वित्त प्रदान करेगा, संरच्चण करेगा और उठको पोत्साहित करेगा। वे सभी उद्योग. जिसमें ५ व्यक्ति हैं और जो शक्ति से उत्यादन कर रहे हैं अथवा वे उद्योग जिनमें १०० व्यक्तियों से कम विना शक्ति के काम कर रहे हैं और जिनकी उप्यक्ति पूँजी ५ लाख रुपये से अधिक नहीं है इस निगम के कार्यचेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह निगम भी एक व्यक्तिगत सम्मिलित पूँजी की संस्था है जिसकी अधिकृत पूँजी १० लाख रुपया है और जो सी-सी रुपयों के १० हजार साधारण अंशों में विभाजित है।

इस प्रकार भारतवर्ष में अब जनता की रुचि उपरोक्त प्रकृर के निगमों की स्थापना के प्रति दिन-दिन बढ़ती जा रही है जो इस बात की सूचक है कि भारतवर्ष में भविष्य में अभैद्योगिक विक्त की कमी पूर्णतया समाप्त हो जायेगी।

अंतर्राष्ट्रीय अर्थ निगम (International Finance Corporation)—जुलाई १९५६ में अंतर्राष्ट्रीय अर्थ निगम नी स्थापना हुई । यह प्रयास विश्व बैंक के पिछले १० वर्षों के महत्वपूर्ण प्रयोगों द्वारा संभव हो सका। इस प्रकार की संस्थाओं को निजी आधार पर चलाने का विचार किया गया तथा इसके द्वारा समस्त निजी चेत्र के विनियोक्ताओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। भारतवर्ष ने इस हेतु अक्तूबर १९५५ में समभौते पर हस्ताच्चर किये।

निगम की श्रिधिकृत पूँजी ४८ करोड़ रुपये हैं जो सम मूल्य के १ लाख श्रंशों में विभाजित की गई। इसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि कम-से-कम ३२ राष्ट्रों को इसमें ७५ मिलियन डालर देने पड़ेंगे। श्रुव तक ४५ देश ६० मिलियन डालर दे चुके हैं। निगम के संचालक मंडल को १० प्रतिशत श्रितिरिक्त विनियोग करने का श्रिधिकार दे दिया गया जिसमें सदस्य देशों को प्राथमिकता दी जायेगी। निगम का सम्बन्ध विश्व बैंक से है, परन्तु श्रस्तित्व उसका स्वतंत्र है। इसके संचालक मंडल में विश्व बैंक का श्रध्यक्त पद पदेन (Ex-officio President) के रूप में रहेगा, श्रथवा किसी श्रन्य को सभापित के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। इसके कार्य स्वतंत्र चार्टर के श्रनुसार ही होंगे।

निगम के उद्देश्य सदस्य देशों को जो ऋविकिसत तथा ऋर्धविकिसत हैं ऋार्थिक सहायता देना तथा निजी चेत्रों को विकास के लिये प्रोत्सहित करना है। हाल में निगम की गतिविधि ऋौद्योगिक संस्थाऋों तक ही सीमित रहेगी, किन्तु भिवष्य में इसका चेत्र बढ़ाया जा सकेगा।

ऋण देने के सम्बन्ध में किसी भी उद्योग ऋथवा उद्योगों का प्रबन्ध तथा व्यापार की स्थिति को देखेगा और संतोषजनक ऋवस्था में ही ऋग् देगा। निगम कुछ ऋग का केवल ५० प्रतिशत देगा तथा ५० प्रतिशत ऋग लेने वाली संस्था को पहले ही विनियोग करना होगा। निगम के द्वारा दिया गया ऋग लेने वाली संस्थाओं के ऋंशों तथा सम्बन्धों में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। निगम का उद्देश्य घरेलू तथा विदेशी निजी चेत्रों में सहकारिता उत्पन्न करना है। इसलिये ज्यों ही ऋग प्राप्तकर्त्ता लाम पर कार्य करने लगता है, निगम उसको दिये गये धन को ऋग्य संस्थाओं में विनियोग कर देगा। यह निगम ऋंतर्राष्ट्रीय ऋर्य-व्यवस्था में ऋत्यन महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तथा ऋगशा की जाती है कि जैसे-जेसे इसका कार्यचेत्र बढ़ेगा, इसके सदस्य देशों को ऋषिकाधिक लाम पहँच सकेगा।

प्रश्न

I. How do the State Bank and the Commercial banks finance Indian industries? Suggest measures by which they can be made more useful in this respect.

स्टेट बैंक तथा व्यापारिक बैंक भारतीय उद्योगों की किस प्रकार आर्थिक सहायता करती हैं ?

2. What in your opinion, should be the lines on which Industrial Banks should work in this country? Are you in favour of their establishment ?

श्रापके विचार में भारतीय श्रीद्योगिक दैंक श्राना कार्य किस प्रकार करें ? क्या त्राप इन वैंकों की स्थापना के पन्न में हैं!

3. What are Industrial Banks ? What is their business and how do they transact this business ?

श्रीद्योगिक थैंक किसे वहते हैं ? वे किन-किन वार्यों को किस प्रकार करती हैं ?

- 4. How are major industries in India financed? भारतीय वृंहत उद्योगों को पूँ जी किस प्रकार प्राप्त होती है ?
- s. What are the causes for the slow growth of industrial banking in India ?

भारतवर्ष में श्रीद्योगिक वेंकों की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

- 6. How do the important industries get their capital?
- 7. Discuss the objects, constitution and functions of the Industrial Finance Corporation in India. What criticism has been levelled against it?

श्रीद्योगिक वित्त निगम के उद्देश्य, विधान तथा कार्यों का वर्णन कीजिये। इसकी क्या ऋालोचनाएँ हुई हैं ?

8. Write short notes on :-

(a) State Finance Corporation;
(b) Industrial Credit and Investment Corporation;

(c) International Finance Corporation.

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये— (म्रा राज्य वित्त निगम, (व) श्रौद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, (स) अन्तर्देशीय वित्त निगम।

ग्रध्याय ५

विदेशी विनिमय वैङ्क

(Foreign Exchange Banks)

परिभाषा—विदेशी विनिमय वैंक वास्तव में वे व्यापारिक वैंक हैं जिनके प्रधान कार्यालय विदेशों में हैं तथा उनकी शाखाएँ भारत में विद्यमान हैं। ये शाखाएँ अधिकतर भारतीय बन्दरगाहों तथा उन मुख्य व्यापारिक केन्द्रों में स्थापित हैं जहाँ से आयात-निर्यात का व्यापार अधिक होता है। इन विदेशी विनिमय बैंकों का मुख्य कार्य विदेशी व्यापार में आर्थिक सहायता तथा विनिमय की सुविधा प्रदान करना है। परन्तु वर्तमान काल में इन बैंकों ने अपनी शाखाएँ देश के आंतरिक भागों में भी स्थापित कर ली हैं और वह अन्य व्यापारिक बैंकों की भाँति साधारण बैंकिंग कार्य भी करती हैं। विदेशी विनिमय बैंक के कार्य

(१) त्रायात-निर्यात के व्यापार को आर्थिक सहायता देना—विदेशी विनिमय वैंकों का मुख्य कार्य भारत के आयात निर्यात को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उदाहरणार्थ जब भारतीय निर्यातकर्ता इस माल का भुगतान करने के लिये लंदन के किसी बैंक या साख कार्यालय से साख का प्रबन्ध कर लेता है स्त्रीर विदेशी बैंक द्वारा भारतीय निर्यातकर्ता को इसकी सूचना देता है श्रीर भारतीय व्यापारी उस साख के त्राधार पर लन्दन स्थित वैंक या साख कार्यालय पर ६० दिन की देखनहार विदेशी विनिमय हुन्डी लिख देता है। इस बिल के साथ अन्य प्रलेख जैसे जहाजी रसीद, बीमा की रसीद, बीजक ऋादि होते हैं। भारतीय व्यापारी इस विनिमय हुन्डी को भारत में किसी वितिमय वैंक को, जिसकी शाखा इंगलैयड में भी हो, देकर रुपये प्राप्त कर एकता है। यह विनिमय बैंक इस विनिमय हन्डी को लंदन में उस विशेष विनिमय बैंक की स्वीकृति के लिये भेज देती है। स्वीकृत हो जाने पर विनिमय बैंक उसे बेचान कर देती है श्रीर यह हुन्डी लंदन की मुद्रा हुन्डी में बेच करके उस बिल की रकम प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार विनिमय बैंक विदेशी विनिमय हुन्डी को मारत में रुपयों में क्रय करके उसकी रकम लंदन में स्टर्लिङ्ग में प्राप्त कर लेते हैं। यदि विदेशी बैंकों के पास यथेष्ट धनरांशि हो तो वे उर्से अविध तक अपने पास रख कर निश्चित तिथि पर उसका सुगतान ले सकते हैं। परन्त यदि बाजार में धन की कमी हो श्रीर व्यापार में तेजी हो तो वह हुन्हीं को लंदन के मुद्रा बाजार में उसी समय बेचकर दुरन्त द्वये प्राप्त कर सकता है। ये विदेशी विनिम्य हुन्हियाँ दो प्रकार की होती हैं: प्रथम—स्वीकृति पर कागजपत्र वाली हुन्हीं हैं हितीय — भुगतान पर कागजपत्र वाली हुन्हीं। न्वीकृति पर कागज-पत्र वालो हुन्हीं ऐसे प्राहकों के नाम लिखी जाती है जो विश्वासपात्र होते हैं श्रीर बिन्हें कुन्न दिन की साख दी जा सकती है। इस प्रकार की हुन्ही ग्राहक द्वारा स्वीकार कर लेने पर ही माल के श्राधिकार सम्बन्धी कागज-पत्र ग्राहक को दे दिये जाते हैं।

यदि विनिमय हुन्ही भुगतान हुंडी है तो विनिमय वैंक लंडन के व्यागारी को कागज-पत्र तभी देशी जब कि वह इस हुन्डी का भुगतान कर है। ब्रिटेन संदुक्त राज्य अमेरिका उथा उपनिवेशों और भारत के भध्य जो विदेशी विनिमय हुन्डियाँ लिखी जाती हैं वे प्रायः स्टिलिङ्क में ही जिखी जाती हैं। कभी-कभी प्राहक अपनी वैंक में रोकड़ी रुपये जमा करा लेता है और उसे आदेश देता है कि वह अपनी विदेश स्थित शाखा अथवा प्रतिनिधि के हारा विकेता से माल सम्बन्धी कागज-पत्रों को लेकर नकद भुगतान कर दे। इस प्रकार के भुगतान पर कागज-पत्र प्राप्त करने को नकद भुगतान पर कागज-पत्र प्राप्त करने को नकद भुगतान पर कागज-पत्र प्राप्त करना कहते हैं।

इस प्रकार यदि किसी भारतीय श्रायातकर्त ने इंगलैश्ड से माल मँगाया हो तो इसका श्रार्थिक प्रवन्ध दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम रीति के श्रनुसार जब भारतीय श्रायातकर्त्ता श्रयवा श्रन्य योरोपियन व्यामार्ग जिनका लंदन मुद्रा बाजार में ऐसा कार्यालय नहीं है जिसकी वहाँ पर श्रन्छी साख हो तब निर्यातकर्त्ता भारतीय श्रायातकर्त्ताश्चों पर ६० दिन का देखनहार बिल लिखता है। उसके साथ ही माल के श्रिष्ठकार सम्बन्धी पत्र जैसे जहाजी रसीद, समृद्री बीमा, माल का बीजक श्रादि लगा देता है। ये पत्र श्रीर विनिमय बिल इंग्लैंड वा व्यापार्ग किसी विनिमय बैंक के द्वारा जिसकी शाखा भारत में स्थित है, भेज देना है। यह भारत स्थित शाखा भारतीय श्रायातकर्त्ता से बिल का सुगतान लेकर (यद्व बिल का मुगतान विल है) श्रयवा बिल को स्वीकृत कराकर माल के श्रिष्ठकार पत्र में भारतीय श्रायातकर्त्ता को दे देगी। इस श्रविष के पश्चात् इस हुन्डी का भुगतान भारतीय श्रायातकर्त्ता से लेकर यह रकम यह बैंक श्रपन प्रधान कार्यालय को मेज देती है।

दूसरी विधि के अनुसार यदि भारत के किन्हीं ऐसे आगातक का आहे द्वारा इंग-लैपड से माल कय कर लिया गया है जिसके कार्यालय इंगलैपड में है, तो निर्यातक की इंगलैपड की विनिमय बैंक के नाम विपन प्रलेख लिखकर उसे वहीं पर स्वीकृत करा के उसकी लंदन के मुद्रा बाजार में ही कटौती करा लेता है। और इस प्रकार माल का मूल्य स्टिलिङ्क में प्राप्त कर लिया जाता है। लंदन स्थित बैंक उस हुन्ही को स्वीकार करके जहाजी रसीद, समुद्री बीमा तथा बीजक ऋादि विपन्न भारत से ऋपनी शाखा को भेज देता है। भारत स्थित शाखा भारतीय ऋगयातकर्ता से ऋविष समाप्त होने से पहले ही रुपये प्राप्त करके लंदन भेज देती है। इस प्रकार विदेशी हुन्डियाँ दोनों ऋवस्थाओं में स्टिलिङ्ग में ही लिखी जाती हैं। परन्तु प्रथम रीत्यानुसार बिलों की कटौती में भारतीय व्यापारियों को ऋषिक ऊँची दर से ब्याज देनी पड़ती है क्योंकि ये विनिमय हुन्डियाँ लंदन में ही मुना ली जाती हैं जहाँ पर बड़े की दर बहुत ही कम होती है।

- (२) विदेशी विनिमय बिलों का क्रय-विक्रय—विदेशी विनिमय बैंक विदेशी व्यापार का मुगतान करने तथा प्राप्त करने के लिये विदेशी विनिमय हुन्डियों का क्रय-विक्रय करती हैं। जब इनके पास इस प्रकार की हुंडियों की मात्री बहुत ऋधिक हो जाती है तो वे रिजर्व वैंक को ये हुन्डियाँ एक निश्चित दर पर बेच सकती हैं और यदि इनके पास इन बिलों की कमी हो तो रिजर्व वैंक से विदेशी विनिमय एक निश्चित दर पर क्रय कर सकती हैं।
- (३) विदेशों को रूपये भेजने की सुविधा प्रदान करना—विदेशी विनिमय वैंक, वैंक ड्राफ्ट, विदेशी विनिमय हुन्हियों तथा तार द्वारा विदेशों में घन भेजने का प्रवन्ध करती हैं। ये विदेशों में रूपये भेजने का एक सस्ता श्रीर सुविधाजनक साधन है। इसके श्रितिरिक्त विदेशी विनिमय बैंक संसार के प्रत्येक व्यापारिक केन्द्र पर तार की हुन्डी वेचती है।

भारतवर्ष में विदेशी विनिमय बैंकों का स्थान—विनिमय बैंक मुख्यतः विदेश व्यापार में आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं जब कि व्यापारिक बैंकों का मुख्य कार्य देश के आंतरिक व्यापार को आर्थिक सहायता देना है। भारत में आयात और निर्यात व्यापार की उन्नति के साथ ही विनिमय की सुविधाओं के लिए विनिमय बैंकों की स्थापना हुई है। परन्तु प्रारंभिक अवस्था में विदेशी व्यापार इंगलैंड और भारत के मध्य ही सीमित रहा। अतः भारत में स्थापित पहले की विनिमय बैंक अंग्रेजी बैंकों की शाखायें थीं उन बैंकों के प्रधान कार्यालय लंदन में होते थे। किन्तु बाद में जब संसार के अन्य प्रमुख देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार अधिक मात्रा में होने लगा तब लंदन सुदूर पूर्व तथीं संयुक्त राज्य में स्थापित विनिमय बैंकों की शाखाएँ भारत में भी स्थापित होने लगीं। उनमें से कुछ अपना अधिकतर व्यापार भारत में ही करती हैं, जैसे नेशनल बैंक आफ इंडिया, आस्ट्रेलिया ऐन्ड चाइना; दी मर्केन्टाइल बैंक आफ इंडिया, बिहले ऐंड कम्पनी तथा ईस्टर्न बैंक। परन्तु दूसरी बैंक भारत में बहुत ही थोड़ा व्यापार करती हैं। विनिमय बैंकों के प्रधान कार्यालय भारत से बहुत ही थोड़ा व्यापार करती हैं। विनिमय बैंकों के प्रधान कार्यालय भारत से बाहर है। आजनकल भारत में व्यापार करने वाली १८ बैंक हैं।

विनिमय बैंकों का मुख्य कार्य भारत के विदेशी व्यापार की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ये वैंक भारतीय निर्यात करने वाली द्वारा वारी की गई विनिमय हर्डियों को कय-विक्रय करती तथा कटौती करती हैं श्रीर साथ ही भारतीय श्रायात ·करने वालों पर क्रय की हुई वस्तुम्रों के लिये जारी की गई हडियों का स्वया प्राप्त करती हैं। इन विनिध्य वैंकों का भारत के विदेशी व्यापार में सहायता पहुँचाने का एकाधिकार है, क्योंकि सीमित मात्रा में अपने व्यापारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के विदेशी व्यापार में ऋार्थिक सहायता करना स्टेट बैंक के लिये विधानतः निविद्ध है। इसी प्रकार संयुक्त पूँजी वाली वैंकों के पास न तो पर्यान साधन ही हैं और न उनमें यह कार्य करने की त्रिशेष योग्यता तथा प्रशिक्तण है। ऋतएव ये दोनों प्रकार की बैंक यह कार्य नहीं कर पार्ती। जमा के कार्यों में ये विनिमय बैंक हमारी संयुक्त पँजी वाली बैंकों से प्रतियोगिता करने में बड़ी समर्थ हैं। इन बैंकों ने ऋभी हाल में उन स्थानों में जहाँ वे स्थापित हैं, देश के भीतरी व्यापार में आधिक सहायता पहुँचाने की श्रोर प्रयास किया है। इमारे भारत की बैंकिंग के लिये यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में व्यापार का इतना ऋषिक विस्तार होने पर भी केवल विदेशी व्यापार का काम करने के लिये अपनी निजी वैंक नहीं हैं। मरत में काम करने वाली इन बैंकों के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें केन्द्रीय तथा मांतीय बैंकिंग कमेटियों के सामने आई हैं।

भारतीय वैंकिंग के पिछड़े होने के कारण्—जरतीय वैंक विनिम्य वैंकों का कार्य करने में अधफल रही हैं। इसका मुख्य कारण् यह है कि ब्रिटिश सरकार की छत्रछाया में विदेशी वैंकों ने भारतीय विनिम्य वैंकों के साथ उचित तथा अनुनित प्रतिद्वंद्विता करके उनकी उन्नति को ठेस पहुँचाई। भारतीय वैंकों की आधिकतर पूँजी देश के आंतरिक व्यागर में लगी रहती है तथा विदेशों व्यागर के लिये उनके पास बहुत कम पूँजी शेष रहती है। भारतीय वैंकों ने विदेशों में शाखायें खोलने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। विदेशी हुडियों के क्रय करने तथा बेचने से सदैव ही पूँजी विदेशों से आती-जाती रहती है। इस पूँजी का प्रवन्ध करने के लिये विदेशों में इस वैंक की शाखा होना आवश्यक है। ब्रिटिश काल में भारतीय वैंकों को विदेशों में शाखा खोलने के लिये आर्थिक कठिनाई के आतिरिक्त राजनैतिक कठिनीइयाँ मी थीं। यदि विदेशों में शाखायें खोल भी दी जातीं तो भारतीय दासता के कारण वहाँ उनकों किसी प्रकार के स्थानीय जमा मिलने की आशा न थी। विदेशों की मुद्रा प्रणाली की गूद समस्याओं को समफने के लिये भारतीय वैंकों के पास सुरव्हित तथा अनुभवी कमेचारीन थे। रिजेर्व वैंक की स्थापनी से पहले भारतीय वैंकों को विनिमय वैंकों के कार्य करने में प्रोत्साहन देने वाली कोई संस्था न थी। इस्पीरियल वैंक जिससे भारतीय

र्वेंक पथ प्रदर्शन की आशा करती थीं भारतीयों के मुकाबले सदैव विदेशियों का ही पच प्रहरण करता था। यहाँ तक कि भारत सरकार भी अपना विनिमय का कार्य भारतीय वेंकों से कराने को तैयार न थी।

भारतीय विनिमय बेंक की स्थापना—भारतीय व्यापारियों को विदेशी विनिमय वैंकों के कारण विदेशी व्यापार चलाने में बड़ी श्रमुविधा रहती है। एक भारतीय विनिमय वैंक की स्थापना अनुभव की जा रही है। विनिमय बैंक के मारी व्यय को हिट में रखते हुए केन्द्रीय बैंकिंग जाँच सिमिति ने यह सुकाव दिया कि भार-तीय शक्तिशाली बैंक विदेशों में बैंकों से ऋपना सम्बन्ध स्थापित करके विदेशी व्यापार के लिये पूँजी जुटाने का कार्य करें। जर्मनी के बैंकों ने यही टंग अपनाकर अपने विदेशी व्यापार को सहायता प्रदान की, किन्तु भारतीय बैंकों ने ऋभी तक विदेशी व्यापार में कोई भाग नहीं लिया । इसके कारण भारतीय व्यापारियों को बड़ी कठि-नाइयों का सामना करना पड़ा। किन्तु यह हर्ष का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वैंकों ने विदेशी व्यापार पर ध्यान देकर विदेशों में ऋपनी शाखायें स्थापित कीं ऋथवा सम्बन्ध स्थापित किये। १६५८ में ३२ ऋतुस्चित बैंकों की ऋौर २७ ऋन-अनुस्चित वैंकों की १५ देशों में शाखायें तथा सम्बन्ध थे। ये शाखायें अधिकतर पाकि-स्तान, मलाया, ब्रह्मा, लंका, जापान, त्र्रासाम, इंगलैयड तथा अमेरिका में हैं। हमारे वैंकों की विदेशी शाखायें बहत अञ्छा कार्य कर रही हैं। इनके पास विदेशों में १३५ करोड़ के लगभग जमा प्राप्त है। इन बैंकों का नकद कोष सुदृढ़ है। इन शाखाश्रों के स्थापित हो जाने से भारतीय व्यापारियों को विदेशी व्यापार चलाने में पर्याप्त सुविधार्ये प्राप्त हुई हैं। यदि भारतीय वैंक विदेशों में श्रीर श्रिधिक शाखायें स्थापित कर लें तो इससे हमारे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा श्रीर विदेशी विनिमय बैंकों का महत्व भी कम हो जायेगा।

विदेशी विनिमय बैंकों की आलोचनायें—विदेशी विनिमय बैंकों की कार्य पद्धति की समय-समय पर बड़ी आलोचनायें हुई हैं जो इस प्रकार हैं:—

- (१) इन बैंकों के संचालक, ऋधिकारीगण तथा सब बड़े बड़े कर्मचारी विदेशी होते हैं तथा भारतवासियों के साथ इन लोगों का व्यवहार ईर्षाजनक होता है। इन बैंकों ने विदेशी व्यापारियों को ऋधिक सुविधायें देकर तथा भारतीय व्यापारियों को उन सुविधाओं से बंचित रखकर विदेशी व्यापारियों को ऋधिक प्रोत्साहन दिया है।
- (२) इन बैंकों की द्वेषपूर्ण नीति के कारण भारतीय जहाजी तथा बीमा कम्पनियाँ भी नहीं पनप सकीं; क्योंकि जो भारतीय व्यापारी इन बैंकों के साथ व्यवहार करते हैं उनको विदेशी जहाजों तथा विदेशी बीमी कम्पनियों की सेवा प्राप्त करने के लिये बाध्य किया जाता है।

- (३) ये वैंक विदेशी व्यासारियों को ही विदेशों से माल साख पर मँगवाने की सुविधा देती हैं। परन्तु भारतीय व्यासारियों को ये मुविधायें रोकड़ मूल देने पर भी बड़ी कठिनता से देती हैं। ये वैंक विदेशी व्यासारियों की हुडिंथों को बहुत कम बहे तथा विना किसी जमानत के चुका देते हैं परन्तु भारतवालियों को नहां देतीं। ये भारतीय व्यासारियों से हर प्रकार का अनुचित व्यवहार करती हैं। इतना ही नहीं, ये विदेशी विनिमय वैंक भारतीय व्यासारियों को विदेशी विनिमय भी समय-समय पर ऊँची दरों से वेचती हैं जिससे भारतीय व्यासारियों को हानि उठानों पड़ती है।
- (४) यह विदेशा विनिमय वेंक भारतीयों से बहुत-सा स्थया जमा करा लेती हैं श्रीर उस घन का उपयोग विदेशी व्यायारियों के लिये करती हैं। श्रीर कर्मा-कभी इस प्रकार जमा की हुई पूँजी को विदेशों में ले जाकर ब्याज पर लगा देती हैं जब कि भारत में स्वयं पूँजी की कभी है। ये वेंक भारत में नकद केंप नहीं रखतीं। फलस्वरूप भारतीय सुद्रा बाजार में पूँजी की सदेव ही कभी बनी रहती है।

भारतीय मुद्रा बाजार में इन बैंकों का कितना ऋाधिनत्य है यह निम्निलिखित ऋाँकड़ों से सुरपब्ट हो जायेगा :—

विदेशी वैंकों का भारतीय व्यापार

		_			
वर्ष	जमाराशि भ	सरकारी प्र रितयों में विनि		डियों की कटौती एवं क्रय	लाख रुग्यों में शुद्ध लाभ
3838	१६५,८८	४६,१५	१०५,६१	१६,४६	२,२४
१९५०	१७४,१६	४⊏,३३	११२,७३	२३,०१	२,०६
१९५१	१६६,८४	४४,१६	१४८,६९	२५,⊏३	₹,१४
१९५२	१७६,५०	४३,३४	१३१,००	95,39	१,८७
१९५३	१६५,⊏४	84,80	११०,७१	२०,४४	१,३६
१९५४	३७=,४६	४६,३९	23,859	રૂપ,હ્ય	१,२५
१९५५	१९५,१३	88,08	38,588	₹१,≒=	१,६८
१९५६	१६६,१६	४६,७६	१४०,३२	३२,१९	. २,⊏१
१२५७	१६६,०४	42,22	१३६,२५	३४,२२	2,80

उपरोक्त ताहिका यह स्पष्ट करतो है कि स्रभी तक विदेशी विनिमय वैंकों का भारत में व्यापार लगातार बढ़ रहा है। किन्तु यह इसिलेये स्राश्चर्यजनक नहीं है कि भारत में व्यापारिक एवं स्रोद्योगिक चहलू-पहल स्रिवित हो रही है। जनता की क्रय-शक्ति में बृद्धि हुई है स्रीर न केवल विदेशी विनिमय वैंकों के व्यापार में, स्रपित भारतीय वैंकों के व्यापार में भी स्राशातीत बृद्धि हुई है।

- (५) इन बैंकों ने भारत की राजनैतिक एवं आर्थिक उन्नति में सदैव ही अइ-चनें डाली हैं और सदैव ही इस बात का प्रयत्न किया है कि भारत में कोई अच्छा मुद्रा मान स्थापित न होने पाये। ये बैंक ऐसी नीति अपनाती हैं जो राष्ट्रीय हित में नहीं होतीं। ये बैंक विदेशियों को भारत के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति के विषय में द्वेषपूर्ण सूचना देती हैं जिससे हमारी साख को ठेस पहुँचती है।
- (६) अधिकतर इन बैंकों का कार्य लन्दन मुद्रा बाजार के अल्पकालीन कोषों से चलता रहा है, परन्तु कुछ वर्षों में इन बैंकों ने पर्याप्त धन लोगों से जमा के रूप में प्राप्त कर लिया है और अब ये उसी से काम चलाते हैं। दे बैंक भारतीय व्यापार बैंकों से प्रतियोगिता करती हैं। वे भारतीयों से अधिक ब्याज देकर अधिक जमा प्राप्त करती हैं। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में पूँजी होने के कारण तथा उनका संबच्छ लंदन मुद्रा बाजार से होने के कारण भारतीय मौद्रिक अधिकारी उन पर उपर्युक्त नियंत्रण रखने में असफल रहे।
- (७) ये बैंक विदेशी व्यापारियों से विनिमय समभौतों के पूरा होने में यि देर हो जाये तो अनुचित हर्जाना ले लेते हैं। विनिमय बैंक संघ की प्रत्येक कार्यवाहां को भारतीय व्यापारियों से छिपाकर रखा जाता है जिससे भारतीय व्यापारियों को संघ के व्यवहारिक नियमों से कोई लाभ नहीं मिलता। कुछ व्यापारियों का यह भी आरोप है कि ये बैंक उन देशों की मुद्रा को परिवतन के लिए बहुत अधिक समय लेती हैं और अधिक कमीशन भी लेती हैं जिन देशों की बैंकें या बैंकों की शाखार्य भारत में नहीं है। भारतीय व्यापारियों का यह भी कथन है कि ये बैंक भारतीय पूँजी के विदेशी उद्योगों और प्रतिभूतियों में विनियोगित करती हैं तथा इस प्रकार भारतीय पूँजी से लाभ विदेशियों को होता है।
- (६) प्रत्येक देश में यह प्रथा है कि हुन्डी उस देश की मुद्रा में लिखी जाती है जो माल आयात करता है, और आयातकर्ता की स्वीकृति हो जाने पर इन हुन्डियों की कटौती होती है, किन्तु भारतीय विदेशी न्यापारिक हुंडियाँ भारतीय मुद्रा में न लिखी जाकर इंग्लैंड तथा अमेरिका की मुद्रा में लिखी जाती हैं, क्योंकि विदेशी विनिमय बैंक विदेशी मुद्रा की हुंडियों को ही प्रोत्साहन देती हैं। फलस्वरूप भारतीय बैंक इन हुंडियों की कटौती करने में असमर्थ रहती हैं।

विदेशी विनिमय वैंकों के उपरोक्त दोषों का अध्ययन करने के पश्चात् इस बात की आवश्यकता अनुभव होती है कि ईन वैंकों पर पूर्ण कियंत्रण रखा जाये। केन्द्रीय वैंकिंग जाँच समिति के सम्मुख साची देते हुए श्री मनु सूबेदार तथा नित्री रंजन सरकार ने इन दोषों को दर करने के लिये कुछ सुभाव दिये थे। विनिमय वैंकों की कार्य पद्धति में सुधार करने के सुमाव

- (१) इन विदेशी विनिमय वैंकों को अपनी कार्यशील पूँजी का ५० प्रतिशत विदेशों से लाभ चाहिये।
- (२) इन वैंकों को भारत में केवल इतनी जमा राशि प्राप्त करने की अनुमति दी जाये जितना भारतीय विदेशी व्यापार में विनियोग करने के लिये आवश्यक है तथा भारतीय जमा राशि के लिये इन वैंकों पर कुछ विशेष कर लगाया जाये।
- (३) केवल उन्हीं वेंको को जमाराशि प्राप्त करने का ऋषिकार दिया जाये जो भारतीय मुद्रा के साथ पंजीकृत हुई हैं तथा जिनकी संचालक समिति में ऋषिकतर भारतीय हैं।
- (४) विदेशी विनिमय वैंकों के बंदरगाहों के ऋति कि ऋन्य स्थानो पर शाखा खोलने की ऋनुमति प्रदान नहीं की जाये।
 - (५) भारतीय वैंकों के संगठन में इन्हें किसी प्रकार का ऋषिकार न दिया जाये।
- (६) इन वैंको पर यह प्रतिबंध लगाया जाये कि ये किसी प्रकार का संयोग सिन्निधि, पार्पद् एवं प्रन्यास इत्यादि स्थापित न करें क्योंकि ऐसा करने में वैंक शक्ति-शाला होकर भारतीय वैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सफल होता हैं।
- (७) विनिमय बैंक श्रपने नियमों में केवल भारतीय व्यापारियों के परामर्श से ही परिवर्तन करें।
- (c) इन वैंकों के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाये कि भारतीय युवकों को ऊँचे पद पर नियुक्त करें तथा भारतीय बीमा कम्पनियों को प्रोत्साहन दें।
- (६) इन बैंकों को भारतीय बैंकों तथा व्यापारियों के साथ सौतेली माता जैसा व्यवहार न करना चाहिये। जहाँ भी विनिमय बैंक की शाखा हो वहाँ एक स्थानीय परामर्श बीर्ड स्थानित की जाये जो ऋण देने के सम्बन्ध में उचित परामर्श दे सके। इस से विदेशी बैंकों तथा भारतीय व्यापारियों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो जायेंग।
- (१०) केवल उन देशों के बैंकों को ही भारत में व्यापार करने की अनुमित प्रदान की जाये जो भारतीय बैंकों को अपने देश में इसी प्रकार की अनुमित प्रदान करती हैं। इंगलैंड तथा अमेरिका में विदेश बैंक सम्बन्धी यही नीति है। हमें भी इसका अनुसरण करना चाहिये।

१६४६ के भारतीय बैं किंग कम्पनी अधिनियम में विनिमय वैंक संबंधी विधान—१६४६ वैंकिङ्ग कम्पनीज अधिनियम के पारित हो जाने से विदेशी विनिमय वैंक पर पर्याप्त नियंत्रण होने लगा है। अधिनियम के अंतर्गत वैंकों पर निम्नलिखित अतिबन्ध लगाये गये हैं:—

- (१) उस विदेशी बैंक की, जो भारतवर्ष से बाहर पंजीकृत है, चुकता पूँजी तथा संचय १५ लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिये श्रीर यदि यह बैंक बम्बई श्रथवा कलकत्ते या दोनों में व्यापार करती हैं, तो यह राशि २० लाख से कम न होनी चाहिये। इसके श्रितिरक्त इन बैंकों के लिये यह भी श्रितिवार्य है कि एक निर्धारित रकम नकदी में श्रथवा सरकारी प्रतिभृतियों में रिजर्व बैंक के पास जमा रखें, जिससे इस रकम से बैंक का विघटन हो जाने पर ऋग्यदाताश्रों का भुगतान किया जा सके।
- (२) रिजर्व बैंक केवल उन्हीं बैंकों को अनुमित प्रदान करेगी जिनकी आर्थिक अवस्था संतोषजनक है तथा जिस देश की वे बैंक हैं वे देश भारतीय बैंकों के साथ कोई मेदभाव नहीं करतीं।
- (३) इन बैंकों की कम-से-कम इतनी सम्पत्ति भारत में होनी चाहिये जो इनकी माँग तथा सामाजिक दायित्व के ७५ प्रतिशत के समान हो। इस सम्पत्ति की सूची रिजर्व बैंक के पास ३१ मार्च, ३० जून, ३० सितम्बर तथा ३१ दिसम्बर को मेजी जायेगी। यह विधान इसलिये किया गया है जिससे भारतीय पूँजी बाहर जाने से इक जाये। इन बैंकों के लिये यह स्त्रनिवार्य है कि ये भारतीय व्यापार सम्बन्धी लामालाभ लेखे तथा चिट्ठे प्रथक बनायें स्त्रीर इनका स्त्रकेच्च्ण तथा प्रकाशन उसी प्रकार करें जिस प्रकार भारतीय बैंक करती हैं।
- (४) प्रधान कार्यालय तथा प्रत्येक शाखा में एक प्रमुख स्थान पर बैंक का लाभालाभ लेखा तथा चिट्ठा हर समय तब तक लगा रहेगा जब तक दूसरा नवीन न लग जाये।

रिजर्व वेंक द्वारा नियंत्रण के कारण विदेशी विनिमय बेंक अब उतनी शक्ति-शाली नहीं रहीं जितनी पहले थीं श्रीर शनै:-शनै: भारतीय वेंकों के साथ इनकी प्रति-स्पर्घा कम होती जा रही है।

प्रश्न

I. Explain the nature of the business of the Exchange Banks in India. What criticism have been levelled against them?

भारतवर्षु में विनिमय बैंकों के कार्यों की विवेचना कीजिये। उन पर क्या स्थारोप लगाये जाते हैं ?

2. How do the Exchange Banks Finance the foreign trade of this country? Can you suggest improvements in the method of their operations?

विनिमय बैंक इस देश के विदेशी व्यापार की किस प्रकार ऋार्थिक सहायता करती हैं ! क्या ऋाप इनकी कार्य पद्धति में सुवार के सुकाव दे सकते हैं ! 3. What specific measures would you suggest for the creation and growth of Exchange Banking in India ? Why has Indian Exchange Banking remained undeveloped so far?

भारतवर्षे में विनिमय वैंकों की स्थापना एवं विकास के छिये आपके ठीस सुफाव क्या हैं ?

4. Indicate the place of Exchange Binks in the Indian banking system and describe the nature of work the perform.

भारतीय वैकिंग पद्धति में विनिमय वैकों का स्थान बतलाइये तथा उन्के कार्यों का वर्णन कीजिये।

6. The Exchage Banks operating in India are mostly foreign. How do you account for this and how does this fact operate against the interests of our country?

"भारतवर्ष में कार्य करने वाली अधिकांश विनिमय बैंक विदेशी हैं।" आप इस कथन की कहाँ तक पुष्टि करते हैं ? और यह भारतीय हितों के किस प्रकार विरुद्ध हैं ?

6. Describe the main functions of Exchange Banks. Give names of four important Exchange Banks working in India.

विनिमय वैंकों के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये तथा भारतवर्ष में कार्य करने वाली चार प्रमुख विनिमय वैंकों के नाम बतलाइये।

7. "Foreign Exchange Banks gave a step-mothetly treatment to Indian traders." Confirm this statement.

"विदेशी विनिमय वैंकों ने भारतीय व्यापारियों के साथ सदैव ही सौतेले बेट जैसा व्यवहार किया है।" इस कथन की पुष्टि कीजिये।

 How are the Foreign Exchange Banks controlled in India ? विदेशी विनिमय वैंकों पर भारतवर्ष में किस प्रकार नियंत्रण होता है !

ग्रध्याय ६

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक

(International Bank)

बैंक की स्थापना—दितीय महायुद्ध काल में संसार के सभी ऋथंशास्त्रियों एवं राजनीतिज्ञों ने यह ऋनुभव किया कि युद्ध के कारण हुए विनाश की पूर्ति करने के लिये सभी देशों के पुनर्निर्माण तथा विकास की आवश्यकता होगी। कोई भी व्यक्तिगत संस्था इतने बड़े त्रार्थिक भार को सहन करने में त्रासमर्थ रहेगी। त्रातः १६४४ में ब्रीटनबुड्ज़ में एक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस हुई श्रीर अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण् तथा विकास बैंक की स्थापना के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय समभौता हुआ। बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन पूँजी को एक देश से दूसरे स्थान पर पहुँचाना, श्चन्तर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देना तथा सदस्य देशों के भुगतान के संदुलन की समानता स्थिर रखना था। इसके त्र्यतिरिक्त सदस्य राष्ट्री की श्रार्थिक उन्नति एवं पुनर्निर्माण में सहायता पहुँचाने के हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सदस्य राष्ट्रों को ऋण देगी तथा अन्य देशों द्वारा दिये गये ऋगा की जमानत करेगी। इस प्रकार वैंक का मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रों की ऋार्थिक सहायता करना है। इसके ऋतिरिक्त वैंक श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत ऋणों की गारंटी लेकर प्रोत्साहन देगी श्रीर यदि ऐसे ऋण उपलब्ध न हो सकें तो स्वयं उत्पादन कार्यों के लिये ऋगा प्रदान करेगी जिससे सदस्य देशों की उत्पादक शक्ति, जीवन स्तर तथा श्रमिकों की काय-दशा में उन्नित हो सके । बैंक का एक उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय विनियोगों को उचित सुविधाएँ प्रदान करके प्रोत्साहन देना भी है जिससे इनका व्यापारिक स्थिति पर ठीक प्रभाव पड़े। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये १६४५ में श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई। यह बैंक केवल उत्पादन कार्यों के लिये ही ऋण प्रदान कर सकती है। बैंक से ऋण लेकर सदस्य किसी भी देश में सामान क्रय करने के लिये स्वतंत्र होता है। उस पर ऐसा कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता कि वह किसी भी देश में घन व्यय करे।

बैंक की पूँजी—श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक की अधिकृत पूँजी १० श्ररव डालर है। सन् १६५५ में ६ श्ररव डालर पूँजी बैंक के ५८ सदस्य देशों द्वारा लगाई गई थी। अप्रतर्राष्ट्रीय वैंक का केवल वही राष्ट्र सदस्य हो सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय कोप का भी सदस्य हो।

श्रन्तर्राष्ट्रीय वेंक की पूँजी का जितना माग प्रत्येक देश को दिया गया है उसकी केवल २० प्रतिशत पूँजी ही सदस्यों ने चुकाई है। शेप ८० प्रतिशत पूँजी सुरिच्चित गारंटी के तौर पर है जिसे बैंक जब चाह माँग सकता है। वास्तव में श्रन्तर्राष्ट्रीय वेंक के मुख्य कार्य सदस्य वेंकों द्वारा लिये श्रृण की गारटी देना है। श्रम्त, श्रन्तर्राष्ट्रीय वेंक को बहुत श्रिषक पूँजी इकट्टी करने की श्रावश्यकता नहीं थी। यांद कोई देश श्रपना श्रृण न चुका सके तभी श्रन्तर्राष्ट्रीय वेंक को उस श्रृण का मूलधन तथा उसकी ब्याज देशी होगी, क्योंकि उसने उस श्रृण की गारटी दी है। ऐसी स्थिति बहुत कम उपस्थित होगी। श्रतएव श्रन्तर्राष्ट्रीय वेंक के लिये यह श्रावश्यक नहीं था कि वह प्रत्येक देश से उसके माँग की पूर्ग रकम प्राप्त कर लेती। श्रस्त, वेंक ने प्रत्येक देश से उसके माँग की २० प्रतिशत रकम ही प्राप्त की है। शेप ८० प्रतिशत जब वेंक चाह तब प्राप्त कर सकती है।

प्रत्यंक देश न अपन माँग की २० प्र तशत रकम की इस प्रकार चुकाया है.—
२ प्रांतशत स्वर्ण अथवा अमीरकन डाकर के रूप म तथा शेप उस देश की
अपनी सुद्रा म। याद कमी बेंक का शेप प्र प्रांतशत पूँचा की माँगना पड़ा ती
सदस्य देश की सुविधानुसार स्वर्ण म, अथवा अमीरकन डालर म, अथवा उस
सुद्रा में जिसका बेंक की सुगतान करने के लिये उस समय अपवश्यकता है, चुकाया
जावेगा।

श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने प्रत्येक देश से उसके भाग की केवल २० प्रतिशत रक्त ही प्राप्त की है। यही ऋन्तर्राष्ट्रीय बैंक की कार्यशील पूँकों है। किन्तु इसने यह न समभ लेना चाहिये कि इससे ही बैंक की सदस्य देशों को ऋण देने की शक्ति सीमित हो जाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ऋण की गारंटी देने ऋथवा सीधा ऋण देने के ऋतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर किसी सदस्य देश के बाजार में ऋपनी प्रतिभूति (ऋण्पत्र) बेचकर धन प्राप्त कर सकती है तथा उस धन को ऋण स्वरूप श्रन्य देश को दे सकती है।

भारतवर्ष में ४० करोड़ डालर पूँजी क्रय करने वा वक्क दिया है । जिसमें से कुछ डालर में, कुछ भारतीय रुपये में तथा कुछ ब्याज रहित ऋविनिमय साध्य माँगपत्रों में लगाई गई है । भारत को ४२५० मतों का ऋषिकार प्राप्त है ।

बेंक का संगठन—बेंक का सगठन एक गवर्नर-परिषद, कार्यकारिणी सिमिति तथा श्रध्यच्च द्वारा • होता है। प्रमुख्क संगठन गवर्नर परिषद ही है। इस परिषद में प्रत्येक सदस्य श्रपना एक-एक प्रतिनिधि भेजता है। कार्यकारिणी सिमिति में १२

सदस्य होते हैं जिसमें से ५ सदस्य बड़े-बड़े देशों द्वारा तथा शेष अन्य सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। अध्यक्त की नियुक्ति कार्यकारिणी समिति करती है। बैंक ७ सदस्यों वाली एक परामर्शदात्री समिति नियुक्त करती है जो बैंक को समय-समय पर वैंक की सामान्य नीति सम्बन्धी परामर्श देती है। ऋग्ण सम्बन्धी आवेदन-पत्रों की जाँच-पड़ताल एक विशेष समिति द्वारा की जाती है जिसे कार्यकारिणी समिति नियुक्त करती है। बैंक की गवर्नर-परिषद की बैठक सदस्य देशों के नियंत्रण पर मिन्न-मिन्न देशों में होती है। इस अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का सदस्य नहीं है, अतः भारत ५ बड़े राष्ट्री की अंग्री में आ गया और उसको बैंक की परिषद में एक स्थान मिला हुआ है।

बेंक की कार्य-प्रणाली—श्रन्तर्राष्ट्रीय बेंक केवल निम्तलिखित परिस्थितियों में ही ऋण प्रदान करती है—

- (१) यदि कोई सदस्य राष्ट्र की सरकार स्वयं ऋण लेना चाहे तब तो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक बिना केन्द्रीय बैंक की जमानत पर ऋण दे देगी अन्यथा जिस देश में कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है उसको ऋण देने के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उस देश की केन्द्रीय बैंक से ऋण के चुकाने की जमानत लेगी। यदि बैंक ऋण्यता देश के ब्याज की दर और शर्तों से संतुष्ट है और ऋणों के सुगतान करने की नीति उसे उचित लगती है, तभी वह ऋण प्रदान करती है।
- (२) जब ऋँग किसी देश के उद्योगों अथवा स्थानीय सरकारों द्वारा लिया जाता है, उस समय ऋगा का उत्तरदायित्व उस देश की सरकार को लेना पड़ता है, तभी विश्व बैंक ऋगा प्रदान करती है अथवा व्यक्तिगत ऋगों का उत्तरदायित्व लेती है।
- (३) बैंक स्वयं ऋष उसी समय प्रदान करती है जब कि ऋण माँगने वाले देश को किसी अन्य देश से ऋण प्राप्त नहीं होता। ऋणी देश ऋणदाता देश से वस्तुओं के रूप में ऋण लेने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता।
- (४) ऋग्ण देते समय बैंक इस बात का भी ध्यान खती है कि सदस्य राष्ट्र उस ऋग्ण को चुकाने की च्वनता रखता है ऋथवा नहीं। यदि बैंक स्वयं किसी सदस्य राष्ट्र को ऋग्ण देगी तभी तो वह उचित ब्याज लेगी ही, परन्तु यदि बैंक स्वयं किसी राष्ट्र को दिये गये ऋगण की आमदनी की गारंटी देगी तो भी वह इस जोखिम के बदले में कुछ गारंटी कमीशन लेगी।
- (५) जिस योजना के लिये ऋण माँगा गया है, बैंक उस योजना की जाँच एक विशेषज्ञों की समिति दारा कराती है ऋौर जब उसे ये संतोष हो जाता है कि योजना ऋार्थिक दृष्टि से ठीक है तभी उसे ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋगवस्यक नहीं कि योजना प्रत्यच्च रूप से लामदायक हो। योजना का महत्व एवं लाम देश

के आर्थिक विकास की पृष्टिभूमि से ज्ञात किया जाता है। वैंक अनुस उसी समय प्रदान करती है जब अनुस माँगने वाले देश को किसी अन्य प्रकार से अनुस प्राप्त न हो सके।

- (६) बैंक इस बात का भी निरीन्निण करती है कि जिस उद्देश्य के लिये ऋण लिया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये दमक उन्नेप किया जा नहीं है आधवा नहीं। इसी दृष्टि से बैंक ऋण लेने वाले सदस्यों को तांत्रिक (Technical) प्रामर्श भी देती है।
- (७) किंधी भी समय में बैंक द्वारा दिये गये ऋगों तथा उत्तरदायिन्व लिये गये ऋगों की कुल राशि बैंक की पूँजी और संचित कींप से श्राधक नहीं होगी। इस नकार बैंक के कुल दायित्व उसने कुल साधनों के समान होंगे। दिये गये ऋगों का जोत्विम सदस्य देशों में उसके भाग के अनुस्त में विभाजित होता है।

वैंक के ऋणों की मात्रा सदस्यों के चंदे पर निर्भर नहीं रहती। ऋण प्रदान करने के सम्बन्ध में वैंक किसी भी देश से प्रतियोगिता नहीं करती। वैंक ऋपने ऋणों पर ब्याज प्राप्त करने के छितिरक्त छन्य देशों के ऋणों का उत्तरद्वापित्व लेती हैं जो एक ऋलग कोष में जमा कर दिया जाता है। इस कोष का उपयोग केवन हूवने ऋणों के कारण होने वाली हानि को पूरा करने के लिये होता है।

वेंक की सफलता—जैसे ही वैंक स्थापित हुई डालर ऋण के लिये कई देशों के प्रार्थनापत्र श्राये किन्तु मई १६४७ में जाकर कहीं वैंक ने पहला ऋण दिया। श्रीष्ठ ही यह स्पष्ट हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय वैंकों को ऋण देने के लिये सकुक्त राज्य अमेरिका के द्रव्य बाजार में ऋण लेना होगा। बीटन-वुड्ज सम्मेलन में लोगों का यह विचार था कि प्रत्येक देश जो डालर ऋण लेना चाहेगा अपने बैंड सयुक्त राज्य अमेरिका में बेचेगा और अन्तर्राष्ट्रीय वैंक उनकी अदायगी की गारंटी देगी। विद्वानों का विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीय वैंक की गारंटी अमेरिकन पूँजीपितियों को उन देशों के बौंडों में अपना धन लगाने के लिये प्रोत्साहित करेगी। परन्तु वैंक ने द्रव्य बाजार की अव्यवस्थित दशा के कारण अन्य देशों के बौंडों की गारंटी न देकर स्वयं अपने बौंड संयुक्त राज्य अमेरिका के द्रव्य बाजार में बेक्कर धन प्राप्त करना प्रारंग किया। वैंक की जून १६५० में समाप्त होने वाली वर्ष की रिपोर्ट से विदित है कि मार्च १६५० में वैंक ने रिचस वैंकों और "बैंक फार इएटरनेशनल सेटिलमेंट" को भी अपने बौंड बेचे। जून १६५१ में समाप्त होने वाले वर्ष में वैंक ने पहली बार बिना अपनी गारंकी के अपने ऋणियों कै बौंड, योरोप, कनाडा तथा संयुक्त अमेरिका में बेचे। लंदन के बाजार में भी वैंक ने ब्रिटिश प्रतिभृतियाँ बेचीं।

वेंक ने ३१ मार्च १६५८ तक कुल मिलाकर २ ऋरब ६२ करोड़ ७० लाख डालर के ऋण प्रदान किये बिसमें से २ ऋरब २० करोड़ वास्तव में दे दिये गये हैं। इनमें से ५२ करोड़ ६० लाख डालर के ऋणों का भुगतान वापस मिल गया है तथा कुछ व्यक्तिगत विनियोग दाताऋों ने बैंक से क्रय कर लिया है। कुल ऋणा में से १ ऋरब ८१ करोड़ ३५ लाख डालर का ऋण ऋमेरिकन मुद्रा में दिया गया है। ऋषिकांश ऋण फ्रांस, नीदरलेंड्ज, डेनमार्क, लाक्जम्बर्ग, बेल्जियम, फिनलेंड, टकीं, यूगोस्लेविया, चिली, मेस्किको, ब्राबील, कोलम्बिया, ईराक, पाकिस्तान तथा भारत को दिये गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बेंक द्वारा भारत को ऋगा—बेंक ने भारत को ३ करोड़ ४० लाख डालर का प्रथम ऋण ऐंजिन क्रय करने के लिये १८ ऋगस्त १६४६ की प्रदान किया। यह ऋण ३ प्रतिशत ब्याज पर तथा १ प्रतिशत कमीशन पर १५ वर्ष के लिये लिया गया। १ करोण डालर का दूसरा ऋण उसी ब्याज की दर से ७ वर्ष के लिये मध्य प्रदेश तथा भूपाल में काँसप्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये २६ सितम्बर १६४६ को प्रदान किया गया। १ करोड़ ८८ लाख डालर का तीसरा अप्रगा ४ प्रतिशत ब्याज तथा १ प्रतिशत कमीशन की दर से अप्रेल १६५० में दामोदर घाटी के विकास के लिये दिया गया। चौथा ऋण ३ करोड़ १५ लाख डालर का पौने पांच प्रतिशत ब्याज तथा १ प्रतिशत वमीशन की दर से १५ वर्षों के लिये इंडियन आयरन एएड स्टील कम्पनी को १९५२ में प्रदान किया गया। जनवरी १६५३ में दामोदर घाटी निगम को २५ वर्ष के लिये १ करोड़ ६५ लाख डालर का एक और ऋण अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त हुआ। १६५६ में ७ करोड़ ५० लाख डालर का एक ऋग्ए १५ वर्ष की अवधि के लिये ३३ प्रतिशत ब्याज की दर पर टाटा ग्रायरन एगड स्टील कम्पनी को अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त हुईंग । द्वितीय योजना को सफल बनाने के लिये भारतवर्ष को अधिक पूँजी की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में भारत के वित्त मन्त्री श्री सुरारजी देसाई ने ऋपनी ऋमेरिका यात्रा में बैंक के ऋघिकारियों से ऋगा देने का अनुरोध किया। बैंक ने कुछ कार्यों के लिये अपा देना स्वीकार भी कर लिया है श्रीर श्रपने विशेषज्ञों द्वारा अपा के उद्देश्यों की जांच-पहताल कर रही है।

सन् १९५६ में बैंक ने श्रपने से सम्बन्धित श्रन्तर्राष्ट्रीय विनियोग को बढ़ावा देने के लिये एक श्रन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की । इस बैंक की पूँजी ७ करोड़ ८० लाख डालर है जो ३१ सदस्य देशों द्वारा लगाई गई है । इस निगम द्वारा दिये शृशा के लिये सरकार की जमानत की श्रावश्यकता नहीं है । यह श्राशा की जाती है कि यह निगम व्यक्तिगत पूँजी को भिन्न देशों के उत्पादक कार्यों में लगाने के लिये प्रोत्साहन देगा !

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय वैंक ने अधिकांश ऋण पाश्चान्य देशों को ही प्रदान किये . हैं फिर भी इसका कार्य सराहनीय है। भारत को इस वैंक से पर्यान्त सहायता प्राप्त हो रही है। आज भी भारत में ऐसी कई योजनाएँ विचार वेन हैं जिनके लिये अन्तर्राष्ट्रीय वैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त कानर्राष्ट्रीय वैंक अपने सदस्य देशों के आर्थिक विवादों के शान्तिपूर्वक मुक्तभाने में भी योग प्रदान करती है। भारत, पाकिस्तान का नहरी-पानी विवाद इसी वैंक की अध्यद्धता में मुलभाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

प्रदन

- What is Inter at onal Bank and what are its functions?
 विश्व वैंक क्या है, तथा वह क्या कार्य करती है?
- 2. Describe the constitution and working of the World Bank. विश्व वैंक के विधान एवं कार्यों का वर्णन की जिसे।
- 3. What help do you expect for India from the International Bank for Development and Reconstruction? To what extent this help has been extended to this country?

अन्तर्देशीय विकास एवं पुनर्निर्माण वैंक से भारत के लिये आप किस सहा-यता की आशा करते हैं ? भारतवर्ष को यह सहायता कहाँ तक प्रदान की गई है ?

ग्रध्याय १०

सहकारी बेंक

(Co-operative Banks)

भारतवर्ष का कृषक सदा से ही निर्धन रहा है क्योंकि भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर है। वर्षा न होने से भारतीय कृषक पर संकट आ जाता है। उसे अपना समस्त कार्य भूग्या लेकर चलाना पड़ता है। भारतीय कृषक के पास कृषि करने के लिये बहुत कम जमीन है। जैसे जैसे कुटुम्ब बढ़ता है वैसे-वैसे जमीन कम होती चली खाती है तथा कृषक को खेत में वर्ष में १५० दिन कार्य करना पड़ता है और शेष समय कुछ अन्य घंघा न होने के कारण व्यर्थ ही नष्ट करना पड़ता है। निर्धन होने के कारण भारतीय कृषक अच्छे औजार, अच्छे बीज तथा अच्छे खाद का प्रबन्ध नहीं कर सकता। फलतः कृषि में उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है। जो कुछ होती भी है उसके बेचने का उचित प्रबन्ध नहीं है। अतः निर्धन कृषक को परिश्रम द्वारा कमाई हुई उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। इन सब कारणों से कृषक की आर्थिक अवस्था सदैव अच्छी नहीं रही है तथा उसे अपना कार्य भूग्या लेकर चलाना पड़ता है।

कृषि के लिये तीन प्रकार के ऋगों की आवश्यकता होती हैं:-

- (१) थोड़े समय के लिये कृषक खाद तथा बीज को क्रय करने के लिये, आवपाशी तथा लगान चुकाने के, लिये गृह संबंधी व्यय के लिये थोड़े समय को ऋण् लेता है। यह ऋण् प्राय: ६ मास से लेकर १ वर्ष तक के लिये लिया जाता है।
- (२) साधारण समय के लिये—पशुस्रों के क्रय करने, कृषि सम्बन्धी श्रधिक मूल्य के यंत्रों तथा श्रीजारों को क्रय करने तथा भूमि सुधार के लिये १ वर्ष से ३ वर्ष तक के लिये ऋण की श्रावश्यकता होती है।
- (३) लंबी श्रविध के लिये—पशुत्रों के क्रय करने, पुराने ऋण चुकाने, कुत्रों इत्यादि बनाने के लिये ३ वर्ष से २० वर्ष तक के ऋग की आवश्यकता होती है।

ऋण मिलने के साघन—कृषक को भिन्न प्रकार के ऋण मिलने के साधन केवज प्रामीण साहूकार सरकारी तकावी ऋण, सहकारी साख समिति तथा भूमि बंधन वैंक है। साहूकार—भारतवर्ष के प्रत्येक प्राम में महाजन ऋषवा साहूकार होता है जो लेन-देन का कार्य करता है। इन पेशेवर महाजनों तथा संहूकारों के ऋतिरिक्त ऋौर बहुत से गैर पैशेवर लोग, जैसे अमीदार, नौकरी करने वाले, व्कील तथा व्यापारी इत्यादि भी ऋषा देते हैं। जिसके पास योजा सा भी घन संग्रह हो जाता है वहीं लेन-देन करने लगता है।

ग्रामों का पेशेवर साहकार अथवा महाजन छोटी-मोटी रकम का आगा अपनी बही में लिखकर देता है। उसकी न कोई साची होती है, किन्तु बब रकम अधिक होती है तो प्राप्तिसरी नोट लिख लिया जाता है। वे कृपक को बिना किसी जमानत के इस आधार पर ऋण देते हैं कि ऋणी क्राक अपनी पैदाबार की महाबन की बेच देगा श्रथवा महाजन द्वारा बेचेगा । एक अकार मे यह फ़सल को गिरवी रख लेना है किन्त रकम जब अधिक होती है तो भूमि, गहने तथा मकान बंधक रख दिये जाते हैं। महाजन को इस बात की कोई चिन्ता नहीं होतों कि कृपक किस कायं के लिये ऋण ले रहा है। उत्पादक कार्य अथवा विवाह-शादी जैसे अन्य अनुत्पादक कार्यी के लिये ऋण लेता है इससे महाजन को कोई सम्बन्ध नहीं होता। ऋण सम्बन्ध सुविधाओं के लिये ग्रामीण साहकार ही केवल कृषकों का सहायक है। यह बिना जमानत के हर समय ऋण देने को प्रस्तुत रहता है। यह तो ठीक ही है कि वह ऋषिक व्याज लेता है, परन्तु फिर भी कुषक की स्त्रावश्यकतास्त्रों को बिसे कोई दूनरा पूरा करने के लिये वैयार नहीं है, पूरा कर ही देता है। साहूकार ही एक ऐसा ऋखदाता है जो सकट काल में भी अपने ऋगी की सहायता करता है। अतः साहकार प्रामीण साख में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साह्कारों का पूर्ण ऋध्ययन एक प्रथक ऋध्याय में किया जायेगा ।

सरकारी तकावी ऋण — भारतवर में राज्यीय सरकारें कृपक को लम्बे समय के लिये तकावी ऋण १८८३ के भूमि सुधार कानून के अंतर्गत दिया जाता है। श्रीर थोड़े समय के लिये तकावी ऋण १८८३ के भूमि सुधार कानून के अंतर्गत दिया जाता है। पहले कानून के अंतर्गत भूमि सुधार करने, कुँ आ लोदने अथवा बाँध बनाने के लिये लम्बे समय के लिये ऋण दिन कार है। तथा दूसरे कानून के अंतर्गत खेतीबारी के लिये, उदाहरणतः - बीज, खाद, इल, बैल, खाद इत्यादि क्रय करने के लिये थोड़े समय के लिये ऋण दिना जाता है। पहले कानून के अनुसर ऋण अधिक से अधिक ३५ वर्षों के लिये दिया जाता है। पहले कानून के अनुसर ऋण अधिक से ऋषिक ३५ वर्षों के लिये दिया जाता। दूसरे कानून के अंतर्गत ऋण एक अथवा दो वर्ष के लिये दिया जाता है तथा फसन तैयार होने पर प्राप्त कर लिया जाता है। इन दोनों कानूनों के अंतर्गत स्व प्रान्तीय सरकारों होने पर प्राप्त कर लिया जाता है। इन दोनों कानूनों के अंतर्गत स्व प्रान्तीय सरकारों

द्वारा दिये गये ऋगा की रकम कमशा: ३५ लाख श्रीर ६० लाख रुपये वार्षिक होती है। भारत जैसे विशाल देशों में इतना कम ऋगा लिया जावे, इस बात को सिद्ध करता है कि यह ऋगा श्रिषक श्राकर्षक नहीं है तथा कृषक सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का उपयोग नहीं करते। इसके निम्नलिखित कारण हैं:—

कृषकों की आवश्यकता को देखते हुए ऋण बहुत कम दिया जाता है। जब कृषक ऋण के लिये प्रार्थनापत्र देता है तो उसे महीनों प्रतीचा करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उसे ऋण मिलता है। यद्यपि व्याज बहुत रचित दी जाती है (६ प्रतिशत) परन्तु तहसील के कर्मचारी जो ऋण देने का कार्य करते हैं वे कृषक से उत्कोच और नजराना लेकर उनके प्रार्थनापत्र पर सिफारिश करते हैं। अतएव कृषक को ६ प्रतिशत से बहुत अधिक देना पड़ता है। ऋण को प्राप्त करने में बहुत अधिक कठोरता का व्यवहार किया जाता है। कभी-कभी कृषक को महाजन से ऋण लेकर तकावी का रुपया जुटाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह ज्ञान कि तकावी किस प्रकार ली जाती है, अधिकांश कृषकों को नहीं है। इस कारण तकावी ऋण का भारतीय कृषकों ने अधिक उपयोग नहीं किया।

यदि ऋण का प्रवन्ध ठीक प्रकार से हो, ऋण लेने वाले को ऋषिक समय तक प्रतीचा नहीं करनी पड़े, उसे तहसील के कर्मचारियों को उत्कोच तथा नजराना न देना पड़े, यदि फसल नष्ट हो जावे तो वस्ती रोक दी जाये, तकावी के प्राप्त करने में कम कठोरता व्यवहार में लाई जावे, तकावी किस प्रकार मिलती है इसका ज्ञान ऋषक को दिया जावे तथा सरकार यथेष्ट रकम ऋण देने लगे तो इसका ऋषिक उपयोग हो सकता है। नहीं तो तकावी ऋणों का प्रामीण साल में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।

सहकारी साख समितियाँ—कृषकों की ऋण समस्या को सुलक्काने के लिये तथा उनकी ऋार्थिक उन्नति के लिये १६०४ में एक कानून पास करके सरकारी साख समितियाँ स्थापित करने का कार्य प्रारम्म किया गया। उक्त कानून में कुछ दोषों को दूर करने के लिये १६१२ में एक नवीन सहकारी संविधान बना दिया गया तथा उसके ऋंतर्गत बहुत से स्थानों पर प्रारंभिक साख समितियाँ स्थापित कर दी गई जो देश में कुषकों तथा अत्रन्थ छोटे छोटे व्यक्तियों की उचित सेवायें कर रही हैं। ग्राम में चालू होने वाली एक प्रारंभिक साख समिति का विधान तथा कार्यों का वर्णन नीचे दिया जाता है:—

प्रायः एक ग्राम में एक ही साख समिति स्थापित की जाती है। समिति का प्रवन्ध करने का ऋषिकार साधारण समा तथा प्रवन्य कारिणी समिति ऋर्थात् पंचायत को होता है। साधारण सभा सब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ऋपना मत स्पष्ट देती है। और पंचायत साधारण समा की आशा का पालन करती है। वस्तुतः साधारण समा केवल नीति निर्धारित करती है और पंचायत द्वारा कार्य करती है।

प्रबन्धकारिग्री समिति निम्नलिखित कार्यं करती है :---

- (१) सब सदस्यों को ऋंश देती है और समिति का सदस्य बनाती है।
- (२) यह प्राम में जमा संग्रह करने का प्रयत्न करती है तथा सेन्ट्रल तथा जिले के सहकारी बैंक से ऋण लेने का प्रयत्न करती है।
- (३) वह यह भी निश्चय करती है कि किन सदस्यों को कितने समय के लिये रुपया उघार दिया बावे । साथ ही उस अवधि के अंत में अनुष के रुपयों को प्राप्त करती है ।
- (४) यह समिति के ऋाय-व्यय का लेखा रखती है और सहकारिता विभाग के रिजस्ट्रार से लिखा-पढ़ी करती है।
- (५) यह उन सदस्यों के लिये जो सम्मिलित रूप से आवश्यक वस्तुओं को क्रय करना चाहते हैं, तथा खेती की पैदावार को बेचना चाहते हैं, दलाल का काम करती है।
- (६) यह सदस्यों में मितव्ययता का प्रचार करती है नथा ऋग्नी बचत को जमा करने के लिये प्रोत्साहित करती है। यह सरपंच तथा मंत्री का चुनाव करती है। सरपंच समिति के कार्य की देखमाल करती है तथा मंत्री समिति का हिसाब खता है।

सिमिति प्रवेश फीस, श्रंशों का मूल्य, डिपाजिट तथा शृख के द्वारा कार्यशील पूँ जी संग्रह करती है। रिव्ति कोष सभी सिमिति की कार्यशील पूँ जी को बदाता है। प्रवेश फीस नाम मात्र की होती है जो सिमिति की स्थापना में होने वाले व्यय के लिये ली जाती है। कुछ प्रान्तों में श्रंश होते ही नहीं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, तथा मद्रास में साख सिमितियाँ श्रंशवाली होती हैं। श्रन्य प्रान्तों में श्रंश तथा श्रंश रहित दोनों ही प्रकार की सिमितियाँ हिटगोचर होती हैं।

भारतवर्ष में सिमितियाँ ऋंशवाली तथा ऋंश रहित होनी चाहिये यह प्रश्न विचारणीय है। कुछ विद्वानों का मत है कि सिमितियाँ ऋंशवाली होनी चाहिये क्योंकि ऋंशों को बेचकर, थोड़ी कार्यशील पूँची इकट्टी कर ली बाती है। सिमिति ऋपनी पूँची सदस्यों को ऋृण स्वरूप देकर उन पर लाम उठाती है तथा प्रत्यच्च रूप से रिच्चित कोष की वृद्धि होती है। सदस्य सिमिति के कार्यों में विशेष रुचि से माग लेते हैं क्योंकि वे सिमिति को ऋपनी वस्तु समफते हैं। यह सब ठीक है परन्तु भारत के प्रामों में इतनी निर्धनता है कि ईमानृदारी परिश्रमी को ऋंश का मृत्य चुकाने में कठिनाई हो सक्ती है तथा वह सिमिति की सदस्यता से वंचित रह सकता है। इस कारण कुछ प्रान्तों में तो श्रंश होते ही नहीं तथा जहां होते भी हैं बीस रुपये से श्रिषक नहीं होते जिन्हें सदस्य घीरे घीरे चुकाता है।

साल सिमिति का कोई भी सदस्य एक निश्चित रकम से श्रिधिक के श्रंश क्रय नहीं कर सकता । प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट देने का श्रिषकार होता है। प्रवेश फीस तथा श्रंशों के मूल्य से सिमिति के पास नाम-मात्र की पूँची इकट्ठी होती है। इस कारण सिमितियाँ श्रिधिकतर सहकारी श्रथवा जिला सहकारी वैंकों से श्रृण लेकर काम चलाया करती हैं। भारत में सहकारी साख सिमितियाँ श्रभी तक दिपाजिट श्राकर्षित करने में सफल नहीं हुई। वास्तव में कोई साख सिमिति जितनी ही श्रिधिक दिपाजिट श्राकर्षित करे वह उतनी ही सफल समभी जानी चाहिये, क्योंकि दिपाजिट तमी जमा होगी जब कि जनता को सिमिति का विश्वास होगा। भारतवर्ष में बम्बई प्रान्त को छोड़कर श्रन्य किसी प्रान्त में श्रभी तक साख सिमितियाँ दिपाजिट श्राकर्षित नहीं कर पाई हैं। साख सिमितियाँ उन लोगों से भी दिपाजिट स्वीकार करती हैं जो सिमिति के सदस्य नहीं होते। सिमिति के पंचों को कोई वेतन नहीं मिलता। केवल मन्त्री को यदि वह सदस्य हो तो थोड़ा सा वेतन दिया जाता है।

सहकारी साख सिमितियों की स्थापना लाम की दृष्टि से नहीं की जाती। ख्रतः क्रपिरिमित दायित्व वाली सिमितियों का लाम तो बाँटा नहीं जाता ख्रीर यदि बाँटा भी जाता है तो जब रिच्चित कोष पूँजी के बराबर हो जाता है तब प्रान्तीय सरकार से ख्राजा लेकर बाँटा जाता है। परिमित दायित्व वाली सिमितियों में लाम बाँटा जा सकता है। किन्तु उनको भी यथेष्ट धन रिच्चित कोष में जमा करना पड़ता है।

सहकारी साल समितियों का प्रबन्ध-व्यय बहुत कम होने के कारण तया लाम न बँटने के कारण रिच्चत कोष यथेष्ट जमा हो जाता है। प्रत्येक साल समिति के लिये रिच्चत कोष ब्रात्यन्त ब्रायश्यक है। रिच्चत कोष किसी भी ब्रायस्था में सदस्यों में बाँटा नहीं जा सकता। उसका उपयोग समिति के कार्यों में हानि होने पर उसे पूरा करने में होता है। यदि किसी देनदार से रुपया प्राप्त नहीं होता श्रथवा किसी वस्तु को बेचने में हानि हो तो उसको रिच्चत कोष से पूरा किया जाता है। यदि साल समिति मंग हो जाने तो रिच्चत कोष या तो किसी ब्रान्य सहकारी समिति को दे दिया जायेगा श्रथवा सहकारिता विमाग के रिजस्ट्रार की श्रानुमित से प्राम सार्वजनिक हितकर कार्य में व्यय किया जायोगा। श्रपरिमित दायित्व वाली समितियाँ रिच्चत कोष के धन को निजी कार्य में लगाती हैं। बाहर जमा नहीं करतीं।

क धन की निजा कार्य में लगाती है। बाहर जमा नहीं करता। यदि किसी समिति को हानि हो आये तो सर्व प्रथम उस्म सदस्य से रूपया प्राप्त किया जायेगा जिसने ऋगा लिया है। यदि उससे प्राप्त न हुन्ना तो रिच्ति कीष से हानि भर दी बायेगी। यदि उससे मी हानि पूरी न हुई तो समिति की पूँबी का उपयोग किया बायेगा। यदि समिति की पूँबी देकर भी हानि पूरी न हो सके तो समिति के सदस्यों को समिति के लेनदारों का रूपया चुकाना होगा। प्रत्येक सदस्य को कितना काया देना होगा इसका हिसाब Liquidater सगायेगा। व्यवहारिक हिट से अपरिमित दायित्व से यही अर्थ निकलता है। किन्तु सिदान्त से प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से सारे अप्रया को चुकाने के लिये बाब्य है। यह उसी दशा में हो सकता हैं जब अन्य सदस्यों से रूपया प्राप्त न हो सके।

साधारण सभा अपनी मीटिंग में समिति की सास निर्धारित कर देती है। पञ्चायत उससे अधिक ऋणा नहीं ले सकती। समिति की सास को निर्धारित करने के लिये यह आवश्यक है कि समिति के सदस्यों की सम्पत्ति का एक-नौयाई से आधी तक सास निर्धारित की जाती है। समिति इस कार्य के लिये एक हैसियत रिबस्टर रखती है जिसमें प्रत्येक सदस्य की हैसियत का लेखा रहता है। इस रिबस्टर का प्रतिवर्ध संघोधन होता है तथा प्रत्येक सदस्य की हैसियत का यथार्थ लेखा रखने का प्रयत्म कि याजाता है।

इसके श्रांतिरिक यह भी निश्चित कर दिया बाता है कि प्रत्येक सदस्य श्राधिका-धिक कितना रुपया उघार ले सकता है। किसी भी दशा में सदस्य की सम्पत्ति का ५० प्रतिशत से श्रिधिक ऋण नहीं दिया बाता। रुपया उघार देने के समय पञ्चायत ऋख लेने का उद्देश्य तथा सदस्य की चुकाने की शक्ति का श्रनुमान लगा कर ही ऋण देने का निश्चय करती है।

सहकारी साख त्रान्दोलन का यह सिद्धान्त है कि ऋण त्रानुत्पादक तथा व्यर्थ कार्यों के लिये न दिया जाये। किन्तु भारत में सहकारी समितियाँ त्रानुत्पादक कार्यों के लिये विशेषकर धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों के लिए ऋण देती हैं। पञ्चायत का यह मुख्य कर्त्तव्य है कि वह इस बात की जाँच करे कि सदस्य ऋण किस कार्य के लिये ले रहा है। साथ ही पञ्चायत को इस बात का भी पता लगना चाहिये कि सदस्य ने उसी कार्य में घन व्यय किया ऋथवा नहीं। यदि सदस्य ने किसी अन्य कार्य में घन व्यय किया है तो पञ्चायत को रुपया वापस ले लेना चाहिये, परन्तु भारतवर्ध में इस ऋगेर पञ्चायत कभी भी ध्यान नहीं देती। कृषि के लिये धन दिया जाता है तथा व्यय होता है अनुत्पादक कार्यों पर। किन्तु पञ्चायत कभी भी रोक-टोक नहीं करती। पञ्चायत ऋण देते समय सदस्य की स्थिति को घ्यान में रख कर किश्तें बाँध देती है, क्योंकि सदस्यों को किश्तों में रुपया चुकाने में सुविधा होती है। पञ्चायत का यह मुख्य कार्य है कि वह सदस्य से समय-समय पर किश्त प्राप्त करे।

केन्द्रीय बैङ्क तथा चैं किंग यूनियन—१९१२ के सहकारिता कानून के झंतर्गत केन्द्रीय चैंक स्थापित करने की सुविधायें दी गई।

केन्द्रीय बैंक दो प्रकार की होती हैं :—(१) ऐसी केन्द्रीय बैंक जिनके सदस्य केवल समितियाँ हो हो सकती हैं, उन्हें बैंकिंग यूनियन भी कहते हैं। ऐसी केन्द्रीय बैंक जिनके सदस्य व्यक्ति तथा समितियाँ दोनों ही होते हैं। बैंकिंग यूनियन वास्तव में आदर्श सहकारी बैंक हैं। समितियाँ इन बैंकों की नीति को निर्धारित करती हैं तथा बैंक का प्रबन्ध भी उन्हों के हाथ में रहता है। इन बैंकिंग यूनियनों की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि समितियों के सदस्य योग्य तथा प्रभावशाली व्यक्ति हों। यही कारण है कि बैंकिंग यूनियन संख्या में अधिक नहीं है। दूसरे प्रकार की केन्द्रीय बैंक ही अधिक हैं। इस प्रकार केन्द्रीय बैंकों में योग्यता और व्यापारिक कुशलता की हिंद से कुछ योग्य व्यक्तियों को लेने की सुविधा रहती है।

केन्द्रीय बैंक का च्रेत्र प्रत्येक प्रान्त में भिन्न होता है, उस च्रेत्र की सहकारी समितियाँ उसी बैंक से ऋण लेती हैं। दिच्चणी तथा पश्चिमी भारत में केन्द्रीय बैंक का च्रेत्र श्रिषकतर एक तहसील होती है। इस कारण इन प्रान्तों के केन्द्रीय बैंकों से सम्बन्धित समितियों की संख्या तथा पूँजी कम होती है।

बैंकिंग यूनियन में केवल समितियाँ ही श्रंश खरीद सकती हैं किन्तु केन्द्रीय बैंकों में व्यक्ति भी श्रंश कय कर सकते हैं। साधारणतया केन्द्रीय बैंकों के श्रंश ५० रुपये से लेकर १०० रु० तक के होते हैं। समितियाँ श्रपने ऋण के श्रनुपात में श्रंश लेती हैं। साधारणतया श्रंशधारियों का दायित्व श्रंशों के मूल्य तक ही सीमित हैं किन्तु कुछ प्रान्तों में श्रंशधारियों का दायित्व चार गुने से लेकर दस गुने तक है। कानून के श्रनुसार प्रत्येक परिमित दायित्व वाली समिति को २५ प्रतिशत लाम रिक्त कोष में जमा करना होता है। केन्द्रीय बैंक इस २५ प्रतिशत के श्रतिरिक्त श्रन्य कार्यों के लिये विशेष कोष जमा करते हैं।

त्रंश पूँची तथा रिच्त कोष तो बैंक की निजी पूँची होती है, त्रीर डिपाजिट तथा उचार ली हुई पूँची होती है, भारत के प्रत्येक प्रान्त में निजी पूँची तथा ऋष ली हुई पूँची का अनुपात १:८ है।

सदस्यों तथा गैर सदस्यों की डिपाजिट ही कार्यशील पूँजी का बड़ा माम होती है। केन्द्रीय बैंक में दो प्रकार की ड्रिपाजिट होती है—मुद्दती तथा सेविंग्स। अधिकतर केन्द्रीय बैंक चालू खाता नहीं रखर्ती । कुछ प्रान्तों में रखती भी हैं। चाल खाता जोखिम का काम है। उसके लिये संचालकों में यथेष्ट व्यापारिक कुशलता होनी चाहिये । केन्द्रीय वैंकों के पास निजी पूँजी भी बहुत कम होती है। इस कारण भी बहु वेंक सफलतापूर्वक चालू लाता नहीं रल सकतीं। कहीं-कहीं सेविंग्स डिपाजिट भी नहीं ली जाती। किन्तु अधिकतर यह वैंक सेविंग्स डिपाजिट लेती हैं। इन वैंकों में अधिक-तर सहती जमा ली जाती है। यह अधिकतर एक वर्ष के लिये जमा लेती हैं। केवल विहार-उड़ीसा में यह नियम है कि चाहे जब रुपया जमा किया जावे। ३१ मई को रुपया वापस दे दिया जाता है। केन्द्रीय वैंकों में अधिकतर जमीदार, नौकरी करने वाले तथा संस्थायें ही रुपया जमा करती है।

डिपाजिट के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर बैंक अपूर्ण भी लेती है। केन्द्रीय बैंक, स्टेट बैंक आदि दूसरी बैंकों से तथा प्रान्तीय सरकारी बैंक से भी अपूरण लेती हैं। पख़ाब को छोड़ कर केन्द्रीय बैंक प्रान्तीय सरकार से सीधे अपूरण नहीं लेती किन्तु देशी राज्यों में केन्द्रीय बैंक राज्य से ही अपूर्ण लेती हैं। के बल मैस्र में बैंक राज्य से अपूरण नहीं लेती।

केन्द्रीय बैंक सरकारी कागज तथा प्रारम्भिक साख समितियों के प्राप्तिमक साख की जमानत पर ऋण लेती हैं। कुछ समय से स्टेट बैंक ने प्रारम्भिक सरकारी समितियों को प्राप्तिसरी नोट पर ऋण देना बन्द कर दिया है और केवल सरकारी कागज पर ही ऋण देती है, क्योंकि सहकारी समितियों की ऋण्यिक दशा शोचनीय है। जहाँ प्रान्तीय सहकारी बैंक स्थापित हो चुकी हैं वहाँ केन्द्रीय बैंक अन्य मिश्रित पूँची वाली व्यापारिक बैंकों तथा दूसरी केन्द्रीय बैंकों से सीधा संबन्ध नहीं रख सकतीं।

केन्द्रीय बेंक केवल सहकारी साख समितियों को ही ऋण देती है। व्यक्तियों को ऋण नहीं देती। सहकारी समितियों के पास जमा करने के लिये ऋषिक पूँजी तो होती नहीं, इस कारण बैंक समितियों को ऋण देने का ही कार्य ऋषिक करती है।

यह जानने के लिये कि प्रत्येक सहकारी साख समिति को श्रिषिक से श्रिषिक कितना श्रुण देना उचित है केन्द्रीय बैंक अपने से संबन्धित साख समितियों की साख का अनुमान लगाती हैं। जो श्रुण साख समितियों को दिया जाता है वह निश्चित वधों में प्राप्त कर लिया जाता है। श्रुण की स्वीकृति देने में बहुत की कान्नी कार्यवाही करनी पड़ती है, अतः श्रुण प्राप्त होने में विलंब हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिये कुछ केन्द्रीय बैंक एक रकम निश्चित कर देती हैं। उस सीमा तक समितियों को बिना किसी विलंब के श्रुण दे दिया जाता है। श्रिषक रकम के लिये नियमित कार्यवाही करनी एड़ती है, कुछ प्रांतों में समितियों की सामान्य साख निर्धारित कर दी जाती है। समिति की सामान्य साख निश्चित करने से पूर्व उसके सदस्यों की सम्पत्ति,

उनकी त्रावश्यकता, उनकी त्राय तथा उनकी बचाने की शक्ति का ब्यौरा रहता है। इस लेखे के त्राघार पर वैंक समिति की ऋषिकतम साख निर्घारित कर देती है।

केन्द्रीय बैंक मिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न समय के लिए ऋण देती है। फसल उत्पन्न करने के लिये जो ऋण लिया जाता है वह एक-दो वर्षों के लिये होता है और जो ऋण भूमि में सुवार के लिये ऋयवा पुराने ऋण को चुकाने के लिये दिया जाता है वह ५ से १० वर्षों के लिये होता है। ऋज यह धारणा प्रत्येक प्रांत में बल पकड़ती जाती है कि केन्द्रीय बैंक ऋषिक समय के लिये ऋण नहीं दे सकती। इसके लिये भी बन्धक बैंक स्थापित करनी चाहिये।

केन्द्रीय बैंक श्रमी तक द से १२ प्रतिशत ब्याज समितियों से लेती रही हैं। जब बाजार में ब्याज की दर बहुत घट गई तब इन बैंकों ने दर घटाई। श्रव यह प्रयत्न किया जा रहा है कि ब्याज की दर श्रीर घटाई जावे। भारतीय सहकारिता श्रांदोलन की सबसे बड़ी कभी यह है कि समितियाँ श्र्मण को उचित समय पर नहीं चुकार्ती श्रीर बहुत सा रुपया शेष रह जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सदस्य श्रश्चित हैं, सहकारिता के सिद्धांतों का उन्हें ज्ञान नहीं, वे श्रत्यंत निर्धन हैं। कभी-कभी फसल के नष्ट हो जाने के कारण वे श्र्मण भे नहीं चुका पाते। यदि फसल नष्ट हो जाने से सिमितियाँ श्रपना श्रमण नहीं चुकार्ती तो बैंक जहाँ तक हो सकता है रुपया प्राप्त करती है। यदि रुपया किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं होता तो बैंक रिजस्ट्रार से सिमिति को तोड़ देने के लिये कहता है श्रथवा न्यायालय से डिग्री करवाता है।

जब सिमितियाँ केन्द्रीय बैंक को ऋण का रुपया चुकाती है उस समय बैंक के पास श्रिष्ठिक रुपया जमा हो जाता है। यह स्थिति वर्ष में दो-चार मास तक रहती है। इस समय केन्द्रीय बैंक प्रांतीय सहकारी बैंकों में रुपया जमा कर देती है, जहाँ प्रांतीय बैंक नहीं है वहाँ इम्पीरियल बैंक में रुपया जमा कर दिया जाता है, इसके श्रितिरिक्त बैंक के पास कुछ रुपया स्थायी रूप से श्रिष्ठिक होता है जो समितियों को अगुण देने में नहीं लगाया जा सकता। यह कोष प्रांतीय बैंक में श्रिष्ठिक समय के लिये जमा कर दिया जाता है अथवा द्रस्टी प्रतिमृतियों में लगा दिया जाता है। इस समय केन्द्रीय बैंकों की नीति यह है कि के आवश्यकता से श्रिष्ठिक डिपाजिट नहीं लेना चाहती। अतः हिपाजिट पर न्याज की दर बहुत घटा दी गई है।

सहकारिता श्रांदोलन की बाँच के लिये बिटाई गई मैकलेगन कमेटी ने केन्द्रीय बैंकों को नकदी रखने की श्रावश्यकता इस प्रकार बतलाई थी—जिन बैंकों में चालू खाता तथा सेविंग्स बैंक खाता दोनों ही हों उन्हें चालू खाते की रकम तथा बचत की ७५ प्रतिश्रत रकम नकदी श्रथवा प्रतिभृति में रखनी चाहिये जो दुरंत ही नकदी में परिश्वत की जा सके। मुद्दी जमा के लिये कमेटी का सम्मिति यह है कि जो डिपाजिट अगले १२ मास में देनी हो उसकी आधी रकम नकदी में रहे। किन्तु इस नियम के अनुसार कहीं भी कार्य नहीं होता। प्रायः नकदी इससे बहुत कम रहती है।

• केन्द्रीय बैंक प्रति वर्ष वार्षिक लाम का २५ प्रतिशत राइत कीय में बमा करके शेष अंशघारियों में विभाजित कर सकते हैं किन्तु केन्द्रीय बैंकों के उपनियमों में अधिक से अधिक लाम की दर निश्चित कर दी जाती है बिससे अधिक लाम और प्राप्ति में नहीं विभाजित किया जा सकता।

केन्द्रीय बैंक ६ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक लाम बाँटने हैं। अधिकतर प्रांतों में ६ प्रतिशत लाम भी बाँटा जाता है। साधारण रच्चित कोप के अतिरिक्त कोई-कोई केन्द्रीय बैंक इमारत, बहीखाता तथा लाम-हानि संतुलन के लिये, विशेष कोष जमा करते हैं। रच्चित कोष का स्पया तो प्रतिभृतियों में अथवा प्रांतीय हैं को में लगा दिया जाता है अथवा वह बैंक में ही रहता है और कार्यशील पूँजी की शृद्धि करता है।

केन्द्रीय बैंकों की ब्याज की दर मिन्न मिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न है किन्तु हिपा-जिट पर ब्याज की दर तथा प्रारम्भिक समितियों में जो ब्याज ली जाती है उसमें २ से प्रप्रतिशत तक का अंतर रहता है।

केन्द्रीय बैंक अपने से संबन्धित समितियों की देखभाल रखते हैं तथा उन पर अपना नियत्रण भी रखते हैं। इस कार्य के लिये उन्हें कुछ, कर्मचारी रखने पड़ते हैं। ये कर्मचारी ऋण के लिये आये हुए प्रार्थनापत्रों की बाँच करते हैं। बो समितियाँ अपने पुराने ऋण को चुकाने के लिये अधिक समय माँगती हैं, उनके प्रार्थनापत्रों की बाँच करते हैं और समिति को सदस्यों से स्पया प्राप्त कराने में सहायक होते हैं।

प्रांतीय सहकारी वैङ्क अथवा सर्वोपिर वैङ्क —देश में सहकारिता आन्दोलन के क्रमशः फैलने पर अनुमान होने लगा कि केवल केन्द्रीय वैङ्क, आन्दोलन के लिये जितनी पूँजी की आवश्यकता होती है, उसका उचित प्रक्रव नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वैङ्कों का नियंत्रण तथा उनके द्वारा साख समितियों के लिये आवश्यक पूँजी का प्रवन्ध करने के लिये भी प्रान्तीय वैंकों की आवश्यकता प्रतीत हुई। मैकलेगन कमेटी ने जो १६१५ में सहकारिता आन्दोलन की जाँच करने के लिये बिठाई गई थी, प्रत्येक प्रांत में केन्द्रीय वैङ्कों का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये ऐसी संस्था की अत्यन्त आवश्यकता बतलाई गई थी। प्रांतीय वैङ्कों से पूर्व यह कार्य रिजस्ट्रार करता था। यदि किसी केन्द्रीय वैङ्क को पूँजी की अधिक आवश्यकता होती तो रिजस्ट्रार स्वना पाने पर प्रान्त की प्रत्येक केन्द्रीय वैंक को गश्तीपत्र लिख देता था। पर इससे रिजस्ट्रार का उद्देश्य धीक प्रकार से पूरा नहीं होता था और साथ ही उसका बहुत-सा समय इस कार्य में लग जाता था। कुछ केन्द्रीय वैंक ऐसी थीं, जो अपनी आवश्यकता

से अधिक पूँ जी आकर्षित कर लेती थीं श्रीर कुछ ऐसी भी थीं जिनको यथेष्ट पूँजी नहीं मिल पाती थी। श्रतः ऐसी प्रान्तीय बैंड्डों की आवश्यकता थी जो पहले प्रकार की बैंकों की अतिरिक्त पूँजी को जमा करें और दूसरे प्रकार की बैंकों को पूँजी दें। इसके अति-रिक्त द्रव्य बाजार तथा सहकारिता आन्दोलन के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिये भी प्रान्तीय बैंकों की आवश्यकता हुई।

प्रान्तीय बैक्क तथा केन्द्रीय बैक्क — प्रान्तीय सहकारी बैंकों तथा केन्द्रीय बैंकों का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न है। वे केन्द्रीय बैंकों पर कोई नियंत्रण नहीं रखतीं। केन्द्रीय बैंक अपना रुपया प्रायः प्रान्तीय बैंकों में अथवा सुदृढ़ व्यापारिक बैंकों में जमा करती हैं। मद्रास प्रान्त में केन्द्रीय बैंक अपना सारा रखित कोष प्रान्तीय सहकारी बैंकों में जमा करती हैं। बम्बई प्रान्तीय बैंक सहकारी संस्थाओं की मुद्दती जमा पर व्यक्तियों से अधिक ब्याज देती है, यहां प्रान्तीय बैंक के नेतृत्व में बम्बई सहकारी बैंक ऐसोसिएशन स्थापित की गई है जो केन्द्रीय बैंकों को सम्बद्ध करती है। मद्रास प्रान्तीय बैंक केन्द्रीय बैंकों का वार्षिक सम्मेलन करती है जिसमें उन बैंकों की नीति और उनके सम्बन्ध में विचार होता है। मद्रास प्रान्तीय बैंक ने सम्बन्धित केन्द्रीय बैंकों का अपने संचालकों द्वारा निरीच्या करने की परिपाटी पहले ही स्थापित कर दी थी। किन्तु अब मद्रास सहकारिता कानून के अनुसार उसके कर्मचारी उन बैंकों का निरीच्या कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में भी प्रान्तीय बैंक अपने निरीच्यक द्वारा सम्बन्धित केन्द्रीय बैंकों का निरीच्या करता है।

उन सभी प्रान्तों में जहाँ प्रांतीय बैंक स्थापित हैं केन्द्रीय बैंक एक दूसरे को सीधे ऋष्ण नहीं दे सकती। वास्तव में प्रांतीय बैंक का कार्य तो यह है कि वे केन्द्रीय बैंकों के संतुलन केन्द्र का काम करें, उन्हें बैंकिंग, द्रव्य बाजार, ऋण देने ऋौर व्याज की दर निर्धारित करने के संबंध में परामर्श दें। यद्यपि प्रांतीय बैंकों का केन्द्रीय बैंकों पर नियं-त्रण बांछनीय नहीं है, प्रांतीय बैंकों द्वारा उनका नियंत्रण ऋगवश्यक है।

प्रान्तीय बैङ्क तथा सहकारिता विभाग—पिछले दिनों इस प्रश्न को लेकर बहुत खींचातानी रही कि सहकारिता विभाग के रिजस्ट्रार द्वारा बहुत हस्तच्चेप श्रीर कहा नियंत्रण होता है। इससे बड़ी उलमन उत्पन्न होती है। बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय बैंकों में रुपया जमा करने वालों का श्रिष्ठकांश रुपया मारा गया क्योंकि प्रारम्भिक साल समितियों से श्रृण प्राप्त नहीं किया जा सका। वहाँ यह प्रश्न उद्धाया गया कि यह रुपया सरकार दे क्योंकि समितियों को वह रुपया सहकारिता विभाग की सिर्फारिश पर दिया गया था जो सरकार का एजेंट है। बर्मा में प्रांतीय बैंक जब (१६२८-२६) श्रुपने जमा करने वालों का रुपया चुका नहीं सका तो वहाँ की सरकार को ३० लाख रुपया देना पड़ा। इसी प्रकार की स्थिति बंगाल में उत्पन्न हो गई जन

कि सहकारिता विमाग के रिबस्ट्रार ने प्रान्तीय बैंक को जूट विक्रय समितियों को ऋख देने का अनुरोध किया और वे समितियों ऋख न चुका सकी। फलतः सरकार को २४ लाख रुपये प्रान्तीय बैंक की चृति पूर्ति के देने पड़े। उन्नु बंगान, बिहार तथा मध्य प्रदेश और वरार में केन्द्रीय बैंकों को जो भीषण चृति उठानी पड़ी उसे देना सरकार ने स्वीकार नहीं किया। प्रान्तीय बैंक के कार्य में रिजस्ट्रार और उसका विभाग केवल अपना परामर्श प्रान्तीय बैंक को दे। यह भी आवश्यक है कि रिबस्ट्रार बैंक का संचालक न हो। प्रान्तीय बैंक ऋगु देने अथवा न देने का निगाय स्वयं करे।

प्रान्तीय वेद्क तथा रिजर्व वेद्ध—वेंकों श्रीर उनसे सम्बन्धित वेंकों को सरकारी प्रतिभृतियों की जमानत पर नकद साल देती है परन्तु बहाँ तक सहकारी कामज को सुनाने का प्रश्न है, प्रान्तीय वेंक तथा केन्द्रीय वेंक जब रिजर्व वेंक की इन्ह्यन्त स्थानी श्रार्थिक स्थिति श्रीर कारवार को बना लेगे तभी वह उनके सहकारी कामज को सुनाने की सुविधा प्रदान करेगा। इस कार्य के लिये रिजर्व वेंक ने केन्द्रीय वेंकों को प्रान्तीय सहकारी वेंक की शाला मान लिया है। कुछ प्रान्तीय वेंकों ने रिजर्व वेंक की योजना को स्वीकार कर लिया है तथा ये उसमें सम्भितित हो गई हैं। रिजर्व वेंक की प्रान्तीय वेंकों को श्रप्ना लेन देन का लेला एक निश्चित रूप में तैयार करने को कहा है श्रीर कुछ वेंक वैसा भी करने लगी हैं। जैसे-जैसे प्रान्तीय वेंक रिजर्व वेंक की इच्छानुसार श्रपने कारवार करती जार्येगी वैसे ही वैसे पारस्परिक सम्बन्ध धनिष्ट होता जायेगा। यद्यपि रिजर्व वेंक की स्थापना से सहकारी वेंकों को श्रभी तक वे सुविधार्ये नहीं मिली हैं जो वे चाहती थीं, परन्तु श्रव श्राखल भारतीय सहकारी श्रथवा सर्वोपरि वेंक की श्रावश्यकता नहीं रही।

भूमिबंधक बेंद्ध — क्रुषक को साधारण खेतीबारी के कार्य को चलाने के लिये थोड़े समय और मध्यम समय के लिये ऋण की आवश्यकता होती है इसके अंतर्गत वह सभी ऋण आ बाता है जो पशु, बीज, खाद, हल तथा अन्य यंत्र क्रय करने के लिये, लगान देने के लिये तथा अपने कुटुम्ब के पालन के लिये लिया बाता है। इसके अतिरिक्त कृषक को पुराने ऋण को चुकाने के लिये भूमि की चक्चंदी करने तथा उसको उपजाऊ बनाने के लिये, अन्य सुधार करने के उद्देश्य से, भूमि क्रय करने के लिये तथा मूल्यवान यंत्र क्रय करने के लिये अधिक समय के लिये ऋण चाहिये।

ग्राम सहकारी साख सिमितियाँ कृषकों को योड़े समय श्रौर मध्यम समय के लिये ऋग्य देती हैं। जब सहकारिता श्रान्दोलन का श्रीगर्याश हुआ या तब लोगों की घारखा थी कि साख सिमितियाँ अधिक समय के लिये मी ऋग्य दे सकेगीं। श्रारंम में ग्राम्य साख सिमितियों ने श्रिषिक स्पये के लिये ऋग्य दिया भी। किन्द्र न तो साख

समितियों के पास इतनी पूँची थी कि वे सदस्यों के पुराने ऋण को चुका सकें तथा न यह उनके हित में ही थी। इस कारण साख सिमितियों ने ऋधिक समय के लिये प्रमुख लेना बंद कर दिया । सभी प्रान्तीय बैंकिंग जाँच कमेटियाँ तथा विशेषज्ञों की यही सम्मति थी कि अधिक समय के लिये अपूर्ण देना साख समितियों के लिये उचित नहीं है। कारण यह है कि सरकारी केन्द्रीय बैंकों तथा अन्य समितियों में जमा थोड़े रूपरे के लिये ली जाती है श्रीर थोड़े समय के लिये जमा किये हुए रुपये से श्रिधिक समय के लिये ऋषा देना जोखिम से खाली नहीं है। यह वैंकिंग सिद्धान्त के विरुद्ध है। इसके ऋतिरिक्त ऋधिक समय के लिये ऋगा देने में सम्पत्ति की जमानत लेते समय उसके मह्य को ब्राँकने तथा उसे स्वामित्व की जाँच करने के लिये अपने ब्रनुमवी कार्यकर्तात्रों तथा कर्मचारियों की त्रावश्यकता होती है जो प्रामीण समितियों के पास नहीं हैं। इसके अतिरिक्त एक कठिनाई यह भी है कि भूमि बंधक रखने पर उसके सम्बन्ध के कागज ग्राम्य साख समितियों के पास रखने में जोखिम हैं तथा सबसे ऋंतिम कठिनाई यह है कि सदस्यों के ऋण न चुकाने पर समिति की पूँजी फँस जायेगी और समिति को सदस्य के विरुद्ध डिग्री कराकर उस भूमि को नीलाम करवाना होगा। यह सब काम सहकारी समिति सफलतापूर्वक नहीं कर सकती। फिर यदि प्राम्य सहकारी साख समितियाँ भूमि बंघक रख कर लम्बे समय के लिये ऋण दे दें तो व्यक्तिगत साख का महत्व कम हो जाने की सम्भावना रहेगी जो सहकारिता के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। यही कारण था कि केन्द्रीय बैंकिंग जाँच कमेटी, प्रान्तीय बैंकिंग जाँच समितियाँ, रिजर्व वैंक तथा वैंकिंग विशेषज्ञों ने एक मत से यह निर्णय दिया कि लम्बे समय के लिये ऋगा केवल भूमि बंधक बैंक ही दे सकती है। साख समितियों को थोड़े समय तक मध्यम समय के लिये ऋण देना चाहिये। अब साख समितियों तथा केन्द्रीय वैंक लम्बे समय के लिये ऋगा सर्वथा नहीं देतीं। ऐसा ऋगा भूमि बंघक वैंक द्वारा दिया जाता है।

भूमि बंधक बैङ्क का अर्थ — भूमि बन्धक बैङ्क वे संस्थायें हैं जो भूमि को बन्धक रखकर दीर्घकाल के लिये कृषकों को ऋग्ण देती हैं। दीर्घकाल के लिये, पुराने ऋग्ण चुकाने के लिये, भूमि की चकबन्दी और उसे उपजाऊ बनाने के सुधारों के लिये, भूमि क्रय करने के लिये तथा खेतों की चकबन्दी करने के लिये ये बैंक कृषकों को ऋग्ण देती हैं।

सहकारी भूमि बन्धक बैंक केवल ऋपने सदस्यों को ही ऋया देती है। बैंक की ऋपनी निजी पूँजी नहीं होती। जो भूमि बन्धक रख, दी जाती है उस्प्री की जमानत पर बन्धक बौंड बेचे जाते हैं ऋौर उनसे पूँजी प्राप्त की जाती है। सहकारी भूमि बन्धक बैंक लाम को लच्य करके कार्य नहीं करती वरन् न्याब की दर को घटाने का प्रयत्न करती हैं।

गैर सरकारी भूमि बन्धक वैंक मिश्रित पूँची की होती हैं। जिस प्रकार श्रन्य व्यापारिक वैंक लाभ की दृष्टि से स्थापित की खाती हैं दैसे ही ये बैंक भी श्रंशाबारियों की सम्पत्ति होती है तथा लाभ की दृष्टि से चलाई खाती है। कृपक तथा जमींदार श्रपनी भूमि बन्धक रखकर उनसे श्रृण लेते हैं। इस प्रकार मिश्रित पूँची वाली भूमि बन्धक वैंक योरोप में सर्वत्र पाई जाती है किन्तु राज्य उन पर नियंत्रण रखता है जिससे कि वे श्रृण लेने वालों को मनमाने दंग पर लूटने न लगें तथा न्यांच की दर बहुत श्रिषक न रखें। श्रर्थ सरकारी भूमि बन्धन न तो पूर्ण रूप से सरकारी होते हैं और न गैर सरकारी।

भूमि वंधक वैङ्क के कार्य — भूमि को बन्धक रख कर दीर्घकाल के लिये कृषकों को ऋण देती हैं। दीर्घकाल के लिये ऋण निम्मलिखित कार्यों के लिये दिया जाता है:—

- (क) पुराने ऋण चुकाने के लिये।
- (ख) भूमि की चकबन्दी कराने के लिये तथा उसे उपजाऊ बनाने के श्रान्य सुघारों के लिये।
 - (ग) सूमि क्रय करने के लिये
 - (घ) सिंचाई के लिये कुन्ना बनवाने, मूल्यवान यंत्र ऋय करने के लिये।

यह ऋगा पायः ५ वर्ष से २० वर्ष की ऋविष तक ही दिये जाते हैं। व्यवहार में ऋभी तक भूमि बन्धक बैंक केवल पुराने ऋगा को चुकाने के लिये ही ऋगा देते हैं।

मूमि बंधक बैक्कों का प्रवंध— भूमि बन्धक बैंक का संचालन संचालकों के प्रमंडल द्वारा होता है। ऋष लेने वाला कुषक अपने ऋण लेने के क्योरे और अपने भूमि सम्बन्धी कागजों सहित ऋण लेने के लिये भूमि बन्धक बैंक के पास मेब देता है। बैंक का एक संचालक तथा सुपरवाइजर मूमि की जाँच तथा मूल्यांकन करके केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक को रिपोर्ट देते हैं। फिर बैंक का वैधानिक परामर्शदाता कुषक की भूमि पर दायित्व की जाँच करके अपनी रिपोर्ट देता है। इसके परचात् केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक कुषक से भूमि सम्बन्धी कागजों को अपने नाम कुरवा लेती है तथा ऋण की रकम भूमि बन्धक बैंक द्वारा कुषक को दे देती है। ऋण ६ से ६ प्रतिशत की दर से प्रायः २० वर्ष के लिये दिया जाता है। भूमि विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित मूल्य के ५० प्रतिशत से अधिक रकम का ऋण नहीं दिया जाता। बहुत से स्थानों पर भूमि बन्धक बैंक कुषकों को १० हजार रुपये से 'अधिक का ऋण नहीं देतीं। ऋण की रकम कुषक क्याज सहित किश्तों में चुकाता है तथा किश्तों का समय ऐसा निर्धारित किया

जाता है जब कुषक की फसल तैयार होकर बाजारों में बिक जाता है श्रीर कुषक को अप्रुग्ध का मुगतान करने में मुविधा रहे।

वर्तमान स्थिति—भारतवर्ष में सर्व प्रथम ऐसी बैंक १६२० में पंजाब में स्थापित हुई थी। परन्तु भूमि हस्तांतर कान्त के लागू होने तथा पैदावार कम होने के कारण भूमि के मूल्य गिरने से यह श्रसफल हो गई। बाद में १६२६ में मद्रास में ऐसी बैंक खुली। १६४२-४३ में मारतवर्ष में श्रुघं सरकारी भूमि बन्धक बैंकों की संख्या मद्रास, बस्बई, मैसूर, मध्य प्रांत, बरार, पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश श्रीर उद्दीसा में क्रमानुसार १२०,२८,६७,२१,१०,४५,५,१ थी श्रीर उनकी पूँची ६७,७८,४०,१४,७,६,२, श्रीर २ लाख थी। ऐसी बैंक मद्रास में श्रिषक उन्नति पर हैं। मद्रास की भूमि बन्धक बैंक के बनाने से द्रव्यवाचार में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा भी नहीं रही है। केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक को श्रन्य बैंकों के निरीच्या करने का श्रषकार है तथा मद्रास सरकार ने एक ऐक्ट के श्रनुसार इन बैंकों के श्र्य-पत्र के मूलधन श्रीर ब्याच की गारंटी दे दी है तथा भुगतान न होने पर क्रषक की भूमि श्रीर उपज बिना न्यायालय की श्राशा लिये जब्त करके बेच सकते हैं, बम्बई में उनका संगठन मद्रास जैसा नहीं है।

सुधार के सुम्ताव—मार्च सन् १६५४ में भूमि बन्धक बैंकों का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में भूमि बन्धक बैंकों की कठिनाइयों पर विशेष रूप से विचार किया गया। सम्मेलन के सदस्यों के अनुसार मुख्य कठिनाइयाँ धन की कमी, ऊँची ब्याज की दर, ऋण देने में अधिक समय का लगना तथा ऋण वापनी में अनेक कठिनाइयों का होना था।

मूमि बन्धक वैंक के कार्यों में सुधार करने के लिये निम्नलिखित तीन सुमाव दिये जाते हैं:—

- (१) पहले ऋण के पश्चात् दूसरे तथा अगले ऋणों की ब्याज की दर अधिक कर देनी चाहिये।
- (२) ऋण को थोड़े काम के लिये दिया जाना जाहिये, जिससे थोड़े कोषों से अधिक लोगों को ऋण दिये जा सकें।
- (३) ऋणों के प्रयोग से जो लाम हो उसे ऋण के मुगतान के लिये ही उप-योग करना ऋनिवार्य कर दिया जाना चाहिये।

द्वितीय योजना काल में भारत सरकार ने भूमि बन्धक बैंकों के विकास तथा सुधार करने के सम्बन्ध में श्राम्य साख सर्वे चुण समिति के सुधारों के आधार पर नीति बनाई है। समिति ने सुफाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय मूमि बन्धक वैंक होनी चाहिये। भूमि को बन्धक रखने के वैधानिक टंग सस्ते श्रीर स्थल बनाने चाहिये। वैंकों की पूँजी में सरकार का ५१% भाग होना चाहिये। केन्द्रीय वैंकों को प्रारम्भिक वैंकों की पूँजी में भाग लेने का श्रिषकार होना चाहिये। उत्पादन कार्यों के लिये श्रुगों को प्रायमिकता देनी चाहिये। इसी प्रकार प्रारम्भिक भूमि बन्धक वैंकों को बड़ी सावधानी से पूर्णतया बाँच-गइताल करके स्थापित करना चाहिये। सरकार को इन वैंकों की पूँजी में साम्भीदार होनी चाहिये।

सहकारी वैङ्कों को रिजर्व वेंक की सहायता—रिजर्व वेंक का एक कृषि साख विभाग भी है। उसमें विशेषक्ष कर्मचारी होते हैं। उनके कार्य निम्न लिखित हैं:—

- (क) कृषि साख सम्बन्धी सभी प्रश्नों का ऋष्ययन करना ऋौर सभी वैंकों को ऋावश्यकता पड़ने पर परामर्श देने के लिये उपलब्ब होना, तथा
- (ल) कृषि साल के सम्बन्ध में बैंक के कार्यों में राज्य सहकारिता बैंक तथा व्यापारिक बैंकों को समान रूप में सहयोग देना । इस प्रकार उसका कार्य मुख्य रूप से एक परामर्शदाता के रूप में है श्रीर वह सीचे सहायता नहीं करता ।

१६३५ में श्री एम०एल० डार्लिङ्ग से सहकारिता संस्थात्रों के कार्य की बाँच करने को कहा गया। उनकी रिपोर्ट से इस बात का पता चलता है कि रिजर्व बैंक कृषि अर्थ व्यवस्था में किस प्रकार सहायता कर सकता है। १६४७ में रिजर्व बैंक ने एक विधान बनाया। उसने अनेक विज्ञित्वियाँ भी निकालीं। उसमें उन कटिनाइयों को बतलाया गया जो उधार देने वाले साहूकारों के बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य कार्य को छोड़ने तथा आधुनिक बैंकिंग प्रणाली को अपनाने के लिये तैयार करने के मार्ग में आती हैं।

सहकारी श्रान्दोलन मूमि बन्घक बेंकों, ऋण विधानों, बाजार में बेचने तथा श्रम्य सम्बन्धी विषयों की समस्याश्रों का यह विभाग बराबर श्रम्थयन करता रहा। इस विभाग में सहकारी श्रांदोलन के सम्बन्ध में लंका, मस्कट, चीन श्रादि अनेक देशों तथा भारत के श्रासाम एवं बम्बई जैसे कुछ चुने हुए प्रांतों के सम्बन्ध में श्रनेक पुस्तिकार्ये प्रकाशित कर चुका है।

रिजर्व बेंक पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह कृषकों को प्रत्यच्च आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करती, किन्तु आरोप लगाने वाले यह भूल जाते हैं कि रिजर्व बेंक श्रंतिम ऋग्यदाता के रूप में कार्य करती हैं और साधारण समय में किसी को ऋग प्रदान करना उसके लिये उपयुक्त नहीं है। वह तो केवल संकट काल में अथवा मीसमी कमी दूर करने के लिये अस्थायी आर्थिक सहायता दे सकती है। किन्तु धारा

- १७ (२) (ब), (४अ,स,द) के अंतर्गत रिजर्व बैंक प्रांतीय सहकारी बैंकों को तथा उनके द्वारा साख समितियों को नीचे लिखी शतों के अंतर्गत आर्थिक सहायता करती हैं:—
- (ऋ) ६० दिन तक के लिये सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर प्रांतीय सह-कारी तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋगा दे सकती है।
- (ब) इसी प्रकार के ऋगा मान्य भूमि बंधक बैंकों के ऋगा-पत्रों तथा अन्य ट्रस्टी प्रतिभृतियों की जमानत पर इसी प्रकार का ऋगा दिया जा सकता है।
 - (स) सरकारी खजाने की हुएिडयों की कटौती कर सकती है।
- (द) प्रान्तीय सहकारी बैंकों को ६० दिन तक के लिये मान्य सहकारी विपण्न तथा गोदाम समितियों के ऋण्-पत्रों पर ६० दिन तक के ऋण् दे सकती है। किन्तु यह आवश्यक है कि ये ऋण् पत्र कृषि उपज के विक्रय के लिये लिखे गये हों।
- (ई) इसी प्रकार के ऋगा उन प्रतिज्ञापत्रों की पुनर्कटौती करके दिये जा सकते हैं जो अगले १५ मास में देय हैं।
- (फ) इसी प्रकार के ऋग्ण प्रान्तीय सहकारी बैंकों के उन ऋग्ण-पत्रों की जमानत पर दिये जा सकते हैं जिनके साथ गोदामों की रसीद अथवा अन्य अधिकार प्रपत्र (Documents of Title) बन्धक रख दिये गये हैं।
- (ज) ऐसे ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ऋण-पत्रों पर भी दिये जा सकते हैं, यदि इन ऋण-पत्रों का बेचान किसी प्रान्तीय सहकारी बैंक ने कर दिया है।

उपरोक्त सहायता तभी प्रदान की जा सकती है जब रिजर्व बैंक सम्बन्धित प्रान्तीय सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक की ऋार्थिक स्थिति से संतुष्ट हो जाये।

ऋग माँगने वाले प्रान्तीय सहकारी बैंक को निम्नलिखित बातों की पूर्ति भी करनी होती हैं—

- (१) त्रानुस्चित बैंकों की भाँति ऋपने माँग-दायित्व का २५ प्रतिशत तथा साम-यिक-दायित्व का १ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा रखना।
- (२) ऋपने चिट्ठे को ठीक ढंग से बनाना तथा समय-समय पर निर्धारित नक्शे मेजना।
 - (३) समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा श्रपना निरीच्च कराना । केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निम्नलिखित बातों की पूर्ति करनी होती है—
- (१) श्रपनी श्रार्थिक श्रवस्था तथा श्रपने के सम्बन्धित प्रारम्भिक समितियों की कार्य प्रशाली की पूर्ण सूचना प्रदान कराना।

- (२) श्रपने यहाँ बमा का ४० प्रतिशत नकदी तथा सरकारी प्रतिभूतियों में रखना।
- (३) केवल श्रल्पकालीन श्रृण प्रदान करना तथा किसी भी श्रवस्था में स्वर्ण से श्रधिक की श्रवधि के श्रृण न देना।

रिजर्व वैद्ध द्वारा सहायता की आलोचना—रिवर्व वैंक ने प्रान्तीय सहकारी वैंक तथा केन्द्रीय सहकारी वैंकों के ऋण प्रदान करने के लिये इतने प्रतिवन्त्र लगा दिये हैं कि उन सबका किसी भी समय में पूरा किया बाना असम्भव है। बमा का ४० प्रतिशत नकदी तथा सरकारी प्रतिभृतियों में रखने से केन्द्रीय सहकारों वैंकों का व्यवसाय प्रायः ठप हो बायगा। सहकारी वैंक अपनी रकम को कम ब्याब वाली प्रतिभृतियों में अपना रुपया लगाने में असमर्थ हैं। इससे वैंकों की आय कम हो बायगी और वे अपने साधारण व्यय भी पूरे करने में असमर्थ देंगी। न अंश्रधारियों को लामांश दिया जा सकता है और न वैधानिक संचिति बनाकर आर्थिक अवस्था सुदृद की जा सकती है।

रिजर्व बैंक का यह प्रतिबन्ध भी कठोर है कि केवल उन्हीं हुन्डिं की उनकेंटीनी की जा सकती है जिन पर किसी प्रान्तीय सहकारी बैंक ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि ये हुन्डियाँ उपज की बिक्री के सम्बन्ध में लिखी गई हैं। इस प्रकार के प्रतिबन्धों से प्रगति को ठेस पहुँचती है और सहकारी बैंक रिजर्व बैंक से पूर्ण आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं कर सकती। रिजर्व बैंक भी इतनी अधिक सावधानी रखना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। किन्दु रिजर्व बैंक शनै:-शनै: अपनी कठोर नीति में परिवर्तन करके उदार नीति अपनाती जा रही है। रिजर्व बैंक के लिये भी यह उचित ही है कि वह सहकारी बैंकों को अपूर्ण प्रदान करने से पूर्व उनकी सुदद आर्थिक स्थिति पर बल दे।

१६५१ में रिजर्व वैंक ने अखिल भारतीय ग्रामीण साल सर्वेद्मण का कार्य अपने ऊपर लिया। इस कार्य को पूरा करने के लिये गोरावाला की अध्यद्धता में एक समिति नियुक्त की। इसने सहकारी वैंकों के पुननिर्माण के लिये इन्छ सुम्काव दिये। सहकारी साख के विकास के हेतु अखिल भारतीय छपि साख सर्वेद्मण समिति के सुम्भाव

गोरावाला समिति ने पूर्ण श्रध्ययन के पश्चात् सहकारी सौल का विकास करने के लिये निम्नलिखित सुभाव प्रदान किये—

(१) सहकारी साख समितियों के समद्ध सम्बन्धी योजना बनाने के लिये रिजर्ब बैंक राज्य सहकारों के सम्बन्ध स्थापित करे तथा राज्य सरकारों को दीर्घ कालीन ऋगा प्रदान करे जिससे राज्य सरकार सहकारी बैंको के ऋंश तथा ऋगा-पत्र कय कर सके ।

- (२) रिजर्व बैंक प्रान्तीय सहकारी बैंकों तथा उनके द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा समितियों को १५ मास की अविध से लेकर ५ वर्ष की अविध तक के लिये मध्य-कालीन ऋण प्रदान करे और यह प्रतिबन्ध उठा दिया जाये कि रिजर्व बैंक केवल ५ करोड़ के ऋणा प्रदान कर सकती है।
- (३) रिजर्व बैंक भूमिबंधक बैंकों को ५ वर्ष से अधिक अविध के लिये दीर्ध-कालीन सहायता अग्रण देकर अथवा अग्रण-पत्र क्रय करके प्रदान करे।
- (४) रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग का पुनर्गठन किया जाये श्रीर श्रपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिये उसे श्रिषिक शक्तिशाली बनाया जाय। राष्ट्रीय श्राघार पर भिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक परामर्श समिति बनाई जाय तथा यह समिति रिजर्व बैंक कृषि-मंत्रालय तथा सहकारी विकास एवं गोदाम संघ को परामर्श प्रदान करे।
- (५) राज्य सरकारें रिजर्व बैंक के परामर्श से सहकारी साख संस्थाओं का पुनर्गठन करें। पुनर्गठन में राज्य सरकार सहकारी बैंकों के सामेदार के रूप में कार्य करे। राज्य सरकार सहकारी सविंस चालू करके सहकारी संस्थाओं के संचालन के लिये योग्य अधिकारी उपलब्ध करे तथा सभी बड़ी-बड़ी सहकारी संस्थाओं का संगठन एवं प्रबन्ध इन्हीं अधिकारियों के हाथ में हो जिससे इनका संचालन योग्यता के साथ हो सके।
- (६) श्रल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋगों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाये। सहकारी बैंक एवं भूमि बंधक बैंक एक-दूसरे से पृथक रहते हुए भी पारस्परिक परामर्श से कार्य करें। इनके उच्चाधिकारी सम्मिलित हों तथा हो सके तो इनकी संचालन समिति भी एक ही हो। यदि यह संभव नहीं है तो कम-से-कम कुछ संचालक ऐसे हों जो दोनों प्रकार की संस्थाश्रों में ही संचालक रहे।
- (७) श्रल्पकालीन ऋषा केवल दैनिक श्रावश्यकतात्रों की पूर्ति के लिये एवं उत्पादन कार्यों के लिये ही प्रदान किये जाये तथा जिस समय कृषि उपज बिके उसी समय ले लिये जायें। मध्यकालीन ऋषा कृषि, पशु तथा यंत्र-क्रय करने के लिये प्रदान किये जायें।
- (二) भावी विकास के लिये प्रारम्भिक साख समितियाँ बृहत रूप में सीमित है दायित्व के साथ स्पापित की जायें तथा समितियों के निरीच्च का दायित्व प्रांतीय तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर हो, किन्तु अंकेच्चण का दायित्व राज्य सरकार पर ही होना चाहिये।
- (६) सहकारी विभाग राज्य सरकारों से मिलकर सहकारी कर्मचारियों के प्रशिच्च का प्रवन्ध करे तथा केन्द्रीय सरकार पूर्व रिजर्व कें कें इस कार्य के लिये

. स्त्रार्थिक सहायता प्रदान करें। यह प्रशिद्धण न केवल महकारी विभाग के कर्मचारियों के विपत्ति वरन् सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये मी हो। उन्हें विशेष रूप से वैंकिंग विपण्यन तथा श्रीवोगिक प्रशिद्धण के साधन जुटाये बायें।

यदि रिजर्व वेंक ने तथा राज्य सरकारों ने समिति के उररोक मुक्तावों को कार्यान्वित किया तो यह आशा को जाती है कि सहकारी आन्दोलन विशेषकर सहकारी वेंकों की स्थिति मुद्द हो जायेगी और वे कृषि वित्त में पूरा हाथ बँटा सकेंगी।

पंचवर्षीय योजनात्रों में सहकारी साख का रहान — हार्या साल सर्वेचण सिमित के सुभावों को भारत सरकार ने स्वीकार करके उन्हीं के आधार पर अपनी नवीन नीति निर्धारित की है। सरकार सहकारी संस्थाओं के कार्य में हम्मचेत्र एवं नियंत्रण नहीं करेगी। भविष्य में सरकार हर प्रकार से सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके लिये रिजर्व वैंक ने दो वोप स्थापित किये हैं: (१) राष्ट्रीय कृषि साल दीर्घकालीन कोप तथा (२) राष्ट्रीय कृषि साल कोष। प्रथम कोप में रिजर्व वैंक ने प्रारम्भ में १० करोड़ स्थये दिये और १६५६ के प्रचात भ कोड़ स्पये प्रति वर्ष दिये जाते हैं। इस प्रकार १६६० में इस कोप की गृह्य कर करने हो लायेगी। इसी कोप से राज्य सरकारों को सहकारी संस्थाओं को पूँजी में भाग लेने के लिये ऋण दिये जायेंगे। भूमि बन्धक वैंकों के लिये ऋणपत्र कर करने के लिये भी इस कोष का उपयोग किया जायेगा। राष्ट्रीय कृषि साख कोष में १६६० तक रिजर्व वैंक प्र करोड़ स्थया देशी और इसी कोष से राज्य वैंकों के श्रव्यकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

द्वितीय योजना में सहकारी साख संगठन के विकास के निम्नलिखित लच्य निर्घारित किये गये हैं—

बड़े त्राकार की समितियाँ श्रल्पकालीन साख मध्यकालीन साख दीर्घकालीन साख

20,800

१५० करोड़ ६०

५० करोड़ रू

२५ करोड़ इ०

प्रश्न

1. Briefly explain the functions of the co-operative credit societies.

सहकारी साख समितियों के कार्यों की विवेचना कीजिये।

2. Carefully describe the constitution and functions of a primary credit society in India.

भारतीय सहकारी साख सिमितियों के विघान तथा कार्यों का वर्णन कीजिये।

3. What are Land Mortgage Banks? How do they help agricultural finance?

मृ्मि बन्धक बैंक किसे कहते हैं ? वे ग्रामीण साख में किस प्रकार सहायता करती हैं ?

4. What are the agencies that supply rural credit in India? Discuss the part played by each agency and suggest improvements.

भारतवर्ष में प्रामीण साख की पूर्ति किनके द्वारा होती है ? हर एक मध्यस्थ इस सम्बन्ध में क्या कार्य करता है ? उनके सुधार के सुभाव दीजिये ।

5. What part has the Co-operative Department in India played in regard to the rural finance?

ग्रामीण साख के सम्बन्ध में सहकारी विभाग ने क्या कार्य किया है ?

6. What do you understand by Land Mortgage Banks? What are their functions? What is their present position in India?

भूमि बन्धक बेंक का क्या ऋर्थ है ? उसके कार्य क्या हैं ? भारतवर्ष में उनकी वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिये ।

7. How does the Reserve Bank of India help agricultural credit? Explain in detail.

भारतीय रिजर्व बैंक कृषि साख को क्या सहायता प्रदान करती है ? पूर्ण वर्णन की जिये।

- Describe the organization and functions of co-operative credit societies.
- 9. What is an Apex Bank? What is relationship with Reserve Bank and agricultural finance?

शीर्ष अथवा प्रांतीय सहकारी बैंक किसे कहते हैं ? इसका रिजर्व बैंक तथा कृषि वित्त से क्या सम्बन्ध है ?

भ्रध्याय ११

देशी वैंकर तथा साहुकार

(Indigenous Bankers and Moneylenders)

देशी बैंकर का अर्थ - केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी के शन्टों में देशी बैंकर वे व्यक्ति स्त्रथवा निजी फर्म हैं जो जनता का घन जमा पर प्राप्त करते हैं तथा जो इन्यीरि-यल बैंक आफ इंडिया. विनिमय बैंक. सहकारी बैंक तथा व्यापारी बैंक से भिन है। श्रुत: द्रव्य का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति श्रुथवा निजी पम जो धन पर जमा करते हैं अथवा उधार देते हैं वे देशी वेंकर कहाते हैं। देशी वेंकर्म साधारणतया वेंकिंग का वह काम करते हैं जिसे आजकल भी बैंक करती हैं तथा देश के भीतरी व्यापार श्रीर उद्योग-धंधों की आर्थिक सहायता करने में बड़ा महत्व रखते हैं। वे रुपया उधार देते, चालू अथवा मुद्दती खातों में डिपाजिट लेने, दर्शनी श्रीर मुद्दती हुणिडयाँ जारी रखने तथा कमीशन लेकर उन्हें भुनाने का काम करते हैं। परन्तु देशी वैंकर्स तथा सयुक पूँजी बैंकों के कार्यों में पर्याप्त स्त्रंतर है, भारतीय बैंकिंग का काम या तो प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा अथवा कुटुम्बों द्वारा होता है परन्तु संयुक्त पूँची के आधार पर नहीं होता । देशी बैंकर्स डिपाजिटों से थोड़ी ही पूँजी इकट्ठी करते हैं तथा उनके यहाँ डिपा-जिट का जो रुपया निकाला जाता है ऋथवा वापस लिया जाता है वह चेक द्वारा नहीं लिया जाता वरन् नकदी के रूप में लिया जाता है। दूसरा ऋंतर यह है कि देशी वेंकर्स बैंक के कार्य के अतिरिक्त दूसरे अनेक कार्य करते हैं जैसे, धान्य बेचना, कमीशन एवेंट, दलाल तथा उद्योग-धंघे चलाने वाले सभी का कार्य करते हैं। इन सभी प्र≉ार के कार्यों को एक साथ करने से देशी बेंकर्स के बेंकिंग के कार्यों की अवनित हो रही है। इसके अतिरिक्त उनकी अवनित के और भी कई कारण हैं। फिर भी यह कहना सत्य है कि स्राजकल भी देश की स्रार्थिक व्यवस्था में इन सर्राफों का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये भारत के द्रव्य बाजार तथा देश के विस्तृत व्यापार में एक श्रविवार्य शृङ्खला-सी बनाये रखते हैं । ये कृषकों को स्थानीय साह्कारों की मार्फत आधिक सहायता पहुँचाता, छोटे-छोटे कारीगरों तथा व्यापारियों को घन द्वारा सहायता देता है तथा चहाँ आवश्यकता हो ऐसे स्थानों तथा बंदरगाहों पर फसल पहुँचाने में, देश में सभी प्रकार की वस्तुओं का वितरण करने में सहायता करता है।

इन बैंकरों का कारबार पारिवारिक होता है श्रीर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। श्रतः इनको बैंकिंग की शिक्षा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। देशी बैंकरों का कारवार सरल तथा भांभारों से मुक्त होता है। इस कारण देशी बैंकर से काम कराने में देर नहीं लगती । ग्राहक किसी समय भी बैंकर के पास जा सकता है क्योंकि उनके कार्य का कोई समय निश्चित नहीं होता। वह हर समय काम करता है। उसके काम करने का दंग बहुत कम व्यय साध्य है क्योंकि वह किसी प्रकार का स्त्राधुनिक ढंग का कार्यालय. फर्नीचर इत्यादि नहीं रखता। उसके यहाँ तो जमीन पर बैटनेवाले मुनीम तथा रूपया रखने की एक तिजोरी होती है। हिसाव रखने का ढंग बहुत सादा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती क्योंकि वह ग्राने कारबार का स्वयं त्वामी होता है। ग्रात: हिसाव को श्राडिट कराना वह श्रावश्यक नहीं समभता । इन वैंकरों का कारबार भी श्रिधिकतर प्राने प्राहकों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बैंकर ऋपने प्राने प्राहकों के परिवार से, उनकी त्र्यार्थिक स्थिति तथा व्यापार की दशा से भली-भाँति परिचित होता है। त्र्रतः उसे इस बात का निश्चय करने में देर नहीं लगती कि किस ग्राहक को कितना रुपया दिया जाय क्योंकि ऋण प्रायः जाने-पहचाने व्यक्तियों को दिया जाता है। ऋतः ये देशी वैंकर ऋण देने के पश्चात भी अपने ऋणी के कार्यों की देखभाल करता रहता है जो अन्य बैंकों के लिये सम्भव नहीं। इससे ऋणदाता तथा ऋणी के मध्य अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो बाते हैं तथा वैंकर का रुपया मारे जाने की सम्भावना नहीं रहती।

संयुक्त पूँ जी वाली बैंड्डों तथा देशी बैंकरों में निम्नलिखित ऋंतर है-

- (१) संयुक्त पूँजीवाली बैंक १६१६ के कम्पनी कानून के स्रांतर्गत स्थापित की जाती हैं। मेमोरेंडम स्राफ एसोसियेशन तथा स्राटिकिल्स स्राफ एसोसियेशन बनाकर इन बैंकों की कम्पनी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री होनी स्रावश्यक है। देशी बैंकर किसी कानून के स्रंतर्गत नहीं होते तथा न उनकी रजिस्ट्री होनी स्रावश्यक है।
- (२) व्यक्तिगत पूँजीवाली बैंकों का संचालन श्रंशधारियों द्वारा नियुक्त किये गुप्ते संचालक करते हूँ श्रीर उनको इस प्रबन्ध के लिये कुछ कमीशन श्रथवा मत्ता मिलता है। देशी बैंकर श्रपना प्रबन्ध स्वयं करते हैं श्रीर श्रपनी सहायता के लिये मुनीमों के श्रितिरिक्त किसी प्रबन्धकर्त्ता को नहीं रखते।
- (३) संयुक्त पूँ जीवाली बैंक अपना कारबार तब तक चालू नहीं कर सकतीं जब तक रिजर्व बैंक के प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लें और रिजर्व बैंक प्रमाण-पत्र देते समय उन बैंकी की पूँजी कार्य-पद्धति इत्यादि पर कुछ प्रतियन्ध लगा देती है। देशी बैंकरों को इस प्रकार का कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं करना पड़ता।

- (४) संयुक्त पूँजीवाली बैंक रिजर्ब बैंक से सम्बंधित रहती है तथा उन्हें अपनी जमाओं का कुछ अंश हर समय रिजर्ब बैंक में रखना पड़ता है। जिजर्ब बैंक इन बैंकी के के कार्यों पर पूरा नियंत्रण रखकर समय पर इनकी सहायता भी करती है। इन बैंकों की प्रति सप्ताह अपने कारवार का ब्यौरा रिजर्ब बैंक को मेजना पड़ता है। देशी बैंकरों का रिजर्ब बैंक से ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं होता। न उनके कार्यों पर कोई नियंत्रण होता है तथा न उनको अपने कारवार का ब्यौरा मेजना पड़ता है। अतः उनको रिजर्ब बैंक से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती।
 - (५) समितित पूँजीयाची बैंक स्योकि द्याधिकतर जनता का राया लेकर ही स्थाना कार्य चलाती हैं स्थान उन्हें इस पूँजी के लगाने में पर्यान सनके रहना पहला है। ये केवल व्यापारियों से ही ऋषिकाधिक ६ मासों के लिये जमानत लेकर स्मृत देती हैं। परन्त देशी बैंकर ऋषिकतर ऋपनी पूँजी का प्रवन्य करने हैं, खनः वे व्यापारियों के स्थातिरिक्त कृषकों तथा उद्योगपतियों को भी ऋगा देते हैं। ६ मास से ऋषिक के लिये भी ऋगा देने में आपित नहीं उठाते। देशी बैंकरों का व्यवहार ऋपने प्राहकों के साथ वंशापरंपरागत चलता है।
 - . (६) संयुक्त पूँजीवाली वैंक केवल १०१ से १२ बजे तक ही जनता से व्यवहार करते हैं और इसके पश्चात् जनता का कैसा ही आवश्यक कार्य हो उनसे रकम सम्बन्धी लेन-देन नहीं करते जब कि देशी वैंकरों का लेन-देन ब्राहकों में हर समय चलता रहता है तथा छावश्यक्त पड़ने पर देशी वैंकरों के ब्राहक राजि में भी स्पया उधार ले सकते हैं अर्थात् किसी भी समय स्पया ले सकते हैं।
 - (७) सम्मिलित पूँ जीवाली वैंकों को वर्ष भर में एक बार अपने लेन-डेन का चिट्ठा (Balance Shet) छाप कर जनता के सूचनार्थ प्रकाशित करनी पड़ती है। परन्तु देशी वैंकरों का व्यवहार प्रायः गोपनीय होता है तथा वे अपने लेन-डेन का चिट्ठा प्रकाशित नहीं करते।
 - (二) संयुक्त पूँ जीवाली बैंक बैंकिंग कारबार के द्यतिरिक्त द्यन्य कोई कार्य नहीं कर सकतीं। न वे सहा लगा सकती हैं, न ब्यापार कर सकती हैं, न अचल सम्पत्ति क्य-विक्रय कर सकती हैं तथा न अचल सम्पत्ति पर ऋण दे सकती हैं। देशी बैंकर रुपये के लेन-देन के द्यातिरिक्त व्यापार भी करते हैं, सहा भी लगाते है तथा अचल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण भी देते रहते हैं।
 - (१) संधुक्त पूँ जीवाली बेंक़ों में जनता जो रूपया जमा करती है उसे चेक द्वारा वापस ले लिया जाता है। देशी बेंकर जनता का रूपया जमा पर बहुत कम प्राप्त करते हैं तथा जो जमा होता भी है उसे चेक द्वारा निकालने की प्रथा नहीं है।

देशी वेंकरों के कार्य-देशी वेंकर साधारणतया वह कार्य करते हैं जिसे वर्तमान वैंक करती हैं तथा देश की भीतरी व्यापार तथा उद्योग-घंघों की त्रार्थिक सहायता करने में बड़ा महत्व रखते हैं। वे रुपया उधार देने. चाल श्रथवा महती खातों में जमा प्राप्त करने, दर्शनी तथा मुद्दती हुंडियाँ चालू करने तथा कमीशन लेकर उन्हें भुनाने का कार्य करते हैं। परन्तु देशी बैंकर्स तथा संयुक्त पूँजी बैंकों के कार्यों में बड़ा श्रंतर है। भारतीय वैंकिंग का कार्य या तो प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा श्रथवा कुद्धम्बों द्वारा होता है। परन्तु संयुक्त पूँची के आधार पर नहीं होता। देशी बैंक्स जमात्रों से थोड़ी ही पूँजी इकट्टी करते हैं तथा उनके यहाँ जमा का जो रुपया निकाला जाता है ऋथवा वापस किया जाता है वह चैक द्वारा नहीं लिया जाता परन्त नकद लिया जाता है। दूसरा कार्य यह है कि देशी बैंकर्स बैंकिंग के कार्य के अतिरिक्त अस्य अनेक कार्य करते हैं। वे व्यापार जैसे घान्य बेचना. कमीशन एजेंट दलाल स्रोर उद्योग धंवे चलाने वालों सभी का कार्य करते हैं। इन सभी प्रकार के कार्यों को एक साथ करने से देशी बैंकर्स के बैंकिंग कार्यों की अप्रवनित हो रही है। यद्यपि लसकी अवनति के और भी कई कारण हैं फिर भी यह कथन सत्य है कि आजकल भी देश की त्रार्थिक व्यवस्था में इन सर्राकों का बड़ा महत्व है। क्योंकि वे भारत के द्रव्य बाजार श्रीर देश के विस्तृत व्यापार में एक श्रनिवार्य अंखला-सी बनाये रहते हैं। वे क्रकों को स्थानीय साहकारों की मार्फत ऋार्थिक सहायता पहेंचाता. होटे-छोटे कारीगरों तथा व्यापारियों को भी घन से सहायता देता है श्रीर श्रावश्यकता के स्थानों में अथवा बन्दरगाहों पर अथवा उपज पहुँचाने में तथा देश में सर्व प्रकार की वस्तुओं का वितरण करने में सहायता करता है।

देशी बैंकर्स के मुख्यतः ३ कार्य हैं-

- (१) जमा स्वीकार करना—देशी बैंकर निश्चित को जमा प्राप्त करते हैं श्रीर ऐसी भी जमा प्राप्त करते हैं जिसका भुगतान माँगने पर तुरन्त कर दिया जाये। इनकी ब्याज की दर प्राय: ५ से ७ प्रतिशत होती है।
- (२) ऋगा देना—ये प्रत्येक प्रकार की प्रतिभृति पर ऋगा देते हैं। यदि जमानत श्रव्छी है तो ने ६ प्रतिशत से १८ प्रतिशत की दर पर ही ऋगा देते हैं अन्यथा उसके ब्याज की दर ४४ प्रतिशत तक होती है। यह कृषकों को उनकी तैयार फराल श्रीर कारीगरों को इस प्रतिशा पर ऋगा देते हैं कि ये लोग तैयार माल उन्हीं को बेचेंगे। सारांश यह है कि ये केंवल गोदामों में रखे हुए माल पर ऋगा नहीं देते वरन प्रत्येक प्रकार की जमानत पर ऋगा देते हैं।
- (३) हुंडियों का व्यवसाय करना—देशी वैंकर हुंडियों का व्यवसाय करते हैं श्रोर ये हुंडियों को सुनाते भी हैं।

वैंकिंग का कार्य करने वे श्रातिरिक्त देशी बैंकर अन्य स्थापार भी करते हैं। उनकी जो पूँजी दैंकिंग के स्थापार में लगी होती हैं उसमें तथा स्थापार में लगी पूँजी उधर लगा दी जाती है। केवल मद्रास पान्त के नद्दू कोटाई, चेटी तथा बस्बई पान्त के सुल्तानी ही ऐसे देशी बैंकर है जो कि बैंकिंग के साथ अन्य स्थापार नहीं करते हैं। नहीं तो अधिकांश देशी बैंकर अनाज, करास, जुट तथा अन्य इपि की उपजो, बस्क तथा सोना-चाँदी का स्थापार अथवा सट्टा करते हैं। इसके अतिरिक्त वे जनरल मचेट, आदत, बोकर, देवलर्स का भी कार्य करने हैं। स्थापार के साथ-साथ वे शकर, तेल, आदत, बोकर, देवलर्स का भी कार्य करने हैं। स्थापार के साथ-साथ वे शकर, तेल, आदे के कारखानों तथा कपास, जुट, धान, रेशम तथा शीशे के कारखानों को भी चलाते हैं।

संदोप में कहा जा सकता है कि देशी वैंक्स वैंकिंग के साथ साथ ख्रीर मीं व्यापार तथा व्यवसाय करते हैं ख्रीर बहुधा उनको व्यवसायिक कारखाने से वैंकिंग की ख्रपेत्वा ख्रधिक लाम होता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि विछले दिनों देशी वैंक्स का बैंकिंग कारबार कम होता जा रहा है। इस कारण उन्होंने ख्रपना ध्यान व्यापार तथा व्यवसाय की ख्रोर ख्रधिक लगाना प्रारम्भ कर दिया है।

देशी बैंकसै की किमयाँ—(१) देशी बैंकर आधुनिक बैंकिंग प्रकाली से बहुत दूर हैं।

- (२) साहूकारों में पारस्परिक ईषों है जिससे इनका कोई अच्छा संगठन नहीं है। इनके किसी भी संगठन ने आधुनिक कंपनी में अपने को परिएत नहीं किया है तथा इनके आधुनिक संगठनों में से भी केवल इने गिने संगठन रहे हैं, जैसे बम्बई सर्राफ एसोसियेशन, मारवाड़ी चैम्बर आफ कामसे तथा मुल्तानी बेंकर्स एसोसियेशन आप आदि।
- (३) ये लोग बहुत धन जमा के रूप में प्राप्त करते हैं। ऋतः जनता को केवल ऋग् देते हैं और उनमें मितव्ययता के बजाय ऋपव्ययता बढ़ाते हैं।
 - (४) प्रायः सारी हुण्डियों का नकद रुपयों में लेन-देन होता है।
- (५) ये लोग बैंकिंग व्यवसाय के साथ-साथ ऋन्य वस्तुक्रों का भी व्यवसाय करते हैं।
 - (६) ये लोग सोना-चाँदी के बाजारों में सट्टा करते हैं।
- (७) इनकी पूँजी बहुत कम है क्यों कि ये लोग जमा घन पर बहुत कम प्राप्त करते हैं।
- (८) ये श्रपना हिंसाब ठीक श्राधुनिक ढंग से नहीं रखते तथा न तो उसका श्रंकेच्या ही कराते हैं श्रीर न उनको जनता के सामने प्रकाशित करते हैं।

(E) ये हुएडी तथा चेक श्रादि द्रव्य बाजार के प्रमुख साखपत्रों में कार्य करवे उन्हें उत्साहित नहीं करते हैं।

देशी बैंकर्स की स्थिति में सुधार के सुमाव

- (१) रिजर्व बैंक को अपनी स्वीकृत तालिका (Approved List) में उनके नाम श्रंकित करके उनसे निम्न प्रकार से संबन्ध स्थापित करना चाहिये:—
- (त्र) ब्रन्य वैंकों को तरह उन्हें भी हुिएडयों की पुनर्कटौती की सुविधा देनी चाहिये।
- (ब) एक न्यूनतम पूँजा की रकम निश्चित कर देनी चाहिए जो हर एक वैंकर के लिये आवश्यक है। यह रकम व्यापारिक वैंकों की न्यूनतम रकम से कम होनी चाहिये।
- (स) उनका ठीक हिसाब रखना चाहिये। उनका रजिस्टर्ड अंकेच्क के द्वारा वार्षिक अंकेच्यण होना चाहिये तथा रिजर्व वैंक जब चाहे तब हिसाबों का निरीच्यण करा सके।
- (द) श्रन्य बैंकों की तरह ये भी रिजर्व बैंक के पास श्रपने दायित्वों का विशेष प्रतिशत जमा रखें। परन्तु उन बैंकरों को जनकी जमा पाँच गुनी से श्रिधिक नहीं हैं, उन्हें ५ वर्ष तक इससे छूट मिलनी चाहिये। यह बहुत कठिन है, क्योंकि देशी बैंकर का जमा घन बहुत कम है तथा उसके पास स्टाक भी नहीं है।
 - (ई) देशी बैंकों को एक निश्चित नकद कोष भी रखना चाहिये।
- (फ) अन्य बैंकों को दी जाने वाली दूसरी सुविधायें देकर रिजर्व बैंक को इन्हें अपना आदृतिया बना देना चाहिये जो प्रामों में यह कार्य करे।

वे अपने को निन्न प्रकार के रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं-

- (क) ऋपने को निजी सीमित दायित्व की कंपनियों (Private Limited Liability Companies) में परिवर्तित कर लें।
 - (ख) वे ऋपने को संयुक्त पूँची की बैंकों में सम्मिलित कर लें।
- (ग) वे अपने अपने अपनि कर्मनी की कोमंडित (Comandit) सिद्धान्त की बैंकों के रूप में स्थापित कर लें। इन बैंकों को भागीदार व्यवस्थित करते हैं। अतः संचालकों का असीमित दायित्व होता है। अतः बड़ी बैंक इन बैंकर्स के साथ भागीदार के रूप में कार्य करके देशी बैंकर की कार्य कुशालता का पूरा लाम उठा सकती हैं।
- (घ) स्वदेशी बैंकर संयुक्त पूँजी बैंकों के ब्राइतिये बन कर बैंकिंग के कार्य
 - (ङ) एक विशेष स्थान के सारे ऐसे बैंकर्ष का एक संयुक्त पूँ जी का सहकारी

वैंक अथवा एसोसियेशन बना दिया जाये जिसमें पूँजी का अभाव नहीं रहेगा तथा सब मिलकर अच्छी प्रकार कार्य कर सकेंगे।

- (च) रवदेशी वैंकर हुन्डी के दलाली के कार्य को सबसे ऋषिक महत्व दें।
- (छ) केन्द्रीय बैंक कमेटी वी प्रोट के अनुसार देशी वैंकरी की सम्भूष भारत के बैंकरों के एसोसियेशन का सबस्य बनना चाहिये। इससे उनके व्यापन में प्रशंन उन्नति होगी।
- (ज) देशी वैंकर तथा संयुक्त पूँ जी वाली वैंक दोनों मिल कर वैंकिंग का कार्य सामें में करें। इसके वे जनता के वैकार पड़े घन को संचित करके प्राप्तान वालों को उधार देने में समर्थ होंगे तथा इससे हुंडी बाबार की उन्नति होंगी।
- (३) रिजर्व वैंक, इम्पीरियल वेंक. संयुक्त पूँजी की वैंकी को इसके दाग हुडी तथा चैक के रुपये एकत्रित करवाने चाहिये तथा इनके दृश्य भेजने की मुविधा भी दें।
- (४) बैंक की किताबी सम्बन्धी कान्त (Bank B. oks Evidence Act, की सुविधार्ये इनको भी दा जानी चाहिये।
- (५) स्थानीय परामर्श बोर्ड भी स्थापित किये जाये जिनमें ये वेकर क्रांभ्मलित हों तथा वे वेंकों को ग्राहकों की आर्थिक अवस्था के विषय में बतलाये । अपन्य वेंकों को उन देशी बेंकर्स की हुन्डी भुना देनी चाहिये जो पूरी जमानत देते हैं तथा बोर्ड जिनके विषय में ठीक परामर्श देती हैं।
- (६) देशी बैंकर्स को आधुनिक बैंकिंग के हंग पर ऋपने हिसान रखने चाहिये, उनका अंकेब्र्ण करवाना चाहिये तथा चैक और हुन्डियों का प्रयोग करना चाहिये।
- (७) उनको स्रपनी सहेवाजी का कार्य वन्द कर देना चाहिये। उनको स्राने सहकारी माल गोदाम बनाने चाहिये तथा इनसे हुन्डी वाजार की उन्नीत करने का प्रयन्न करना चाहिये।
 - (=) उनको न्याज दर कम कर देनी चाहिये तथा श्रामनी दूपित पद्धतियों को याग देना चाहिये।
 - (६) प्रमाणित तथा रजिस्टर्ड वैंक्स को कुछ सुविघायें देते हुए उनका एक ।
 सुदाय बनाना चाहिरे ।
 - (१०) उन्हें स्रपने बैंकिंग तथा स्रन्य व्यापारों के हिसाबों की किताबें स्रलग-
 - (११) उनको अपनी हुन्डियों के कटौती के दङ्ग को सुघार कर अपना सारा कृषि का व्यापार, उन्हीं के द्वारा करना न्वाहिये। .

कृषि के ऋण् संम्बंधी तथा उनके हिसाबों सम्बन्धी कई कान्तों के बनने के कारण ये सुम्ताव कुछ सीमा तक सफल हुए हैं।

साहकार-साहकारी प्रथा भारतवर्ष में प्राचीन काल से चली आ रही है। साहकार लोग, महाजन, बनिया, सेठ, बोहरा, चेट्टी त्रादि अनेक नामों से भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पुकारे जाते हैं। बम्बई के मारवाड़ी, पञ्जाब के खत्री ग्रीर श्ररोड़ा, दिच्या, के चेड्डी, सिंघ तथा गुजरात में मुल्तानी तथा रेहती तथा उत्तरी भारत में बनिया, सर्गफ इत्यादि नामों से रुपये के लेन-देन का कार्य करते हैं। भारत एक कृषि-प्रधान देश है श्रीर यहाँ का कृषक सदैव ही श्रत्यंत गरीन श्रीर दुखी रहा है। सूखा पड़ जाने. बाद श्रा जाने तथा श्रन्य कारणों से किसी समय भी उसे हानि उठानी पड़ती है तथा इसी लिये कार्य चलाने के लिये उसे हर समय दूसरों का मुँह ताकना पड़ता है। लगान तथा श्राबपाशी का भुगतान करने के लिये, बैल, बीज तथा लेने के लिये, विवाह-शादी-बारात इत्यादि पर व्यय करने के लिये तथा फसल नष्ट हो जाने पर ऋपने जीवन निर्वाह के लिये भारतीय कुषक को हर समय ऋगा की आवश्यकता पड़ती रहती है। भारत में थोड़ी बहुत जितनी भी बैंक स्थापित हुई हैं वे सब व्यापारियों की सहायता करती हैं ऋौर कुषक को ऋग देने में असमर्थ हैं। इसका कारण यह है कि भारतीय कृषकों के पास कोई ऐसी अच्छी समाचि नहीं जिससे उनको सरलता से ऋण प्राप्त हो सके। सहकारी आ्रान्दोलन का भी जन्म भारत में बहुत देर से हुआ है। सहकारी त्रान्दोलन सुसंगठित रूप से अपना कार्य करने में असफल रहा है। ऐसी अवस्था में कृषकों के लिये प्रामीण साहूकार ही एक जीवनाधार है। वे कृषकों को फसल, धान्य, चल-श्रवल सम्पत्ति की जमानत पर, ऋण लेने वालों की व्यक्तिगत जमानत पर धान्य. बीज, रुपया श्रथवा पशु के रूप में ऋण देते हैं। वास्तव में यदि ये महाजन लोग कुषकों की समय पर सहायता न करें तो खेती का काम नहीं चल सकता। समय पर बीज न मिलने से फसल बोई नहीं जा सकती। प्रामीया साहूकार हर समय कृषक की सहायता करने को तत्पर रहता है। यदि स्राधी रात को स्रावश्यकता पड़े तो उस समय भी कृषक वे रोक टोक जाकर साहूकार से रुपया ला सकता है। साहूकार अपने ग्राहक की सारी आवश्यकताएँ चाहे वे व्यक्तिगत हों अथवा सामाजिक, कृषि सम्बन्धी हों श्रथवा उद्योग सम्बन्धो पूरा करने का वचन देता है। कोई भी बैंकिंग संस्था बिना जमानत के ऋण देने को तैयार नहीं होती जब कि साहूकार केवल लेने वाले के हस्ता-द्धर करवा कर अथवा अँगूठा लगवा कर विना किसी जमानत के ऋगा देता है। श्रन्छी जमानत मिल जाने पर भी बैंक ६ मास से श्रिधिक के लिये ऋण नहीं देते। परन्त कृषक तो ऋष तब तक के लिये चाहिये जब तक कि उसका नवीन फसल न आ जाये तथा ऐसा करने के लिये ६ मास से वर्ष अर तक का समय अग जाता है। संसार में भारतीय साहकार ही एक ऐसा ऋ खदाता है जो श्रेपिंक संकट आ जाने पर ही अपने प्राहकों को ऋण देता है। बैंक इत्यादि तो मीसमी मित्र होते हैं तथा संकट काल में ऋणी की महायता करने से मुख नहीं मोड़ लेते किन्तु अपने ऋण की वम्सी की धमकी देकर उसके संकट को और बढ़ाते हैं जब कि साहूकार संकट काल में ऋणी की अपनी देकर उसके संकट को और बढ़ाते हैं जब कि साहूकार संकट काल में ऋणी की और भी अधिक सहायता करता है। भारतीय साहूकार दिये हुए ऋण को गीपनी रखता है और इस प्रकार प्राहक की प्रतिष्ठा को भी बहा नहीं लगने देना। इसके ऋणि रिक्त समय-समय पर अपने ऋणी को आर्थिक परामशों भी देता रहता है। श्रीर ऋषक फसल को विकवाने तथा उसके लिये आयश्यक परतुओं का प्रधन्य करता है। इस प्रकार भारतीय साहूकार भारतवर्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है तथा तिर्धम ऋषों को समय-समय पर ऋण देकर उनकी आर्थिक सहायता करता है।

उपरोक्त का यह तात्रर्य नहीं कि साहूकार सबधा दोपरहित है। वह ऋी से बहुत ऋषिक ब्याज लेता है तथा एक बार ऋण लेने पर ऋणी को सर्व ही छाने चंगुल में फँसाये रखता है। कुछ साहूकार थोड़ी रकम देकर ऋषिक लिख लेते हैं तथा ऋणी से ऋषिक रुपया लेकर उनको कृष्ट पहुँचाते हैं। साहूकार लोग विवाह शादी, मकान इत्यादि के लिये भी ऋण देकर ऋपकों को ऋपव्यय के लिये भीत्माहत करते हैं जिससे छात में उनको हानि उठानी पड़ती है। साहूकार लोग लेन-देन के साथ-साथ व्यापार का भी कार्य करते हैं तथा ऋणो ऋषकों की फसल को स्वयं कम मूल्य पर कथ करके ऋनुचित लाभ उठाते हैं। परन्तु इन दोषों का यह ऋप नहीं कि साहूकारी प्रथा का खंत कर दिया जाये। रोग को समाप्त करने के लिये रोगी को समाप्त कर देना कोई ऋच्छी बात नहीं हैं। यदि साहूकारों के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया जाय तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह और ऋषिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

साहूकार और देशी बैंकर्स में अंतर

- (१) देशी बैङ्कर घन जमा करते हैं और हुंडियों का लेन देन करते हैं, परन्तु साहूकार और महाजन बहुत कम ही वैंकिंग कार्यों को करते हैं।
- (२) देशी बैंकर महाजनों की अपेक्षा ऋगण के उद्देश्यों की आरे बहुत अधिक ध्यान देते हैं।
 - (३) महाजनों की अपेचा देशी बैङ्कर्स की ब्याज की दर कम होती है।
- (४) देशी बैङ्कर व्यापार तथा उद्योग को ऋार्थिक सहायता देते हैं परन्तु महाजन श्रीर साहूकार उपयोग के लिये ऋण देते हैं।
 - (५) देशी बैक्क सें का कार्य चेत्र महाजनों की अपेचा अधिक विस्तृत होता है। यद्यपि देशी बैंकर व्यवसाय ही में भाग लेते हैं और इनको यदि बैंक कहा

जाये तो कोई त्रुटिन होगी। किन्तु फिर भी इनमें श्रौर श्राष्ट्रिक बैंकों में पर्याप्त स्रंतर है।

बम्बई राज्य में देशी वैंकसं-वम्बई राज्य के देशी बैंकर्स साधारण ऋषि-कोषगा जैसे सभी कार्य करते हैं। वे हर प्रकार की जमायें प्राप्त करते हैं, चालू खाते खोलते हैं. खातेदारों के लिखित आदेशों का पालन करते हैं. ऋण प्रदान करते हैं। हंडियों की कटौती करते हैं तथा ग्रान्तरिक व्यापार को ग्रार्थिक सहायता प्रदान करते है। ये बैङ्कर्स उन सभी ग्राहकों से सम्बन्ध स्थापित करते हैं जिनके पूर्वज़ों से उनका व्यापार होता त्र्याया है ऋौर जिनसे वे भली भाँति परिचित हैं। किसी समय इंगलैंड में भी तो ऐसा होता था। इससे लोगों को बचत करके जमा करने का प्रोत्साहन Îमलता है। भारत के अन्य भागों की तरह बम्बई के देशी बैंकर्स भी बैंकिंग के साथ अन्य व्यादार भी चलाते हैं तथा अपना हिसाब पुराने ढंग से खते हैं। ये बैंक्स चाल खाते में अधिनिकरण (overdraft) की सुविधा देकर ऋण प्रदान करते हैं। जो ऋण किसी निश्चित समय के लिये दिया जाता है उसे खाता-पेटा कहते हैं। ये बैंकर्स दो-दो. चार-चार दिन के लिये हथउधार के ढंग पर भी ऋण प्रदान कर देते हैं। ये लोग व्यापारियों को, लघु उद्योगपतियों, तथा सुनार इत्यादि को भी ऋण देते हैं। इषकों की सहायतार्थ ये लोग साहकारों को ऋण प्रदान करते हैं, क्योंकि कृषक अपना संबंध साहकारों से आधिकतर रखते हैं। ये बैंकर्स जिन्हें सर्राफ भी कहते हैं दर्शनी हुएडी की कटीती करते हैं। अधिकतर ये लोग कमीशन एजेंट का भी कार्य करते हैं और इनके पास जो माल बिकने आता है उसके मूल्य का ७५ से ६० प्रतिशत तक पेशगी दे देते हैं जो माल की विक्री पर काट लिया जाता है। ये सर्राफ कटौती की हुई हंडियाँ व्यापारिक बैंकों से पुनर्कटीती करके घन प्राप्त करके ऋपना कारबार चलाते हैं । मुल्तानी सर्राफ स्टेट बैक्क से इस प्रकार की सहायता प्राप्त करते हैं ।

बंगाल में देशी बेंकर्स — बंगाल के अधिकांश देशी बेंकर्स मारवाड़ी हैं जो बैंक्किंग के साथ साथ अन्य व्यापार भी करते हैं। ये लोग जनता से जमायें प्राप्त न करके अपनी ही पूँजी से कारवार करते हैं। वंगाल में कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत लगभग १२०० अनुसा कार्यालय पंजीकृत हैं और देशी बैंक्क्स हुन्डियों की कटौती करके आन्तरिक व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। अधिकतर अनुसा उन व्यापारियों को प्रदान किये जाते हैं जो प्रामों से माल अय करके निर्यात करते हैं। ये लोग आम्बूब्स तथा भूम गिरवीं रखकर और अर-अन्य व्यक्तियों की क्वमानत पर भी अनुसा प्रदान करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया मेजिन के लिये तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ये बैंकर्स हुण्डियों लिखते हैं और इन हुण्डियों को

४ प्रतिशत से लेकर १८ प्रतिशत तक बट्टे की दर से पुनर्कटीती करते हैं। व्यापारिक वैंक तथा स्टेट वैंक भी इन वैंकर्स को इनकी हुंडियाँ क्रय करके ऋपधिक सहायता प्रदान करते हैं।

मद्रास में देशी वेंकस-मद्रास में देशी वैंकिंग का श्रिष्ठांश कार्य नद्र कोटाई चेटी करते हैं। ये लोग जनता की जमायें प्राप्त करने हैं जो वैक के क्षार निकाली जा सकती हैं। इन लोगों की श्राधिक श्रयस्था मुद्द है ग्रीर इनसे बैंकिंग व्यापार की बड़ी योग्यता है। ये लोग श्रयने कर्मचारियों को वैंकिंग व्यवस्था के प्रार्थ च्यापार की बड़ी योग्यता है। ये लोग श्रयने कर्मचारियों को वैंकिंग व्यवस्था के प्रार्थ च्यापार की बड़ी योग्यता है। ये लोग श्रयने कर्मचारियों को वैंकिंग व्यवस्था के प्रार्थ च्यापार की उनकी भूमि वन्धक रखकर श्रयवा उनके प्रतिशापन पर च्यापारियों के श्रित विद्या के श्रित कुछ मुल्तानी व्यापारिक वैंकों में श्रयम् लेकर व्यापारियों के श्रया करते हैं। कुछ मुल्तानी श्रयनी पूँकी से तथा कभी-कभी जनता से जमायें प्राप्त करके भी श्रयना कारवार चलाते हैं, मद्रास में मारवाड़ों भी वड़ी संख्या में हुन्डियों. श्रामुष्यों तथा माल की जमानत पर व्यापारियों को श्रुग प्रवान करते हैं किन्त इन लोगों की ब्याज तथा वट्टे की दर ऊँची होती है। लघु-उद्योगपतियों को तो ये लोग श्रुण प्रदान करते ही नहीं।

रामनद तथा तिनेवली में कालीदाई क़ुरीची ब्राह्मण भी प्रिक्टियए का कार्य करते हैं। ये लोग ऋषिकांश हुएडी की जमानत पर ही श्रन्य साहूकारों को ऋण प्रदान करते हैं।

देशी बैंकसे का महत्व — देशी कार्यों का अध्ययन करने से यह जात होता है कि मारत में इनका कितना महत्व है। इस देश में आधुनिक बैंकिंग की इतनी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जितनी पाश्चात्य देशों में। ये देशी बैंकर्स तथा साहूकार ही इस अभाव को पूरा करते हैं। व्यापारिक बैक्क प्रामीण खेत्रों में अपनी शासाय स्थापित करने में असमर्थ हैं। अतः वहाँ साहूकार ही लोगों के एक मात्र जीवनाधार हैं। नगरों में भी देशी बैंकर्स का बड़ा महत्व है। बम्बई, इंदौर, अहमदाबाद, कलकत्ता इत्यादि औद्योगिक केन्द्रों में सर्गफ तथा साहूकार उद्योगपितयों को आर्थिक सहा-यता प्रदान करते हैं, कभी-कभी ये लोग प्रवन्ध-अभिकर्ताओं से उनके कमीशन का भाग प्राप्त करने के लिये उनहें अपूण देते हैं। मोली-भाली अनता जितना इन साहू-कारों का विश्वास करती हैं, उतना व्यापारिक बैंकों का नहीं। अतः अधिकतर लोग अपनी बचत इन्हीं के पास जमा करते हैं। इन कारणों से देशी बैंकर्स तथा साहूकारों को प्रोत्साहन देना अति आवश्यक है। यदि ये बैंकर्स अपने कारबार करने के ढंग में सुक्छ सुधार करें और अश्वधुनिक बैंकिंग प्रणाली को अपनायें तथा अपने कारबार में एकस्पता लाने का प्रयत्न करें तो ये देश की आर्थिक व्यवस्था में पूर्ण सहयोग प्रदान है।

कर सकते हैं। बैंकों को भी चाहिये कि देशी बैंकर्स से अपना सम्बन्ध स्थापित करके अपनी सेवाओं को अधिकतम उपयोगी बनायें। रिजर्व बैंक का भी यह कर्त्तव्य है कि वह देशी बैंकर्स को हर प्रकार का प्रोत्साहन देकर देश का कल्याण करे।

देशी बैंकरों से रिजर्ब बैंक का सम्बन्ध—केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी ने यह अनुरोध किया था कि रिजर्ब बैंक स्थापित हो जाने पर देशी बैंकर का उससे सीधा संबन्ध
स्थापित हो जाना चाहिये। इस अनुरोध को कार्यान्वित करने के लिये सन् १६३५ र्षे
रिजर्ब बैंक की स्थापना हो जाने के पश्चात् तुरन्त ही रिजर्ब बैंक ने देशी बैंकरों से
सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक योजना तैयार की। योजनानुसार जो भी देशी
वैंकर योजना से सम्बन्धित होगा ये तथा रिजर्ब बैंक से सुविधायें चाहेगा उसे
शुद्ध बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य न्यापार को छोड़ देना होगा। उन्हें अपना हिसाब ठीक
प्रकार से जिस प्रकार से रिजर्व बैंक कहे उस प्रकार रखना होगा। अपने हिसाब को
नियमित रूप से अंकेच्च्या करवाना होगा। रिजर्व बैंक के आवश्यकता समभने पर
उनके हिसाब तथा कारबार का निरीच्या कर सकेगा। उन्हें रिजर्व बैंक को समयसमय पर अपने कारबार के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी तथा स्चनाएँ देनी होंगी
तथा रिजर्व बैंक को उनके बैंकिंग के कारबार का नियन्त्रण करने का अधिकार होगा।
प्रत्येक देशी बैंकर की निज की पूँजी कम से कम ५ लाख होगी। उनको अपनी जमा
का एक निश्चत प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा करना होगा। फिर भी रिजर्व बैंक
उनसे सीधा सम्बन्ध स्थापित न करके अप्रत्यच्च सम्बन्ध स्थापित करने के पच्च में था।

उपरोक्त प्रस्ताव केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी के मत के विरुद्ध था। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच कमेटी का यह मत था कि त्रारम्भ में देशी बैंकरों के साथ नरमी का व्यवहार करना चाहिये। उन पर कड़े प्रतिबन्ध न लगाना चाहिये। उदाहरण के लिये त्रारम्भ में कुछ वर्षों तक देशी बैंकर्स को रिजर्व बैंक में त्रानवार्य रूप से जमा रखने पर विश्वास करना चाहिये। किन्तु पहली गश्ती चिट्ठी में रिजर्व बैंक ने उपरोक्त शतें लिख मेजी। वे इतनी कठोर थीं कि कोई देशी बैंकर उनको स्वीकार करने के लिये तैयार न था। इससे पहले प्रस्ताव का ऐसा घोर विरोध हुत्रा कि रिजर्व बैङ्क को २६ त्रामस्त १६३७ को एक दूसरी योजना उपस्थित करनी पड़ी जो कि केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी के त्रानुरोध के त्रानुरूप थी तथा उसमें देशी बैंकर्स का रिजर्व से सीधा संबन्ध स्थापित हो जाने की व्यवस्था थी। जिन शतों पर रिजर्व बैंक देशी बैंकरों को त्रापने से सम्बन्धित करने के लिये तैयार थी वे ये थीं—

जो देशी बैंकर रिजर्व बैंक से सीघा सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं उन्हे अपने कारबार को शुद्ध बैंकिंग तक ही सीभित रखना हीगा। वे दूसरे प्रकार का व्यापार न सकेंगे। उन्हें अपने हिसाब को ठीक-ठीक रखना होगा तथा रजिस्टर्ड एकाउंटेन्ट से उसकी जाँच करवानी होगी श्रीर जब रिजर्व बैंक चाहेगी तो उनके हिशाब का निरीच्या कर सकेगी। रिजर्व बैंक उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये जो
भी स्चना चाहेगी देनी होगी। शिड्यून बैंक जो भी विवरण-पत्र श्राने कारबार के
सम्बन्ध में समय-समय पर रिजर्व बैंक को मेजते हैं वे उन्हें भी मेजने होंगे। श्रीर
लेनदेन का लेखा (Balance sheet) इत्यादि जो कम्पनी ऐक्ट के श्रानुसार बैंक
को प्रकाशित करना श्रनिवार्य है वे उन्हें भी प्रकाशित करने होंगे। जब कि देशी
बैंकरों की जमा उनकी पूँजी से पाँच गुनी श्रधिक हो जावे तभी उन्हें रिजर्व बैंक में
श्रनिवार्य जमा रखनी होगी। श्रन्थथा उन्हें रिजर्व बैंक में श्रनिवार्य जमा रखने की
कोई श्रावश्यकता न होगी। प्रत्येक देशी बैंकर को कम से कम २ लाख की पूँजी
(Capital) रखनी होगी जिसे ५ वर्षों में बढ़ाकर ५ लाख करनी होगी। जो देशी
बैंकर इन शर्तों को पूरा करेंगे रिजर्व बैंक उनकी हुण्डियों तथा बिलों को मुनावेगा।
सरकारी प्रतिभृति की जमानत पर ऋणा देगा तथा उनये को एक स्थान से दूसरे स्थान
पर मेजने के लिये वही सुविधार्य देगा जो वह शिड्यल बैंक को देता है।

इस प्रस्ताव को भी देशी वैङ्कों ने स्वीकार नहीं किया। व न तो अन्य व्यापार को छोड़ना ही चाहते हैं और न अपने हिसाव का निरीच्या सही कराने के लिये तैयार हैं। रिजर्व वैङ्क का इस प्रस्ताव से उद्देश्य यह था कि देशी वैंकर अपन कारबार को छोड़कर अधिकाधिक डिपाजिट वैंकिंग की ओर लावें तथा जिस प्रकार से संयुक्त पूँची वाजे कारबार करते हैं वे भी कारबार करें। किन्तु देशी वैंकर अपने पुराने ढंग को छोड़ने को तैयार न थे और न वे यही पसंद करते थे कि वे किसी को अपना हिसाब दिखलावें। इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्त में देशी वैंकर को रिजर्व वैंक के बतलाये हुए मार्ग पर ही चलना होगा। किन्तु रिजर्व वैंक के अधिकारियों को यह समफना चाहिये कि देशी वेंकर एकरात्रि में अपनी पुरानी पद्धति को छोड़कर आधुनिक वैंकिंग पद्धति को किस प्रकार अपना सकते हैं। रिजर्व वैंक और देशी वैंकर्स का कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका। यद्यि रिजर्व वैंक ने अपनी और से उपरोक्त शर्तों पर देशी वैंकर्स को सम्बन्धित करने का प्रस्ताव वापस नहीं लिया है। इस प्रकार देशी वैंकर्स को सम्बन्ध तथा रिजर्व वैंक के सम्बन्ध का प्रकार बाप परन समाप्त नहीं हो यदि दोनों ही पच अपने अपने हिस्टकोया में थोड़ा परिवर्तन कर दें तो इस समस्या का हल श्रीघ हो सकता है।

कुछ प्रान्तीय बैंकिंग जाँच समितियों ने बैंकिंग के साथ श्रन्य व्यवसाय को बुरा नहीं बतलाया। उनके कथनानुसार भारत जैसे देश में यह सर्वथा उपयुक्त है। देशी बैंकर्स श्रन्य व्यापार को प्राचीने काल से करते सफलतापूर्वक करते चले श्रा रहे हैं। श्रदः रिजर्व बैंक को उन्हें बन्द करने का श्राग्रह नहीं करना चाहिये। देशी

वैंकर्स को भी चाहिये कि वे अपनी कार्य पद्धति में मुघार करके संसार की प्राप्त का अनुगमन करें। हिसाब-किताब के अंकेद्यण से भयभीत न हों, क्योंकि अंकेद्यण से गोपनीयता भंग नहीं होती।

यदि रिजर्व वैंक से देशीं बैंकर का सीघा सम्बन्ध कुछ समय तक करते हैं तों इनका सम्बन्ध अनुसूचित बकों के द्वारा स्थापित करने के प्रश्न विचार करना चाहिये। कुछ व्यापारिक वैंक देशी बैंक्स तथा साहूकारों की हुंडियाँ को क्रय कर लेते हैं। यदि ये बैंक देशी बैंक्स से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करें तो रिजर्व बैंक का कार्य सरल हो सकता है। व्यापारिक बैंक देशी बैंक्स के सम्बन्ध में जो सूचनायें प्राप्त करते हैं उससे रिजर्व बैंक लाभ उठा सकती है। अनुसूचित बैंकों से देशी बैंक्स का जिंतना धनिष्ट सम्बन्ध स्थापित होगा उतने ही देशी बैंक्स रिजर्व बैंक के निकट आ जायेंगे।

२१ जुलाई सन् १६५१ को ग्रांखिल भारतीय सर्गफ कान्फ्रेंस में भाषण देते हुए रिजव बैंक के गवर्नर श्री रामाराव ने देशी बैंकर्स के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा—"रिजव बैंक को इस बात से प्रसन्नता होगी कि देश के श्रार्थिक विकास में देशी बैंकर्स पूरा सहयोग प्रदान करें। किन्तु यह सहयोग तभी सफल हो सकता है जब देशी बैंकर्स श्रुपने पुरानी पद्धति में परिवर्तन करके श्राधिन करंग से कार्य करें।"

रिजर्व बैंक ने प्रामीण साल की जाँच करने के लिये एक अलिल मारतीय प्रामीण साल सर्वेच्चण समिति नियुक्त की । इस समिति ने भी देशी बैंकर तथा साहूकारों के महत्व को स्वीकार किया और रिजर्व बैंक से यह अनुरोध किया कि देशी बैंकर्स की सेवाओं को अधिकतम लाभदायक बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। रिजर्व बैंक ने समिति की सिफारिशों को सिद्धांततः मान लिया है और देशी बैंकर्स को अधिक उपयोगी बनाने तथा उनसे घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

प्रश्न

1. Describe briefly the functions of indigeneous bankers. Point out the criticisms that have been levelled against them. Suggest remedies to remove those defects.

देशी बैंकरों के कार्यों का संद्वेप में वर्णन कीजिये। उनकी क्या आलोच-नार्यें हुई हैं ! उनके दोषों को दूर करने के सुभाव दीजिये।

2. What part is played by the indigenous bankers in financing the inland trade of this country? Examine their prencipal defects, and suggest measures for improvement.

इस देश के आंतरिक व्यापार की आर्थिक सहायता में देशी बैंकर क्या

कार्य करते हैं ? इनके मुख्य दोषों की विवेचना की जिये तथा मुझार के मुक्ताब दीजिये।

3. What do you understand by Indigeneous Banking in India? What attitude has been adopted by the Reserve Bank of India in linking indigeneous bankers with it?

भारतीय देशी वैंकरों से श्रापका क्या तात्मर्य है ! रिवर्ष वैंक ने इनसे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये क्या नीति श्रपनाई है !

4. Do you consider the services of moneylenders in India useful to society? What part do they play in helping agriculture? What are their defects?

क्या ऋषं भारतीय साह्कारों की सेवाओं को समाज के किये लाभदायक समभते हैं ? ये कृषि की सहायता में किस प्रकार भाग लेते हैं ? इनकी कमियाँ बतलाइये।

5. What are the functions of a joint-stock bank? In what respects does it differ from indigeneous banker?

सम्मिलित पूँची वाली बैंक देशी बैंकर्स से किस प्रकार मिन्न होती हैं। दोनों के कार्यों की तुलना की जिये।

भ्रध्याय १२

बैंकिंग के सिद्धान्त

(Principles of Banking)

बेंक की वित्तराशि के साधन—बेंक अपनी वित्तराशि की निम्नलिखित साधनों से एकत्रित करती हैं:—

(१) पूँजी—प्रत्येक बेंक के लिये यह आवश्यक है कि वह कुछ न कुछ निजी पूँजी लगाकर श्रपना कार्य प्रारम्भ करे। श्रंशािरयों की बेंकों के लिये यह आवश्यक है कि उनकी चुकता पूँजी, चालू पूँजी के ५० प्रतिशत से कम न हो। पर्याप्त मात्रा में चालू पूँजी रखने के लिये बेंक की चुकता पूँजी निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:—

यदि बैंक दो राज्यों में काम करती है तो उसकी चुकता पूँ जी तथा सुरिह्मत कोष कम से कम भ लाख होना आवश्यक है।

यदि बैंक बम्बई अथवा कलकत्ते में है तो चुकता पूँजी १० लाख होना चाहिये।

यदि वैंक की सारी शाखायें एक ही राज्य में हैं तो प्रधान कार्यालय के लिये १ लाख रुपया श्रीर जिले की अन्य शाखात्रों के लिये १० हजार रुपया प्रति शाखा श्रीर अन्य शाखात्रों के लिये २५ हजार रुपया प्रति शाखा होना चाहिये। परन्तु यह कुल ५ लाख रुपये से अधिक होना आवश्यक नहीं है।

यदि बैंक का केवल एक ही कार्यालय है तो उसकी चुकता पूँजी तथा सुरिच्चत कोष ५० हजार रुपया पर्याप्त है। यदि शाखायें कलकत्ता, बम्बई में हैं तो ५ लाख रुपये के ऋतिरिक्त कलकत्ता, बम्बई की प्रत्येक शाखा के लिये २५ हजार रुपया होना ऋनिवार्य है। कुल मिलाकर १० लाख रुपये से ऋषिक होना ऋत्वरयक नहीं।

(२) सुरिच्ति कोष—बैंकों के लिये यह आवश्यक है कि वे लाभ वितरण करने से पहले कुछ लाभ का कम से कम २० प्रतिशत सुरिच्ति कोष में तब तक रखती रहें जब तक सुरिच्चित कोष चुकता पूँची के समान न हो जाय। सुरिच्चित कोष का रखना इसिच्ये अनिवार्य कर दिया गया है जिससे संकर्ट काल में उस कोष दो काम में लाया जा सके। बहुत-सी बैंक सुरिच्चित कोष चुकता पूँची के समान हो जाने के पश्चात् भी

लाभ वितरित करने से पहले लाभ का कुछ न कुछ प्रतिशत अपने कीय में रखकर अपनी आर्थिक स्थिति को हद बनाती हैं।

- (३) जनता से जमा प्राप्त करना—वैंकों का मुख्य कार्य बनता की बचत को अपने यहाँ जमा करके उसका अधिकाधिक लाम उठाना है। उनता हैं में चार प्रकार से रुपया जमा किया करती है:—
- (श्र) स्थाई जमा खाता (Fixed Deposit Account)—कैंक के इस खाते में घन एंक निश्चित समय के लिये जमा किया जाता है श्रीर घन वापस होने की अवधि समाप्त होने अथवा वैंक को आवश्यक स्चना देने पर निकाला जा सकता है। बाजार दर धनराशि और अवधि के अनुसार घटती-बद्दी रहती है। जमा खाते समय वैंक जमा रसीद देती है जिसको निकालते समय लौटाना अनिवार्य है। यह रसीद हस्तांतरित नहीं की जा सकती है।
- (ब) चालू खाता (Current Account)—इसमें धन चाहे जब जमा कराया अथवा चेक द्वारा निकाला जा सकता है। इसे व्यापारिक खाता भी कहते हैं। श्रीर बैंक इस पर बहुत कम ब्याज देती है। परन्तु इसमें एक न्यूनतम रकम जमा होनी चाहिये तथा इसके न होने पर बैंक कुछ भीस प्राहक से लेती है। कोई भी नया आदमी बैंक के किसी पुराने ग्राहक की साची से ही यह हिसाब खोल सकता है। उसके हस्ताचर श्रीटांग्राफ बुक में लिये जाते हैं तत्पश्चात् बैंक के साथ सारे लेन-देन के कागज-पत्रों पर वे ही हस्ताचर होने चाहिये। बैंक ग्राहक को एक पास हुक, एक जमा हुक और एक चेक बुक भी देती है।
- (स) गोलक खाता (Home Safe Account)—मितव्ययता की आदत डालने के लिये एक गोलक ग्राहक को घर ले जाने के लिये दी जाती है जिसमें वह घन डालता रहता है। एक निश्चित समय के पश्चात् बैंक उसे खोलकर ग्राहक के नाम में यह रकम जमा कर देती है। इस पर बहुत कम ब्याज दी जाती है। वह ग्राहक को पास बुक और चेक बुक भी देती है।
- (द) चालू खाता (Current Account)—यह खाता एक खुला हिसाब होता है जिसमें रुपया जमा करने वाला किसी समय भी रुपया जमा कर सकता है तथा निकाल सकता है। इस हिसाब पर प्रथम श्रेगी की बैंक कोई न्याज नहीं देती। यदि चालू खाते में एक निश्चित रकम से रुपया कम हो जाता है तो जमा करने वाले को कुछ न्यय करना पज़ता है। इम्पीरियल बैंक आप इंडिया में कम से कम ५०० रुपये की रक्म रहनी चाहिये। यदि हिसाब रखने वाले के रुपये ५०० से कम होंगे तो स्टेट

चाल् खाता खोलने की विधि—चाल् खाता खोलने के लिये सर्वप्रथम श्रावश्यकता यह होती है कि बैङ्क के किसी पुराने श्रोर विश्वसनीय ग्राहक श्रथवा श्रन्थ किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा खाता खोलने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को श्रपनी साख के विषय में बैङ्क के उच्चाधिकारियों को श्रावश्यक शान कराया जाये। यह ज्ञान प्राप्त करना बैङ्क इसलिये श्रावश्यक समभती है कि जिससे उसे भविष्य में श्रविश्वस्त, जाल-साज तथा दिवालिया व्यक्तियों से हानि न हो।

बैक्क प्राहक की श्रार्थिक दशा से संतुष्ट हो जाते ही हस्ताच्चर बही पर उसके हस्ताच्चरों का नमूना (Speciman Signature in Autograph Book) लेती है जिससे उसके घनादेशों पर हुए हस्ताच्चरों को नमूने के हस्ताच्चरों से मिलाया जा सके। जो बैक्क ऐसा किये बिना ही जाली एवं मूठे घनादेशों का मुगतान कर देती हैं उन्हें प्राहकों को उक्त प्रकार से हुई च्रित की पूर्ति करनी होती है। जहाँ कोई व्यापारिक कर्म चालू खाता खोलती है तो उसके सभी सामेदारों को हस्ताच्चर करने पड़ते हैं, जहाँ यह श्रिषकार एक श्रयवा दो सामेदारों को देना श्रावश्यक हो वहाँ पर सभी सामेदारों को एक घोषणा-पत्र मर कर बैक्क को दे देना चाहिये। कम्पनियाँ चालू खाता खोलते समय बैक्क के पास सिद्धान्त-पत्र (Memorandum), श्रिषकार-पत्र (Articles) तथा प्रार्थना-पत्र (Resolution) जमा कर देती हैं। इससे बैक्क के श्रावकारी यह जान लेते हैं कि उक्त खाता कम्पनी के नाम से ही खोला जा रहा है। स्कूल, कालेज, श्रयस्ताल, नगरपालिका श्रादि के खाते खोलने के लिये भी बैक्क के पास प्रसाव-पत्र जमा करना श्रावश्यक है।

चालू खाता खोलने वाले को प्राप्त होने वाली बहियाँ

- (अ) पास बुक—इस चालू खाता खोलने वाले व्यक्ति के दिन-प्रति-दिन होने वाली जमा और नाम की रकमों का उल्लेख तिथिवार दिया जाता है। उसे अपनी पास बुक को प्रति मास, पखवारे अथवा इसी प्रकार निश्चित की गई अन्य अविधि के पश्चात् बैक्क मेजना पड़ता है जिससे उसमें इस अविध के मध्य में किये गये समस्त जमा तथा नाम के लेखों को दिया जा सके। पास बुक में तिथि, विवरण, धनादेश, संख्या निकाली गई रकम तथा खजान्ची के हस्ताच्चर के लिये भिन्न-भिन्न खाने बने रहते हैं। प्रत्येक जमा नाम के समय खजान्ची अथवा अन्य अधिकारी इनमें आवश्यक खेला कर देते हैं।
- (आ) जमा की बही (Pay-in-Book)—इस बह्ध में १०, २०,५० अथवा १०० की नंख्या में छुपे फार्म होते हैं। इन फार्मों को रुपया जमा करते समय प्रयोग करना आवश्यक होता है, क्योंकि उस समय इनमें उनकी क्रम संख्या, जमा की

कम, जमा खाते वाले प्राहक का नाम तथा जमा की तिथि लिखनी पहती है। इसके । एचात् इसे बैक्क के खजान्ची को दे दिया जाता है। खजान्ची इसके दाहिनी छोर के गाग को अपने पास रख लेता है तथा बाई आरे के माग को हस्ताच्चर करने के गाग एप में लौटा देता है। इस पर बैक्क की मुहर भी लगा दी जाती है। आवश्यकता के समय इसे ग्राहक रूपया जमा करने के प्रमाश्य-स्वरूप न्यायालय में प्रस्तुत कर उकता है।

चेक जुक—इसमें १०, २५,५०, १०० पृष्ठों के रूप में चेक जुड़े रहते हैं तथा इनका प्रत्येक पृष्ठ पुस्तिका से निकाला जाने पर चेक (धनःदेश) कहलाता है। इसमें चेक एवं उसका प्रतिरूपक दो माग होते हैं जिसमें चेक लिखने की तिथि, सुगतान की रकम, (अच्चरों तथा शब्दों में), सुगतान करने वाले तथा पाने वाले व्यक्ति का नाम आदि सभी बातों का उल्लेख रहता है। यदापि वैद्ध में साधारण कागज पर लिखे गये आदेश पर रुपया सुगतान करने पर कोई रोक-टोक नहीं है तथापि सुगतान की सुविधा, जाल से सुरुद्धा, घोखेबाजी से बचत तथा आकृति की समानता लाने के लिये चेक का विशेष एवं निश्चित रग-रूप होना आवश्यक है। वैद्ध इन्हें अपने ग्राहकों को निःशुल्क वितरित करती है।

प्राहकों के चेकों का संप्रह—वैङ्क अपने ग्राहकों के चेकों तथा दृषिदयों का रूपया संग्रह करके उसके चालू खाते में बमा करती है। इस संबन्ध में बैंड्क का यह कर्त्तव्य है कि पूरी सावधानी से कार्य करे। चेक तथा दृ्ष्ण्डी को उचित समय पर प्रस्तुत करके रूपया प्राप्त करे। ग्राहक से बैंड्क को जिस दिन चेक प्राप्त हुआ है उसी दिन या श्रिषक से श्रिषक अगले दिन उस चेक को उस बैंड्क पर प्रस्तुत करे जिसके लिये यह लिखा गया है। यदि बैंड्क ने चेक प्रस्तुत करने में देर की श्रीर इस बीच बैंड्क लिखने वाले ने अपने भुगतान स्थिगत कर दिये तो इससे चेक जमा करने वाले को हानि होगी उसका उत्तरदायित्व संग्रह करने वाली बैंड्क पर है। यदि चेक श्रनाहत होकर वापस आ गया है तो वह चेक श्रापत्ति-पत्र सहित ग्राहक के पास तुरन्त मेज देना चाहिये।

जमा करने वाले द्वारा लिखे गये चेकों का भुगतान वैद्ध का कर्तव्य है कि वह जमा करने वाले द्वारा लिखे गये चेक का, यदि चेक नियमानुसार लिखा गया है श्रीर वह बैक्क के कार्य-समय में प्रस्तुत किया गया है; तुरन्त मुगतान कर दे। क्योंकि ऐलान करने पर चेक लिखने वाले की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। यदि बैक्क ने सद्विश्वास के साथ चेक का भुगतान कर दिया है तो यह मुगतान जमा करने वाले के नाम लिखा जायगा। बैक्क को निम्नलिखित श्रवस्थाश्रों में भुगतान श्रस्वीकृत देकर ना चाहिये —

(१) जब चेक लिखने वाले ने चेक का भुगतान रोक दिया हो तथा इसकी सचना बैड्ड को दे दी हो।

(२) जब चेक लिखने वाले की मृत्यु हो गई है ऋौर उसकी मृत्यु का नैङ्क को

पता चल गया हो।

(३) यदि चेक लिखने वाला दिवालिया हो गया हो श्रीर न्यायालय ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया हो।

(४) जब चेक लिखने वाला पागल हो गया हो ऋौर उसे न्यायालय ने पागल

घोषित कर दिया हो।

(५) जब चेक लिखने वाले ने श्रापने खाते की समस्त रकम किसी श्रन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित कर दी हो।

(६) जब चेक का भुगतान माँगने वाले के ऋधिकार में कोई दोष हो ऋौर

बैङ्क को इस दोष का पता हो।

(७) जब न्यायालय द्वारा भुगतान न करने का ऋादेश प्राप्त हो गया हो।

निम्नलिखित अवस्थाओं में भी बैक्क चेक का भुगतान करने से इनकार कर सकती है, किन्तु यदि सद्विश्वास के साथ चेक का भुगतान कर दिया है तो चेक की रकम खातेदार के खाते में नाम डाल दी जायेगी।

- (१) जब चेक पर कोई तारीख न पड़ी हो। ऐसी अवस्था में बैक्क को यह समभ्यते का अधिकार है कि जिस तारीख को चेक प्रस्तुत किया है, चेक उसी तारीख को लिखा गया है।
 - (२) चेक पर ऋागामी तारीख पड़ी है।
 - (३) यदि चेक लिखने वाले के हस्ताच्चर भिन्न हैं।
 - (४) यदि चेक में बिना चेक लिखने वाले के कोई परिवर्तन न हो गया है।
 - (५) जब शब्दों त्रौर त्रंकों में लिखी रकम में मिन्नता है। ऐसी श्रवस्था में जो रकम शब्दों में लिखी गई है वही ठीक मानी जाती है; किन्तु सावधानी के तौर पर बैक्क उस रकम का भुगतान करता है जो शब्दों तथा श्रंकों में लिखी दोनों में से जो मी कम है।
 - (६) जब जमा करने वाले के खाते में श्रपर्याप्त रकम है श्रथवा श्रमी तक जमा किया हुश्रा कोई चेक संग्रह नहीं हुश्रा है।
 - (७) जब रेखार्कित चेक खिड़की पर नकद भुगतान के लिये प्रस्तुत हुआ है। उपरोक्त परिस्थितियों में शदि बैङ्क ने चेक का भुगतान करने से इनकार क दिया है तो इसके लिये बैङ्क को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा संकता।

चेंक के संबन्ध में अन्य सब बातों का अध्ययन एक प्रथक अध्याय में किया जायेगा।

बैंक के धन का उपयोग—बैङ्क जनता से जमा प्राप्त करती है और उस स्वयं को जमा करने वालों के हितों को हिन्द में रखते हुए इस प्रकार उपयोग करती है जिससे बैङ्क को अधिक से अधिक लाम भी हो जाये और किसी प्रकार की बैक्किम भी न उठानी पड़े। इन सब बातों को हिन्द में रखते हुए बैङ्क अपने धन को दो प्रकार के विनियोगों में लगाती है—

(१) लाम न देने वाले विनियोग तथा (२) लाम देने वाले विनियोग ।

लाभ देने वाले विनियोग में नकद कोष तथा मवन इत्यादि आते हैं। नकद कोष का अर्थ है कि बैड्डों के कोष में तथा केन्द्रीय नैक्क के कोष में रखा हुआ। धन। इसको हस्तस्य राशि भी कहते हैं। यह बैड्ड की प्रथम रह्म पंक्ति है। यह निश्चित करना बहुत किन है कि नकद कोष और माँग पर देय धन का क्या अनुपात होना चाहिये। साधारणतया बहुत कम धन माँग पर लगाया जाता है। एक सुन्दर बैड्ड का मवन प्राहकों को जुभाता है। परन्तु श्री राक्त के अनुसार तुरन्त उनका विकय होना किन है तथा इससे बैड्ड की बदनामी भी होती है। इसलिये बैड्ड को इनमें बहुत कम स्पया लगाना चाहिये।

लाभ देने वाले विनियोगों में निम्नलिखित त्राते हैं :--

(१) याचना द्रव्य तथा अल्पकालीन ऋण (Money at Call and Short Notice)—यह बैक्क की दूसरी रह्मा पंक्ति बनावी है। बहाँ द्रव्य बाजार कन्न अवस्था में है वहाँ बैक्क बिलों और स्टाक बाजार के दलालों को उच्च अंगी की देखनहार प्रविभृतियाँ गिरवीं रखकर थोड़े से समय के लिये ऋण देती हैं तथा आवश्य-कता के समय वापस ले लेती हैं। मारतवर्ष में बड़े नगरों के अविरिक्त हुएडी बाजार उजत नहीं है। अतः बैक्क नकद साख (Cash credit) अथवा अधिविकः (Overdraft) पर जमानत लेकर ऋण लेती है। ऐसे ऋण यदि माँग पर दुरन्त ही नहीं लौटाये जाते तो बैक्क जमानतों को बेचकर अपना नकद कोष बढ़ा लेती है। ऐसे ऋण शांति के समय अच्छे है, संकट काल में नहीं।

Cash Credit—यह वह प्रकार है जिसमें बैक्क व्यापारी के चालू खाते में ली गई रकम को जमा कर दे श्रीर व्यापारी के नाम से एक ऋषा खाता खोल कर व्यापारी के नाम डाल दे। इस प्रकार ऋषा देने में बैक्क व्यापारी की व्यक्तिगत साल के श्रांतिरिक्त व्यापारी के माल को श्रांपेने यहाँ सुरिच्चित खती है। इस प्रकार माल की व्यक्तिगत जमानत पर ही नकद साख दी जाती है। माल के पूरे मूल्य के बराबर

ऋण नहीं मिल सकता। बैंक्क प्रायः माल के मूल्य के ६० प्रतिशत से श्रिषिक ऋण नहीं देती। शेष को मार्जिन के तौर पर इसिलये रख लिया जाता है कि माल के मूल्य में सदैव उतार-चढ़ाव होता रहता है। श्रीष्र खराव होने वाले माल पर ऋण नहीं दिया जाता। यदि किसी समय जमानत में रखे हुए माल का मूल्य पर्याप्त कम होने लगता है तो बैंक्क ऋणी व्यापारी को यह सूचना देती है कि ऋण का कुछ रुपया वापस कर दिया जाये नहीं तो माल को बेचकर ऋण का मुगतान कर दिया जायगा। नकद साख में बैंक्क की जोखिम कुछ कम होती है। श्रतः व्याज की दर भी कम होती है। परन्तु व्याज के श्रितिरिक्त ऋणी व्यापारी को बैंक्क के गोदाम का किराया भी देना पड़ता है जिससे बैंक्क माल मुरचित रखती है। नकद साख में यदि किसी समय व्यापारी थोड़ा बहुत माल छुड़ाना चाहे तो यह उसी श्रमुपात से ऋण का मुगतान करके छुड़ा सकता है क्योंकि वह समस्त माल को श्रपने पास न रख कर उतना ही लाते रहते हैं श्रीर बेचते रहते हैं।

Overdraft-यह पहले ही बैड्ड के साथ तय कर लिया जाता है कि त्रावश्यकता पड़ने पर व्यापारी अपने चालू खाते के समय जमा की हुई रकम से अधिक कितनी रकम निकाल सकता है। व्यापारी को अधिक निकाले हुए धन पर च्याज देनी पड़ती है। इस प्रकार का ऋण व्यापारी को व्यक्तिगत साख पर अरथवा प्रतिभृतियों की जमानत पर मिलता है। इसमें व्यापारी को पूरी तय की हुई रकम पर न्याज नहीं देनी पड़ती क्योंकि इसमें नकद साख की तरह से व्यापारी का ऋण खातां नहीं लोला जाता। इसमें तो जिस समय जितनी रकम व्यापारी की जमा की हुई रकम से ऋधिक निकाल देता है उसे उतने ही पर ब्याज देनी पड़ती है। ऋोवर ं ड्राफ्ट द्वारा दिया हुन्ना ऋण हर Transaction के पश्चात् घटता-बढ़ता रहता है। मान लीजिये किसी व्यापारी के चालू खाते में १००० रुपये जमा हैं तथा जमानत दे कर उसने तय कर लिया कि उसको २००० रुपये तक स्रोवर ड्राफ्ट मिल सकता है। इस प्रकार व्यापारी ऋपने जमा किये हुए १००० रुपये जमा समेत ऋपने चालू खाते से ३००० रुपये निकाल सकता है। मान लीजिये उसने १५०० रुपये की रकम एक ं मास के पश्चात् पहली नवम्बर को निकाली श्रीर फिर ५०० रुपये की रकम पहली दिसम्बर को फिर ५०० रुपये पहली जनवरी को निकाले, ३०० रुपये पहली फरवरी को अपने हिसाब में जमा कर दिये और फिर ५०० रुपये अपने चालू खाते में पहली मार्च को निकाले । इस प्रकार पहली मार्च को उसके पास १००० रूपये का स्रोवरङ्गाफ्ट हुन्ना जिसका भुगतान वह ३१ मार्च तक १००० रुपये पर ब्याज नहीं देगा । पहली नवम्बर को उसने ५०० रुपये का श्रोवरङ्गपर्ट लिया है। श्रातः पहली नवम्बर को ५०० की न्याज होगी। पहली दिसम्बर को ५०० रूपये फिर निकालने से १००० रुपये का त्रोवरड्राप्ट हो गया इसिलये दिसम्बर मास की न्याच १००० रुपये पर देगा। पहली जनवरी को फिर ५०० रुपये निकालने पर १५०० रुपये का त्रोवर-ड्रापट हो गया। श्रतः जनवरी मास का न्याच १५०० रुपये पर देगा। पहली फरवरी को २०० रुपये जमा कर देने से श्रोवरड्रापट १२०० रुपये का रहग्या। इसिलये फरवरी मास का न्याच १२०० रुपये पर देगा। पहली मार्च को ५०० रुपये फिर निकालने से त्रोवरड्रापट १७०० रुपये का हो गया। इसिलये केवल मार्च मास का न्याच १७०० रुपये पर देगा। ये सब सुविधाएँ होने के कारग्र क्यायार लोग क्रोवरड्रापट करते हैं; परन्तु श्रोवरड्रापट के द्वारा श्रिषक सूर्ण नहीं मिलता।

- (२) बिलों की कटौती (Discounting of Bills) यह बैंड्र की तीसरी रचा पंक्ति हैं। बिल कटौती का ऋर्य है कि बिल का ऋाब का मूल्य ब्याब घटा कर चुकाना। केवल निजी जमानत पर यह ऋण दिया जाता है। बिल कटौती घरों तथा बिल के दलालों से भी भुनाये जाते हैं। जो बाद में बैंड्र से बिल भुनवा लेते हैं। बैंड्र को यह कार्य करते समय सावधानी से यह देख लेना चाहिये कि बिल ठीक प्रकार से नियमानुसार लिखे, बेचे तथा स्वीकृत किये गये हैं और ऐसा करने वालों की ऋार्यिक दशा ऋच्छी है, बैंड्र को लगातार पकने वाले बिलों पर रकम लगानी चाहिये जिससे प्राहकों की माँग पूरी होती रहे।
- (३) विनियोग (Investment)—बैङ्क अपनी रकम सरकारी साल पत्र, जनहित के लिये बनी अर्घ सरकारी संस्थाओं तथा उद्योग-धन्धों सम्बन्धी साल-पत्रों में लगाती हैं। यह बैङ्क की चौथी रच्चा पंक्ति है।

जिन प्रतिभूतियों में बैङ्क अपना धन लगाती हैं वे निम्नलिखित हैं :-

- (अ) सरकारी प्रतिभूतियाँ के श्रांतर्गत वे सारी प्रतिभृतियाँ श्रा बाती हैं जो केन्द्रीय, प्रान्तीय, तथा रियासतों की सरकार बेचती हैं। ये सबसे श्रिषक सुरिच्चित तथा सरलता से बस्ल की जाने वाली लामप्रद प्रतिभृतियाँ हैं। बैड्ड में जनता का विश्वास भी इनसे जमता है। श्रातः वे इनमें श्रापना घन लगाती हैं। परन्तु संकट काल में ये श्राच्छी नहीं हैं।
- (ब) द्यर्घ सरकारी प्रतिभृतियाँ —के त्रांतर्गत स्थानीय नगरपालिका, द्रांत-रिम जिला परिषद तथा ट्रस्ट द्वारा बेची जाने वाली प्रतिभृतियाँ त्राती हैं जो अपना दसरा स्थान खती हैं।
- (स) रेलवे की प्रतिभूतियाँ—के श्रंतर्गत रेलवे कम्पनियों द्वारा बेची बाने वाली प्रतिभूतियाँ श्राती हैं जिनकी सरकारी जमानत मी होती है। मारतवर्ष में रेलें सरकारी हो गई हैं। श्रत: प्रतिभृतियाँ यहाँ कुछ Light Railway Companies द्वारा बेची जाती हैं।

- (द्) जनिह्त संस्थाओं की प्रतिभूतियाँ—के श्रंतर्गत, बैङ्क, श्रंश, तथा श्राप्य श्राते हैं जो पानी बिजली श्रादि कम्पनियों द्वारा बेचे जाते हैं।
- (३) अन्य ऋगापत्र तथा स्टाक—के अंतर्गत अन्य खनिज आदि की कम्प-नियाँ आती हैं। बैङ्कर को इनमें रुपये नहीं लगाने चाहिये।
- (४) अन्य प्रकार के ऋग्ण—के अंतर्गत वे सारे ऋग आते हैं जो बैङ्कर अधिक समय के लिये नकद साख अथवा मुख्य ऋग्ण अथवा अधिविकर्ष के रूप में देता है। ये दो प्रकार के होते हैं:—
- श्च—सुरिच्चत—भारतीय बैंक प्रायः इसी प्रकार का ऋण देती हैं। बैङ्क जमानत रख कर रुपया देती हैं श्रीर समय पर सुगतान न होने पर उन्हें तुरन्त बेच देती हैं। श्रथवा किसी श्रन्य बैङ्क में गिरवी रख कर रुपया प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार वे ऋणों पर कम ब्याज मिलता है। बैङ्क निम्नलिखित जमानतों पर ऋण देती हैं:—
- (क) स्टाक बाजार में बिकने वाले पत्र—के ग्रंतर्गत वे सरकारी तथा ग्रन्थ कम्पनियों के स्टाक ग्राते हैं जो श्रन्छा श्रिधकार देने वाले तथा न देने वाले दोनों ही होते हैं।
- (ख) अच्छा अधिकार देने वाले पुर्जे—के अंतर्गत विनिमय के बिल आते हैं जिनका मूल्य निर्धारित रहता है। अविध बीतने पर वस्ती होना निश्चित है तथा उनको दुबारा केन्द्रीय या अन्य बैक्क से सुनाया भी जा सकता है। यदि बैक्कर ने इनको अच्छी नीयत से प्राप्त किया है तो इसका इन पर अच्छा अधिकार रहता है। बैंकर को स्थान रहना चाहिये कि उसे उनको गिरवीं रखने के बजाय सुना ही लेना चाहिये। इनमें दोष यह है कि इनके बीतने पर बैंकर को इनकी वस्ती करनी पड़ती है।
 - (ग) माल अथवा माल के अधिकार-पत्र—माल गोदाम की कुन्जी लेकर बहाज, बिल्टी, डाकपत्र तथा रेलवे बिल्टी आदि को रख कर धन उधार दिया जाता है। मारतवर्ष में गोदामों की कमी प्रमापीकरण (Standardisation) तथा संगठित बाजार न होने के कारण यह उन्नति नहीं कर पाया है।
 - (घ) जानबीमा-पत्र— बैंकों का बहुत थोड़ा घन इन पर उधार दिया जाता है क्योंकि बीमा कम्पनी स्वयं ही ऋपने बीमा पत्रों के ऋाधार पर ऋग्ण देती हैं। इसका ब्याज मूल्य (Surrender Value) सरलता से या तो उसी में लिखा रहता है नहीं तो बीमा कम्पनी से ज्ञात किया जा सकता है। इसकी ऋावश्यकता पड़ने पर ऋग्य व्यक्ति के नाम बेची भी जा सकती है। ऋगण लेने वाले के एक विशेष ऋग्य पहुँचने पर ऋग्यवा मृत्यु होने पर बीमा-पत्र स्वयं ही प्रक जाता है।
 - (४) श्रचल सम्पत्ति बैंकर को श्रचल सम्पत्ति पर्य घन नहीं देना चाहिये

क्योंकि उसके खराव होने, श्राग लगने का भय रहता है तथा इसको बेचने से पहले कई वैधानिक कार्यवाहियाँ करनी पड़ती हैं तथा श्रुण लेने वाले के वह पूर्ण श्रिधकार में है श्रथवा नहीं, यह शत करने में बहुत कठिनाई पड़ती है।

त्रेंक जो धन ब्याज पर लगाती है वह दूसरों का होता है तथा उसके मुख्य रखने के लिये यह आवश्यक है कि ब्याज पर पूँजी लगाते समय निम्न लिखित साब-धानी से काम लें—

- (१) वैंक को अपने प्राहक को इतनी पूँ जी उधार नहीं देनी चाहिये जिसके अपूरण मात्र से ही उसका व्यापार चल सके। बैंक को उसे कम पूँ जी नहीं देनी चाहिये जिससे कि वह निजी पूँ जी भी व्यापार में लगा सके तथा एक स्थान पर पूँ जी भी संग्रहीत न होने पाये।
- (२) अपने ऋणों को चुकाने के लिये उसे अपनी सम्पत्ति इस प्रकार रखनी चाहिये कि आवश्यकता के समर तुरन्त ही वह स्वयों में परिवर्तित को जा सके। इसीलिये उसे लम्बे ऋणों तथा ऋणपत्रों पर अचक सम्प्रत ति परिवर्तित को जा सके। इसीलिये उसे लम्बे ऋणों तथा ऋणपत्रों पर अचक सम्प्रत ती विस्तर रकम नहीं देनी चाहिये। क्योंकि एक मकान अथवा इसारत को तुरन्त ही बेचना म्हा मिल का है। परन्तु एक विल के रुपये प्राप्त करना सरल है। अतः वैकर वहां है जो विल का औ रहन का अतर समभता है तथा रहन पर बहुत कम उचार देता है, क्योंकि इसका उद्देश्य स्पये को चलायमान रखना है, रोकना नहीं।
- (३) उसे प्राहक को बड़ी रकम उधार नहीं देना चाहिये किन्तु उनकी ग्रह्म आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिये तथा धनराशि को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का उधार देनी चाहिये। उसे सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखने चाहिये क्यों कि इससे सारे के सारों का टूटने का भय रहता है।
- (४) बैंक को पुरच्चितता का ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि वह पूँ बी उसकी निजी नहीं है दूसरों की है तथा बैंकर तो केवल मध्यस्थ है।
- (५) उसे यह ध्यान रखना चाहिये कि उसको न्यापारियों के चालू लेन-देन का प्रबन्ध रखना है। उसको न तो सब प्रकार के न बिकने वाले धन को द्रव्य में परिगात करना है तथा उसे भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिये साख ही उत्पन्न करना है।
 - (६) उसको त्रपने पच्च में यथेष्ट गुंजायश (margin) रख लेनी चाहिये।
- (७) ऋगों का बराबर नवीनीकरण नहीं करना चाहिये । उपमोग के लिये ऋग नहीं देना च्याहिये। यदि ऋसावधानी से ऐसा हो भी जाय तो ऋन्य जनानत माँग कर शीघ ही कभी की पूर्ति कर लेनी चाहिये।

- (६) कम ब्याज की नीति भी सदैव ठीक नहीं रहती है। इससे अत्यधिक उधार हो जाता है।
- (१०) ऋग लेने वाले का चिरत्र भी ऋन्छा होना चाहिये यदि वह विश्वास पात्र, तत्वर तथा ईमानदार है तो इससे बढ़कर कोई जमानत नहीं होती।

ऋगा की सरचा-ऋग देते समय बैंक ऋगी से कुछ जमानतें माँगती है। परन्तु कभी-कभी प्राहक की व्यक्तिगत जमानत पर भी उसे ऋगा दे दिया जाता है श्रीर उससे एक प्रतिज्ञापत्र लिखवा लिया जाता है। यह श्ररिच्चत ऋग्ण कहलाता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि बैंक अपने रुपये की सुरद्धा का ध्यान किये बिना ही ऋण देती है। इस प्रकार के ऋण की जमानत ऋणी की तात्कालिक ऋार्थिक स्थिति तथा मविष्य में ऋगी के व्यापार ऋथवा कारबार की कैसी सम्भावना है, इस पर निर्भर होती है। इस प्रकार का ऋण देने से पूर्व बैंक ऋणी से पिछले कुछ समय का उसका लाम-हानि खाता तथा लेन-देन का लेखा माँगती है। इसका एक विश्वसनीय अंकेच्चक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। बैंक इनका अध्ययन करती है और अण लेने वाले की ऋार्थिक स्थिति का ऋनुमान लगाती है। इसके ऋतिरिक्त उस ऋगी की बाजार में कैसी साख है तथा उसका चरित्र कैसा है ? इसका ज्ञान बैंक प्राय: करती है। यदि ऋण लेने वाला वैंक का ग्राहक रहा है तो उसकी ईमानदारी, उसके कारवार की स्थिति तथा त्रार्थिक त्र्यवस्था का बैंक को ज्ञान होता ही है। इन पर त्र्यवलम्बित होकर बैंक व्यक्तिगत जमानत पर ऋण देना स्वीकार करती है। संद्वेप में कहा ज सकता है कि ऋण देते समय बैंक ऋण लेने वाले के चरित्र, योग्यता तथा पूँ जी इन तीन बातों का ज्ञान प्राप्त करती है। यदि बैंक ऋगा लेने वाले की व्यक्तिगत जमानत को यथेष्ट नहीं समऋती तथा ऋण माँगने वाला कोई अन्य आनुसंगिक जमानत मं नहीं दे सकता तो बैंक जमानत माँगती है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी साख में बैंक क का विश्वास हो ऋण माँगने वाले की गारंटी देने वाला व्यक्ति बैंक के लिये उत्तरदायं होगा अर्थात उस रुपये को स्वयं चुकायेगा। गारंटी अगण माँगने वाले के लिये मं सुविधाजनक है तथा बैंक के लिये भी एक अच्छी जमानत होती है। इसका एव दुर्गुंग भी है कि यदि गारंटी का लेख अञ्छे प्रकार से ठीक-ठीक तैयार नहीं किया गय है तो श्रागे चलकर बहुत फंफट खड़े हो सकते हैं तथा इस जमानत की उपयोगित जमानत करने वाले की ब्रार्थिक स्थिति पर ही निर्भर होती है। यदि गारंटी देने वाला दिवालिया हो बावे तो वह बेकार हो बाती है। बैंक को गारंटी देने वाले के चरित्र, उसकी योग्यता तथा साख का भी पता लगाना पड़ता है । बैंक को जब गारंटी-पत्र पर गारंटी करने वाले से हस्ताचर कराने हों तब उसे उसकी शतों को बकला देना चाहिये जिससे कि वह आगे चलकर यह न कह सके कि उसे शतीं का पता न था अथवा गारंटी-पत्र में क्या लिखा है यह जात न था। साथ ही गारंटी-पत्र में इस बात का मी उल्लेख कर दिया जाता है कि ऋण की राशि चाहे घटती-बढ़ती रहे किन्तु गारंटी पूरे ऋण के समान होगी।

व्यक्गित जमानत तथा गारंटी के ऋतिरिक्त ऋन्य ऋानुसंगिक उनानत भी नी जाती है। ऋगा लेने वाला कम्पनियों के ऋंश, डिवेंचर तथा बौंड इत्यादि कन्चा माल तथा तैयार माल ऋथवा उस माल सम्बन्धी कागज पत्र (जिनसे माल का स्वामित्व इस्तान्तरित होता है) तथा ऋचल सम्पत्ति इमारत इत्यादि जमानत के रूप में बैंक के पास रखता है।

बैंक नीचे लिखी हुई वस्तुत्रों की सुरचा के ऊपर भी ऋषा प्रदान करती हैं। किन्तु यह वस्तुयें ऐसी होनी चाहिये जो सरलता से विक सकें। इन वस्तुत्रों के सम्बन्ध में बैंक को कुछ सावधानी रखनी चाहिये जिनका वर्ष्यन नीचे किया जाता है:—

- (१) सरकारी प्रतिभृतियों की सुरत्ता पर—सरकारी प्रतिभृतियाँ स्टाक एक्स-चेंज में क्रय-विक्रय होती हैं। ऋतः यह बहुत ऋच्छी सुरत्त्वा समभी जाती हैं, क्योंकि ऋण न चुकने पर इन प्रतिभृतियों को सुगमता से बाजार में बेचकर धन प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु इस सम्बन्ध में बैंक को यह देखना चाहिये कि ये सरकारी प्रतिभृतियाँ रिजर्व बैंक के लिये कार्यालय में पंजीकृत हैं। एक स्पया शुल्क देकर उन प्रतिभृतियाँ को ऋपने नाम में करा लेना चाहिये। प्रतिभृतियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहना है, ऋतः इनके तत्कालीन मूल्य के ८०-६० प्रतिशत से ऋषिक ऋण न देना चाहिये। यदि इन प्रतिभृतियों की सुरद्धा पर कोई कंपनी ऋण ले रही है तो इसके साथ संचालक समिति के प्रस्ताव की एक प्रति भी माँगनी चाहिये।
- (२) अंश तथा ऋणपत्रों की सुरत्ता पर—सार्वजनिक कम्पनी के अंश तथा अमृणपत्रों का भी बाजार में कय-विकय होता है। यद्यपि यह पत्र इतने अधिक सुरिच्चित नहीं समके जाते जितनी सरकारी प्रतिभृतियाँ फिर भी कुछ अच्छी कम्पनियों के पत्र पूर्ण सुरिच्चत होते हैं। इन पत्रों की सुरत्वा पर भी बेंक ऋण प्रदान कर देती है। अंश पत्रों से ऋणपत्र अधिक सुरिच्चत समके जाते हैं, क्योंकि अंश-पत्रों पर तो लाभांश तभी मिलता है जब कम्पनी को लाभ हो। किन्तु ऋण्पत्रों पर तो ब्याज देनी ही पहती है कम्पनी को लाभ हो अथवा हानि। अंश तथा ऋणपत्रों के सम्बन्ध में बेंक को चाहिये कि सर्वप्रथम यह देखे कि कम्पनी कैसी है और उसके प्रवंध अभिक्तांओं की बाजार में क्या साल है श्रेतंशों पर पीछे कितना लाभांश घोषित किया गया है, कम्पनी की आर्थिक अवस्था कैसी है, ऋणपत्रों पर ब्याज की दर क्या है, यदि ब्याज की दर ऋषिक है तो कम्पनी की आर्थिक अवस्था कैसी है, त्राणपत्रों पर ब्याज की दर क्या है, यदि ब्याज की दर ऋषिक है तो कम्पनी की आर्थिक अवस्था की पूरी जाँच करनी

चाहिये, क्योंकि अधिक ब्याज देनी वाली कम्पनी की साल में सन्देह होना प्राकृतिक है। ऋगुपात्रों का भुगतान कम होना, उनके लिये कम्पनी की कोई स्थायी अथवा अस्थायी सम्पत्ति बंधक है या नहीं, सभी बातों की जाँच-पड़ताल करनी चाहिये। यह तो देखना आवश्यक है ही कि अंश-पत्र अथवा ऋगुपपत्र ऋगु माँगने वाले के नाम हैं अथवा नहीं और उनका कोरा बेचान (Blank transfer) कम्पनी के नाम में हो गया है या नहीं।

- (३) जीवन बीमा पालिसियों की सुरत्ता पर—जीवन बीमा पालिसियों के सम्बन्ध में बीमा श्रिधिनयम का यह विधान है कि कोई भी पालिझी जो दो वर्ष पुरानी है बाद में यह प्रमाणित करने पर रह नहीं हो सकती कि बीमित ने कपट द्वारा पालिसी प्राप्त की थी। दो वर्ष पश्चात् प्रत्येक जीवन बीमा पालिसी पर कुछ न कुछ, तात्कालिक मूल्य देय हो जाता है। मले ही बीमित पालिसी को मिविष्य में चालू रखे अथवा नहीं ख्रतः तात्कालिक मूल्य तक जीवन बीमा पालिसियों की सुरत्ता पर बैंक ऋष्य दे सकती हैं। किन्तु उन्हें यह देखना चाहिये कि पालिसी किस कम्पनी की है और उसकी आर्थिक अवस्था कैसी है, उसका तात्कालिक मूल्य कितना है और उसे तात्कालिक मूल्य के द्रुप्त पर से अधिक ऋष्य प्रदान न करना चाहिये और यह भी देखना चाहिये कि बीमित की आयु कम्पनी ने स्वीकार कर ली है या नहीं और पालिसी किसी अन्य कम्पनी के नाम तो की हुई नहीं है।
- (४) व्यापारिक माल की सुरत्ता पर—पूर्वकाल में ऋणदाता के गोदाम में माल रखकर ऋण जेने की प्रथा बुरी समभी जाती थी। किन्तु अब ऐसी नहीं है। आब तो सभी व्यापारी अपने माल की सुरत्ता पर ऋण प्राप्त करते हैं। बैंक के लिये ऐसी सुरत्ता पर ऋण प्रदान करना कुछ जोखिम से रहते हैं, क्योंकि माल सम्बन्धी विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और उसकी पूरी देखमाल आवश्यक है। थोड़ी सी भी असावधानी से माल नष्ट हो सकता है। उसकी नापतोल तथा मूल्यांकन का काम भी कठिन है। ऋषि-उपज एक प्रकार की नहीं होती। अतः उसके सम्बन्ध में बैंक्क के कर्मचारियों को घोखे का भय रहता है। भारत में अच्छे गोदामों की भी कभी है। और कभी-कभी अच्छे गोदामों की कमी से भी माल खराब हो जाता है। माल की सुरत्ता पर ऋण प्रदान करते समय बैंक्क को विशेष सावधान रहना चाहिये।

बैङ्क को चाहिये कि माल पर अपना अधिकार रखे और यह देख ले कि भ्रूग्ण प्राप्त करने वाले का अधिकार दूषित तो नहीं है। जिस गोदाम में यह माल रखा जाता है, उसमें बैङ्क प्राय: अपना चिन्ह लगाकर अपने नाम का ताला डाल देती है। गोदाम की ताली सुरिच्चत अलमारी में रखनी चाहिये, वंयोंकि कभी-कभी अप्रणी सूठा बहाना बनाकर ताली ले जाते हैं और अच्छा माल निकाल कर उसके स्थान

पर खराब माल श्रथवा नकली वस्तु रख देते हैं। गोदाम का समय-समय पर निरीच्या करते रहना चाहिये तथा माव के उतार-चढ़ाव पर दृष्टि रखनी चाहिये। यदि माव में कमी श्रा गई है तो ऋणी को इसकी स्चना देनी चाहिये श्रौर उसके कुछ श्रौर माल श्रथवा ऋणा की कुछ, रकम माँग लेनी चाहिये। माल को श्रिषक दिन श्रपनी सुरखा में नहीं रखना चाहिये। उसकी बाजार में माँग हो जाने पर उसे तुरन्त विकवा देना चाहिये। यदि ऋणी ऋण का भुगतान करके माल न छुड़ाये तो उस माल को नीलाम द्वारा बेच देना चाहिये। यह तो श्रित श्रावश्यक है ही कि माल का श्रमिन, चोरी तथा दुर्घटना का बीमा करना चाहिये।

- (४) निर्मित माल की सुरत्ता पर कृषि माल की अपेद्धा निर्मित माल में कुछ अधिक समस्याएँ होती हैं, क्योंकि इसका बाजार अधिक विस्तृत नहीं होता । निर्मित माल असंख्य प्रकार का होता है तथा कोई भी व्यक्ति उनके सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान नहीं खल सकता । फिर भी निर्मित माल में कुछ गुण भी होते हैं। गोदाम में वह कम स्थान घरता है । उसे दूर के स्थानों पर ले जाकर सुगमता से बेचा जा सकता है तथा यह वर्ष भर बिकता रहता है । अतः बड़े-बड़े केन्द्रों में विशेष कर बन्दरगाहों पर बैंक निर्मित माल की सुरत्वा पर ऋण प्रदान कर देती है । इस सम्बन्ध में बैक्क को चाहिये कि माल के बीजक को भली अकार देख ले जिससे माल की मात्रा, प्रकार तथा मूल्य का ठीक ज्ञान हो जाये । माल के मूल्य के ८० प्रतिशत से अधिक ऋण प्रदान नहीं करना चाहिये तथा ऐसे माल की सुरत्वा पर ही ऋण देना चाहिये जिस की माँग विस्तृत हो ।
- (६) श्रिधिकार-पत्रों (Documents of title to goods) की सुरहा पर जहाजी बिल्टी, रेल बिल्टी, डाक वारन्ट, गोदाम का प्रमाण्यत्र इत्यादि श्रिधिकार पत्र कहलाते हैं। जब माल एक देश से दूसरे देश जहाज द्वारा मेजा जाता है तो मेजने वाले को जहाजी कम्पनी से जहाजी बिल्टी प्राप्त होती है। बब माल रेल द्वारा मेजा जाता है तो रेल बिल्टी मिलती है। इसी प्रकार सार्वजनिक गोदाम में माल रख देने पर गोदाम का स्वामी एक प्रमाण्यत्र देता है। इन पत्रों के वापस कर देने पर ही माल वापस मिलता है। माल का स्वामी इन पत्रों का जिस व्यक्ति के नाम मी एष्ठांकन करें वही माल प्राप्त करने का श्रिधिकारी हो जाता है। श्रतः बैक्क भी इन श्रिधिकार-पत्रों की सुरह्मा पर श्रृण प्रदान कर देती है। बैक्क को चाहिये कि श्रृण प्रदान करने से पूर्व माल को श्रपने सामने पैक कराये जिससे घोलाघड़ी की गुंबायश न रहे। कभी-कभी चालाक व्यापारी मिट्टी श्रथवा रही कागज पैक करके में व देते हैं श्रीर उस पर श्रव्छे माल का लेबिल लंगा देते हैं। बैंक से श्रृण प्राप्त करके निरोहित हो जाते हैं। बैक्क जब माल को लोबली है तो उसे श्रमली माल के स्थान पर कुछ

श्रीर ही वस्तु मिलती है। श्रतः माल को श्रपने सामने पैक कराना श्रति श्रावश्यक है। फिर भी श्रिषिकार-पत्रों की सुरद्धा पर केवल जाने पहचाने व्यक्तियों को ही श्रूण प्रदान करना चाहिये श्रीर उनकी श्रार्थिक स्थिति एवं साख की पूरी जाँच कर लेनी चाहिये। श्रिषकार-पत्रों का पृष्ठांकन श्रपने नाम करा लेना चाहिये तथा साथ-साथ बीमा पालिसी भी ले लेनी चाहिये किसी भी श्रवस्था में माल के मूल्य के ६०-७० प्रतिशत से श्रिषक श्रुण नहीं देना चाहिये।

(७) अन्य वस्तुओं की सुरह्मा पर—बहुमूल्य धातु, स्वर्ण-रज्ञत-पाट, श्राभू-पणों तथा अपनी ही महती जमा की रसीदों पर भी बैंक सुरह्मापूर्वक अनुष्ण पदान कर देती हैं। स्वर्ण तथा रजत के मूल्य में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होते किन्तु आमूष्णों के सम्बन्ध में बैंक को विशेष सावधान रहना चाहिये। उसमें कितनी मिलात्रट है तथा शुद्ध घातु की कितनी मात्रा है इसका रकम हर व्यक्ति को नहीं हो सकता। आमूष्णों के सम्बन्ध में यह और भी आवश्यक है कि आण लेने वाले का अधिकार देख लिया जाये। कभी-कभी आमूष्णा स्त्री-धन होते हैं। और उस पर पित का अधिकार नहीं होता। अतः अनुष्ण माँगने वाले से एक घोषणा पत्र पर हस्ताद्धर कराने चाहिये कि आमूष्णा उसी की सम्पत्ति है। स्वर्ण तथा रजत पाट पर ६० प्रतिशत तथा आमृष्णों पर ७०प्रतिशत तक अनुण प्रदान किया जा सकता है। मुद्दी जमा की रसीदों पर अनुष्ण प्रदान करने में कोई कोखिम नहीं है। इतनी बात अवश्य है कि उसकी ब्याज की सुरह्मा पर कोई अनुण नहीं देना चाहिये।

किसी भी अवस्था में बैंक को अचल-सम्पत्ति की सुरचा पर ऋष नहीं देना चाहिये, क्योंकि अचल-सम्पत्ति में बहुत से वैधानिक भंभट होते हैं और उसका बेच देना कठिन होता है। कोई भी व्यापारिक बैंक भूमि तथा भवन की सुरचा पर ऋष अदान नहीं करता। उनके मूल्य का ठीक अनुमान लगाना भी असम्मव है।

बैद्ध लेखे (Bank Accounts)—प्रत्येक बैंक की अपनी-अपनी बही खाते की पद्धति होती है, किन्तु बैंक की सामान्य खाता बही के लच्चण निम्नलिखित हैं:—बैंक की खाता बही में मुख्य कर प्राप्त किये हुए और दी हुई नकदी का विस्तारपूर्वक विमाजन कर दिया जाता है। खाता बहियाँ दो शीर्षकों में विभाजित की जा सकती है:—

- (क) सहायक रोकड बहियाँ तथा सहायक खाता बहियाँ।
- (ख) साधारण रोकड बही तथा साधारण खाता बही। सहायक बहियाँ निम्न-लिखित है:—
- (क) प्राप्त किये सये सारे 'नकदी' के लेखे के लिये "प्राप्त करने वाले रोक-डिये की काउन्टर रोकड़ बही।"

- (ख) दिये हुए सारे नकदी के लेखे के लिये "देने वाले रोकड़िये की काउन्टर रोकड़ बही" और
- (ग) सहायक लाता बहियाँ, जैसे चालू खातों की खाता बही, स्थायां जमा खाता वही, नकद प्रमाग पत्र लाता बही, विनियोग खाता बही, ऋण खाता बही, नकद साल खाता बही, कय किये हुए विलों तथा हुन्डियों की खाता बही, किस संचय खाता बही, प्राहकों की सरकारी हुन्डी खाता बही, प्रत्येक सहायक बही में उससे सम्बन्धित लेन देनों के खाते होंगे।

साधारण रोकड़ बही में प्राप्त करने वाले और सुगतान करने वाले रोकड़ियों की रोकड़ बहियों में लिखे हुए लेन देनों का क्रमबढ़ सागंश होता है। साधारण खाता बही में दिखाई देने वाले भिन्न-भिन्न खाते इस बही से विकार के प्राप्त स्वाप्त

साधारण खाता बही बहुत ऋषिक मुख्य खाता बही है, इसमें प्रत्येक सहायक खाता बही सम्बन्धी कुल खाता होता है तथा इसमें वे खाते भी होते हैं जिनके लिये पृथक खाता-बहियाँ नहीं रखी गई हैं। यह ऋातमिवश्वासी खाता बही छोर इसमें सारे लेन देनों का लेखा होता है। ऋत: बैंक के ऋंतिम काते इस सावपर खाटा बही से लिये गये कन्चे आँकड़ों से तैयार किये जाते हैं।

उन व्यापारिक बहियों के ऋदिरिक्त वैंक की कई एक स्मृति बहियाँ (Memorandum Banks) भी रखनी चाहिये। उदाहरणार्थ; सुरच्चित रचा के लिये प्राप्त किये गये सारे मूल्यवान पदार्थों के विवस्ण लिखने का रिवस्टर। उन स्मृति बहियों में दुहरी इन्दराज पद्धति नहीं होती।

खाते तथा उनका अंकेच्या: वार्षिक खाते—प्रत्येक अंग्रेबी वर्ष के अंत में भारतवर्ष में प्रत्येक संस्थापित वैंकिंग कम्पनी अपने सारे व्यवसाय से सम्बन्धित तथा भारतवर्ष के बाहर संस्थापित कम्पनी अपने भारतवर्ष में किये गये व्यापार से सम्बन्धित उस वर्ष का चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता बनायेगी।

चिट्ठे तथा लाम-हानि खाते पर (क) मारतवर्ष में संस्थापित वैंकिंग कम्मनी में व्यवस्थापक के हस्ताच्चर होंगे श्रीर जहाँ पर तीन से श्रीधिक संचालक हो वहाँ कम-छे कम तीन संचालकों के श्रीर जहाँ तीन से श्रीधिक संचालक नहीं हों वहाँ सारे संचालकों के हस्ताच्चर होंगे। श्रीर (ख) भारतवर्ष के बाहर संस्थापित वैंकिंग कम्पनी में भारत की कम्पनी के प्रधान कार्यालय के व्यवस्थापक के हस्ताच्चर होंगे।

खातों का श्रंकेच्रण्—वैकिंग कम्पनी के चिट्ठे तथा लाम-हानि खाते का श्रंकेच्रण होगा तथा श्रंकेच्रक की योग्यता वही होगी जो कि कम्पनियों के श्रंकेच्रकों की होती है। बैंकिंग कम्पनी के श्रंकेच्रकों की तियुक्ति, उनके श्रधिकार, तथा कर्चव्य श्रोर उनके व्यक्तित्व Indian Companies Act 1913 में लिखे अनुसार होंगे।

खातों का रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजना—श्रंकेच्चण किया हुआ चिट्ठा श्रीर लाभ हानि-खाते की तीन प्रतियाँ तथा अंकेच्चक की रिपोर्ट रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के पास ब्योरे के रूप में उनकी श्रविष की समाप्ति के तीन मास के भीतर भेज देनी चाहिये। रिजर्व बैंक इन तीन मास की श्रविष को श्रीर बढ़ा सकती है।

घारा २७ (२) के ऋंतर्गत रिजर्व बैंक को ऐसी कम्पनी के व्यवसाय सम्बन्धी ऋौर सूचना बैंकिंग कम्पनी से माँगने का ऋधिकार है।

बैंकिंग कम्पनी को श्रंकेक्षण किया हुश्रां चिट्ठा श्रौर लाम-हानि खाते की तीन प्रतियाँ तथा श्रंकेक्षक की रिपोर्ट रिजस्ट्रार को भी भेजनी होती है श्रौर यदि रिजर्व बैंक खातों से सम्बन्धित सूचनायें माँगती है तो ऐसी श्रातिरिक्त सूचना की एक प्रति- लिपि रिजस्ट्रार को भी भेजनी पड़ती है।

खातों का प्रकाशन—प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को चिट्ठा, लामहानि खाता तथा श्रंकेच्चक की रिपोर्ट कम्पनी के प्रधान कार्यालय के स्थान पर श्राने वाले किसी भी समाचार-पत्र में बही खाते के वर्ष के अन्त से ६ मास के भीतर भीतर प्रकाशित कर देनी चाहिये।

वैंकिंग कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत वैंक का चिट्ठा निम्न प्रकार तैयार किया जाता है जो अगले पृष्ठ संख्या ३५५ पर छपा है।

३१ दिसम्बर १६५८ को हिंद बेंक लिमिटेड का नमूने का चिट्ठा

देनदारियाँ		क लिमटंड का नम्ने का	। बडा
निर्घारित, प्रचारित तथा		लेनदारियाँ	Í
चुकता पूँजी ५०)-५०)		रोकड बाकी तथा रिजर्व	1
के १०,००० त्रंश	U	वैंक में चमा	€,00,000
सुरचित कोष	4,00,000	श्रल्पकालीन माग का	
जमायें	2,00,000	ऋग ु	2,50,000
मुद्दती खाते में		श्रन्य वैंकों में शेष सर-	
		कारा विनयोग	१,२०,०००
४,१०,००० चान नाने ने		अन्य विनियोग	₹,00,000
चालू खाते में		ऋण तथा ऋप्रिम ऋग	2,44,000
११,१५,०००	1 -	व ऋग जो म्रस्तित	-1 - 3
बचत खाते में ४५,०००	24,50,000	समम जात है जिसके	
प्राहकों की ऋोर से		लिये वैंक मुरच्चित हैं	
स्वीकार किये हुए जिल		2.00,000	
(दूसरी तरफ भी देखिए)	20,000	विलों की पुनकंटीती पर	
संप्रहार्थं विषत्र दूसरी		理型	
श्रोर भी देखिये	₹0,000	मिश्रित प्रामिसरी नोट	
वितरित लाभ जो माँगा		पर ऋग २५,०००	
नहीं गया	20,000	नगद साल तथा श्रीवर-	
लाभ-हानि खाता	80,000		
	,	ड्राफ्ट ७५,००० वैंक में संचालको पर	
•	1		
		ऋण जो जोखिम में	
		समभा जाता है	
		१५,०००,	850,000
		संप्रहार्थ विपत्र दूसरी स्रोर	
	P. Carriera	भी देखिये	३०,०००
	-	ग्राह्कों का उत्तरदायित्व	
		विलों के लिये दूसरी श्रोर	
		भी देखिये	₹0,000
		फर्नीचर इत्यादि	44,000
		भवन इत्यादि	2,00,000
	२२,८०,०००	DAMP	२२,⊏०,०००

वैङ्क की देनदारियाँ—निर्धारित पूँजी उस रवम को कहते हैं 'उन हैं के अधिकार-पत्र में निर्धारित किया गया है। प्रचारित पूँजी उस रकम को कहते हैं जिसमें मूल्य के अर्थ जनता को बेचने के लिये बैद्ध ने घोषणा की है।

चुकता भूँजी— उस राभ्रिको कहते हैं जितने की रकम केता श्रों को प्राप्त हो चुकी है।

सुरचित कोष—प्रति वर्ष बैङ्क अपने लाम का २० प्रतिशत सुरचित कोष में तब तक जमा करती है जब तक यह कोष चुकता पूँजी के बराबर न हों जाये। प्रत्येक अच्छी बैङ्क अपने लाम का एक अंश सुरचित कोष में अवश्य ही जमा करती है, क्योंकि इससे बैक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और बैङ्क की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह ध्यान में रखने की बात है कि सुरचित कोष और न वस्तुल की हुई पूँजी अथवा दायित्व में बहुत अंतर है। सुरचित कोष को अंश्रधारी नहीं देते हैं वरन् वे वार्षिक लाम में से एक पृथक माग निकाल कर रखने से बनता है। सुरचित कोष प्रथम अंशी की प्रतिभृतियों में लगाया जाता है। चुकता पूँजी (Paid up Capital) तथा सुरचित कोष मिल कर बैङ्क की कार्यशील पूँजी (Working Capital) बनती है। यदि कभी बैङ्क को मारी हानि हो जाये तो वह अपने सुरचित कोष में से उसकी पूर्ति कर सकती है। इस प्रकार सुरचित कोष ग्राहकों के लिये सुरचा का काम देता है तथा उसका उपयोग अंशधारियों को बोनस अंश देने तथा लाम की दर को समान करने (Equalisation of Divident) में किया जा सकता है।

लेन-देन के लेखे में जो सुरिच्चित कोष प्रगट रूप से दिखलाया जाता है उसके ग्रांतिरिक बहुत सी बैङ्क इस सुरिच्चित कोष का भी निर्माण करती है जिन्हें लेन-देन के लेखों में नहीं दिखलाया जाता। इस सुरिच्चित कोष से बैङ्क की ग्रार्थिक स्थिति ग्रीर भी हद होती है ग्रीर उसकी सुरच्चा तथा प्रतिष्ठा बढ़ती है। गुप्त सुरिच्चित कोष का निर्माण सम्पत्ति ग्राथवा लेनी (Assets) का मूल्य कम निर्धारित करके किया जाता है।

चालू खाता तथा अन्य खाते (Current Account and other Accounts)—जो रुपया बैङ्क में सर्वधाधारण जमा करते हैं वह इस शीर्षक में दिखलाया जाता है। यह बैङ्क की सब से महत्वपूर्ण देना (Liability) होती है। बैङ्क जमा रूप में पाई हुई इस धन राशि को अधिक न्याज पर लगा देती है तथा इससे लाम कमाती है। किन्तु इस जमा किये रुपये को लामदायक ढंग से लगाने में बैङ्क को यह ध्यान रखना पड़ता है कि जमा करने वालों ने जो धनराशि बैङ्क के पास अमानत के रूप में रखी है वह सुरक्षित रहे। उसकी सुरक्षा को खतरा न हो।

बैक्क चालू खातों में रुपया लेती है। जमा करने वाला जब चाहे चेक काट कर इस खाते में से रुपया निकाल सकता है। इसके श्रांतिरिक्त मुद्दी जमा एक निश्चित समय का नोटिस देने के उपरांत ही निकाली जा सकती है। इनके श्रांतिरिक्त हमारे देश में बैक्क बचत जमा लेती है श्रीर कैश साटींफिकेट भी बेचती है। सेविंग जमा में से रुपया सप्ताह में एक या दो बार ही निकाला जा सकता है। कुछ बैक्क बचत खाते पर भी चेक काटने की सुविधा देती हैं। परन्तु कुछ बैक्क यह सुविधा नहीं देतीं। यही नहीं, सेविंग बैक्क खाते में कुल श्राधिक से श्राधिक कितना रुपया जमा किया

जा राकता है यह भी निश्चित होता है। कैश साटीं फिकेट २ ऋयवा ५ वधीं के लिए होते हैं।

विलों को स्वीकार करने तथा उन पर वेचान करने के संबन्ध में बैंक का दायित्व—वैक्क अपने प्राहकों को ऋण देने तथा थोड़े समय के लिये साल देने के उद्देश्य में हु डियों को स्वीकार करती है अथवा उन पर वेचान (Endorsement) करती है। किन्तु वैक्क के विलों पर हस्ताच्चर होने के कारण यदि वैक्क का प्राहक उस विल के पकड़ने पर उसका भुगतान करे तो वैक्क को उस विल का भुगतान करना पड़ सकता है। वास्तव में इन विलों का भुगतान वैक्क को प्राहक ही करते हैं तथा वे ही उसके लिये उत्तरदायी होने हैं। परन्तु यदि वे समय पर विलों का भुगतान करें तो वैंक को उनका भुगतान करना पड़ना है और इसके पश्चान् वैंक अपने प्राहक से रकम प्राप्त करते हैं। किन्तु एक देनी (Liability) से विवच्च में लेनी (Assets) की ओर भी इतनी ही रकम दिलाई बाती है, क्योंक उतनी रकम के लिये ग्राहक वैंक के लिये उत्तरदायी है।

बैंक के प्राहक स्राये हुए चेक तथा प्राप्त हुण्डियों को वैक्क में समह के लिये भेज देते हैं। जब तक इनका घन प्राप्त न हो जाये ये विपन्न बैक्क की सम्पत्ति सममें जाते हैं, क्योंकि बैक्क को इनका घन प्राप्त करने का ऋषिकार है किन्तु साथ ही घन प्राप्त हो जाने पर यह रकम प्राहक को देय है। ऋतः यह बैंक का दायित्व भी है। इसीलिये इन विपन्नों को चिट्ठे में दोनों स्त्रीर दिखलाया जाता है।

कभी कभी समस्त लाभ को अंशाषादियों में वितरित नहीं किया जाता तथा इस प्रकार यह लाभ हानि-लाभ खात में ही पड़ा रहता है। अतः वह भी वैंक चिट्ठें क देनी अर्थ में दिखलाया जाता है।

बैंक की लेनी—बैंक को कुछ नकदी हर समय इसिलेये रखनी पहती है कि जो चेक आवे उसका भुगतान कर दिया जाये। इसके आदिरिक्त अपने यहाँ जमा हुए धन का कुछ अंश हर समय बैंक में रखना पड़ता है जिसे संकट काल में बैंक से निकालकर काम में लाया जा सके। बैंक एक दो दिन अथवा एक-दो घन्टे के लिये व्यापारियों को अध्या देती हैं, जिसे द्रव्य अथवा अल्पकालीन अध्या कहते हैं। ये अध्या विना किसी जमानत के केवल उन्हीं बड़े-बड़े व्यापारियों को दिया जाता है जिनका बैंक को पूर्ण विश्वास प्राप्त है। इस प्रकार का दिया हुआ अध्या एक प्रकार की नकदी ही है, क्योंकि यह माँगने पर तुरन्त मिल सकता है। समाशोधन के लिये कुछ बैंक अन्य बैंकों में कुछ धन जमा करती हैं जिसे निकालने का उन्हें किसी मी समय पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। बैंक की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि बैंक अपने कोष को मिन्न-मिन्न प्रकार के विनियोग में इस प्रकार लगाये कि

बैंक अपनी कार्यशील पूँजी पर अधिक-से-अधिक ब्याज लगा सके तथा साथ ही त्रावश्यकता पहने पर विनियोग को बेचकर रोक में परिवर्तित किया जा सके। इसी लिये बैंक अपना रुपया सरकारी विनियोग तथा अन्य कम्पनियों के ऋगुपपत्र इत्यादि में लगाती है जो स्टाक एक्सचेंज पर किसी समय बेचे जा सकते हैं। बैंकों का मुख्य कार्य व्यापारियों को ऋगा देना होता है। श्रिधिकतर रुपया व्यापारियों को दिए हए समस्त ऋगा को न्यौरेवार दिखलाना पड़ता है जैसे यह ऋगा जिसमें कोई भय नहीं है। श्रीर जिसके लिये बैंक सुरचित भी नहीं है। यह ऋगा जो हुगिडयाँ की पुर्नकटौती पर दिया गया है यह ऋण जो व्यापारियों को उनकी निजी जमानत पर दिया गया है। यह ऋण जो बैंक के संचालक को दिया गया है ऋथवा दिखलाना पड़ता है, जिसकी साधारण जनता को पता चल जाये कि बैंक के संचालक किस सीमा तक बैंक के धन को अपने कार्य में लगा लेते हैं यह ऋग्ए भी पृथक रूप से दिखलाना पड़ता है जिसके प्राप्त होने में जोखिम है जिसके लिये बैंक सुरिच्चत नहीं हैं। बैंक के भवन तथा अचल सम्पति एक प्रकार का अचल विनियोग होता है जो शीव ही रोकड़ में परिण्त नहीं किया जा सकता। ऋतः बैंक की इस प्रकार की अचल सम्पत्ति को सबसे ऋलग खाते दिखलाते हैं। बैङ्क को ऋपने लेन-देन का लेखा बैंकिंग नियमा-नुसार ही बनाना पड़ता है जिससे जनता बैंक की वास्तविक स्त्रार्थिक स्थिति को समक सके।

समाशोधन गृह—वैंकिंग विभाग के साथ-साथ प्रायः प्रत्येक व्यापार केन्द्र में वैंकों की शाखायें खुल गई हैं। मिन्न-मिन्न व्यापारी मिन्न-मिन्न वैंकों में अपना हिसाब रखते हैं। अप्रधुनिक काल में वैंक, बिल, हुएडी चेक, इत्यादि भुगतान के माध्यम बन गये हैं। अतः व्यापारी के पास अनेकों स्थानों के चेक आया करते हैं। इस प्रकार प्राप्त समस्त चेकों को व्यापारी अपनी बैंक में जमा करने के लिये मेज देता है। यह वैंक उन सब चेकों का भुगतान उन सब वैंकों से प्राप्त करती हैं जिन पर वे लिखे गये हैं तथा ऐसा करने में बैंक समाशोधन गृह की सहायता लेती हैं, क्योंकि ऐसी सहायता प्राप्त करने में वैंक समाशोधन गृह की सहायता प्राप्त करना कठिन कार्य है। मान लीजिये कि कानपुर में अमरनाथ अपना हिसाब बंगाल वैंक में रखता है तथा बसन्त लाल अपना हिसाब पंजाब नेशनल वैंक में रखता है। अमरनाथ ने २०,०००) की चीनी बसंत लाल के हाथ बेची तथा मूल्य का भुगतान करने के लिये बसंत लाल ने २०,०००) का चेक पंजाब नेशनल वैंक पर काट कर अमरनाथ को दे दिया। अमरनाय इस चेक को अपनी बंगाल बैंक में मेज देगा जिससे बंगाल वैंक पंजाब नेशनल वैंक के पर काट कर अमरनाथ को दे दिया। अमरनाय इस चेक को अपनी बंगाल वैंक में मेज देगा जिससे बंगाल वैंक पंजाब नेशनल वैंक से स्पर्या प्राप्त करके अमरनाथ के हिसाब में जमा कर दे। इसी प्रकार मान लीजिये बङ्गाल वैंक के पास अन्य प्राहकों के हिसाब विमा कर दे। इसी प्रकार मान लीजिये बङ्गाल वैंक के पास अन्य प्राहकों के हिसाब

में जमा होने के लिये स्टेट वैंक, छेन्द्रल वैंक, हिन्दुस्तान कर्माश्चयल वैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, तथा जयपुर बैंक पर काटे हुए चेक आये हैं। इन सब चेकों को वसूल करने की, यदि समाशोधन गृह न हो, तो एक ही उपाय है कि प्रति दिन प्रत्येक बैंक अपने एक क्लर्क और चपराची को केवल इसीलिये नियुक्त करे कि वह सब चेकों को लेकर प्रत्येक वैंक के कार्यालय बाये और वहाँ उन चेकों का रूपया वसूल करे । इस प्रकार प्रत्येक वैंक के कर्मचारियों को बार-बार चेक तथा ड्राफ्ट इत्यादि का रुपया प्राप्त करने के लिये भिन्न-भिन्न वैंकों को जाना पढ़ेगा। इससे कर्मचारियों का समय तो नष्ट होता ही है, सवारी इत्यादि का व्यय भी होता ही है तथा करने को लाने-ले जाने में उसके को जाने अथवा लुट जाने का भय रहता है। इसके अतिरिक्त जब प्रत्येक बैंक को अपने ऊपर काटे गये चेकों अध्यवा ड्राफ्टों का नकद स्वया देना पड़ता है तो उन्हें अपने पास नकदी भी अधिक रखनी पड़ती है। ऊपर का डंग अपवैज्ञानिक, कष्टसाध्य तथा जोलिम का है। साथ ही इसमें ऋषिक व्यय हैं ता है श्रीर बैंकों को श्रपने पास नकदी भी श्रधिक रखनी पड़ती है। यही कारण है कि जब बैंकिंग कारबार बढ़ा तथा ऋषिकांश लोग ऋपना कारबार बैंकों की सहायता से करने लगे तो इस बात की ऋावश्यकता हुई कि एक-रूसरे पर काटे हुए चेकी की प्राप्ति का अधिक सुविधाजनक तथा सरल ढंग निकाला जाये। अतः समाशोधन गृह की व्यवस्था की गई। चेक निष्कासन में एक बैंक की दूसरी बैंक पर जितनी माँग होती है उसको काटकर शेष को चुका दिया जाता है। निष्कासन समाशोधन यह द्वारा होता है। इस ढंग से बहुत लाभ होते हैं। समाशोधन-एह की व्यवस्था होने से बैंक के कर्मचारियों को चेक इत्यादि की वस्ली के लिये बार-बार स्थ्रन्य वैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते तथा न बैंकों तथा ड्राफ्टों की नकदी में वस्ता करने की श्रावश्यकता . बड़ती है। इससे लाभ यह होता है कि मार्ग में रुपये लुट जाने अथवा मारे जाने की जोखिम नहीं रहती। यही नहीं वैंकों को ऋपने पास ऋषिक नकदी रखने की त्रावश्यकता नहीं पड़ती। यह पद्धति बहुत ही चुविधाजनक. सरल, कोलिम रहित श्रीर लाभदायक है।

प्रत्येक बैंक का हिसाब केन्द्रीय बैंक में होता है तथा समाशोधन यह का हिसाब भी केन्द्रीय बैंक में होता है। जिस बैंक को किसी दिन समाशोयन-यह के हिसाब में देना निकलता है तो केन्द्रीय बैंक उस बैंक के हिसाब में से उतना रुपया कम करके समाशोधन-यह के हिसाब में जमाकर देती है। श्रीर जिस बैंक को समाशोधन यह के हिसाब में लेना होता है उसे समाशोधन यह उतने की केन्द्रीय बैंक पर चेक काट देता हैं। केन्द्रीय बैंक उतना रुपया समोशोधन-यह के हिसाब में लिखकर उस बैंक के हिसाब में जमा कर देती है। इस प्रकार समाशोधन-यह का हिसाब प्रति दिन पूर्या संतुलित हो जाता है तथा प्रत्येक सदस्य बैंक की केन्द्रीय बैंक जमा घटती-बढ़ती रहती है।

भारतवर्ष में रिजर्व बैंक अन्य देशी केन्द्रीय बैंकों की भाँति देश के समाशोधन
गृह का कार्य करती है। रिजर्व बैंक के बम्बई, दिल्ली, मद्रास आदि स्थानों पर अपने
समाशोधन गृह हैं। अन्य स्थानों पर रिजर्व बैंक की ओर से स्टेट बैंक आफ इंडिया
समाशोधन गृह का कार्य करके बैंकों को पर्याप्त सुविधा प्रदान करती है।

समाशोधन-गृह की त्राथिक सेवायें—यदि समाशोधन-गृह न हो तो एक-दूसरे पर काटे हुए चेकों को वसूल करने के लिये प्रति दिन प्रत्येक बेंक, श्रपने एक क्लर्क तथा चपरासी को केवल इसीलिये नियुक्त करेगी कि वह सब चेकों को लेकर प्रति दिन वहाँ जाये और रुपया वसूल करे। इस प्रकार प्रत्येक बैंक के कर्मचारियों को बार-बार चेक म्राथवा ड्राफ्ट का रुपया प्राप्त करने के लिये भिन्न-भिन्न बैंकों को जाना पड़ेगा। इससे कर्मचारियों का समय तो नष्ट होगा ही सवारी इत्यादि का व्यय भी होगा श्रीर रुपये को लाने ले जाने में उसके खो जाने श्रथवा लूट जाने का भी भय रहेगा। इसके श्रविरिक्त जब प्रत्येक बैंक को अपने ऊपर काटे गये चेकों श्रयवा ड्राफ्टों का नकद रुपया देना पड़ेगातो उन्हें श्रपने पार नकदी भी श्रिधिक रखनी पड़ेगी। यह ढंग अवैज्ञानिक, कष्टसाध्य श्रीर जोखिम का है। साथ ही इसमें अधिक व्यय होगा और बैंकों को अपने पास नकदी भी अधिक रखनी पड़ेगी। यही कारण है कि जब वैंकिंग कारवार बढ़ा श्रीर श्रधिकांश लोग श्रपना कारबार वैंकों की सहायता से करने लगे तो इस बात की आवश्यकता हुई कि एक दूसरे पर काटे हए चेकों की वसली का सविधाजनक श्रीर सरल ढंग निकाला जाये। श्रवः समा-शोधन-गृह की त्रावश्यकता प्रतीत हुई, श्रीर उसकी व्यवस्था की गई। चेकों के निष्कासन में एक बैंक की दूसरी बैंक पर जितनी माँग होती है उसको काटकर शेष को चुका देती है। निष्कासन का कार्य समाशोधन-गृह द्वारा होता है। इस ढंग से बहत-से लाभ होते हैं। समाशोधन एह की व्यवस्था होने से बैंक के कर्मचारियों को चेक इत्यादि की वस्तुती में अन्य बैंकों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते श्रीर न चेकों तथा ड्राफ्टों को वसूल करने की श्रावश्यकता पड़ती है। इससे लाभ यह होता है कि मार्ग में लुट जाने ऋथवा मारे जाने की जोखिम नहीं रहती। यही नहीं, बैंकों को अपने पास अपनी नर्दि। रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह पद्धति बहुत ही सुविधाजनक, सरल तथा जोखिम रहित और लाभदायक है।

प्रश्न

^{1.} What are the various forms of security against which advances may be made by a banker? Discuss the merits of each form of security.

वैंकर कितने प्रकार की सुरचात्रों पर ऋण प्रदान करता है ? हर एक सुरचा के गुणों का वर्णन की जिये ।

2. How does a bank get its funds? Explain in detail.
बैंक स्त्रानी निधि किस प्रवार प्राप्त करती है ! विन्तापन्त्रीय बतलाइये।

3. Examine the different wars in which a bank utilizes its working capital. What precautions are necessary for a bank in making advances to its customers?

वैंक ऋपनी कार्यशाल पूँजी को जिन विभिन्न प्रकारों से उपयोग करती है: उनकी विवेचना कीजिये। ऋपने प्राहकों को ऋग्य प्रदान करते समय वैंक को क्या सावधानियाँ व्यवहार में लानी चाहिये?

4. Distinguish between a 'Cash Credit' and a 'Over Draft.'

Discuss their relative merits and demerits.

ऋधिविकरण तथा नकद साल का भेद बतलाइये। उनके सापेद्धिक गुण तथा दोषों का वर्णन कीजिये।

5. How does a person open his current account at a bank? Explain the procedure and enumerate the documents he will be supplied by the bank.

बैंक में चालू खाता किस प्रकार खोला जाता है ? इसकी कार्यविधि बत-

लाइये तथा उन प्रपत्नों का वर्णन कीजिये जिन्हें वैंक खाता खोलने वालों को देती है ! 6. What are the different types of loans usually granted by a

6. What are the different types of loans usually granted by a Commercial Bank? What precautions should be observed by a bank while granting these loans.

व्यापारिक वैंक प्रायः कितने प्रकार के ऋण प्रदान करती है ! ऋण प्रदान करते समय वैंक किन सावधानियों को व्यवहार में लाती है !

7. Draw an imaginary Balance Sheet of a Bank and explain various items appearing thereir.

बैंक का एक काल्पनिक चिट्ठा बनाइये तथा उसकी भिन्न मटों को समभाइये।

8. Describe the functions of a Clearing House and its economic services.

समाशोधन-गृह के कार्यों का वर्णन कीजिये तथा उनकी ऋार्थिक सेवार्ये

बतलाइये। 9. Discuss carefully the advantages of a banker's clearing-house and also the part usually played by Central Bank in this connection.

बैंकों के समाशोधन-गृह के लाभों का वर्णन की ज़िये। केन्द्रीय वैंक इस संबन्ध में क्या कार्य वरती है ?

ाठ. What is the importance of a Bankers' Clearing-House?

How does it work? बैंकों के समाशोधन-गृह का महत्व बृतलाइये। यह किस प्रकार कार्य करता है ?

साख एवं साखपत्र

(Credit and Credit Instruments

साख का महत्व — साख ही आधुनिक व्यापार और शिला है। वर्तमान आर्थिक व्यवसाय में साख का महत्व ऋत्यन्त अधिक बढ़ गया है। जितने विशाल पैमाने पर आज उत्यक्ति और विनिमय होता है वह बिना साख की सहायता के कदापि संभव नहीं हो सकता। संसार का अधिकतर व्यापार आज साख के आधार पर होता है न कि राकड़ी रुपयों के आधार पर। यही कारण है कि आधुनिक आर्थिक संगठन में साख को एक ऋत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आर्थिक जीवन के प्रत्येक पहलू में इसका बोलबाला है र्प फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से, थोक विक्रेता कारखाने वाले से, कारखाने वाले स्वयं अन्य व्यापारियों से साख पर वस्तुयें क्रय करते हैं। इस प्रकार समस्त आर्थिक ढाँचा साख के धागे में बँधा हुआ है।

साख का अर्थ — माघारणतः साख का अर्थ 'विश्वास' अथवा भरोसे से लिया जाता है। यह पर्याप्त क्याप्त अर्थ है। अर्थशास्त्र में इसका अर्थ विशेष रूप से संकुचित होता है। यहाँ पर इसका अभिप्राय केवल ऋण लौटाने अथवा भुगतान करने की शक्ति के विश्वास से होता है। इस प्रकार यदि हम किसी व्यक्ति विशेष के बाजार में साख का वर्णन करते हैं तों इससे हमारा अभिप्राय यह होता है कि अधिक साख वाले व्यक्ति पर लोगों को उसकी ऋण लौटाने की शक्ति का अधिक विश्वास होता है, अर्थात् उसे बाजार में सरलतापूर्वक अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त हो सकता है। इसके विपरीत कम साख वाले व्यक्ति को कम मात्रा में ऋण प्राप्त होता है, क्योंकि उस पर लोगों का कम विश्वास होता है।

भिन्न-भिन्न विद्वानों ने साल की भिन्न-भिन्न परिभाषायें की हैं। मैकोलियड ने लिखा है कि साल भविष्य में सुगतान पाने का वर्तमान श्रिष्ठकार है। वालरस ने साल को पूँजी का उधार देना कहा है। जेवन्स का कथन है कि साल सुगतान कुछ विलम्ब के पश्चात् करने के श्रितिरिक्त श्रीर कुछ नहीं है। जीड के श्रिनुसार साल वर्तमान धन को भविष्य में परिवर्तित कर देती है। साल (Credit) शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द

Credu से हुई है जिसका अर्थ है 'मैं विश्वास करता हूँ।' व्यापारिक अर्थ में साख शब्द किसी व्यापारी अथवा व्यापार संस्था की उस द्रव्य सम्बन्धी प्रतिष्ठा तथा विश्वसनीयता का द्योतक है जिसके आधार पर वह अन्य किसी व्यापारी अथवा संस्था से ऋण लेता है। यह ध्यान देने योग्य है कि साख एक अदृह्य वस्तु होने के कारण साखपत्रों से सर्वथा भिन्न होती है। 'साख के आधार पर आवक्त कर्न प्राप्त के कारण साखपत्रों से सर्वथा अधार लेते हैं। यदि किसी व्यापारी की साख अन्ही है तो उसे बड़ी रकम उधार मिल सकती है। किन्तु संदेहपूर्ण साख वाले व्यापारी को स्पया उधार देने में सब कोई हिचकते हैं।

ईस प्रकार साख का ऋर्थ किसी व्यक्ति का किसी ऋन्य व्यक्ति की ईमानदारी में उस विश्वास से हैं किसके ऋषार पर वह व्यक्ति ऋन्य व्यक्ति की कोई मी मृल्यवान वस्तु एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित मात्रा में ऋथवा ब्याञ्च सहित वह वस्तु लौटा देगा।

किसी व्यापारी की साख निम्नलिखित वातों पर निर्भर हैं :-

- (१) व्यक्ति के भुगतान करने की योग्यता— व्यव्वाद में संस्त्र प्राप्त करने की शिक्त उनके भुगतान करने की योग्यता पर निर्मर है। योग्यता से ऋभिप्राय उन साधनों से है जिनके द्वारा व्यक्ति विशेष भुगतान कर एके। यदि किसी व्यक्ति के पास साधन पर्याप्त मात्रा में है तो उसकी साख बाजार में ऋधिक होगी तथा यदि साधनों का ऋभाव है तो कोई व्यक्ति भी ऋण देने को प्रस्तुत न होगा। इस दृष्टिकोण में प्रत्येक व्यक्ति की बाजार में पृथक-पृथक साख होती है। घनी व्यापारी से ऋधिक मात्रा में ऋणा प्राप्त हो सकता है जब कि थोड़ी श्राय वाले व्यक्ति को थोड़ा ऋण मिलना भी कठिन हो जाता है। किसी व्यक्ति के पास यदि पर्याप्त साधन नहीं हैं और उसमें ऋनेकों व्यक्तिगत गुण हैं, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, वह शिक्ति में मुगतान के समय पर्याप्त मात्रा में साधन प्राप्त करने की शक्ति निहित है। इस प्रकार यदि देखा कार्य तो चिरित्र ही व्यक्ति विशेष में सुगतान करने की योग्यता उत्पन्न कर देता है।
- (२) व्यक्ति की सम्पत्ति—व्यक्ति विशेष का चरित्र तथा ऋण का भगतान करने की योग्यता केवल छोटे ऋण प्राप्त करने में ही सहायता दे सकते हैं। वरन्तु बंह ऋणों के लिये व्यक्तिगत पूँजी और सम्पत्ति ही आधार का कार्य करते हैं। वहें ऋण ऋधिकतर बैंकों द्वारा प्राप्त होते हैं। व्यक्ति विशेष की पूँजी ही उसके ऋण लेने की शिक्ति को निर्धारित करते हैं, क्योंकि बैंक ऋण देने से पहले ऋण लेने वाल की पूँजी शिक्त को निर्धारित करते हैं, क्योंकि बैंक ऋण देने से पहले ऋण लेने वाल की पूँजी का पूर्ण रूप से निरीच्ण कर लेती हैं। इस प्रकार ऋधिक सम्पत्ति ऋषिक शास की सचक है।

- (३) चरित्र—िकिसी भी व्यक्ति की साख उसके चरित्र पर निर्भर होती है। इसका अभिप्राय यह है कि भूतकाल में ऋगा भुगतान के सम्बन्ध में उसका चरित्र कैसा रहा है। यदि किसी व्यक्ति ने भूतकाल में लिये हुए ऋगों का भुगतान ठीक समय पर अथवा ठीक प्रकार से नहीं किया है तो उसका चरित्र विश्वसनीय नहीं है। लोग उसे संदेह की हिट से देखेंगे और उसे ऋगा प्राप्त करने में पर्याप्त कठिनाइयाँ उठानी पड़ेगी। उसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति ने अपने ऋगों का भुगतान भूतकाल में ठीक प्रकार से किया है तो बाजार में वह व्यक्ति चरित्रवान् कहलायेगा—उसकी प्रतिष्ठा और मान बाजार में बहुत ऊँचा होगा—लोग उसका विश्वास करेंगे। उसकी साख अधिक होगी तथा उसे सरलता से ऋगा प्राप्त हो जायेगा।
- (४) सामाजिक प्रतिष्ठा—िकसी व्यापारी की साख उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी निर्भर होती है, क्योंकि प्रपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के उद्देश्य से वह ऋणों का भुगतान करने में दिलचस्पी रखता है। कभी-कभी लोग प्रतिष्ठा भंग न हो इस भय से अपने आभूषण तथा वस्त्र बेचकर भी अपना ऋण भुगतान करते हैं। प्रायः कुटुम्ब वाले व्यक्ति बिना बच्चों वालों से अधिक ईमानदार हुआ करते हैं, क्योंकि उन्हें यह भय रहता है कि ऋणों का भुगतान न करने से उनके बच्चों की शादी-विवाह में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो जाये तथा ऋणदाता रकम प्राप्त न होने के कारण उनके बच्चों को किसी प्रकार का शाप न दे। किन्तु इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आय कम होने के कारण दूसरों का स्पया ऐंठ कर अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं।
- (४) वैधानिक सुविधा—साल बहुत कुछ सीमा तक सरकार की नीति एवं विधान पर भी निर्मर होती हैं । कभी-कभी विधान का अनुचित लाभ उठाकर ही ऋगी, ऋगा का सुगतान करना नहीं चाहता । दिवालिया अधिनियम के कारण कुछ व्यक्ति दिवाला निकालकर दूसरों का स्पया हज्म कर जाते हैं और ऐसा करने से वे तिनक भी नहीं हिचकते, क्योंकि यह कार्य अवैधानिक नहीं है ।

साख का वर्गीकरण—कुछ अर्थशास्त्री साख का वर्गीकरण साख की अविषि के अनुसार करते हैं, किन्तु साख का ठीक वर्गीकरण उसके उपयोग तथा साख प्राप्त करने वालों के अनुसार होना चाहिये। अतः सर्वप्रथम साख को दो भागों में विभाजित किया जाता है—सार्वजनिक साख तथा व्यक्तिगत साख। सार्वजनिक साख उस अभूण को कहते हैं जो विभिन्न सरकारें सार्वजनिक कार्यों के लिये लेती हैं। व्यक्तिगत साख के अंतर्गत व्यक्तिगी, व्यापारिक एवं व्यवसायिक संस्थाओं की साख सम्मिलित होती है। इस व्यक्तिगत साख को साख के उद्देश्यानुसार व्यवसायिक साख एवं उपयोग तथा

उत्पादन साख में विभाषित कर सकते हैं । बैद्ध साख उपदम्भि साख का ही एक ऋंग है।

व्यवसायिक साख-जन किसी ऋग की छात्रश्रकः किसी व्यापार अधवा उद्योग-धन्धों को चलाने को होती है तो इसे ही व्यवसायिक साल कहते हैं। यह ऋग कार्यशील पूँजी प्राप्त करने के जिये ऋथवा स्थायी सम्मत्ति क्रय करने के लिए लियं जाते हैं। कभी-कभी व्यानारी ऋगों को ऋपनी सम्पत्ति बन्धक रख कर प्राप्त करता है।

वैङ्क साख — वैंक अपनी व्यक्तिगत पूँजी एवं प्रतिभृतियों द्वारा जो रकम प्राप्त करती है उसे बैंक साख कहते हैं। इसके द्यांतर्गत सभी प्रकार की जमायें, प्रतिकार्ये. ऋगापत्र इत्यादि सिम्लित होते हैं। वैंक ऋपनी साम्त जनता से, संस्थाओं से तथा देश के केन्द्रीय बैंक से प्राप्त करती है।

उपभोग एवं उत्पादन साख -- उपभोग सम्बन्धी साख के ऋंतर्गत व नभी ऋण त्राते हैं जिनसे ऋणी को कोई स्राय प्राप्त नहीं होती। केवल उसकी स्नावश्य कतार्थे संतुष्ट हो जाती हैं। ऋतः ऐसे ऋगों तथा उसकी ज्याज का सुगतान ऋगां न्नपनी न्नान्य त्राय में से करता है। इस प्रकार के ऋण भवन, भोजन, शादी-विकार. मुकदमेवाजी इत्यादि के लिए लिये जाते हैं। उत्पादन साख के त्रांतर्गत लिये गये ऋण उत्पादक कार्यों पर व्यय किये जाते हैं जिनसे ऋणी को आय प्राप्त होती है और इस आय में से ही ऋण तथा उसकी व्याज का भुगतान किया जाता है।

साख के लाभ-

- (१) साल द्वारा घातु द्रव्य के प्रयोग की बचत होती है तथा इस प्रकार अधिक व्यय वाले विनिमय के माध्यम के स्थान पर क्रय व्यय वाला माध्यम प्राप्त हो जाता है। श्राजकल की त्रावश्यकतात्रों को पूरा करने के लिये वह श्रपर्याप्त है। साख-पत्रों द्वारा द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुविधा से तथा कम व्यय में मेका जा सकता है।
- (२) साख द्वारा बचत करने के लिये प्रोत्साहन मिलता है ऋौर पूँची बनाना संभव होता है। लोग पैसा बचाते हैं तथा अपनी बचत अपने ब्राहकों को उस विश्वास पर दे देते हैं कि वे उससे ऋधिक उत्पादन करेंगे। बैंक लामप्रद पूँची लगाने के अव-सर उत्पन्न करती है तथा ऋपने ग्राहकों को निश्चित समय पर उस पूँची के मुगतान का विश्वास दिलाती है जिससे रूपया जमा करने वालों के द्रव्य खींचती है तथा वह द्रव्य उद्योग घंचे ऋौर व्यापार लाभ के कार्यों में संयुक्त होता है।
- (३) ब्राजकल साख मुख्यतः उत्पादन की वृद्धि के लिये है। यह वृद्धि योग्य ब्यापारियों के हाथों को श्रिधिक उत्पादक बनाने से होती है। उत्पादन करने वाले ये

व्यक्ति, जो अपने व्यवहार तथा व्यापारिक योग्यता का लोगों में विश्वास करा सकते हैं, अपने लाम-हानिपूर्ण व्यापारिक कार्यों के लिये साख प्राप्त कर सकते हैं। साख सम्बन्धी सुविधाओं के अपनाव में ऐसे बहुत से उत्पादन करने वालों के लिये, जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, व्यापार करना अथवा व्यापारिक कार्यों को प्रारम्भ करना बड़ा कठिन है।

(४) सुचार रूप से व्यवस्थित साख के कारण मूल्यों की घटती-बढ़ती में कमी होती है तथा व्यापार की दशा, भावों की बढ़ती के समय साख सुविधाओं पर रोक लगाकर तथा भावों की घटती के समय साख की सुविधाओं को बढ़ाकर स्थिर होती है। संचेप में, आजकल साख उद्योग-धन्धों तथा व्यापार को उन्नत बनाने का एक महान् समर्थ साधन है।

साख के दोष— साख की वृद्धि की कोई सीमा नहीं है। सिक्कों को तो घातु की मात्रा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, किन्तु साख की बढ़ोतरी पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कभी-कभी साख इतनी मात्रा में प्रदान कर दी जाती है जिसका वापस करना प्राप्त करने वाले की शक्ति के बाहर है। इससे अप्रयक्ति में वृद्धि होती है और भात्रों में तेजी का भय रहता है। इससे अप्रयिक उत्पादन एवं सहें बाजी को प्रोत्साहन मिलता है। अयोग्य व्यक्ति भी अप्रण् प्राप्त करके हानि पर ही अपने व्यापार को चलाते रहते हैं जिससे राष्ट्र को हानि होती है, साख लोगों की असफलता पर पर्दा डाल देती है। साख के कारण ही एका विकार स्थापित हो जाता है। सरकार भी अप्रण प्राप्त करके अपव्यय कर सकती तथा अपनी कुव्यवस्था को जनता से छिपा सकती है।

किन्तु इस सबका यह ऋर्य नहीं कि साम्ब इतनी बुरी है कि उसको समाप्त कर दिया जाये । उपरोक्त दोष साख के नहीं हैं वरन् साख देने वालों के हैं । यदि साख प्रदान करने वाला सब बातों पर विचार करके विवेकपूर्यों कार्य करे तो साख के दोष स्वतः ही समाप्त हो जायें तथा साख ऋावश्यकता पड़ने पर जीवनाधार बनकर जनता की सेवा करेगी।

साख की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व — साख की मात्रा निम्न- लिखित तत्वों से प्रभावित होती है —

सट्टेंबाजी — सट्टेंबाजी के ऋघिकतर व्यवहार उचार ही चलते हैं। सट्टेंबाजी के विकास के साथ साख का भी विकास होता है तथा साख के विकास के साथ सट्टें-बाजी को प्रोत्साहन मिलता है। साख कम हो जाने पर सट्टा स्वतः ही कम हो जाता है।

व्यापारिक एवं श्रौद्योगिक दशायें—व्यापार तथा उद्योग-धून्धों के विकास के कारण ऋगों की माँग बढ़ती है। ऋगों की बढ़ती हुई माँक को पूरा करने के लिये साख का विस्तार होता है। व्यापारिक एवं श्रीद्योगिक चहल-पहल के साथ साख प्रदान करने वालों को उत्साह मिलता है। व्यापारिक मन्दी में व्यापारी तथा उद्योगपितयों की हानि सहन करने की शक्ति कम हो बाती है। ऐसे समय में लोग उन्हें कम ऋग् प्रदान करते हैं बिससे साख में कमी श्रा बाती है। श्रवः व्यवस्पिक उन्नित के साथ साख का विस्तार होता है तथा शिथिलता के साथ साख में कमी होती है।

ब्याज तथा लाभ की दर—यदि ब्यवसाय से प्राप्त लाभ की दर ऋषिक है तो विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है और ऋषों की मांग बदती है। प्रश्चित बराज के लालच में बहुत से लोग अपनी बचत को ऋषा पर देने को तैयार हो जाते हैं जिससे साख का विस्तार होता है। इसके विपरीत लाभ तथा बराज की दर कम हो जाने से साख में भी कमी आ जाती है।

वैकिंग व्यवस्था— वैंक ही साख की महत्वपूर्ण स्रोत हैं श्रीर इन्हों के द्वारा साख का निर्माण होता है। जिस देश में वैंकिंग की मुदद व्यवस्था होती है वहीं पर साख का भी श्रिषक विस्तार होता है। उन्नतिशील देशों में साख का जितना विस्तार है उतना पिछड़े हुए देशों में नहीं। वैंक की त्रृण प्रदान करने की नीति भी साख की मात्रा निर्धारित करती है। सरकारी मौद्रिक नीति का भी साख पर भागी प्रभाव पहता है। केन्द्रीय वैंक की दर कम होने से साख को बढ़ावा मिलता है जब कि वैंक दर ऊँची होने से साख का विस्तार तथा तेज मुद्रा नीति से साख का संकुचन होता है।

राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय हलचल—यदि देश में शान्ति तथा स्थिरता है तो लोगों का ऋार्थिक जीवन भी स्थिर रहता है। ऋार्थिक विकास के साथ-साथ नवीन योजनाओं का निर्माण होता है। ऋगों की प्रति दिन माँग बद्दती है ऋौर साल का विस्तार होता है। ऋशांति काल में ऋार्थिक जीवन स्थिर नहीं रह पाता। ऋतः ऋग्ण प्रदान करने तथा माँगने वालों की संख्या में कभी हो जाती है। सरकार के बदल जाने पर भी साख के विस्तार में कम हो जाती है। ऋंतर्राष्ट्रीय वातावरण दृष्ति हो जाने पर व्यापार में ऋनिश्चतता ऋाती है जिसके कारण साल में कभी हो जाती है। युदक्ताल में धनी लोग ऋग्ण प्रदान न करके सोना क्रय करके रखना पसंद करते हैं जिसके कारण साल में कभी हो जाती है।

साख तथा पूँजी—साख पूँजी से भिन्न होती है। सख में द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। स्नतः साख स्वयं उत्पादन का साधन है। यह तो केवल उत्पादन करने में सहायता प्रदान करती है। साख केवल उन व्यक्तियों से जो धन का ख्रच्छा उपयोग नहीं कर सकते, धून लेकर उन व्यक्तियों के पास पहुँचाती है जो इसका ख्रच्छा उपयोग करना जानते हैं। कुछ स्वर्थशास्त्रियों का मत है कि "साख पूँजी है।" मैंकलौयड ने

साल को पूँजी ही माना है। किन्तु अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात से सहमत नहीं क्योंकि वास्तव में साल उत्पत्ति का साधन नहीं है। यह तो केवल वह रीति है जिसके द्वारा वस्तुओं में उपयोगिता सिन्धिहत होती है। अतः साल एक विनिमय मात्र है। साल स्वयं पूँजी नहीं वरन् पूँजी प्राप्त करने का एक साधन है। इससे पूँजी उत्पन्न नहीं होती। केवल यह बात निर्धारित होती है कि पूँजी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाये। मिल के कथनानुसार ऋण प्रदान करने से पूँजी का कवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण हो जाता है; नवीन पूँजी उत्पन्न नहीं होती। कुछ लोग साल पत्रों को पूँजी मानते हैं। किन्तु ये पत्र पूँजी नहीं। केवल पूँजी के प्रतिनिधि हैं। तथा पूँजी के हस्तांतरण में सुविधा प्रदान करते हैं। इससे केवल पूँजी में गतिशीलता उत्पन्न होती है और पूँजी की उत्पादनशक्ति में वृद्धि हो जाती है। किसी मी अवस्था में इससे पूँजी की मात्रा नहीं बढ़ती। अतः साल को पूँजी मानना उचित नहीं है।

बैंकों द्वारा साख की उत्पत्ति—साख ही श्राधुनिक व्यापार श्रीर व्यवसाय की श्राधार-शिला है। वर्तमान श्राधिक व्यवसाय में पैमाने पर श्राज उत्पत्ति श्रीर विनिमय होता है। वह बिना साख की सहायता के कदापि सम्मव नहीं हो सकता। संसार का श्रिषकतर व्यापार श्राज साख के श्राधार पर ही होता है न कि रोकड़ी रुपयों के श्राधार पर। यही कारण है कि श्राधुनिक श्राधिक संगठन में साख को श्रात्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसका श्राधिक जीवन के प्रत्येक पहलू में बोलबाला है। फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से, थोक विक्रेता कारखाने वाले से तथा कारखाने वाले स्वयं व्यापारियों से साख पर वस्तुएँ क्रय करते हैं। साख-व्यवस्था में बैङ्क बड़ा महत्व रखती हैं। बैङ्क तथा साख में गहरा सम्बन्ध है। बैङ्क समय-समय पर व्यापारियों को निम्न प्रकार की साख प्रदान करती है:—

- (१) व्यक्तिगत साख—इस साख को विशुद्ध साख भी कहते हैं। इसमें गिरवी इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस साख में बैंक बिना किसी गिरवी अथवा जमानत के उधार देती है।
- (२) नकद साख—इस साख के अनुसार बैंक अपने गोदाम में माल रख लेती हैं श्रीर अपने लेनदार को उधार देती है।
- (३) श्रपरिमासिगत साख इस साख के श्रनुसार बैंक यह उत्तरदायित्व नहीं लेती । किन्हीं विशेष दशाश्रों श्रीर शर्तों पर वह सुगतान दे देती है। बैंक चाहे तो सुगतान दे सकती है श्रीर न चाहे तो नहीं भी दे सकती । इसे संयुक्त राज्य श्रमेरिका में प्रत्यादेश्य (Revocable Credit) कही बाती है।
 - (४) निश्चित साख-र्यंद्र गाख किसी विशेष समय तक निश्चित धन के

लिये होती है। इसमें एक साथ अथवा कई बार में उधार का निश्चित धन दे दिया जाता है।

- (४) चालू साख—यह साख लगमग निश्चित माल की उल्टी होती है। इसमें हर समय नया हिसाब होता रहता है तथा पुरानी बिलें चुका दी बाती हैं। बैसे-जैसे नई बिलों के चुकाने का समय आता है उसी प्रकार नई बिलें आती रहती हैं।
- (६) सीमांत साखपत्र—यह वह पत्र है जो बिल के साथ रहता है तथा जिसकी शर्तों और रकम के अनुसार बिल का सुगतान होता है। यह बिल का मुख्य अंग होता है और इसके अनुसार निर्यात करने वाले को उधार मिलता है। इसमें बिल लिखने के समय आर्थिक स्थिति का पर्श्व ज्ञान रहता है।
- (७) खाते की साख—श्राजकल इस प्रकार की साख बहुत अविन है। इसके श्रमुसार दो संस्थायें श्रथवा व्यापारी एक दूसरे को किसी सीमा तक उधार देना निश्चित कर लेते हैं तथा उधार लेते-देते रहते हैं तथा हर समय नकद नहीं देने। श्रंत में हिसाब करते समय नकद लेन-देन होता है।
- (प) विपन्न साख इसके अनुसार लिखे जाने वाले बिलों के साथ रेल की रसीद अथवा बिल आप लेंडिंग लगा दिये जाते हैं जो कि एक रेहन के समान होने हैं तथा इन विपन्नों के होने पर इस प्रकार के बिल का सुगतान अथवा स्वीकृति होती है।
- (६) सांकेतिक साख—जब विदेश में भ्रमण करने वाला विदेश में रहता है तो वह सांकेतिक साखपत्र को प्रस्तुत करके बैक्क से क्या प्रप्त करता है। यह प्रान्टर द्वारा साखपत्र के साथ दिया जाता है। इसका भुगतान देते समय बैक्क रुपया लेने बाले का हस्ताच्चर करवा लेती है।

इसके श्रातिरिक्त भ्रमण करने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिये बैक्क यात्री साखपत्र, यात्रियों को चेक तथा गश्ती चेक इत्यादि देकर मी सहायता प्रदान करती है।

साखपत्र—साखपत्र सरकार त्राथवा किसी संस्था द्वारा जारी किया गया वह लिखित दस्तावेज है जिसमें भविष्य की तिथि पर रुपया जुकाने की प्रतिज्ञा की जाती है। द्रव्य की भाँति साखपत्रों से भी विनिमय के कार्यों में बड़ी सुविधा रहती है किन्दुं उनका चलन सीमित रहता है। जारी करने वाली पार्टी की साख जितनी ऋषिक हट तथा प्रसिद्ध होगी उतना ही श्रिधिक उसके साखपत्रों का चलन होगा।

साखपत्र निम्न प्रकार के होते हैं.-

(१) प्रतिज्ञापत्र—इंडियन निगोशियेबिल इन्स्ट्रुमेंट ऐक्ट के अनुसार प्रतिशा-पत्र एक लिखित दस्तावेज हैं जिसमें लिखनेवाले के हस्ताच्चर रहते हैं और बिना किसी शर्त के एक निश्चित रकम चुकाने की वह प्रतिशा करता है। इसकी रकम उसी को मिल सकती है जिसके नाम वह दस्तावेज हो श्रीर जिसके लिये कहा गया हो श्रथवा जो उस दस्तावेज को लाया हो।

प्रतिज्ञापत्र का नम्ना

2000)

मेरठ

२३ नवम्बर, १६५८

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से ३ मास पश्चात् १००) श्री रत्नलाल गोयल को श्रथवा उनकी श्राज्ञानुसार किसी श्रन्य व्यक्ति को सुगतान कर दूँगा जिसका म्लय मुक्ते मिल चुका है। पीतम चन्द मेरठ

2000)

२३ नवम्बर, १६५८

में प्रतिज्ञा करता हूँ कि माँगने पर १०००) श्री रत्नलाल गोयल को अथवा उनकी आज्ञानुसार किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान दूँगा, जिसका मुल्य सुक्ते मिल चुका है।

पीतम चन्द

संयुक्त प्रतिज्ञापत्र—इस प्रकार के प्रतिज्ञापत्र दो अथवा अधिक व्यक्तियो द्वारा लिखे जाते हैं तथा इनके भुगतान का उत्तरदायित्व लिखने वालों पर केवल संयुक्त रूप से रहता है। दूसरे शब्दों में यदि ऐसे प्रतिज्ञापत्र की श्रप्रतिष्ठा हो जावे तो पत्रवाहक प्रतिज्ञा की रकम को प्राप्त करने के लिये प्रतिज्ञा करने वाले सभी व्यक्तियों पर सम्मिलित रूप से दावा कर सकता है। दुर्माग्य से, यदि वह किसी एक का नाम देने में भूल जाये वो बाद में उस पर ऋलग से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

(२) विपत्र अथवा बिल आफ एक्सचेंज-यह एक लिखित आज्ञा होती है। इसका लिखने वाला अपने देनदार अन्य व्यक्ति को अपने हस्ताच्चर करके यह श्राज्ञा लिखता है कि वह बिना किसी शर्त के तीसरें व्यक्ति को अथवा उसकी श्राज्ञा-तुसार श्रन्य किसी व्यक्ति को श्रथवा श्राभापत्र पेश करने वाले व्यक्ति को उसमें लिखित रकम दे दे।

भुगतान की दृष्टि से बिल दो प्रकार के होते हैं-

- (१) दर्शनी बिल-जिसका भुगतान बिल पेश होते ही किया जाता है।
- (२) मुद्दती बिल-बिनमें दर्ज रकम का भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात् जैसे बिल स्वीकृति के ३० श्रथवा ६० दिन पश्चात् किया जाता है। हुन्डी का

गतान करने के लिये ३ दिन तक का ऋषिक समय जिसे रियायत के दिन कहते हैं, लिता है। दर्शनी बिल बिल्कुल चेक की तरह होती है किन्तु बिल आफ एक्सचेंज था: मुद्दती ही होता है।

बिल आफ एक्सचेंज देशी बिल और विदेशी बिल के रूप में होते हैं। बो बिल क ही देश के मीतर जारी किया जाय और उसका मुगतान मी वहाँ ही किया जाये व वह देशी बिल कहलाता है। और बो बिल एक देश से जाये और दूसरे देश में सका मुगतान किया जाये वह विदेशी बिल कहलाता है। विदेशी बिल विदेशों में गुगतान करने के •िलये बनाये जाते हैं। जिस प्रकार विदेशी बिल एक बड़ी मात्रा में गातु द्रव्य की आवश्यकता को कम करके विनिमय के कार्य को सरल बना देते हैं उसी गकार विदेशी बिल भी विदेशों से व्यापार करने का कार्य सरल कर देते हैं।

बिल श्रथवा विपत्र के नमूने :-

देशी बिल का नम्ना

₹0 400-0-0

पटना

28-88-45

स्टाम्प

श्राज के ३ मास पश्चात्, हमारी श्राशानुसार, केवल पाँच सौ क्यये प्राप्त मूल्य के बदले मुगतान कीजिये।

श्री रामचन्द्र

बोरिंग रोड,

ब्रह्मदेव श्राचार्य

पटना ।

विदेशी बिल का नमूना

स्टाम्प

संख्या—क ५५७ पौंड ५०० ७४५, लौगऐकरे रीडिंग नवम्बर २२, १९५८

ं इस अथम विषत्र के द्रश्नन के ६० दिन पश्चात् (यदि उक्त तिथि एवं विवरण के दितीय एवं कृतीय विषत्र का मुगतान न किया गया हो), स्टेट के आफ इंडिया को, केवल पचास पौंड प्राप्त मूल्य के बदले मुगतान की जिये।

सेवा में. श्री मैनेजर महोदय, माडर्न ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर ऐन्ड इम्मोर्टर ४२, थर्ड ए गेरी लेन, बम्बई।

रेमंड ऐन्ड एटकिंसन के लिये ऐम, मास्टर्स मैनेजर

हुएडी—हुएडी बिल के ही समान होती है। उसका प्रयोग बाजार के व्यापारी तथा सर्राफ बहुत करते हैं। इनका चलन व्यापार के रीति-रिवाज के अनुसार होता है। जब बिल की ऋावश्यक बातें पूरी करती हैं तो वे भारतीय विनिमय साध्य पुर्जा कान्त के अन्तर्गत आ जाती हैं। बिल की हुिएडयाँ तीन प्रकार की होती हैं,:--

(१) दर्शनी हुएडी—िबसका भुगतान माँगने पर करना पड़ता है।

दर्शनी हुण्डी का नमूना

सिद्ध श्री कानपुर शुभस्थान श्री पत्री भाई हर प्रसाद बालमुकुन्द जोग लिखी प्रयाग जी से बंशीधर रामचन्द्र की राम राम बाँचना। आरो हुगडी कीनी एक। आप ऊपर दिया रुपया ५०० ऋाँकड़े पाँच सौ के नीमे दो सौ पचास के दूने पूरे देना। यहाँ राखा भाई दी स्टेट बैङ्क स्राफ इंडिया, इलाहाबाद वाले के मिती फागुन बदी २ को पहुँचे। दान धनीजोग बिना जाप्ता बाजार चलन हुगडी की रीति ठिकाने लगाय दाम चौकस कर देना। फागुन बदी २, सं० २०१५

विशेष—यह हुगडी इलाहाबाद (प्रयाग जी) के बंशीधर रामचन्द्र ने कानपुर के हरप्रसाद बालमुकुन्द पर ५००) के लिये की है। स्टेट बैक्क स्राफ इंडिया के माँगने पर फागुन बदी २, सं० १६१५ के पश्चात् इसका मुगतान कर देगा।

(२) मिती हुएडी - जिसका भुगतान देखने के उपरान्त कुछ दिनों पश्चात् होता है। मिती हुगडी ऋषिकतर देखने के ६१ दिन पश्चात् भुगतान के लिये की जाती है। मिती हुएडी पर रियायती दिन उस स्थान की रिवाजों के अनुसार दिये जाते हैं जहाँ हुग्डी का भुगतान होता है। हुग्डी श्रिधिकतर मुड़िया में लिखी जाती है।

मिती हुण्डी का न नृना

हापुड़ से रामस्वरूप की राम-राम बाँचना । श्रपरंच हुएडी एक रुपया २५०० आंकड़े पच्चीस सौ जिसका नीमा रुपया बारह सौ का दूना पुरा।

अहे राखा दि स्टेट बैंक्क लिमिटेड पास मिती फागुन सुदी दसमी (१०) से दिन इकसठ (६१) पीछे, नामे साह जोग हुएडी चलन कल्दार दी जी मिती साक्न सुदी दसमी (१०) सम्बत् २०१५।

(३) साह जोग हुएडी—यह वह हुएडी होती है जिसका सुरादान बाजार चलन के अनुसार किसी प्रतिष्ठित साह अथवा सेठ को ही किया वा सकता है। यदि हुन्हीं किसी अन्य व्यक्ति के नाम में है तो उसका सुगतान लेने के पहले उसका बेचान किसी सेठ के नाम होना आवश्यक है। इस प्रकार की हुंडियों का भुगतान करने वाले को कोई जोखिम नहीं है।

हुन्ही एक प्रकार की देशी बिल ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि बिल प्राय: अंग्रेजी में लिखे जाते हैं और हुन्ही किसी भारतीय मापा अथवा देवनागरी वा विशेष कर सराफी में लिखी जाती हैं।

बिलों का चेलन मारतीय निगोशियेबित इन्स्टर्मेंट ऐक्ट के अनुसार होता है जब कि हुन्डी का चलन बाजार प्रथा के अनुसार होता है।

चेक — उन्नत देशों में मनुष्य सुविधा के कारण बैक्कों में क्यया जमा करना और आवश्यकता पड़ने पर वैक्कों द्वारा क्या निकालना पसन्द करते हैं जिसे क्या जमा करने वाला अपनी वैक्क के नाम जारी करता है और जिसमें उस वैक्क के लिये यह आदेश रहता है कि उस व्यक्ति को जिसका नाम वैक्क में लिखा है अथवा उसकी अपनानुसार किसी अन्य व्यक्ति को जिसका नाम चेक में लिखा है अथवा उसकी अपनानुसार किसी अन्य व्यक्ति को जिसका नाम चेक में लिखा है अथवा उसकी अपनानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा चेक लाने वाले को चेक में लिखी रकम दुरन्त चुका दूँगा। माँग होने पर चेक का मुगतान करना पड़ता है तथा वैक्क चेक का क्या देने से इन्कार नहीं कर सकती जब तक कि चेक जारी करने वाले का उतना करया देने से इन्कार सहीं कर सकती जब तक कि चेक जारी करने वाले का उतना करया वैक्क में जमा रहता है। सुविधा, ज्ञमता तथा जालसाजी से बचने के लिये बैक्क क्या का करने वालों को एक छपी किताब अर्थात् चेक बुक देता है। वह व्यक्ति जो करना निपाली अथवा चेक लिखता है Drawer कहलाता है। वेक्क अथवा जिसके नाम चेक लिखता है Drawer कहलाता है। किमी-कमी जब कमी वह निजी अववस्त्रका के लिखे क्यो निकालता है (Self) लिख कर चेक जारी करता है। इस्तान्तरस्य की लीये क्यो निकालता है (Order Cheque अथवा Bearer Cheque हो सकता है। योग्यता की होंकेट से Order Cheque अथवा Bearer Cheque हो सकता है।

हस्तान्तरण की दृष्टि से चेक दो प्रकार के होते हैं—वाहक चेक तथा आदे-शात्मक चेक।

वाहक चेक(Bearer Cheque) अथवा घनाजोग चेक की रकम चेक रखने वाले अथवा लाने वाले को मिलती है। चेक पेश करने वाले को उसकी रकम दुरन्त मिल जाती है। वाहकू चेक की 'रकम यदि किसी अन्य गलत आदमी को देदी जाती है तो बैङ्क उसके लिए दोषी नहीं ठहरती क्योंकि ऐसे चेक में बैङ्क को यह जानने की श्रावश्यकता नहीं है कि पेश करने वाला उसका वास्तविक श्रिष्ठिकारी है श्रथवा नहीं।

यदि चेक में Bearer शब्द काटकर Order शब्द लिख दिया जाये तो Bearer चेक ही Order चेक श्रयवा शाहजोग चेक बन जाता है। यह श्रधिक सुरिद्धित होता है, क्योंकि तैं इह उस चेक का रुपया तब तक नहीं देती जब तक रुपया लेने वाला यह सिद्ध न कर सके कि वह वही व्यक्ति है जिसके नाम चेक है। यह दूसरे के नाम तभी हस्तान्तरित किया जा सकता है जब रुपया पाने वाला उस चेक पर श्रपने हस्तान्तर न कर दे।

वाहक चेक का नम्ना भुगतान की जिये श्रीराम मेहता श्रथवा वाहक को श्रादेशात्मक चेक का नम्ना

भुगतान कीजिये श्री मुरेशराम भाई स्रथवा स्रादेश प्राप्त को चेक का रेखांकन (Crossing of Cheques)

रेखांकन शब्द का सीधा-साधा ऋर्थ है रेखायें बनाना। ऋतः चेक पर दो समानान्तर रेखायें खींचने का ऋर्थ चेक का रेखांकन करना होता है।

रेखाङ्कन के भेद—(१) साधारण रेखांकन (Ordinary Crossing)— यदि किसी चेक पर दो तिछीं समानान्तर रेखायें खींच दी जाती है, परन्तु उनमें बैङ्क विशेष का नाम नहीं दिया होता तो उसे साधारण रेखांकन कहते हैं। इस प्रकार के चेकों को खिड़की पर भुगतान किया जा सकता है। यही कारण है कि इनके भुगतान में कभी-कभी घोखेबाजी हो जाती है। साधारण रेखांकन निम्नांकित ढंग से किया जा सकता है:—

- (श्र) केवल समानान्तर रूप से दो तिरछी रेखार्ये खींचकर,
- (त्रा) रेखात्रों के बीच में 'एन्ड कम्पनी' त्रादि महत्वहीन शब्द लिखकर।
- (इ) रेखाश्रों में केवल भुगतान वाला खाते में (Account payee only) लिखकर । इसका प्रमाव यह होता है कि बैंक चेक की रकम केवल उसी खाते में जमा करती है, जिसका नाम लेखक ने पाने वाले के रूप में दिया है। श्रन्य को नहीं । श्रतः इनका भुगतान खिड़की पर घोखेबाब श्रथवा चोर नहीं पा सकते।
- (ई) रेखा श्रों में केवल पचास रुपये के श्रांतर्गत जैसे शब्द लिखकर इन शब्दों को लिखने के दो उद्देश्य होते हैं। प्रथम, साहू कार की रकम का श्रानुमान तो हो परन्तु वास्तविक रकम का पता न हो। ऐसी दशा में चेक में रकम नहीं लिखी जाती।

केवल रुपये की अनुमान से गोल संख्या में लिख दी बाती है। मुगतानदाता उनमें उक्त रेखांकित रकम तक कोई भी रकम पाने का अधिकारी हो बाता है। दूसरे, उक्त रकम से अधिक रकम बालसाबी द्वारा नहीं घटाई बा सकती है। ऐसी दशा में सिद्धहस्त जालसाबों की दाल नहीं गल पाती।

- (उ) रेखात्रों में 'बेचान साध्य नहीं' (Not Negotiable) क्लिक्सइसका प्रभाव यह होता है कि चेक पाने वाला देने वाले के क्रिकार के विषय में
 भली प्रकार निश्चित करने के पश्चात् ही चेक प्राप्त करने का साहस करता है। यह
 उसे उसके अधिकार के दूषित होने की किचित भी गंध आ बाती है तो वह मुगतान
 को अस्वीकृत कर सकता है। यह ध्यान में रखने की वाल है कि चेक को स्वीकार
 करने के लिये किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि वह इसका ज्ञान होने पर
 भी चेक स्वीकार करता है तो उसका अधिकार भी दूषित हो बाता है। यही कारस
 है कि विद्यार्थी कभी-कभी अबेचानसाध्य का अर्थ 'अहस्तांतर योग्य' लगा बैठते हैं।
 परन्तु यह सममना भारी भूल है। बो चेक पूर्ण विश्वास के साथ, वस्तु विशेष के
 प्रतिकृत में तथा ठीक प्रकार से लिखा जा रहा है, उसके स्वामी को उस चेक पर
 अच्छा अधिकार प्राप्त होता है। और देने वाले के दूषित अधिकार का प्रमाव उस
 पर किचित मात्र भी नहीं पहता। परन्तु यदि उस पर 'अबेचानसाध्य' रान्द लिखा
 रहता है तो उक्त शर्तों की पूर्ति पर भी पाने वाले का अधिकार देने वाले के अधिकार
 से अच्छा नहीं होता। अतः पाने वाले को ऐसे इस्तांतर कर्ताओं से चेक प्राप्त करते
 समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए।
- (२) विशेष रेखांकन (Special Crossing)—इस प्रकार के रेखांकन में साधारण रेखांकन की तरह दो तिरखी समानान्तर रेखायें खिची यहती हैं; रेखांकन के मध्य में साधारण रेखांकन के संबन्ध में ऋणिखित सभी शब्द दिये चा सकते हैं, तथा उनके बीच में किसी बैंक का नाम आवश्यक रूप से दिया यहता है। बिना बैंक के नाम से रेखांकन को विशेष रेखांकन नहीं कहा चा सकता। श्नका मुगतान बैंक की खिड़की पर नहीं होता वरन बेचान द्वारा बैंक्क से चालू खाते में खमा की रकम के रूप में किया जाता है। अतः यदि कोई व्यक्ति घोलेबाजी, चोरी अथवा चाल द्वारा इनका स्थातान प्राप्त कर ले, तो बैंक्क की संहायता से उसका पत्तान प्राप्त कर ले, तो बैंक्क की संहायता से उसका पता सरलता से लगाया चा सकता है।

साधारण तथा विशेष रेखांकन के उदाहरण

१-साधारग रेखांकन

		*	111111	1 /211.15	. 1		
	एएड कमनी		केवल पचास रुपये तक		केबल सुगतानदाता के खाते में	केचान साध्य नहीं	,
		₹—	-विशेष [ः]	रेखांकन		1	}
पंजाब हैक एएड कम्पनी		पंजाब बैंक फेवल पचास रुपये तक		पंजाब वैक केवल भुगतानदाता के खाते में		पंजाब बैक ऋबेचान साध्य	

रेखाङ्कन करने वाले पच्च चेक निम्नोकित पच्चों द्वारा रेखाँकित किया जा ॥ है:---

- (१) लेखक—वंह स्वयं उपरोक्त उल्लिखित दोनों प्रकार से चेक का रेखांकन कर सकता है। इतना ही नहीं, वह 'स्पया मुगतान की जिये' (Pay Cash) शब्द लिखकर पहले किये गये रेखांकन को समाप्त कर सकता है। इस प्रकार का चेक वाहक चेक' समझा जाता है।
 - (२) धारक--कोई भी धारक अरेखांकित चेक को सीधारण अथवा विशेष

रेंलांकित, साधारण रेलांकित को निशेष रेलांकित तथा वेचान साध्य को अवेचान साध्य कर सकता है।

(३) बैंक—वह वैंक जिसके नाम कोई चेक लिखा गया हो, दूसरी वैंक स्प्रधा अपने प्रतिनिधि के नाम साधारण अथवा विशेष रेखांकित कर सकती है। इस प्रकार उसे धारक के भी अधिकार प्राप्त होते हैं।

चेक का रेखांकन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया बाता है--

- (१) इन्हें अनुचित अधिकारी (जैसे चोर, घोलेबाब, बेईमान आदि) पहले तो प्राप्त ही.नहीं कर सकते तथा यदि किसी प्रकार उनका सुगतान भी पा लेते हैं तो उसका पता लगाना, सरल हो जाता है।
- (२) इसे डाक द्वारा मेजने में मुविधा और सुरचा रहती है, क्योंकि उसके रास्ते में खो जाने पर भी हानि होने की कोई संमावना नहीं रहती।
- (३) बैंक इन्हें बड़ी सावधानी से भुगतान करती है। साधारण रेखांकन होने पर किसी बैंक द्वारा तथा विशेष बैंक द्वारा उल्लिखित स्कम समा के रूप में भुगतान की जाती है। अतः स्वका रूपया नकद खिड़की पर नहीं दिया जाता।
- (४) उनके पाने वाला अपने अथवा अन्य किसी जानकार व्यक्ति के चालू खाते में रेखांकित चेक की रकम जमा करने के पश्चात् ही नकद रकम पा सकता है। यदि इनका किसी भी बैंक में निजी चालू खाता नहीं होता तो वे बेचान द्वारा चेक की रकम को अन्य व्यक्ति के खाते में डलवा देते हैं। बैंक किसी अन्धिकृत चेक अथवा व्यक्ति को भूल से खिड़की पर अथवा जमा द्वारा भुगतान करने पर स्वयं उत्तरहायी होती है।
- (५) इन्हें प्राप्त करने वाले को भी सावधानी रखनी पड़ती है। यदि उसका श्रिधिकार दूषित होता है तो वह वास्तविक स्वामी के प्रति उत्तरदायी उहराया जाता है तथा उसको पहुँची हुई ज्ञित की पूर्वि करनी पड़ती है।

चेक का बेचान

बहुधा च्यापारी लोग चेक, विपन्न श्रयवा प्रतिश्चापत्र श्रादि सभी विनिमय-साध्य पत्रों को श्रपने साहूकारों को ऋग्य के मुगतान में सौंप देते हैं। साहूकार इनको मुना कर श्रयवा निश्चित तिथि तक श्रपने पास रख कर प्राप्त हुए पत्र में उल्लिखित रकम पा लेते हैं।

बेचान के भेद

ं (१) साधारण बेचान (General Endorsement)—जिस विनिमय साध्य पत्र को केवल इस्ताचर मात्र से इस्तांतरित किया जाता है उस पर किये गये बेचान को साधारण बेचान कहते हैं। यदि किसी चेक अध्या विपत्र में परिवर्तन करना हो तो उस पर खुला बेचान कर देना चाहिये। इनका मुगतान किसी भी व्यक्ति को बैंक द्वारा किया जा सकता है।

- (२) पूर्ण बेचान (Special Endorsement)—इस प्रकार के बेचान के लिये यह त्रावर्यक है कि बेचानकर्ता न केवल हम्ताच्र ही करे वरन् बेचान पाने वाले का नाम तथा बेचान तिथि उल्लेख मी करें। इस प्रकार के बेचान के परचात् किये गये सभी बेचान उक्त रीति से ही होने चाहिये ऋन्यथा उन्हें ऋपूर्ण समभा जायेगा। कोई भी धारक साधारण बेचान में बेचान पाने वाले व्यक्ति का नाम लिख सकता है। ऐसा करने से वह न केवल हस्ताच्र करने से ही वर्रन् विपन्न के उत्तर-दायित्व से अपने को बचा लेता है।
- ·(३) प्रतिबन्धित बैचान (Restrictive Endorsement)—ये वे आधारण श्रथवा विशेष बेचान होते हैं, जिनके भुगतान के संबन्ध में किसी न किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। श्रतः इसके पाने वाले के श्रधिकार सीमित हो जाते हैं।
- (४) आंशिक बेचान (Partial Endorsement)—यह वह बेचान है जिनमें बेचान का अधिकारी बेचान-पत्र की रकम के कुछ अंश का ही बेचान करता है। यह बहुधा उसी समय आवश्यक होता है जब बेचान पाने वाले को बेचान-पत्र की शेष रकम पहले ही प्राप्त हो गई हो। आजकल इसका चलन कम हो गया है।
- (४) दायित्व रहित बेचान—इस बेचान के द्वारा बेचानकर्ता बेचान-पत्र के उत्तरदायित्व से छुट्टी पा लेता है। यदि इसे भुगतानकर्ता भुगतान नहीं करता तो घारक को यह अधिकार नहीं होता कि यदि वह चाहे तो उसे अस्वीकार न करे।
- (६) प्रतिबंधित बेचान (Conditional Endorsement)—इस प्रकार की बेचान में बेचान कर्ता बेचान पाने वाले को बेचान-पत्र पर अधिकार देने से पूर्व कुछ शर्ते पालन करने का अधिकार देता है। इसे अनुबंधित आज्ञा कहना अनुपयुक्त न होगा।
- (७) सुविधा युंक्त वेचान (Facultative Endorsement)— जहाँ वेचान कर्ता यह स्पष्ट कर देता है कि उसे विपत्र के भुगतान न होने श्रथवा श्रप्रतिष्ठा की स्चना देना श्रावश्यक नही वहाँ पर विना स्चना दिये हुए भी वेचानकर्ता को उत्तरदायी बनाया जा सकता है। इस प्रकार के बेचान 'सुविधा युक्क वेचान' कह- लाते हैं।

चेक के सम्बन्ध में अन्य बातें :---

- (१) पूर्व तिथि का चेक—इसमें चैक लिखने वाला लिखने वाली तारील के पूर्व की कोई तारीख डाल देता है। यदि बैंक में उपस्थित करते समय चेक ६ मास के श्रीधिक पुराना है तो बैंक ऐसे चेक का सुगतान नहीं करती। ऐसे चेकों को पुराने चेक श्रीधिक Stale Cheque भी कहते हैं।
- (२) भविष्य की तारीख का चेक—(Post-dated Cheque)—इन चेकें पर त्राने की तारीख पड़ी रहती है। जब तक मविष्य की वह तारीख न आ बाये को चेक पर पड़ी है तब तक बेंक इसका भुगतान नहीं करती। किन्तु वह तारीख आने से पूर्व ऐसे चेकों का बेचाम किया जा सकता है और वह वैष्ठ होता है।
- (३) अपूर्ण चेक (Inchoate Cheque)—यदि चेक में तारीस, रक्म, पाने वाले का नाम अथवा कोई और बात लिखने से रह गई है तो ऐसे चेक का भुगतान बैंक नहीं करती। यदि चेक पर लिखने वाले के हस्ताचर है तो भुगतान माँगने वाला अपूर्ण चेक को वे सारी बातें लिख कर पूर्ण कर सकता है किन्हें लिखने वाला लिखना चाहता था। ऐसे चेकों में यह समका बाता है कि लिखने वाले ने चेक के घारक को पूर्ण करने का अधिकार दे दिया है।
- (४) कटा-फटा चेक (Mutilated Cheque)— को चेक कटा-फटा हेट है अथवा जिस पर किसी प्रकार का घब्बा पड़ गया है। बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करता। किन्तु घारक उसके बदले चेक लिखने वाले से दूसरा चेक प्राप्त करने का अधिकारी होता है।
- (प्र) चिन्हित चेक (Marked Cheque)—यदि धारक कि.टी. कारण से चेक का भुगतान तुरन्त न लेना चाहे तो वह चेक पर बैंक से यह प्रमाणित करा सकता है कि चेक लिखने वाले के हिसाब में चेक का भुगतान करने के लिये पर्याप्त करवा है। किन्तु इसं प्रमाण का यह अर्थ नहीं कि बैंक ने भुगतान का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। प्रमाणित करने के पश्चात् चेक लिखने वाला अपना क्पया निकाल लेता है अथवा उसके हिसाब में से किसी दूसरे चेक का भुगतान हो जाता है अथवा न्यायालय भुगतान पर प्रतिबन्ध लगा देता है तो चेक का धारक बैंक को भुगतान देने के लिये विवश नहीं कर सकता।

श्रन्य साख पत्र :---

बैंक्ट ड्राफ्ट (Bank Draft)—यह एक प्रकार का चेक ही है जिसे एक बैंक दूसरी बैंक के नाम अथवा अप्य रियान पर स्थित अपनी बैंक की शासा के नाम जारी करता है तथा यह लिखा रहता है कि अमुक व्यक्ति को अथवा ड्राफ्ट पेश करने वाले को इसमें लिखित रकम दे दी जाये। ऐसी अवस्था में जो केंक ड्राफ्ट बनता है वह Drawee और जिसे रकम का सुगतान दिया जाता है वह Payee कहलाता है। व्यापारियों को प्रायः दूरस्थ देशों में रहने वाले लोगों को रुपया देना पड़ता है। ऐसी रकम का सुगतान करने का सबसे सस्ता तरीका यही है कि वह रकम अपने शहर के किसी बैंक में जमा कर उस व्यक्ति के नाम जिसको रुपया मेजना है, बैंक ड्राफ्ट बनवा लें। बैंक ऐसे चेक जारी करने के लिये कुछ कमीशन लेती है। विदेशों का सुगतान प्रायः बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है। आई० ओ० यू० (I. O. U.) इसका अर्थ होता है कि सुक्त पर आपका चाहिये। कमी-कभी अल्प काल के लिये सद्दन सा अर्थ होता है कि सुक्त पर आपका चाहिये। कमी-कभी अल्प काल के लिये सद्दन सा अर्थ हाता है कि सुक्त वह लिख कर ही ले लिया जाता है। अर्थ लेने वाला एक कागज के दुकड़े पर केवल वह लिख कर अपना हस्ताच्चर कर देता है कि सुक्त पर आपके इतने रुपये चाहिये। ऐसे पत्र पर किसी टिकट की आवश्य-कता नहीं और इसीलिये वह पत्र केवल २०) तक के लिये लिखा जाता है। अधिक के लिये नहीं। इस पत्र का बेचान नहीं होता। यह पत्र केवल व्यवहारिक है, वैधा-निक महत्व नहीं एखता।

प्रश्न

1. What is credit? Discuss the limitations on the power of banks to create credit.

साख किसे कहते हैं ? बैंक की साख उत्पन्न करने की शाक्ति की सीमाओं का वर्णन कीजिये।

2. Explain the processes by which banks create credit. What is the effect of credit on prices?

बैंक साख की उत्पत्ति किस प्रकार करती है ? साख का मूल्यों पर क्या

प्रभाव पड़ता है ?
3. What is a Darshani Hundi? Draw up a Darshani Hundi in proper form.

दर्शनी हुन्डी किसे कहते हैं ? उपयुक्त रूप में दर्शनी हुन्ड्डी लिखिये।

4. What is a cheque? Illustrate the different ways of crossing a cheque and indicate the implication of each type of crossing.

चेक की पैरिभाषा दीजिये। चैक को विभिन्न प्रकार से रेखांकित करने के उदाहरण दीजिये तथा हर प्रकार के रेखांकन का प्रभाव बतलाइये।

5. Why and how are cheques crossed? Explain "Nor Negotiable Crossing."

चेक क्यों श्रीर किस प्रकार रेखां कित किये जाते हैं ? श्रविनिमय साध्य रेखांकन का क्या श्रर्थ है !

- 6. What is meant by endorsement of a negotiable instrument. विनिमय साध्य प्रपत्र के बेचान का क्या ऋर्य है! भिन्न प्रकार के बेचान का वर्णन कीजिये।
- 7. What is a P/N? What are its advantages? Prepare a P/N in proper form with imaginary data.

प्रतिज्ञापत्र किसे कहते हैं ? इसके क्या लाभ हैं ? उभयुक्त रूप से एक काल्पनिक प्रतिज्ञापत्र लिखिये।

- 8. What are the important credit instruments used in India ? भारतवर्ष में भिन्न-भिन्न प्रकार के कौन से महत्वपूर्ण साख-पत्र उपयोग में आते हैं ?
- 9. Distinguish between (a) cheque; (b) P/N; and (c) Bill of exchange.

(त्र) चेक, (ब) प्रतिज्ञापत्र, (स) हुन्डी में मेद बत लाइये।

10. Describe the circumstances under which a Banker (a) may, (b) must refuse payment of a cheque.

उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिये जिनमें वैंकर (म्र) चेक का भुगतान करने से इनकार कर सकता है, (व) चेक का भुगतान करने से ऋवश्य इनकार करना चाहिए।

Is credit capital ? Explain fully.
 क्या साख पूँ जी है ? पूर्णतया विवेचना कीजिये ।

ग्रध्याय १४

बैंकिंग विधान

(Banking Law in India)

भारतवर्ष में सन् १६३६ तक बैंकिंग कम्पनियों के लिये कोई विशेष विधान नहीं था और उसमें इंडियन कम्पनीज ऐक्ट १६१३ ही लागू होता था। सन् १६१३ के पश्चात् बहुत सी बैंकों के असफल हो जाने के कारण देश में बैंकिंग व्यवसाय की व्यवस्था की माँग हुई। सन् १६११ में स्थापित की हुई सेंन्ट्रल बैंकिंग जांच कमेटी ने बैंकिंग कम्पनियों की व्यवस्था के लिये एक योजना रखी। किन्तु सन् १६३६ तक भारतीय कम्पनी ऐक्ट में बैंकिंग कम्पनियों से संबन्धित कोई विशेष नियम नहीं जोड़ा गया। ये नियम जमा करने वालों के हित की रक्षा के लिये अपर्याप्त थे। अतः प्रथक वैंकिंग कम्पनी विधान का बनाया जाना आवश्यक हो गया।

सन् १६४१ का बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट १६४६ में पारित किया गया श्रीत १६ मार्च १६४६ से लागू हुआ । यह जम्मू-काश्मीर की रियासत को छोड़ कर सम्पूष् भारतवर्ष पर लागू होता है तथा इस ऐक्ट में भारतवर्ष शब्द का अर्थ है— वे राज्य जिनमें यह लागू होता है । इस ऐक्ट के कुछ मुख्य नियम निम्नलिखित हैं:—

बेंकिंग व्यवसाय— बैंकिंग का श्रर्थ है उधार देने तथा विनियोग करने के लिये जनता के द्रव्य को जमा करना, वह द्रव्य माँग पर श्रथवा श्रन्य किसी प्रकार से लौटाया जा सकता है। श्रीर चेक, ड्राफ्ट, आर्डर श्रथवा किसी प्रकार लौटाया जा सकता है। श्रीर चेक, ड्राफ्ट, आर्डर श्रथवा किसी प्रकार लौटाया जा सकता है। श्रतः वैंकिंग कम्पनी वह कम्पनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करती है तथा कम्पनी शब्द का श्र्य है—कोई भी कम्पनी जिसकी समाप्ति भारतीय कम्पनी ऐक्ट के श्रन्तर्गत हो सकती है।

१६ मार्च १८५६ के पश्चात् बैंकिंग कम्पनी को छोड़ कर श्रीर कोई कम्पनी श्रपने नाम से बैंक, बैंकर बैंकिंग श्रादि शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी। श्रीर भारतवर्ष में कोई भी कम्पनी श्रपने नाम में ऐसे कम से कम एक शब्द का प्रयोग किये बिना बैंकिंग की व्यवसाय नहीं करेगी।

बैंकिंग कम्पनी ट्रस्टों के आरंभ करने तथा पूर्ण करने, ट्रस्टी या अन्य किसी रूप में जायदाद के शासन का दायित्व लेने तथा जमा करने वालों को सुरचा प्रदान करने के उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य से सहायक कम्पनियों का निर्मास नहीं कर सकती। और न कोई बैंकिंग कम्पनी किसी कम्पनी में अपनी प्राप्त अंश पूँजी के ३० प्रतिशत से अधिक अथवा उस कम्पनी की प्राप्त अंश पूँजी के ३० प्रतिशत से अधिक अथवा उस कम्पनी की प्राप्त अंश पूँजी के ३० प्रतिशत से अधिक अथवा उस कम्पनी की प्राप्त कर सकती रहै। बैंकिंग कम्पनी उस कम्पनी के अंश भी नहीं रख सकती जिसके प्रवन्ध में बैंकिंग कम्पनी के प्रवन्ध संचालक अथवा मैनेजर का हित हो।

श्चन्य व्यापार पर प्रतिबंध—वैंक वैंकिंग व्यवसाय के श्वतिरिक्त किसी श्चन्य प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकती, क्योंकि श्चन्य व्यापार करने में सदैव ही बोलिम रहती है। दूसरों के धन से बोलिम वाला व्यापार चलाने का वैंक को श्विकार नहीं है। यदि किसी कारण से दिये हुए श्रृणों की प्रगति में वैंक को कोई श्चन्य व्यापार लेना पड़े तो वैंक को चाहिये कि उसे शीव्रतम बेच दे। इस प्रकार वैंक केवल

बैंकिंग का ही व्यवसाय कर सकती है। ऋन्य प्रकार का व्यापार नहीं। बैंकों का लाइसेन्स लेना—कोई भी कम्पनी तब तक भारतवर्ष में बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती जब तक उसके पास रिजर्व बैंक के द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स न हो। उसके लिये रिजर्व बैंक को व्यवस्थित रूप में एक प्रार्थनापत्र देना पहता है।

लाइसेन्स स्वीकार करने के पहले रिजर्व बैंक को यह संतोष हो जाना चाहिये कि:—
(क) कम्पनी इस स्थिति में है कि वह जमा करने वालों को उनके

दावों की पूरी रकम चुका देगी,
(ख) कम्पनी का कार्य इस प्रकार से तो नहीं चलाया जा रहा है जिससे
जमा करने वालों के हितों की हानि हो, तथा

(ग) भारतवर्ष में रिजस्टर्ड विदेशी बैंकों के विरुद्ध उनका मूल देना किसी प्रकार का अन्तर तो नहीं समभ्तता है।

बैंक का प्रबन्ध—बैंकिंग कम्पनी का प्रबन्धक प्रबन्ध अमिकत्ती अथवा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिये जो कि अन्य बैंकिंग कम्पनी (बैंकिंग कम्पनी की सहायक कम्पनी के अतिरिक्त) का संचालक हो अथवा किसी दूसरे व्यवसाय में जमा हुआ हो अथवा किसी एक समय कम्पनी के उसके प्रबन्ध का पाँच वर्ष से अधिक का ठेका

बैंकिंग कम्पनियाँ अपने नौकरों को कमीशन के रूप में पारितोषिक अथवा लाभों में से अश अथवा अपने साधनों के भिन्न अनुपात में वेतन नहीं दे सकती। अंतिम विषय में रिजर्व बैंक आफ इंडिया का अंतिम निर्माय होगा।

लिया हुआ हो।

पर्याप्त साधन—१६ मार्च १६४६ की वर्तमान कोई भी वैंकिंग करनी उस तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भारतवर्ष में व्यापार नहीं करेगी तथा कोई भी अन्य वैंकिंग कर्मनी भारतवर्ष में तब तक व्यापार नहीं करेगी जब तक कि उसके पास निम्नलिखित मूल्य की प्राप्त की हुई पूँजी तथा रिजर्व न हो :—

(क) यदि उसके एक से ऋषिक राज्यों में व्यापारिक स्थान हों तो ५ लाख रुपयें, श्रीर यदि ऐसे ही व्यापारिक स्थान वस्वई ऋथवा कलकत्ता ऋथवा दोनों स्थानों पर हों तो १० लीख रुपय ।

(ख़) यदि इसके सारे व्यापारिक स्थान एक राज्य में हों तो व्यापार के प्रधान

स्थान के लिये १ लाख रुपये तथा जिस जिले में प्रधान स्थान स्थित है उसी जिले में स्थित व्यापार के अन्य स्थानों में से प्रत्येक के लिए १० हजार रुपये तथा उनके अतिरिक्त अन्य राज्यों में स्थित प्रत्येक स्थान के लिये २५ हजार रुपये।

परन्त जिस बैंकिंग कम्पनी में यह नियम लागू होता है उससे ५ लाख रुपयों

चे ऋषिक वाली प्राप्त ऋश पूँजी तथा रिजर्व नहीं माँगे जायेंगे। (ग) यदि इसके व्यापार के सारे स्थान एक ही राज्य में हैं, जिनमें एक ऋथवा अधिक बम्बई या कलकत्ता में हों तो ५ लाख रुपये, तथा बम्बई अथवा कलकत्ता के बाहर प्रत्येक स्थान के लिये २५,००० रुपये।

परन्त जिन बैंकिंग कम्पनियों में यह नियम लागू होता है उनको १० लाख रुपयों से ऋधिक की प्राप्त की हुई पूँजी तथा रिजर्व रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

भारतवर्ष से बाहर संस्थापित (Incorporated) बैंकिंग कम्पनी की प्राप्त पूँजी तथा रिजर्व १५ लाख रुपयों से कम नहीं होने चाहिये तथा यदि इनके व्यापार का स्थान बम्बई ऋथवा कलकत्ता में भी है तो २० लाख रुपये तथा वह रकम रिजर्व वैंक के पास नकद में ऋथवा ऋगुए से न दबी हुई स्वीकृत प्रतिभृतियों में जमा रखी जायेगी। यदि ऐसी कम्पनी भारतवर्ष में व्यापार करना बन्द कर देती है तो रिजर्व बैंक की जमा रकम कम्पनी की सम्पत्ति होगी जिसमें भारत के ऋण्दाता सर्वप्रथम चुकाये जायेंगे।

पूँजी का निर्माण - वैंकिंग कम्पनी की बिकी हुई पूँजी उसकी अधिकृत पूँबी की ऋाधी से कम नहीं होनी चाहिये तथा प्राप्त की हुई पूँजी बिकी हुई पूँजी के ऋाधे से कम नहीं होनी चाहिये। तो भी यह आयोजन रख दिया गया है कि यदि कंपनी ऋपनी पँजी बढ़ाती है तो उसे वे शतें रिजर्व बैंक के द्वारा स्वीकार की जा सकने वाली

दो वर्ष की अवधि के भीतर प्री कर देनी चाहिये।

पँजी में केवल साधारेण अंश ही होने चाहिये तथा प्रत्येक अंशघारी के मत देंने के श्रिधिकार उसके द्वारा प्राप्त की हुई पूँ जी की रकम के श्रमुपात तक ही सीमित नहीं होने चाहिये किन्तु वे अंशघारियों के मत देने के कल अधिकारों के ५ प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिये।

पूँ जी निर्माण सम्बन्धी उपयु क्त नियम १५ जनवरी, १६३७ से पहले स्थापित

वैंकिंग कम्पनियों में लागू नहीं होते।

बैंकिंग कम्पनी की उनके द्वारा निर्गमित श्रंशों पर उनके प्राप्त किये हुए मूल्य के २१ प्रतिशत से ऋषिक रकम कमीशन, दलाली, बहे अथवा पारितोषिक के रूप में श्रप्रत्यच् रूप से देने की स्वीकृति नहीं है।

कोंई भी बैंकिंग कम्पनी अपनी न माँगी हुई पूँ जी पर किसी प्रकार के क्रय का निर्माण नहीं कर सकती तथा इस प्रकार का कोई भी क्रय अथवा भार अवैद्यानिक है।

लाभांशों पर विरोध — जब तक किसी बैंकिंग कम्पनी के सारे पूँजीगत व्यय बहे खाते नहीं लिख दिये जाने हैं तब तक वह अपने अंशों पर कोई लाभांश नहीं दे सकती।

रिज्ञव कोष — बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट १६४६ की घारा १७ के अनुसार भारत-वर्ष में संस्थापित बैंकिंग कम्पनी को लामांश घोषित करने के पहले कुछ रकम (जो । प्रत्येक वर्ष के शुद्ध लामों की २० प्रतिशत से कम न हो) तब तक रिजर्व कोष में हस्तान्तरित नहीं करनी चाहिये तब तक कि रिजर्व कोष की रकम प्राप्त की हुई पूँजी के समान न हो जावे। इस उद्देश्य के लिये शुद्ध लाम इंडियन कम्पनीज ऐक्ट १६१८ की घारा ८७३ (३) के अनुसार निकाला जाना चाहिये। अर्थात् ऋण ब्याज तथा कटौती देने के पश्चात् किन्तु आय-कर अथवा डिबेंचरों पर ब्याज सम्बन्धी रकम कम करने से पहले बचा खाम।

रोकड़ी रिजर्ब — प्रत्येक वैंकिंग कम्पनी (प्रामाणिक वैंक न हो) को अपने पास रोकड़ी रिजर्ब के रूप में, अथवा रिजर्ब वैंक के पास कम से कम अपने समय-दायित्व की र प्रतिशत तथा माँग दायित्व की ५ प्रतिशत रकम रखनी चाहिये।

इस नियम पर किये गये आचरण की पुष्टि के लिये प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी के प्रत्येक मास के १५ वें दिन के पहले पिछले मास के प्रत्येक शुक्रवार को इस प्रकार रखी रकम के ब्यौरे तथा प्रत्येक शुक्रवार को उसकी समय तथा माँग दायित्व के विवरण की तीन प्रतिलिपियाँ रिजर्व वैक के पास नत्थी करनी पड़ती हैं।

्र रिजर्व बैंक आफ्र इंडिया की धारा ४२ के अनुसार प्रमाणित बैंक भी रिजर्व बैंक के रूप में कुछ स्थायी रकम रखते हैं।

ऋगों पर विरोध—वैंकिंग कम्पनी भी (क) अपने श्रंशों की प्रतिभृति पर ऋग लेने अथवा (ख) अपने किसी संचालक की फर्म अथवा उस प्राइवेट कम्पनी को जिसमें इसका अथवा इसके किसी संचालक अथवा साभीदार अथवा प्रबन्ध अभिकर्त्ता के रूप में हित हो अथवा किसी एक व्यक्ति को, फर्म को, अथवा किसी निजी कम्पनी को, जहाँ इसका कोई संचालक जमानतदार हो, अरिच्चित ऋग्य या एडवांस स्वीकृत करने की आज्ञा नहीं है।

पत्येक वैंकिंग कम्पनी को मास के मास रिजर्व वैंक के पास एक ब्यौरा मेजना पड़ता है जिसमें उनके द्वारा उन कम्पनियों को, जिसमें इसका अथवा किसी संचालक का, संचालक अथवा प्रवन्ध अभिकर्त्ता अथवा जमानतदार के रूप में हित हो, स्वीकार किये हुए अरिच्त अग्ण तथा एडवांस दिसाये जाते हैं। यदि रिजर्व वैंक यह देखती है कि इस प्रकार स्वीकार किये गये अरिच्त अग्णों अथवा एडवांसों से जमा कराये जाने वालों के हितों की हानि होती है तो वह वैंकिंग कम्पनी को भविष्य में ऐसे अग्ण देने के लिये मना कर सकती है अथवा वैंकिंग कम्पनी को ऐसे अग्णों अथवा एडवांसों के पुनर्भगतान को सुरुच्तित रखने के लिये आशा दे सकती है।

तरल सम्पत्ति का रखना—१६ मार्च १६४६ के दो वर्ष पश्चात् प्रत्येक वेंकिंग कम्पनी ने व्यापार के किसी भी दिन के अन्त में भारत में उसके समय और माँग-दाशित्व की कुल रकम की कम से कम २० प्रतिशत रकम नकदी रुपये, स्वर्ण अथवा ऋण मुक्त, स्वीकृत प्रतिभृतियों के रूप में रखनी पड़ेगी। ऐसे दाशित्व में से प्राप्त की हुई पूँजी और रिजर्व, लाभ-हानि खाते का जमा बैलेंस और रिजर्व बैंक से लिया हुआ कोई ऋण छोड़ दिये जाते हैं। रिजर्व बैंक के पास रखी प्रतिभृतियाँ अथवा नकद रकम को नकद ही समक्ता जायेगा।

इस नियम के द्वारा वैंकिंग की ठोस रीतियों को वैधानिक रूप से निश्चित करना है अर्थात् बैंक को अपने माँग-दायित्व को चुकाने के लिये नकद रिर्व्व तथा तरल सम्पत्ति रखनी चाहिये। भारतीय वैंकिंग की सबसे बड़ी कभी यह है कि छोटे-छोटे बैंक तरलता के मूल्य पर पूँजी से अधिक व्यापार करने की ओर सुके हुए हैं। अतः वैंकों से उनकी सम्पत्ति की बहुत बड़ी रकम नकद अथवा ट्रस्ट प्रतिभृतियाँ (अचल सम्पत्ति को छोड़कर) के रूप में रखने के लिये अधिह करना अच्छा जान पड़ता है।

भारतवर्ष में प्रत्येक चतुर्थां श के ऋतिम दिन की सम्पत्ति के समय प्रत्येक वैंकिंग कम्पनी की सम्पत्ति उसके मांग ऋौर समय दायित्वों के ७५ प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये।

इन नियमों का पालन यह विश्वास दिलाने के लिये प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को रिजर्व बैंक के पास व्यवस्थित ऋाकार में मासिक ऋथवा त्रैमासिक व्यौरा मेजना पेड़ता है।

ऋगा चुकाने की बढ़ी हुई खबि — धारा ३० में यह आयोजन है कि यदि कोई बैंकिंग कम्पनी अपने ऋगों को दुछ समय तक चुकाने में असमर्थ है तो उसके प्रार्थना पत्र पर न्यायालय डांचत शतों पर कुछ समय तक कम्पनी के विरुद्ध कदम उठाने से रकने की आशा दे सकता है। समय-समय पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। पर ऋगा चुकाने की कुल बढ़ी हुई अवधि ६ मास से अधिक नहीं होती। न्यायालय की अशा की एक प्रतिलिपि रिजर्व बैंक के पास भेजनी होती है।

साचारणतया ऐसा प्रार्थना-पत्र तभी स्वीकार किया जायेगा जब उसके साथ रिजर्व वैंक की पह रिपोट हो कि बैंक की सम्मित में यदि यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार हो जाये तो बैंकिंग कम्पनी अपने ऋण चुकाने के योग्य हो जायेगी। किन्तु न्यायालय अपनी रीति से काम कर सकती है और यदि इसके पास पर्याप्त कारण है तो यह रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के बिना भी अपनी धारा के अन्तर्गत उनको सहायता देना स्वीकार क्र सकता है।

ऐसी सहायता दिये जाने के पश्चात् न्यायालय को रिजर्व बैंक से उस बैंकिंग कम्पनी के कारबार की रिपोर्ट माँगनी चाहिये तथा उसकी प्राप्ति पर या तो वह अपनी दी हुई आजा की तोड़ सकता है अथवा अवस्थाओं के अनुसार अन्य आजायें दे सकता है। श्रनवें किंग सम्पत्ति का समापन—वैंकिंग कमनी को निजी प्रयोग के श्रितिरिक्त किसी भी श्रवल सम्पत्ति को ७ वर्ष से श्रविक ने लिये श्रपने पान स्वने का श्रविकार नहीं है। यदि किसी कारण कोई श्रवल सम्पत्ति नैंक के श्रविकार में न श्रा जाये तो इसे ७ वर्ष के भीतर बेच देना चाहिये। जना करने वालों के दित में यदि श्रावश्यक है तो रिजर्व नैंक इस श्रविध को ७ की श्रवेदा १२ वर्ष तक बढ़ा स्वती है।

शाखाओं पर प्रतिवन्ध—रिजर्व वैंक की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना कोई वैंक नवीन शाखा स्थापित नहीं कर सकती और न शाखा को एक नगर में दूनरे नगर में ले जा सकती है। उसी नगर में स्थान परिवर्तन पर कोई प्रतिवन्ध नहीं है। इसी प्रकार कोई भी भारतीय वैंक रिजर्व वैंक की अनुमित प्राप्त किये जिना विदेश में न अपनी शाखा खोल सकती है और न व्यापार कर सकती है तथा उसी नगर के अतिरिक्त शाखा अथवा व्यापार का स्थान परिवर्तन की नहीं कर सकती।

सामयिक विवरण—प्रत्येक वैंक के लिये यह श्रानियाय है कि प्रति भास रें श्रानिस शुक्रवार को जो उसकी सम्पत्तियाँ तथा दायित्व थे उनका निर्धारित विवरण रिजर्व वैंक के पास मेजे। रिजर्व वैंक को किसी भी श्रान्य विवरण एवं एउटा मार्ग ने आधिकार है। विशेषकर उन ऋणों तथा विनियोगों का जो उन्होंग, व्यवसाय एवं कृषि के लिये किये गये हैं। रिजर्व वैंक हर प्रकार की सूचनायें चाहे वे गोपनीय भी क्यों नहीं, कैंक में माँगने की श्राविकारी है।

हों, केंक से माँगने की अधिकारी है।

'वेंकों का निरीक्ता — रिजर्व वेंक स्वयं अथवा केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार किसी भी बैंक की पुस्तकों का निरीक्तण कर सकती है। बैंक के संचालकों का
कर्त्तव्य है कि वे हर प्रकार की स्वना तथा विपन्न रिजर्व वेंक को मेजें। रिजर्व वेंक
अपने निरीक्तण की एक प्रति सम्बन्धित वेंक को देने के लिये बाध्य है। वर्द इस
रिपोर्ट में बैंक के ऊपर बुद्ध आरोप लगाये गये हैं तो केन्द्रीय सरकार बेंकों को नवीन
जमा प्राप्त न करने का आदेश दे सकती है अथवा रिजर्व वेंक को यह आदेश दे
सकती है कि बैंक के निरीक्षण के लिये न्यायालय में प्रार्थना-पन्न प्रस्तुत करें। रिजर्व
बैंक से रिपोर्ट पर विचार करने के लिए संचालकों की बैटक बुलाने का आदेश दे सकती
है। अथवा सहभी आग्रह कर सकती है कि बेंक का कोई प्रमुख अधिकारी रिजर्व वेंक
के प्रमुख अधिकारी से इस सम्बन्ध में वार्तालाप करें। संचालकों की मीटिंग पर हिस्ट
रखने के लिए बेंक अपने किसी अधिकारी को मेज सकती है। रिजर्व बेंक को यह भी
अधिकार है कि वह बेंक से व्यवस्था में परिवर्तन करने को कहे।

रिजर्व बैंक बैंक को किसी विशेष लेन-देन न करने के लिये श्रामह कर सकती है तथा संकट काल मैं ऋणा प्रदान करके उनकी सहायता कर सकती है। रिजर्व बैंक ब्रैंकों को व्यवस्था में स्थार करने के संबन्ध में भी श्रादेश दे सकती है। यदि वे सुधार